

तृतीय सेमेस्टर
Third Semester

लोक वित्त
Public Finance

एम.ए.ई.सी. - 602
M.A.E.C. - 602

विषय-सूची

खण्ड – 1 प्रस्तावना एवं सिद्धान्त (Introduction and Theories)	पृष्ठ संख्या 1-97
इकाई 1- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade)	1-14
इकाई 2- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विश्लेषणात्मक तकनीक (Analytical Technique of International Economics)	15-34
इकाई 3- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त (Classical Theory of International Trade)	35-52
इकाई 4- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नव प्रतिष्ठित सिद्धान्त (Neo-Classical Theory of International Trade)	53-73
इकाई 5- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धान्त (Modern Theory of International Trade)	74-97
खण्ड – 2 व्यापार की शर्तें मुक्त व्यापार संरक्षण एवं सीमा संघ के सिद्धान्त (Terms of Trade, Free Trade, Protection and Custom Union) 98-159	पृष्ठ संख्या
इकाई 6- व्यापार की शर्तें और आर्थिक संवृद्धि (Terms of Trade and Economic Growth)	98-111
इकाई 7- मुक्त व्यापार एवं संरक्षण (Free Trade and Protection)	112-121
इकाई 8- गैर-टैरिफ व्यापार बाधाएं (Non-Tariff Trade Barriers)	122-134
इकाई 9- राशिपातन और राज्य व्यापार (Dumping and State Trading)	135-144
इकाई 10- सीमा संघ के सिद्धान्त (Theory of Customs Union)	145-159

खण्ड – 3 भुगतान सन्तुलन (Balance of Payments)	पृष्ठ संख्या 160-263
इकाई 11- भुगतान सन्तुलन:परिभाषा और अवधारणा (Balance of Payments: Definition and Concepts)	160-181
इकाई 12- विदेशी व्यापार गुणक (Foreign Trade Multiplier)	182-205
इकाई 13- भुगतान संतुलन में समायोजन के परम्परागत अवशोषण (Conventional Absorption adjustment in Balance of Payments)	206-225
इकाई 14- मौद्रिक उपागम तथा भुगतान-सन्तुलन में समायोजन (Monetary Approach and Adjustment Mechanism of Balance of Payments)	226-246
इकाई 15- इष्टतम मुद्रा क्षेत्र सिद्धान्त (Theory of Optimum Currency Area)	247-263

Suggested Readings:

1. Berg, H.V.D. (2012) *International Economics –A heterodox Approach*, Yes Dec Publishing Pvt. Ltd., Chennai
2. Bhagwati, J. (Ed.) (1981), *International Trade: Selected Readings*, Cambridge University Press, Mass.
3. Carbough, R. J. (1999) *International Economics*, International Thompson Publishing, New York
4. Cherunilam, Francis (2009) *International Economics*, Oxford University Press India.
5. Dana, M. S. (2000) *International Economics: Study, Guide and Work Book*, (5th Edition), Routledge Publishers, London
6. Ellsworth, P.T. (1958) *The International Economy*, Macmillan Company, New York
7. Kenen, P. B. (1994) *The International Economy*, Cambridge University Press, London.
8. Kindleberger, C. P. (1973) *International Economics*, R. D. Irwin, Homewood.
9. Krugman, P.R. and Maurice Obstfeld (2009) *International Economics*, Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd., New Delhi
10. Mannur, H.G. (1999) *International Economics, Theory & Practice*, Vikash Publishing House Pvt. Ltd, New Delhi
11. Mithani, D.M. (2008) *International Economics*, Himalaya Publishing House, New Delhi.
12. Mundell, R. (1968), *International Economic*, The Macmillan Company Ltd., New York
13. Murthy, G. (2010) *International Trade and Economic Co-operation*, New Century Publications, New Delhi
14. Rana, K. C. and K. N. Verma (2014) *International Economics*, Vishal Publishing Company, Jalandhar
15. Salvatore, D. (1997) *International Economics*, Prentice Hall, New York
16. Sodersten, Bo and Geoffrey Reed (1994) *International Economics*, Macmillan Press Ltd., London
17. Sudama, Singh (1998), *International Economics*, Oxford University Press India.
18. Verma, M.L. (1995) *International Trade*, Vikas Publishing House Pvt. Ltd, New Delhi

इकाई 1- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade)

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, प्रकृति एवं लाभ
 - 1.3.1 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लक्षण
 - 1.3.2 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ
- 1.4 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार
- 1.5 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतरक्षेत्रीय व्यापार
- 1.6 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धांत की आवश्यकता
- 1.7 अभ्यास हेतु प्रश्न
- 1.8 सारांश
- 1.9 शब्दावली
- 1.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 1.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 1.12 उपयोगी/ सहायक पाठ्य सामग्री
- 1.13 निबंधात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के खंड एक “प्रस्तावना एवं सिद्धांत” से सम्बंधित यह पहली इकाई है। इससे पहले अर्थशास्त्र के व्यष्टि तथा समष्टि सिद्धांतों के अध्ययन के पश्चात् आप विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बता सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की ही एक विशेष स्थिति है। समस्त आंतरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रियाओं का आधार वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय या क्रय-विक्रय है; अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सम्बन्ध राष्ट्रों के मध्य समस्त आर्थिक सौदों से है।

प्रस्तुत इकाई में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, अर्थ और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतरक्षेत्रीय व्यापार में अंतर के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धांत की आवश्यकता पर भी चर्चा की गयी है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार एवं प्रकृति के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

1.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप

- ✓ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अर्थ एवं प्रकृति को समझ सकेंगे।
- ✓ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार जान सकेंगे।
- ✓ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतरक्षेत्रीय व्यापार में अंतर समझ सकेंगे।
- ✓ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धांत की आवश्यकता को समझ सकेंगे।

1.3 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, प्रकृति एवं लाभ

व्यापार का अर्थ है वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय या क्रय-विक्रय। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार का ही एक विशेष स्वरूप है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ है राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय या क्रय-विक्रय। स्वतंत्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ उस वाणिज्यिक नीति से है जो वस्तुओं तथा सेवाओं के घरेलू तथा विदेशी विनिमय के मध्य विभेद नहीं करती।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक ऐसी क्रियाविधि या तरीका है। जोकि वस्तुओं, सेवाओं तथा संसाधनों के जरिये विश्व के विभिन्न देशों को आपस में जोड़ता है। आर्थिक समृद्धि मुख्यतया श्रम विभाजन और विष्टिकरण पर निर्भर करता है जबकि श्रम विभाजन और विष्टिकरण बाजार के आकार पर निर्भर करता है; बाजार का आकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से बढ़ता है। व्यापार से तात्पर्य है पूर्ति, यदि घरेलू उपभोग देश के उत्पादन से अधिक हो, तथा मांग, यदि देश का उत्पादन घरेलू उपभोग से अधिक हो के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भरता। एक देश व्यापार न होने की स्थिति में आत्मनिर्भर हो सकता है परन्तु भौतिक रूप से वह काफी गरीब होगा; ऐसी आत्मनिर्भरता देश के उत्पादन के आकार तथा उसकी दक्षता को बिलकुल सीमित कर देती है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत पुरे विश्व को एक समुदाय के रूप में देखता है। जोकि देशों की सीमाओं में भले विभाजित हो परन्तु आय व रहन – सहन के स्तर में वृद्धि के समान उद्देश्य से बंधा है। यह विकास के अंतर्मुखी रणनीति की अपेक्षा बहिर्मुखी रणनीति की वकालत करता है। जोकि अपेक्षाकृत सरल और कम श्रमसाध्य तरीका है। **सर डेनिस राबर्टसन (Dennis Robertson)** अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी देश के आर्थिक समृद्धि और विकास का इंजन कहा है।

1.3.1 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लक्षण

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं:

1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में संसाधनों की गतिशीलता अनेक कारणों से अंतरक्षेत्रीय या घरेलू व्यापार की अपेक्षा काफी कम रहती है इसलिए संसाधनों और उत्पादों की कीमतों में भी अंतर होता है।
2. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राजनीतिक इकाइयों के बीच ही उत्पन्न होता है। राजनीतिक तंत्र के भिन्न होने से एक देश की राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियां, विभिन्न कानून व नियम, सरकारी हस्तक्षेप के तरीके तथा उनकी गुणवत्ता इत्यादि भिन्न होते हैं।
3. विभिन्न देशों के बीच सामाजिक- आर्थिक वातावरण भी काफी भिन्न होने से व्यापार उत्पन्न होता है।
4. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न देशों के बाजारों में भी; भिन्न भाषा, रीतिरिवाज, जलवायु, आदतें, प्राथमिकताएं इत्यादि भिन्न होने के कारण; भिन्नता होती है। असमांग बाजार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख प्रभेदक लक्षण है।
5. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख प्रभेदक लक्षण यह है कि यह विभिन्न प्रकार कि मुद्राओं को अपने व्यापार में सम्मिलित करता है। चूंकि हर एक देश कि मुद्रा अलग है इसलिए विनिमय दरों और विदेशी विनिमय से सम्बंधित विभिन्न देशों कि नीतियां भी अलग- अलग है।

1.3.2 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं:

1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विष्टिकरण और श्रम विभाजन को बढ़ावा देकर व्यापार में सम्मिलित देशों के लाभों को बढ़ाता है।
2. अन्तर्राष्ट्रीय विष्टिकरण और भौगोलिक श्रम विभाजन से विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन सुनिश्चित करता है।
3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार में सम्मिलित देशों के उत्पादन में वृद्धि लाकर उन्हें समृद्ध बनाता है, उनके धन में वास्तविक वृद्धि लाता है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रत्येक देश के उपभोग या आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है।
4. इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पुरे विश्व के उत्पादन तथा आर्थिक कल्याण में वृद्धि लाता है।
5. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देकर एकाधिकरात्मक प्रवृत्तियों को रोकता है तथा एकाधिकरात्मक शोषण से उपभोक्ताओं को बचाता है।
6. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व के सभी देशों के हितों कि रक्षा करता है और कच्चे मॉल कि उपलब्धि के लिए सभी देशों को समान अवसर प्रदान करता है।
7. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग तथा सांस्कृतिक मूल्यों के आदान प्रदान का माध्यम बनता है।
8. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बाजार के आकार को बढ़ाता है जिससे और जटिल विष्टिकरण और श्रम विभाजन को बढ़ावा मिलता है।
9. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर घरेलू उत्पादकों को अत्यधिक दक्ष होने और उत्पादों कि गुणवत्ता बढ़ाने को प्रेरित करता है।
10. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार श्रम और पूंजी कि प्रकृति में गुणात्मक परिवर्तन लाता है साथ ही तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान के कारण भी काफी भिन्न प्रकार के परिवर्तन देशों में होते हैं।

1.4 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त के सामने एक मूलभूत प्रश्न यह रहा है कि दो या दो से अधिक देश आपस में व्यापार क्यों करते हैं? कोई भी देश व्यापार तभी करेगा जब उसे व्यापार से लाभ होगा। तो प्रश्न यह उठता है कि व्यापार से लाभ क्यों होता है? इन्हीं प्रश्नों-उत्तरों में तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का सार निहित है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रीयों ने मात्र श्रम को ही उत्पादकता का साधन मानते हुए, विभिन्न देशों के बीच श्रम-उत्पादकता के अंतर को ही व्यापार कारण कहा है।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार दो देशों के बीच लागतों या लागत दशाओं में जितना ही अंतर होगा उतना ही व्यापार से लाभ होगा, यह लाभ व्यापार में भाग लेने वाले एक या दोनों ही देशों को प्राप्त हो सकता है। जिन कारणों से विभिन्न व्यक्ति आपस में व्यापार करते हैं उन्हीं कारणों से विभिन्न राष्ट्र भी एक दूसरे से व्यापार करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने उपभोग के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकता है और यह बात राष्ट्रों के संदर्भ में भी लागू होती है। प्रकृति ने पृथ्वी की सतह पर उत्पादन के संसाधनों का वितरण असमान ढंग से किया है। जलवायु दशाओं, खनिज संसाधनों, श्रम तथा पूंजी संसाधनों, प्राकृतिक संसाधन प्रचुरता, तकनीकी क्षमताओं, उद्यमीय तथा प्रबंधकीय क्षमताओं और उन सभी चीजों जो कि किसी देश की उत्पादन क्षमता को निर्धारित करती है, में विभिन्न राष्ट्रों की स्थिति भिन्न होती है। उत्पादन संभावनाओं में यह अन्तर ऐसी स्थितियों को जन्म देता है जहाँ कुछ देश अन्य देशों की अपेक्षा कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन अधिक दक्षतापूर्वक कर सकते हैं और कोई भी देश सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन पूरी दक्षता पूर्वक अर्थात् न्यूनतम संभव उत्पादन लागत पर नहीं कर सकता है।

जिस प्रकार व्यक्तियों के बीच श्रम विभाजन होता है उसी तरह विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण हो सकता है। एक राष्ट्र उस वस्तु या सेवा के उत्पादन में विशिष्टता हासिल करता है जिसमें कि वह अन्य देशों की अपेक्षा उत्पादन में श्रेष्ठ होता है विनिमय की प्रक्रिया में व्यक्ति या उपभोक्ता जिस प्रकार अपनी संतुष्टि या विनिमय से लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है उसी प्रकार अर्न्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से कम कीमत पर वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद करके लाभ प्राप्त करता है।

वस्तुतः वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय से प्राप्त होने वाला लाभ ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है यदि कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा। और व्यापार से लाभ का तात्कालिक कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में विद्यमान अंतर है जो कि पूर्ति तथा माँग की दशाओं में अन्तर के कारण उत्पन्न होता है।

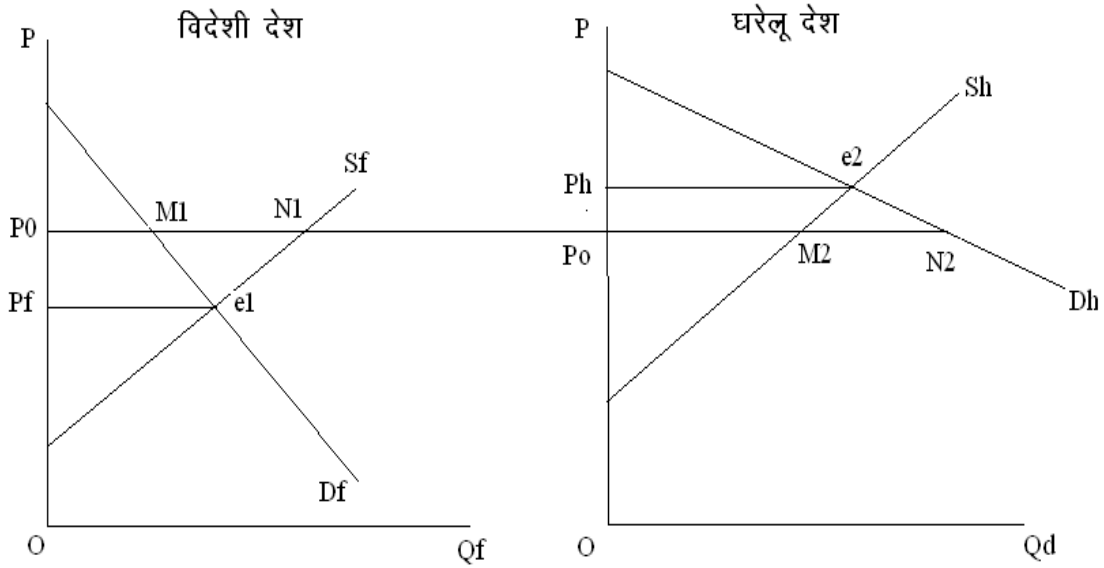
इस प्रकार वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में अन्तर, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है, निम्नलिखित स्थितियों के कारण उत्पन्न हो सकता है

- (क) यदि पूर्ति-दशाओं में अन्तर हो, या
- (ख) यदि माँग-दशाओं में अन्तर हो या
- (ग) यदि माँग और पूर्ति दोनों की दशाओं में अन्तर हों

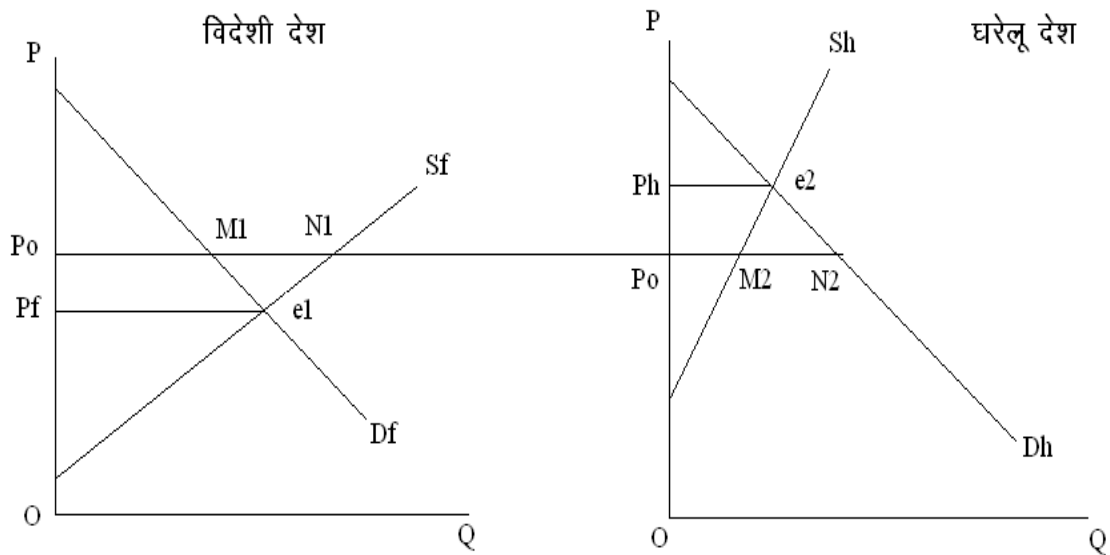
स्पष्ट है कि यदि दो देशों में माँग तथा पूर्ति, दोनों दशाएँ एक समान है, तो उनमें कोई व्यापार सम्भव नहीं है, क्योंकि तब व्यापार से किसी भी देश को लाभ नहीं होगा।

पूर्ति दशाओं में अंतर बहुत सारे कारणों से पैदा हो सकते हैं, जैसे-आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता, इन संसाधनों की दक्षता का स्तर, उत्पादन में प्रस्तुत तकनीकी का स्तर, श्रम की योग्यता, साधन गहनता इत्यादि। वास्तव में पूर्ति-पक्ष राष्ट्रों के बीच साधन-सम्पन्नता तथा उत्पादन-दक्षता में अंतर का बताता है, जो कि वस्तुओं तथा सेवाओं की उत्पादन लागतों और बिक्री कीमतों में व्यक्त होती है।

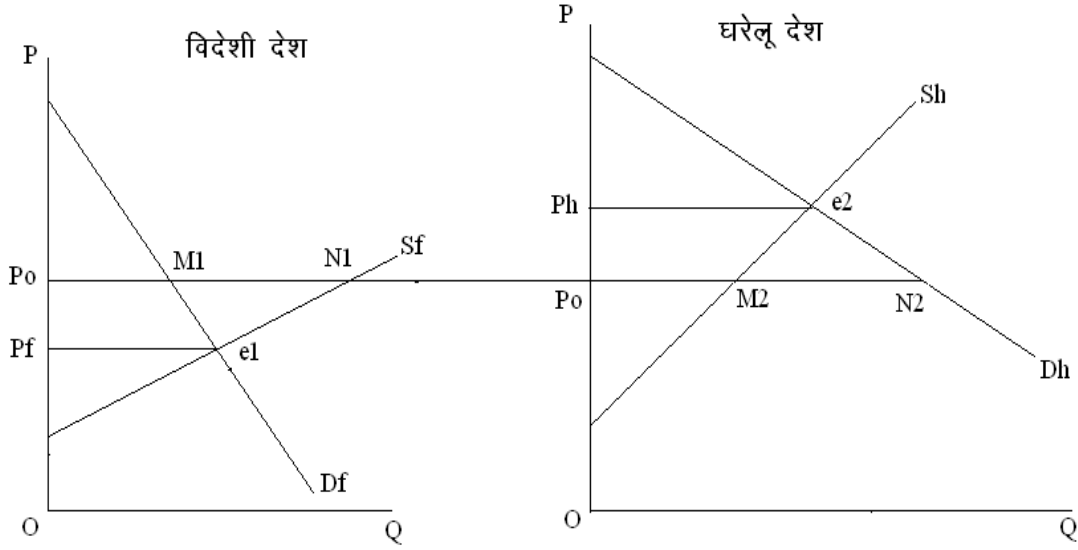
दो देशों के मध्य पूर्ति दशाएँ या उत्पादन लागत समान होने की स्थिति में भी, माँग दशाओं में अंतर के कारण कीमतों में भिन्नता हो सकती है। माँग में अन्तर मुख्यतः आय के स्तरों तथा रुचि पर निर्भर करता है। हम उपरोक्त तीनों स्थितियों को चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं:



चित्र-1.1 जब पूर्ति दशाएँ समान हों, तथा माँग दशाओं में अन्तर हो



चित्र-1.2 जब पूर्ति दशाएँ समान हों, तथा माँग-दशाओं में अन्तर हो



चित्र-1.3 जब पूर्ति तथा मांग दशाएँ दोनों भिन्न हों।

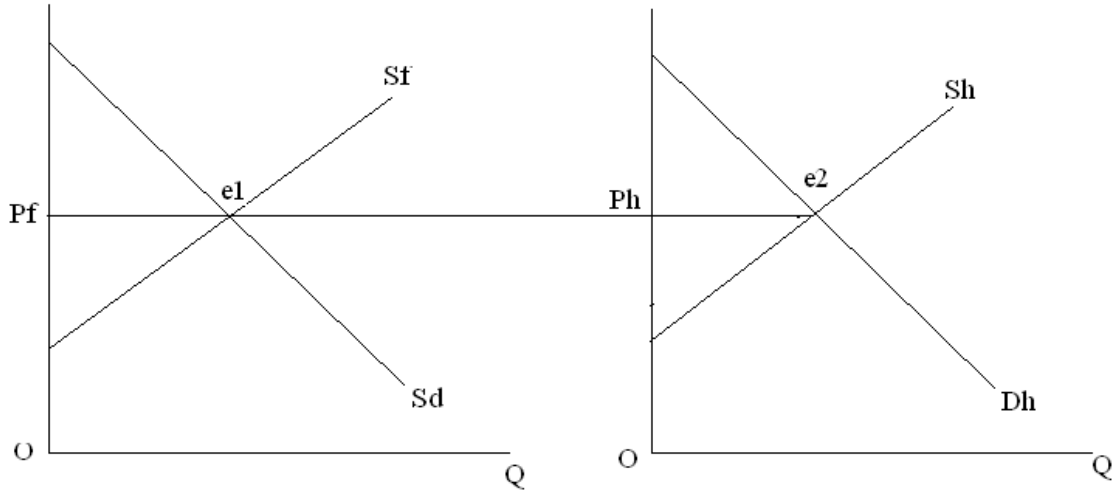
उपरोक्त तीनों चित्रों में विदेशी तथा घरेलू देश की, एक दिए हुए वस्तु या उत्पाद के संदर्भ में, माँग तथा पूर्ति की विभिन्न दशाओं को दर्शाया गया है। X-अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा Y अक्ष पर कीमत प्रदर्शित की गयी है। Sf तथा Df क्रमशः विदेशी देश के पूर्ति तथा माँग वक्र को और Sh तथा Dh क्रमशः घरेलू देश के पूर्ति तथा माँग वक्र है। Pf तथा Ph क्रमशः विदेशी तथा घरेलू देश में व्यापार न होने की दशा में कीमतें हैं। P_0 व्यापार शुरू के पश्चात् दोनों देशों की संतुलन कीमत को व्यक्त करता है।

उपरोक्त सभी चित्रों में, विदेशी देश में वस्तु की कीमत (Pf) घरेलू देश की कीमत (Ph) से कम है ($P_f < P_h$) यह अंतर निम्नलिखित कारणों से है -

- (क) चित्र-1.1 में पूर्ति-दशाएँ भिन्न हैं। विदेशी पूर्ति वक्र (Sf) घरेलू पूर्ति वक्र (Sh) की अपेक्षा अधिक लोचदार है।
- (ख) चित्र-1.2 में माँग-दशाओं में भिन्नता है। घरेलू माँग वक्र (Dh) विदेशी माँग वक्र (Df) की अपेक्षा अधिक लोचदार है।
- (ग) चित्र-1.3 में पूर्ति तथा माँग-दशाएँ दोनों भिन्न हैं।

चूँकि घरेलू देश में वस्तु की कीमत विदेशी देश की अपेक्षा अधिक है, इसलिए विदेशी देश से घरेलू देश को वस्तु का आयात होगा। इस प्रकार कीमत अंतर के कारण वस्तु का व्यापार होगा जिसमें विदेशी देश निर्यातक तथा घरेलू देश आयातक होगा। वस्तु का विदेशी देश से निर्यात तथा घरेलू देश से आयात तब तक जारी रहेगा जब तक कीमतों में अंतर पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता है और घरेलू देश का आयात विदेशी देश के निर्यात की मात्रा के बराबर और स्थिर नहीं हो जाता। चित्र में संतुलन की स्थिति में कीमत P_0 है जिस पर आयात और निर्यात की मात्राएँ स्थिर तथा एक दूसरे के बराबर हैं। P_0 कीमत पर, कीमत अंतर समाप्त हो जाने के बाद आगे व्यापार के लिए कोई प्रेरणा नहीं होगी।

चित्र-1.4 में, दोनों देशों में समान पूर्ति और माँग की स्थितियाँ दर्शायी गयी हैं। चूँकि कीमतों में कोई अंतर नहीं है ($P_s = P_h$) इसलिए व्यापार संभव नहीं है।



चित्र-1.4 जब पूर्ति व मांग दशाएँ दोनों समान हैं

इस प्रकार जब कीमतों में अन्तर होगा तो व्यापार से दोनों देशों को लाभ होगा और उनके उपभोग तथा कल्याण के स्तर में वृद्धि होगी। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व के राष्ट्रों के समक्ष यह संभावनाएं खोल देता है कि वे उन आर्थिक गतिविधियों में विशिष्टीकरण प्राप्त करें जिनमें वे सर्वाधिक सम्पन्न तहत दक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उप-विभाजन तथा विशिष्टीकरण व्यापार में भाग लेने वाले सभी देशों को लाभ पहुंचाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तु कीमतों के साथ-साथ कीमतों में भी सामानीकरण लाता है।

1.5 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतरक्षेत्रीय व्यापार

दो राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा एक राष्ट्र की सीमाओं के भीतर होने वाले व्यापार को अंतरक्षेत्रीय या आंतरिक व्यापार कहते हैं। अंतरक्षेत्रीय या आंतरिक व्यापार को ओहलिन अंतर स्थानीय व्यापार कहते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कई अर्थशास्त्री अंतरक्षेत्रीय तथा स्थानीय व्यापार से भिन्न नहीं मानते हैं क्योंकि दोनों ही विनिमय की क्रियाएँ हैं और मूलतः एक-सी हैं।

वास्तव में अर्थशास्त्रियों के बीच यह काफी विवाद का विषय रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतरक्षेत्रीय या स्थानीय व्यापार से भिन्न है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार दन दोनों में एक निश्चित मूलभूत अन्तर है परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्रियों जैसे ओहलिन और गॉटफ्राइड वॉन हैबरलर (Gottfried Von Haberler) के अनुसार इन दोनों के बीच अंतर स्थापित करना न तो संभव है और न ही इसकी आवश्यकता है।

एक देश के नागरिकों के मध्य वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय आन्तरिक व्यापार तथा एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ विनिमय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जा सकता है। इन दोनों के बीच अंतर के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं

1. **साधन गतिशीलता-** प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री उत्पादन के संसाधनों की भौगोलिक गतिशीलता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतरक्षेत्रीय व्यापार के मध्य विभेद करते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक देश के भीतर उत्पादन के संसाधन पूरी तरह गतिशील होते हैं, इसलिए देश के भीतर एक ही प्रकार तथा गुणवत्ता वाले किसी भी संसाधन की कीमत समान होगी परन्तु राष्ट्रों के बीच संसाधन पूरी तरह गतिशील हैं। इसलिए सापेक्षिक कीमतों का निर्धारण करने वाला सिद्धान्त घेरलू तथा विदेशी व्यापार के लिए अलग-अलग होगा।

ओहलिन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार देश के भीतर अंतरक्षेत्रीय स्तर पर भी, संसाधन जैसे श्रम व पूँजी अगतिशील रहते हैं। एक देश के अंदर मजदूरी दरें न केवल भिन्न-भिन्न व्यवसायों में भिन्न-भिन्न होती हैं बल्कि एक ही व्यवसाय में विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होती हैं। ब्याज दरें भी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए बदलती रहती हैं। इसी प्रकार, श्रम और पूँजी राष्ट्रों के बीच पूरी तरह अगतिशील नहीं हैं। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा तथा लैटिन अमेरिका देशों का तीव्र विकास इंग्लैण्ड और यूरोप से श्रम और पूँजी के चलन से ही संभव हुआ। आज विदेशी पूँजी का अल्पविकसित देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। यूरोपीय संघ के देशों में श्रमिक स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि संसाधनों की घेरलू गतिशीलता और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता में केवल अंश (डिग्री) का ही अंतर है। संसाधनों की अंतरक्षेत्रीय गतिशीलता इसकी अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता से अधिक होती है।

वास्तव में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में संसाधनों की स्थान गतिशीलता को शून्य मानते हैं। पर्याप्त संसाधन गतिशीलता के अभाव में एक ही जैसे व्यवसायों में संसाधनों की कीमतों में अन्तर विद्यमान रहेगा। इस अर्थ में, जहाँ तक प्राकृतिक संसाधनों की बात है, शून्य गतिशीलता होगी।

2. **उत्पाद गतिशीलता** – एक राष्ट्र के भीतर वस्तुओं तथा सेवाओं की आवाजाही या गतिशीलता स्वतंत्र होती है। यह गतिशीलता सिर्फ भौगोलिक दूरी या परिवहन लागत द्वारा सीमित होती है परन्तु दो राष्ट्रों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं की गतिशीलता पर अनेक मानवव्यजनित प्रशुल्क तथा गैर-प्रशुल्क अवरोध होते हैं। जोकि वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को न सिर्फ सीमित कर देते हैं बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता से भिन्न प्रकार का बना देते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्राकृतिक अवरोध जैसे भौगोलिक दूरी तथा परिवहन लागत भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।

राजनैतिक सीमाओं का अस्तित्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान का नियंत्रण एवं नियमन विभिन्न रूपों में करता है, जैसे, प्रशुल्क, कोटा, विनिमय नियंत्रण, विदेशी व्यापार अधिनियम एवं नियंत्रण के अति सूक्ष्म उपाय, जिसे प्रशासनिक संरक्षणवाद कहा जाता है, आदि।

3. **अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक विभिन्नताएँ** - अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक विभिन्नताएँ अंतर्राष्ट्रीय लेन-देनों में अनेक प्रकार की जटिलता एवं अवरोध पैदा करती हैं जो कि घेरलू व्यापार तथा विनिमय में नहीं होता है। एक राष्ट्र के अंदर मौद्रिक कानून तथा वित्तीय प्रणाली व व्यवस्था सभी क्षेत्रों में एक ही तरह की होती है। जबकि आन्तरिक या अंतरक्षेत्रीय व्यापार में विनिमय के माध्यम के लिए या मूल्य के मापन के लिए एक ही करेंसी का प्रयोग किया जाता है जिससे विनिमय काफी आसान होता है। स्वतंत्र राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के कारण विभिन्न देशों की मुद्राओं को एक निश्चित अनुपात में विनिमय की आवश्यकता है।
4. **आर्थिक एवं राजनैतिक वातावरण** – राष्ट्र के अंदर आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक वातावरण देश के सभी क्षेत्रों में लगभग समान रहता है। उपभोग, उत्पादन, निवेश और वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय को संचालित करने वाला वैधानिक ढाँचा या कानून पूरे देश में एक समान रहता है। ब्याज दरों, मजदूरी तथा कीमतों से संबंधित सरकारी नीतियां पूरे राष्ट्र में एक-सी होती हैं। इसी प्रकार बाजार-संरचना, उपभोक्ताओं की रुचि की प्रवृत्तियों और अधिमान कमोवेश पूरे राष्ट्र में एक-

से होते हैं। परन्तु विभिन्न राष्ट्रों के बीच इनमें महत्वपूर्ण अन्तर पाया जाता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से आंतरिक व्यापार से अलग कर देता है।

5. **भुगतान-शेष की समस्या** - आन्तरिक व्यापार में राष्ट्र के अंदर किसी क्षेत्र या राज्य में भुगतान-शेष की समस्या नहीं होती है क्योंकि आंतरिक असंतुलन का वित्तीयन अपने आप हो जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान-शेष के असंतुलन की समस्या काफी गम्भीर और व्यापक है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री उपरोक्त तर्कों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंतरक्षेत्रीय व्यापार से मूलतः भिन्न मानते हैं।

1.6 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री उत्पादन के संसाधनों की भौगोलिक गतिशीलता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतरक्षेत्रीय व्यापार के मध्य विभेद करते हैं। इस प्रकार उन्होंने तुलनात्मक लागत अंतरों के सिद्धान्त पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्रियों जैसे ओहलिन और गॉटफ्राइड वॉन हैबरलर (Gottfried Von Haberler) के अनुसार इन दोनों के बीच अंतर स्थापित करना न तो संभव है और न ही इसकी आवश्यकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धान्त की कोई आवश्यकता नहीं है।

1. **आधुनिक दृष्टिकोण** - ओहलिन के अनुसार घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मूलतः कोई मूलभूत अंतर नहीं है। दोनों में स्थान कारक महत्वपूर्ण है तथा वस्तुएँ व सेवाएँ उन स्थानों से जहाँ कि वे प्रचुर मात्र में होती हैं, उन स्थानों कि ओर जाती हैं जहाँ वे कम होती हैं। दोनों में ही परिवहन लागतें शामिल हैं। दोनों में लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य से फर्म व्यापार करती हैं। एक देश की मुद्रा भी दूसरे देश की मुद्रा से परिवर्तनीय होती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतरक्षेत्रीय व्यापार में कोई मूलभूत अंतर नहीं पाया जाता है।

ओहलिन के अनुसार किस प्रकार कोई व्यक्ति या समूह अपनी आवश्यकता की समस्त वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते और आपस में व्यापार करते हैं उसी प्रकार विभिन्न राष्ट्र भी व्यापार में संलग्न हैं। विशिष्टीकरण का मूलभूत सिद्धान्त जो जीवन के सभी श्रेणों में पाया जाता है, निश्चित रूप से उसी प्रकार और उतनी ही दृढ़ता से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी लागू होता है। इस प्रकार, तुलनात्मक लागतों के सिद्धान्त का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रयोग अनावश्यक है क्योंकि यह समस्त प्रकार के व्यापारों का आधार है।

अतः ओहलिन का विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धान्त की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतरस्थानीय या क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय की गयी वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें उसी प्रकार निर्धारित होती है जिस प्रकार अंतरक्षेत्रीय स्तर पर विनिमय की गयी वस्तुओं की क्योंकि कीमत निर्धारण का आधार दोनों ही स्थितियों में मांग और पूर्ति का सामान्य संतुलन है। प्रशुल्क अवरोध, करेन्सी की भिन्नताएँ, भाषा, आदतों, रुचियों, रीति-रिवाजों इत्यादि की विभिन्नताएँ मात्रात्मक हैं, मूल्यात्मक नहीं है। वास्तव में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं तथा सेवाओं के मुक्त प्रवाह को नहीं रोकती है। इस प्रकार ओहलिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वीकृत विशिष्टताओं को ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू व्यापार के लक्षणों में अंतर मात्रात्मक है या केवल अंश (डिग्री)

का अंतर है, यह अंतर मूलभूत गुणात्मक प्रकृति का नहीं है जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धांत के औचित्य को स्वीकार किया जाता है।

2. **निष्कर्ष-** परंतु वास्तविकता में अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतरक्षेत्रीय व्यापार में काफी भिन्नताएँ हैं। जैसा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं। अंतरक्षेत्रीय व्यापार में विनिमय दरों, भुगतान शेषों, प्रशुल्कों इत्यादि की समस्याएँ बिल्कुल उत्पन्न नहीं होती हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ये अभिन्न अंग हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, गैट (GATT), अंकटाड (UNCTAD) तथा विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसी संस्थाएँ स्थापित की गयीं, जिनका घरेलू व्यापार से कोई सरोकार नहीं है। इतना ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समष्टि तथा व्यष्टि भागों से संबंधित अनेक सिद्धांत और मॉडल, हेक्सर, ओहलिन, सैम्युलसन, लियोन्टिफ, जोनसन, भगवती आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित किये गये हैं। जोकि आन्तरिक व्यापार से संबंधित सिद्धान्तों से सर्वथा भिन्न है।

1.7 अभ्यास हेतु प्रश्न

लघुउत्तरीय प्रश्न:

1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख क्या हैं?
2. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लक्षण क्या हैं?
3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य लाभ क्या हैं?
4. *"संसाधन घरेलू स्तर पर पूरी तरह गतिशील तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगतिशील होते हैं।"* विवेचना कीजिए।
5. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धान्त की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न:

1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं?
2. श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण से क्या तात्पर्य है?
3. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है?
4. दो या दो से अधिक देश आपस में व्यापार क्यों करते हैं?

निश्चित उत्तरीय प्रश्न:

1. व्यापार से लाभ का क्या कारण है?
2. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतरक्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा है। किसका कथन है?

बहुविकल्पीय प्रश्न:

1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार परिणाम है
 - i. भौगोलिक श्रम विभाजन का
 - ii. सांस्कृतिक मूल्यों के आदान प्रदान का आदान प्रदान का
 - iii. राजनीतिक संबंधों का
 - iv. उपरोक्त सभी

2. किसने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी देश के आर्थिक समृद्धि और विकास का इंजन कहा है।
 - i. डेनिस राबर्टसन
 - ii. मार्शल
 - iii. मिल
 - iv. रिकार्डो
3. निम्नलिखित में से कौन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ नहीं है:
 - i. विश्व के उत्पादन में वृद्धि
 - ii. आर्थिक कल्याण में वृद्धि
 - iii. वस्तुओं कि किस्मों में वृद्धि
 - iv. श्रम कि गतिशीलता में वृद्धि
4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है
 - i. मांग की दशाओं में अंतर, यदि पूर्ति की दशाएँ समान है
 - ii. पूर्ति की दशाओं में अंतर यदि मांग की दशाएँ समान है
 - iii. मांग तथा पूर्ति दोनों दशाओं में अन्तर
 - iv. उपरोक्त सभी
5. यदि दो देशों में मांग तथा पूर्ति दोनों दशाएँ समान हैं तो
 - i. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को लाभ होगा
 - ii. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को लाभ नहीं होगा
 - iii. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक देश को लाभ होगा
6. माँग दशाओं में अंतर निर्भर करता है
 - i. आय के स्तरों तथा रुचि पर
 - ii. साधन-सम्पन्नता तथा उत्पादन-दक्षता पर
 - iii. उत्पादन में प्रस्तुत तकनीकी का स्तर
 - iv. उपरोक्त सभी
7. पूर्ति दशाओं में अंतर निर्भर करता है
 - i. श्रम की योग्यता पर
 - ii. साधन-सम्पन्नता तथा उत्पादन-दक्षता पर
 - iii. उत्पादन में प्रस्तुत तकनीकी का स्तर
 - iv. उपरोक्त सभी
8. प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों की अगतिशीलता से तात्पर्य था
 - i. स्थान अगतिशीलता
 - ii. व्यवसाय अगतिशीलता
 - iii. दोनों
9. प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों की गतिशीलता से तात्पर्य था
 - i. स्थान अगतिशीलता
 - ii. व्यवसाय अगतिशीलता
 - iii. दोनों

निम्नलिखित कथनों में सत्य व असत्य चुनिए :

1. ओहलिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतरक्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा है
2. हेक्सर, के अनुसार संसाधन घरेलू स्तर पर पूरी तरह गतिशील तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगतिशील होते हैं।
3. प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतरक्षेत्रीय व्यापार में मूलभूत अंतर नहीं है।
4. गॉटफ्राइड वॉन हैबरलर (Gottfried Von Haberler) के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतरक्षेत्रीय व्यापार के बीच अंतर स्थापित करना न तो संभव है और न ही इसकी आवश्यकता है।
5. एक देश के नागरिकों के मध्य वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय आन्तरिक व्यापार तथा एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ विनिमय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है।

1.8 सारांश

जिस प्रकार व्यक्तियों के बीच श्रम-विभाजन होता है उसी तरह विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण हो सकता है। एक राष्ट्र उस वस्तु या सेवा के उत्पादन में विशिष्टता हासिल करता है जिसमें कि वह अन्य देशों की अपेक्षा उत्पादन में श्रेष्ठ होता है। विनिमय की प्रक्रिया में व्यक्ति या उपभोक्ता जिस प्रकार अपनी संतुष्टि या विनिमय से लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से कम कीमत पर वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद करके लाभ प्राप्त करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं, सेवाओं तथा संसाधनों के जरिये विश्व के विभिन्न देशों को आपस में जोड़ता है। आर्थिक समृद्धि मुख्यतया श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण पर निर्भर करता है जबकि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण बाज़ार के आकार पर निर्भर करता है; बाज़ार का आकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से बढ़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विशिष्टीकरण और भौगोलिक श्रम विभाजन के द्वारा विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन सुनिश्चित करता है।

वस्तुतः वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय से प्राप्त होने वाला लाभ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है यदि कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा। और व्यापार से लाभ का तात्कालिक कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में विद्यमान अंतर है जो कि पूर्ति तथा माँग की दशाओं में अन्तर के कारण उत्पन्न होता है।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतरक्षेत्रीय व्यापार में मूलभूत अंतर है क्योंकि अंतरक्षेत्रीय स्तर पर संसाधनों में पूर्ण गतिशीलता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शून्य गतिशीलता पायी जाती है। आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे हेक्सर, ओहलिन इत्यादि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंतरक्षेत्रीय व्यापार की ही एक विशेष स्थिति मानते हैं। ओहलिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू व्यापार के लक्षणों में अंतर मात्रात्मक है या केवल अंश (डिग्री) का अंतर है, यह अंतर मूलभूत गुणात्मक प्रकृति का नहीं है जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धांत के औचित्य को स्वीकार किया जाता है।

1.9 शब्दावली

- **व्यापार** - व्यापार का अर्थ है वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय या क्रय-विक्रय।
- **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** - एक राष्ट्र द्वारा अपनी सीमाओं से बाहर शेष विश्व के साथ होने वाले समस्त प्रकार के लेन - देन या व्यापार को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अर्थात् दो राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापार को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं।

- **अंतरक्षेत्रीय या आंतरिक व्यापार** - एक राष्ट्र की सीमाओं के भीतर होने वाले समस्त प्रकार के लेन - देन या व्यापार को अंतरक्षेत्रीय, घरेलू या आंतरिक व्यापार कहते हैं।
- **श्रम विभाजन** - किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन की विभिन्न गतिविधियों तथा प्रक्रियाओं के संपादन में लगे श्रम का उन गतिविधियों तथा प्रक्रियाओं के आधार पर बंटवारा और उसमें विशिष्टीकरण प्राप्त करना ही श्रम विभाजन है। इस प्रकार श्रम विभाजन उत्पादन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत कार्य विशेष को कई प्रक्रियाओं तथा उप प्रक्रियाओं में बाँट दिया जाता है और प्रत्येक प्रक्रिया तथा उप प्रक्रिया को विभिन्न व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों द्वारा पूरा किया जाता है।
- **विशिष्टीकरण** - उत्पादन गतिविधि को कम समय में अधिक गुणवत्ता के साथ करने की क्षमता, जो की श्रम विभाजन से प्राप्त होती है। श्रम विभाजन जितना ही जटिल होगा विशिष्टीकरण उतना ही अधिक होगा। वस्तुतः विशिष्टीकरण अधिक विस्तृत अवधारणा है जिसका प्रयोग किसी निकाय या क्षेत्र या फर्म में उत्पादन दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न उत्पादन गतिविधियों तथा प्रक्रियाओं के विभाजन के सन्दर्भ में किया जाता है। श्रम विभाजन इसकी एक किस्म है। विशिष्टीकरण से किसी निकाय या क्षेत्र या फर्म या व्यक्ति को यह मौका मिलता है की जिस कार्य में वह दक्ष है उसी में विशिष्टता हासिल करे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार देशों को विशिष्टीकरण का अवसर देता है।

1.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न:

1. i 2.1 , 3.iv 4. iv, 5.ii , 6.i , 7.iv 8. i 9.ii

निश्चित उत्तरीय प्रश्न:

1. कीमतों में अन्तर , 2.ओहलिन

सत्य व असत्य :

1. सत्य , 2.असत्य , 3.असत्य 4.सत्य , 5.सत्य

1.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

- HH. G. Mannur, International Economics, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Bo Sodersten, International Economics ,Macmillan, 1999
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: International Economics: Theory and Policy,
- Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- Charles P Kindleberger, International Economics, Richard D. Irwin Inc., Illinois, 1968
- Dominik Salvatore, International Economics, John Willy & Sons, Inc., 2008
- International Economics: Theory and Policy, Ronald Press, New York 1968.
- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006
- Robert M. Dunn, and John H. Mutti, International Economics, Rougledge, London.

- सुदामा सिंह एवं एम0सी0 वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफ़ोर्ड एंड आई0बी0एच0 पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम0एल0 झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010।
- ज्ञानेंद्र सिंह कुशवाहा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1979।

1.12 उपयोगी/सहायक पाठ्य सामग्री

- HH. G. Mannur, International Economics, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Bo Sodersten, International Economics, Macmillan, 1999
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: International Economics: Theory and Policy, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- Charles P Kindleberger, International Economics, Richard D. Irwin Inc., Illinois, 1968 5. Dominik Salvatore, International Economics, John Willy & Sons, Inc., 2008
- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006
- एस. एन. लाल, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहबाद, 2004
- एच. एस. अग्रवाल, तथा सी. एस. बरला, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2003।
- सुदामा सिंह एवं एम0सी0 वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफ़ोर्ड एंड आई0बी0एच0 पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम0एल0झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010।
- डॉ. जी. सी. सिंघई एवं डॉ. जे. पी. मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा, 2010

1.13 निबन्धात्मक प्रश्न:

1. व्यापार क्यों होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है? विस्तार से समझाइये।
2. "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतरस्थानीय व्यापार की ही एक विशेष स्थिति है।" इस कथन की समीक्षा कीजिए।
3. अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतरक्षेत्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए।
4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य कारण क्या है? क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत का होना आवश्यक है?

इकाई 2- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विश्लेषणात्मक तकनीक (Analytical Technique of International Economics)

- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 उद्देश्य
- 2.3 उत्पादन संभावना वक्र
 - 2.3.1 समान प्रतिफल का नियम या स्थिर अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र
 - 2.3.2 घटते हुए प्रतिफल का नियम या बढ़ती अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र
 - 2.3.3 वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल या घटती अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र
 - 2.3.4 उत्पादक का संतुलन
- 2.4 समोत्पाद वक्र
 - 2.4.1 रेखीय समोत्पाद वक्र
 - 2.4.2 उन्नतोदर समोत्पाद वक्र
 - 2.4.3 प्रतिस्थापन की सीमान्त दर (MRTS)
 - 2.4.4 साधन गहनता
 - 2.4.5 उत्पादक का संतुलन
- 2.5 बाक्स - चित्र
- 2.6 समुदाय अनधिमान वक्र
- 2.7 प्रस्ताव वक्र
- 2.8 अभ्यास हेतु प्रश्न
- 2.9 सारांश
- 2.10 शब्दावली
- 2.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 2.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 2.13 उपयोगी/ सहायक पाठ्य सामग्री
- 2.14 निबंधात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई में अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के कुछ विश्लेषणात्मक यंत्रों के बारे में बताया गया है। जिसका अर्थशास्त्रीयों ने विभिन्न सिद्धान्तों में उपयोग किया है। अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र कि बुनियादी अवधारणाएं एवम विश्लेषणात्मक यंत्र वही हैं। जिसका अध्ययन आप अर्थशास्त्र के व्यष्टि तथा समष्टि सिद्धान्तों के अंतर्गत कर चुके हैं। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विश्लेषणात्मक यंत्रों के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

2.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप

- ✓ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मांग पक्ष व पूर्ति पक्ष के विश्लेषणात्मक यंत्रों को समझ सकेंगे।
- ✓ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विश्लेषण में उत्पादन संभावना वक्र, समोत्पाद वक्र और समुदाय अनधिमान वक्र के प्रयोग के बारे में जान सकेंगे।
- ✓ बाक्स - चित्र और प्रस्ताव वक्र जैसे प्रयुक्त महत्वपूर्ण यंत्रों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विश्लेषण में प्रयोग तथा उपयोगिता के बारे में जान सकेंगे।

2.3 उत्पादन संभावना वक्र

किसी देश द्वारा प्रत्येक वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जायगा यह उसे संसाधनों की उपलब्धता तथा उसकी तकनीकी के ज्ञान पर निर्भर करता है। **संसाधन सम्पन्नता** का अर्थ है देश के पास उपलब्ध कुल संसाधनों की मात्रा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों या **रिकाडों** के संदर्भ में बात करें तो प्रत्येक देश कितना उत्पादन करेगा यह उसकी श्रम की कुल मात्रा पर निर्भर करेगा, यदि उत्पादन तकनीकी दी हुई है।

अन्य शब्दों में, उत्पादन संभावना वक्र यह बताता है कि कोई देश उपलब्ध प्रौद्योगिकी से अपने उत्पादन के संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करके दो वस्तुओं के किन वैकल्पिक संयोगों का उत्पादन कर सकता है। स्पष्ट है कि वक्र के सभी बिन्दुओं पर देश के समस्त संसाधन पूर्ण रोजगार में होंगे।

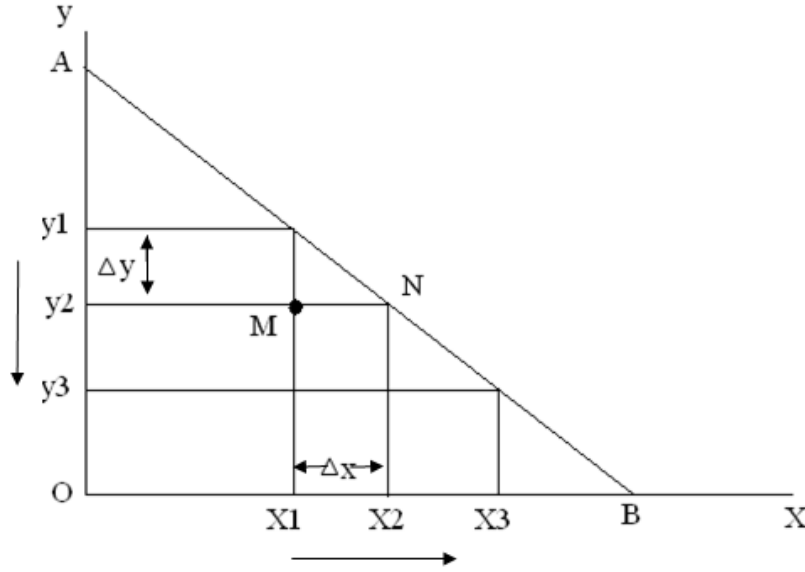
2.3.1 समान प्रतिफल का नियम या स्थिर अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र

उत्पादन संभावना वक्र या प्रतिस्थापन वक्र या रूपान्तरण वक्र अवसर लागत पर आधारित है। वस्तु X की अवसर लागत, वस्तु Y की वह मात्रा है जो कि वस्तु X की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ी जाती है। उदाहरणार्थ, यदि 5 इकाई X के उत्पादन के लिए 10 इकाई Y का त्याग करना पड़े तो 1X की अवसर लागत 2Y होगी ($5X=10Y$) अर्थात् X और Y का विनिमय अनुपात होगा $1X=2Y$ उत्पादन संभावना वक्र की ढाल एक वस्तु की उस मात्रा को बताती है जो एक देश को किसी दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाई पाने के लिए छोड़नी पड़ती है।

इसका आकार मुख्यतः उत्पादन के पैमाने के प्रतिफल पर निर्भर करता है। यदि उत्पादन में समान प्रतिफल का नियम क्रियाशील होता है या स्थिर अवसर लागत है तो उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा होगा। जैसा कि चित्र-2.1 में प्रदर्शित है।

इस स्थिति में, वस्तु X तथा Y की सीमान्त प्रतिस्थापन दर ($\Delta Y/\Delta X$) उत्पादन संभावना वक्र AB पर सदैव स्थिर रहेगी। अर्थात् अवसर लागत उत्पादन परिवर्तन के साथ स्थिर रहेगी। उत्पादन संभावना वक्र के सीधी

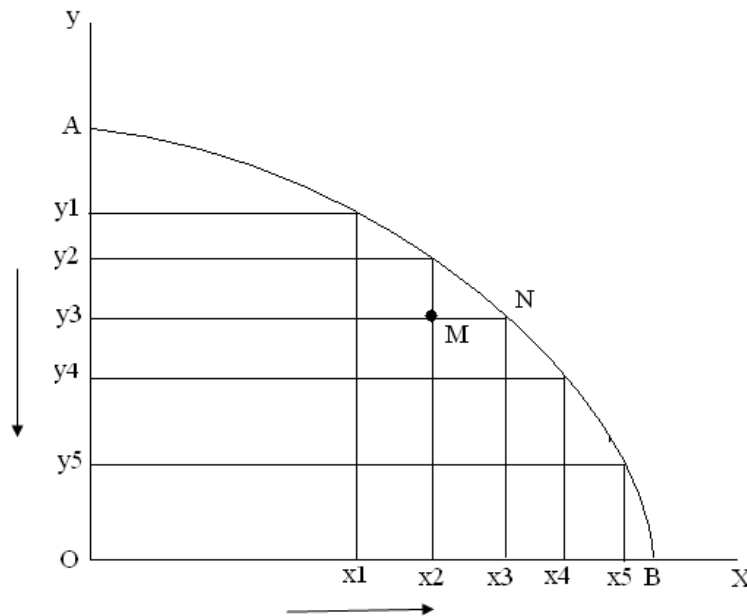
रेखा या स्थिर अवसर लागत का अर्थ है उत्पादन के सभी संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से दक्ष है। परन्तु यह एक वास्तविक मान्यता नहीं है।



चित्र-2.1

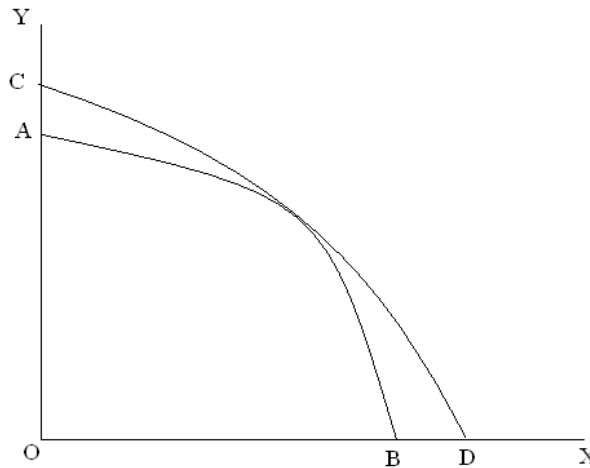
2.3.2 घटते हुए प्रतिफल का नियम या बढ़ती अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र

यदि उत्पादन में लागत वृद्धि नियम या घटते हुए प्रतिफल का नियम लागू हो तो वस्तु X और Y की सीमान्त प्रतिस्थापन दर ($\Delta Y/\Delta X$) क्रमशः बढ़ती जाएगी उत्पादन संभावना का आकार मूल बिन्दु के प्रति अवतल या नतोदर होगा जैसा कि चित्र-2.2 से स्पष्ट है। वस्तु X की प्रत्येक अगली इकाई के लिए वस्तु Y की उत्तरोत्तर अधिक इकाईयाँ त्याग करनी पड़ रही है। अर्थात् वस्तु X की, वस्तु Y के पदों में, अवसर लागत लगातार बढ़ रही है, जैसे-जैसे हम वस्तु X का उत्पादन बढ़ाते हैं तथा Y का उत्पादन कम करते हैं।



चित्र-2.2

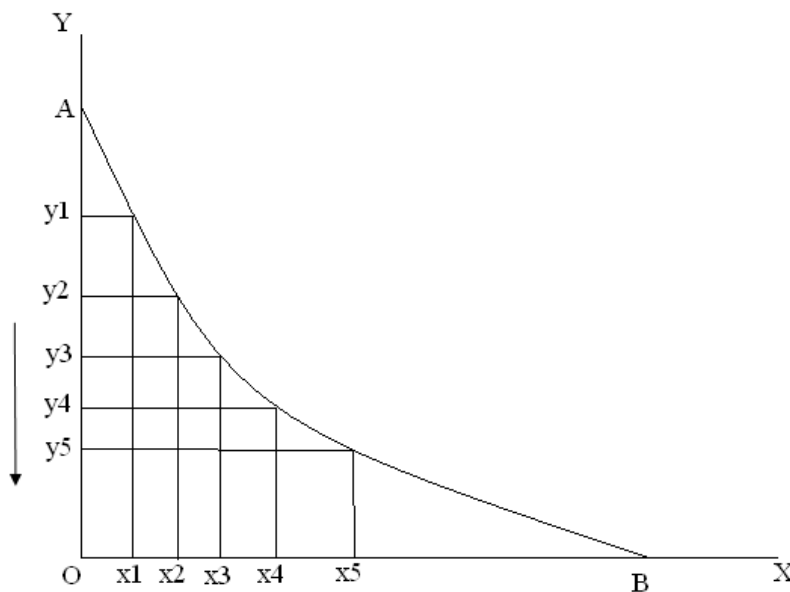
इस स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र का आकार या इसकी अवतलता (वक्रता) उत्पादन की स्थितियों पर निर्भर करेगी – कि उत्पादन के साधन आसानी से एक उद्योग से दूसरे वस्तु उद्योग में आ जा सकते हैं। अल्पकाल में, हम यह मान सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की ग्राह्यता कम होगी और दी हुई स्थिति से एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने पर उनकी अवसर लागत में तीव्र वृद्धि होगी। जबकि दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था की ग्राह्यता अधिक होने की संभावना होनी है जिससे एक वस्तु की अवसर लागत कम होगी। जैसा कि चित्र-2.3 में दिखाया गया है। AB अल्पकाल में तथा CD दीर्घकाल में उत्पादन संभावना वक्र के आकार प्रदर्शित करता है।



चित्र-2.3

2.3.3 वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल या घटती अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र

यदि उत्पादन में लागत हास नियम या वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल लागू होता है तो उत्पादन संभावना वक्र मूलबिन्दु के प्रति उन्नतोदर होगा। इस स्थिति में सीमान्त प्रतिस्थापन की दर ($\Delta Y / \Delta X$) क्रमशः घटती जाएगी। जैसा कि चित्र 2.3 में प्रदर्शित है। वस्तु- X की प्रत्येक अगली इकाई के लिए वस्तु- Y की उत्तरोत्तर कम इकाईयाँ त्याग करनी पड़ रही है। अर्थात् वस्तु X की, Y के पदों में, अवसर लागत लगातार कम हो रही है, जैसे- जैसे हम X का उत्पादन बढ़ाते हैं।

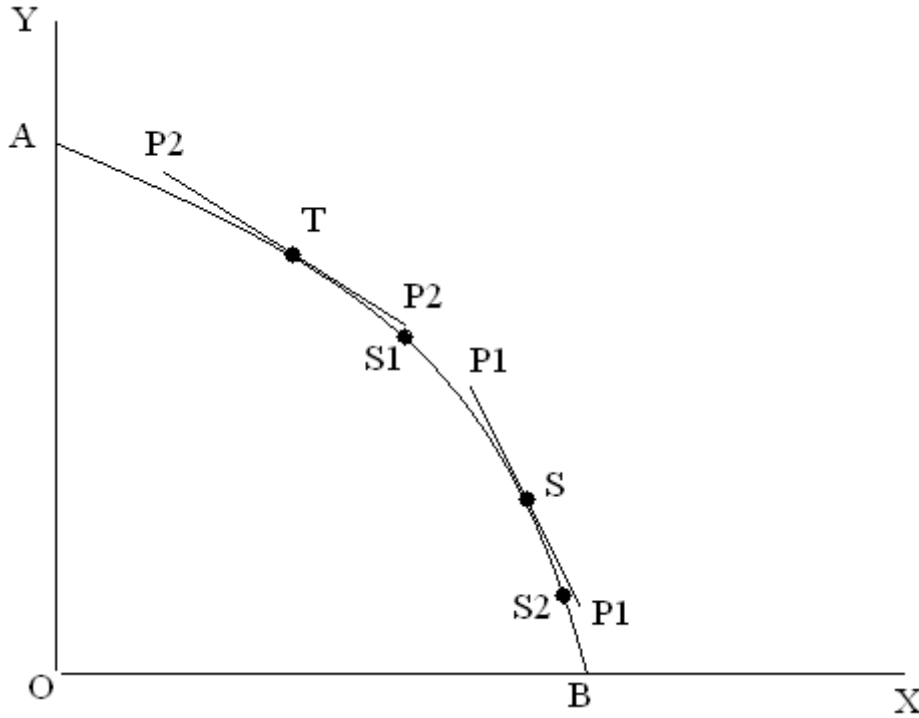


चित्र-2.4

एक बन्द अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न होने की स्थिति में, एक देश अपने उत्पादन संभावना वक्र के किसी बिन्दु पर उत्पादन करेगा। यदि वह उत्पादन संभावना वक्र (AB) के किसी भी बिन्दु पर उत्पादन कर रहा है ता इसका अर्थ है उसके समस्त संसाधन पूर्ण रोजगार में है। दिए हुए संसाधनों की स्थिति में स्पष्ट है कि वह अपने उत्पादन संभावना वक्र के किसी बाहर स्थित बिन्दु पर उत्पादन नहीं कर सकता है। वह AB वक्र के अंदर के किसी बिन्दु पर उत्पादन कर सकता है जैसे चित्र-2.1 तथा चित्र-2.2 में बिन्दु M पर। परन्तु यह अनुकूलतम या दक्ष बिन्दु नहीं है क्योंकि वह वस्तु Y की उतनी मात्रा के साथ X की अधिक मात्रा का उत्पादन कर सकता है इसलिए उत्पादक M की अपेक्षा N पर उत्पादन करेगा। AB वक्र के अंदर के किसी बिन्दु पर, जैसे चित्र-2.1 तथा चित्र-2.2 में बिन्दु M पर, समस्त संसाधन पूर्ण रोजगार में नहीं हैं।

2.3.4 उत्पादक का संतुलन

परिवर्तनशील अवसर लागतों की स्थिति में वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों की विशेष भूमिका होती है। कीमतों के परिवर्तन की स्थिति में उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादन को पुनः समायोजित करते हैं; जैसा कि चित्र-2.5 में स्पष्ट है।



चित्र-2.5

मान लिया एक अर्थव्यवस्था में किसी समय घेरलू सापेक्षिक कीमत रेखा P1P1 है। इस स्थिति में उत्पादक S बिन्दु पर संतुलन में होंगे जहाँ कीमत रेखा P1P1 की ढाल उत्पादन संभावना वक्र बिन्दु की ढाल के बराबर है। यदि उत्पादक दी हुई कीमतों की स्थिति में S1 बिन्दु पर उत्पादन करेगा तो वस्तु X की लागत उसकी कीमत से कम होगी और वह उत्पादन बढ़ाकर अपने लाभ अधिकतम कर सकता है। जबकि S2 बिन्दु पर वस्तु X की उत्पादन लागत उसकी कीमत से ज्यादा होगी। सिर्फ S बिन्दु पर सापेक्षिक कीमतें, अवसर लागत के बराबर है और लाभ अधिकतम है।

यदि कीमतें परिवर्तित होकर P1P1 हो जाय तो इसका अर्थ है वस्तु-Y की कीमत X के सापेक्ष बढ़ गयी। ऐसी स्थिति में उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए संसाधनों का पुनः आवंटन करेंगे और नए अनुकूलतम बिन्दु T पर उत्पादन करेंगे, जहाँ कीमत, अवसर लागत के बराबर है।

2.4 समोत्पाद वक्र

उत्पादन फलन उत्पादन तथा उत्पादन के साधन आगतों के बीच तकनीकी संबंधों को दर्शाता है। उत्पादन फलन एक उद्योग फर्म की तकनीकी को बताता है। उत्पादन फलन में तकनीकी रूप से सभी विधियाँ सम्मिलित होती हैं। यदि सिर्फ दो साधन श्रम (L) तथा पूँजी (K) हो तो उत्पादन-फलन को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है

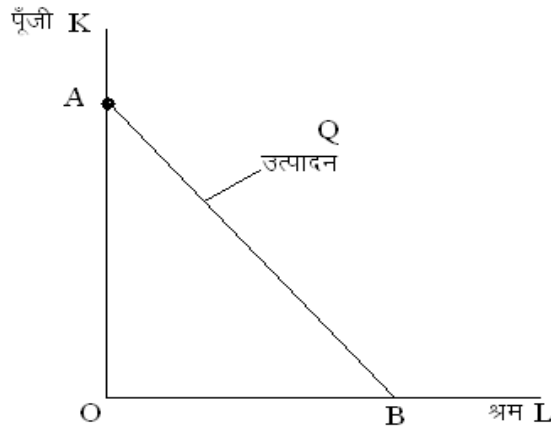
$$Q = f(L, K)$$

जहाँ Q उत्पादन है।

एक समोत्पाद वक्र, उत्पादन के साधनों के सभी संयोगो अर्थात् तकनीकी रूप से दक्ष सभी विधियों को दर्शाता है जिससे कि उत्पादन का एक समान स्तर प्राप्त होता है। समोत्पाद वक्र का आकार साधनों की स्थानापन्नता के अंश पर निर्भर करता है। समोत्पाद वक्र का ढाल उत्पादन के साधनों की स्थानापन्नता के अंश को बताता है।

2.4.1 रेखीय समोत्पाद वक्र

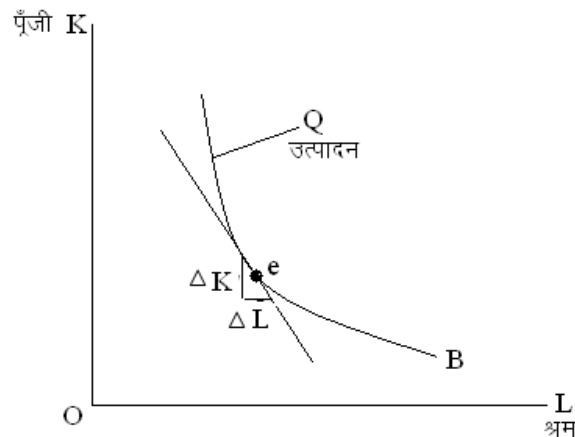
यदि दो साधनों श्रम (L) और पूँजी (K) के बीच पूर्ण स्थानापन्नता हो तो समोत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी जैसा कि चित्र-2.6 में है। इसे रेखीय समोत्पाद वक्र कहते हैं।



चित्र-2.6

2.4.2 उन्नतोदर समोत्पाद वक्र

यदि उत्पादन के साधनों (श्रम और पूँजी) के बीच एक निश्चित सीमा के भीतर सतत् स्थानापन्नता हो तो समोत्पाद वक्र मूलबिन्दु के प्रति उतल होगा जैसा कि चित्र-2.7 में है।



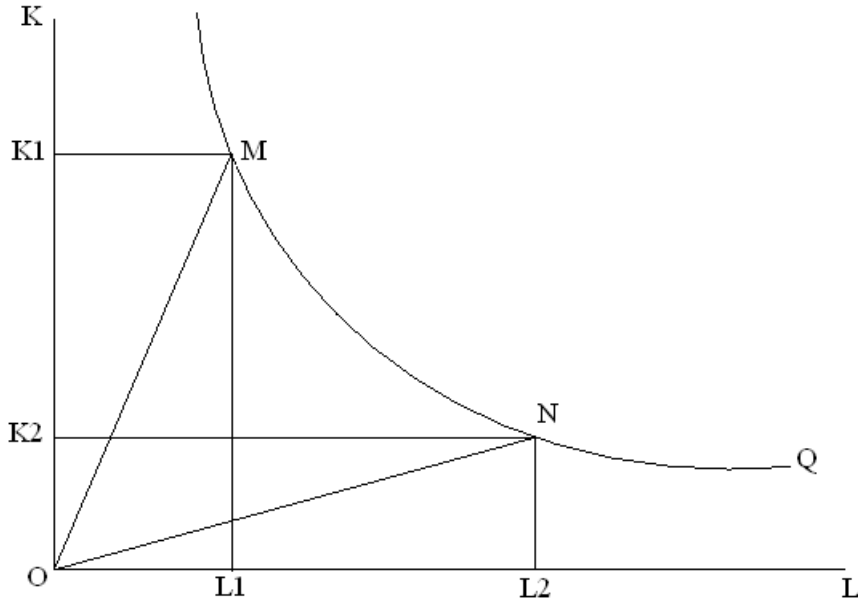
2.4.3 प्रतिस्थापन की सीमान्त दर (MRTS)

समोत्पाद वक्र के ढाल को तकनीकी प्रतिस्थापन की दर या प्रतिस्थापन की सीमान्त दर (MRTS) कहा जाता है। समोत्पाद वक्र पर हम जैसे-जैसे नीचे की ओर आते हैं समोत्पाद वक्र का ढाल कम होता जाता है जोकि K तथा L के बीच प्रतिस्थापन की बढ़ती अठिनाइयों के बताता है। संकेतात्मक रूप से

$$MRTS_{L,K} = -\frac{\Delta K}{\Delta L}$$

2.4.4 साधन गहनता

मूल बिन्दु से समोत्पाद वक्र पर खींची गयी रेखा का ढाल किसी उत्पादन विधि की साधन गहनता को बताती है। इस प्रकार साधन गहनता पूँजी श्रम अनुपात है।



चित्र 2.8

चित्र 2.8 में OM उत्पादन प्रविधि अत्यधिक पूँजी प्रधान तथा ON उत्पादन प्रविधि अत्यधिक श्रम प्रधान है। समोत्पाद वक्र का ऊपर का भाग अत्यधिक पूँजी प्रधान प्रविधियों को तथा नीचे का भाग अधिक श्रम प्रधान प्रविधियों को सम्मिलित करता है।

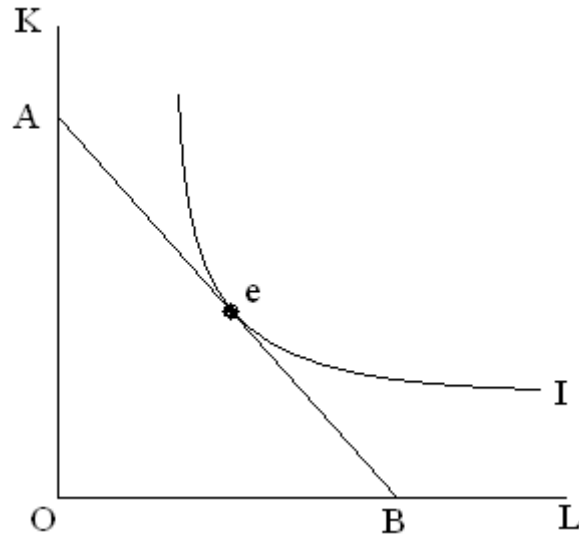
2.4.5 उत्पादक का संतुलन

उत्पादन की दी हुई मात्रा, अर्थात् समोत्पाद वक्र के दिए होने पर, उत्पादन के लिए कुशलतम साधन संयोग (अर्थात् उत्पादक का संतुलन) वहाँ होगा जहाँ साधन कीमत रेखा या सम लागत रेखा समोत्पाद वक्र को स्पर्श करती है। चित्र-2.9 में e बिन्दु पर उत्पादक संतुलन में होगा जहाँ उसका लाभ अधिकतम होगा। बिन्दु e पर साधन कीमत रेखा AB का ढाल (P_L/P_K) समोत्पाद वक्र के ढाल ($\Delta K/\Delta L$) के बराबर है।

$$\frac{P_L}{P_K} = \frac{\Delta K}{\Delta L} = MRTS_{LK}$$

P_L = श्रम की कीमत

P_K = पूँजी की कीमत



चित्र-2.9

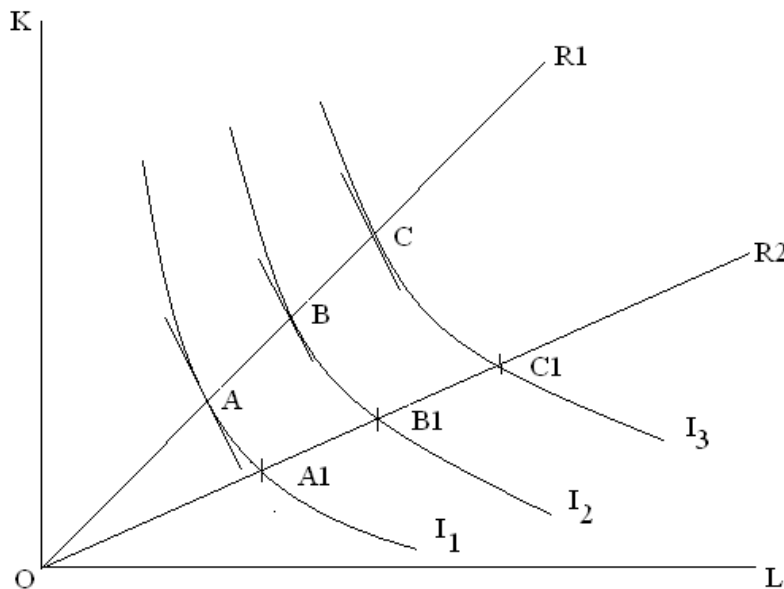
2.4.6 रेखिक समरूप समोत्पाद वक्र

यदि सभी आगतों को एक निश्चित अनुपात k से बढ़ाया जाय और उत्पादन में भी यदि उसी अनुपात, K , के बराबर वृद्धि होती है, तो उत्पादन फलन रेखिक समरूप होगा।

गणितीय रूप में

$$kQ=f(kL,kK)$$

यदि उत्पादन में पैमाने का स्थिर प्रतिफल क्रियाशील होता है अर्थात् यदि रेखीय समरूप उत्पादन फलन हो तो, जैसे-जैसे दो साधनों को एक ही अनुपात में लगाया जाता है तो दोनों साधनों की सीमान्त उत्पादकताएँ अपरिवर्तित रहती हैं। दूसरे शब्दों में श्रम तथा पूँजी की सीमान्त उत्पादकता इस पर निर्भर करेगी कि श्रम-पूँजी अनुपात क्या है। चित्र 2. 10 में मूल बिन्दु से खींची गयी रेखा OR_1 एक निश्चित पूँजी-श्रम अनुपात को व्यक्त करती है। अर्थात् बिन्दु A , B तथा C तीनों पर पूँजी तथा श्रम का एक ही अनुपात में संयोग है। अतः तीनों ही बिन्दुओं पर श्रम तथा पूँजी की सीमान्त उत्पादकता एक समान है।



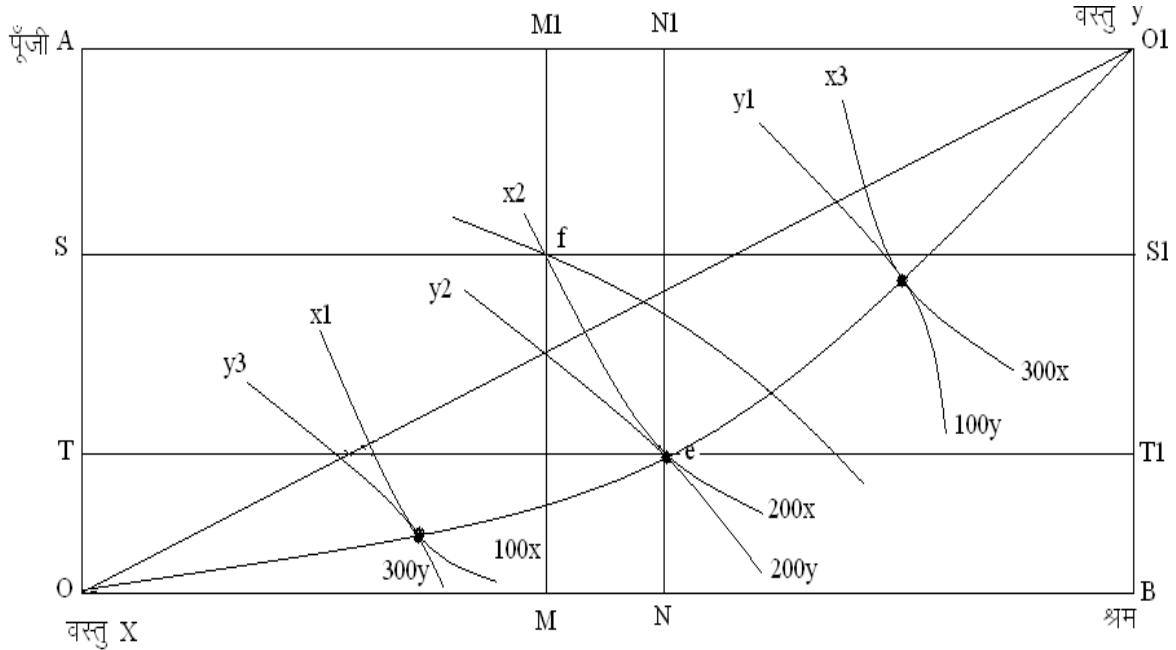
चित्र-2.10

इसी प्रकार OR, के साथ A1, B1 तथा C1 बिन्दुओं पर श्रम की सीमान्त उत्पादकता समान है उसी प्रकार इन सभी बिन्दुओं पर पूँजी की सीमान्त उत्पादकता भी समान है। अतः 0 से खींची गयी रेखा OR1 तथा OR2 के साथ उत्पादन के दो साधन की सीमान्त उत्पादकता समान है।

2.5 बाक्स चित्र

बाक्स या संदूक चित्र की सहायता से उत्पादन फलनों तथा उत्पादन के साधन की कुल मात्रा के बीच अंतर्संबंध का अध्ययन किया जाता है। इससे दो वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त आगतों के कुशलतम संयोगो को भी प्रदर्शित किया जाता है। बाक्स या संदूक चित्र का प्रयोग सर्वप्रथम एजवर्थ ने किया इसलिए इसे एजवर्थ संदूक चित्र भी कहा जाता

चित्र 2.11 में बाक्स चित्र को दिखाया गया है। क्षैतिज अक्ष पर श्रम तथा उर्ध्व अक्ष पर पूँजी की मात्रा ली गयी है। बाक्स चित्र देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों की मात्रा को बताता है। OA अर्थव्यवस्था में उपलब्ध समस्त पूँजी तथा OB कुल श्रम की मात्रा को मापता है। विकर्ण OO1 अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण साधन गहनता को बताता है।



चित्र 2.11

माना दो वस्तुओं X और Y का उत्पादन हो रहा है। X वस्तु के उत्पादन को मूल बिन्दु 0 से तथा Y वस्तु के उत्पादन को मूल बिन्दु 0 से मापते है। इस प्रकार O मूल बिन्दु से X के समोत्पाद वक्रों के समूह को तथा O1 से Y के समोत्पाद वक्रों के समूह को खींचा जा सकता है।

समोत्पाद वक्रों को रेखीय समरूप उत्पादन फलन के अनुरूप खींचा गया है अर्थात् समोत्पाद वक्र X1 की अपेक्षा X2 दुगुनी तथा X3 तिगुनी मात्रा को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार समोत्पाद वक्र Y1 की अपेक्षा Y2 दुगुनी तथा Y3 तिगुनी मात्रा को प्रदर्शित करता है।

बाक्स के अंदर कोई भी बिन्दु दोनों वस्तुओं X तथा Y के एक निश्चित संयोग को व्यक्त करता है। साथ ही यह भी बताता है कि इन वस्तुओं के उत्पादन में साधनों का संयोग क्या है। बिन्दु e पर 200X तथा 200Y का

उत्पादन हो रहा है। 200X के उत्पादन के लिए OM श्रम तथा OT पूँजी और 200Y के उत्पादन के लिए बचे हुए श्रम O1N1 तथा बची हुई पूँजी O1T1 का इस्तेमाल हो रहा है। बिन्दु e पर X वस्तु का समोत्पाद वक्र तथा Y वस्तु का समोत्पाद वक्र स्पर्श कर रहा है। यह उत्पादन के अनुकूलतम दक्ष साधन संयोग को बताता है। इन दोनों ही उत्पादन स्थितियों में सीमान्त उत्पादन स्थिति में सीमान्त उत्पादकताओं के अनुपात समान हैं। अतः दोनों वस्तुओं के उत्पादन में, उत्पादन के साधनों की सापेक्षिक दक्षता समान है तथा संसाधनों का आवंटन अनुकूलतम है।

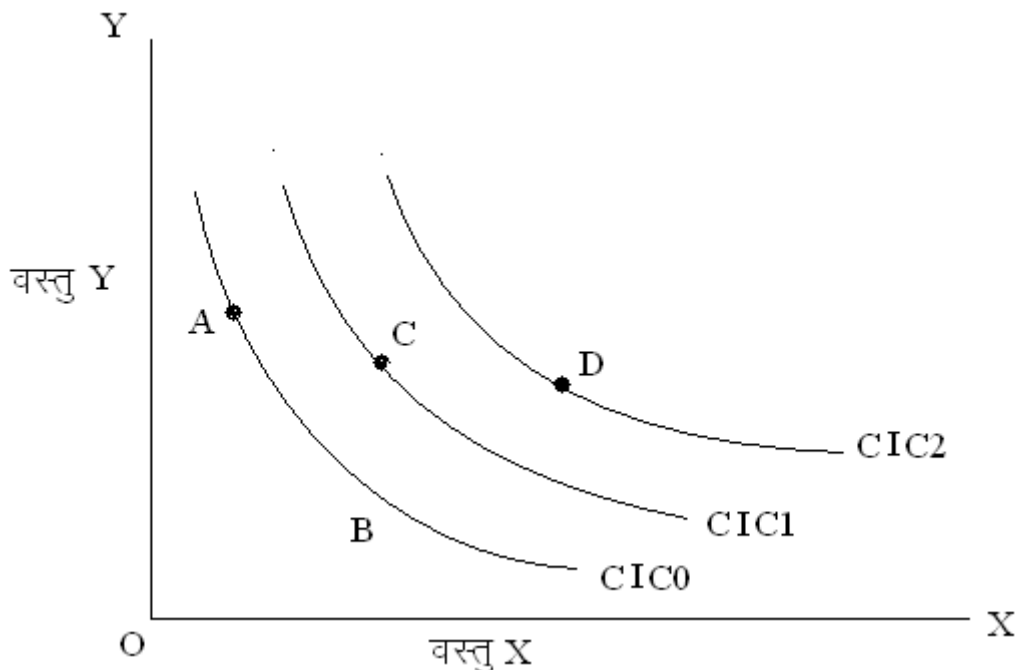
यदि हम बाक्स में दो समोत्पादक वक्रों के सभी स्पर्श बिन्दुओं को मिलाएँ तो हमें एक वक्र OO1 प्राप्त होगा, जिसे 'आकुंचित वक्र' (Contract Curve) कहते हैं। इस वक्र पर स्थित सभी बिन्दु दक्ष बिन्दु हैं जो कि उत्पादन तथा साधनों के दक्ष संयोगों को प्रदर्शित करते हैं। OO1 वक्र से इतर कोई भी बिन्दु उससे कम दक्ष होगा और अनुकूलतम संयोग को प्रदर्शित नहीं करेगा। जैसे बिन्दु f दक्ष बिन्दु नहीं है क्योंकि X वस्तु की उसी (X2 समोत्पाद वक्र पर) मात्रा के साथ Y वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त की जा सकती है यदि उत्पादन बिन्दु e पर हो।

आकुंचित वक्र की व्युत्पत्ति सिर्फ उत्पादन की तकनीकी दशाओं के आधार पर की जाती है। वक्र OO1 पर कौन सा बिन्दु अन्य की उपेक्षा बेहतर होगा यह माँग दशाओं पर निर्भर करेगा।

2.6 समुदाय अधिमान वक्र

यदि हम किसी एक उपभोक्ता के माँग को दिखाते हैं तो इसके लिए तटस्थता या अधिमान वक्र का प्रयोग करते हैं जो कि उपभोक्ता के माँग-कारकों को दर्शाता है। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हम पूरे समुदाय या राष्ट्र के माँग कारकों को दर्शाने के लिए समुदाय अधिमान वक्र का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से कुछ निश्चित मान्यताओं के अंतर्गत एक उपभोक्ता के लिए अधिमान वक्र खींचे जाते हैं उसी प्रकार पूरे समुदाय या राष्ट्र के लिए खींचे जा सकते हैं। परन्तु समुदाय अधिमान वक्र के लिए और कठोर मान्यताओं का सहारा लेना पड़ेगा।

समुदाय अधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिससे समुदाय या राष्ट्र के उपभोक्ताओं को समान संतुष्टि मिलती है। यदि हम यह मान लें कि किसी देश में आय-वितरण में परिवर्तन नहीं होता है तो हम एक देश के समुदाय अधिमान मानचित्र को खींच सकते हैं।



चित्र 2.12

इन अधिमान वक्रों की विशेषताएँ वहीं हैं जो व्यक्ति अधिमान वक्रों की होती है। इनकी चार मुख्य विशेषताएँ हैं

1. ये बाएं से दायें नीचे की ओर झुके हुए होते हैं।
2. ये मूल-बिन्दु के प्रति उन्नतोदर (Convex) होते हैं।
3. आय-वितरण स्थिर होने की दशा में दो समुदाय अधिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते।
4. ऊपर स्थिर समुदाय अधिमान वक्र नीचे के वक्र की अपेक्षा संतुष्टि के उच्चतर स्तर को व्यक्त करता है।

चित्र 2.12 में CIC_0 , CIC_1 , CIC_2 समुदाय अधिमान वक्रों का मानचित्र दिखाया गया है। वक्र CIC_0 पर स्थित बिन्दु A तथा B के संयोग समान संतुष्टि के स्तर को व्यक्त कर रहे हैं। जबकि संयोग C, A तथा B की अपेक्षा और संयोग D संयोग C की अपेक्षा अधिक संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित करता है।

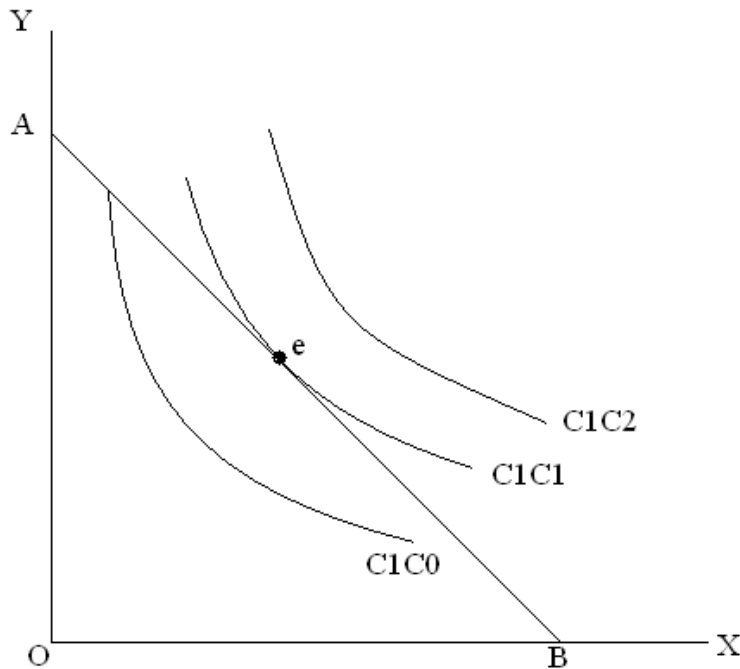
यदि विभिन्न समुदाय अधिमान वक्र अलग-अलग आय वितरण को प्रदर्शित करें तो वे एक दूसरे को काट सकते हैं परन्तु यदि एक राष्ट्र के सभी निवासियों की प्राथमिकताएँ तथा रुचियाँ एक जैसी मान ली जाएँ और सभी आय स्तरों पर आय वितरण का स्तर समान हो तो समुदाय अधिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटेंगे।

समुदाय अधिमान वक्र के किसी बिन्दु की ढाल उसकी सीमान्त प्रतिस्थापन दर को बताती है। वस्तु X की वस्तु Y के लिए प्रतिस्थापन की सीमान्त दर (MRS_{xy}) Y की वह मात्रा है जिसको वस्तु X की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता छोड़ने को तैयार है, जिससे उसकी संतुष्टि का स्तर समान बना रहे।

2.6.1 उपभोक्ता संतुलन

एक देश के समुदाय अधिमान मान चित्र के दिये हुए होने पर देश के उपभोक्ता का संतुलन वहाँ होगा अर्थात् उसे अधिकतम संतुष्टि वहाँ प्राप्त होगी जहाँ घरेलू कीमत रेखा किसी समुदाय अधिमान वक्र को स्पर्श करती है अर्थात् जहाँ समुदाय अधिमान वक्र का ढाल, घरेलू कीमत रेखा के ढाल के बराबर है।

चित्र 2.13 में, बिन्दु e पर, समुदाय अधिमान वक्र का ढाल $MRS_{xy}=PX =$ कीमत रेखा का ढाल अर्थात् बिन्दु e पर देश के उपभोक्ता संतुलन में है।



चित्र 2.13

वास्तव में समुदाय अधिमान वक्र की धारणा बहुत संतोषजनक नहीं है। किसी समुदाय या राष्ट्र के भीतर संतुष्टि की अन्तर वैयक्तिक तुलना काफी कठिन है। एक वस्तु की समान मात्रा के उपभोग से दो व्यक्तियों को अलग-अलग संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। यदि समाज में एक ही उपभोक्ता है तो व्यक्तिगत तथा समुदाय अधिमान वक्र में कोई अन्तर नहीं होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में समुदाय अधिमान वक्रों का प्रयोग व्यापार से पूर्व तथा व्यापार के पश्चात् राष्ट्र किस प्रकार संतुलन में आते हैं और उनके कल्याण में वृद्धि होती है, इसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है।

2.7 प्रस्ताव वक्र

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक यंत्र प्रस्ताव वक्र है, जिसके द्वारा हम यह दिखाते हैं कि यदि दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो किस प्रकार से माँग तथा पूर्ति की अंतर्क्रिया से साम्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त का निर्धारण होता है। इसकी सहायता से व्यापार से होने वाले लाभों को भी दिखाया जा सकता है।

प्रस्ताव वक्र की तकनीकी को एल्फ्रेड मार्शल तथा एजवर्थ से विकसित किया। प्रस्ताव वक्रों की खूबी यह है कि ये इस समस्या को हल करने में सफल रहे कि किस प्रकार व्यापार संतुलन की स्थिति में बिल्कुल सही व्यापार-शर्त का निर्धारण होगा।

एक देश का प्रस्ताव वक्र एक ओर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों (व्यापार-शर्त) पर आयातित वस्तु के बदले देश द्वारा निर्यात-वस्तु की प्रस्तावित मात्रा को व्यक्त करता है और दूसरी ओर यह विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर उस देश की विदेशी वस्तु (आयात) की माँग को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार प्रस्ताव वक्र में माँग और पूर्ति दोनों के ही तत्व विद्यमान होते हैं। इसलिए इसे प्रस्ताव वक्र के साथ-साथ प्रतिपूरक माँग वक्र भी कहा जाता है।

एक देश के प्रस्ताव वक्र को व्युत्पन्न करने के लिए विभिन्न व्यापार शर्तों पर उसके द्वारा आयातित वस्तु की मांगी गयी मात्रा और उसके बदले निर्यात की प्रस्तावित मात्रा जाननी होगी।

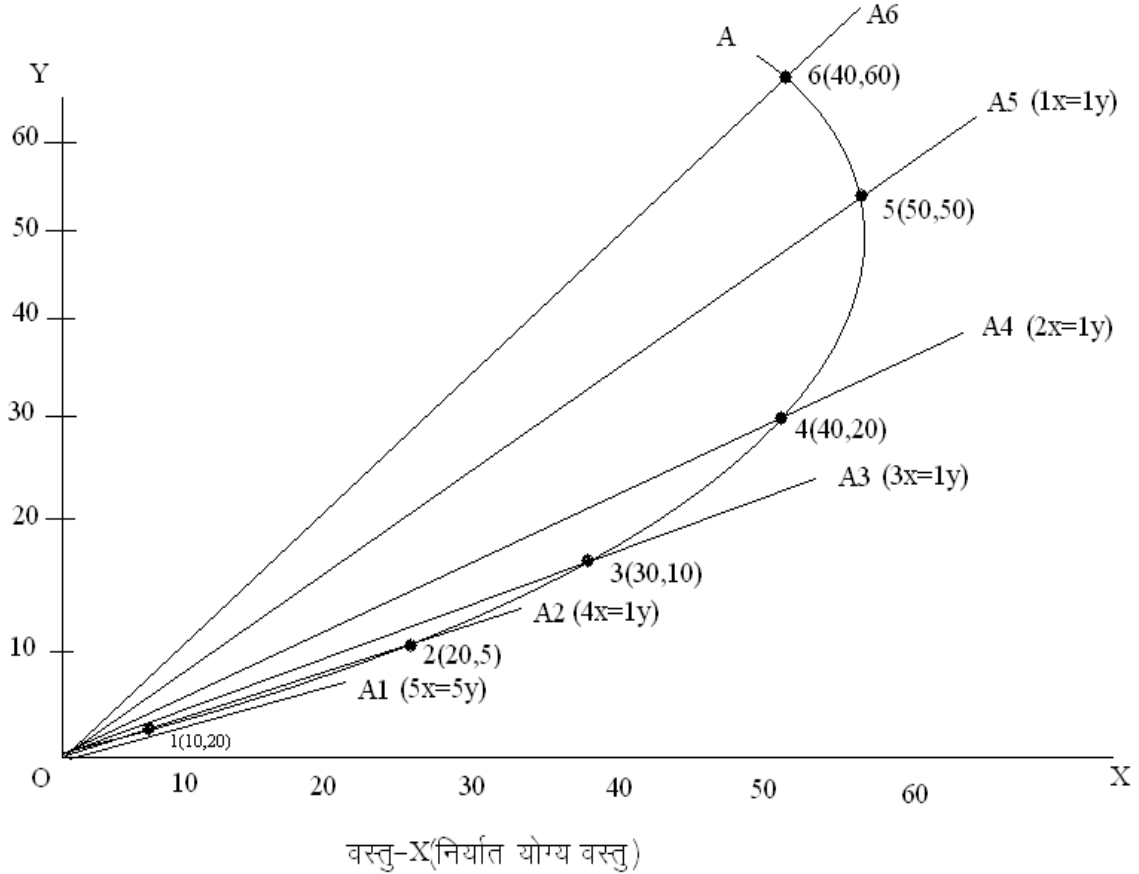
माना दो देश A और B हैं और दो वस्तुएँ X और Y हैं। देश को X वस्तु के उत्पादन में, और देश B को Y वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण हासिल हैं क्योंकि देश A को X वस्तु और देश B को Y वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष या तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। इस प्रकार देश A के लिए X निर्यातित वस्तु तथा Y आयातित वस्तु है और देश B के लिए Y निर्यातित वस्तु और X आयातित वस्तु है।

निम्नलिखित सारणी 2.1 में विभिन्न सापेक्षिक कीमत अनुपातों (व्यापार शर्तों) पर देश A द्वारा आयात की मांगी गयी मात्रा तथा उसके बदले निर्यात की प्रस्तावित मात्रा को दिखाया गया है।

सारणी 2.1: देश A की विभिन्न व्यापार शर्तों पर आयात व निर्यात की मात्राएँ

क्र०सं०	वस्तु-x (निर्यातित वस्तु)	वस्तु-y (आयातित वस्तु)	कीमत अनुपात (व्यापार शर्त)
1	10	2	5x : 1y
2	20	5	4 x : 1y
3	30	10	3 x : 1y
4	40	20	2 x : 1y
5	50	50	1 x : 1y
6	40	60	1 x : 1.5y

प्रारम्भिक स्थिति में, जबकि देश A के पास वस्तु-y की मात्रा नहीं है तो वह 2y के लिए 10x देने के लिए तैयार है यदि व्यापार के पूर्व 1y के बदले 5x घरेलू बाजार की सापेक्षिक कीमत है तो 1y के लिए 5x से अधिक कीमत होन पर देश A व्यापार नहीं करेगा। देश A घरेलू कीमत रेखा और अन्तर्राष्ट्रीय कीमत रेखा के समान होने की स्थिति में व्यापार के प्रति उदासीन होगा। यदि कीमत अनुपात $4x=1y$ हो तो देश A, 5 इकाई y वस्तु के बदले वस्तु x की 20 इकाई देने को तैयार है। जैसे-जैसे देश A के पास वस्तु y की मात्रा बढ़ती जा रही है वह वस्तु y के बदले वस्तु x की कम मात्रा देने को तैयार हो रहा है और वस्तु y की कीमत x के पदों में कम होती जा रही है।

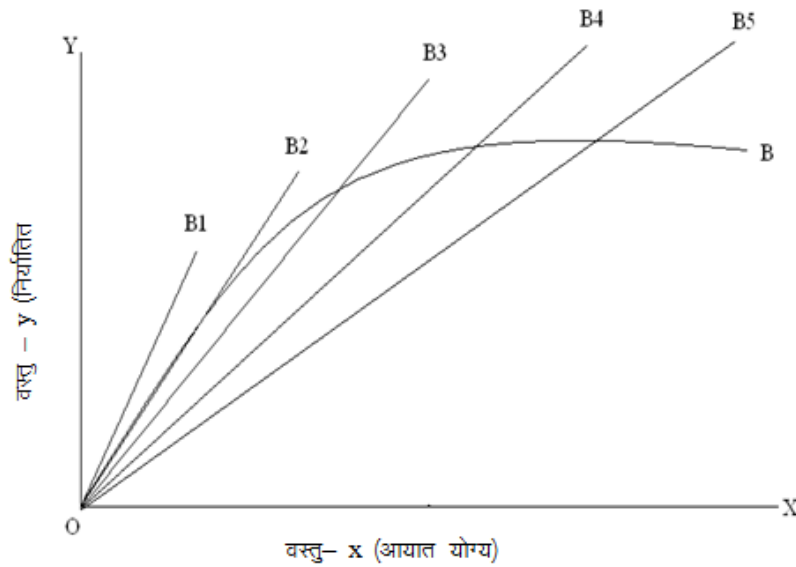


चित्र 2.14: देश-A का प्रस्ताव वक्र

यदि हम देश A के निर्यातों (वस्तु x) को x अक्ष पर तथा उसके आयातों (वस्तु y) को y अक्ष पर अर्थात् तो सारणी में दी गई व्यापार-शर्तों पर देश A के निर्यातों तथा आयातों की मात्राओं को दिखा सकते हैं। चित्र 2.14 में बिन्दु 1, 2, 3, 4 तथा 5 विभिन्न व्यापार शर्तों क्रमशः OA1, OA2, OA3, OA4 तथा OA5 पर देश A का देश से B व्यापार की प्रवृत्ति को दिखाते हैं। इस प्रकार प्रस्ताव वक्र यह दिखाते हैं कि व्यापार शर्त बदलने पर कैसे व्यापार की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है।

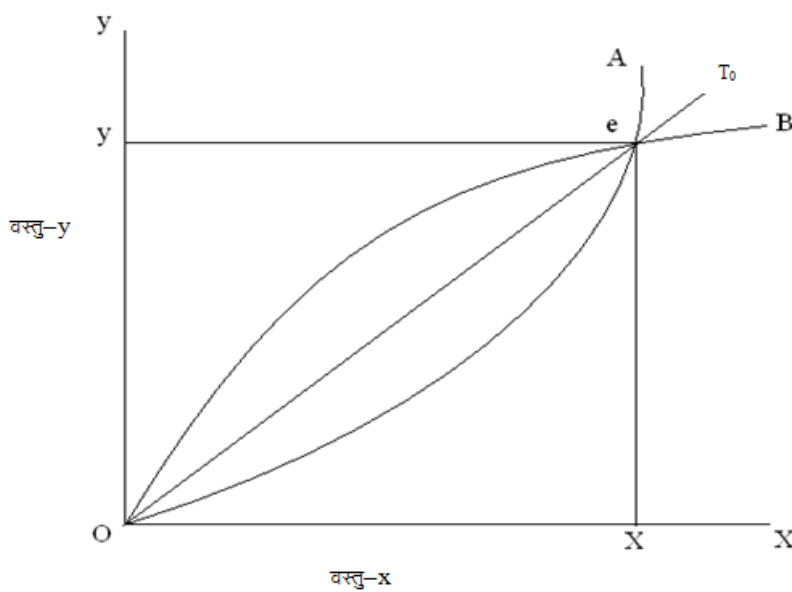
मूल बिन्दु से खींची गयी रेखा OA जो कि इन सभी बिन्दुओं को मिलाती है। देश-A का प्रस्ताव वक्र है। प्रस्ताव वक्र OA का ढाल बिन्दु 5 तक धनात्मक है और यह गैर-रेखिक है। बिन्दु 5 के बाद वस्तु-y की अधिक मात्रा के बदले देश A वस्तु-X की पहले से एक इकाई निर्यात करने को तैयार है। बिन्दु 6 पर 60 इकाई के y लिए वह वस्तु x की 40 बिन्दु 6 पर 60 इकाई 5 के लिए वह वस्तु x की 40 इकाई ही देने को तैयार है; अर्थात् बिन्दु 5 के बाद प्रस्ताव वक्र का ढाल ऋणात्मक है। यहाँ स्पष्ट है कि देश-A वस्तु x की 50 से अधिक इकाई का निर्यात

करना नहीं चाहता है। बिन्दु 6 पर व्यापार-शर्त देश A के और अधिक पक्ष में होगी और वह x वस्तु की पहले से कम मात्रा देकर अधिक y का आयात करेगा, परन्तु देश B के लिए यह व्यापार-शर्त स्वीकार्य नहीं होगी, वह बिन्दु 5 पर व्यापार करना चाहेगा। इस प्रकार प्रस्ताव वक्र का ऋणात्मक ढाल वाला हिस्सा संभाव्य व्यापार क्षेत्र को व्यक्त नहीं करेगा। अतः प्रस्ताव वक्र केवल धनात्मक ढाल वाला ही होगा। हम इसी प्रकार देश B का प्रस्ताव वक्र खींच सकते हैं।



चित्र 2.15: देश-B का प्रस्ताव वक्र

चित्र 2.15 में विभिन्न कीमत रेखाओं (व्यापार शर्तों) पर देश B के आयात तथा उसके बदले निर्यात की गयी मात्राओं के विभिन्न संयोगों का बिन्दु-पथ OB देश B का प्रस्ताव वक्र है। स्पष्ट है कि प्रस्ताव वक्र का संभाव्य व्यापार शर्तों से एक प्रकार संबंध है। संतुलित व्यापार-शर्त का निर्धारण वहाँ होगा जहाँ देश A तथा देश B के प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को काटते हैं।



चित्र 2.16

चित्र 2.16 में देश A का प्रस्ताव वक्र OA तथा देश B का प्रस्ताव वक्र OB एक दूसरे को e बिन्दु पर काट रहे हैं और संतुलित व्यापार-शर्त OT_0 है। OT_0 व्यापार-शर्त पर देश A का आयात OY, उसके निर्यात OX तथा देश B का निर्यात OY, उसके आयात OX के बराबर होगा। इस प्रकार संतुलन में दोनों देशों का आयात तथा निर्यात एक दूसरे के बराबर होगा।

प्रस्ताव वक्रों का आकार संबंधित देशों की पूर्ति तथा मांग दोनों दशाओं द्वारा निर्धारित होता है। प्रस्ताव वक्र दोनों देशों की घरेलू कीमत रेखाओं (व्यापार न होने की दशा में) की सीमा में ही रहते हैं। किसी देश की घरेलू कीमत रेखा को मूल बिन्दु से उसके प्रस्ताव वक्र की ढाल द्वारा दिखाया जाता है। चित्र में OA तथा OB क्रमशः देश A तथा B की घरेलू कीमत रेखा को प्रदर्शित कर रहा है।

प्रस्ताव वक्र सामान्य-संतुलन विश्लेषण से संबंधित एक संकल्पना है। यह उत्पादन तथा उपभोग द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित होता है। प्रस्ताव वक्र का प्रत्येक बिन्दु विभिन्न व्यापार-शर्तों पर एक देश के उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के संतुलन को व्यक्त करता है। उत्पादन तथा उपभोग की दशाएं ही प्रस्ताव वक्रों के आकार को निर्धारित करती हैं जो कि संतुलित व्यापार-शर्त का निर्धारण करते हैं।

2.8 अभ्यास हेतु प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न:

1. रैखिक समरूप समोत्पाद वक्र क्या है? सचित्र समझाइए।
2. साधन गहनता को सचित्र समझाइए।
3. प्रतिस्थापन की सीमान्त दर (MRTS) क्या है?
4. समुदाय अधिमान वक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
5. आकुंचित वक्र को चित्र की सहायता से समझाइए।
6. प्रस्ताव वक्रों से आप क्या समझते हैं?

अति-लघु उत्तरीय प्रश्न:

1. घटती हुई लागतों की स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होगा?
2. रेखीय उत्पादन फलन उत्पादन में पैमाने के किस प्रतिफल को व्यक्त करता है?

बहुविकल्पीय प्रश्न:

1. किसी देश में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की मात्रा निर्भर करती है
 - i. संसाधन उपलब्धता पर
 - ii. तकनीकी ज्ञान पर
 - iii. उपरोक्त दोनों पर
2. उत्पादन संभावना वक्र के सभी बिन्दुओं पर उत्पादन के संसाधन होंगे
 - i. अपूर्ण-रोजगार में
 - ii. पूर्ण-रोजगार में
 - iii. सिर्फ श्रम पूर्ण-रोजगार में
 - iv. सिर्फ पूँजी पूर्ण-रोजगार में

3. उत्पादक का संतुलन होगा
 - i. उत्पादन संभावना वक्र के सभी बिन्दुओं पर
 - ii. जहाँ उत्पादन संभावना वक्र X अक्ष को काटता है
 - iii. जहाँ उत्पादन संभावना वक्र Y अक्ष को काटता है
 - iv. जहाँ उत्पादन संभावना वक्र, वस्तु कीमत रेखा को स्पर्श करता है
4. यदि उत्पादन के साधनों के बीच एक निश्चित सीमा के भीतर सतत स्थानापन्नता हो तो समोत्पाद वक्र होगा
 - i. एक सीधी रेखा
 - ii. मूल-बिन्दु के प्रति उत्तल
 - iii. मूल-बिन्दु के प्रति अवतल
 - iv. विकुंचित
5. उत्पादन फलन रैखिक समरूप होगा
 - i. यदि सभी आगतों को एक निश्चित अनुपात k से बढ़ाया जाय और उत्पादन में यदि K से अधिक की वृद्धि होती है
 - ii. यदि सभी आगतों को एक निश्चित अनुपात k से बढ़ाया जाय और उत्पादन में भी यदि उसी अनुपात, K , के बराबर वृद्धि होती है
 - iii. यदि सभी आगतों को एक निश्चित अनुपात k से बढ़ाया जाय और उत्पादन में यदि K से कम वृद्धि होती है
 - iv. उपरोक्त में से कोई नहीं
6. उत्पादन संभावना वक्र आधारित है
 - i. अवसर लागत पर
 - ii. श्रम लागत
 - iii. मौद्रिक लागत पर
 - iv. उपरोक्त सभी
7. इनमें से कौन सी अधिमान वक्रों की विशेषता नहीं हैं
 - i. ये बाएं से दायें नीचे की ओर झुके हुए होते हैं
 - ii. मूल बिन्दु के प्रति अवतल या नतोदर होते हैं
 - iii. दो समुदाय अधिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते
 - iv. ऊपर स्थिर समुदाय अधिमान वक्र नीचे के वक्र की अपेक्षा संतुष्टि के उच्चतर स्तर को व्यक्त करता है
8. एक अधिमान वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ता को
 - i. समान संतुष्टि प्राप्त होती है
 - ii. अलग अलग संतुष्टि प्राप्त होती है
 - iii. कितनी संतुष्टि प्राप्त होगी यह कीमत पर निर्भर करेगा
 - iv. कितनी संतुष्टि प्राप्त होगी यह आय पर निर्भर करेगा
9. उपभोक्ता का संतुलन वहाँ होगा
 - i. जहाँ घरेलू कीमत रेखा किसी समुदाय अधिमान वक्र को स्पर्श करती है
 - ii. जहाँ समुदाय अधिमान वक्र का ढाल, घरेलू कीमत रेखा के ढाल के बराबर है
 - iii. जहाँ $MRS_{xy} = B$

- iv. उपरोक्त सभी
10. बाक्स या संदूक चित्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया?
- एजवर्थ
 - मार्शल
 - ओहलिन
 - हेक्शर
11. प्रस्ताव वक्रों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है
- प्रस्ताव वक्र मांग और पूर्ति दोनों स्थितियों को दिखाते हैं
 - ये उत्पादन तथा उपभोग द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित होते हैं
 - यह आंशिक संतुलन विश्लेषण से संबंधित एक संकल्पना है
 - प्रस्ताव वक्र का संभाव्य व्यापार शर्तों से एक प्रकार संबंध है।
12. प्रस्ताव वक्र की तकनीकी को विकसित किया
- एल्फ्रेड मार्शल तथा एजवर्थ ने
 - जे0एस0 मिल तथा एजवर्थ ने
 - जे0एस0 मिल तथा एल्फ्रेड मार्शल ने
 - रिकार्डो तथा एल्फ्रेड मार्शल ने

निम्नलिखित कथनों में सत्य व असत्य चुनिए :

- यदि रेखीय समरूप उत्पादन फलन हो तो, जैसे-जैसे दो साधनों को एक ही अनुपात में लगाया जाता है दोनों साधनों की सीमान्त उत्पादकताएँ अपरिवर्तित रहती हैं।
- साधन गहनता पूँजी श्रम अनुपात को नहीं बताती है।
- यदि दो साधनों श्रम (L) और पूँजी (K) के बीच पूर्ण स्थानापन्नता हो तो समोत्पाद वक्र एक सीधी रेखा नहीं होगा।
- उत्पादन फलन उत्पादन तथा उत्पादन के साधन आगतों के बीच तकनीकी संबंधों को नहीं दर्शाता है।
- उत्पादन संभावना वक्र की अवतलता उत्पादन की स्थितियों पर निर्भर करेगी कि उत्पादन के साधन आसानी से एक उद्योग से दूसरे वस्तु उद्योग में आ जा सकते हैं।
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में समुदाय अधिमान वक्रों का प्रयोग व्यापार से कल्याण में वृद्धि को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है।
- उपभोक्ता का संतुलन वहाँ होगा जहाँ उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी।
- आय-वितरण स्थिर होने की दशा में दो समुदाय अधिमान वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं।
- समुदाय अधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिससे समुदाय या राष्ट्र के उपभोक्ताओं को समान संतुष्टि नहीं मिलती है।
- समुदाय अधिमान वक्र के किसी बिन्दु की ढाल उसकी सीमान्त प्रतिस्थापन दर को बताती है।
- यदि समाज में एक ही उपभोक्ता है तो व्यक्तिगत तथा समुदाय अधिमान वक्र में कोई अन्तर नहीं होगा।
- आकुंचित वक्र की व्युत्पत्ति उत्पादन की तकनीकी तथा मांग दशाओं के आधार पर की जाती है।
- बाक्स या संदूक चित्र की सहायता से उत्पादन फलनों तथा उत्पादन के साधनों की कुल मात्रा के बीच अंतर्संबंध का अध्ययन किया जाता है।

2.9 सारांश

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में कुछ व्यष्टि तथा समष्टि सिद्धान्तों के विश्लेषणात्मक यंत्रों का अर्थशास्त्रीयों ने विभिन्न सिद्धान्तों में उपयोग किया है।

उत्पादन संभावना वक्र यह बताता है कि कोई देश उपलब्ध प्रौद्योगिकी से अपने उत्पादन के संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करके दो वस्तुओं के किन वैकल्पिक संयोगों का उत्पादन कर सकता है। स्पष्ट है कि वक्र के सभी बिन्दुओं पर देश के समस्त संसाधन पूर्ण रोजगार में होंगे। यह अवसर लागत पर आधारित है। इसका आकार मुख्यतः उत्पादन के पैमाने के प्रतिफल पर निर्भर करता है।

एक समोत्पाद वक्र, उत्पादन के साधनों के सभी संयोगों अर्थात् तकनीकी रूप से दक्ष सभी विधियों को दर्शाता है जिससे कि उत्पादन का एक समान स्तर प्राप्त होता है। समोत्पाद वक्र का आकार साधनों की स्थानापन्नता के अंश पर निर्भर करता है। समोत्पाद वक्र के ढाल को तकनीकी प्रतिस्थापन की दर या प्रतिस्थापन की सीमान्त दर (MRTS) कहा जाता है। मूल बिन्दु से समोत्पाद वक्र पर खींची गयी रेखा का ढाल किसी उत्पादन विधि की साधन गहनता को बताती है। इस प्रकार साधन गहनता पूँजी श्रम अनुपात है।

बाक्स या संदूक चित्र की सहायता से उत्पादन फलनों तथा उत्पादन के साधनों की कुल मात्रा के बीच अंतर्संबंध का अध्ययन किया जाता है। इससे दो वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त आगतों के कुशलतम संयोगों को भी प्रदर्शित किया जाता है।

समुदाय अधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिससे समुदाय या राष्ट्र के उपभोक्ताओं को समान संतुष्टि मिलती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में समुदाय अधिमान वक्रों का प्रयोग व्यापार से पूर्व तथा व्यापार के पश्चात राष्ट्र किस प्रकार संतुलन में आते हैं और उनके कल्याण में वृद्धि होती है, इसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। प्रस्ताव वक्र के द्वारा हम यह दिखाते हैं कि यदि दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो किस प्रकार से माँग तथा पूर्ति की अंतर्क्रिया से साम्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त का निर्धारण होता है। इसकी सहायता से व्यापार से होने वाले लाभों को भी दिखाया जा सकता है।

2.10 शब्दावली

- **उत्पादन संभावना वक्र** - देश के पास उपलब्ध कुल संसाधनों से दो वस्तुओं के उत्पादन के संभाव्य वैकल्पिक संयोगों का बिन्दुपथ।
- **समोत्पाद वक्र** - दो साधनों के विभिन्न संयोगों बिन्दुपथ जिससे कि उत्पादन का एक समान स्तर प्राप्त होता है।
- **तकनीकी प्रतिस्थापन की दर (MRTS)** - L की K के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर का अर्थ है L की एक इकाई K की कितनी इकाईयों के लिए प्रयोग हो सकती है जिससे कि उत्पादन समान रहे। $MRTSLK = AK/AL$ साधन गहनता: साधन गहनता पूँजी श्रम अनुपात को बताती है।
- **अधिमान वक्र** - दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों का बिन्दुपथ जिससे उपभोक्ताओं को समान संतुष्टि मिलती है।
- **प्रस्ताव वक्र** - एक देश का प्रस्ताव वक्र एक ओर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों (व्यापार-शर्त) पर आयातित-वस्तु के बदले देश द्वारा निर्यात-वस्तु की प्रस्तावित मात्रा को व्यक्त करता है और दूसरी ओर यह विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर उस देश की विदेशी वस्तु (आयात) की माँग को प्रदर्शित करता है।

इस प्रकार प्रस्ताव वक्र में मांग और पूर्ति दोनों के ही तत्व विद्यमान होते हैं। इसलिए इसे प्रस्ताव वक्र के साथ-साथ प्रतिपूरक मांग वक्र भी कहा जाता है।

2.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अति-लघु उत्तरीय प्रश्न:

1. मूलबिन्दु के प्रति उन्नतोदर
2. स्थिर

बहुविकल्पीय प्रश्न:

1. iii 2.11 ,3.iv ,4.ii ,5.11 ,6.i, 7. ii, 8. i, 9.iv, 10.i, 11. iii, 12.1

सत्य व असत्य :

- | | | | | |
|-----------|------------|---------|-----------|---------|
| 1. सत्य , | 2.असत्य , | 3.असत्य | 4.असत्य , | 5.सत्य |
| 6. सत्य | 7.सत्य , | 8.असत्य | 9.असत्य , | 10.सत्य |
| 11.सत्य , | 12.असत्य , | 13.सत्य | | |

2.12 संदर्भ ग्रंथ सूची

- HH. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Bo Sodersten, International Economics ,Macmillan, 1999
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: International Economics: Theory and Policy, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- Charles P Kindleberger, International Economics, Richard D. Irwin Inc., Illinois, 1968
- Dominik Salvatore, International Economics, John Willy & Sons, Inc., 2008
- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006 •
- Robert M. Dunn, and John H. Mutti, International Economics, Rouledge, London.
- सुदामा सिंह एवं एम0सी0 वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड एंड आई0बी0एच0 पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम0एल0 झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010।
- ज्ञानेंद्र सिंह कुशवाहा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1979।

2.13 उपयोगी/सहायक पाठ्य सामग्री

- HH. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt.Ltd. 2001

- Bo Sodersten, International Economics ,Macmillan, 1999
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: International Economics: Theory and Policy, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- Charles P Kindleberger, International Economics, Richard D. Irwin Inc.,Illinois, 1968
- Dominik Salvatore, International Economics, John Willy & Sons, Inc.,2008
- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006
- एस. एन. लाल, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहबाद, 2004
- एच. एस. अग्रवाल, तथा सी. एस. बरला, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2003.
- सुदामा सिंह एवं एम. सी. वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड एंड आई. बी. एच. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम0 एल0 झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010.
- डॉ. जी. सी. सिंघई एवं डॉ. जे. पी. मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा, 2010

2.14 निबन्धात्मक प्रश्न

1. उत्पादन संभावना वक्र क्या है? विभिन्न लागत स्थितियों में उत्पादन संभावना वक्र के विभिन्न आकारों की सचित्र व्याख्या कीजिए। घटते हुए प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से उत्पादक के संतुलन को दर्शाए।
2. समोत्पाद वक्र क्या है? इनकी विशेषताओं को बताइए। समोत्पाद वक्र की सहायता से उत्पादक के संतुलन की सचित्र व्याख्या कीजिए।
3. बाक्स चित्र पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए।
4. प्रस्ताव वक्र क्या है? इसे कैसे व्युत्पन्न किया जाता है?

इकाई 3 - अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत (Classical Theory of International Trade)

- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 उद्देश्य
- 3.3 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत- भूमिका
- 3.4 एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत
- 3.5 रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत
- 3.6 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यताएं
- 3.7 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की कमियां
- 3.8 मूल्यांकन
- 3.9 मिल का प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत
- 3.10. अभ्यास हेतु प्रश्न
- 3.11 सारांश
- 3.12 शब्दावली
- 3.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 3.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 3.15 उपयोगी/ सहायक पाठ्य सामग्री
- 3.16 निबंधात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

इससे पहले की इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति तथा उसके विलेशणात्मक यंत्रों के बारे में बता सकते हैं। आप जान गए होंगे की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार तथा उससे होने वाला लाभ है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार जब तक दो देशों के बीच लागतों का अंतर विद्यमान है। तब तक कम से कम एक या दोनों ही देशों को व्यापार से लाभ होगा। बाद में जे.एस. मिल ने तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में मांग पक्ष को सम्मिलित कर प्रतिपूरक मांग का सिद्धान्त दिया।

प्रस्तुत इकाई में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विशुद्ध सिद्धान्त के बारे में विस्तार से बताया गया है। जोकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया है। विशेष रूप से रिकार्डो द्वारा प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की विस्तार से चर्चा की गयी है। साथ ही जे. एस. मिल के प्रतिपूरक मांग के सिद्धान्त का भी वर्णन किया गया है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

3.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप

- ✓ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विशुद्ध सिद्धान्त के बारे में जान सकेंगे।
- ✓ निरपेक्ष लाभ एवं तुलनात्मक लाभ सिद्धान्त में अंतर समझ सकेंगे।
- ✓ जे.एस. मिल के प्रतिपूरक मांग के सिद्धान्त को समझ सकेंगे।
- ✓ प्रतिष्ठित सिद्धान्त की खूबियां तथा कमियां जान सकेंगे।

3.3 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त - भूमिका

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्त का मुलभूत प्रश्न यह है की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है? या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ क्यों होता है? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने श्रम को उत्पादन का एक मात्र साधन मानते हुए कहा की विभिन्न देशों के बीच श्रम उत्पादकता में अंतर के कारण ही व्यापार होता है।

प्रतिष्ठित सिद्धान्त से पूर्व आधुनिक राष्ट्र राज्य के विकास के दौरान 17वीं तथा 18 वीं शताब्दी में वणिकवादी विचारधारा थी। वणिकवाद में कई आधुनिक तत्व थे; जैसे वणिकवादी अत्यधिक राष्ट्रवादी थे, उनके लिए अपने देश का कल्याण सर्वोपरि था, राष्ट्रीय उदेश्यों को प्राप्त करने के लिए वे आर्थिक गतिविधियों के नियमन और आयोजन के पक्ष में थे। वणिकवादीयों के लिए एक देश के समृद्ध होने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय अधिक से अधिक बहुमूल्य धातुएं विशेष रूप से सोना अर्जित करना है। निर्यात से यदि देश में बहुमूल्य धातुएं या सोना आता है तो उसका वे समर्थन करते हैं परन्तु आयात से सोना देश के बाहर जायेगा। इसलिए वे विनियमित, नियन्त्रित तथा प्रतिबंधित व्यापार नीति के पक्ष में थे।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने दिखाया की किसी राष्ट्र के धन का सही मापन सोने से नहीं बल्कि उन वस्तुओं और सेवाओं से होता जो देश में उत्पादित होती है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक '**An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations**' में उन्होंने वणिकवादी विचारधारा को गलत तथा अतार्किक बताया। उनके अनुसार यदि सरकार विदेशी व्यापार से वणिकवादी नियंत्रणों को हटा दे, तो राष्ट्र के उत्पादन यानि धन में तेजी से वृद्धि होगी। स्मिथ वणिकवादीयों की इस

धारणा का भी खंडन करते हैं की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से एक देश को लाभ दुसरे की कीमत पर होगा। स्मिथ ने दिखाया की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के द्वारा व्यापार में लगे सभी देशों को लाभ होता है।

स्मिथ और रिकार्डो की विचारधारा के केन्द्र में व्यक्ति है ; राष्ट्र तो मात्र उसके नागरिकों का योग है। इसलिए उनके लिए अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय उपभोक्ता था। मनष्य मेहनत और उत्पादन उपभोग के लिए करता है। और कोई भी चीज जो उपभोग को बढ़ा दे या **रिकार्डो** के शब्दों में **‘आनंदों के योग’** को बढ़ा दे, उसका समर्थन किया जाना चाहिए। स्मिथ और रिकार्डो द्वारा प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त मुख्यतः इसी बात की व्याख्या करता है की व्यापार से कैसे व्यापार में लगे देशों को लाभ होता है अर्थात देश के लोगों के उपभोग में वृद्धि होती है।

एडम स्मिथ ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त के निर्माण की आधारशिला रखी। परन्तु **डेविड रिकार्डो** ने **एडम स्मिथ** के सिद्धान्त को और स्पष्ट किया, इसका विस्तार किया तथा इसे वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त को रिकार्डो द्वारा प्रस्तुत तुलनात्मक लागत सिद्धान्त या तुलनात्मक लाभ सिद्धान्त द्वारा जाना जाता है। बाद में **जान स्टुअर्ट मिल** ने **तुलनात्मक लागत सिद्धान्त** में मांग पक्ष को सम्मिलित कर प्रतिपूरक मांग का सिद्धान्त दिया।

3.4 एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धान्त

एडम स्मिथ ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ सिद्धान्त प्रस्तुत किया। **एडम स्मिथ** ने **लागतों में निरपेक्ष अंतर के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त** प्रस्तुत किया। यदि एक देश को एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लागत लाभ तथा दुसरे वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष हानि हो तो फिर व्यापार होगा। प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसके उत्पादन में निरपेक्ष लागत लाभ होगा और उस वस्तु का आयात करेगा जिसके उत्पादन में निरपेक्ष लागत हानि होगी। इस तरह स्वतंत्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बाजार की सीमा में विस्तार करके श्रम के अत्यधिक विशिष्टीकरण को संभव बनाता है; फलस्वरूप श्रम के सीमापार क्षेत्रीय विभाजन से प्राप्त लाभों को बढ़ाता है।

एडम स्मिथ के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से बाजार का विस्तार होता है जिससे श्रम विभाजन की संभावना बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन और उसके फलस्वरूप होने वाले विशिष्टीकरण के कारण उत्पादन और उपभोग में हुई वृद्धि का लाभ व्यापार में सम्मिलित सभी देशों को होता है। जिस प्रकार दर्जी अपने जूतों को स्वयं नहीं बनाता, बल्कि कपड़े के बदले मोची से उसे खरीदता है। इस प्रकार दर्जी और मोची दोनों का लाभ होता है। उसी प्रकार, स्मिथ के अनुसार, एक देश भी दूसरे देशों के साथ व्यापार करके लाभ प्राप्त कर सकता है।

स्मिथ के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार तभी होता है जब लागतों में निरपेक्ष अंतर हो अर्थात् एक देश को एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ तथा दूसरे देश को दूसरी वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ हो। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश को उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण हासिल करना चाहिए और निर्यात करना चाहिए, जिसमें उसे निरपेक्ष लाभ हो तथा उस वस्तु का आयात करना चाहिए जिसमें उसे निरपेक्ष हानि है।

माना दो देश A और B हैं दो वस्तु X और Y का उत्पादन कर रहे हैं। दोनों देशों की लागत दशाओं को निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है।

सारणी 3.1 दो देशों में दो वस्तुओं की लागतों की तुलना

देश	प्रति इकाई उत्पादन लागत (श्रम घण्टों में)	
	1 इकाई वस्तु X की उत्पादन लागत	1 इकाई वस्तु Y की उत्पादन लागत
A	100	200
B	200	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि देश A में वस्तु X की उत्पादन लागत (100 श्रम घण्टे), देश B में X की लागत (200 श्रम घण्टे) की आधी है। इस प्रकार वस्तु Y की देश A में लागत देश B की अपेक्षा दुगुनी है। स्पष्ट है कि देश A, वस्तु X के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से अधिक दक्ष है। जबकि देश B, वस्तु Y के उत्पादन में अधिक दक्ष है। यदि देश A सिर्फ X का तथा B सिर्फ Y का उत्पादन करें तो कुल उत्पादन बढ़ जायेगा।

विशिष्टीकरण के पश्चात् देश A कुल 300 श्रम घण्टे (100+200) से वस्तु X की 3 इकाई का उत्पादन करेगा, इसी प्रकार देश B, कुल 300 श्रम घण्टे (200+100) से 3 इकाई वस्तु Y का उत्पादन करेगा।

सारणी 3.2: दो देशों में दो वस्तुओं की व्यापार के पूर्व तथा पश्चात् उत्पादन की तुलना

देश	वस्तु X उत्पादन		वस्तु Y उत्पादन		कुल उत्पादन	
	व्यापार के पूर्व	व्यापार के पश्चात्	व्यापार के पूर्व	व्यापार के पश्चात्	व्यापार के पूर्व	व्यापार के पश्चात्
A	1	3	1	0	2	3
B	1	0	1	3	2	3
कुल उत्पादन	2	3	2	3	4	6

सारणी 3.2 से स्पष्ट है कि विशिष्टीकरण के पश्चात् उतने ही संसाधनों (श्रम घण्टों) से दोनों ही देशों में दोनों ही वस्तुओं का एक-एक इकाई अधिक उत्पादन होगा तथा कुल संयुक्त उत्पादन 4 से बढ़कर 6 हो जायगा।

व्यापार के फलस्वरूप उत्पादन में हुई वृद्धि दोनों देशों के कल्याण या उपभोग में कितनी वृद्धि लाएगा। यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त पर निर्भर करेगा। यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त या कीमत अनुपात $1x=1y$ हो तो दोनों देशों को व्यापार से लाभ होगा। जैसा कि सारणी 3.3 से स्पष्ट है।

सारणी 3.3: व्यापार के पश्चात् उपभोग (यदि अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात $1x=1y$ हो)

देश	वस्तु - X	वस्तु - Y	कुल
A	2	1	3
B	1	2	3

व्यापार से पूर्व दोनों देश वस्तु X और Y की एक-एक इकाई का उपभोग कर रहे थे, परन्तु अब देश A $1x$ के बदले $1y$ प्राप्त करेगा और बचे हुए $2y$ का उपभोग करेगा। इसी प्रकार देश B भी पहले की अपेक्षा एक इकाई अधिक वस्तु y का उपभोग करेगा। इस प्रकार व्यापार से दोनों ही देशों के जीवन के रहन-सहन के स्तर में सुधार आएगा। एडम स्मिथ की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ की व्याख्या अत्यंत सरल और स्पष्ट है। तथा स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में बड़े ही दृढ़ता पूर्वक अपने तर्क को प्रस्तुत करती है। हालांकि यह सिद्धान्त संकीर्ण है और थोड़ी जटिल स्थितियों में व्यापार से होने वाले लाभों की व्याख्या करने में असमर्थ है।

3.5 रिकार्डों का तुलनात्मक लागत सिद्धान्त

रिकार्डों द्वारा प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त तुलनात्मक लागत सिद्धान्त कहा जाता है। रिकार्डों एक कदम और आगे बढ़कर यह दिखाते हैं की यदि एक देश को दूसरे देश की अपेक्षा किसी भी वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लागत लाभ नहीं है तब भी व्यापार होगा और व्यापार में लगे सभी देशों को लाभ होगा। उनके अनुसार अन्य बातें सामान रहने पर एक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टिकरण प्राप्त करेगा और निर्यात करेगा जिसमें उसे अधिकतम तुलनात्मक लागत लाभ या न्यूनतम तुलनात्मक लागत हानि हो। इसी प्रकार देश उस वस्तु का आयात करेगा जिसमें उसे तुलनात्मक लागत लाभ न्यूनतम या तुलनात्मक लागत हानि अधिकतम हो। इस प्रकार देश अपने उत्पादन और उपभोग को अधिकतम करने में समर्थ होगा।

रिकार्डों ने अपने सिद्धान्त को एक उदहारण द्वारा समझाया। माना दो देश इंग्लैंड और पुर्तगाल हैं जो दो वस्तुओं कपड़े और शराब का उत्पादन करते हैं। सारणी 1 में दोनों देशों की लागत दशाओं को दर्शाया गया है।

सारणी 3.4: इंग्लैंड और पुर्तगाल के लागत दशाओं की तुलना

देश	उत्पादन की लागत(श्रम घंटों में)		घरेलू विनिमय अनुपात
	1 इकाई शराब	1 इकाई कपड़ा	
पुर्तगाल	80	90	1 इकाई शराब = 80/90 = 0.89 इकाई कपड़ा या 1 इकाई कपड़ा = 1.125 इकाई शराब
इंग्लैंड	120	100	1 इकाई शराब = 120/100 = 1.2 इकाई कपड़ा या 1 इकाई कपड़ा = .83 इकाई शराब
तुलनात्मक लागत अनुपात	80/120=0.67	90/100= 0.90	

तुलनात्मक लागत लाभ जानने के लिए हम दोनों देशों में एक वस्तु की उत्पादन लागत की तुलना दूसरे वस्तु की उत्पादन लागत से करते हैं। रिकार्डों के उदहारण में -

$$\frac{\text{पुर्तगाल में शराब की श्रम लागत}}{\text{इंग्लैंड में शराब की श्रम लागत}} < \frac{\text{पुर्तगाल में कपड़ा की श्रम लागत}}{\text{इंग्लैंड में कपड़ा की श्रम लागत}} < 1$$

अर्थात् $80/120 < 90/100 < 1$

अर्थात् $0.67 < 0.90 < 1$

पुर्तगाल में दोनों वस्तुओं की एक इकाई की उत्पादन लागत इंग्लैंड से कम है; पुर्तगाल दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त कर रहा है। परन्तु वह कपड़े की अपेक्षा शराब के उत्पादन में अधिक तुलनात्मक लाभ प्राप्त कर रहा है। क्योंकि एक इकाई शराब के उत्पादन में पुर्तगाल की श्रम लागत, इंग्लैंड में शराब की श्रम लागत का मात्र 67% है, जबकि कपड़े में यह 90% है।

स्पष्ट है कि **इंग्लैंड** दोनों वस्तुओं के उत्पादन में **निरपेक्ष हानि** प्राप्त कर रहा है। परन्तु वह कपड़े की अपेक्षा शराब के उत्पादन में अधिक **तुलनात्मक हानि** प्राप्त कर रहा है। **रिकाडों** के अनुसार चूंकि पुर्तगाल का तुलनात्मक लाभ शराब के उत्पादन में अधिक है और इंग्लैंड की तुलनात्मक हानि कपड़े के उत्पादन में कम है इसलिए यदि पुर्तगाल शराब के उत्पादन में तथा इंग्लैंड कपड़े के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टिकरण करे तो व्यापार से दोनों देशों को लाभ होगा। अर्थात् दक्षता को वहाँ विशिष्टिकरण करना चाहिए जहां वह अधिक हो और अदक्षता को वहाँ विशिष्टिकरण करना चाहिए जहां वह कम हो।

विशिष्टिकरण के पश्चात दोनों वस्तुओं, कपड़े और शराब, का उत्पादन व्यापार शुरू होने से पहले के उत्पादन की अपेक्षा अधिक होगा। इसे आप निम्नलिखित ढंग से समझ सकते हैं:

पुर्तगाल में कुल संसाधन = 170 श्रम घंटे

इंग्लैंड में कुल संसाधन = 220 श्रम घंटे

सारणी 3.5: व्यापार ना होने की स्थिति में उत्पादन और उपभोग

देश	शराब	कपड़ा	कुल उत्पादन तथा उपभोग
पुर्तगाल	1	1	2
इंग्लैंड	1	1	2
विश्व	2	2	4

व्यापार ना होने की स्थिति में दोनों देश एक – एक इकाई कपड़े और शराब का उत्पादन तथा उपभोग करते हैं और कुल विश्व उत्पादन चार इकाई के बराबर है।

सारणी 3.6: व्यापार होने की स्थिति में उत्पादन और उपभोग

देश	शराब	कपड़ा	कुल उत्पादन तथा उपभोग
पुर्तगाल	2.125	0	2.125
इंग्लैंड	0	2.2	2.2
विश्व	2.125	2.2	4.325

व्यापार शुरू होने के पश्चात विशिष्टिकरण के कारण दोनों वस्तुओं, कपड़े और शराब, का उत्पादन तथा उपभोग अधिक होगा। पुर्तगाल अब अपने कुल 170 श्रम घंटे संसाधन से 2.125 इकाई शराब का उत्पादन करेगा जबकि इंग्लैंड में कुल 220 श्रम घंटे से 2.2 इकाई कपड़े का उत्पादन करेगा और कुल विश्व उत्पादन 4 इकाई से बढ़कर 4.325 इकाई हो जायगा।

परन्तु वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाला उत्पादन लाभ यह सुनिश्चित नहीं करता की व्यापार से दोनों देशों के कल्याण या उपभोग में वृद्धि होगी। उत्पादन लाभ सकल राष्ट्रीय आय में लाभ या आय लाभ है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप व्यापारत देशों के आर्थिक रहन सहन का स्तर कितना ऊपर उठा इसके निर्धारण में उपभोग लाभ महत्वपूर्ण है। प्रत्येक देश के उपभोग या कल्याण में कितनी वृद्धि होगी यह पूरी तरह से व्यापार शर्त पर निर्भर करेगा।

इंग्लैंड एक इकाई शराब के उत्पादन के लिए 120 श्रम घंटे तथा एक इकाई कपड़े के उत्पादन के लिए 100 श्रम घंटे ले रहा है। स्पष्ट है कि इंग्लैंड में शराब की उत्पादन लागत कपड़े की उत्पादन लागत से अधिक है

1 इकाई शराब = 120/100 या 1.2 इकाई कपड़ा

1 इकाई कपड़ा = 0.83 इकाई शराब

पुर्तगाल एक इकाई शराब के उत्पादन के लिए 80 श्रम घंटे तथा एक इकाई कपड़े के उत्पादन के लिए 90 श्रम घंटे ले रहा है। स्पष्ट है कि पुर्तगाल में कपड़े की उत्पादन लागत शराब की उत्पादन लागत से अधिक है-

1 इकाई शराब = 80/90 या 0.89 इकाई कपड़ा।

यदि अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात या व्यापार शर्त हो :

1 इकाई कपड़ा = 1 इकाई शराब;

अर्थात् पुर्तगाल शराब के 1 इकाई निर्यात से 1 इकाई कपड़ा प्राप्त करेगा, जबकि घरेलू स्तर पर सिर्फ 0.89 इकाई कपड़ा मिलता था क्योंकि पुर्तगाल का घरेलू विनिमय अनुपात है: 1 इकाई शराब = 0.89 इकाई कपड़ा। तो पुर्तगाल को व्यापार से लाभ होगा: 0.11 (1- 0.89) इकाई कपड़ा।

शराब के पदों में देखें तो पुर्तगाल घरेलू स्तर पर 1 इकाई कपड़ा के लिए 1.125 इकाई शराब देता है (क्योंकि पुर्तगाल का घरेलू विनिमय अनुपात है: 1 इकाई कपड़ा -1.125 इकाई शराब); जबकि व्यापार के पश्चात सिर्फ 1 इकाई शराब के निर्यात से 1 इकाई कपड़ा प्राप्त करेगा अर्थात् पुर्तगाल को व्यापार से लाभ होगा। 0.125 (1.125 – 1) इकाई शराब।

इसी प्रकार इंग्लैंड को व्यापार से लाभ होगा 0.20 (1.20 – 1) इकाई कपड़ा या 0.17 (1 - 0.83) इकाई शराब; क्योंकि इंग्लैंड का घरेलू विनिमय अनुपात है: 1 इकाई शराब = 1.20 इकाई कपड़ा या 1 इकाई कपड़ा- 0.83 इकाई शराब। अर्थात् इंग्लैंड घरेलू स्तर पर 1 इकाई शराब के लिए 1.20 इकाई कपड़ा देता है या 1 इकाई कपड़ा से सिर्फ 0.83 इकाई शराब ही मिलती है।

यदि व्यापार पुर्तगाल की घरेलू विनिमय अनुपात पर होता है तो इसे व्यापार से कोई लाभ नहीं होगा, व्यापार का समस्त लाभ इंग्लैंड को होगा। इसके विपरीत यदि व्यापार इंग्लैंड की घरेलू विनिमय अनुपात पर होता है व्यापार का समस्त लाभ पुर्तगाल ले जायेगा। वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात या व्यापार शर्त दो देशों के इन्हीं घरेलू विनिमय अनुपातों के बीच कंही निर्धारित होगी। यदि व्यापार शर्त दो देशों के घरेलू विनिमय अनुपातों के बिलकुल बीच में स्थित है तो दोनों ही देशों को व्यापार से बराबर बराबर लाभ होगा।

3.6 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त की मान्यताएं

चूंकि वास्तविक जगत में चीजें काफी जटिल हैं और तेजी से बदलती रहती हैं। इसलिए प्रत्येक आर्थिक सिद्धान्त कुछ निश्चित मान्यताओं पर आधारित होते हैं। जोकि वास्तविकता के ही सरलीकृत रूप होती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है:

1. केवल दो देश हैं जो दो समरूप वस्तुओं का व्यापार करते हैं।
2. श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है अर्थात् यह सिद्धान्त 'मूल्य के श्रम सिद्धान्त' पर आधारित है। सभी श्रम-इकाईयाँ समरूप हैं।
3. उत्पादन में पैमाने के स्थिर प्रतिफल की स्थिति है।
4. परिवहन लागतें शून्य है।
5. उत्पादन के साधन देश के भीतर पूर्णरूप से गतिशील तथा देशों के मध्य पूर्णरूप से अगतिशील हैं।
6. दोनों देशों में पूर्ण रोजगार है तथा पूर्ण-प्रतियोगिता की स्थिति पायी जाती है।
7. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। अर्थात् दो देशों में स्वतंत्र व्यापार हो रहा है।
8. दोनों देशों के मध्य वस्तु-विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार होता है। अर्थात् मुद्रा के अस्तित्व की उपेक्षा की गयी है।
9. उपभोक्ता की रुचि, उत्पादन फलन, उत्पादन के साधनों की मात्रा आदि को स्थिर मान लिया गया है।

3.7 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त की कमियां

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त बड़े ही तार्किक और सुन्दर ढंग से व्यापार से होने वाले लाभों की व्याख्या करता है। तुलनात्मक लागतों में विद्यमान अन्तर के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सभी व्यापाररत देशों के लिए लाभदायक होगा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बड़े ही स्पष्ट ढंग से इस बात को कहते हैं कि विभिन्न देशों के उत्पादन फलन अलग-अलग होते हैं, इसी कारण तुलनात्मक लागतों में अन्तर होता है।

प्रथम विश्वयुद्ध तक यह सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक लोकप्रिय सिद्धान्त बना रहा। संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग को सुनिश्चित करने और इस प्रकार कुल उत्पादन तथा उपभोग में वृद्धि करने की दृष्टि से इस सिद्धान्त की खूबियाँ बिल्कुल स्पष्ट हैं। परन्तु यह सिद्धान्त जिन मान्यताओं पर आधारित हैं वे व्यवहारिक रूप से अवास्तविक हैं। इसलिए इस सिद्धान्त का विश्लेषणात्मक ढांचा काफी कमजोर रहा है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ओहलिन, ग्राहम आदि ने इस सिद्धान्त की कमियों को महत्वपूर्ण रूप से रखांकित किया है। सिद्धान्त की महत्वपूर्ण आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं।

1. प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यह बताने में असफल रहे कि विभिन्न देशों के उत्पादन फलन भिन्न-भिन्न क्यों होते हैं।
2. यह सिद्धान्त 'मूल्य के श्रम सिद्धान्त' पर आधारित है जो कि अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। किसी वस्तु की उत्पादन लागत उसके उत्पादन में लगे सिर्फ श्रम की मात्रा के बराबर नहीं होती है बल्कि उसमें सभी संसाधन लागते सम्मिलित होती हैं। विभिन्न श्रम-इकाईयाँ भी समरूप नहीं होती हैं। श्रम अनेक वर्गों में विभक्त होता है जैसे, कुशल श्रम, अकुशल श्रम, अर्द्धकुशल श्रम इत्यादि और ये विभिन्न वर्गों के श्रम आपस में प्रतियोगी नहीं होते हैं। श्रम की अन्तर्क्षेत्रीय पूर्ण गतिशीलता और श्रम-बाजार की पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता भी अवास्तविक है इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने श्रम के मूल्य सिद्धान्त को रद्द कर दिया है।

प्रतिष्ठित सिद्धान्त के समर्थकों का तर्क है कि उनका विश्वास मुख्यतः कल्याणकारी अर्थशास्त्री में था। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त लाभ की माप के लिए उन्होंने श्रम लागत का प्रयोग 'वास्तविक लागत' के रूप में किया है। 'वास्तविक लागत' की धारणा का प्रयोग सामान्यतः उत्पादन के दौरान श्रम की अनुपयोगिता या कष्टानुभूति के रूप में किया गया है। परन्तु अनुपयोगिता एक आत्मनिष्ठ प्रत्यय है जो कि देश, काल और व्यक्ति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। सिद्धान्त इस मान्यता पर भी आधारित है कि सभी वस्तुओं के उत्पादन में श्रम समान अनुपात में प्रयुक्त होता है। यह मूलतः एक स्थैतिक विश्लेषण है इसलिए अवास्तविक है।

परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अन्य लागत की परिभाषाओं को लेकर भी स्मिथ तथा रिकार्डों के निष्कर्षों को सिद्ध किया है। प्रो. जगदीश भगवती के अनुसार रिकार्डों का सिद्धान्त एक कल्याणकारी मॉडल के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र व्यापार का समर्थन था। यह सिद्धान्त व्यापार के विभिन्न तथ्यों की व्याख्या के लिए निर्मित धनात्मक (positive) मॉडल नहीं है।

3. प्रतिष्ठित सिद्धान्त उत्पादन में पैमाने के स्थिर प्रतिफल की मान्यता मान लेता है और इस आधार पर सभी व्यापाररत देशों में पूर्ण विशिष्टीकरण की बात करता है। वास्तविक जगत में न तो उत्पादन में स्थिर लागत की स्थिति और न ही किसी देश में पूर्ण विशिष्टीकरण की स्थिति पायी जाती है। अनेक देश अनेक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और लागत दशाएँ उत्पादन में बढ़ते हुए प्रतिफल से घटते हुए प्रतिफल के बीच परिवर्तित होती रहती है। परन्तु बाद में नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अन्य लागत दशाओं में भी व्यापार-सिद्धान्त का विस्तार किया और प्रतिष्ठित सिद्धान्त के निष्कर्षों को सिद्ध करने की कोशिश की।

4. प्रतिष्ठित सिद्धांत में परिवहन लागतों की भी उपेक्षा की गयी है जबकि इन लागतों की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा और दिशा दोनों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उच्च परिवहन लागते तुलनात्मक लाभों और व्यापार से लाभों को समाप्त कर सकती हैं। यह आलोचना सिद्धांत को गम्भीर चुनौती पेश नहीं करती क्योंकि परिवहन लागतों व अन्य सम्बन्धित लागतों को जोड़कर कुल लागत के पदों में तुलनात्मक लाभों को पुनः परिभाषित करना सम्भव है।
5. सिद्धांत में उपभोक्ताओं की रुचियों, उत्पादन-फलन, उत्पादन साधनों की मात्रा आदि को स्थिर मान लिया गया है परन्तु व्यवहार में ये स्थिर नहीं है। देश में उसकी खपत सम्भव नहीं है। दूसरी ओर छोटा देश पूर्ण विशिष्टीकरण के पश्चात् भी बड़े देश की मांग को संतुष्ट नहीं कर सकता है। द्वितीय स्थिति में, उच्च मूल्य की वस्तु उत्पादित करने वाला देश पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त करने में समर्थ होगा जबकि निम्न मूल्य वाली वस्तु का उत्पादन करने वाला देश ऐसा नहीं कर सकेगा क्योंकि कम मूल्य वाली वस्तु के सम्पूर्ण निर्यात का मूल्य, उस देश की उच्च मूल्य की वस्तु की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। इस प्रकार, जब तक व्यापार में सम्मिलित देश समान आर्थिक आकार के न हों या व्यापारिक वस्तुएँ लगभग समान उपभोग मूल्य की न हों उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण सम्भव नहीं है।
6. यह सिद्धांत सिर्फ कुछ संकीर्ण प्रश्नों के उत्तर देने तक ही सीमित हैं, जैसे- किसी दिये हुए समय में किन वस्तुओं का व्यापार किया जाएगा और व्यापार से क्या लाभ होगा? यह इस बात को नहीं बताता कि समय के साथ व्यापार की मात्रा, संरचना तथा लाभ में किस प्रकार परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में, यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या नहीं करता कि समय के साथ तुलनात्मक लाभ की संरचना में कैसे परिवर्तन होगा।
7. रिकार्डों का सिद्धांत एकपक्षीय है क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के केवल पूर्ति पक्ष पर विचार करता है और मांग पक्ष को पूरी तरह से उपेक्षित कर देता है। तुलनात्मक लागत में भिन्नता के लिए मांग की दशाओं की उपेक्षा की गयी है। वास्तव में प्रतिष्ठित सिद्धांत अल्पकालीन नहीं बल्कि दीर्घकालीन समस्या पर विचार करता है इसलिए इसलिए लागतों में अंतर के लिए सिर्फ पूर्ति दशाओं को ही प्रभावशाली मानता है। हालांकि बाद में जे0एस0 मिल ने प्रतिष्ठित सिद्धांत की इस कमी को दूर करते हुए मांग पक्ष को भी सम्मिलित किया।
8. बर्टिल ओहलिन इस सिद्धांत को बेढंगा और अवास्तविक कहते हैं, क्योंकि यह विभिन्न देशों के मध्य सीधे सीधे पूर्ण लागत की भिन्नता पर विचार नहीं करता है। यह सिर्फ श्रम लागतों पर विचार करता है और अन्य लागतों की अवहेलना करता है। ओहलिन इस सिद्धांत को खतरनाक मानते हैं क्योंकि यह केवल दो देशों तथा दो वस्तुओं वाली परिस्थितियों का विश्लेषण करता है और इससे प्राप्त निष्कर्षों को अनेक देशों और वस्तुओं वाली परिस्थितियों पर लागू करने का प्रयास करता है।
ओहलिन के अनुसार संसाधन न सिर्फ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि देश के भीतर भी विभिन्न क्षेत्रों के बीच अगतिशील होते हैं। इसलिए तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत न सिर्फ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि सभी प्रकार के व्यापार में लागू होता है। इसलिए ओहलिन मूल्य के सामान्य सिद्धांत पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नये सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं।
9. इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए मिर्डल कहते हैं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय असमानताओं और विकास तथा अल्पविकास की समस्याओं की उपेक्षा करता है।
10. **फ्रैंक ग्राहम** ने यह दिखाया कि इस सिद्धांत की मान्यताओं के आधार पर भी पूर्ण विशिष्टीकरण सम्भव नहीं होगा। अपूर्ण या आंशिक विशिष्टीकरण निम्नलिखित स्थितियों में होगा।

- a. यदि दो व्यापार कर रहे देशों में उत्पादन की दृष्टि से एक बहुत छोटा तथा दूसरा बहुत बड़ा हो।
- b. यदि दोनों देशों के व्यापार में सम्मिलित वस्तुओं का मूल्य तुलनीय हो। जब एक वस्तु उच्च मूल्य वाली वस्तु हो तथा दूसरी वस्तु निम्न मूल्य वाली हो।

प्रथम स्थिति में छोटा देश पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेगा परन्तु बड़ा देश पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं कर सकेगा। यदि बड़ा देश पूर्ण विशिष्टीकरण करता है तो छोटे देश में उसकी खपत सम्भव नहीं है। दूसरी ओर छोटा देश पूर्ण विशिष्टीकरण के पश्चात् भी बड़े देश की मांग को संतुष्ट नहीं कर सकता है। द्वितीय स्थिति में, उच्च मूल्य की वस्तु उत्पादित करने वाला देश पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त करने में समर्थ होगा जबकि निम्न मूल्य वाली वस्तु का उत्पादन करने वाला देश ऐसा नहीं कर सकेगा क्योंकि कम मूल्य वाली वस्तु के सम्पूर्ण निर्यात का मूल्य, उस देश की उच्च मूल्य की वस्तु की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। इस प्रकार, जब तक व्यापार में सम्मिलित देश समान आर्थिक आकार के न हों या व्यापारिक वस्तुएँ लगभग समान उपभोग मूल्य की न हों उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण सम्भव नहीं है।

11. इस सिद्धांत की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि यह सिर्फ 2 वस्तुओं और 2 देशों को लेकर विश्लेषण करता है। परन्तु दो से अधिक देशों तथा वस्तुओं के संदर्भ में भी इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया जा सकता है।
12. सिद्धांत की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है स्वतंत्र व्यापार की मान्यता पर आधारित है। यह मान्यता सिद्धांत को अवास्तविक बना सकती है परन्तु यह किसी भी तरह इसे अवैध नहीं बनाती; गैर स्वतंत्र व्यापार स्थिति में भी व्यापार-संतुलन को दिखाया जा सकता है।

3.8 मूल्यांकन

तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की इस आधार पर आलोचना कि इसकी मान्यताएँ वास्तविक जगत से मेल नहीं खाती हैं, बहुत उचित नहीं है। इनमें से अधिकांश मान्यताएँ सैद्धान्तिक सरलता के लिए ली गयी है।

एक तो विश्व की वास्तविकताएँ काफी जटिल हैं और दूसरे ये समय के साथ बदलती रहती है। सिद्धांत के पक्ष में यह बात उल्लेखनीय है कि आर्थिक सिद्धांत आदर्शों को वास्तविकता की ओर ले जाने की अपेक्षा वास्तविकता को आदर्शात्मक बनाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में, सिद्धांत यह बताता है कि आर्थिक नीति के उद्देश्य आदर्श स्थितियों को उत्पन्न करना और उन्हें वास्तविकता में परिवर्तित करना होना चाहिए और उन आदर्शों को पूरा करने के बाद सिद्धांत यह कहता है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के लिए हमें तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि आगे विश्व में संसाधनों का अत्यधिक अनुकूलतम आवंटन सुनिश्चित होगा तथा पूरे विश्व के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। इस आधार पर तुलनात्मक लाभ सिद्धांत आदर्शात्मक सिद्धांत हो जाता है, यह वर्णनात्मक की अपेक्षा निर्देशात्मक हो जाता है। यह सामान्य धनात्मक अर्थशास्त्र की अपेक्षा आदर्शात्मक कल्याण अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु बन जाता है।

स्मिथ व रिकार्डो यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रों के हित एक दूसरे से टकराएँ यह जरूरी नहीं है। वे विश्व के राष्ट्रों के बीच एक अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, यह दिखाकर कि कुछ व्यापार; व्यापार न होने से बेहतर है। राष्ट्रों के बीच व्यापार को प्रतिबंधित करने की अपेक्षा इसे प्रोत्साहित करना विश्व के उत्पादन में वृद्धि लायेगा तथा सार्वभौमिक कल्याण को अधिकतम करेगा। तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का यही संदेश था और अब भी है। सिद्धांत व्यापार के पक्ष में रहा है और स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है। अपनी सभी सीमाओं के बावजूद यह सिद्धांत समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यद्यपि इसमें काफी सुधार किये गए हैं, पर इसका मूल ढांचा वैसा ही है। सिद्धांत उल्लेखनीय रूप से अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है।

3.9 जे. एस. मिल का प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत

रिकार्डों ने अपने तुलनात्मक लागत सिद्धांत में यह दिखाया कि यदि व्यापार-शर्त रेखा दोनों व्यापाररत देशों की घरेलू कीमत रेखा के बीच में है तो दोनों ही देशों को व्यापार से लाभ होगा। परन्तु दो देशों की घरेलू विनिमय अनुपातों के बीच वास्तविक विनिमय अनुपात कहाँ निर्धारित होगा अर्थात् वास्तविक व्यापार शर्त रेखा का निर्धारण किस प्रकार होगा, इसका उत्तर रिकार्डों नहीं दे सके क्योंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री माँग-पक्ष की उपेक्षा कर देते हैं। इनके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त दो देशों में आन्तरिक लागत अनुपातों अर्थात् सिर्फ पूर्ति दशाओं द्वारा निर्धारित होती है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा एक देश के अंदर के सापेक्षिक लागत अनुपात के बराबर है तो उस देश को व्यापार से कोई लाभ नहीं होगा। इस प्रकार दो देशों के आन्तरिक लागत अनुपात, उच्चतम तथा निम्नतम सीमा का निर्धारण करते हैं। जिसके बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-शर्त रेखा हो सकती है।

परन्तु व्यापार-शर्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यापार किया जाता है, उनकी कीमते हैं और किसी भी अन्य कीमतों की तरह इसका निर्धारण की माँग और पूर्ति दोनों के द्वारा किया जाना चाहिए। स्मिथ और रिकार्डों माँग की दशाओं की उपेक्षा कर देते हैं इसलिए वास्तविक व्यापार-शर्त रेखा का निर्धारण नहीं कर पाते हैं। 1948 में जान स्टुअर्ट मिल ने वास्तविक व्यापार शर्त या विनिमय अनुपात के निर्धारण की समस्या का समाधान अपने प्रतिपूरक माँग सिद्धांत में किया। मार्शल तथा एजबर्थ ने प्रस्ताव वक्रों के माध्यम से मिल के सिद्धांत को आगे बढ़ाया।

संतुलित विनिमय दर के निर्धारण की व्याख्या के लिए जे. एस. मिल ने प्रतिपूरक माँग सिद्धांत का विकास किया। उन्होंने जोर दिया कि वास्तविक वस्तु विनिमय व्यापार शर्त केवल लागत दशाओं पर ही निर्भर नहीं करती है, जैसा कि रिकार्डों मान लेते हैं, बल्कि मूलतः यह माँग दशाओं पर भी निर्भर करती है। उनके अनुसार संतुलित व्यापार शर्त प्रतिपूरक माँग की दशाओं द्वारा निर्धारित होती है। प्रतिपूरक माँग का अर्थ है दो व्यापाररत देशों की अपने उत्पाद के पदों में एक-दूसरे के उत्पाद के लिए माँग की सापेक्षिक शक्ति तथा लोचा विनिमय का स्थिर अनुपात उस बिन्दु पर होगा जहाँ प्रत्येक देश आयातों व निर्यातों का मल्य संतुलन में हो।

जे. एस. मिल ने तुलनात्मक सिद्धांत की व्याख्या करते हुए उसमें संशोधन किया और यह बताया कि वास्तविक व्यापार-शर्त का निर्धारण कैसे और कहाँ होता है। मिल ने श्रम की एक दी हुई मात्रा से दो देशों में दो वस्तुओं के उत्पादन की तुलना के आधार पर तुलनात्मक लागत (लाभ) सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस प्रकार मिल का सिद्धांत तुलनात्मक लाभ या श्रम की क्षमता के रूप में है।

माना दो देश A और B हैं, जो संसाधनों की दी हुई मात्रा (जैसे एक श्रम वर्ष) से वस्तु X और Y का उत्पादन करते हैं। निम्नलिखित सारणी में दोनों देशों द्वारा व्यापार से पूर्व उत्पादन तथा उपभोग की स्थिति दी हुई है।

सारणी 3.7 संसाधनों की दी हुई मात्रा (जैसे एक श्रम वर्ष) से उत्पादन तथा उपभोग

	वस्तु X	वस्तु Y	घरेलू विनिमय अनुपात
देश A	250	150	250 X=150Y या $1x=0.6 y$
देश B	200	100	200X=100Y या $1x=0.5 y$
तुलनात्मक लागत अनुपात	200/250=.80	100/150=.66	

देश A दिए हुए संसाधनों से वस्तु X की 250 इकाई या Y की 150 इकाई का उत्पादन करता है जबकि देश B, X की 200 तथा Y की 100 इकाई का उत्पादन करता है। देश A दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में देश B की अपेक्षा निरपेक्ष लाभ की स्थिति में है। परन्तु तुलनात्मक लागत अनुपात से स्पष्ट है कि देश A में वस्तु X की उत्पादन लागत, देश B में वस्तु X की उत्पादन लागत की 0.80 % है। जबकि वस्तु Y की उत्पादन लागत देश A में देश B की अपेक्षा मात्र 66% है।

इस प्रकार देश A, वस्तु Y के उत्पादन में तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ की स्थिति में है जबकि देश B का वस्तु X के उत्पादन में तुलनात्मक हानि कम है। अतः देश A वस्तु Y के उत्पादन में और देश B वस्तु X के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा। देश A, वस्तु X के बदले Y का निर्यात करेगा जबकि देश B, Y के बदले X का निर्यात करेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात की संभावित सीमा का निर्धारण श्रम की क्षमता द्वारा स्थापित घरेलू विनिमय अनुपात के आधार पर होगा। सारणी 3.7 में दोनों देशों की घरेलू अनुपात रेखाएँ दी हुई हैं। 1 इकाई X के विनिमय की सीमा 0.5 तथा 0.6 के मध्य होगी। इस सीमा के भीतर वास्तविक व्यापार-शर्त का निर्धारण एक देश की वस्तु की दूसरे देश की माँग या प्रतिपूरक माँग की तीव्रता द्वारा होगा। संतुलित व्यापार शर्त रेखा पर दोनों देशों के आयात तथा निर्यात एक दूसरे के बराबर होंगे।

मार्शल व एजबर्थ ने मिल के प्रतिपूरक माँग सिद्धान्त की प्रभावी व्याख्या के लिए प्रस्ताव वक्रों की तकनीकी का विकास व प्रयोग किया। एक देश का प्रस्ताव वक्र आयातों की माँगों के बदले निर्यातों की देय मात्रा को व्यक्त करता है।

प्रस्ताव वक्र एक ओर किसी देश द्वारा वस्तु-विशेष की एक निश्चित मात्रा के बदले दूसरी वस्तु की एक निश्चित मात्रा देने की इच्छा को व्यक्त करता है और दूसरी ओर यह विभिन्न संभव व्यापार शर्तों या विनियम अनुपातों पर एक देश के उत्पाद के लिए माँग की इच्छा को व्यक्त करता है। इस प्रकार प्रस्ताव वक्र में माँग व पूर्ति दोनों की तत्व विद्यमान होते हैं।

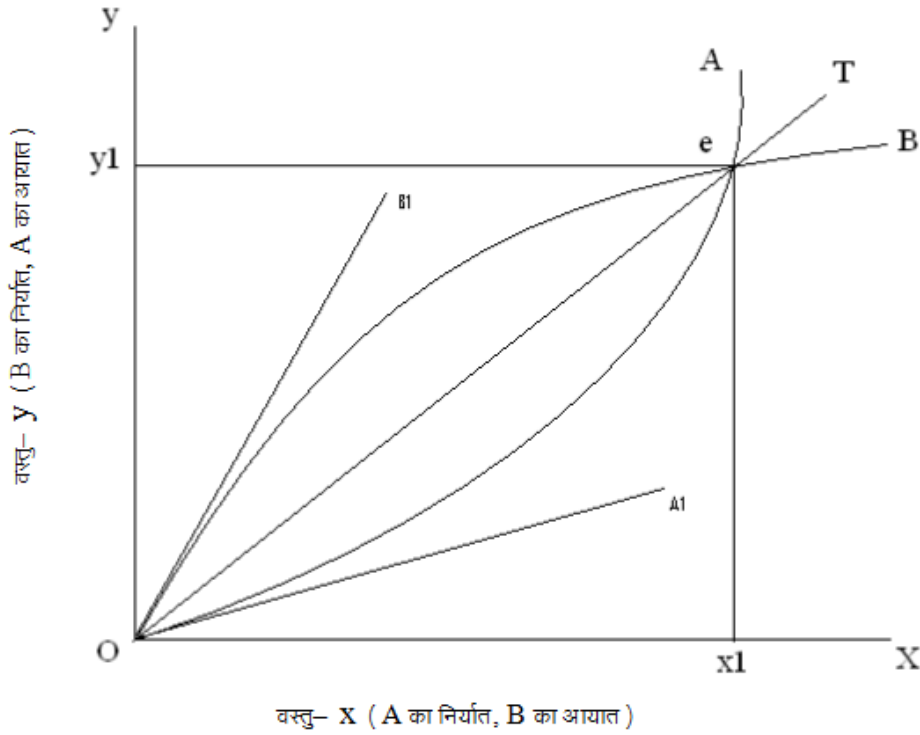
प्रस्ताव वक्र दोनों देशों में व्यापार न होने की दशा की व्यापार-शर्त या घरेलू कीमत-रेखाओं के भीतर ही स्थित होते हैं। प्रस्ताव वक्र उत्पादन व उपभोग दशाओं द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित होते हैं। ये दशाएँ ही व्यापाररत देशों के प्रस्ताव वक्र के आकार को निर्धारित करता है; प्रस्ताव वक्र के आकार आगे व्यापार-शर्त को निर्धारित करते हैं।

मान लिया विश्व में दो देश A व B तथा दो वस्तुएँ X व Y हैं; तब प्रतिपूरक माँग के नियम के अनुसार व्यापार-शर्त देश B के उत्पाद (वस्तु X) के लिए A की माँग तथा देश A के उत्पाद (वस्तु Y) के लिए देश B की माँग द्वारा निर्धारित होगी। दूसरे शब्दों में व्यापार-शर्त विदेशी वस्तुओं के लिए घरेलू माँग की तीव्रता और घरेलू वस्तु के लिए विदेशी माँग की तीव्रता द्वारा निर्धारित होती है। प्रस्ताव वक्र प्रतिपूरक माँग की लोच को प्रदर्शित करते हैं।

आयातों में प्रतिशत परिवर्तन

$$\text{प्रतिपूरक माँग की लोच} = \frac{\text{आयातों में प्रतिशत परिवर्तन}}{\text{(निर्यात की कीमतों में प्रतिशतपरिवर्तन/आयात की कीमतों में प्रतिशतपरिवर्तन)}}$$

देश A का प्रस्ताव वक्र देश B के उत्पाद Y के लिए उसकी माँग की तीव्रता को बताता है तथा देश B का प्रस्ताव वक्र देश A के उत्पाद X के लिए उसकी माँग की तीव्रता का दर्शाता है। संतुलित व्यापार-शर्त उस बिन्दु पर निर्धारित होती जहाँ दोनों प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को काटते हैं। चित्र 3.1 में OA देश A तथा OB देश B का प्रस्ताव वक्र है। दोनों प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को e बिन्दु पर काटते हैं। यही एक मात्र संतुलन बिन्दु है और मूल बिन्दु से खींची गयी रेखा OT संतुलित व्यापार शर्त रेखा है। जोकि e बिन्दु से होकर जाती है। केवल संतुलित व्यापार शर्त पर ही देश A से X का निर्यात देश B से X के आयात के बराबर होगा तथा देश A में Y का आयात देश B से Y के निर्यात के बराबर होगा। इस प्रकार, बाजार संतुलन में होगा। दूसरे शब्दों में e बिन्दु पर B के उत्पाद के लिए A की माँग A के उत्पाद के लिए की B की माँग के बिल्कुल बराबर है।



चित्र 3.1

यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-शर्त की रेखा दोनों देशों की घरेलू विनिमय अनुपात की रेखाओं OA_1 व OB_1 के मध्य A पर है तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को लाभ होगा।

व्यापार शर्त एक देश के पक्ष और दूसरे देश के विपक्ष में हो सकती है। यह इस पर निर्भर करता है कि संबंधित देश में मांग की सापेक्षिक लोच क्या है, इससे व्यापार से होने वाले कुल लाभ में उस देश का हिस्सा निर्धारित होता है।

स्पष्टतः बेलोच मांग (आयातों के लिए) वाले देश को दूसरे वस्तु की निश्चित मात्रा (आयातों) के लिए अधिक वस्तुएँ (निर्यात) देनी पड़ेगी। इस प्रकार व्यापार-शर्त उस देश के प्रतिकूल होगी। जब एक देश व्यापार-शर्त को दूसरे देश की घरेलू लागत अनुपात की ओर कर देने में सफल हो जाता है तो उसका अपना लाभ बढ़ जाता है।

3.10 अभ्यास हेतु प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न:

1. एडम स्मिथ के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये।
2. निरपेक्ष लाभ सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिये।
1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यताएं बताइए।
2. तुलनात्मक लागत सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

अति-लघु उत्तरीय प्रश्न:

1. एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम बताइये।
2. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया? सत्य व असत्य :

3. सारणी इंग्लैंड और पुर्तगाल के लागत दशाओं की तुलना दी गयी है , इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए -

देश	उत्पादन की लागत(श्रम घंटों में)	
	1 इकाई शराब	1 इकाई कपड़ा
पुर्तगाल	10	20
इंग्लैंड	15	25

- पुर्तगाल का घरेलू विनिमय अनुपात क्या है?
- इंग्लैंड का घरेलू विनिमय अनुपात क्या है?
- दो देशों का शराब के उत्पादन में तुलनात्मक लागत अनुपात?
- दो देशों का कपड़ा के उत्पादन में तुलनात्मक लागत अनुपात?
- पुर्तगाल को किस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टिकरण करना चाहिए?
- इंग्लैंड को किस वस्तु का निर्यात करना चाहिए?
- यदि अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात 1 इकाई कपड़ा = 1 इकाई शराब तो पुर्तगाल को व्यापार से होने वाले लाभ का मापन कीजिये।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

- रिकार्डों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक लागत में अंतर का कारण है?
 - लाभ में अंतर
 - तकनीकी प्रगति
 - उत्पादन की श्रम लागत में अंतर
 - उत्पादन की अन्य लागतों में अंतर
- निम्नलिखित में से कौन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यता नहीं है?
 - उत्पादन में पैमाने के स्थिर प्रतिफल की स्थिति नहीं है।
 - दोनों देशों में पूर्ण रोजगार है तथा पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पायी जाती है।
 - उत्पादन के साधन देश के भीतर पूर्णरूप से गतिशील तथा देशों के मध्य पूर्णरूप से अगतिशील हैं।
 - श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है।
- प्रतिपूरक मांग का अर्थ है
 - दो व्यापाररत देशों की अपने उत्पाद के पदों में एक-दूसरे के उत्पाद के लिए मांग की सापेक्षिक शक्ति तथा लोच।
 - देश B के उत्पाद (वस्तु X) के लिए A की मांग तथा देश A के उत्पाद (वस्तु Y) के लिए देश B की मांग
 - विदेशी वस्तुओं के लिए घरेलू मांग की तीव्रता और घरेलू वस्तु के लिए विदेशी मांग की तीव्रता
 - उपरोक्त सभी
- निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ?
 - प्रस्ताव वक्र प्रतिपूरक मांग की लोच को प्रदर्शित करते हैं।
 - प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री माँग-पक्ष की उपेक्षा कर देते हैं।
 - मिल का सिद्धांत तुलनात्मक लाभ या श्रम की क्षमता के रूप में है।
 - संतुलित व्यापार शर्त रेखा पर दोनों देशों के आयात तथा निर्यात एक दूसरे के बराबर होंगे।

v. उपरोक्त में से कोई नहीं

सत्य व असत्य:

1. स्मिथ और रिकार्डो की विचारधारा के केन्द्र में व्यक्ति हैं।
2. स्मिथ के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार तभी होता है जब लागतों में निरपेक्ष अंतर नहीं हो।
3. प्रतिष्ठित सिद्धांत से पूर्व आधुनिक राष्ट्र राज्य के विकास के दौरान 17वीं तथा 18 वीं शताब्दी में वणिकवादी विचारधारा थी।
4. लागतों में समान अंतर होने पर भी व्यापार होगा।
5. वणिकवादी विनियमित, नियन्त्रित तथा प्रतिबंधित व्यापार नीति के पक्ष में नहीं थे।
6. वास्तविक जगत में न तो उत्पादन में स्थिर लागत की स्थिति और न ही किसी देश में पूर्ण विशिष्टीकरण की स्थिति पायी जाती है।
7. परिवहन लागतों व अन्य सम्बन्धित लागतों को जोड़कर कुल लागत के पदों में तुलनात्मक लाभों को पुनः परिभाषित करना सम्भव है।
8. तुलनात्मक सिद्धांत मूलतः एक स्थैतिक विश्लेषण है।
9. प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यह बताने में सफल रहे कि विभिन्न देशों के उत्पादन फलन भिन्न-भिन्न क्यों होते हैं।
10. तुलनात्मक सिद्धांत में उपभोक्ता की रुचि, उत्पादन फलन, उत्पादन के साधनों की मात्रा आदि को स्थिर नहीं माना गया है।

3.11 सारांश

एडम स्मिथ ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के निर्माण की आधारशिला रखी। परन्तु डेविड रिकार्डो ने एडम स्मिथ के सिद्धांत को और स्पष्ट किया, इसका विस्तार किया तथा इसे वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत को रिकार्डो द्वारा प्रस्तुत तुलनात्मक लागत सिद्धांत या तुलनात्मक लाभ सिद्धांत द्वारा जाना जाता है। बाद में जान स्टुअर्ट मिल ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत में मांग पक्ष को सम्मिलित कर प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत दिया। एडम स्मिथ ने लागतों में निरपेक्ष अंतर के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यदि एक देश को एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लागत लाभ तथा दूसरे वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष हानि हो तो फिर व्यापार होगा। प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसके उत्पादन में निरपेक्ष लागत लाभ होगा और उस वस्तु का आयात करेगा जिसके उत्पादन में निरपेक्ष लागत हानि होगी। रिकार्डो यह दिखाते हैं की यदि एक देश को दूसरे देश की अपेक्षा किसी भी वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लागत लाभ नहीं है तब भी व्यापार होगा। उनके अनुसार एक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा और निर्यात करेगा जिसमें उसे अधिकतम तुलनात्मक लागत लाभ या न्यूनतम तुलनात्मक लागत हानि हो। इसी प्रकार देश उस वस्तु का आयात करेगा जिसमें उसे तुलनात्मक लागत लाभ न्यूनतम या तुलनात्मक लागत हानि अधिकतम हो। जे. एस. मिल ने तुलनात्मक सिद्धांत की व्याख्या करते हुए उसमें संशोधन किया और अपने प्रतिपूरक मांग सिद्धांत में यह बताया कि वास्तविक व्यापार-शर्त का निर्धारण कैसे और कहाँ होता है। मार्शल तथा एजबर्थ ने प्रस्ताव वक्रों के माध्यम से मिल के सिद्धांत को आगे बढ़ाया।

3.12 शब्दावली

- **मूल्य का श्रम सिद्धांत** - इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य-निर्धारण उस वस्तु में निहित श्रम की मात्रा के द्वारा होता है। यह सिद्धांत रिकार्डो द्वारा दिया गया निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है
 1. श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है।
 2. सभी श्रम समरूप इकाईयाँ हैं।
 3. देश के भीतर श्रम पूर्णतया गतिशील हैं।
 4. श्रम बाजार में पूर्ण-प्रतियोगिता है।

श्रम के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अगतिशील होने के कारण यह सिद्धांत घरेलू व्यापार के संदर्भ में तो लागू होता है पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में विघटित हो जाता है।

- **लागतों का निरपेक्ष अन्तर** - कुछ देश कुछ विशेष प्राकृतिक सुविधाओं के अधिक मात्र में उपलब्ध होने के कारण कुछ वस्तुओं का उत्पादन अन्य देशों की अपेक्षा कम लागत पर कर सकते हैं। लागत के इस अंतर को निरपेक्ष अंतर कहते हैं। माना दो देश X तथा Y हों, जो दो वस्तुओं का A तथा B उत्पादन करते हों, यदि देश X में A की श्रम लागत X_a तथा B की श्रम लागत X_b तथा देश Y में क्रमशः Y_a तथा Y_b हो तो लागत के निरपेक्ष अंतर निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है:

$$\frac{X_a}{X_b} < 1 > \frac{Y_a}{Y_b}$$

अर्थात् देश X को A वस्तु के उत्पादन में तथा देश Y को B के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है। एक देश की एक वस्तु के उत्पादन में लागत कम है तथा दूसरे देश की दूसरे वस्तु के उत्पादन में लागत कम है, अर्थात् एक देश को एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ तथा दूसरी वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष हानि हो। लागतों में तुलनात्मक अन्तर-यदि एक देश की उत्पादन लागत दोनों ही वस्तु के संदर्भ में दूसरे देश से कम हो तो, उसे दोनों ही वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में यह देखना होगा कि वह देश किस वस्तु के उत्पादन में अधिक दक्ष है अर्थात् उसकी तुलनात्मक लागत कम है तथा दूसरे देश की किस वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक हानि कम है।

उपरोक्त उदाहरण से लागत के सापेक्ष अंतर को निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है:

$$\frac{X_a}{X_b} < 1 > \frac{Y_a}{Y_b} < 1$$

अर्थात् देश X को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में देश Y की अपेक्षा निरपेक्ष लाभ है परन्तु वस्तु A के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ वस्तु B की अपेक्षा अधिक है।

- **प्रतिपूरक मांग** - प्रतिपूरक मांग का अर्थ है दो व्यापाररत देशों की अपने उत्पाद के पदों में एक-दूसरे के उत्पाद के लिए मांग की सापेक्षिक शक्ति तथा लोच। अर्थात् विदेशी वस्तुओं के लिए घरेलू मांग की तीव्रता और घरेलू वस्तु के लिए विदेशी मांग की तीव्रता।
- **प्रस्ताव वक्र** - प्रस्ताव वक्र एक ओर किसी देश द्वारा वस्तु-विशेष की एक निश्चित मात्रा के बदले दूसरी वस्तु की एक निश्चित मात्रा देने की इच्छा को व्यक्त करता है और दूसरी ओर यह विभिन्न संभव व्यापार शर्तों या विनियम अनुपातों पर एक देश के उत्पाद के लिए मांग की इच्छा को व्यक्त करता है।

3.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अति-लघु उत्तरीय प्रश्न:

1. एन इन्क्वायरी इनटू नेचर एंड काजेज आफ वेल्थ आफ नेशंस , 2.डेविड रिकार्डो 3 i. 1 इकाई शराब = 0.5 इकाई कपड़ा, ii.1 इकाई शराब = 0.6 इकाई कपड़ा iii. $10/15= 0.66$, iv. $20/25= 0.80$, V.शराब , vi.कपड़ा , vii.0.5 इकाई कपड़ा vi. 0.4 इकाई कपड़ा

बहुविकल्पीय प्रश्न:

1. iii , 2.i 3. iv , 4.v

सत्य व असत्य:

1. सत्य ,2.सत्य,3.सत्य,4.असत्य 5.असत्य 6. सत्य 7.असत्य ,8.सत्य ,9.असत्य ,10.असत्य

3.14 संदर्भ ग्रंथ सूची

- HH. G. Mannur, International Economics , Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Bo Sodersten, International Economics ,Macmillan, 1999
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: International Economics: Theory and Policy, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- Charles P Kindleberger, International Economics, Richard D. Irwin Inc., Illinois, 1968
- Dominik Salvatore, International Economics, John Willy & Sons, Inc., 2008
- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006
- सुदामा सिंह एवं एम0सी0 वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड एंड आई0बी0एच0 पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम0एल0 झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010।
- ज्ञानेंद्र सिंह कुशवाहा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1979।

3.15 उपयोगी/सहायक ग्रंथ

- HH. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Bo Sodersten, International Economics ,Macmillan, 1999
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: International Economics: Theory and Policy, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- Charles P Kindleberger, International Economics, Richard D. Irwin Inc., Illinois, 1968
- Dominik Salvatore, International Economics, John Willy & Sons, Inc., 2008

- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House,
- Mumbai, 2006 • एस. एन. लाल, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद, 2004
- एच. एस. अग्रवाल, तथा सी. एस. बरला, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2003
- सुदामा सिंह एवं एम0सी0 वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड एंड आई0बी0एच0 पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम0एल0झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010.
- डॉ. जी. सी. सिंघई एवं डॉ. जे. पी. मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा, 2010

3.16 निबंधात्मक प्रश्न

1. प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
2. रिकार्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का विस्तृत विवेचन करते हुए इसकी कमियों का वर्णन कीजिए।
3. तुलनात्मक लागत व्यापार सिद्धांत की मान्यताएँ अवास्तविक है, इसलिए यह सिद्धांत अवैध है। विवेचना कीजिए।
4. जे.एस. मिल के प्रतिपूरक मांग के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिये।

इकाई 4 - अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत (Neo-Classical Theory of International Trade)

- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 उद्देश्य
- 4.3 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत - भूमिका
- 4.4 उत्पादन में स्थिर प्रतिफल या स्थिर लागतों के अंतर्गत व्यापार संतुलन
- 4.5 उत्पादन में हासमान प्रतिफल या वृद्धिमान लागतों के अंतर्गत व्यापार संतुलन
- 4.6 उत्पादन में वृद्धिमान प्रतिफल या हासमान लागतों के अंतर्गत व्यापार संतुलन
- 4.7 एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धिमान प्रतिफल तथा दूसरी वस्तु के उत्पादन में हासमान प्रतिफल के अंतर्गत व्यापार संतुलन
- 4.8 मूल्यांकन
- 4.9 विनिमय से लाभ तथा विशिष्टीकरण से लाभ
- 4.10 अभ्यास हेतु प्रश्न
- 4.11 सारांश
- 4.12 शब्दावली
- 4.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 4.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 4.15 उपयोगी/ सहायक पाठ्य सामग्री
- 4.16 निबंधात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

इससे पहले की इकाईयों के अध्ययन के पश्चात् आप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत तथा प्रतिपूरक मांग के सिद्धांत के बारे में बता सकते हैं। आप जान गए होंगे की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण क्या है तथा उससे होने वाला लाभ कैसे मापा जा सकता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार जब तक श्रम लागतों का अंतर विद्यमान है व्यापार देशों को व्यापार से लाभ होगा। परन्तु श्रम के अतिरिक्त दूसरे साधन भी उत्पादन में उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हैबरलर ने अवसर लागत के रूप में लागतों का मापन करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत दिया। अवसर लागत व उत्पादन संभावना वक्र के साथ समुदाय अधिमान वक्रों के प्रयोग के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नव-प्रतिष्ठित सिद्धांत विकसित किया गया, जिसमें हैबरलर, लियोटीफ, लर्नर, मार्शल, एजबर्थ और मीड का योगदान है।

प्रस्तुत इकाई में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताया गया है। जोकि हैबरलर द्वारा दिया गया है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नव प्रतिष्ठित सिद्धांत के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

4.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप

- ✓ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नव प्रतिष्ठित सिद्धांत को समझ सकेंगे।
- ✓ उत्पादन में स्थिर लागतों के अंतर्गत अवसर लागत सिद्धांत या व्यापार संतुलन के बारे में जान सकेंगे।
- ✓ उत्पादन में बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत व्यापार संतुलन या अवसर लागत सिद्धांत के बारे में जान सकेंगे।
- ✓ उत्पादन में घटती हुई लागतों के अंतर्गत व्यापार संतुलन या अवसर लागत सिद्धांत के बारे में जान सकेंगे।
- ✓ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विनिमय तथा विशिष्टीकरण से होने वाले लाभों को जान सकेंगे।

4.3 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत - भूमिका

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के शुद्ध सिद्धांत में यह दिखाने का प्रयास किया कि व्यापार सभी व्यापार देशों के लिए लाभदायक है। स्मिथ के मॉडल में व्यापार सम्भव तभी है जब एक देश को एक वस्तु के उत्पादन में और दूसरे देश को दूसरे वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है। परन्तु रिकार्डो ने अपने तुलनात्मक लागत सिद्धांत में यह दिखाया कि यदि एक देश दूसरे देश की अपेक्षा दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ की स्थिति में हो तब भी व्यापार हो सकता है। यदि एक देश को एक वस्तु के उत्पादन में अत्यधिक तुलनात्मक लाभ तथा दूसरे देश को दूसरी वस्तु के उत्पादन में अत्यधिक तुलनात्मक हानि प्राप्त है तो भी व्यापार सम्भव है। यह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की एक महान उपलब्धि है क्योंकि तुलनात्मक लागत सिद्धांत की वैधता सार्वभौमिक है।

परन्तु तुलनात्मक लागत सिद्धांत के मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित होने के कारण कटू आलोचना की जाती है। परन्तु मूल्य का श्रम सिद्धांत अनेक दुर्बल तथा त्रुटिपूर्ण मान्यताओं पर आधारित होने के कारण अर्थशास्त्रियों द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है। वास्तव में, व्यवहारिक जगत में श्रम एक समरूप साधन नहीं है। श्रम कई अप्रतियोगी समूहों में बँटा होता है। जिसके मध्य मजदूरी के समान होने की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे, एक खेत में काम करने वाले मजदूर, आफिस में काम करने वाले क्लर्क तथा एक कम्पनी के प्रबन्धक, तीनों की अलग-अलग श्रेणियाँ हैं, जो कि अप्रतियोगी हैं, इनकी मजदूरी के समान होने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसके

अतिरिक्त वस्तुओं का उत्पादन केवल श्रम का ही नहीं बल्कि उत्पादन के अन्य साधनों भूमि, श्रम, पूँजी और उद्यमिता के भी संयोग से होता है।

परन्तु यदि हम मूल्य के श्रम सिद्धांत को अस्वीकार दें, तब भी रिकार्डों के तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का निष्कर्ष, कि यदि तुलनात्मक लाभ के आधार पर व्यापाररत दो देश विशिष्टीकरण करते हैं तो इससे विश्व के सकल घरेलू उत्पाद तथा आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी, प्रभावित नहीं होगा। इस प्रकार का प्रयास सबसे पहले 1936 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैबरलर ने किया। हैबरलर ने वास्तविक लागत सिद्धांत के विकल्प के रूप में 'अवसर लागत का सिद्धांत' प्रस्तुत किया। और जब तुलनात्मक लाभ को अवसर लागत रूप के रूप में परिभाषित किया जाता है तो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उत्पादन सिर्फ श्रम से हो रहा है या श्रम के साथ सभी उत्पादन के साधनों के संयोग से। हैबरलर का मानना है कि लागतों का अर्थ वस्तु के उत्पादन में निहित श्रम की मात्रा से नहीं बल्कि वस्तु के उत्पादन के लिए किए गए वैकल्पिक उत्पादन के त्याग अर्थात् अवसर लागत से है। हैबरलर इस बात को जोर देकर कहते हैं कि मूल्य के श्रम सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य दो व्यापाररत देशों में, प्रत्येक में एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु के पदों में निर्धारित करना था।

इस प्रकार अवसर लागत के पदों में एक वस्तु की उत्पादन लागत उस वस्तु के मूल्य के बराबर होगी जिसका त्याग विचाराधान वस्तु के उत्पादन के लिए किया गया है। वस्तु X की अवसर लागत, वस्तु Y की वह मात्रा है जो कि वस्तु X की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए त्यागनी पड़ती है। इस प्रकार दो वस्तुओं के मध्य विनिमय अवसर लागत के रूप में होता है, जिसकी व्याख्या उत्पादन संभावना वक्र के साथ की जा सकती है।

अवसर लागत व उत्पादन संभावना वक्र के साथ समुदाय अधिमान वक्रों के प्रयोग के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नव-प्रतिष्ठित सिद्धांत विकसित किया गया, जिसमें हैबरलर, लियोटीफ़, लर्नर, मार्शल, एजबर्थ और मीड का योगदान है। विशेषरूप से मीड ने आधुनिक ज्यामितीय तकनीकी की मदद से तुलनात्मक लागत के नवप्रतिष्ठित सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान किया।

नव प्रतिष्ठित व्यापार सिद्धांत में मूल्य के श्रम सिद्धांत को त्यागने के साथ-साथ उत्पादन की अलग-अलग दशाओं में व्यापार-संतुलन की व्याख्या करता है। जबकि प्रतिष्ठित सिद्धांत उत्पादन के स्थिर प्रतिफल के अंतर्गत ही व्यापार-संतुलन की व्याख्या करता है।

प्रतिफल के तीन नियमों के अनुरूप नवप्रतिष्ठित व्यापार सिद्धांत, निम्नलिखित तीन स्थितियों में व्यापार-संतुलन की व्याख्या करता है

1. जब उत्पादन में स्थिर पैमाने का प्रतिफल हो, अथवा जब उत्पादन में सीमान्त अवसर लागतें स्थिर हों।
2. जब उत्पादन में घटते हुए प्रतिफल या बढ़ती हुई सीमान्त अवसर लागतों की स्थिति हो।
3. जब उत्पादन में बढ़ते हुए प्रतिफल या घटती हुई सीमान्त अवसर लागत की स्थिति हो।

4.4 उत्पादन में स्थिर प्रतिफल या स्थिर लागतों के अन्तर्गत व्यापार संतुलन

उत्पादन में स्थिर प्रतिफल या स्थिर लागतों की स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा होगा। अर्थात् एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु की त्याग की गयी मात्रा सदैव स्थिर रहेगी।

माना दो देश A और B तथा दो वस्तुएँ A और B हैं। दोनों देशों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ की संभावना तब होगी। जबकि दोनों देशों में उत्पादन संभावना वक्र का ढाल असमान होगा अर्थात् लागतों में तुलनात्मक भिन्नता की स्थिति होगी।

माना देश A का उत्पादन संभावना वक्र A_1A_2 तथा देश B का B_1B_2 है। देश A को X वस्तु तथा देश B को Y वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है।

देश A के उत्पादन संभावना वक्र A_1A_2 से स्पष्ट है कि वह साधनों की दी हुई मात्रा से या तो OA_1 मात्रा में वस्तु X या OA_2 मात्रा में वस्तु Y का उत्पादन कर सकता है या A_1A_2 वक्र पर स्थित X और संभावित संयोग का उत्पादन कर सकता है। इसी प्रकार देश B दिए हुए साधनों से OB_2 मात्रा में वस्तु X या OY_1 मात्रा में वस्तु Y का उत्पादन कर सकता है या BB रेखा पर स्थित दोनों का कोई संभावित संयोग उत्पादित कर सकता है।

व्यापार की अनुपस्थिति में देश A, वक्र A_1A_2 के e बिन्दु पर, तथा देश B वक्र B_1B_2 के f बिन्दु पर उत्पादन तथा उपभोग कर रहे हैं। बिन्दु e पर देश A के उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों संतुलन में है क्योंकि e बिन्दु पर

उत्पादन संभावना वक्र A_1A_2 की ढाल = समुदाय अधिमान वक्र ICA_1 की ढाल = कीमत रेखा A_1A_2 का ढाल (रेखा A_1A_2 देश A की घरेलू कीमत रेखा को भी दर्शाती है)

अर्थात्

$$MRTS_{xy} = MRS_{xy} = \frac{P_y}{P_x}$$

अर्थात्

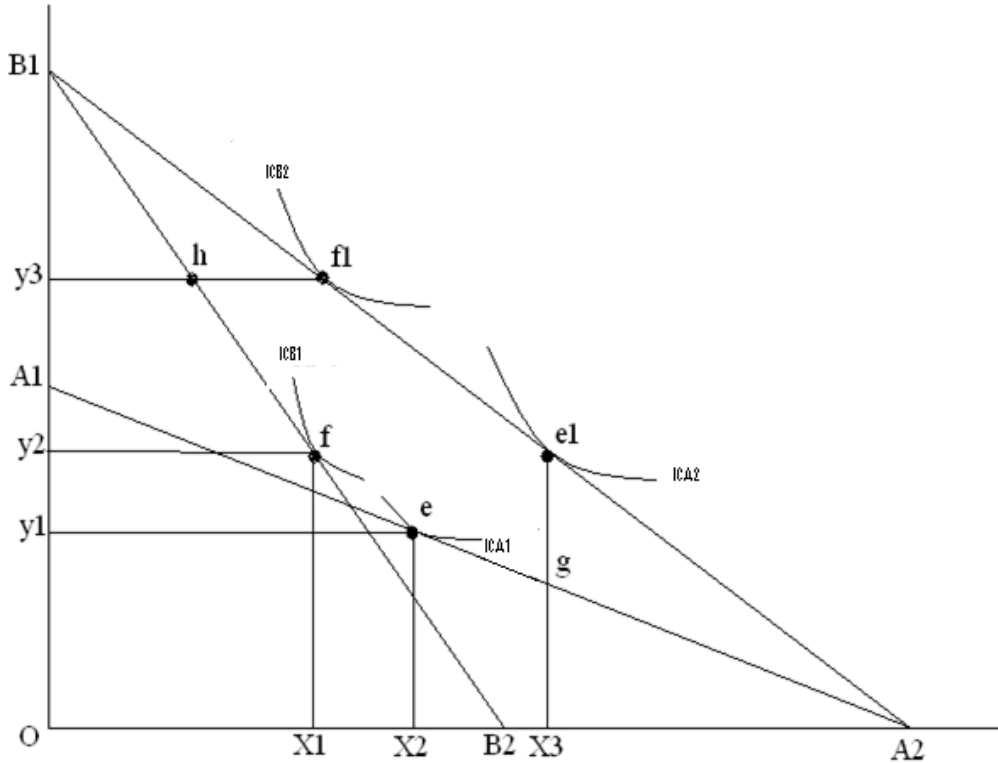
उत्पादन में तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर = उपभोग में सीमांत प्रतिस्थापन की दर = वस्तु कीमत अनुपात

इसी प्रकार बिन्दु f पर देश B में उत्पादन और उपभोग दोनों का एक साथ संतुलन में है क्योंकि f बिन्दु पर, उत्पादन संभावना वक्र B_1B_2 की ढाल = समुदाय अधिमान वक्र ICB_1 की ढाल = कीमत रेखा (B_1B_2) का ढाल।

व्यापार न होने की दशा में दोनों ही देशों के लिए यह सम्भव नहीं है कि वे अपने उत्पादन संभावना वक्र के बाहर के किसी बिन्दु को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार बिन्दु e पर, देश A में और बिन्दु f पर देश B में उत्पादन के सभी संसाधन रोजगार में लगे हैं। दोनों बिन्दु संबन्धित देशों में उत्पादन तथा उपभोग या आर्थिक कल्याण के उच्चतर स्तरों को व्यक्त करते हैं।

व्यापार के पश्चात् देश A वस्तु X के उत्पादन में तथा देश B, वस्तु Y के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा। इस प्रकार देश A अपने समस्त साधनों के प्रयोग से OA_2 मात्रा में X वस्तु का उत्पादन करेगा; जबकि देश B अपने सभी संसाधन Y वस्तु के उत्पादन में लगा देगा और OB_1 मात्रा में Y का उत्पादन करेगा। A देश, व्यापार के पश्चात् A_2 बिन्दु पर तथा B देश B_1 बिन्दु पर उत्पादन करेगा।

पूर्ण विशिष्टीकरण के पश्चात् दोनों देश अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात या व्यापार-शर्त रेखा के अनुरूप आपस में व्यापार करेंगे। दोनों देशों को व्यापार से लाभ तभी होगा जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा दोनों देशों की घरेलू कीमत रेखा के बीच हो। चित्र 4.1 में रेखा B_1A_2 दोनों घरेलू कीमत रेखा के लगभग बीच में है। अतः व्यापार से A और B दोनों ही देशों को लाभ होगा। दोनों देश आपस में कितना व्यापार करेंगे या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार-शर्त रेखा पर वास्तव में उपभोग का संतुलन कहाँ होगा, यह दोनों देशों के उपभोक्ताओं की रुचियों की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा।



चित्र 4.1 स्थिर लागतों के अन्तर्गत व्यापार संतुलन

व्यापार के पश्चात् उपभोक्ताओं की रुचियाँ दी हुई होने पर देश के उपभोक्ता अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा पर e_1 बिन्दु पर संतुलन में होंगे, जहाँ उसका समुदाय अधिमान वक्र ICA_2 स्पर्श कर रहा है, जबकि B देश के उपभोक्ता f बिन्दु पर संतुलन में होंगे, जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा उसके समुदाय अधिमान वक्र ICB_2 को स्पर्श कर रही है।

देश A को व्यापार से लाभ

$$= eX_3 - gX_3$$

$$= e_1g \text{ इकाई वस्तु}$$

देश B को व्यापार से लाभ

$$= f_1y_3 - hy_3$$

$$= fh \text{ इकाई वस्तु-X}$$

व्यापार के पश्चात् देश A, बिन्दु A_2 पर उत्पादन कर रहा है जबकि e_1 बिन्दु पर उपभोग कर रहा है। देश A, OA_2 मात्रा X का उत्पादन करता है, परन्तु OX_3 मात्रा का उपभोग करता है और बाकी X_3A_2 मात्रा देश B को निर्यात कर देता है जिसके बदले में वह वस्तु Y की e_1x_3 मात्रा देश B से आयात करता है। स्पष्ट है कि व्यापार के पश्चात् देश A, X और Y दोनों ही वस्तुओं का पहले से अधिक उपभोग कर रहा है।

व्यापार से पूर्व e बिन्दु पर वह X की OX_2 , तथा y की Oy_1 मात्रा का उपभोग कर रहा था, जबकि व्यापार के बाद 1 बिन्दु पर X की OX_3 ($> OX_2$) तथा y की eX_1 ($> Oy_1$) का उपभोग कर रहा है। व्यापार के पश्चात् देश A निचले समुदाय अधिमान वक्र ICA_1 के बिन्दु e से, ऊँचे अधिमान वक्र ICA_2 के बिन्दु 1 पर संतुलन में है जो कि उसके उपभोग या आर्थिक कल्याण के बढ़े हुए स्तर को व्यक्त करता है।

देश B व्यापार के पश्चात् B_1 बिन्दु पर उत्पादन तथा f बिन्दु पर उपभोग कर रहा है। वह y वस्तु के कुल OB_1 उत्पादन में से Oy_3 मात्रा का उपभोग करता है, बाकी B_1y_3 मात्रा, देश A को निर्यात कर देता है जिसके

बदले में वह YF_1 मात्रा वस्तु X का देश A से आयात करता है। व्यापार से पूर्व वह Y वस्तु की OY तथा X वस्तु OX_1 मात्रा का उपभोग करता था, जबकि व्यापार के पश्चात् वह Y वस्तु की $OY_3 (>OY_2)$ तथा X वस्तु की $Y_3f_1 (>Y_2f)$ मात्रा का उपभोग करता है। स्पष्ट है कि व्यापार के पश्चात् वह ICB_1 समुदाय अधिमान वक्र से और ऊँचे अधिमान वक्र ICB_2 पर चला जाता है, जो कि उसके बढ़े हुए उपभोग या आर्थिक कल्याण के स्तर को व्यक्त करता है।

स्पष्ट है कि व्यापार के पश्चात् दोनों ही व्यापाररत देशों के लिए यह सम्भव हो पा रहा है कि वह अपने उत्पादन संभावना वक्र की सीमा से इतर किसी बिन्दु पर जा सके, व्यापार से पहले यह सम्भव नहीं था। चित्र 4.1 में बिन्दु e तथा f क्रमशः देश A तथा B के उत्पादन संभावना वक्र की सीमा से काफी ऊपर है। व्यापार के पश्चात् दोनों ही देश, दोनों ही वस्तुओं का पहले से अधिक उपभोग कर रहे हैं।

व्यापार के पश्चात् कुल विश्व उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है। व्यापार से पूर्व वस्तु X का कुल उत्पादन $=OX_1$ (देश B का उत्पादन) $\times OX_2$ (देश A का उत्पादन) है, जोकि व्यापार के पश्चात् के कुल उत्पादन OA_2 की अपेक्षा कम है। इसी प्रकार वस्तु Y का व्यापार के पश्चात् का उत्पादन (OB_1) व्यापार के पूर्व के उत्पादन $(OY_1 \times OY_2)$ से अधिक है। स्थिर अवसर लागत की स्थिति में जबकि दोनों देश समान आर्थिक आकार के हों निरपेक्ष लाभ सिद्धांत के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलन को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।

4.5 उत्पादन में हासमान प्रतिफल या वृद्धिमान लागतों के अंतर्गत व्यापार संतुलन

यदि दोनों देशों में, दोनों वस्तुओं के उत्पादन में सीमान्त अवसर लागत बढ़ती हुई हो, तो दोनों देशों के उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिन्दु के प्रति अवतल होगा। इकाई-2 के अध्ययन बाद आप परिचित हो गए होंगे कि यदि उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिन्दु के प्रति अवतल है तो उत्पादन में घटता हुआ प्रतिफल प्राप्त होता है। माना दो देश A और B हैं, जो कि समान आर्थिक आकार के हैं। वे दो वस्तुओं X और Y का उत्पादन करते हैं। देश A, वस्तु X के उत्पादन में और देश B, वस्तु Y के उत्पादन में अधिक दक्ष है। A देश का उत्पादन संभावना वक्र A_1A_2 तथा देश B का B_1B_2 है।

व्यापार से पूर्व दोनों देश अपने-अपने उत्पादन संभावना वक्र के उस बिन्दु पर संतुलन में हैं जहाँ घरेलू कीमत रेखा या लागत अनुपात उत्पादन संभावना वक्र तथा समुदाय अधिमान वक्र को स्पर्श करती है। चित्र 4.2 (A) तथा (B) में, देश A के उत्पादन तथा उपभोग का संतुलन बिन्दु e तथा देश B का बिन्दु f पर है।

बिन्दु e पर,

देश A की घरेलू कीमत रेखा A_0A_0 का ढाल = उत्पादन संभावना वक्र A_1A_2 की ढाल = समुदाय अधिमान वक्र ICA_0 की ढाल

अर्थात्

$$\frac{P_y}{P_x} = MRTS_{XY}$$

बिन्दु f पर,

देश B की घरेलू कीमत रेखा B_0B_0 का ढाल = B के उत्पादन संभावना वक्र B_1B_2 का ढाल = समुदाय अधिमान वक्र ICB_0 की ढाल

अर्थात्

$$\frac{P_y}{P_x} = = RTS_{XY} = MRS_X$$

व्यापार न होने की स्थिति में, यह दोनों बिन्दु e और f देशों के अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार तथा अधिकतम संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करता है क्योंकि दोनों ही बिन्दु (e तथा f) देश A तथा B के उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित है। बिन्दु e तथा f पर वस्तु तथा साधन बाजार दोनों संतुलन की स्थिति में है। प्रत्येक देश में, साधन बाजार में प्रत्येक साधन का मूल्य उसकी सीमान्त उत्पादन के बराबर है तथा वस्तु बाजार में कीमत अनुपात, सीमान्त लागत अनुपात के बराबर है।

कीमत रेखा A_0A_0 देश A में दो वस्तुओं के आन्तरिक लागत अनुपातों को व्यक्त करती है। इसी प्रकार B_0B_0 देश B में दोनों वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों या लागत अनुपातों को दर्शा रही है। A_0A_0 रेखा अधिक चपटी है जो कि देश A में Y वस्तु की अधिक इकाई लागत तथा X वस्तु के उत्पादन की कम इकाई लागत को व्यक्त करती है। B_0B_0 रेखा अधिक तिरछी है, जो कि देश B में X वस्तु की अधिक इकाई तथा Y वस्तु के उत्पादन की कम इकाई लागत को व्यक्त करती है। दो देशों में दो वस्तुओं के उत्पादन की सापेक्षिक लागतों में अन्तर व्यापार की संभावना को जन्म देता है। वस्तुओं के तुलनात्मक सस्तेपन के कारण लाभदायक व्यापार के लिए पर्याप्त अवसर है। स्पष्ट है कि देश A को X वस्तु तथा देश B को Y वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण हासिल करना चाहिए।

व्यापार शुरू होने के पश्चात् दोनों ही देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा (T_0T_0) के अनुरूप अपने उत्पादन के संसाधनों को दो वस्तुओं के उत्पादन में पुनर्आवंटित करेंगे। उत्पादन का संतुलन उस बिन्दु पर होगा जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय कीमत रेखा T_0T_0 , संबंधित देश के उत्पादन संभावना वक्र को स्पर्श करती है। चित्र 4.2 में, देश A का उत्पादन का संतुलन g बिन्दु पर होगा, जहाँ, T_0T_0A , A_1A_2 को स्पर्श करती है।

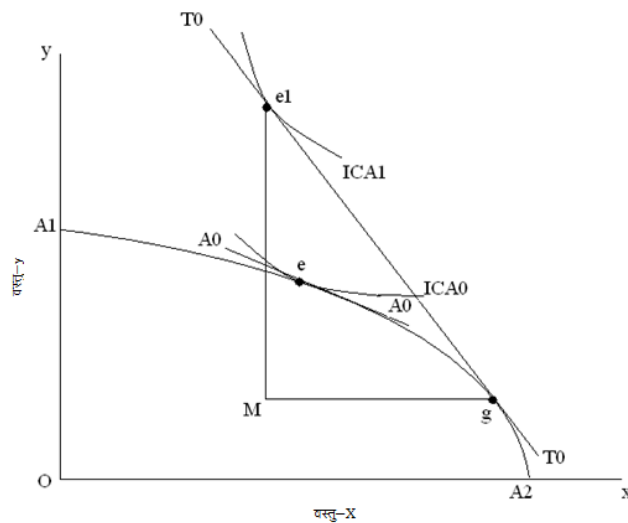
अर्थात्

अन्तर्राष्ट्रीय कीमत रेखा T_0T_0 का ढाल = उत्पादन संभावना वक्र A_1A_2 का ढाल

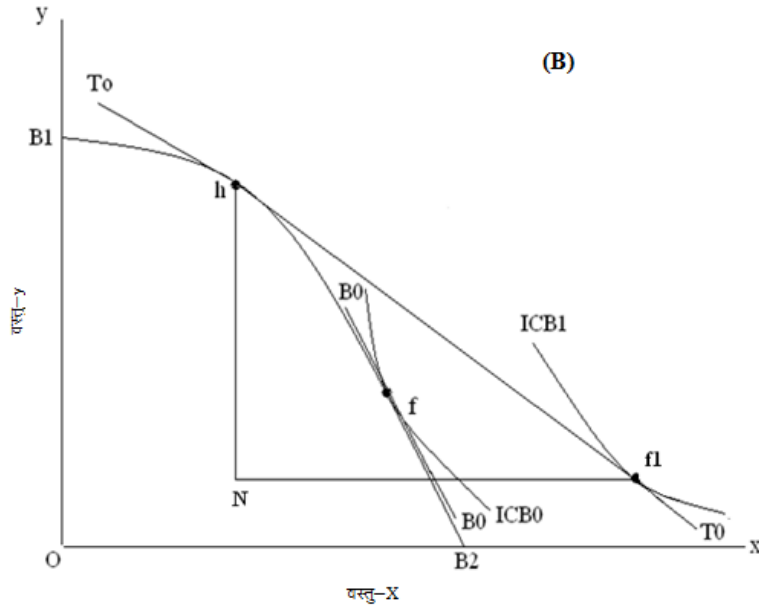
अर्थात्

$$\frac{P_y}{P_x} = MRTS_{XY}$$

देश A का e बिन्दु से अंततः g बिन्दु तक की गति यह बताती है कि वह Y वस्तु से संसाधनों हटाकर X वस्तु उद्योग में लगा रहा है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु X की सापेक्षिक कीमत घरेलू बाजार से अधिक है, जबकि X की सापेक्षिक उत्पादन लागत देश A में कम है। अर्थात् उसे X के उत्पादन में निरपेक्ष (या तुलनात्मक) लाभ प्राप्त है। इसलिए देश A , वस्तु X का उत्पादन बढ़ा रहा है तथा Y वस्तु का उत्पादन कम कर रहा है।



चित्र संख्या 4.2 A



चित्र संख्या 4.2 b

वृद्धिमान लागतों के अंतर्गत व्यापार संतुलन

इसी प्रकार देश B व्यापार के पश्चात् वस्तु Y का उत्पादन बढ़ाएगा क्योंकि उसे Y के उत्पादन में निरपेक्ष (या तुलनात्मक) लाभ प्राप्त है। जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु Y की कीमत देश B के घरेलू बाजार की अपेक्षा अधिक है। देश का अंतिम उत्पादन का संतुलन h बिन्दु पर होगा जहाँ उसके उत्पादन संभावना वक्र B_1B_2 का ढाल, अन्तर्राष्ट्रीय कीमत रेखा T_0T_0 के ढाल के बराबर है। देश B संसाधनों को X वस्तु उद्योग से हटाकर Y वस्तु उद्योग में लगाएगा।

इस प्रकार, देश A वस्तु X के उत्पादन में तथा देश B, वस्तु Y के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा, परन्तु बढ़ती हुई लागतों की स्थिति में विशिष्टीकरण पूर्ण नहीं होगा। देश A के लिए अनुकूलतम उत्पादन बिन्दु Y तथा देश B के लिए g होगा। इस स्थिति में दोनों ही देशों का आर्थिक कल्याण अधिकतम होगा। व्यापार के पश्चात्, देश A बिन्दु e_1 तथा देश B बिन्दु f_1 पर उपभोग करेगा। बिन्दु e पर, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार रेखा T_0T_0 देश A के समुदाय अधिमान वक्र ICA_1 को स्पर्श कर रही है। अर्थात् e_1 पर

$$T_0T_0 \text{ का ढाल} = ICA_1 \text{ का ढाल}$$

$$\text{या } \frac{P_y}{P_x} = MRS_{XY}$$

इसी प्रकार बिन्दु f पर T_0T_0 देश B के समुदाय अधिमान वक्र ICB_1 को स्पर्श कर रही है। अर्थात् T_0T_0 का ढाल = ICB_1 का ढाल

देश A वस्तु X की mg मात्रा का निर्यात करेगा और बदले में me मात्रा में वस्तु Y का आयात करेगा; देश B, वस्तु Y, की nh मात्रा (= e_1m) के निर्यात के बदले वस्तु X की nf_1 मात्रा (=mg) का आयात करेगा। व्यापार के पश्चात् दोनों देश पहले की अपेक्षा उच्च समुदाय अधिमान वक्र पर पहुँच जा रहे हैं। जोकि उनके बढ़े हुए उपभोग या आर्थिक कल्याण के स्तर को व्यक्त करता है। बिन्दु e_1 तथा f_1 पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा T_0T_0 का ढाल, दोनों देशों के समुदाय अधिमान वक्रों के ढाल के बराबर है। चूँकि बिन्दु g और h पर T_0T_0 का ढाल

दोनों देशों के उत्पादन संभावना वक्रों के ढाल के बराबर है। अतः दोनों देश के उत्पादक तथा उपभोक्ता एक साथ सामान्य संतुलन की स्थिति में है। संतुलन की स्थिति में
उत्पादन संभावना वक्रों की ढाल = समुदाय अधिमान वक्रों की ढाल = अन्तर्राष्ट्रीय कीमत रेखा का ढाल

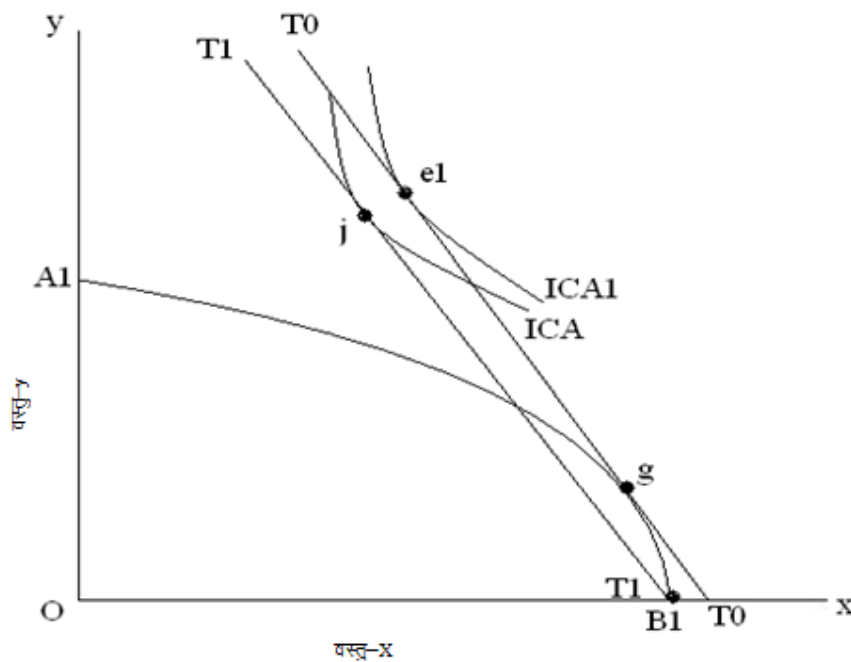
$$\text{या } MRST_{XY} = MRS_{xy} = \frac{P_y}{P_x}$$

संतुलन की स्थिति में,

देश A का निर्यात (वस्तु-x की mg मात्रा) = देश B का आयात (x की nf₁ मात्रा) तथा

देश A का आयात (y की mg मात्रा) = देश B का निर्यात (y की ny मात्रा)

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बढ़ती हुई लागतों की दशा में उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण सम्भव है परन्तु यह अनुकूलतम स्थिति नहीं होगी। पूर्ण विशिष्टीकरण के पश्चात् उस देश के आर्थिक कल्याण के स्तर में कमी आ जायेगी। उदाहरण के तौर पर, यदि देश A वस्तु X के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करता है तो वह उत्पादन संभावना वक्र के बिन्दु B₁ पर उत्पादन करेगा। ऐसी स्थिति में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा T₁T₁ जो कि T₀T₀ के समानान्तर है अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में X ओर Y की सापेक्षिक कीमतें अपरिवर्तित है, होगी। T₁T₁ रेखा, उत्पादन संभावना वक्र A₁B₁ को स्पर्श नहीं करती है। अतः B₁ उत्पादन का अनुकूलन बिन्दु नहीं है। पूर्ण विशिष्टीकरण की स्थिति में उपभोग का बिन्दु e₁ से बिन्दु j पर आ जाएगा, जहाँ व्यापार शर्त T₁T₁ समुदाय अधिमान वक्र ICA को j बिन्दु पर स्पर्श करती है। बिन्दु j, देश A के उत्पादन संभावना वक्र की सीमा से बाहर है जो कि यह बताता है कि व्यापार न होने से व्यापार का होना बेहतर है, क्योंकि इससे आर्थिक कल्याण का स्तर बढ़ जाता है। परन्तु बिन्दु j, बिन्दु e की अपेक्षा निचले समुदाय अधिमान वक्र पर स्थित है। अर्थात् g की अपेक्षा B₁ बिन्दु पर उत्पादन करने पर आर्थिक कल्याण या उपभोग का स्तर कम हो जाएगा। इस प्रकार अपूर्ण विशिष्टीकरण बढ़ती हुई लागतों की स्थिति में अनुकूलतम संतुलन की स्थिति को व्यक्त करता है जिसमें कि आर्थिक कल्याण अधिकतम होगा।



चित्र संख्या 4.3 बढ़ती हुई लागतों की दशा में पूर्ण तथा अपूर्ण विशिष्टीकरण की स्थिति में व्यापार के संतुलन की तुलना

4.6 उत्पादन में वृद्धिमान प्रतिफल या हासमान लागतों के अंतर्गत व्यापार संतुलन

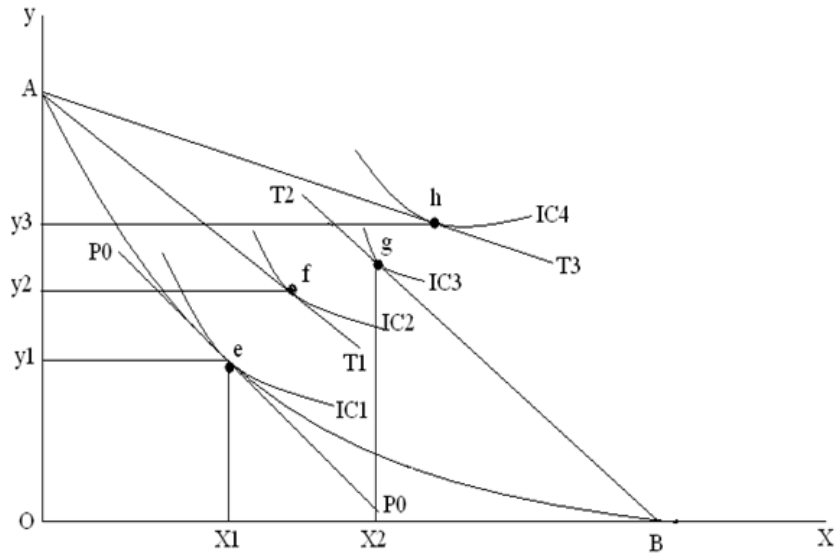
उत्पादन में बढ़ते हुए प्रतिफल या हासमान लागतों की स्थिति में, उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ औसत तथा सीमान्त लागतों में कमी आती है। प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी बड़े पैमाने के उत्पादन से प्राप्त आन्तरिक बचतों तथा बाह्य बचतों के कारण होता है। परन्तु ऐसी स्थिति में पूर्ण-प्रतियोगिता नहीं रहेगी। क्योंकि पूर्ण-प्रतियोगिता में सभी फर्म अनुकूलतम आकार की होती है, जिन्हें कोई आन्तरिक तथा बाह्य बचतें नहीं प्राप्त होती है। यदि पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता का त्याग कर दिया जाय तो फर्मों के आकार में वृद्धि के कारण, उत्पादन बढ़ने पर आन्तरिक बचतें या मितव्ययिताओं में वृद्धि तथा उनका पूर्ण दोहन हो पाता है।

हासमान लागतों की दशा में उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिन्दु के प्रति उत्तल होगा। एक अकेले देश के व्यापार संतुलन की स्थिति को भी हम घटती हुई लागतों की स्थिति में दिखा सकते हैं। चित्र 4.4 में, एक देश A का उत्पादन संभावना वक्र AB दिया हुआ है, जो कि मूल बिन्दु के प्रति उन्नतोदर है। दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में हासमान लागतों या वृद्धिमान प्रतिफल की स्थिति है। व्यापार से पूर्व e बिन्दु पर संतुलन है जहाँ कि उस देश की घरेलू कीमत रेखा P_0P_0 , उत्पादन संभावना वक्र AB को स्पर्श करती है। बिन्दु e पर A देश Ox_1 मात्रा x तथा oy_1 मात्रा y का उत्पादन तथा उपभोग कर रहा है।

व्यापार शुरू होने के पश्चात् देश किसी भी वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उत्पादन बढ़ने पर दोनों ही वस्तु उद्योगों को आन्तरिक बचतें प्राप्त हैं। वास्तव में यह देश किस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा, यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा पर निर्भर करेगा। यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा और घरेलू कीमत रेखा का ढाल बराबर हो, अर्थात् दोनों अनुपात एक ही हों तब भी देश A को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होगा।

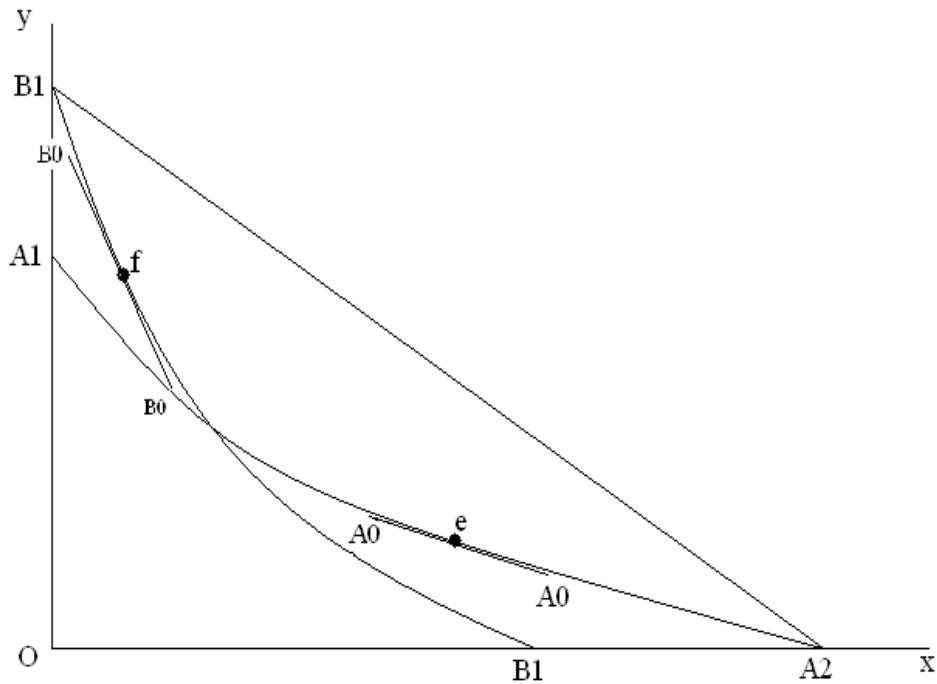
यदि अन्तर्राष्ट्रीय कीमत या व्यापार-शर्त रेखा AT_1 , घरेलू कीमत रेखा P_0P_0 एक समान हों, अर्थात् व्यापार के पश्चात् दोनों वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो देश वस्तु y के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करता है। चित्र 4.4 में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-शर्त रेखा AT घरेलू कीमत रेखा P_0P_0 के समानान्तर है। व्यापार शुरू होने के पश्चात् देश अपने सभी संसाधनों को X वस्तु उद्योग से Y वस्तु उद्योग में लगा देता है और उत्पादन का बिन्दु e से बिन्दु A पर चला जाता है। जहाँ वह वस्तु y की OA तथा वस्तु X की शून्य मात्रा का उत्पादन करता है। परन्तु उपभोग का संतुलन बिन्दु e से बिन्दु f पर चला जाता है। बिन्दु f पर वह Ay_2 मात्रा Y का निर्यात करता है और बदले में y_2f मात्रा X का आयात करता है। स्पष्ट है कि व्यापार के पश्चात् देश के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो जा रही है। देश IC_1 के e बिन्दु से IC_2 के f बिन्दु पर चला जा रहा है जो कि उपभोग तथा कल्याण के बढ़े हुए स्तर को प्रदर्शित करता है।

यदि देश वस्तु X के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है तो बिन्दु B पर उत्पादन का संतुलन होगा। यदि व्यापार-शर्त रेखा वही है अर्थात् रेखा BT_2 , AT_1 तथा P_0P_0 के समानान्तर हो, तो देश X_2B मात्रा में X का निर्यात करेगा और बदले में X_2g मात्रा y का आयात करेगा। व्यापार-शर्त रेखा से स्पष्ट है कि X के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना देश A के लिए अधिक फायदेमंद है। यह बात इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि अब उत्पादन का संतुलन बिन्दु g पर है जो कि ऊपर के समुदाय अधिमान वक्र IC_3 पर स्थित है। चूंकि बिन्दु f की अपेक्षा बिन्दु g आर्थिक कल्याण के ऊँचे स्तर के व्यक्त करता है इसलिए इस देश के लिए B बिन्दु पर उत्पादन और बिन्दु g पर उपभोग करना उपयुक्त होगा।



चित्र 4.4 हासमान लागतों के अंतर्गत व्यापार संतुलन

यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के शुरु होने बाद व्यापार-शर्तों में परिवर्तन हो जाता है तो उत्पादन व उपभोग संतुलन परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लिया अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा AT_3 है, जो कि व्यापार से पूर्व कि कीमत रेखा P_0P_0 से अधिक चपटी है। अर्थात् विश्व बाजार में वस्तु X की अपेक्षा वस्तु y काफी मंहगी है। इसलिए देश के लिए यह अधिक लाभदायक होगा कि वह वस्तु y के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण हासिल करे। वह OA मात्रा में y वस्तु का उत्पादन करेगा, उसमें से Ay_3 मात्रा निर्यात करके बदले में Y_3h मात्रा X का आयात करेगा। देश का उत्पादन का संतुलन A बिन्दु पर तथा उपभोग का संतुलन h बिन्दु पर होगा। बिन्दु h, समुदाय अधिमान वक्र IC_4 पर स्थित है, जो कि पहले कि स्थितियों से सबसे अधिक आर्थिक कल्याण के स्तर को प्रदर्शित करता है।



चित्र 4.5 हासमान लागतों के अंतर्गत व्यापार संतुलन

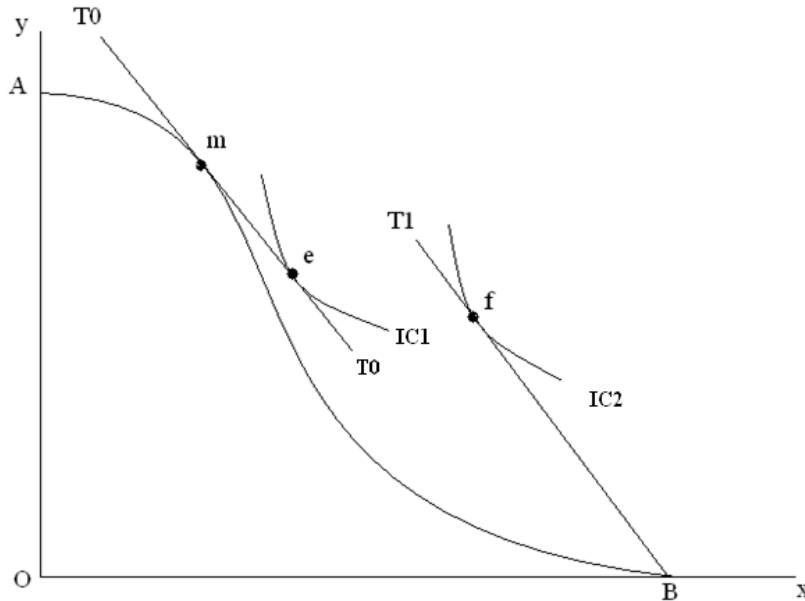
जब दो देश A और B हों, जो दो वस्तुओं X और Y उत्पादन बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत कर रहे हों, उनके व्यापार का संतुलन चित्र 4.5 में दिखाया गया है। देश A का उत्पादन संभावना वक्र A_1A_2 तथा देश B का B_1B_2 है। व्यापार से पहले दोनों देश क्रमशः e और f बिन्दु पर संतुलन में हैं जहाँ घरेलू कीमत रेखा A_0A_0 तथा B_0B_0 उनके उत्पादन संभावना वक्रों क्रमशः A_1A_2 तथा B_1B_2 को स्पर्श कर रही है।

देश A की घरेलू कीमत रेखा A_0A_0 अधिक चपटी है, जो कि यह बताती है कि Y की अपेक्षा वस्तु X काफी सस्ती है। अर्थात् देश A को X के उत्पादन में अधिक लाभ प्राप्त है, क्योंकि उसकी उत्पादन लागत कम है। इसी प्रकार देश B की घरेलू कीमत रेखा B_0B_0 अधिक तिरछी है, जो यह दर्शाती है कि देश B को Y के उत्पादन में अधिक लाभ प्राप्त है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-शर्त रेखा B_1A_2 हो तो देश B, वस्तु Y के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त करेंगे। रेखा B_1A_2 से स्पष्ट है कि वस्तु X की वैश्विक बाजार में कीमत देश A की घरेलू कीमत से अधिक है। इसी प्रकार, वस्तु Y की देश B में घरेलू कीमत की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत अधिक है। इस प्रकार व्यापार के पश्चात् देश A वस्तु X में तथा देश B वस्तु Y में पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु X देश A के घरेलू बाजार से मंहगी है। जबकि वस्तु Y अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में देश B के घरेलू बाजार की अपेक्षा मंहगी

देश A का उत्पादन का बिन्दु, e से हटकर A_2 तथा देश B का f से B_1 पर आ जाएगा। जबकि दोनों देशों में उपभोक्ताओं का संतुलन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा B_1A_2 पर कहीं स्थित होगा। देश A, वस्तु X का निर्यात और वस्तु Y का आयात करेगा तथा देश B वस्तु Y का निर्यात तथा X का आयात करेगा। संतुलन की स्थिति में दोनों देशों के आयात व निर्यात परस्पर बराबर होंगे।

4.7 एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धिमान प्रतिफल तथा दूसरी वस्तु के उत्पादन में हासमान प्रतिफल के अंतर्गत व्यापार संतुलन

एक वस्तु के उत्पादन में बढ़ते हुए प्रतिफल या घटती हुई लागतों तथा दूसरे वस्तु के उत्पादन में घटते प्रतिफल या बढ़ती हुई लागतों की स्थिति में व्यापार-संतुलन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-शर्त रेखा पर निर्भर करेगा। साथ ही व्यापार संतुलन की स्थिति घटती हुई लागतों की स्थिति मजबूत है या सामान्य है, इस पर निर्भर करेगी।

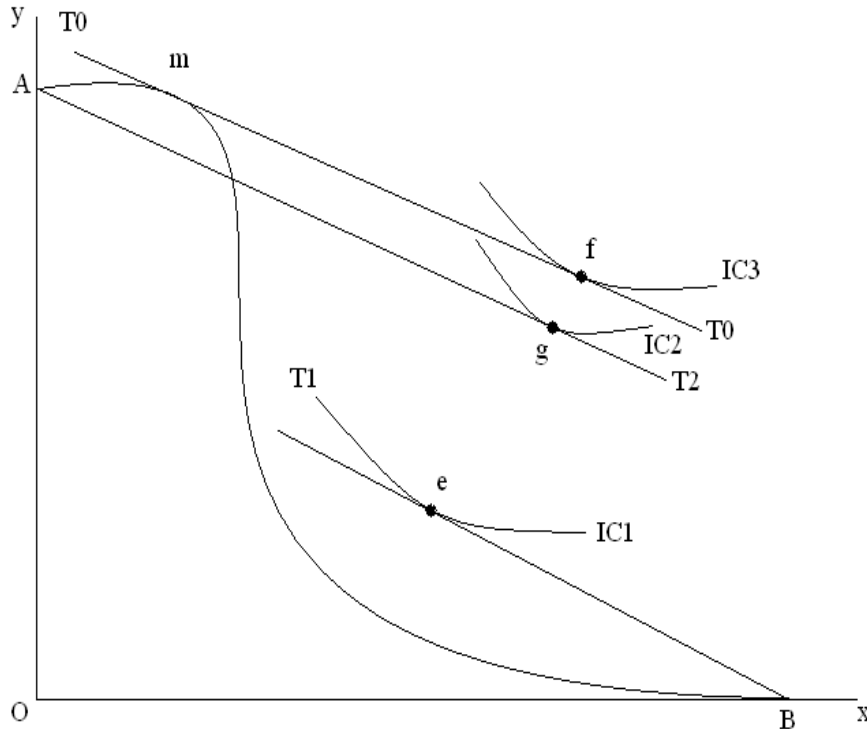


चित्र 4.6: एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धिमान प्रतिफल तथा दूसरी वस्तु के उत्पादन में हासमान प्रतिफल के अंतर्गत व्यापार संतुलन

चित्र 4.6 में, एक देश को X वस्तु के उत्पादन में बढ़ते हुए प्रतिफल तथा Y वस्तु के उत्पादन में घटते हुए प्रतिफल की स्थिति दिखायी गयी है। व्यापार के पश्चात् देश वस्तु-X के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा या वस्तु-Y के उत्पादन में, यह पूरी तरह से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-शर्त रेखा या वैश्विक बाजार में वस्तु X तथा Y की सापेक्षिक कीमतों पर निर्भर करेगा।

यदि अन्तर्राष्ट्रीय कीमत रेखा T_0T_0 है, तो स्पष्ट है कि वैश्विक बाजार में वस्तु Y की अपेक्षा वस्तु X मंहगी है। इसलिए देश वस्तु X के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा। वैश्विक माँग देशों के साथ ही देश में वस्तु X के लिए उत्पादन की दशाएँ भी अनुकूल हैं क्योंकि X के उत्पादन में बढ़ता हुआ प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। व्यापार के पश्चात् उत्पादन का संतुलन B बिन्दु पर तथा उपभोग का f बिन्दु पर होगा, जो कि ऊँचे समुदाय अधिमान वक्र पर स्थित है।

देश, यदि वस्तु Y के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा तो भी व्यापार से पहले की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त करेगा। चूंकि वस्तु Y के उत्पादन में घटते हुए प्रतिफल की स्थिति है इसलिए उत्पादन में अपूर्ण विशिष्टीकरण से ही उसका लाभ अधिकतम होगा। Y वस्तु में विशिष्टीकरण की स्थिति में उत्पादन का संतुलन M बिन्दु पर होगा जहाँ व्यापार शर्त रेखा T_0T_0 (जो कि T_1B के समानान्तर है) वक्र AB का स्पर्श करती है तथा उपभोग का संतुलन अधिमान वक्र IC_1 के e बिन्दु पर होगा। IC_1 वक्र IC_2 के नीचे स्थित है। अतः बिन्दु e, बिन्दु f की अपेक्षा आर्थिक कल्याण के निम्नतर स्तर को व्यक्त करता है। अतः देश के लिए सबसे अच्छी स्थिति होगी वह वस्तु X के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करे तथा IC_2 के f बिन्दु पर उपभोग करे।



चित्र 4.7: एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धिमान प्रतिफल तथा दूसरी वस्तु के उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल के अंतर्गत व्यापार संतुलन

यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा बहुत चपटी है, अर्थात् यदि वैश्विक बाजार में वस्तु X की अपेक्षा वस्तु Y मंहगी हो, जैसा कि चित्र 4.7 में T_0T_0 $\frac{1}{4}AA$ T_1B) से स्पष्ट है तो ऐसी स्थिति में वस्तु X के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण के पश्चात् देश IC के e बिन्दु पर उपभोग करेगा। जबकि यदि वह Y वस्तु के उत्पादन में m बिन्दु पर

अपूर्ण विशिष्टीकरण करता है तो IC_3 के f बिन्दु पर उपभोग कर रहा है जो e की अपेक्षा अधिक आर्थिक कल्याण के स्तर को व्यक्त करता है। अतः X के उत्पादन में बढ़ते हुए प्रतिफल की स्थिति के बावजूद, व्यापार की शर्तों के विरुद्ध होने के कारण, इसके उत्पादन में विशिष्टीकरण नहीं करेगा। यदि देश Y के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करता है तो IC_1 के e बिन्दु की अपेक्षा अधिक कल्याण अर्जित कर रहा है। चित्र में Y वस्तु के पूर्ण विशिष्टीकरण की स्थिति में उत्पादन का संतुलन A बिन्दु पर होगा जबकि उपभोग IC_2 के बिन्दु g पर होगा, जोकि IC_1 के e बिन्दु से ऊपर है। परन्तु IC_2 वक्र IC_3 के नीचे स्थित है। अतः स्पष्ट है कि देश, वस्तु Y के उत्पादन में अपूर्ण विशिष्टीकरण करके, अर्थात् बिन्दु M पर उत्पादन करके अपने उपभोग तथा आर्थिक कल्याण के स्तर को बढ़ा सकता है।

4.8 मूल्यांकन

अवसर लागत पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नवप्रतिष्ठित सिद्धान्त, न सिर्फ मूल्य के श्रम सिद्धान्त तथा उत्पादन में स्थिर प्रतिफल जैसे अवास्तविक बातों को त्याग कर व्यापार संतुलन का एक वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, बल्कि यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सामान्य संतुलन सिद्धान्त का एक सरल मॉडल प्रस्तुत करता है जो कि विश्लेषण के महत्वपूर्ण यंत्रों से सुसज्जित है।

प्रतिष्ठित सिद्धान्त के समर्थकों का मानना है कि नवप्रतिष्ठित सिद्धान्त वस्तु के उत्पादन में निहित श्रम की अनुपयोगिता या कष्टानुभूति को मापने में असमर्थ है, यह सिद्धान्त सिर्फ विश्लेषणात्मक कार्यों के लिए श्रेष्ठ है इसका वास्तविक लागतों या कल्याण संबंधी अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं है परन्तु अनेक आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने जैसे केम्प, सैम्युलसन, बाल्डविन आदि ने उत्पादन संभावना वक्र तथा समुदाय अधिमान वक्रों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त लाभों को कल्याण के रूप में प्रदर्शित किया है।

4.9 विनिमय से लाभ तथा विशिष्टीकरण से लाभ

अब तक के अध्ययन से आप यह समझ गए होंगे कि यदि दो देशों के बीच एक वस्तु की उत्पादन लागतों में तुलनात्मक रूप से अंतर है तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों ही देशों के लिए लाभदायक होगा। व्यापार से होने वाले लाभ दो तरह के होते हैं विनिमय से लाभ तथा विशिष्टीकरण से लाभ। ये दोनों लाभ मिलकर व्यापार से होने वाले कुल लाभों को बताते हैं। व्यापार से होने वाले लाभों या आर्थिक कल्याण में वृद्धि को हम उपभोग में या उपभोक्ताओं की संतुष्टि में हुई वृद्धि के रूप में मापते हैं, जो कि समुदाय अधिमान वक्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। यदि एक देश के उपभोक्ता निचले समुदाय अधिमान वक्र से ऊपर के समुदाय अधिमान वक्र पर पहुँच जाते हैं तो यह उस देश के रहन-सहन या आर्थिक कल्याण में वृद्धि को दर्शाता है, जो कि व्यापार से होने वाले लाभ हैं। यह लाभ दो कारणों से होता है, एक तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्तों के देश के पक्ष होने कारण अर्थात् वह जिस वस्तु के उत्पादन में अधिक दक्ष है उसकी वैश्विक बाजार में कीमत, घरेलू बाजार से अधिक होती है, दूसरे देश के आर्थिक संसाधनों के प्रयोग में अर्थात् उत्पादन में, विशिष्टीकरण के कारण।

चित्र 4.8 में, व्यापार न होने की स्थिति में, देश अपने उत्पादन संभावना वक्र AB के बिन्दु e पर संतुलन में है, जहाँ घरेलू कीमत रेखा P_0P_0 , स्पर्श कर रही है। देश e बिन्दु पर उत्पादन के साथ-साथ उपभोग भी कर रहा है। क्योंकि कीमत रेखा P_0P_0 समुदाय अधिमान वक्र IC_1 के e बिन्दु पर स्पर्श करती है। जैसे ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू होता है नयी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा (T_0T_0) के अनुसार देश संसाधनों को पुनर्आवंटित करेगा। चूँकि देश में वस्तु X की सापेक्षिक लागत कम है, जबकि वस्तु X वैश्विक बाजार में तुलनात्मक रूप से मंहगी है। (रेखा T_0T_0 , घरेलू कीमत रेखा P_0P_0 से अधिक तिरछी है)

का आयात करेगा। इस प्रकार IC_2 के बिन्दु f से IC_3 के बिन्दु h तक गति, उत्पादन में विशिष्टीकरण के कारण व्यापार से लाभ को प्रदर्शित करती है।

इस प्रकार व्यापार से होने वाला कुल लाभ, जो देश के उपभोग में या आर्थिक कल्याण में वृद्धि को बताता है, दो प्रकार के लाभों का योग है- विनिमय से प्राप्त लाभ तथा विशिष्टीकरण से प्राप्त लाभ।

विनिमय से लाभ = IC_1 के बिन्दु e से IC_2 के बिन्दु f तक की गति

विशिष्टीकरण से लाभ = IC_2 के f से IC_3 के g तक गति

व्यापार से कुल लाभ = IC_1 के बिन्दु e से IC_3 के g तक की गति

(e से f तक + f गति से g तक गति)

यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि व्यापार के पश्चात् आय के वितरण में देश के भीतर जो परिवर्तन होता है उस पर विचार नहीं किया गया है। उत्पादन में परिवर्तन से देश के भीतर आय के वितरण से महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है परन्तु यहाँ, आय वितरण को स्थिर मानकर समुदाय अधिमान वक्र की रचना की गयी है।

4.10 अभ्यास हेतु प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न:

1. उत्पादन में स्थिर प्रतिफल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलन की व्याख्या कीजिये।
2. उत्पादन में स्थिर प्रतिफल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभों को चित्र की सहायता से दर्शाइए।
3. व्यापार होने पर बढ़ती हुई लागतों की दशा में एक देश उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं करेगा। टिप्पणी कीजिये।
4. उत्पादन में घटता हुआ प्रतिफल प्राप्त होने की स्थिति में एक देश के व्यापार के संतुलन की स्थिति को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिये।
5. एक वस्तु के उत्पादन में बढ़ते हुए प्रतिफल या घटती हुई लागतों तथा दूसरे वस्तु के उत्पादन में घटते प्रतिफल या बढ़ती हुई लागतों की स्थिति में व्यापार-संतुलन की व्याख्या कीजिये।
6. विनिमय से लाभ तथा विशिष्टीकरण से लाभ में अंतर स्पष्ट कीजिये।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

1. व्यापार की अनुपस्थिति में किसी देश का उत्पादन तथा उपभोग का संतुलन होगा
 - i. उत्पादन संभावना वक्र के दो अलग अलग बिंदुओं पर
 - ii. उत्पादन संभावना वक्र के एक ही बिंदु पर
 - iii. उत्पादन संभावना वक्र के अंदर के बिंदुओं पर
 - iv. उत्पादन संभावना वक्र के बाहर के बिंदुओं पर
2. निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री व्यापार के नव प्रतिष्ठित सिद्धांत से जुड़े नहीं हैं
 - i. हैबरलर और लियोन्टीफ
 - ii. एडम स्मिथ तथा रिकार्डो
 - iii. लर्नर और मीड
 - iv. मार्शल और एजबर्थ
3. यदि एक देश की घरेलू कीमत रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा एक ही हो तो

- i. उस देश को व्यापार से कोई ही लाभ नहीं होगा
 - ii. व्यापार से होने वाला समस्त लाभ उस देश को प्राप्त होगा
 - iii. उस देश को व्यापार से हानि होगी
 - iv. उस देश को व्यापार से लाभ और हानि होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता
4. बढ़ती हुई लागतों की स्थिति में अनुकूलतम संतुलन की स्थिति होगी जिसमें कि आर्थिक कल्याण अधिकतम होगा
- i. जब उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण होगा
 - ii. जब उत्पादन में अपूर्ण विशिष्टीकरण होगा
 - iii. उपरोक्त दोनों ही स्थितियों में हो सकता है
 - iv. उपरोक्त दोनों ही स्थितियों में नहीं हो सकता है
5. बढ़ती हुई लागतों की स्थिति में व्यापार के संतुलन की स्थिति में होगा
- i. $MRST_{XY} = \frac{P_y}{P_x}$
 - ii. $MRST_{XY} = MRS_{xy}$
 - iii. $MRS_{xy} = \frac{P_y}{P_x}$
 - iv. उपरोक्त सभी
6. व्यापार के पश्चात् संतुलन की स्थिति में
- i. उत्पादन संभावना वक्रों की ढाल = समुदाय अधिमान वक्रों की ढाल अन्तर्राष्ट्रीय कीमत रेखा का ढाल
 - ii. $MRST_{XY} = MRS_{xy} = \frac{P_y}{P_x}$
 - iii. देश A का निर्यात = देश B का आयात तथा देश A का आयात = देश B का निर्यात
 - iv. उपरोक्त सभी
7. व्यापार के पश्चात में किसी देश का उत्पादन तथा उपभोग का संतुलन होगा
- i. उत्पादन संभावना वक्र के दो अलग अलग बिंदुओं पर
 - ii. उपभोग का संतुलन उत्पादन संभावना वक्र पर तथा उत्पादन का संतुलन उत्पादन संभावना वक्र के बाहर के किसी बिंदु पर
 - iii. उत्पादन का संतुलन उत्पादन संभावना वक्र पर तथा उपभोग का संतुलन उत्पादन संभावना वक्र के बाहर के किसी बिंदु पर
 - iv. उत्पादन तथा उपभोग दोनों का संतुलन उत्पादन संभावना वक्र के बाहर के बिंदुओं पर होगा
8. हासमान लागतों की दशा में यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा और घेरलू कीमत रेखा का ढाल बराबर हो तो देश को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से
- i. लाभ होगा
 - ii. हानि होगी
 - iii. कोई लाभ नहीं होगा।
 - iv. लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है
9. व्यापार से होने वाले लाभ का अर्थ है
- i. आर्थिक कल्याण में वृद्धि

- ii. उपभोग में या उपभोक्ताओं की संतुष्टि में हुई वृद्धि
 - iii. उपभोक्ता का निचले समुदाय अधिमान वक्र से ऊपर के समुदाय अधिमान वक्र पर पहुंचना
 - iv. उपरोक्त सभी
10. व्यापार से लाभ है
- i. विनिमय से लाभ
 - ii. विशिष्टीकरण से लाभ
 - iii. उपरोक्त दोनों
 - iv. उपरोक्त में से कोई नहीं

सत्य व असत्य :

1. वास्तविक बढ़ती हुई लागतों की दशा में उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण के पश्चात् उस देश के आर्थिक कल्याण के स्तर में कमी आ जायेगी।
2. अपूर्ण विशिष्टीकरण बढ़ती हुई लागतों की स्थिति में अनुकूलतम संतुलन की स्थिति को व्यक्त नहीं करता है।
3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा किसी देश की घरेलू कीमत रेखा के जितनी ही पास होगी उसे व्यापार से लाभ उतना ही अधिक होगा।
4. संतुलन की स्थिति में दो देशों का आयात व निर्यात आपस में बराबर होंगे।
5. व्यापार के पश्चात् दोनों देश के उत्पादक तथा उपभोक्ता एक साथ सामान्य संतुलन की स्थिति में होंगे।
6. एक वस्तु के उत्पादन में घटती हुई लागतों तथा दूसरे वस्तु के उत्पादन में घटते प्रतिफल की स्थिति में व्यापार-संतुलन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-शर्त रेखा पर नहीं सिर्फ घटती हुई लागतों की स्थिति मजबूत है या सामान्य है, इस पर निर्भर करेगा।
7. नवप्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में व्यापार के पश्चात् आय के वितरण में देश के भीतर जो परिवर्तन होता है उस पर विचार नहीं किया गया है।
8. हासमान लागतों की दशा में बाज़ार में पूर्ण-प्रतियोगिता नहीं रहेगी।
9. हासमान लागतों की दशा में वास्तव में एक देश किस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा, यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा पर निर्भर करेगा।
10. हासमान लागतों की दशा में यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा और घरेलू कीमत रेखा दोनों का अनुपात एक ही हो तब देश को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ नहीं होगा।

4.11 सारांश

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित होने के कारण कटू आलोचना की जाती है। परन्तु जब तुलनात्मक लाभ को अवसर लागत रूप के रूप में परिभाषित किया जाता है तो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उत्पादन सिर्फ श्रम से हो रहा है या श्रम के साथ सभी उत्पादन के साधनों के संयोग से। हैबरलर ने वास्तविक लागत सिद्धांत के विकल्प के रूप में 'अवसर लागत का सिद्धांत' प्रस्तुत किया। हैबरलर का मानना है कि लागतों का अर्थ वस्तु के उत्पादन में निहित श्रम की मात्रा से नहीं बल्कि वस्तु के उत्पादन के लिए किए गए वैकल्पिक उत्पादन के त्याग अर्थात् अवसर लागत से है। वस्तु X की अवसर लागत, वस्तु Y की वह मात्रा है जो कि वस्तु X की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए त्यागनी पड़ती है। अवसर

लागत व उत्पादन संभावना वक्र के साथ समुदाय अधिमान वक्रों के प्रयोग के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नव-प्रतिष्ठित सिद्धांत विकसित किया गया। नव प्रतिष्ठित व्यापार सिद्धांत में मूल्य के श्रम सिद्धांत को त्यागने के साथ-साथ उत्पादन की अलग-अलग दशाओं में व्यापार-संतुलन की व्याख्या करता है। प्रतिफल नियमों के अनुरूप यह उत्पादन में स्थिरे, घटते तथा बढ़ते हुए प्रतिफल की स्थितियों में व्यापार-संतुलन की व्याख्या करता है।

उत्पादन में स्थिर प्रतिफल या स्थिर लागतों की स्थिति में पूर्ण विशिष्टीकरण होगा। व्यापार से लाभ तभी होगा जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा दो देशों की घरेलू कीमत रेखा के बीच हो। व्यापार के पश्चात् कुल विश्व उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। व्यापाररत देश पहले से अधिक उपभोग करते हैं। हासमान प्रतिफल या बढ़ती हुई लागतों की दशा में उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण सम्भव है परन्तु यह अनुकूलतम स्थिति नहीं होगी। पूर्ण विशिष्टीकरण के पश्चात् उस देश के आर्थिक कल्याण के स्तर में कमी आ जायेगी। अपूर्ण विशिष्टीकरण बढ़ती हुई लागतों की स्थिति में अनुकूलतम संतुलन की स्थिति को व्यक्त करेगा। उत्पादन में बढ़ते हुए प्रतिफल या हासमान लागतों की स्थिति में, देश किस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा, यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा पर निर्भर करेगा।

व्यापार से होने वाला कुल लाभ देश के उपभोग में या आर्थिक कल्याण में वृद्धि को बताता है। यह दो प्रकार के लाभों का योग है- विनिमय से प्राप्त लाभ तथा विशिष्टीकरण से प्राप्त लाभ। दोनों देश आपस में कितना व्यापार करेंगे या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-शर्त रेखा पर वास्तव में उपभोग का संतुलन कहाँ होगा, यह अन्तर्राष्ट्रीय कीमत रेखा के ढाल पर निर्भर करेगा।

4.12 शब्दावली

- **अवसर लागत** - एक वस्तु की उत्पादन या अवसर लागत उस वस्तु के मूल्य के बराबर होगी जिसका त्याग विचाराधान वस्तु के उत्पादन के लिए किया गया है। वस्तु X की अवसर लागत, वस्तु Y की वह मात्रा है जो कि वस्तु X की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए त्यागनी पड़ती है।
- **विनिमय से लाभ** - उत्पादन में बिना विशिष्टीकरण के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा के आधार पर सिर्फ वस्तु विनिमय के द्वारा प्राप्त लाभ है।
- **विशिष्टीकरण से लाभ** - देश के आर्थिक संसाधनों के प्रयोग में अर्थात् उत्पादन में विशिष्टीकरण के कारण व्यापार से प्राप्त लाभ।
- **नव प्रतिष्ठित व्यापार सिद्धांत** - नए विश्लेषणात्मक यंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित व्यापार सिद्धांत की पुनर्व्याख्या और इसके निष्कर्षों की पुनर्स्थापना करने वाले सिद्धांत। अवसर लागत व उत्पादन संभावना वक्र के साथ समुदाय अधिमान वक्रों के प्रयोग के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नव-प्रतिष्ठित सिद्धांत विकसित किया गया, जिसमें हैबरलर, लियोटीफ़, लर्नर, मार्शल, एजबर्थ और मीड का योगदान है। विशेषरूप से मीड ने आधुनिक ज्यामितीय तकनीकी की मदद से तुलनात्मक लागत के नवप्रतिष्ठित सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान किया।

4.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न:

1. ii, 2. ii, 3. i, 4. i, 5. iv 6. iv 7. iii 8. ii 9. iv 10. iii

सत्य व असत्य :

1. सत्य	2.असत्य	3.असत्य	4.सत्य	5.सत्य
6. असत्य	7.सत्य	8.सत्य	9.सत्य	10.असत्य

4.14 संदर्भ ग्रंथ सूची

- HH. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Bo Sodersten, International Economics ,Macmillan, 1999
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: International Economics: Theory and Policy, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- Charles P Kindleberger, International Economics, Richard D. Irwin Inc., Illinois, 1968
- Dominik Salvatore, International Economics, John Willy & Sons, Inc., 2008
- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006
- सुदामा सिंह एवं एम0सी0 वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड एंड आई0बी0एच0 पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम0एल0 झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010।
- ज्ञानेंद्र सिंह कुशवाहा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1979।

4.15 उपयोगी/सहायक पाठ्य सामग्री

- HH. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Bo Sodersten, International Economics ,Macmillan, 1999
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: International Economics: Theory and Policy, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- Charles P Kindleberger, International Economics, Richard D. Irwin Inc., Illinois, 1968
- Dominik Salvatore, International Economics, John Willy & Sons, Inc., 2008
- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006
- एस. एन. लाल, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र , शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहबाद, 2004
- एच. एस. अग्रवाल, तथा सी. एस. बरला, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2003.

- सुदामा सिंह एवं एम. सी. वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड एंड आई. बी. एच. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम0 एल0 झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010.
- डॉ. जी. सी. सिंघई एवं डॉ. जे. पी. मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा, 2010

4.16 निबंधात्मक प्रश्न

1. उत्पादन में स्थिर तथा हासमान प्रतिफल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलन की व्याख्या कीजिये।
2. हासमान अवसर लागत के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन की विवेचना कीजिये।
3. जब दो वस्तुओं के उत्पादन में हासमान प्रतिफल या वृद्धिमान सीमांत लागत की स्थिति हो तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन की विवेचना चित्र की सहायता से कीजिये।
4. विनिमय से लाभ तथा विशिष्टीकरण से लाभ में अंतर स्पष्ट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभों को चित्र की सहायता से समझाइए।

इकाई 5 - अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धान्त (Modern Theory of International Trade)

- 5.1 प्रस्तावना
- 5.2 उद्देश्य
- 5.3 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धान्त
 - 5.3.1 भूमिका
 - 5.3.2 मान्यताएं
 - 5.3.3 साधन सम्पन्नता
 - 5.3.4 साधन सम्पन्नता के कीमत मापदण्ड के आधार पर सिद्धान्त की व्याख्या
 - 5.3.5 साधन सम्पन्नता के भौतिक मापदण्ड के आधार पर सिद्धान्त की व्याख्या
 - 5.3.5.1 जब उत्पादन तथा उपभोग का झुकाव भिन्न दिशाओं में हो
 - 5.3.5.2 जब उत्पादन तथा उपभोग का झुकाव एक ही दिशा में हो
 - 5.3.6 निष्कर्ष
- 5.4 प्रतिष्ठित सिद्धान्त से तुलना
- 5.5 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धान्त की कमियां
- 5.6 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धान्त की आनुभविक जाँच
 - 5.6.1 लियोन्टीफ का विरोधाभास
 - 5.6.2 अन्य अध्ययन
 - 5.6.3 लियोन्टीफ का विरोधाभास की आलोचना
- 5.7 साधन कीमत समानीकरण प्रमेय
 - 5.7.1 साधन कीमत समानीकरण प्रमेय की आलोचना
- 5.8 अभ्यास हेतु प्रश्न
- 5.9 सारांश
- 5.10 शब्दावली
- 5.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 5.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 5.13 उपयोगी /सहायक ग्रन्थ
- 5.14 निबंधात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना

इससे पहले की इकाईयों के अध्ययन के पश्चात् आप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभप्रतिष्ठित सिद्धान्त, प्रतिपूरक मांग के सिद्धान्त तथा अवसर लगत सिद्धान्त के बारे में बता सकते हैं आप जान गए होंगे की. रिकार्डों द्वारा प्रस्तुत तुलनात्मक लाभ सिद्धान्त के अनुसार व्यापार का मुख्य कारण श्रम उत्पादकता में अन्तर है, परन्तु श्रम की उत्पादकता में अन्तर क्यों है इसकी कोई व्याख्या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं प्रस्तुत करते हैं। ओहलिन, रिकार्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को अधूरा बताते हुए उसकी आलोचना करते हैं और तुलनात्मक लागतों में अन्तर के कारणों की व्याख्या करते हैं।

हेक्शर ओहलिन के आधुनिक व्यापार सिद्धान्त में व्यापार के कारणों की दूसरी व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। व्यापार का कारण है- विभिन्न देशों के पास भिन्न-भिन्न साधन उपलब्धता। विभिन्न देशों में साधन उपलब्धताओं में भिन्नता के कारण ही वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में भिन्नता पायी जाती है जिससे देशों के बीच व्यापार सम्भव होता है।

प्रस्तुत इकाई में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के हेक्शर ओलिन द्वारा दिये गये आधुनिक सिद्धान्त के बारे में विस्तार से बताया गया है .इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक व्यापार सिद्धान्त के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

5.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप

- ✓ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धान्त के मुलभूत स्थापनाओं को समझ सकेंगे.
- ✓ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धान्त तथा प्रतिष्ठित सिद्धान्त में अंतरों को जान सकेंगे.
- ✓ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धान्त की आनुभविक अध्ययनों के आधार पर परख कर सकेंगे.
- ✓ साधन कीमत समानीकरण प्रमेय को समझ सकेंगे.

5.3 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धान्त

5.3.1 भूमिका

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो मूल्य सिद्धान्त घरेलू बाजार में लागू होता है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लागू नहीं होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतरक्षेत्रीय व्यापार में अंतर है। परन्तु बर्टिल ओहलिन के अनुसार मूल्य का सामान्य साम्य विश्लेषण जो कि अंतरक्षेत्रीय व्यापार की व्याख्या के लिए उपयुक्त है वही बिना किसी विशेष परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी उपयुक्त है; अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतरक्षेत्रीय व्यापार की ही एक विशेष स्थिति है। मूल्य के सामान्य सिद्धान्त के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उसकी समग्र मांग और समग्र पूर्ति की समानता के द्वारा निर्धारित होता है और संतुलन बिन्दु पर वस्तु की कीमत औसत उत्पादन लागत के बराबर होती है। उत्पादन की लागत उत्पादन में लगे साधनों की कीमतें हैं। जोकि वास्तव में संसाधनों की आय है जिससे आगे वस्तु की मांग उत्पन्न होती है। इस प्रकार वस्तुओं की कीमत, साधनों की कीमत, वस्तुओं की मांग और साधनों की मांग और पूर्ति में पारस्परिक अंतर्संबंध और निर्भरता होती है।

वास्तव में, मार्शल के मूल्य के सामान्य साम्य विश्लेषण में समय आयाम (time dimensions) तो है परन्तु स्थान आयाम (space dimensions) नहीं है। यह एक एकाकी बाजार सिद्धान्त है जो कि एक क्षेत्र या देश में प्रयुक्त होता है। ओहलिन का विचार है कि मूल्य के सामान्य सिद्धान्त में स्थान तत्व (space element) को

सम्मिलित करके इसका बहु-बाजार सिद्धान्त दिया जा सकता है, और इसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों या देशों के मध्य व्यापार में मूल्य निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार हेक्शर-ओहलिन का सिद्धान्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सामान्य संतुलन सिद्धान्त है।

सर्वप्रथम एली हेक्शर ने यह बताया कि जब दो देशों के मध्य व्यापार होता है तो मूल्य के पारस्परिक निर्भरता का सिद्धान्त क्रियाशील होता है। इसी आधार पर ओहलिन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धान्त की व्याख्या प्रस्तुत की। ओहलिन, रिकार्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को अधूरा बताते हुए उसकी आलोचना करते हैं और तुलनात्मक लागतों में अन्तर के कारणों की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित सिद्धान्त की रिक्तता की पूर्ति करता है।

ओहलिन के अनुसार विभिन्न देशों में, विभिन्न वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में पायी जाने वाली भिन्नता के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है। वस्तुओं की कीमतों में भिन्नता मुख्यतः उत्पादन साधनों की पूर्ति या उपलब्धता में भिन्नता के कारण होती है। रिकार्डों द्वारा प्रस्तुत तुलनात्मक लाभ सिद्धान्त के अनुसार व्यापार का मुख्य कारण श्रम उत्पादकता में अन्तर है, परन्तु श्रम की उत्पादकता में अन्तर क्यों है इसकी कोई व्याख्या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं प्रस्तुत करते हैं।

आधुनिक व्यापार सिद्धान्त में व्यापार के कारणों की दूसरी व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। हेक्शर ओहलिन के आधुनिक व्यापार सिद्धान्त के अनुसार व्यापार का कारण है- विभिन्न देशों के पास भिन्न-भिन्न साधन उपलब्धता। विभिन्न देशों में साधन उपलब्धताओं में भिन्नता के कारण ही वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में भिन्नता पायी जाती है जिससे देशों के बीच व्यापार सम्भव होता है।

सर्वप्रथम एली हेक्शर ने 1919 में यह विचार प्रस्तुत किया कि विभिन्न देशों में साधन सम्पन्नताओं में अन्तर के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्भव होता है। बर्टिन ओहलिन ने हेक्शर के इसी विचार के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धान्त प्रस्तुत किया। ओहलिन ने अपनी पुस्तक **Inter-regional and International Trade (1933)** में प्रतिष्ठित सिद्धान्त की आलोचना की ओर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सामान्य संतुलन सिद्धान्त प्रस्तुत किया। हेक्शर ओहलिन सिद्धान्त के अनुसार एक देश को उस वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ होगा और उसका निर्यात करेगा जो कि उस साधन का अधिक गहनता से प्रयोग करता है जो कि उस देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में, कुछ देशों के पास पूँजी अधिक है और कुछ देशों के पास श्रम। सिद्धान्त के अनुसार जो देश पूँजी सम्पन्न है वह पूँजी-प्रधान वस्तु तथा जो देश श्रम सम्पन्न है वह श्रम-प्रधान वस्तु का उत्पादन तथा निर्यात करेगा।

5.3.2 मान्यताएं

सिद्धान्त की व्याख्या से पहले हम इसकी मान्यताओं का अध्ययन करेंगे, जिन पर यह सिद्धान्त आधारित है।

1. मात्र दो उत्पादन के साधन हैं श्रम और पूँजी।
2. दो देश हैं। जोकि साधन सम्पन्नता में भिन्न है। एक देश पूँजी सम्पन्न है और श्रम दुर्लभ तथा दूसरा देश श्रम सम्पन्न और पूँजी दुर्लभ है।
3. मात्र दो वस्तुएँ हैं। दोनों वस्तुओं के उत्पादन में श्रम और पूँजी दोनों संसाधन लगे हैं।
4. सभी उत्पादन-फलन प्रथम कोटि के समरूप हैं।
5. उत्पादन फलन इस प्रकार के हैं कि दो वस्तुओं की कारक गहनता भिन्न है परन्तु दो देशों में प्रत्येक वस्तु की कारक गहनता समान है।
6. दो वस्तुओं के उत्पादन फलन भिन्न है परन्तु दोनों देशों में एक ही वस्तु का उत्पादन-फलन समान है। अर्थात् वस्तुएँ दोनों ही देशों में एक ही तकनीकी से उत्पादित होती है।

7. परिवहन लागत, प्रशुल्क एवं अन्य प्रतिरोध नहीं है।
8. वस्तु तथा साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता है।

इन मान्यताओं के आधार पर हेक्श्वर-ओहलिन प्रमेय कहती है कि पूँजी आधिक्य देश, पूँजी गहन वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा और निर्यात करेगा तथा श्रम प्रधान देश, श्रम-गहन वस्तु का उत्पादन तथा निर्यात करेगा।

5.3.3 साधन सम्पन्नता

हेक्श्वर-ओहलिन मॉडल में साधन-सम्पन्नता या प्रचुरता की धारणा को दो अर्थों में लिया गया है

1. साधन-सम्पन्नता को साधन कीमतों के रूप में परिभाषित किया गया है। मूल्य मापदण्ड के अनुसार एक देश जिसमें पूँजी सापेक्षिक रूप से सस्ती और श्रम सापेक्षिक रूप से महंगी है उसे पूँजी-प्रचुर देश कहा जाएगा भले ही इस देश में पूँजी और श्रम की उपलब्ध भौतिक मात्रा दूसरे देश के मुकाबले कितनी भी हो।

यदि दो देश I और II हैं तो देश A पूँजी-प्रचुर देश होगा यदि

$$\frac{Pk_1}{Pl_1} < \frac{Pk_2}{Pl_2}$$

जहाँ Pk_1 – देश I में पूँजी की कीमत

Pl_1 – देश I में श्रम की कीमत

Pk_2 – देश II में पूँजी की कीमत

Pl_2 – देश II में श्रम की कीमत

यह मापदण्ड दो देशों में उत्पादन के संसाधनों की माँग तथा पूर्ति दोनों दशाओं पर विचार करता है। ओहलिन सापेक्षिक संसाधन सम्पन्नता के लिए कीमत मापदण्ड का प्रयोग करते हैं परन्तु उनके अनुसार दो देशों में साधन कीमतों में अन्तर साधनों की आपूर्ति में भिन्नता के कारण होती है। दूसरे शब्दों में ओहलिन का विश्वास है कि किसी देश में साधनों की सापेक्षिक कीमत निर्धारण में पूर्ति पक्ष की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है।

2. साधन-सम्पन्नता को भौतिक पदों में भी परिभाषित किया जा सकता है। इस मापदण्ड के आधार पर एक देश सापेक्षिक रूप से पूँजी-प्रचुर देश होगा यदि दूसरे देश की अपेक्षा यहाँ पूँजी का अनुपात श्रम से अधिक है। इसी प्रकार एक देश श्रम-प्रचुर होगा यदि दूसरे देश की अपेक्षा यहाँ श्रम-पूँजी अनुपात अधिक है।

देश I पूँजी-प्रचुर और देश II श्रम-प्रचुर होगा यदि

$$\frac{k_1}{L_1} < \frac{k_2}{L_2}$$

जहाँ K_1 - देश I में पूँजी की कुल मात्रा

K_2 - देश II में पूँजी की कुल मात्रा

L_1 - देश I में श्रम की कुल मात्रा

L_2 - देश II में श्रम की कुल मात्रा

यह विशुद्ध पूर्ति पक्ष दृष्टिकोण है जो कि माँग दशाओं की पूरी तरह से उपेक्षा करता है।

साधन सम्पन्नता के दो वैकल्पिक मापदण्ड समान नहीं है। हेक्श्वर-ओहलिन का सिद्धान्त या प्रमेय कीमत-मापदण्ड का प्रयोग करने पर सिद्ध किया जा सकता है पर भौतिक मापदण्ड के साथ यह सिद्ध हो पाए, यह आवश्यक नहीं है। ओहलिन कीमत-मापदण्ड के आधार पर ही साधन-सम्पन्नता को परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार यदि एक देश में पूँजी सापेक्षतया पूँजी सस्ती है तो वहाँ पूँजी की पूर्ति अवश्य ही अधिक होगी और यदि श्रम सापेक्षिक सस्ता है तो उस देश में श्रम की प्रचुरता होनी चाहिए।

5.3.4 साधन सम्पन्नता के कीमत मापदण्ड के आधार पर सिद्धांत की व्याख्या

हेक्श्वर-ओहलिन प्रमेय; कि एक देश यदि पूँजी-प्रधान है तो पूँजी प्रधान वस्तु का उत्पादन और निर्यात करेगा तथा दूसरा देश जहाँ श्रम की प्रचुरता है वह श्रम-प्रधान वस्तु का उत्पादन तथा निर्यात करेगा; का परीक्षण हम चित्र की सहायता से साधन-सम्पन्नता को कीमत मापदण्ड के आधार पर परिभाषित करके करेंगे।

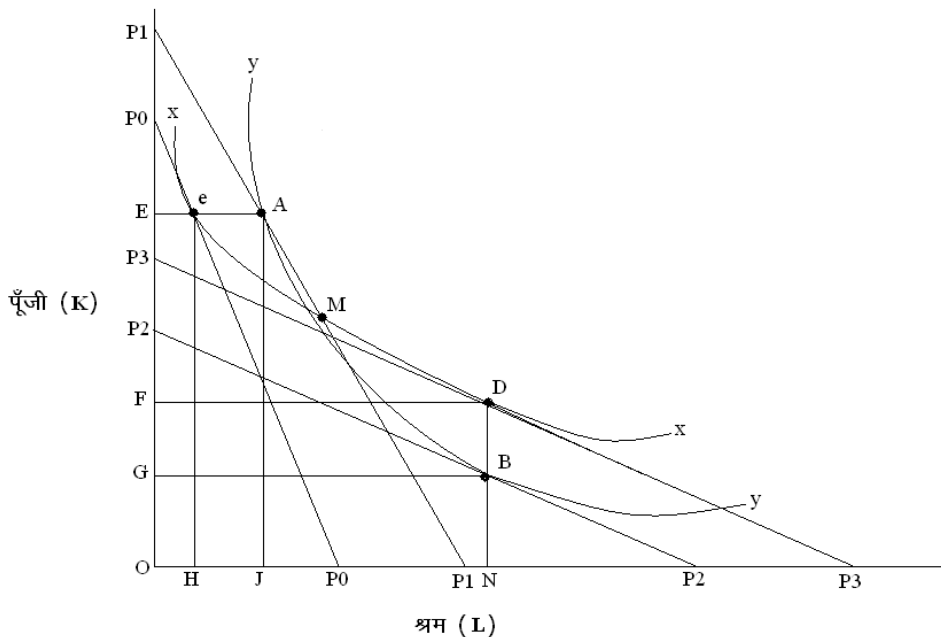
माना दो देश I और II हैं। जोकि दो साधनों श्रम (L) और पूँजी (K) के प्रयोग से दो वस्तुएँ X और Y का उत्पादन करते हैं।

चित्र में P_0P_0 देश I में साधन कीमत अनुपात तथा P_1P_1 देश II में साधन कीमत अनुपात को दर्शाता है। P_0P_0 तथा P_1P_1 की सापोक्षिक ढाल यह बताती है कि देश I में पूँजी सस्ती तथा श्रम महंगा है और देश II में श्रम सस्ता और पूँजी महंगी है। क्योंकि देश I में पूँजी प्रचुर तथा देश II श्रम-प्रचुर देश है।

वस्तु X का समोत्पाद वक्र xx तथा वस्तु Y का yy है जो कि क्रमशः वस्तु x तथा y की एक इकाई उत्पादन मात्रा को व्यक्त करते हैं। दोनों ही देशों में वस्तु x पूँजी-प्रधान तथा वस्तु y श्रम प्रधान है।

चित्र में समोत्पाद वक्र xx तथा yy एक दूसरे को केवल एक ही बार बिन्दु M पर काटते हैं। इससे यह प्रदर्शित होता है कि साधन गहनता की प्रतिलोमता नहीं है। अर्थात् एक वस्तु दोनों ही देशों में श्रम-प्रधान (वस्तु y) तथा दूसरी वस्तु दोनों ही देशों में पूँजी-प्रधान (वस्तु x) है। जैसी कि हेक्श्वर-ओहलिन की मान्यता है कि दो देशों में प्रत्येक वस्तु का उत्पादन फलन एक ही है।

चित्र की सहायता से अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे पूँजी प्रधान देश पूँजी-गहन वस्तु तथा श्रम-प्रधान देश श्रम-गहन वस्तु का निर्यात करेगा।



चित्र 5.1 कीमत-मापदण्ड के आधार पर साधन-सम्पन्नता

पूँजी-प्रचुर देश I में साधन कीमत अनुपात रेखा P_0P_0 तथा P_1P_1 है, जो एक दूसरे समानान्तर है। श्रम-प्रचुर देश II में साधन कीमत अनुपात को सामानान्तर रेखाएँ P_2P_2 तथा P_3P_3 द्वारा दिखाया गया है। P_0P_0 या P_1P_1 के ढाल से स्पष्ट है कि देश I में पूँजी सस्ती है। इसी प्रकार P_2P_2 या P_3P_3 के ढाल से स्पष्ट है कि देश II में श्रम सस्ता है।

देश I एक इकाई वस्तु-X का उत्पादन CH मात्रा में पूँजी तथा CE मात्रा में श्रम के संयोग से करता है, क्योंकि C बिन्दु पर x वस्तु का समोत्पाद वक्र, समलागत रेखा P_0P_0 को स्पर्श करता है। इसी प्रकार देश I में एक इकाई y वस्तु की लागत AJ मात्रा पूँजी तथा AE मात्रा श्रम का संयोग है।

स्पष्ट है कि देश I में एक इकाई वस्तु y के उत्पादन के लिए लगी पूँजी की मात्रा (AJ) वस्तु-x के उत्पादन में लगी पूँजी की मात्रा (CH) के बराबर है, परन्तु श्रम की मात्रा (AE), वस्तु x के उत्पादन में लगी श्रम की मात्रा (CA) से अधिक (AE=CE+CA)

आप इसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं देश I में, वस्तु-x की उत्पादन लागत = CH पूँजी + CE श्रम वस्तु y की उत्पादन लागत

$$= \text{AJ पूँजी} + \text{AE श्रम}$$

$$= \text{CH पूँजी} + \text{AE श्रम}$$

(क्योंकि चित्र में CH=AJ)

$$= \text{CH पूँजी} + (\text{CE} + \text{CA}) \text{ श्रम}$$

(क्योंकि AE=CE+CA)

$$= (\text{CH पूँजी} + \text{CE श्रम}) + \text{CA श्रम}$$

$$= \text{वस्तु-x की उत्पादन लागत} + \text{CA श्रम}$$

(क्योंकि वस्तु-x की उत्पादन लागत=eH पूँजी+ eE श्रम)

इसका अर्थ यह हुआ कि देश I में वस्तु-x,y की अपेक्षा सस्ती है। इसलिए पूँजी-प्रचुर देश I पूँजी-गहन वस्तु-x के उत्पादन में विशिष्टीकरण तथा निर्यात करेगा।

देश II एक इकाई वस्तु y का उत्पादन BN मात्रा में पूँजी तथा BG मात्रा में श्रम के संयोग से करता है। परन्तु वस्तु-x की उत्पादन लागत DN मात्रा में पूँजी तथा DF मात्रा में श्रम है। स्पष्ट है कि वस्तु-x की उत्पादन लागत में श्रम की मात्रा वस्तु-y के बराबर (DF=BG) परन्तु पूँजी की मात्रा (DN) वस्तु-y के उत्पादन में लगी मात्रा (BN) से अधिक है (DN=BN+BD)।

समीकरण के रूप में, आप इसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं।

देश II में,

$$\text{वस्तु-y की उत्पादन लागत} = \text{BG श्रम} + \text{BN पूँजी}$$

$$\text{वस्तु-x की उत्पादन लागत} = \text{DF श्रम} + (\text{BN} + \text{BD}) \text{ पूँजी}$$

(क्योंकि DF=BG तथा DN=BN+BD)

$$= (\text{BG श्रम} + \text{BN पूँजी}) + \text{BD पूँजी}$$

$$= \text{वस्तु-y की उत्पादन लागत} + \text{BD पूँजी}$$

स्पष्ट है कि देश II में वस्तु-y, वस्तु-x की अपेक्षा सस्ती है। इसलिए श्रम-प्रचुर देश II, श्रम गहन वस्तु-y के उत्पादन में विशिष्टीकरण तथा निर्यात करेगा।

इस प्रकार साधन-सम्पन्नता को साधन कीमतों के रूप में परिभाषित करने पर हेक्शर-ओहलिन प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रमेय का उल्टा भी उतना ही सही है अर्थात् यदि एक देश पूँजी प्रधान वस्तु का निर्यात करता है तो पूँजी उस देश में सापेक्षतया सस्ता उत्पादन का साधन है।

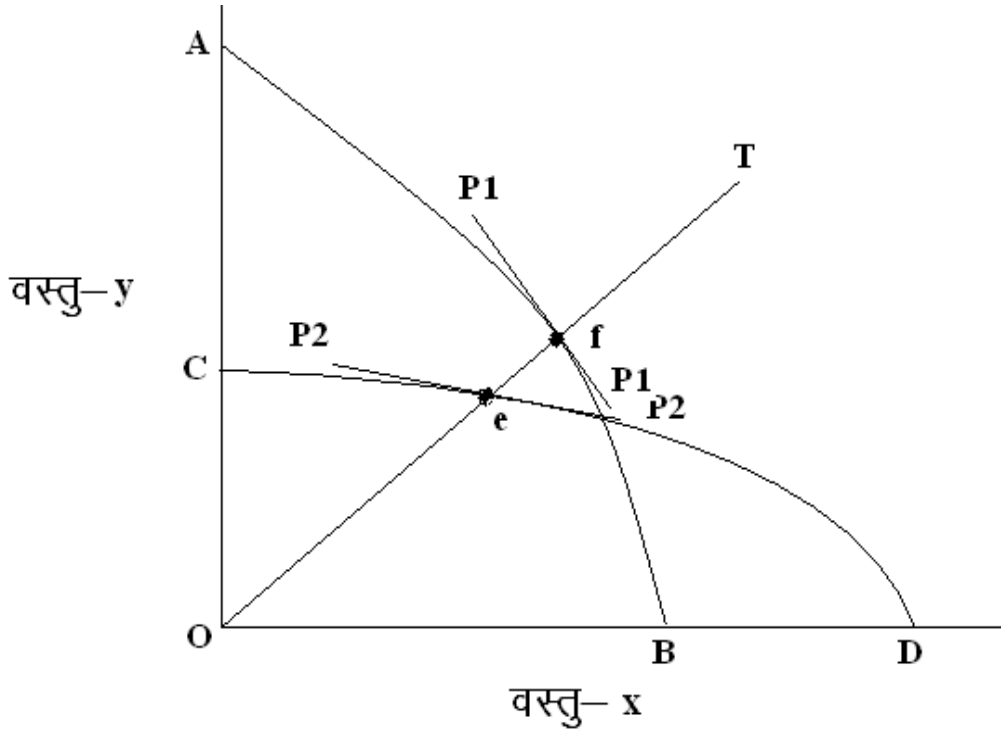
परन्तु साधन कीमतों के आधार प्रमेय को स्थापित करने में माँग दशाओं या साधन उपलब्धता को ध्यान में नहीं रखा गया है। वास्तव में साधन कीमतें साधन की माँग तथा पूर्ति की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल है और साधन की माँग उत्पादन की तकनीक के साथ-साथ वस्तुओं की माँग पर निर्भर करती है। स्पष्ट है कि सिर्फ साधन-सम्पन्नता के आधार पर साधन-कीमतों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

5.3.5 साधन सम्पन्नता के भौतिक मापदण्ड के आधार पर सिद्धांत की व्याख्या

जैसा कि आप ऊपर देख चुके हैं कि यदि दो देश I तथा II हैं, देश I पूँजी-प्रचुर तथा देश II श्रम-प्रचुर देश होगा, यदि

$$\frac{k_1}{L_1} > \frac{k_2}{L_2}$$

जहाँ K_1 तथा K_2 , क्रमशः देश I तथा II में पूँजी की कुल मात्रा और L_1 तथा L_2 . श्रम की मात्रा की

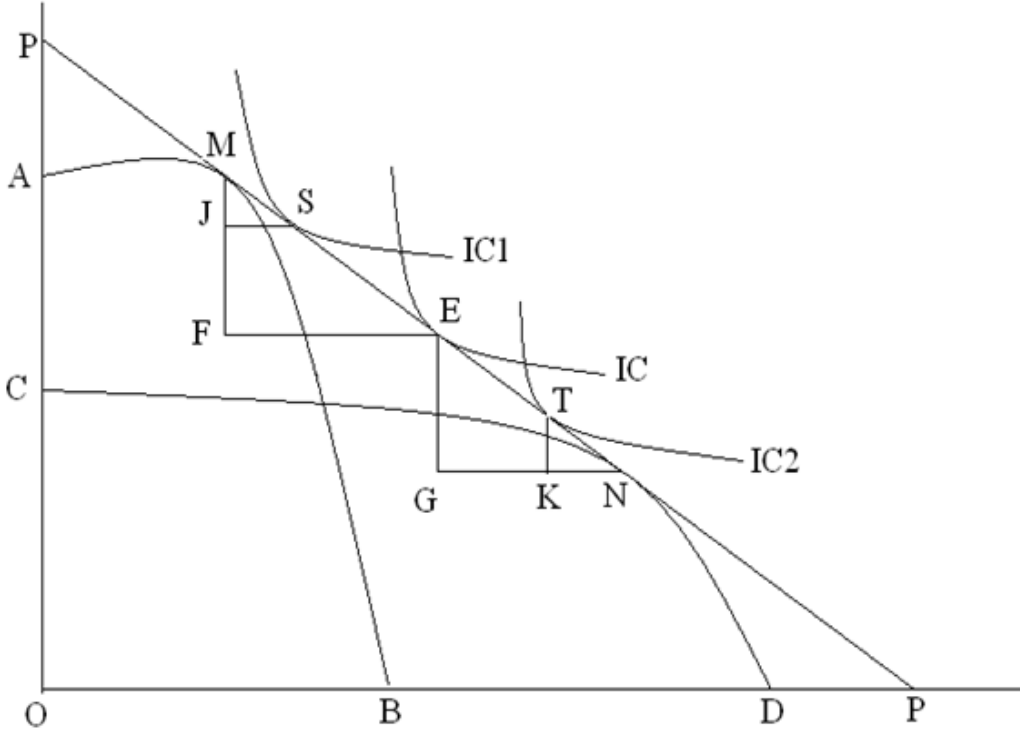


चित्र 5.2 भौतिक मापदण्ड के आधार पर साधन-सम्पन्नता

इस आधार पर अब हम यह दिखाएँ कि देश I जो कि भौतिक मापदण्ड के आधार पर पूँजी-सम्पन्न देश है, पूँजी- प्रधान वस्तु के उत्पादन की ओर झुकाव होगा तथा श्रम सम्पन्न देश II का झुकाव श्रम-प्रधान वस्तु की ओर होगा। इसे चित्र में दिखाया गया है।

चित्र 5.2 में तुलनात्मक रूप से वस्तु y पूँजी-प्रधान तथा वस्तु-x श्रम प्रधान वस्तु है। देश I का उत्पादन सम्भावना वक्र AB तथा देश II का CD है। मान लीजिए कि यदि दोनों देशों में दोनों वस्तुओं का उत्पादन समान अनुपात में, मूल बिन्दु से खींची गयी रेखा OT पर होता है, तो देश I अपने उत्पादन सम्भावना वक्र AB के बिन्दु f पर देश II, अपने उत्पादन सम्भावना वक्र ED के बिन्दु e पर उत्पादन करेगा। देश I के उत्पादन सम्भावना वक्र AB की बिन्दु f पर ढाल, देश II के वक्र ED के बिन्दु e की ढाल से अधिक तिरछी है। इसी प्रकार देश I की वस्तु कीमत रेखा P_1P_1 देश II की कीमत रेखा P_2P_2 से अधिक तिरछी है। इन सबका अर्थ यह है कि देश I में देश II

की अपेक्षा वस्तु y सस्ती है तथा देश II से देश I की अपेक्षा वस्तु x सस्ती है यदि दोनों देश क्रमशः बिन्दु f तथा e पर उत्पादन कर रहे होते हैं।



चित्र 5.3

अतः देश I में वस्तु y के उत्पादन के विस्तार की अवसर लागत, देश II की अपेक्षा कम है तथा देश II में वस्तु X के उत्पादन में विस्तार की अवसर लागत देश I की अपेक्षा कम है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि देश I, जो कि पूँजी-सम्पन्न देश है पूँजी-प्रधान वस्तु v तथा देश II जो कि श्रम-प्रचुर देश है। श्रम-प्रधान वस्तु x का उत्पादन बढ़ाने को उत्सुक होगा।

परन्तु इसके आधार पर हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि देश I, वस्तु y, का तथा देश II, वस्तु x का निर्यात करेगा। कौन सा देश किस वस्तु का निर्यात करेगा यह माँग कारकों पर निर्भर करेगा। भौतिक मापदण्ड के आधार पर हेक्शर-ओहलिन सिद्धान्त उसी स्थिति में सत्य हो सकता है जबकि दोनों देशों में प्रत्येक वस्तु के लिए उपभोक्ताओं की रुचियाँ उपभोग अधिमान समान हो और आयात माँग की लोच इकाई के बराबर हो।

5.3.5.1 जब उत्पादन तथा उपभोग का झुकाव भिन्न दिशाओं में हो

चित्र 5.3 में देश I तथा II का उत्पादन संभवना वक्र चित्र 5.2 की तरह ही है। चित्र में दोनों में माँग की दशाओं को भी दिखाया गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू होने के पश्चात्, देश I, वस्तु y के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है और उसका उत्पादन बिन्दु M पर विवर्तित हो जाता है। जबकि देश II वस्तु x के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है और अब N बिन्दु पर उत्पादन करता है। बिन्दु M तथा N उत्पादन के अनुकूलतम बिन्दु है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार-शर्त रेखा, M तथा N को स्पर्श करती है जो व्यापार के पश्चात् दोनों देशों की सापेक्षिक साधन कीमत रेखा भी है। इस प्रकार पूँजी-प्रचुर देश I, पूँजी-प्रधान वस्तु y का तथा श्रम-प्रचुर देश II, श्रम-प्रधान वस्तु x के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है।

यदि दोनों देशों में माँग की दशाएँ ऐसी हों, जिसे कि चित्र में IC वक्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो दोनों देश बिन्दु E पर उपभोग करते हैं। इस स्थिति में देश I, FM मात्रा वस्तु y का निर्यात तथा FE मात्रा में वस्तु x का

आयात करेगा जबकि देश II वस्तु x की GM मात्रा निर्यात तथा वस्तु y की GE मात्रा का आयात करेगा। अतः पूँजी प्रधान देश I, पूँजी प्रधान वस्तु y का निर्यात तथा श्रम-प्रधान वस्तु x का आयात करेगा। इसी प्रकार श्रम-प्रधान देश II, श्रम-प्रधान वस्तु x का निर्यात तथा पूँजी-प्रधान वस्तु y का आयात कर रहा है। ऐसी स्थिति में हेक्श्वर-ओहलिन प्रमेय स्थापित होती है, और पूरी तरह वैध है।

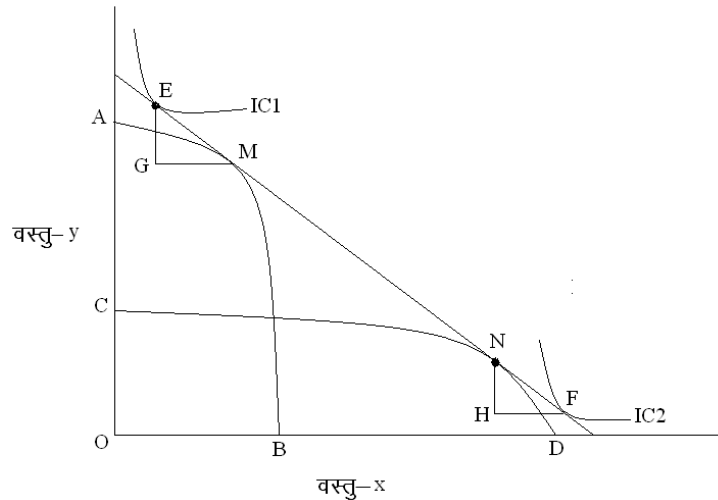
वास्तव में, हेक्श्वर-ओहलिन प्रमेय की वैधता के लिए यह आवश्यक है कि उपभोग बिन्दु, जैसे चित्र 5.3 में बिन्दु E, दोनों देशों के उत्पादन बिन्दुओं के बीच में कहीं हो अर्थात् बिन्दु M के दाहिनी ओर तथा बिन्दु N के बायीं ओर स्थित है।

दोनों देशों में उपभोक्ताओं की रुचियाँ समान होने पर चित्र 5.3 में दोनों देशों के लिए एक ही अधिमान वक्र IC है। परन्तु यदि दोनों देशों में उपभोक्ताओं की रुचियाँ भिन्न हों तो भी हेक्श्वर-ओहलिन प्रमेय मान्य होगा यदि उपभोग बिन्दु M और N के बीच स्थित है। चित्र में, उपभोक्ताओं की रुचियाँ दोनों देशों में भिन्न होने पर देश I का समुदाय अधिमान वक्र IC₁, तथा देश II का IC₂, है। इस स्थिति में, देश उत्पादन M तथा उपभोग S पर और देश II उत्पादन N तथा उपभोग T बिन्दु पर कर रहा है। देश I, JM मात्रा में वस्तु y का निर्यात तथा JS मात्रा में वस्तु x का आयात कर रहा है जबकि देश II KN मात्रा में वस्तु x का निर्यात तथा KT मात्रा में वस्तु y का आयात कर रहा है। और इस प्रकार हेक्श्वर-ओहलिन प्रमेय मान्य है।

यदि माँग दशाएँ ऐसी है कि देश I का समुदाय अधिमान वक्र बिन्दु S तथा देश II का बिन्दु N पर स्पर्श करें तो दोनों देश उसी बिन्दु पर उपभोग करेंगे जहाँ उत्पादन कर रहे हों। ऐसी स्थिति में दोनों देशों में व्यापार नहीं होगा। इस स्थिति में भी हेक्श्वर-ओहलिन सिद्धान्त मान्य होगा, परन्तु सिर्फ उत्पादन में विशिष्टीकरण के सम्बन्ध में माँग की दशाएँ व्यापार की दिशा में परिवर्तन ला सकती है।

5.3.5.2 जब उत्पादन तथा उपभोग का झुकाव एक ही दिशा में हो

जब दोनों देशों में उत्पादन तथा उपभोग का झुकाव एक ही दिशा में हो तो ऐसी स्थिति को चित्र 5.4 में दिखाया गया है।



चित्र- 5.4

चित्र 5.4 में, देश I का समुदाय अधिमान वक्र IC₁ है और देश II का IC₂ जोकि यह दर्शाता है कि देश I में माँग का झुकाव पूँजी-प्रधान वस्तु की ओर तथा देश II माँग का झुकाव श्रम-प्रधान वस्तु की ओर है। फलस्वरूप, देश I, उत्पादन M बिन्दु पर करता है और पूँजी-प्रधान वस्तु y के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है। दी हुई माँग दशाओं के अंतर्गत देश I, बिन्दु E पर उपभोग करेगा, अर्थात् वह GM मात्रा में वस्तु x का निर्यात करेगा तथा GE मात्रा में वस्तु y का आयात करेगा। इसी प्रकार देश II, वस्तु x के उत्पादन में

विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा और बिन्दु N पर उत्पादन करेगा। परन्तु दी हुई माँग दशाओं के अंतर्गत उपभोग बिन्दु F पर करेगा। इस प्रकार देश II, NH मात्रा में वस्तु y का निर्यात तथा HF मात्रा में वस्तु x का आयात करेगा।

स्पष्ट है कि माँग की प्रतिलोमता की स्थिति में पूँजी-प्रचुर देश I, श्रम-प्रधान वस्तु x का निर्यात तथा पूँजी प्रधान वस्तु y का आयात करेगा, जबकि श्रम-प्रचुर देश II, पूँजी प्रधान वस्तु y का निर्यात तथा श्रम-प्रधान वस्तु x का आयात करेगा। इस प्रकार पूर्ति या लागत दशाओं के आधार पर जो व्यापार की दिशा होनी चाहिए, उसे माँग की दशाएँ उलट देती है, और इस स्थिति में हेक्श्वर-ओहलिन प्रमेय असत्य हो जाती है।

5.3.6 निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि हेक्श्वर-ओहलिन सिद्धान्त में साधन-सम्पन्नता की दोनों व्यवस्थाएँ समान नहीं हैं। केवल साधन कीमतों के मापदण्ड के आधार पर साधन सम्पन्नता को परिभाषित करने पर ही यह सिद्धान्त सत्य सिद्ध होता है। भौतिक मापदण्ड के रूप में साधन सम्पन्नता को परिभाषित करने पर यह सिद्धान्त केवल तभी वैध होगा जब माँग की प्रतिलोमता की स्थिति न हो।

5.4 प्रतिष्ठित सिद्धान्त से तुलना

यह सिद्धान्त काफी व्यापक और तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत करता है। उपरोक्त विवेचना से आप समझ गए होंगे की हेक्श्वर ओहलिन द्वारा दिया गया, व्यापार का आधुनिक सिद्धान्त प्रतिष्ठित सिद्धान्त से काफी भिन्न है। साथ ही आधुनिक सिद्धान्त को निम्नलिखित आधार पर प्रतिष्ठित सिद्धान्त से बेहतर कहा जा सकता है

1. प्रतिष्ठित सिद्धान्त की तरह ओहलिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक अलग सिद्धान्त नहीं देते हैं, बल्कि मार्शल द्वारा दिए मूल्य के सामान्य सिद्धान्त में स्थान तत्व को सम्मिलित करके उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में विस्तार देते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंतरक्षेत्रीय व्यापार की ही एक विशेष स्थिति मानते हैं।
2. आधुनिक सिद्धान्त मूल्य के सामान्य संतुलन पर आधारित है, जबकि प्रतिष्ठित सिद्धान्त मूल्य के श्रम सिद्धान्त पर आधारित हो, जो कि अवास्तविक है।
3. रिकार्डों के सिद्धान्त में मात्र एक साधन श्रम है, जबकि ओहलिन श्रम और पूँजी दो साधन को लेकर अपने सिद्धान्त की व्याख्या करते हैं। परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि दो से अधिक साधन होंगे तो साधन गहनता की संकल्पना को परिभाषित करना मुश्किल हो जाएगा।
4. आधुनिक सिद्धान्त साधनों की पूर्ति में अन्तर के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढाँचे को निर्धारित करता है। साथ ही यह साधनों की सापेक्षिक कीमतों पर आधारित होने के कारण अधिक वास्तविक है। जबकि रिकार्डों साधनों की पूर्ति पर ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों पर ही विचार करते हैं। ओहलिन श्रम और पूँजी की सापेक्ष उत्पादकता के अंतरों को व्यापार का आधार मानते हैं। जबकि रिकार्डों सिर्फ श्रम की उत्पादकता के आधार पर ही सिद्धान्त की व्याख्या करते हैं।
5. रिकार्डों दो देशों में श्रम की गुणवत्ता में भिन्नता के आधार पर उत्पादन फलन में अंतर की व्याख्या करते हैं, जो कि व्यापार का आधार है। जबकि ओहलिन देशों की बीच साधन-सम्पन्नता में भिन्नता के कारण कीमतों में अन्तर की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार प्रतिष्ठित सिद्धान्त उत्पादन फलनों में अन्तर के आधार पर तुलनात्मक लाभ की व्याख्या करते हैं, इसके विपरीत आधुनिक सिद्धान्त दोनों देशों में एक वस्तु का एक उत्पादन-फलन मानता है और तुलनात्मक लाभ का आधार देशों के बीच साधन अनुपातों में भिन्नता को मानता है।

6. रिकार्डों तुलनात्मक लागत अंतरों का आधार क्या है, यह स्पष्ट नहीं करते हैं। ओहलिन के अनुसार संसाधनों की भौतिक मात्रा में अंतर के कारण देशों के बीच अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का उदय होता है न कि विभिन्न क्षेत्रों में साधनों की गुणवत्ता में अंतर के कारण। ओहलिन ने स्पष्ट किया कि विभिन्न क्षेत्रों/ देशों में साधन-अनुपातों में अन्तर के कारण ही तुलनात्मक लागतों में अन्तर होता है।
7. प्रतिष्ठित सिद्धान्त विदेशी व्यापार के कल्याणात्मक या मूल्यात्मक पक्ष को स्थापित करता है। इसके अनुसार व्यापार में सम्मिलित सभी देशों को व्यापार से लाभ होगा।

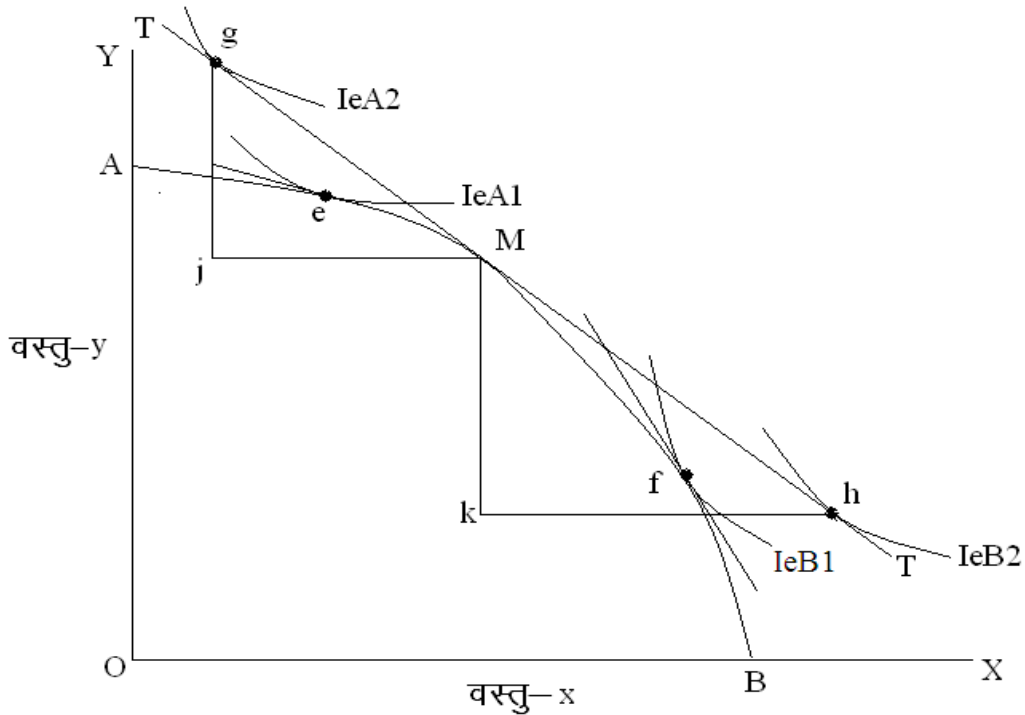
परन्तु ठीक यही बात आधुनिक सिद्धान्त के संदर्भ में नहीं कही जा सकती है। आधुनिक सिद्धान्त व्यापार से होने वाले लाभ पर ध्यान नहीं देता है बल्कि वह व्यापार की संरचना और साधन-कीमतों की स्थिति पर ही ध्यान देता है और इस आधार पर सिर्फ व्यापार के संतुलन की व्याख्या करता है, जो कि धनात्मक अर्थशास्त्र का हिस्सा बन जाता है न कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र का। इस प्रकार आधुनिक सिद्धान्त व्यापार के आधार पर केन्द्रित है, जबकि प्रतिष्ठित सिद्धान्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभों को दिखाने का प्रयास करता है। वस्तुतः आधुनिक सिद्धान्त, प्रतिष्ठित सिद्धान्त से बेहतर ढंग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारणों की व्याख्या करता है और यह उसमें एक बेहतर सुधार करता है।

5.5 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धान्त की कमियां

आधुनिक व्यापार सिद्धान्त की अनेक आधारों पर आलोचना की गयी है-

1. आधुनिक व्यापार सिद्धान्त की मान्यताएँ अवास्तविक तथा अति सरलीकृत हैं। यह सिद्धान्त केवल दो देश, दो वस्तुओं तथा दो साधनों को लेकर ही व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार, समान-उत्पादन-फलन, शून्य परिवहन लागत जैसी मान्यताएँ भी अवास्तविक हैं। परन्तु बाद में ओहलिन ने अनेक, प्रदेशों, अनेक वस्तुओं तथा अनेक साधनों के संदर्भ अपने सिद्धान्त को विस्तारित किया। इसी प्रकार ओहलिन के अनुसार अन्य मान्यताओं में ढील देने पर भी उनका सिद्धान्त उसी प्रकार मान्य है।
2. इस सिद्धान्त के अनुसार व्यापार का कारण दो देशों या क्षेत्रों के बीच साधन सम्पन्नता में भिन्नता है। परन्तु व्यवहार में विश्व व्यापार का एक बड़ा भाग ऐसे देशों के बीच होता है जिनकी साधन-सम्पन्नता लगभग एक जैसी है। वस्तुतः तुलनात्मक लागत में भिन्नता के कारण ही व्यापार होता है। ओहलिन का सिद्धान्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लागत को प्रभावित करने वाले घटकों जैसे, परिवहन लागतों, पैमाने की बचतों, आन्तरिक व बाह्य बचतों आदि की उपेक्षा करता है, और इस प्रकार यह सामान्य साम्य की प्रणाली को विकसित करने में असमर्थ है। प्रो. हैबरलर का कहना है कि यद्यपि ओहलिन का सिद्धान्त वास्तविकता के अधिक निकट है परन्तु यह पूर्ण सामान्य संतुलन प्रणाली को विकसित करने में असफल है। मोटे तौर पर यह एक आंशिक संतुलन विश्लेषण ही है।
3. हेक्शर-ओहलिन सिद्धान्त की वैधता के लिए यह आवश्यक है कि दो देशों में एक वस्तु के उत्पादन-फलन समान हो एवं कारक-गहनता की प्रतिलोमता हो। अर्थात् दो वस्तुओं के समोत्पाद वक्र एक-दूसरे को केवल एक ही बार काटे। कारण-गहनता की प्रतिलोमता की स्थिति में, अर्थात् जब दो समोत्पाद वक्र एक दूसरे को एक से अधिक बार काटेंगे, हेक्शर-ओहलिन सिद्धान्त अवैध हो जाता है। मिन्हास तथा अन्य लोगों ने 19 देशों के 24 उद्योगों के आँकड़ों के आधार पर यह पाया कि 5 मामलों में साधन प्रतिलोमता की स्थिति है। हालांकि लियोन्टीफ तथा मोरोनी मिन्हास के निष्कर्षों की आलोचना करते हैं। परन्तु यह स्पष्ट है कि साधन-प्रतिलोमता की स्थिति में हेक्शर-ओहलिन मॉडल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संरचना तथा दिशा के निर्धारण में महत्वहीन हो जाता है।

4. ओहलिन के अनुसार दो देशों के बीच साधनों की कीमतों में सापेक्षिक अंतर का कारण साधनों की उपलब्धता में सापेक्षिक अंतर है। अर्थात् साधनों के मूल्य निर्धारण में माँग की अपेक्षा पूर्ति अधिक महत्वपूर्ण है। परन्तु यदि माँग की दशाएँ पूर्ति की अपेक्षा साधनों के कीमत निर्धारण में अधिक महत्वपूर्ण हो जाएँ तो सम्भव है कि पूँजी-प्रधान देश श्रम-प्रधान वस्तु का निर्यात करने लगे, जो कि ओहलिन की परिकल्पना के विपरीत है। लियोन्टीफ ने अपने आनुभविक जाँच में यह पाया कि अमेरिका एक पूँजी प्रधान देश होते हुए भी, श्रम-प्रधान वस्तु का निर्यात तथा पूँजी गहन वस्तु का आयात करता है। इसी को 'लियोन्टीफ विरोधाभास' कहते हैं।
5. यदि उपभोक्ताओं के अधिमान और वस्तुओं की माँग पर भी विचार किया जाए तो वस्तु कीमत अनुपात लागत अनुपात से भिन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में ओहलिन का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। दो देशों में समान साधन अनुपात होते हुए भी उपभोक्ता के अधिमान, रुचि या आय-वितरण में अंतर के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है। इस प्रकार दो देशों में साधन तथा वस्तु बाजारों में माँग दशाओं में सापेक्षिक भिन्नता भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार हो सकती है। दो A देश और B हैं, जो कि x और y का उत्पादन करते हैं। दोनों ही देशों का उत्पादन संभावना वक्र AB है। व्यापार से पूर्व देश A का उत्पादन तथा उपभोग का साम्य बिन्दु e पर तथा देश B का f पर है। स्पष्ट है कि देश A में वस्तु y के लिए तथा देश B में वस्तु x के लिए उपभोक्ताओं की रुचि अत्यन्त तीव्र है।



चित्र- 5.5

व्यापार शुरू होने के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा TT के अनुसार दोनों देश व्यापार करते हैं। दोनों देशों का उत्पादन का संतुलन बिन्दु M पर होगा। देश A, वस्तु x तथा देश B वस्तु y के उत्पादन में विशिष्टीकरण का प्रयास करता है। परन्तु व्यापार के पश्चात् दोनों देश अपने उत्पादन संभावना वक्र के बाहर बिन्दु पर उपभोग कर रहे हैं। देश A, बिन्दु g पर तथा देश B का संतुलन बिन्दु h पर होगा। स्पष्ट है कि साधन समानुपात भिन्न होने पर भी व्यापार हो सकता है।

6. साधनों में गुणात्मक भिन्नता, भिन्न उत्पादन तकनीक, उपभोक्ताओं की माँग में भिन्नता आदि कारणों से भी दो देशों की सापेक्षिक कीमतों में भिन्नता हो सकती है। ओहलिन भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। परन्तु उनके अनुसार साधनों की उपलब्धता में अन्तर व्यापार के आधार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है।
7. **विजनहोल्ड्स** का कहना है कि वस्तुओं की कीमतें उनकी उत्पादन लागतों से निर्धारित नहीं होती है बल्कि उसकी उपभोक्ताओं के लिए उसकी उपयोगिता से। कच्चे माल और श्रम की कीमतें अंततः वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती हैं।
8. आधुनिक सिद्धान्त भी स्थैतिक है क्योंकि यह उत्पादन के साधनों की मात्रा, उपभोक्ताओं की आय तथा पसन्दगी, उत्पादन फलन इत्यादि दिया हुआ मान लेता है।

5.6 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत की आनुभविक जाँच

जो सिद्धान्त व्यावहारिक स्थितियों की व्याख्या जितने ही बेहतर ढंग से करेगा वह उतना ही अधिक उपयोगी होगा। सर्वप्रथम मैकडूगल ने व्यापार सिद्धान्तों के सत्यापन का प्रयास आनुभविक जाँच के आधार पर किया। बाद में अनेक अर्थशास्त्रियों ने आधुनिक व्यापार सिद्धान्त को आधुनिक प्रयासों की कसौटी पर कसने का प्रयास किया।

5.6.1 लियोन्टीफ का विरोधाभास

हेक्श्वर-ओहलिन सिद्धान्त के सत्यापन के संदर्भ में पहला व्यापक अध्ययन 1951 में लियोन्टीफ ने किया। लियोन्टीफ ने संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि पूँजी प्रधान है, के आयातों-निर्यातों का अध्ययन किया। वे अपने अध्ययन में हेक्श्वर-ओहलिन के सिद्धान्त के विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अमेरिका पूँजी प्रधान देश होते हुए भी श्रम प्रधान वस्तु का निर्यात तथा पूँजी प्रधान वस्तु का आयात करते हैं। अर्थात् निर्यात उद्योगों की अपेक्षा आयात प्रतियोगी उद्योग सापेक्षतया अधिक पूँजी-गहन है। **लियोन्टीफ** के शब्दों में **“श्रम के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन में अमेरिका की भागीदारी उत्पादन के पूँजी-गहन तरीकों की अपेक्षा श्रम-गहन तरीकों के विशिष्टीकरण पर आधारित है।”** चूंकि लियोन्टीफ के निष्कर्ष हेक्श्वर-ओहलिन के निष्कर्षों के विपरीत थे, इसलिए इसे ‘लियोन्टीफ विरोधाभास’ कहा गया।

5.6.2 अन्य अध्ययन

लियोन्टीफ के अध्ययन से प्रोत्साहित होकर अनेक देशों में हेक्श्वर-ओहलिन सिद्धान्त का परीक्षण अर्थशास्त्रियों ने किया। जापान के दो अर्थशास्त्री **टेटमोटो** तथा **इशिमूरा** ने जापान के व्यापार-ढाँचे का अध्ययन किया और लियोन्टीफ-विरोधाभास की पुष्टि की। अध्ययन के अनुसार जापान एक श्रम-प्रधान देश है, जबकि यह पूँजी-गहन वस्तुओं का निर्यात करता है। उसी प्रकार **स्टोप्लर** और **रोस्कैम्प** ने पूर्वी जर्मनी के अध्ययन में पाया कि पूर्वी जर्मनी पूँजी गहन वस्तु का निर्यात करता है और श्रम गहन वस्तु का आयात, जबकि पूर्वी जर्मनी वास्तव में एक पूँजी-प्रधान देश नहीं है। इसी प्रकार **वाल** ने कनाडा के अमेरिका के साथ व्यापार ढाँचे के अध्ययन में पाया कि कनाडा के निर्यात उसके आयातों की अपेक्षा अधिक पूँजी-गहन थे। जबकि अमेरिका, कनाडा से अधिक पूँजी प्रधान देश है।

आर. भारद्वाज ने भारत के अमेरिका के साथ व्यापार ढाँचे के अध्ययन में पाया कि भारत के आयातों की अपेक्षा, निर्यात अधिक पूँजी-गहन थे। जबकि भारत एक श्रम-गहन देश है। यह निष्कर्ष हेक्श्वर-ओहलिन सिद्धान्त का खण्डन करता है।

5.6.3 लियोन्टीफ विरोधाभास की आलोचना

लियोन्टीफ विरोधाभास, हेक्श्वर-ओहलिन सिद्धान्त ने इस विरोधाभास के हल के लिए अनेक वैकल्पिक व्याख्याएँ प्रस्तुत की और हेक्श्वर-ओहलिन प्रमेय की रक्षा करने का प्रयास किया। लियोन्टीफ द्वारा लिए गए आँकड़ों की विश्वसनीयता तथा उपयुक्तता पर सवाल भी खड़े किये गए। कुछ आलोचकों ने उनकी अध्ययन प्रणाली को भी चुनौती दी।

1. आलोचक लियोन्टीफ के जाँच करने की विधि को तर्कपूर्ण नहीं मानते। वास्तविक आयातों की जगह उनका अध्ययन निर्यात उद्योगों तथा प्रतियोगी आयात प्रतिस्थापन उद्योगों पर केन्द्रित है। लियोन्टीफ ने जो मेथडोलॉजी अपनायी वह अमेरिका के वास्तविक आयातित वस्तुओं की पूँजी गहनता को नहीं बताता है। यदि वास्तविक आयातित वस्तुओं के पूँजी-श्रम अनुपात का अध्ययन किया जाता तो निश्चित ही वे आयात श्रम-गहन होता।
2. प्रो. बुकानन ने लियोन्टीफ द्वारा पूँजी की माप को दोषपूर्ण बताया क्योंकि लियोन्टीफ ने पूँजी-गुणांक की नहीं बल्कि वांछित निवेश गुणांक की गणना की है। इस प्रकार विविध उद्योगों में पूँजी के टिकाऊपन पर ध्यान नहीं दिया है।
3. अनेक शोधकर्ताओं का कहना है कि यदि भौतिक पूँजी में मानव पूँजी को भी जोड़ दिया तो लियोन्टीफ विरोधाभास का समाधान हो जाएगा। वास्तव में निर्यात क्षेत्र में लगी 'मानव पूँजी' उच्चकोटि की है जिसकी उत्पादकता काफी अधिक है। इसलिए कैनन अमेरिकी निर्यातों को 'श्रम-गहन' कहने की बजाए 'मानव पूँजी गहन' वस्तु कहते हैं।
4. पी. टी. एल्सवर्थ के अनुसार लियोन्टीफ को अमेरिका के निर्यात तथा विदेशी निर्यात की तुलना करनी चाहिए थी। आयात-प्रतिस्थापन के लिए श्रम-पूँजी अनुपात की गणना दूसरे देश की आगत-निर्गत सारणी के आधार पर करनी चाहिए थी क्योंकि अमेरिका अपने आयातों को प्रतिस्थापित करने के लिए जिन वस्तुओं का उत्पादन करेगा वे पूँजी-प्रधान ही होंगी।
5. हैबरलर के अनुसार लियोन्टीफ ने पूँजी में श्रम को छोड़कर उत्पादन के अन्य साधन, मशीनरी एवं प्लांट आदि को सम्मिलित किया जबकि प्राकृतिक सम्पदा, साहसी एवं प्रबंध को छोड़ दिया। इन अन्य साधनों के कारण उत्पादन फलन भिन्न-भिन्न देशों में समरूप नहीं है।
6. ट्राविस का कहना है कि प्रतिबंधित व्यापार नीति की अवस्था में साधन-समानुपाती सिद्धान्त व्यापार के वास्तविक प्रवाह को दर्शाने में असमर्थ होता है। ट्राविस के अनुसार लियोन्टीफ विरोधाभास प्रतिबंधित व्यापार नीति का ही परिणाम है।
7. लियोन्टीफ विरोधाभास अमेरिका ने निर्यातों तथा आयातों पर माँग के प्रभाव की उपेक्षा करता है। रोमने राबिन्सन तथा जोन्स सहित अनेक अर्थशास्त्रियों का विचार है कि लियोन्टीफ का विरोधाभास माँग की दशाओं का परिणाम है। पूँजी प्रचुर देश होने के बाद भी चूँकि अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय काफी अधिक है, वहाँ पूँजी-प्रधान वस्तुओं की माँग अधिक हो सकती है।
8. लियोन्टीफ ने स्वयं ही इस विरोधाभास का हल ढंढने का प्रयास किया। लियोन्टीफ के अनुसार मात्रात्मक रूप से अमेरिका में श्रम की आपूर्ति या उपलब्धता भले सीमित लगे परन्तु यदि श्रम की गुणवत्ता पर विचार किया जाए तो अमेरिकी श्रम अन्य देशों की तुलना में कई गुना अधिक कुशल है। फलस्वरूप यहाँ श्रम की प्रभावी आपूर्ति, भौतिक उपलब्धता से तीन गुना अधिक है। यह अधिक उत्पादकता उद्योगशीलता, श्रेष्ठ संगठन तथा बेहतर वातावरण का परिणाम है। इस प्रकार यदि श्रम की उत्पादकता का समायोजन कर दिया जाए तो अमेरिका पूँजी-प्रधान नहीं बल्कि श्रम-प्रधान देश होगा। ऐसी स्थिति में

लियोन्टीफ के निष्कर्ष हेक्श्वर-ओहलिन सिद्धान्त को पुष्ट करते हैं। परन्तु लियोन्टीफ की इस व्याख्या की अनेक अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की। क्रेनिन ने अपने अध्ययन में पाया कि अमेरिकी श्रमिक, अन्य देशों में श्रमिकों की अपेक्षा मात्र 20 से 25% ही अधिक कुशल है, 300% नहीं, जैसा कि लियोन्टीफ का अनुमान है।

9. अन्य अध्ययनों में लियोन्टीफ-विरोधाभास के सम्बन्ध में अनेक अध्ययन इसका खण्डन करते हैं। जापान के अध्ययन में टाटेमोटो तथा इथीमूरा ने पाया कि जापान द्वारा अमेरिका के निर्यातों का पूँजी-श्रम अनुपात अमेरिका के आयातों के पूँजी-श्रम अनुपात से कम था। यह निष्कर्ष हेक्श्वर-ओहलिन सिद्धान्त के अनुरूप है।

पूर्वी जर्मनी पर किए गए अध्ययन में देखा गया कि उसका 75% व्यापार साम्यवादी देशों से होता है और पूर्वी जर्मनी अपने अन्य व्यापार भागीदारों से अधिक पूँजी-प्रचुर है। इस अध्ययन के निष्कर्ष कि पूर्वी जर्मनी पूँजी-गहन वस्तु का निर्यात तथा श्रम गहन वस्तु का आयात करता है, ओहलिन प्रमेय से मेल खाता है।

आर० भारद्वाज ने भारत के संदर्भ में भी यह देखा कि भारत के आयातों की अपेक्षा उसके निर्यात अधिक श्रम गहन थे। जहाँ तक अल्पविकसित देशों द्वारा पूँजी-गहन वस्तुओं के निर्यात करने का सवाल है तो यहाँ उल्लेखनीय है कि ये देश अधिकांशतः आयातित तकनीकी और मशीनरी का प्रयोग करते हैं और साथ ही पूँजी-प्रचुर विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ इन देशों में प्रत्यक्ष-विदेशी निवेश करके वस्तुओं का उत्पादन तथा निर्यात करने में संलग्न रहती हैं। और फिर इन देशों में कई कारणों से साधन कीमतें सही साधन-अनुपात को नहीं दर्शाती हैं।

वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि भूमि प्रचुर देश आस्ट्रेलिया भूमि-प्रधान वस्तुओं जैसे ऊन, माँस और गेहूँ आदि का निर्यात करता है। ब्राजील और कोलम्बिया कॉफी के बड़े निर्यातक हैं। खाड़ी देश पेट्रोलियम उत्पादों के बड़े निर्यातक हैं। ये सभी हेक्श्वर-ओहलिन सिद्धान्त की पुष्टि करते हैं। इस सिद्धान्त के अनेक अपवाद / विरोधाभास विश्व व्यापार में पाए जा सकते हैं परन्तु इससे सिद्धान्त अवैध नहीं हो जाता है।

वनेक ने अपने अध्ययन में बताया कि अमेरिका में अनेक प्राकृतिक संसाधन और पूँजी परस्पर पूरक है। इसलिए अमेरिका का व्यापार ढाँचा ऐसा है कि वह अपने दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखता है। दूसरे शब्दों में अमेरिका प्राकृतिक संसाधन गहन उत्पादन का आयात करता है न कि पूँजी-गहन उत्पाद का।

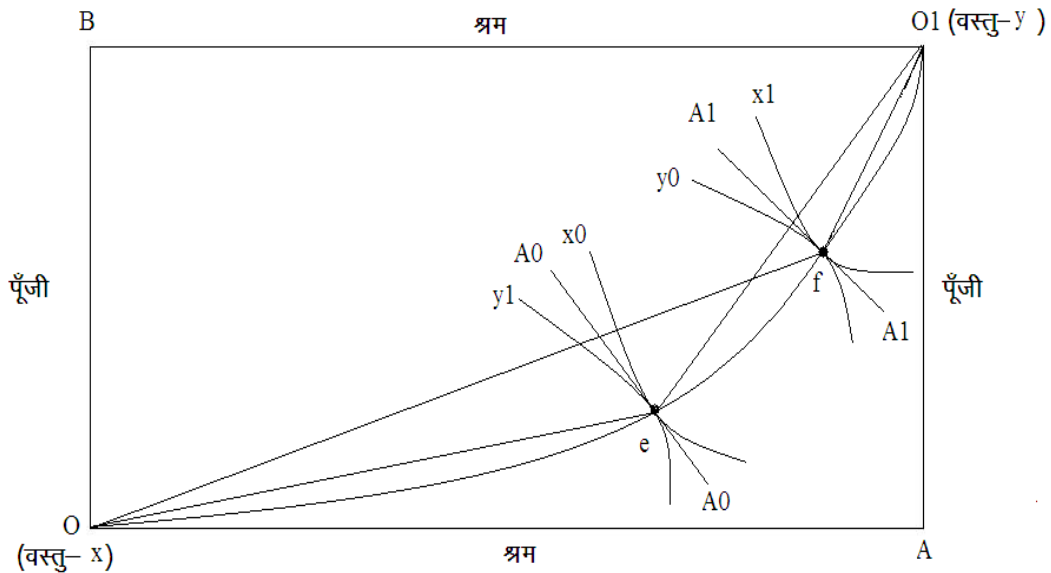
5.7 साधन कीमत समानीकरण प्रमेय

एली हेक्श्वर के अनुसार स्वतंत्र व्यापार से साधन कीमतों में पूर्ण समानता हो जाती है। दूसरी तरफ ओहलिन का कहना था कि व्यवहार में साधन-कीमतों में पूर्ण समानता सम्भव नहीं है। स्वतंत्र व्यापार से सिर्फ साधन-कीमत समानीकरण की प्रवृत्ति आती है और सिर्फ आंशिक साधन कीमत समानीकरण ही सम्भव है। स्टॉलपर तथा सैम्युल्सन और ऊजावा ने भी बाद में अपने मॉडलों में आंशिक समानीकरण का ही समर्थन किया। सैम्युल्सन ने बाद में और लर्नर ने पूर्ण साधन-कीमत समानीकरण के मॉडल दिए। आप 2x2x5 मॉडल (अर्थात् 2 देश, 2 वस्तुएँ और 2 साधन) के द्वारा देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप किस प्रकार साधन-कीमतों में समानीकरण होता है।

साधन कीमत समानीकरण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साधनों की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता का प्रतिस्थापन है। दो देशों की बीच वस्तुओं का स्वतंत्र व्यापार तुलनात्मक लागतों की भिन्नता को समाप्त कर देता है और साधनों के सापेक्षिक मूल्यों में समानता स्थापित हो जाती है।

देश A एक श्रम-प्रचुर देश है और पूँजी-दुर्लभ। इसलिए श्रम सस्ता तथा पूँजी मंहगी है। अतः पूँजी-श्रम अनुपात (K/L) सापेक्षतया कम है। इसी प्रकार देश B में श्रम दुर्लभ और मंहगा तथा पूँजी प्रचुर और सस्ती है तथा पूँजी-श्रम अनुपात (K/L) सापेक्षतया अधिक है। यह स्थिति व्यापार से पहले की है। व्यापार के पश्चात देश A में पूँजी-श्रम अनुपात बढ़ेगा और देश B में कम होगा, जब तक कि K/L अनुपात दो देशों में बराबर नहीं हो जाता। वास्तव में व्यापार शुरु होने के पश्चात देश A श्रम-प्रधान वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा और उसका निर्यात करेगा। जिससे श्रम सापेक्षतया दुर्लभ होता जाएगा और उसकी कीमत बढ़ेगी। जबकि दुर्लभ साधन पूँजी सापेक्षिक रूप से प्रचुर हो जाएगी और इसकी कीमत गिरेगी। इसी प्रकार देश B में व्यापार के बाद पूँजी-प्रधान वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण से पूँजी की कीमत बढ़ेगी तथा दुर्लभ साधन श्रम सापेक्षतया प्रचुर हो जाएगा और उसकी कीमत घटेगी तथा इस प्रकार K/L घटेगा। इस प्रकार व्यापार के परिणामस्वरूप बिना उत्पादन के संसाधनों की गति के दो देशों के बीच साधन कीमतें (K/L अनुपात) समान हो जाती है। साधन-कीमत समानीकरण की प्रक्रिया को एडवर्थ-बाडले बाक्स-चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं।

दो देश A और B में वस्तु x तथा y का उत्पादन होता है। चित्र 5.6 में x और y का मूल बिन्दु क्रमशः O तथा O1 दिखाया गया है। पूँजी को उर्ध्व अक्ष तथा श्रम को क्षेतिज अक्ष पर लिया गया है। दोनों ही देशों में सदैव ही वस्तु x श्रम-गहन तथा वस्तु y पूँजी-गहन है। देश A श्रम-प्रचुर तथा देश B पूँजी-प्रचुर देश है। चित्र 5.6 में बाक्स OAO1 B देश A के साधन पूर्ति को दर्शाता है। संविद वक्र OeO1 है जो कि यह बताता है कि वस्तु x श्रम-गहन तथा वस्तु y पूँजी गहन है।



चित्र- 5.6

समोत्पाद वक्र x_0x_1 वस्तु x के लिए तथा y_0y_1 वस्तु y के लिए है। व्यापार से पहले देश A, बिन्दु e पर उत्पादन करता है। जहाँ कि वस्तु x का समोत्पाद वक्र x_0 , वस्तु y के समोत्पाद वक्र Y को स्पर्श करता है। साधन कीमत रेखा P_0P_0 भी बिन्दु e पर दोनों वस्तुओं के समोत्पाद वक्रों को स्पर्श कर रही है। बिन्दु e पर वस्तु x में पूँजी-उत्पाद

अनुपात (K./L.) वस्तु y के पूँजी-उत्पाद अनुपात (Ky/Ly) से कम है। जो कि यह स्पष्ट करता है कि वस्तु y पूँजी-गहन तथा वस्तु x श्रम-गहन है। ज्यामितीय रूप में वस्तु x पूँजी श्रम अनुपात-

$$\frac{Kx}{Lx} = \angle eo'B \text{ तथा } \frac{Ky}{Ly} = \angle eo'B$$

चित्र में $\angle eo'B > \angle eoA$
अर्थात्

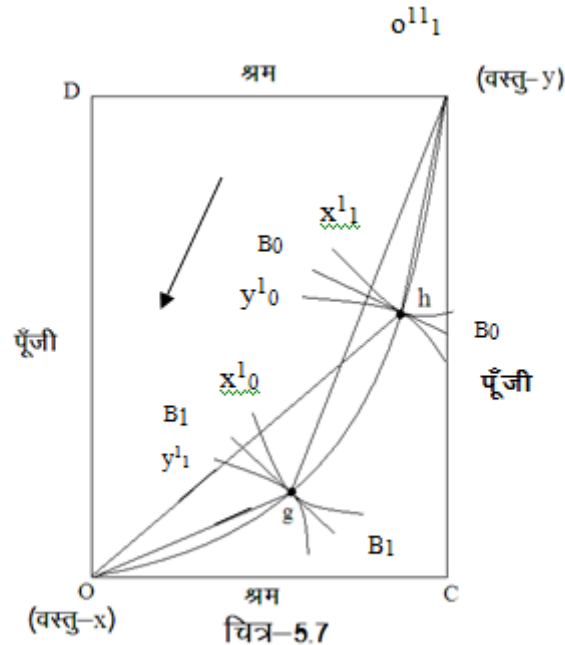
$$\frac{Ky}{Ly} > \frac{Kx}{Lx}$$

अर्थात् वस्तु y पूँजी प्रधान तथा x श्रम-प्रधान है। व्यापार शुरू होने के पश्चात देश A वस्तु x के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा और वह उत्पादन संसाधनों को वस्तु y से वस्तु x उद्योग में लगाएगा। परिणाम स्वरूप संविदा वक्र पर उसका उत्पादन का संतुलन e से बिन्दु f पर चला जाएगा। देश A द्वारा व्यापार के पश्चात वस्तु x का उत्पादन बढ़ाने पर बिन्दु f पर इसके उत्पादन पूँजी-श्रम अनुपात में वृद्धि हो गयी जबकि वस्तु y का उत्पादन घटाने से उसके उत्पादन पूँजी-श्रम अनुपात ($\frac{Ky}{Ly}$) में भी वृद्धि हो गयी।

बिन्दु f पर, $\angle FoA > \angle eoA$ तथा

$$\angle fo'B > \angle eo'B$$

स्पष्ट है कि व्यापार के पश्चात, श्रम-प्रचुर देश A में दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में पूँजी-श्रम अनुपात में वृद्धि हो गयी। यह साधन कीमत रेखा के ढाल में परिवर्तन से भी स्पष्ट है। व्यापार के पश्चात की साधन कीमत रेखा PIP1, व्यापार-पूर्व की कीमत रेखा P₀P₀ से अधिक तिरछी है।



चित्र 5.7 में, OCO'D के बाक्स, देश B, जो कि पूँजी-प्रचुर देश है, के कुल संसाधन आपूर्ति को बताता है। संविदा वक्र O'hO से स्पष्ट है कि वस्तु y, पूँजी गहन तथा वस्तु x, श्रम गहन है। व्यापार से पहले देश B बिन्दु h

पर उत्पादन करता है, जहाँ दोनों वस्तुओं के समोत्पादन वक्र x_0 तथा y_0 साधन कीमत रेखा P_0P_0 , पर, बिन्दु h पर स्पर्श करते हैं।

बिन्दु h पर

$$\frac{Kx}{Lx}, (X \text{ के उत्पादन में पूँजी-श्रम अनुपात}) = \angle hoe \text{ तथा } \frac{Kx}{Lx} = \angle ho^1D \angle ho^{11}D > \angle hoe$$

अर्थात् वस्तु y पूँजी-प्रधान तथा वस्तु x श्रम प्रधान है। व्यापार शुरु होने के पश्चात् देश B , वस्तु y के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करने के लिए उसका उत्पादन बढ़कर और नया उत्पादन का संतुलन बिन्दु पर होगा। फलस्वरूप देश B में वस्तु x तथा y दोनों में पूँजी-श्रम अनुपात में कमी आ जाती है।

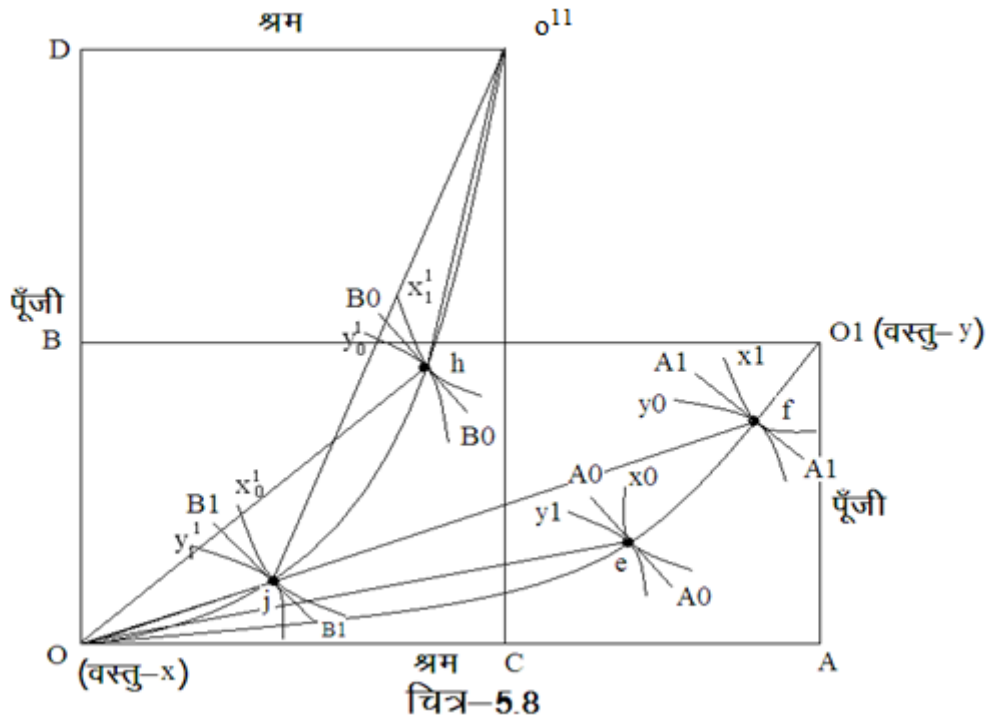
बिन्दु j पर,

$$\frac{Kx}{Lx} = \angle joc \text{ तथा } \frac{Ky}{Ly} = \angle jo^{11}D$$

चित्र में स्पष्ट है कि $\angle joc < \angle hoe$ तथा $\angle jo^{11}D < \angle ho^{11}D$

स्पष्ट है कि व्यापार के पश्चात्, पूँजी-प्रचुर देश B में दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में पूँजी-श्रम अनुपात में कमी हो गयी। यह साधन की सापेक्षिक कीमत अनुपात रेखा के ढाल में परिवर्तन से भी स्पष्ट है। व्यापार के पश्चात् P_1P_1 , P_0P_0 से अधिक सपाट हो जाती है।

अब आप दोनों देशों के बाक्स चित्र को संयुक्त रूप से एक साथ दिखाकर साधन-कीमत समानीकरण को दिखा सकते हैं।



चित्र 5.8 में दोनों देशों के बाक्स चित्रों को एक साथ दिखाया गया है। वस्तु x के लिए दोनों देशों का मूल बिन्दु O है। जबकि वस्तु y के लिए देश A का मूल बिन्दु $O1O$ तथा देश B मूल बिन्दु $O11O$ है। देश A में वस्तु x तथा y के समोत्पादन वक्रों के स्पर्श बिन्दुओं से प्राप्त संविदा वक्र $OeO1$ है। जबकि देश B का संविदा वक्र $OjO11$ है। दोनों देशों के संविदा वक्र इस प्रकार से है कि दोनों ही देशों में सभी साधन-कीमत अनुपातों पर वस्तु x

श्रम-गहन तथा वस्तु y पूँजी-गहन है क्योंकि दोनों वस्तुओं के उत्पादन फलन दोनों देशों में समान हैं, भले ही साधनों की कीमतों में भिन्नता हो।

व्यापार से पूर्व देश A, बिन्दु e तथा देश B, बिन्दु j पर उत्पादन कर रहा है। दोनों देशों में साधन कीमत अनुपात भिन्न है- देश A में A_0A_0 तथा देश B में B_0B_0 व्यापार से पूर्व साधन कीमत अनुपात को व्यक्त कर रही है। व्यापार शुरू होने के बाद दोनों देशों में उत्पादन का संतुलन परिवर्तित हो जाता है और साधन कीमत अनुपात भी परिवर्तित हो जाता है। देश A में उत्पादन का संतुलन बिंदु E से बिंदु F पर तथा देश B में h से j पर चला जायेगा साधन कीमत रेखा देश A में A_1A_1 तथा देश B में B_1B_1 हो जाती है। साधन-कीमत रेखा A_1A_1 तथा देश B_1B_1 में समानान्तर है। अर्थात् दोनों का ढाल बराबर है जो यह प्रदर्शित करता है कि व्यापार के पश्चात्, व्यापार के कारण दोनों देशों में साधनों की कीमतें समान हो जाएगी।

चित्र में व्यापार के पश्चात् देश A में

$$\text{वस्तु } x \text{ के उत्पादन में पूँजी-श्रम अनुपात } \left(\frac{Kx}{Lx}\right)_A = \angle fOA \text{ तथा देश में पूँजी-श्रम अनुपात } \left(\frac{Kx}{Lx}\right)_B = \angle jOA$$

चूँकि $\angle fOA = \angle jOA$

अतः वस्तु y में भी, दोनों देशों में, व्यापार के पश्चात् साधन-कीमत अनुपात समान हो जाता है।

अतः स्पष्ट है कि देशों के बीच संसाधनों की आवाजाही न होने पर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साधन-कीमतों में समानीकरण ले आता है और इस अर्थ में वस्तु और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार श्रम और पूँजी की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता का स्थानापन्न है।

5.7.1 साधन कीमत समानीकरण प्रमेय की आलोचना

साधन-कीमत समानीकरण प्रमेय के अनुसार-व्यापार के पश्चात् दोनों देशों में वस्तु के उत्पादन में पूँजी-श्रम अनुपात समान होगा। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वास्तविक जगत में भी व्यवहार में साधन कीमत समानीकरण सम्भव है। यह प्रमेय वास्तव में जिन मान्यताओं पर आधारित है वे अवास्तविक है और ऐसे अनेक बिन्दु हैं। जोकि साधन-कीमत समानीकरण में अवरोध पैदा करते हैं

1. व्यापार में सम्मिलित सभी देशों में उत्पादन फलन समरूप न होने की स्थिति में यह सिद्धान्त खण्डित हो जाता है। वास्तव में वस्तुओं के उत्पादन के लिए भौतिक जलवायु और सामाजिक तथा बौद्धिक वातावरण अलग-अलग देशों में उत्पादन फलन समरूप नहीं हो सकते।
2. यह सिद्धान्त पूर्ण प्रतियोगिता तथा उत्पादन में पैमाने के समान प्रतिफल की मान्यता पर आधारित है परन्तु वास्तविक विश्व में अपूर्ण तथा एकाधिकारिक प्रतियोगिता की स्थिति पायी जाती है तथा साथ ही बहुत सारी वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ते हुए प्रतिफल नियम भी लागू होता है।
3. यह सिद्धान्त यह मान लेता है कि पूरी तरह से स्वतंत्र व्यापार हो रहा है साथ ही व्यापार से परिवहन लागतें भी शून्य है। परन्तु वास्तविक जगत में अनेक प्रकार के प्रशुल्क तथा गैर-प्रशुल्क बाधाएँ व्यापार में आती ही हैं और फिर परिवहन लागत शून्य नहीं हो सकती। व्यापार प्रतिबन्धों और परिवहन लागतों की उपस्थिति में साधन कीमत समानीकरण सम्भव नहीं होगा। इसी कारण ओहलिन पूर्ण साधन कीमत समानीकरण की सम्भावना से इन्कार करते हैं। साधन कीमतों में पूर्ण समानता तभी सम्भव है जब उत्पादन के साधन स्वयं पूर्ण रूप से गतिशील हों।
4. इस सिद्धान्त के लिए यह भी आवश्यक है कि दोनों देश दोनों वस्तुओं का उत्पादन करें। यदि एक देश एक वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त करता है तो यह सिद्धान्त असफल हो जाता है।

5. साधन कीमतों में समानता के लिए यह जरूरी है कि साधनों की संख्या वस्तु की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनेक वस्तुओं, देशों तथा साधनों की स्थिति में साधन कीमतों की समानता संभव नहीं है।
6. यह सिद्धान्त संसाधनों की मात्रा को प्रत्येक देश में स्थिर मान लेता है जो कि अवास्तविक है।
7. साधन-प्रतिलोमता की स्थिति में यह सिद्धान्त लागू नहीं होता है क्योंकि इस स्थिति में पूँजी सम्पन्न देश पूँजी प्रधान तकनीकी का प्रयोग करके पूँजी गहन वस्तु का उत्पादन व निर्यात करेगा किन्तु श्रम प्रधान देश श्रम प्रधान तकनीकी से उसी वस्तु का उत्पादन करता है।
8. यह एक स्थैतिक सिद्धान्त है। यह एक दिए हुए समय में एक दी हुई संतुलन की स्थिति की कुछ विशेषताओं का केवल अध्ययन करता है। दी हुई तकनीक पर संसाधनों इत्यादि के दिए होने पर व्यापार का प्रभाव क्या हो, परन्तु वास्तविक जगत में चीजें तेजी से बदलती रहती हैं। ऐसे में वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार के जरिए साधन कीमत में पूर्ण समानता संभव नहीं है।

इन तमाम आलोचनाओं के बावजूद इतना अवश्य कहा जा सकता है कि देशों की बीच संसाधनों की अगतिशीलता हो तो, वस्तुओं व सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साधन कीमत समानीकरण के सबसे बेहतर स्थितियाँ पैदा करता है। निःसंदेह व्यापार के अभाव में साधन मूल्यों की भिन्नता और अधिक हो सकती है।

5.8 अभ्यास हेतु प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्त की मान्यताएँ बताइए।
2. विदेशी व्यापार के सामान्य संतुलन दृष्टिकोण पर टिप्पणी लिखिए।
3. साधन-गहनता की प्रतिलोमता क्या है?
4. साधन-प्रचुरता का क्या अर्थ है? समझाइए।
5. आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्त की आलोचना कीजिए।
6. आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्त की प्रतिष्ठित सिद्धान्त से तुलना कीजिए।
7. लियोन्टीफ विरोधाभास पर टिप्पणी लिखिए।
8. लियोन्टीफ विरोधाभास की आलोचना लिखिए।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. सामान्य संतुलन दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्त में लागू करने के लिए ओलिन इसमें किस तत्व को जोड़ते हैं?
 - A) समय
 - B) बाज़ार
 - C) स्थान
 - D) कीमत
2. ओलिन के अनुसार तुलनात्मक लागत अंतर का कारण है :
 - A) श्रम लागत अंतर
 - B) विभिन्न देशों में संसाधन उपलब्धता में अंतर
 - C) विनिमय दरों में अंतर
 - D) उपरोक्त में से कोई नहीं

3. ओलिन के अनुसार प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा
 - A) जिसके उत्पादन में उस देश में उपलब्ध प्रचुर संसाधनों का प्रयोग होता हो
 - B) जिसके उत्पादन में उस देश में उपलब्ध सस्ते संसाधनों का प्रयोग होता हो
 - C) उपरोक्त दोनों
 - D) उपरोक्त में से कोई नहीं
4. किसके के अनुसार व्यवहार में साधन-कीमतों में पूर्ण समानता सम्भव नहीं है
 - A) एली हेक्शर
 - B) ओहलिन
 - C) सैम्युल्सन
 - D) लर्नर
5. साधन कीमत समानीकरण प्रमेय के अनुसार
 - A) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साधनों की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता का प्रतिस्थापन है।
 - B) स्वतंत्र व्यापार तुलनात्मक लागतों की भिन्नता को समाप्त कर देता है और साधनों के सापेक्षिक मूल्यों में समानता स्थापित हो जाती है।
 - C) व्यापार के पश्चात् दोनों देशों में वस्तु के उत्पादन में पूँजी-श्रम अनुपात समान होगा।
 - D) उपरोक्त सभी

सत्य व असत्य :

1. आधुनिक सिद्धान्त मूल्य के सामान्य संतुलन पर आधारित है, जबकि प्रतिष्ठित सिद्धान्त मूल्य के श्रम सिद्धान्त पर आधारित है।
2. वस्तुओं की कीमतों में भिन्नता मुख्यतः उत्पादन साधनों की पूर्ति या उपलब्धता में भिन्नता के कारण नहीं होती है।
3. हेक्शर ओहलिन सिद्धान्त के अनुसार जो देश पूँजी सम्पन्न है वह पूँजी-प्रधान वस्तु तथा जो देश श्रम सम्पन्न है वह श्रम-प्रधान वस्तु का उत्पादन तथा निर्यात करेगा।
4. कीमत मापदण्ड दो देशों में उत्पादन के संसाधनों की माँग तथा पूर्ति दोनों दशाओं पर विचार नहीं करता है।
5. हेक्शर-ओहलिन का सिद्धान्त या प्रमेय भौतिक मापदण्ड का प्रयोग करने पर सिद्ध किया जा सकता है पर कीमत-मापदण्ड के साथ यह सिद्ध हो पाए, यह आवश्यक नहीं है।
6. भौतिक मापदण्ड के रूप में साधन सम्पन्नता को परिभाषित करने पर यह सिद्धान्त केवल तभी वैध होगा जब माँग की प्रतिलोमता की स्थिति हो।
7. आधुनिक सिद्धान्त व्यापार से होने वाले लाभ पर ध्यान नहीं देता है बल्कि वह व्यापार की संरचना और साधन-कीमतों की स्थिति पर ही ध्यान देता है।
8. दो देशों में समान साधन अनुपात होते हुए भी उपभोक्ता के अधिमान, रुचि या आय-वितरण में अन्तर के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है।

5.9 सारांश

हेक्श्वर ओहलिन सिद्धान्त के अनुसार पूँजी आधिक्य देश, पूँजी गहन वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा और निर्यात करेगा तथा श्रम-प्रधान देश, श्रम-गहन वस्तु का उत्पादन तथा निर्यात करेगा। हेक्श्वर-ओहलिन मॉडल में साधन-सम्पन्नता या प्रचुरता की धारणा को दो अर्थों में लिया गया है- साधन कीमतों के रूप में तथा भौतिक पदों में। मूल्य मापदण्ड के अनुसार एक देश जिसमें पूँजी सापेक्षिक रूप से सस्ती और श्रम सापेक्षिक रूप से मंहगी है उसे पूँजी-प्रचुर देश कहा जाएगा भले ही इस देश में पूँजी और श्रम की उपलब्ध भौतिक मात्रा दूसरे देश के मुकाबले कितनी भी हो। भौतिक मापदण्ड के आधार पर एक देश सापेक्षिक रूप से पूँजी-प्रचुर देश होगा यदि दूसरे देश की अपेक्षा यहाँ पूँजी का अनुपात श्रम से अधिक है।

हेक्श्वर-ओहलिन का सिद्धान्त या प्रमेय कीमत-मापदण्ड का प्रयोग करने पर सिद्ध किया जा सकता है पर भौतिक मापदण्ड के साथ यह सिद्ध हो पाए, यह आवश्यक नहीं है। ओहलिन कीमत मापदण्ड के आधार पर ही साधन-सम्पन्नता को परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार यदि एक देश में पूँजी सापेक्षतया पूँजी सस्ती है तो वहाँ पूँजी की पूर्ति अवश्य ही अधिक होगी और यदि श्रम सापेक्षिक सस्ता है तो उस देश में श्रम की प्रचुरता होनी चाहिए। भौतिक मापदण्ड के रूप में साधन सम्पन्नता को परिभाषित करने पर यह सिद्धान्त केवल तभी वैध होगा जब माँग की प्रतिलोमता की स्थिति न हो जबकि दोनों देशों में प्रत्येक वस्तु के लिए उपभोक्ताओं की रुचियाँ उपभोग अधिमान समान हो और आयात माँग की लोच इकाई के बराबर हो।

लियोन्टीफ ने अपने अध्ययन में हेक्श्वर-ओहलिन के सिद्धान्त के विपरीत निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। अमेरिका पूँजी प्रधान देश होते हुए भी श्रम प्रधान वस्तु का निर्यात तथा पूँजी प्रधान वस्तु का आयात करते हैं। अर्थात् निर्यात उद्योगों की अपेक्षा आयात प्रतियोगी उद्योग सापेक्षतया अधिक पूँजी-गहन है। लियोन्टीफ के निष्कर्ष हेक्श्वर-ओहलिन के निष्कर्षों के विपरीत थे, इसलिए इसे 'लियोन्टीफ विरोधाभास' कहा गया।

साधन कीमत समानीकरण प्रमेय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साधनों की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता का प्रतिस्थापन है। दो देशों की बीच वस्तुओं का स्वतंत्र व्यापार तुलनात्मक लागतों की भिन्नता को समाप्त कर देता है और साधनों के सापेक्षिक मूल्यों में समानता स्थापित हो जाती है। देशों के बीच संसाधनों की आवाजाही न होने पर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साधन-कीमतों में समानीकरण ले आता है और इस अर्थ में वस्तु और सेवाओं में अं

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार श्रम और पूँजी की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता का स्थानापन्न है। साधन-कीमत समानकरण प्रमेय के अनुसार-व्यापार के पश्चात् दोनों देशों में वस्तु के उत्पादन में पूँजी-श्रम अनुपात समान होगा।

5.10 शब्दावली

- **मूल्य के सामान्य साम्य सिद्धान्त** - के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उसकी समग्र माँग तथा समपूर्ति द्वारा निर्धारित होती है।
- **कारक गहनता** - उत्पादन में प्रयुक्त साधनों का अनुपात। यदि दो साधन श्रम और पूँजी है तो श्रम और पूँजी का अनुपात कारक गहनता को व्यक्त करता है।
- **कारक गहनता की प्रतिलोमता** - उस स्थिति में पायी जाती है जब एक समोत्पाद वक्र दूसरे समोत्पाद वक्र पर स्थित हो या उसे एक अधिक बिन्दुओं पर काटे। इस तरह पहले को एक साधन गहनता प्रतिलोमता तथा दूसरे को बहुसाधन गहनता प्रतिलोमता कहते हैं।

- **संविदा वक्र** - किसी देश के दो वस्तुओं के समोत्पाद वक्रों के स्पर्श बिन्दुओं को मिलाने पर प्राप्त रेखा। संविदा वक्र के प्रत्येक बिन्दु पर पूँजी और श्रम की सीमांत उत्पादकता का अनुपात समान होता है इसलिए इसे उत्पादन के कुशलता बिन्दुओं का बिन्दूपथ कहते हैं।
- **लियोन्टीफ का विरोधाभास** - लियोन्टीफ ने संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि पूँजी प्रधान है, के आयातों-निर्यातों का अध्ययन किया। लियोन्टीफ के अनुसार अमेरिका पूँजी प्रधान देश होते हुए भी श्रम प्रधान वस्तु का निर्यात तथा पूँजी प्रधान वस्तु का आयात करते हैं। चूंकि लियोन्टीफ के निष्कर्ष 'हेक्शर-ओहलिन के निष्कर्षों के विपरीत थे, इसलिए इसे 'लियोन्टीफ विरोधाभास' कहा गया।
- **साधन कीमत समानीकरण** - दो देशों की बीच वस्तुओं का स्वतंत्र व्यापार तुलनात्मक लागतों की भिन्नता को समाप्त कर देता है और साधनों के सापेक्षिक मूल्यों में समानता स्थापित हो जाती है।

5.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न:

1. C, 2.B , 3.C 4.B 5.D

सत्य व असत्य :

1. सत्य 2.सत्य , 3. असत्य 4.असत्य 5.असत्य ,
6.असत्य , 7.सत्य , 8.सत्य

5.12 संदर्भ ग्रंथ सूची

- HH. G. Mannur, International Economics, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Bo Sodersten, International Economics, Macmillan, 1999
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: International Economics: Theory and Policy, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- Charles P Kindleberger, International Economics, Richard D. Irwin Inc. ,Illinois, 1968
- Dominik Salvatore, International Economics, John Willy & Sons, Inc., 2008 D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006
- सुदामा सिंह एवं एम0सी0 वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड एंड आई0बी0एच0 पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम0एल0 झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010।
- ज्ञानेंद्र सिंह कुशवाहा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1979।

5.13 उपयोगी/सहायक ग्रंथ

- HH. G. Mannur, International Economics, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001

- Bo Sodersten, International Economics, Macmillan, 1999
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: International Economics: Theory and Policy, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- Charles P Kindleberger, International Economics, Richard D. Irwin Inc. ,Illinois, 1968
- Dominik Salvatore, conomicsInternational E, John Willy & Sons, Inc., 2008
- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai,2006
- एस0 एन0लाल , अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद ,2004
- एच. एस. अग्रवाल,बरला 0 एस0तथा सी ,अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा , 2003.
- सुदामा सिंह एवं एम0सी0 वैश्य ,अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र ,ऑक्सफ़ोर्ड एंड आई0 बी0 एच0 पब्लिकेशन ,नई दिल्ली ,2007
- एम0 एल0 झिंगन ,अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र ,वृंदा पब्लिकेशन ,दिल्ली ,2010.
- डॉ.पी.जे .सिंघई एवं डॉ.सी.जी.श्री ,अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्तसाहित्य ,भवन पब्लिकेशंस आगरा,2010

5.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. हेक्श्वर-ओहलिन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्त का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
2. साधन-कीमत सामनीकरण प्रमेय की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
3. चित्र की सहायता से आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
4. प्रतिष्ठित व्यापार सिद्धान्त तथा आधुनिक व्यापार सिद्धान्त की तुलना कीजिए तथा बताइए कि किस प्रकार से आधुनिक सिद्धान्त, प्रतिष्ठित सिद्धान्त से श्रेष्ठ है?
5. लियोन्टीफ विरोधाभास का परीक्षण कीजिए।

इकाई 6- व्यापार की शर्तें और आर्थिक संवृद्धि (Terms of Trade and Economic Growth)

- 6.1 प्रस्तावना
- 6.2 उद्देश्य
- 6.3 व्यापार की शर्त
 - 6.3.1 व्यापार की शर्त का अर्थ
 - 6.3.2 व्यापार की शर्त के प्रकार
- 6.4 व्यापार की शर्त के सिद्धांत
 - 6.4.1 जे. एस. मिल का प्रतिपूरक मांग सिद्धांत
 - 6.4.2 प्रस्ताव वक्र विश्लेषण
- 6.5 व्यापार की शर्त एवं आर्थिक संवृद्धि
 - 6.5.1 व्यापार की शर्त और आर्थिक संवृद्धि में सम्बन्ध
 - 6.5.2 इमिजेराइजिंग विकास का सिद्धांत (Theory of Immiserising Growth)
 - 6.5.3 व्यापार की शर्त एवं विकासशील देश
- 6.6 अभ्यास हेतु प्रश्न
- 6.7 सारांश
- 6.8 शब्दावली
- 6.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 6.10 सन्दर्भ ग्रंथ सूची
- 6.11 उपयोगी/सहायक पाठ्य सामग्री
- 6.12 निबंधात्मक प्रश्न

6.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई में आपको व्यापार की शर्तों के साथ इसके विभिन्न प्रकार, और इसको निर्धारित करने वाले तत्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस इकाई में व्यापार की शर्त से सम्बंधित कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं। साथ ही व्यापार की शर्त और आर्थिक संवृद्धि के बीच के सम्बन्ध को भी रेखांकित किया गया है। इसके अलावा विकसित और विकासशील देशों के बीच व्यापार के कारण पैदा हुई विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया है।

6.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- ✓ व्यापार की शर्त के अर्थ को समझ सकेंगे। -
- ✓ व्यापार की शर्त के विभिन्न प्रकार से परिचित होंगे। -
- ✓ व्यापार की शर्त से सम्बंधित जे. एस. मिल के विचार और प्रस्ताव वक्र तकनीक से परिचित होंगे। -
- ✓ व्यापार की शर्त को प्रभावित करनेवाले घटक को जान पाएंगे। -
- ✓ व्यापार की शर्त तथा आर्थिक संवृद्धि के बीच के सम्बन्ध से परिचित होंगे। -
- ✓ विकासशील देशों का व्यापार की शर्त क्यों प्रतिकूल होता है, इसके बारे में जान सकेंगे।
- ✓ व्यापार को विकास का इंजन क्यों कहा जाता है, यह समझ सकेंगे।

6.3 व्यापार की शर्त

6.3.1 व्यापार की शर्त का अर्थ

साधारण शब्दों में जिस दर पर एक देश की वस्तुओं का विनिमय दूसरे देश की वस्तुओं से होता है, उसे व्यापार की शर्त कहा जाता है। इस प्रकार किसी देश के निर्यात और आयात के बीच का विनिमय अनुपात ही व्यापार की शर्त है। किन्तु आगे जब हम व्यापार की शर्त के विभिन्न प्रकार का अध्ययन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि व्यापार की शर्त का मतलब इससे कहीं अधिक व्यापक है। इसको निर्धारित करने में न सिर्फ विनिमय होने वाले वस्तुओं की भौतिक मात्रा का महत्व है बल्कि उनके मूल्यों का भी उतना ही अधिक महत्व है। साथ ही विनिमय होनेवाले वस्तुओं के उत्पादन में लगे साधनों व उनके पारिश्रमिक की दर का भी महत्व है।

6.3.2 व्यापार की शर्तों के प्रकार

व्यापार की शर्त को निर्धारित करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने कई सूत्र दिए हैं। इन्हें तीन श्रेणीओं में रखा गया है।

1. वस्तु-विनिमय अनुपात से सम्बंधित व्यापार की शर्त
2. संसाधनों के हस्तांतरण से सम्बंधित व्यापार की शर्त
3. उपयोगिता से सम्बंधित व्यापार की शर्त

1. वस्तु-विनिमय अनुपात से सम्बंधित व्यापार की शर्तें:

इनकी तीन श्रेणियाँ हैं -

- A) सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त,
- B) शुद्ध वस्तु-विनिमय व्यापार की शर्त तथा
- C) आय व्यापार की शर्त.

इनमें प्रथम दो अर्थात् सकल वस्तु-विनिमय व्यापार की शर्त तथा शुद्ध वस्तु-विनिमय व्यापार की शर्त का सूत्र **डब्लु. एफ. टौसिग (W.F. Taussig)** ने दिया है, जबकि अंतिम अर्थात् आय व्यापार की शर्त का सूत्र **डी. एस. डोरेंस (D.S. Dorrance)** ने दिया है।

a) सकल वस्तु-विनिमय व्यापार की शर्त (Gross Barter Terms of Trade): - इसके अनुसार व्यापार की शर्त, आयात की भौतिक मात्रा सूचकांक तथा निर्यात की भौतिक मात्रा सूचकांक का अनुपात है। इसके अनुसार हमें इस बात का पता चलता है की देश की वस्तु के निर्यात की भौतिक मात्रा और आयात की भौतिक मात्रा के बीच विनिमय का अनुपात क्या है। इसका सूत्र इस प्रकार है:

$$G = \frac{Mq}{Xq} X100$$

यहाँ G सकल वस्तु-विनिमय व्यापार की शर्त है, Ma आयात की भौतिक मात्रा का सूचकांक तथा X, निर्यात की भौतिक मात्रा का सूचकांक है। मात्रा सूचकांक की गणना किसी आधार वर्ष को मानकर किया जाता है।

b) शुद्ध वस्तु-विनिमय व्यापार की शर्त(Net Barter Terms of Trade): - इसके अनुसार व्यापार की शर्त, निर्यात मूल्य सूचकांक तथा आयात मूल्य सूचकांक का अनुपात है। इसके अनुसार देश से निर्यात की जाने वाली वस्तु के सापेक्षिक मूल्य का पता चलता है। इसका सूत्र इस प्रकार है:

$$N = \frac{Xp}{Mp} X100$$

यहाँ N शुद्ध वस्तु-विनिमय व्यापार की शर्त है, X, निर्यात मूल्य सूचकांक तथा M, आयात मूल्य सूचकांक है। यहाँ भी मूल्य सूचकांक की गणना किसी आधार वर्ष को मानकर किया जाता है। व्यापार की शर्त निकालने के लिए प्रायः इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है।

c) आय व्यापार की शर्त(Income Terms of Trade): - आय व्यापार की शर्त शुद्ध व्यापार की शर्त का संशोधित रूप है। इससे किसी देश की आयात क्षमता(capacity to import) का पता चलता है। इसका सूत्र इस प्रकार है:

$$I = \frac{\text{निर्यात आय सूचकांक}}{\text{आयात मूल्य सूचकांक}} X100$$

यहाँ I, आय व्यापार की शर्त है।

$$I = \frac{Xp \times Xq}{Mp} X100$$

अर्थात् $I = N \times Xq$

यानि, आय व्यापार की शर्त ज्ञात करने के लिए शुद्ध वस्तु-विनिमय व्यापार की शर्त को निर्यात मूल्य सूचकांक से गुणा किया जाता है।

2. संसाधनों के हस्तांतरण से सम्बंधित व्यापार की शर्तें:

इनका प्रतिपादन जैकब वाइनर (Jacob Viner) ने किया है। ये दो प्रकार की हैं –

A) एक घटकीय व्यापार की शर्त (Single Factorial Terms of Trade)

B) द्वि घटकीय व्यापार की शर्त (Double Factorial Terms of Trade)

यहाँ शुद्ध वस्तु-विनिमय व्यापार की शर्त को साधनों की उत्पादकता में हुए परिवर्तन के साथ समायोजित करने का प्रयास किया गया है।

a) **एक घटकीय व्यापार की शर्त (Single Factorial Terms of Trade):** इसे प्राप्त करने के लिए शुद्ध वस्तु-विनिमय व्यापार की शर्त को निर्यात-वस्तु के उत्पादकता में हुए परिवर्तन के साथ समायोजित किया जाता है। इसका सूत्र इस प्रकार है:

$$S = \frac{X_p \times X_z}{M_p}$$

यहाँ S एक-घटकीय व्यापार की शर्त है और X, निर्यात उत्पादकता सूचकांक है। शेष संकेत पूर्व-उद्धरित हैं।

b) **द्वि-घटकीय व्यापार की शर्त (Double Factorial Terms of Trade):** इसे ज्ञात करने के लिए शुद्ध वस्तु-विनिमय व्यापार की शर्त को निर्यात-वस्तु तथा आयातवस्तु के उत्पादकता में हुए परिवर्तनों के साथ समायोजित किया जाता है। इसका सूत्र इस प्रकार है:

$$D = \frac{X_p \times X_z}{M_p \times M_z}$$

यहाँ D द्वि-घटकीय व्यापार की शर्त है और M, आयात-वस्तु उत्पादकता सूचकांक है। शेष संकेत पूर्व-उद्धरित हैं। इन दोनों सूत्रों की सबसे बड़ी कमी यह है कि आयात-वस्तु अथवा निर्यात-वस्तु की उत्पादकता में परिवर्तन की गणना करना बहुत मुश्किल है जिसके कारण इनका प्रयोग बहुत कम होता है।

3. उपयोगिता से सम्बंधित व्यापार की शर्त:

ये दो प्रकार की हैं –

A) वास्तविक लागत व्यापार की शर्त (Real Cost Terms of Trade)

B) उपयोगिता व्यापार की शर्त (Utility Terms of Trade)

a) **वास्तविक लागत व्यापार की शर्त (Real Cost Terms of Trade):** यह एकघटकीय व्यापार की शर्त की कमी दूर करने का प्रयास करता है और निर्यात उत्पाद की वास्तविक लागत के आधार पर व्यापार की शर्त का निर्धारण करता है। निर्यात उत्पाद को उत्पादित करने में प्रति इकाई संसाधन की उपयोगिता में हास को वास्तविक लागत कहते हैं (The amount of utility lost or sacrificed per unit of resources employed in producing exports is the “real cost” of producing export)। इसका सूत्र इस प्रकार है:

$$R = \frac{X_p \times X_z}{M_p \times X_r}$$

अथवा,

$$R = N \times \frac{X_z}{X_r}$$

यहाँ, R वास्तविक लागत व्यापार की शर्त और X, निर्यात उत्पाद को उत्पादित करने का वास्तविक लागत सूचकांक है। शेष संकेत पूर्व-उद्धरित हैं। लेकिन इस व्यापार की शर्त की यह कमी है कि वास्तविक लागत का आकलन बहुत मुश्किल है क्योंकि निर्यात वस्तु में लगे संसाधनों की उपयोगिता में हास का आकलन भला कैसे हो सकता है!

b) **उपयोगिता व्यापार की शर्त (Utility Terms of Trade):** इस अवधारणा को डी. एच. रॉबर्टसन (D.H. Robertson) ने वास्तविक व्यापार की शर्त (True Terms of Trade) कहा। इसका सूत्र इस प्रकार है:

$$U = N \times \frac{X_z}{X_r} \times \frac{1}{U_m}$$

यहाँ, U उपयोगिता व्यापार की शर्त तथा U_m वह सूचकांक है जो आयात वस्तु के कारण घरेलू वस्तु के उपभोग के त्याग की वांछनीयता को दर्शाता है। शेष संकेत पूर्व-उद्धरित हैं। किन्तु यह सूत्र भी अत्यंत जटिल होने के कारण अपनी प्रासंगिकता नहीं रख पाता।

6.4 व्यापार की शर्त के सिद्धांत

एडम स्मिथ ने अपने निरपेक्ष लागत सिद्धांत और डेविड रिकार्डो ने अपने तुलनात्मक लागत सिद्धांत में इस बात का उल्लेख किया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार श्रम-विभाजन और विशिष्टीकरण का अवसर प्रदान करता है जिसके फलस्वरूप कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। उनके अनुसार उत्पादन वृद्धि के फलस्वरूप देशों का उपभोग लाभ अथवा कल्याण में वृद्धि व्यापार की शर्त पर निर्भर करेगा। किन्तु ये दोनों सिद्धांत इस बात की चर्चा नहीं करते कि व्यापार की शर्त का निर्धारण कैसे होता है और व्यापार की शर्त किन बातों पर निर्भर करता है। दोनों सिद्धांत सिर्फ इस बात की चर्चा करते हैं कि व्यापार की शर्त किसी देश के आंतरिक लागत अनुपात या आंतरिक व्यापार की शर्त से जितना ही दूर होगा, उस देश को कल्याण में वृद्धि का लाभ उतना ही अधिक प्राप्त होगा। ये दोनों सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए केवल लागत पक्ष पर बल देते हैं। मांग पक्ष को नजरअंदाज करने के कारण संभवतः ये दोनों प्रतिष्ठित सिद्धांत व्यापार की शर्त निर्धारण तक नहीं पहुँच पाए। जब कभी भी व्यापार की शर्त के सिद्धान्त की बात आती है तब सर्वप्रथम जे. एस. मिल का नाम लिया जाता है जिन्होंने अपने प्रतिपूरक मांग सिद्धांत (Theory of Reciprocal Demand) में व्यापार की शर्त को निकालने का प्रयास किया किन्तु एजवर्थ तथा मार्शल ने इसको प्रस्तावना वक्र की मदद से और अधिक तर्क संगत बनाया। इन दोनों सिद्धांतों की चर्चा करने के उपरांत हम आगे बढ़ेंगे।

6.4.1 जे. एस. मिल का प्रतिपूरक मांग सिद्धांत (Theory of Reciprocal Demand)

जे. एस. मिल के पूर्व एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का मत था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निर्धारित करने में लागत की दशाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मिल के अनुसार लागत ही नहीं बल्कि मांग की दशा भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। उनके अनुसार दो देशों के बीच व्यापार परस्पर मांग पर निर्भर करता है। बिना मांग के व्यापार होगा ही नहीं चाहे वास्तु की लागत अत्यंत कम क्यों न हो। जे. एस. मिल व्यापार की शर्त तो नहीं निकाल पाए किन्तु उन्होंने व्यापार की शर्त की सीमा को अवश्य निर्धारित किया अर्थात् दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान-प्रदान की दर किस सीमा के बीच होगा, यह मिल ने हमें बताया। मिल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिपूरक मांग सिद्धांत और उनके द्वारा निर्धारित व्यापार की शर्त की सीमा (range) को समझने के लिए हम दो देश, दो वस्तु मॉडल का सहारा लेते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में भारत और श्रीलंका दो देश हैं, जबकि कपड़ा और चाय दो वस्तु हैं।

देश -	कपड़ा(इकाई)	या	चाय(इकाई)	श्रम लागत
भारत	120		100	x
श्रीलंका	40		80	x

ऊपर की सारणी से स्पष्ट है कि भारत को कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त है जबकि श्रीलंका को चाय के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त है, क्योंकि

$$\frac{120}{40} > \frac{100}{80}$$

अथवा,

$$\frac{80}{100} > \frac{40}{120}$$

भारत के लिए 120 इकाई कपड़े के लिए न्यूनतम स्वीकार्य मूल्य 100 इकाई चाय है। अतः 1 इकाई कपड़े के लिए $100/120 = 0.83$ इकाई चाय हुआ। इसी प्रकार श्रीलंका तभी व्यापार में सम्मिलित होगा जब उसे 40 इकाई कपड़े के लिए 80 इकाई से कम चाय निर्यात करना पड़े। यानि श्रीलंका के लिए 1 इकाई कपड़े के लिए स्वीकार्य मूल्य अधिक से अधिक $80/40 = 2.0$ इकाई चाय हुआ। इस प्रकार व्यापार की शर्त की सीमा निम्न प्रकार निर्धारित होगी:

1 इकाई कपड़ा = 2.0 इकाई चाय (ऊपरी सीमा)

1 इकाई कपड़ा = 0.83 इकाई चाय (निचली सीमा)

यहाँ मिल ने दो देशों के बीच व्यापार की शर्त की सीमा निर्धारित करने में सफलता प्राप्त की जो दोनों देशों की लागत और मांग की दशाओं पर निर्भर करता है। एजवर्थ तथा मार्शल ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया और अपने प्रस्ताव वक्र विश्लेषण की मदद से व्यापार की शर्त के निश्चित मान को निर्धारित करने में सफलता प्राप्त की जो दोनों देशों की लागत तथा मांग की दशाओं पर निर्भर करता है। इसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं।

6.4.2 प्रस्ताव वक्र विश्लेषण (Offer Curve Analysis)

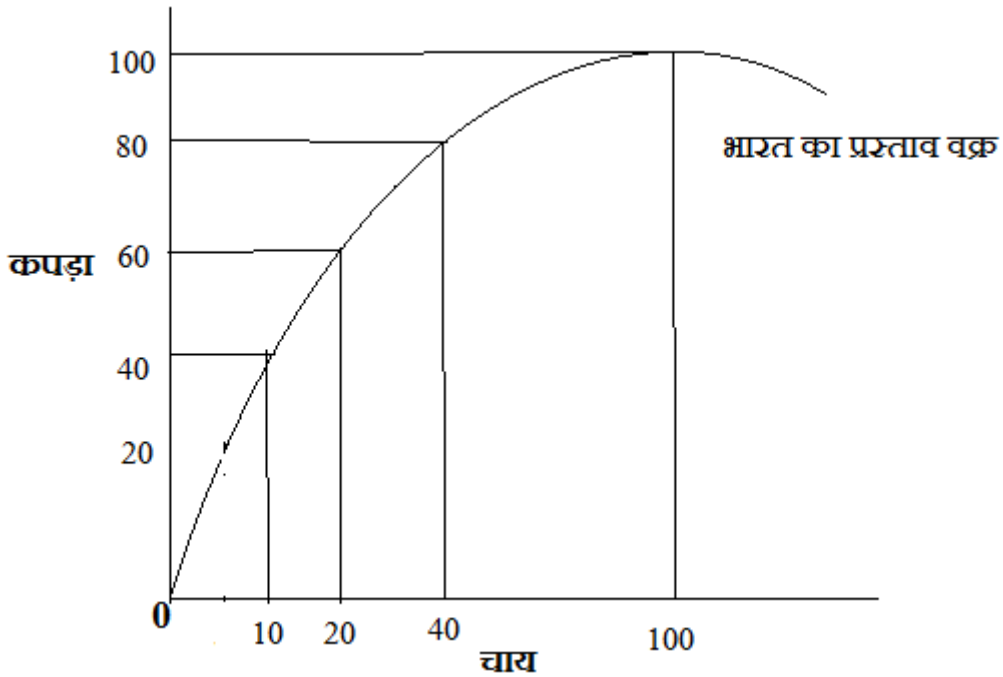
प्रस्ताव वक्र तकनीक जे. एस. मिल के प्रतिपूरक मांग सिद्धान्त का विकसित रूप है। इसे प्रस्तुत करने का श्रेय एजवर्थ और मार्शल को जाता है। प्रस्ताव वक्रों के माध्यम से दो देशों के बीच व्यापार की कुल मात्रा तथा व्यापार की शर्त का निश्चित मान निर्धारित होता है। किसी देश का प्रस्ताव वक्र उस देश की मांग तथा पूर्ति दोनों ही दशाओं का चित्रण करता है। यह विदेशी वस्तु के लिए घरेलू मांग को दर्शाता है, साथ ही यह उस देश की पूर्ति दशा को भी दर्शाता है। यदि इसके माध्यम से आयातित वस्तु की मांग के लिए किये जानेवाले निर्यात-मात्रा को लागत के रूप में प्रदर्शित किया जाय। प्रस्ताव वक्र का स्वरूप गैर-रेखीय होता है क्योंकि खरीदी जानेवाली वस्तु पर क्रमागत उपयोगिता हास नियम लागू होता है। जहाँ पर दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र एक दुसरे को काटते हैं। वहाँ पर कुल आयात-निर्यात की मात्रा तथा साथ ही व्यापार की शर्त का निर्धारण होता है।

प्रस्ताव वक्र का निर्माण तथा इसकी मदद से व्यापार की शर्त के निर्धारण को समझने के लिए हम प्रस्तुत सारणी की मदद लेते हैं। यहाँ भारत और श्रीलंका दो देश हैं जो कपड़ा और चाय का लेन-देन करना चाहते हैं। भारत कपड़ा निर्यातक है और श्रीलंका चाय निर्यातक है। सर्वप्रथम हम भारत के प्रस्ताव वक्र का निर्माण प्रस्तुत सारणी की मदद से करते हैं।

कपड़ा(निर्यात) इकाई	चाय(आयात) इकाई	व्यापार की शर्त अनुपात
25	5	5:1
40	10	4:1
60	20	3:1
80	40	2:1
100	100	1:1

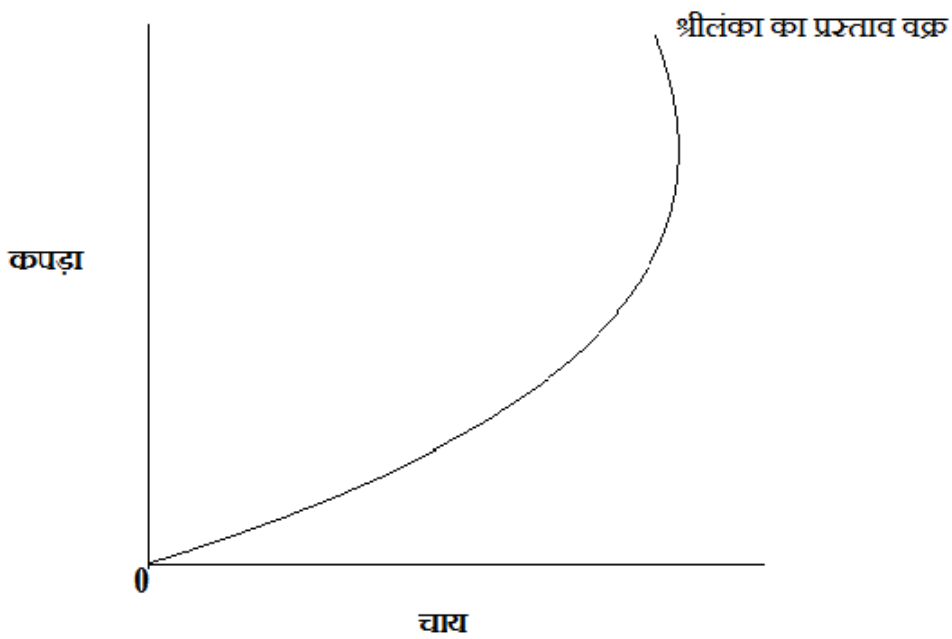
प्रारंभ में भारत 25 इकाई कपड़े के बदले 5 इकाई चाय आयात करने को तैयार है, जिससे व्यापार की शर्त का अनुपात 5:1 हुआ। भारत जैसे-जैसे कपड़े की निर्यात मात्रा बढ़ाने को तैयार होता है, भारत के लिए कपड़े की

सीमांत उपयोगिता बढ़ती है और आयातित वस्तु चाय की मात्रा बढ़ने से उसकी सीमान्त उपयोगिता भारत के लिए घटती है, जिसके कारण व्यापार की शर्त का अनुपात क्रमशः 4:1, फिर 3:1, 2:1 और अंत में 1:1 हो जाता है।

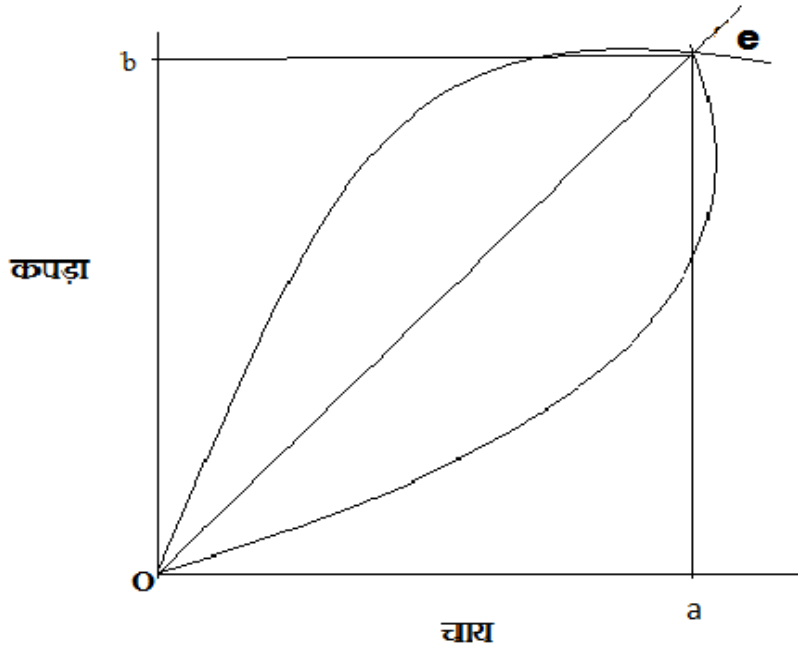


चित्र संख्या 6.1

इसी प्रकार हम श्रीलंका के प्रस्ताव वक्र का निर्माण करते हैं। संतुलन का व्यापार की शर्त वहां निर्धारित होता है जहाँ दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को काटते हैं। O_e व्यापार की शर्त रेखा है जो हमें दोनों देशों के प्रस्ताव वक्रों के कटान बिन्दु से प्राप्त हुआ है। कटान बिन्दु पर हमें व्यापार की कुल मात्रा $(o_a + o_b)$ का भी पता चल जाता है।



चित्र संख्या 6.2



चित्र संख्या 6.3 संतुलन का व्यापार की शर्त

6.5 व्यापार की शर्त और आर्थिक संवृद्धि

6.5.1 व्यापार की शर्त और आर्थिक संवृद्धि में सम्बन्ध

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ अथवा हानि निर्धारित करने में व्यापार की शर्त का महत्वपूर्ण योगदान है। किसी देश के घरेलू उत्पादन में वृद्धि, चाहे, वह उत्पादन-पैमाने के विस्तार से संभव हुआ हो या साधनों के कुशलता में वृद्धि से, उसका लोगों के खुशहाली या जीवन-स्तर के सुधार के रूप में रूपांतरित होना तभी संभव है, जब उस देश के व्यापार की शर्त उसके लिए अनुकूल हो। जगदीश भगवती ने अपने **इमिजेराइजिंग विकास (Immiserising Growth)** का सिद्धांत में इसी बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। व्यापार की शर्त का देश की आर्थिक विकास तथा वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। देश की व्यापार की शर्तों में सुधार होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश की क्रय शक्ति बढ़ती है जो उसके आर्थिक विकास में सहायक होती है, क्योंकि वह देश एक निश्चित निर्यात के बदले अधिक वस्तुओं का आयात कर सकने में सफल होता है। इससे न केवल निर्यात उद्योगों बल्कि आयात प्रतिस्थापन उद्योगों को भी लाभ होता है।

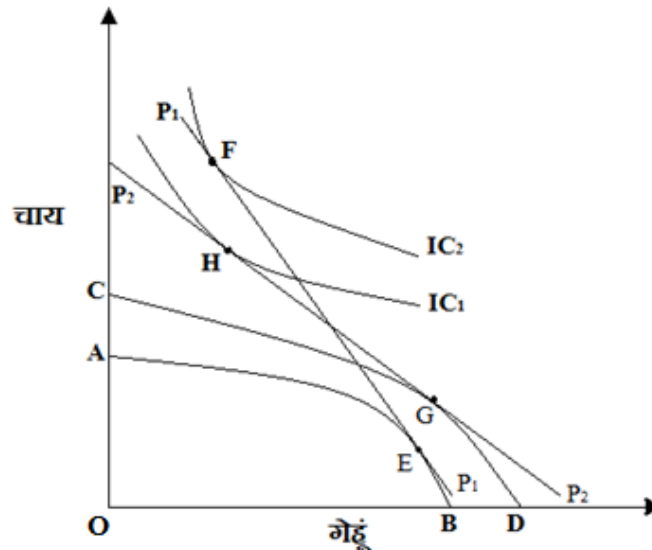
व्यापार की शर्त प्रतिकूल होने से इसका उल्टा असर होता है। आज विकसित और विकासशील देशों के बीच विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर टकराव का एक कारण यह भी है। विकासशील देशों की यह शिकायत रहती है कि विकसित देश कोई न कोई हथकंडा अपनाकर विकासशील देशों के उत्पादों को अपने बाजार में उचित मूल्य प्राप्त नहीं होने देते। इसके कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक विषमता की खाई और चौड़ी होती जा रही है। इस मुद्दे पर विकसित और विकासशील देशों के बीच जो वार्तालाप होता है उसे **उत्तर-दक्षिण संवाद (North-South Dialogue)** के नाम से भी जाना जाता है।

6.5.2 इमिजेराइजिंग विकास का सिद्धान्त (Theory of Immiserising Growth)

सर्वप्रथम एजवर्थ ने इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि निर्यात क्षेत्र में लागत में कमी का लाभ देश को नहीं भी मिल सकता है यदि व्यापार की शर्त देश के प्रतिकूल हो जाय। इसी बात को जगदीश भगवती ने ज्यामितीय विधि से अपने **इमिजेराइजिंग विकास (Immiserising growth)** सिद्धान्त में विधिवत प्रस्तुत किया।

जगदीश भगवती के सिद्धान्त को हम प्रस्तुत चित्र की मदद से समझ सकते हैं। देश गेहूँ के उत्पादन में चाय के उत्पादन की तुलना में अधिक निपुण है। जिसके कारण गेहूँ उसके लिए निर्यात-योग्य वास्तु है जबकि चाय आयात-योग्य वास्तु है। हम यहाँ वास्तु विनिमय प्रणाली की मदद से स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, प्रारम्भ में देश, उत्पादन संभावना वक्र AB के E बिन्दु पर उत्पादन कर रहा है और व्यापार की शर्त P_1P_1 होने पर तटस्थता वक्र IC_2 के F बिन्दु पर उपभोग कर रहा है। अब देश के उत्पादन संभावना वक्र में विस्तार होता है। जिसके कारण देश अब उत्पादन संभावना वक्र CD के G बिन्दु पर उत्पादन करने लगता है।

इस बड़े हुए उत्पादन से यह उम्मीद की जा सकती थी कि देश अब एक ऊँचे तटस्थता वक्र पर उपभोग करेगा और उसके कल्याण का स्तर पहले से ऊँचा यानि तटस्थता वक्र IC_2 से ऊपर होगा। किन्तु व्यापार की शर्त, जो अब P_2P_2 रेखा से दर्शाया गया है, पहले से प्रतिकूल हो गया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि P_2P_2 की ढाल P_1P_1 से कम है। जो इस बात को इंगित करता है कि व्यापार की शर्त पहले से प्रतिकूल हो गया है। इसके कारण देश के उपभोग का स्तर यानि कल्याण का स्तर अब तटस्थता वक्र IC_1 के H बिन्दु पर आ गया। स्पष्ट है, IC_1 के कल्याण का स्तर IC_2 के कल्याण-स्तर से नीचे है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिकूल व्यापार के शर्त के कारण देश के उत्पादन में वृद्धि का लाभ देश की जनता को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देश के उत्पादन-वृद्धि का लाभ देश की जनता को प्राप्त न होकर व्यापार में साझीदार दूसरे देश की जनता को हस्तान्तरित हो गया।



चित्र संख्या 6.4

व्यापार की शर्त के प्रतिकूल होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला, देश के उत्पादन में वृद्धि निर्यात-वस्तु के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुआ हो और दूसरा, दुनिया में देश के निर्यात की मांग की लोच कम हो। किन्तु यह बात तभी लागू होती है। जब निर्यातक देश की अर्थव्यवस्था विशाल हो। जिससे उसकी पूर्ति विश्व को प्रभावित करे। यदि अर्थव्यवस्था का आकार बहुत छोटा है। तब **इमिजेराइजिंग विकास (Immiserising growth)** का

सिद्धांत उसपर लागू नहीं होता क्योंकि उसकी पूर्ति विश्व अर्थव्यवस्था के पूर्ति का बहुत छोटा भाग होगा, जिसके कारण व्यापार की शर्त प्रभावित नहीं होगी।

6.5.3 व्यापार की शर्त और विकासशील देश

इसमें कोई संदेह नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पादन में वृद्धि होती है। कारण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है जिसके कारण उत्पादन तथा व्यापार में वृद्धि होती है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकास का इंजन भी कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमें मौका देता है कि हम किसी वस्तु का उत्पादन न करते हुए भी उसका उपभोग कर लेते हैं। किन्तु यह बात शत-प्रतिशत सही नहीं है। अगर ऐसा होता तब दुनिया में न गरीबी होती और न ही आय की विषमता उत्पन्न होती।

अभी हमने जगदीश भगवती के इमिजेराइजिंग विकास (Immiserising growth) के सिद्धांत में यह अध्ययन किया कि व्यापार की शर्त प्रतिकूल होने पर देश के उत्पादन वृद्धि का लाभ विकासशील देश की जनता को नहीं भी मिल सकता है। विकासशील देशों के सन्दर्भ में व्यापार की शर्त के महत्व को रौल प्रेबिश तथा हेंस सिंगर ने रेखांकित करते हुए कहा है कि यदि विकासशील देशों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करना है तब उन्हें अपने को प्राथमिक वस्तुओं के निर्यातक से औद्योगिक वस्तुओं के निर्यातक के रूप में बदलना होगा क्योंकि विकासशील देशों के प्राथमिक वस्तुओं की मांग की आय-लोच तथा मूल्य-लोच विकसित देशों में कम होती है। मांग की आय लोच कम होने के कारण विकसित देशों की आय में वृद्धि होने से उनके यहाँ उसी अनुपात में विकासशील देशों के प्राथमिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि नहीं हो पाती। मांग की मूल्य लोच के कम होने के कारण विकासशील देश अपनी प्राथमिक वस्तुओं के मूल्य में कमी करके उनकी मांग को विकसित देशों में उसी अनुपात में वृद्धि करने में सफल नहीं हो पाते।

दूसरी तरफ विकसित देशों के उत्पाद की मांग की आय-लोच तथा मूल्य-लोच विकासशील देशों में अधिक होती है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यापार की शर्त विकासशील देशों के प्रतिकूल हो जाता है और उन्हें भुगतान संतुलन की समस्या से जूझना पड़ता है। प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत कृषि तथा कृषि-आधारित उत्पाद, खनिज आदि आते हैं जबकि औद्योगिक वस्तुओं में विनिर्मित वस्तुएं आती हैं। प्रेबिश ने विकसित देशों को केंद्र (center) कहा जबकि विकासशील देशों के लिए उन्होंने हाशिया (periphery) शब्द का प्रयोग किया। प्रेबिश ने अपने तर्क को व्यापार चक्र (Business Cycle) की घटना से जोड़ने का प्रयास किया है।

उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था में तेजी के समय लाभ, मजदूरी और मूल्य में वृद्धि होती है। किन्तु लाभ मजदूरी की तुलना में अधिक वृद्धि पाता है। विकासशील देशों में मूल्य में वृद्धि विकसित देशों की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण विकासशील देशों में लाभ विकसित देशों की तुलना में अधिक वृद्धि पाता है। किन्तु मंदी के समय उल्टा होता है। लाभ, मजदूरी और मूल्य मंदी के समय विकसित और विकासशील दोनों श्रेणी के देशों में गिरना चाहिए किन्तु विकसित देशों में मजदूरी के गिरने की प्रवृत्ति नहीं होती। जबकि विकासशील देशों में श्रमिक संगठित नहीं होते। जिसके कारण इन देशों में लाभ के साथ मजदूरी में भी गिरावट आती है। निष्कर्षतः, विकसित देशों में लाभ में गिरावट विकासशील देशों में हुए लाभ में गिरावट की तुलना में कम होता है। विकसित देश अपने लाभ में हुए गिरावट की भरपाई बेहतर व्यापार की शर्त होने के कारण, विकासशील देश से करने में सफल हो जाते हैं।

6.6 अभ्यास हेतु प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. व्यापार की शर्त का क्या तात्पर्य है?

2. व्यापार की शर्त कितने प्रकार के होते हैं?
3. व्यापार की शर्त से संबंधित प्रेबिश-सिंगर के क्या विचार हैं ?
4. इमिजेराइजिंग विकास का सिद्धांत(Theory of Immiserising Growth) किसने दिया?

अति लघुउत्तरीय प्रश्न

1. प्रस्ताव वक्र तकनीक किसने विकसित की?
2. प्रतिपूरक मांग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया?
3. प्रेबिश ने केंद्र (center) और हाशिया (periphery) शब्द का प्रयोग किन देशों के लिए किया?
4. कृषि प्रधान और औद्योगिक वस्तु में किसकी मांग की लोच अधिक होती है?
5. प्रेबिश और सिंगर के अनुसार आद्योगिक और कृषि प्रधान वस्तु में व्यापार की शर्त किसके पक्ष में होती है?

बहुविकल्पीय प्रश्न:

1. प्रस्ताव वक्र किसी देश की स्थिति को प्रदर्शित करता है –
a) मांग की दशा को b) पूर्ति की दशा को c) मांग और पूर्ति दोनों दशा को।
2. प्रस्ताव वक्र तकनीक विकसित की –
a) मार्शल ने b) एजवर्थ ने c) मार्शल तथा एजवर्थ दोनों ने
3. अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव वक्र पूर्णतः लोचदार होता है -
a) विशाल अर्थव्यवस्था b) लघु अर्थव्यवस्था c) अतिलघु अर्थव्यवस्था
4. प्रतिपूरक मांग सिद्धांत से ज्ञात होता है –
a) व्यापार की शर्त का निश्चित मान b) व्यापार की शर्त की सीमा c) व्यापार की कुल मात्रा
5. प्रस्ताव वक्रों के कटान से ज्ञात होता है –
a) व्यापार की शर्त b) कुल व्यापार की मात्रा c) दोनों
6. प्रस्ताव वक्र किसी देश की स्थिति को प्रदर्शित करता है -
a) मांग की दशा को b) पूर्ति की दशा को c) मांग और पूर्ति दोनों दशा को
7. प्रस्ताव वक्र तकनीक विकसित की -
a) मार्शल ने b) एजवर्थ ने c) मार्शल तथा एजवर्थ दोनों ने
8. अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव वक्र पूर्णतः लोचदार होता है -
a) विशाल अर्थव्यवस्था b) लघु अर्थव्यवस्था c) अतिलघु अर्थव्यवस्था
9. प्रतिपूरक मांग सिद्धांत से ज्ञात होता है -
a) व्यापार की शर्त का निश्चित मान b) व्यापार की शर्त की सीमा c) व्यापार की कुल मात्रा
10. प्रस्ताव वक्रों के कटान से ज्ञात होता है -
a) व्यापार की शर्त b) कुल व्यापार की मात्रा c) दोनों

सत्य-असत्य का चुनाव करें:

1. व्यापार की शर्त का प्रभाव निर्यात आय पर नहीं पड़ता है।
2. किसी देश का प्रस्ताव वक्र उसके मांग और लागत की दशा को दर्शाता है।
3. प्रेबिश ने विकसित देशों को केंद्र (center) कहा।

6.7 सारांश

इस इकाई में हमने व्यापार की शर्त और इसके विभिन्न प्रकार की चर्चा की। व्यापार की शर्त आयात मूल्य और निर्यात मूल्य के बीच का अनुपात है। हमने जाना कि व्यापार की शर्त और आर्थिक संवृद्धि में गहरा सम्बन्ध है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप देश को लाभ तभी प्राप्त हो सकता है। जब व्यापार की शर्त उसके पक्ष में हो, अन्यथा देश के उत्पादन वृद्धि का लाभ दूसरे देश को हस्तांतरित हो जाता है। इस बात का खुलासा पहले एजवर्थ और फिर जगदीश भगवती ने अपने इमिजेराइजिंग विकास के सिद्धांत (Theory of Immiserising Growth) में किया।

प्रेबिश तथा सिंगर ने विकासशील देशों के प्रतिकूल व्यापार की शर्त से निपटने के लिए आद्योगीकरण के रास्ते पर चलने की सलाह दी क्योंकि उनका तर्क था कि विकासशील देश प्राथमिक वस्तुओं के निर्यातक होते हैं। जिनकी मांग की आय-लोच तथा मूल्य-लोच कम होती है। जबकि विकसित देशों के आद्योगिक उत्पाद की मांग की आय-लोच तथा मूल्य-लोच अधिक होती है। इसका नतीजा होता है, विकासशील देशों का प्रतिकूल व्यापार की शर्त। जगदीश भगवती और प्रेबिश-सिंगर के तर्कों से यही लगता है कि मुक्त व्यापार की नीति विकासशील देशों के लिए फायदेमंद नहीं है और उन्हें संरक्षणवादी नीति अपनाने का पूरा अधिकार है।

6.8 शब्दावली

- **व्यापार की शर्त** - साधारण शब्दों में, किसी देश के निर्यात और आयात के बीच के विनिमय अनुपात को व्यापार की शर्त कहते हैं।
- **प्रतिपूरक/पारस्परिक मांग** - प्रतिपूरक मांग(reciprocal demand) शब्द का प्रयोग जे. एस. मिल ने दो देशों के द्वारा एक दूसरे के वस्तुओं के परस्पर मांग के लिए किया।
- **प्रस्ताव वक्र** - किसी देश का प्रस्ताव वक्र उस देश की विदेशी वस्तु की मांग की तीव्रता को प्रकट करता है और साथ ही विदेशी वस्तु को प्राप्त करने के लिए घरेलू वस्तु को त्यागी जाने वाली मात्रा को लागत के रूप में प्रकट करता है।
- **केंद्र (center)** रोल प्रेबिश ने विकसित आद्योगिक देशों के लिए केंद्र(Center) शब्द का प्रयोग किया।
- **हाशिया(Periphery)** - रोल प्रेबिश ने विकासशील देशों के लिए हाशिया (Periphery) शब्द का प्रयोग किया।
- **निर्यात की आय-लोच और मूल्य-लोच** - दूसरे देश की आय में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप देश की निर्यात मांग में होनेवाले आनुपातिक परिवर्तन की दर को निर्यात की आय लोच कहते हैं। जबकि निर्यात किए जाने वाले वस्तु के मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप देश के निर्यात मांग में आनुपातिक परिवर्तन की दर को निर्यात की मूल्य लोच कहते हैं।
- **इमिजेराइजिंग विकास (Immiserising growth)** - इस शब्द का प्रयोग जगदीश भगवती ने किसी देश की उस अवस्था के लिए किया जब उसके उत्पादन-वृद्धि का लाभ प्रतिकूल व्यापार की शर्त के कारण दूसरे देश को हस्तानांतरित हो जाये और इसके परिणामस्वरूप उस देश का कल्याण स्तर पहले से नीचे आ जाये।
- **प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद** - प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन आदि आते हैं।

6.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर:

अति लघुउत्तरीय प्रश्न

1. एजवर्थ और मार्शल ने
2. जे. एस. मिल ने
3. विकसित देशों के लिए केंद्र (center) विकासशील देशों के लिए हाशिया (periphery).
4. औद्योगिक वस्तु की मांग की लोच अधिक होती है।
5. औद्योगिक वस्तु के पक्ष में।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

1. (c) मांग और पूर्ति दोनों दशा को।
2. (c) मार्शल तथा एजवर्थ दोनों ने
3. (a) विशाल अर्थव्यवस्था
4. (b) व्यापार की शर्त की सीमा
5. (c) दोनों

सत्य-असत्य का चुनाव करें:

1. असत्य
2. सत्य
3. सत्य

6.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- Bo Sodersten; International Economics (Macmillan, 1999)
- Charles P Kindleberger, International Economics, (Richard D. Irwin Inc., Illinois, 1968)
- D. M. Mithani, International Economics,(Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006)
- H. G. Mannur; International Economics (Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001)
- Ingo Walter; International Economics: Theory and Policy, (Ronald Press, New York 1968).
- K.R. Gupta: International Economics; (Atma Ram Pub. Delhi, 1969)
- Paul Krugman, Maurice Obstfeld and Marc J. Melitz; International Economics: Theory and Policy (Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.).
- Robert M. Dunn, and John H. Mutti; International Economics, (Routledge, London, 2004).
- V.K. Bhalla; International Economy: Liberalisation Process (Anmol Pub. Delhi, 1993).

- एस0एन0लाल; अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र (शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहबाद, 2004)
- एच. एस. अग्रवाल, तथा सी. एस. बरला: अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र ;(लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा, 2003).
- डालचंद्र बागड़ी; अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ,(अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2009).
- सुदामा सिंह एवं एम0सी0 वैश्य; अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, (ऑक्सफ़ोर्ड एंड आई0 बी0 एच0 पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007)
- एम0 एल0झिंगन; अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र: (वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010)

6.10 उपयोगी/सहायक पाठ्य सामग्री

- Bo Sodersten, International Economics, Macmillan, 1999
- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006
- H. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: International Economics: Theory and Policy, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- एस. एन. लाल , अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र , शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहबाद, 2004
- एच. एस. अग्रवाल, तथा सी. एस. बरला, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2003.
- सुदामा सिंह एवं एम. सी. वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफ़ोर्ड एंड आई. बी. एच. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम. एल. झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010।
- ज्ञानेंद्र सिंह कुशवाहा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1979।

6.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. व्यापार की शर्त से क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं?
2. व्यापार की शर्त से सम्बंधित जे. एस. मिल के प्रतिपूरक मांग सिद्धांत की व्याख्या करें।
3. प्रस्ताव वक्र की मदद से व्यापार की शर्त कैसे निर्धारित होता है?
4. व्यापार की शर्त के महत्व को विकासशील देशों के सन्दर्भ में रेखांकित करें। इस सम्बन्ध में जगदीश भगवती और प्रेबिश-सिंगर के विचार प्रस्तुत करें।

इकाई 7- मुक्त व्यापार एवं संरक्षण (Free Trade and Protection)

- 7.1 प्रस्तावना
- 7.2 उद्देश्य
- 7.3 मुक्त व्यापार
 - 7.3.1 मुक्त व्यापार का अर्थ
 - 7.3.1 मुक्त व्यापार के पक्ष में तर्क
 - 7.3.2 मुक्त व्यापार सीमाएं
- 7.4. संरक्षण
 - 7.4.1 संरक्षण का अर्थ
 - 7.4.2 संरक्षण के पक्ष में मुख्य तर्क
 - 7.4.3 संरक्षण के विपक्ष में तर्क
 - 7.4.4 संरक्षण की विधियाँ
- 7.5 अभ्यास हेतु प्रश्न
- 7.6 सारांश
- 7.7 शब्दावली
- 7.80 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 7.9 सन्दर्भ ग्रंथ सूची
- 7.10 उपयोगी/सहायक पाठ्य सामग्री
- 7.11 निबंधात्मक प्रश्न

7.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई में आपको मुक्त व्यापार का अर्थ, इसके पक्ष में तर्क तथा इससे उत्पन्न चुनौतियों से अवगत कराया गया है। साथ ही इस इकाई में संरक्षण का अर्थ, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क तथा संरक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में बताया गया है।

7.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- ✓ मुक्त व्यापार का अर्थ समझ पाएंगे।
- ✓ मुक्त व्यापार के पक्ष में तर्क से अवगत होंगे।
- ✓ मुक्त व्यापार से उत्पन्न चुनौतियों से अवगत होंगे।
- ✓ संरक्षण का अर्थ जान पाएंगे।
- ✓ संरक्षण से लाभ व इससे उत्पन्न चुनौतियों से अवगत होंगे।
- ✓ संरक्षण के विभिन्न विधियों से अवगत होंगे।

7.3 मुक्त व्यापार

7.3.1 मुक्त व्यापार का अर्थ

मुक्त व्यापार वह नीति है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ऐसी स्थिति में दो देशों के बीच वस्तुओं के आयात-निर्यात में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। मुक्त व्यापार के महत्व को रेखांकित करने का श्रेय एडम स्मिथ को जाता है। उनके पहले सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में जो विचारधारा प्रचलित थी उसे आर्थिक विचारों के इतिहास में वणिकवाद के नाम से जाना जाता है। वणिकवाद बहुत ही संकीर्ण विचारधारा थी। वणिकवाद के अनुसार निर्यात से देश की सम्पदा में वृद्धि होती है, जबकि आयात से देश की सम्पदा में कमी आती है।

एडम स्मिथ ने इस मान्यता का खंडन किया और बताया कि व्यापार से सभी देशों को लाभ होता है इसलिए उन्होंने मुक्त व्यापार की वकालत की। उनके अनुसार **“मुक्त व्यापार की धारणा का उपयोग व्यापारिक नीति की उस प्रणाली को बंद करने के लिए किया जाता है जिसमें देश तथा विदेशी वस्तुओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता इसलिए न तो विदेशी वस्तुओं पर अनावश्यक कर लगाये जाते हैं और न ही स्वदेशी उद्योगों को कोई विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।”**

इस प्रकार, मुक्त व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आंतरिक व्यापार में कोई अंतर नहीं करता। जिस प्रकार आंतरिक व्यापार में स्वतंत्रता होने पर कोई भी व्यक्ति सबसे कम मूल्य वाले बाजार में वस्तु खरीद सकता है अथवा उत्पादक अपनी वस्तु को उस बाजार में बेच सकता है जहाँ उसे सबसे ज्यादा मूल्य प्राप्त हो सके। ठीक उसी प्रकार मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई भी देश सबसे कम मूल्य पर वस्तु खरीद सकता है और साथ ही सबसे अधिक मूल्य देने वाले देश में अपनी वस्तु बेच सकता है।

7.3.2 मुक्त व्यापार के पक्ष में तर्क

एडम स्मिथ के आगमन के साथ ही मुक्त व्यापार के पक्ष में हवा चल गई। उन्होंने इसके लाभ के बारे में इतना ठोस तर्क रखा कि सभी प्रतिष्ठित व नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री इसके पक्ष में बोलने लगे। एक जुमला चल पड़ा

“some trade is better than no trade and free trade is better than protected or restricted trade.” यानि कुछ व्यापार शून्य व्यापार से बेहतर है, जबकि मुक्त व्यापार प्रतिबंधित या संरक्षित व्यापार से बेहतर है। मुक्त व्यापार के पक्ष में प्रायः निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं:

1. **उत्पादन के साधनों का समुचित प्रयोग:-** मुक्त व्यापार के अंतर्गत प्रत्येक देश केवल उसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसमें उसे लागत सम्बन्धी लाभ प्राप्त हो। यह लाभ चाहे वह निरपेक्ष हो या तुलनात्मक, उत्पादन के साधनों के समुचित तथा कुशलतम प्रयोग को सुनिश्चित करेगा।
2. **तकनीकी विकास को प्रोत्साहन:-** मुक्त व्यापार में देशों के बीच पारस्परिक प्रतियोगिता रहती है। इस प्रतियोगिता के कारण प्रत्येक उत्पादक भरसक कोशिश करता है कि उसके उत्पाद की लागत कम हो जिससे कि वह कम मूल्य पर अपने उत्पाद को बेच सके। इसके लिए उत्पादक तकनीकी अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहन देता है।
3. **सामाजिक उत्पादन का अधिकतमीकरण:** मुक्त व्यापार श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को बढ़ाता है जिसके कारण कुल उत्पादन में वृद्धि होती है और साथ ही वस्तु का उत्पादन लागत भी गिरता है। यानि समाज को पहले से कम मूल्य पर और साथ ही अधिक वस्तुओं का उपभोग करने का मौका मिलता है। वस्तुओं का मूल्य उनके सीमान्त लागत के बराबर हो जाता है। यह स्थिति अनुकूलतम उत्पादन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक देश की आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है और यह मुक्त व्यापार में प्राप्त किया जा सकता है।
4. **आयातित वस्तुओं के मूल्यों में कमी:** मुक्त व्यापार सस्ते आयातित वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। उपभोक्ताओं को ऐसे देश की वस्तु का उपभोग करने का अवसर प्राप्त होता है जहाँ वह कम-से कम लागत पर प्राप्त किया जाता है। यह अलग बात है कि इस तर्क में देशी उत्पादकों के हितों की अवहेलना की गई है और साथ ही रोजगार के पहलू को भी नजरंदाज किया गया है।
5. **एकाधिकारिक शोषण से मुक्ति:** मुक्त व्यापार में प्रतियोगिता होने के कारण उपभोक्ता एकाधिकारिक शोषण से बच जाते हैं। प्रत्येक देश के उत्पादक को केवल देश के ही नहीं बल्कि विदेशी उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है जिसके कारण एकाधिकार का जन्म नहीं होता और फलस्वरूप उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त होती हैं।
6. **स्वर्णमान प्रणाली के अनुकूल:** मुक्त व्यापार देशी मुद्रा के विदेशी मुद्रा में पूर्ण परिवर्तनीयता को सुनिश्चित करता है। यह एक प्रकार से स्वर्णमान प्रणाली वाली स्थिति उपलब्ध कराता है क्योंकि विभिन्न मुद्राओं का क्रय-विक्रय आसानी से हो जाता है।
7. **विश्व के सभी देशों के आर्थिक हितों की सुरक्षा:** मुक्त व्यापार व्यवस्था से विश्व के सभी देशों के हितों की रक्षा होती है। मुक्त व्यापार प्रणाली व्यापारिक संघर्ष नहीं बल्कि समरसता उत्पन्न करता था। मुक्त व्यापार के फलस्वरूप आयात करनेवाले देश और निर्यात करनेवाले देश दोनों को लाभ प्राप्त होता है। मुक्त व्यापार के अंतर्गत एक देश दूसरे देश पर निर्भर होता है। फलस्वरूप उन देशों के बीच सहयोग एवं सद्भावना जागृत होती है।

एडम स्मिथ के पूर्व यह मत था कि आयात करनेवाले देश को नुकसान और निर्यात करनेवाले देश को लाभ प्राप्त होता है। यह व्यापार का संकुचित दृष्टिकोण था, जिसके कारण व्यापार ने औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया और देशों के बीच युद्ध भी हुए। एडम स्मिथ ने यह समझाया कि मुक्त व्यापार श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को जन्म देता है, जिसके कारण सभी देशों के आर्थिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

7.3.3 मुक्त व्यापार की सीमाएं

मुक्त व्यापार से लाभ के बारे में अभी हम अवगत हुए। इससे हम यह सोच लेते हैं कि यही आदर्शात्मक स्थिति है। किन्तु मुक्त व्यापार की अपनी सीमाएं हैं, जिसके कारण हमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होता। अनुभव तो यही बताता है कि जैसे-जैसे दुनिया मुक्त व्यापार की ओर अग्रसर हो रही है, विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई और चौड़ी होती जा रही है। बहुराष्ट्रीय कम्पनिओं का जाल विकासशील देशों में फैलता जा रहा है। उनके यहाँ के घरेलू उद्योग इन बहुराष्ट्रीय कम्पनिओं के आगे प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। कई उद्योग तो बहुराष्ट्रीय कम्पनिओं के सामने अपना अस्तित्व ही खो चुके हैं। ऐसे में अब पुनः इन देशों में संरक्षण के उपाय की बात की जा रही है।

मुक्त व्यापार की निम्नलिखित सीमाएं हैं:

1. **मुक्त व्यापार अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है:** मुक्त व्यापार की पुरजोर वकालत करनेवाले एडम स्मिथ और अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ऐसी मान्यताएं ले बैठे जो वास्तविकता से दूर हैं। जैसे स्थिर लागत की दशा का उत्पादन, साधन की गतिशीलता की मान्यता आदि शायद ही देखने को मिलता है।
2. **पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित:** मुक्त व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभ वस्तु तथा साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है, जो शायद ही उपलब्ध हो पाती है। इसके कारण साधनों का अनुकूलतम आवंटन और वस्तुओं का अनुकूलतम वितरण नहीं हो पता जिसके कारण मुक्त व्यापार से वो स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती जो दावा किया जाता है।
3. **शिशु उद्योग के लिए अनुपयुक्त:** मुक्त व्यापार शिशु उद्योग के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि ऐसे उद्योग प्रतियोगिता को झेल पाने में सक्षम नहीं होते। **फ्रेडरिक लिस्ट** ने अपने शिशु उद्योग तर्क में इस बात को बहुत सरल तरीके से बताया है और ऐसे उद्योगों को प्रारंभ में संरक्षण देने की वकालत की है।
4. **मांग और पूर्ति का पूर्णतः लोचदार होना आवश्यक:** मुक्त व्यापार इस मान्यता पर आधारित है कि दीर्घकाल में मांग और पूर्ति पूर्णतः लोचदार हो जाते हैं जिसके कारण उद्योगों की लागतें स्थिर हो जाती हैं। किन्तु वास्तविक जगत में ऐसा संभव नहीं।

7.4 संरक्षण

7.4.1 संरक्षण का अर्थ

देश के उद्योगों को विभिन्न प्रोत्साहनों द्वारा विकसित करने तथा विदेशी वस्तुओं के प्रतिस्पर्धा से बचाने की नीति को संरक्षण कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देश के उद्योग-धंधों का विकास करना होता है। संरक्षण की वकालत सर्वप्रथम अमेरिकी राजनीतिज्ञ अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने की। उनके अनुसार देश में उद्योगों के विकास तथा अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए संरक्षण की नीति अपनानी चाहिए। जर्मन राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री **फ्रेडरिक लिस्ट** ने अपने **शिशु उद्योग तर्क** के माध्यम से संरक्षण पर जोर दिया।

7.4.2 संरक्षण के पक्ष में मुख्य तर्क

1. **देश की मुद्रा देश में ही रहने का तर्क:** संरक्षण के पक्ष में दिया जानेवाला यह सामान्य तर्क है। इसके अनुसार यदि देश के लोग देश में निर्मित वस्तुओं का उपभोग करेंगे। तब देश की मुद्रा देश में ही रहेगी। जबकि विदेशी वस्तु खरीदने से देश की मुद्रा का भुगतान विदेशी वस्तु के निर्माताओं को हो जाने से मुद्रा

- का पलायन हो जायेगा। वणिकवादी प्रायः यही तर्क देते थे। उनका मत था कि देश का स्वर्ण आयात करने से देश से बाहर चला जायेगा।
2. **भुगतान संतुलन का तर्क:** इस तर्क के अनुसार आयात होने से भुगतान संतुलन में घाटा और निर्यात से भुगतान संतुलन में लाभ होता है।
 3. **घरेलू बाज़ार का तर्क:** यह तर्क विशेषकर विकासशील देशों के सन्दर्भ में दिया जाता है। इस तर्क के अनुसार विकासशील देश एक निम्न-संतुलन की स्थिति में होते हैं। पूर्ति में वृद्धि होने पर मांग में भी उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाती। गुन्नार मिर्डल के अनुसार, *“अल्पविकसित देशों के औद्योगिक विकास में एक बड़ी कठिनाई तथा विकास सम्बन्धी नीति को मूर्त रूप देने में एक बड़ी बाधा यह है कि ये देश पूर्ति में वृद्धि के साथ-साथ घरेलू मांग में वृद्धि नहीं कर पाते।”* इस प्रकार अल्पविकसित अथवा विकासशील देशों में प्रभावी मांग में कमी एक बड़ी बाधा है। संरक्षण के माध्यम से घरेलू उद्योगों के निर्मित वस्तुओं की मांग को सुनिश्चित किया जा सकता है।
 4. **मजदूरी का तर्क:** इस तर्क के अनुसार जिन देशों में मजदूरी की दर ऊँची होती है वहां लागत भी अधिक होती है जिसके कारण ऊँचा मूल्य रखना पड़ता है। ऐसे देश कम मजदूरी दर वाले देश से आने वाली वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसलिए उद्योग को संरक्षण देने की आवश्यकता होती है। आजकल तो विकासशील देशों में भी शक्तिशाली श्रम-संघों के उदय के कारण मजदूरी की दर ऊँची होने लगी है। कई बार तो मजदूरी की दर मजदूर के सीमान्त उत्पादकता से भी ज्यादा होती है। इसके कारण लागत में वृद्धि हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप मूल्य भी अधिक रखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में संरक्षण की आवश्यकता होती है।
 5. **लागतों को सामान करने का तर्क:** ऐसा शायद ही हो कि एक वस्तु का दो देशों में उत्पादन लागत समान हो। परिस्थितियों में भिन्नता होने के कारण उत्पादन लागत भी भिन्न होते हैं, जिसके कारण मूल्य भी भिन्न हो जाते हैं। यदि घरेलू वस्तु की उत्पादन लागत विदेशी वस्तु के उत्पादन लागत से 10% अधिक हो तो वह देश आयातित वस्तु पर 10% आयात शुल्क लगा कर मूल्य को समान करने की चेष्टा करेगा जिससे उपभोगताओं को दोनों वस्तु एक ही मूल्य के प्रतीक हो।
 6. **शिशु उद्योग से सम्बंधित तर्क:** संरक्षण के पक्ष में सबसे प्रबल तर्क शिशु उद्योग को लेकर है। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर हेमिल्टन ने शिशु उद्योग के संरक्षण की बात कही। बाद में जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट ने इसे तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि शिशु उद्योगों का विकास मुक्त व्यापार के सिद्धांतों के आधार पर नहीं हो सकता। कम विकसित देशों के शिशु उद्योग अपने स्थापना के प्रारंभिक दौर में विकसित देशों के बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं होते। इसलिए उन्हें प्रारंभिक दौर में संरक्षण की आवश्यकता होती है। परन्तु लिस्ट ने इस बात पर बल दिया कि संरक्षण कुछ ही समय के लिए दिया जाना चाहिए तथा उद्योग विशेष की ‘परिपालना’ अर्थात् नर्सिंग के उपरांत जब वे अपनी आंतरिक बचतों (Internal Economies) का पूर्ण प्रयोग कर चुके होंगे तब संरक्षण नीति समाप्त कर देनी चाहिए।
 7. **उद्योगों में विविधता लाने सम्बन्धी तर्क:** आद्योगिक उत्पादन में विविधता लाने के उद्देश्य से भी संरक्षण की नीति का प्रयोग किया जाता है। देश में सुनियोजित आद्योगिक विकास के लिए संरक्षण का सहारा लिया जाता है।
 8. **राशिपातन(Dumping) से बचाने हेतु:** राशिपातन से बचाने के लिए भी संरक्षण की नीति का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रतियोगी देश कम मूल्य पर अथवा घाटा सहन कर, दूसरे देश में अपने उत्पाद को

उतारते हैं। तब इसे राशिपातन (Dumping) इससे घरेलू उद्योगों के नष्ट होने का खतरा बना रहता है। ऐसी स्थिति में संरक्षण अपरिहार्य हो जाता है।

9. **बेरोजगारी एवं संरक्षण:** संरक्षण की नीति का समर्थन इस बात पर किया जाता है कि इससे घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है जिससे देश में रोजगार का सृजन होता है और बेरोजगारी दूर करने में मदद मिलती है।
10. **प्रतीकात्मक संरक्षण:** कभी-कभी देश के लिए मुक्त व्यापार की नीति पर चलना संभव नहीं हो पाता क्योंकि अन्य देश घरेलू उत्पादकों को कई प्रकार से रियायतें देकर संरक्षण दिए होते हैं। ऐसी स्थिति में उस देश को भी संरक्षण की नीति अपनानी पड़ती है।

7.4.3 संरक्षण के विपक्ष में तर्क

1. **मुद्रा स्फीति में वृद्धि:** देशी उद्योग को संरक्षण देने के नाम पर आयातित वस्तु पर आवश्यकता से अधिक प्रतिबन्ध लगाने से देश में स्फीतिकारी स्थिति पैदा होने का खतरा उत्पन्न होने लगता है। आयात पर प्रतिबंधों के फलस्वरूप उन उद्योगों का विकास अवरूद्ध हो जाता है। जिनमें आयातित मशीनों व कच्चे माल का उपयोग होता है। जिसके परिणामस्वरूप देश के निर्यातों में भी कमी होने की संभावना हो जाती है।
2. **एकाधिकार को प्रोत्साहन:** घरेलू उद्योग को संरक्षण देने से उनमें एकाधिकारी शक्ति के उदय होने का भी खतरा उत्पन्न होता है। इसके फलस्वरूप देश की जनता निरपेक्ष/तुलनात्मक लागतों के लाभ से वंचित रह जाती है।
3. **भुगतान-असंतुलन को प्रोत्साहन:** यह तर्क कि संरक्षण से भुगतान संतुलन में सुधार आता है, पूर्णतः सत्य नहीं है। कई बार भुगतान संतुलन को ठीक रखने के लिए अधिक आयात कर भुगतान संतुलन में घाटे के स्थिति उत्पन्न करती है। यह कोई आवश्यक नहीं कि अधिक आयात कर आयात में कमी ला दे। इसके अलावा अधिक आयात पर निर्भरता की स्थिति में आयात कर, निर्यात में भी कमी ला सकता है।
4. **व्यावसायिक शिथिलता:** जैसा कि पहले चर्चा किया गया, संरक्षण घरेलू रोजगार सृजन में मदद करता है। किन्तु यह भी संभव है कि अत्यधिक संरक्षणवादी नीति व्यावसायिक शिथिलता उत्पन्न कर दे, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार में वृद्धि न होकर इसमें कमी आ जाय।

7.4.4 संरक्षण की विधियाँ

संरक्षण की निम्नलिखित विधियाँ हैं। इनका संक्षेप में परिचय प्रस्तुत है:

1. **प्रशुल्क (Tariffs):** संरक्षण प्रदान करने की यह सबसे प्रचलित विधि है। आयात होने वाले वस्तु पर जब कर लगाया जाता है। तब उसका मूल्य घरेलू बाजार में बढ़ जाता है। जिसके कारण देश में निर्मित वही वस्तु अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाती है।
2. **अभ्यंश एवं लाइसेंस(Quota and Licences):** अभ्यंश अथवा कोटा के अंतर्गत सरकार आयातित वस्तु की अधिकतम मात्रा निर्धारित करती है। इसके कारण घरेलू उद्योगों के लिए निश्चिन्तता हो जाती है कि उसे सीमित विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। लाइसेंसिंग प्रणाली के अंतर्गत सरकार सोंच-समझकर और घरेलू उद्योगों का हित देखकर आयात का लाइसेंस प्रदान करती है।
3. **अनुदान (Subsidies):** अनुदान भी घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की विधि है। अनुदान के अंतर्गत घरेलू उद्योग के उत्पाद को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार उसके उत्पादन लागत का कुछ भाग स्वयं वहन करती है। कभी-कभी निर्यात बोनस, निर्यात पुरस्कार, निर्यात करों में छूट के द्वारा भी सरकार

घरेलू निर्यातकों को संरक्षण प्रदान करती है। इन सब विधियों से वस्तुओं के मूल्यों को कृत्रिम रूप से कम करके निर्यातों को प्रोत्साहित किया जाता है।

4. **राज्य व्यापार (State Trading):** राज्य व्यापार संरक्षण प्रदान करने की प्रत्यक्ष विधि है। विशेषकर समाजवादी देशों में राज्य व्यापार के माध्यम से घरेलू उद्योग के उत्पाद को विश्व बाज़ार में बेचने की जिम्मेवारी सरकार अपने ऊपर लेती है। इसके लिए सरकार ट्रेडिंग एजेंसियां निर्मित करके विदेश व्यापार करती है।
5. **अंतर्राष्ट्रीय संघ (International Cartel):** कई देश आपस में मिलकर संघ बना लेते हैं जिसका उद्देश्य अपने उत्पाद का विश्व बाज़ार में अधिक मूल्य सुनिश्चित करना होता है। ऐसे संघ को कार्टेल कहा जाता है। उदाहरणस्वरूप तेल निर्यातक देशों का संगठन **ओपेक (OPEC)** एक प्रकार का कार्टेल है जिसका उद्देश्य विश्व बाज़ार में तेल का उचित मूल्य प्राप्त करना है। इससे घरेलू तेल उत्पादक कम्पनियों को संरक्षण प्राप्त होता है।

7.5 अभ्यास हेतु प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. मुक्त व्यापार किसे कहते हैं?
2. वणिकवाद क्या है?
3. संरक्षण से क्या समझते हैं?
4. संरक्षण से क्या समझते हैं?
5. कार्टेल क्या है?
6. राशिपातन(Dumping) क्या है?

सत्य/असत्य का चुनाव करें

1. वणिकवादी मुक्त व्यापार के समर्थक थे।
2. एडम स्मिथ ने मुक्त व्यापार के पक्ष में तर्क दिया।
3. मुक्त व्यापार से श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण घटता है।
4. भूमंडलीकरण मुक्त व्यापार की दिशा में कदम है।
5. प्रशुल्क व कोटा मुक्त व्यापार में बाधक हैं।
6. प्रशुल्क व अनुदान संरक्षण के उपाय हैं।
7. राज्य व्यापार मुक्त-व्यापार की दिशा में उपाय है।
8. कोटा एक प्रकार का कर है।

बहुविकल्पी प्रश्न

1. एडम स्मिथ के अनुसार मुक्त व्यापार से
 - a. कुल उत्पादन बढ़ता है
 - b. कुल उपभोग बढ़ता है
 - c. कुल उत्पादन और कुल उपभोग दोनों बढ़ता है
 - d. कुल उत्पादन बढ़ता है और कुल उपभोग घटता है।
2. मुक्त व्यापार से विश्व बाज़ार में

- a. वस्तु का मूल्य समान होने लगता है b. साधन का मूल्य समान होने लगता है
- c. वस्तु व साधन दोनों का मूल्य समान होने लगता है
- d. वस्तु अथवा साधन मूल्य का मुक्त व्यापार से कुछ लेना-देना नहीं
3. निम्नलिखित में कौन संरक्षण का उपाय है
- a. प्रशुल्क b. कोटा
- c. राज्य व्यापार d. उपर्युक्त तीनों
4. आयात को कम करने का प्रत्यक्ष विधि है
- a. प्रशुल्क b. कोटा
- c. प्रशुल्क व कोटा दोनों d. इनमें से कोई नहीं

7.6 सारांश

इस इकाई में हमने मुक्त व्यापार और संरक्षण विषय पर विचार किया। दोनों ही विषय एडम स्मिथ के जमाने से लेकर आज भूमंडलीकरण के दौर में महत्वपूर्ण हैं। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभ को रेखांकित करते हुए एडम स्मिथ ने मुक्त व्यापार की वकालत की थी। उनके पूर्व वणिकवादियों का तर्क था कि आयात से देश को नुकसान तथा निर्यात से देश को फायदा होता है। किन्तु एडम स्मिथ ने तर्क दिया कि मुक्त व्यापार से आयात व निर्यात करनेवाले दोनों पक्षों को लाभ मिलता है और इससे विश्व में कल्याण का स्तर ऊँचा उठता है।

आज का युग भूमंडलीकरण का युग है जिसमें व्यापार के अवरोध तोड़े जा रहे हैं और विश्व मुक्त-व्यापार की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। किन्तु कहना न होगा कि इस प्रणाली ने दुनिया में कई विसंगतियां पैदा की है जिसका दुस्परिणाम कई देशों विशेषकर विकासशील देशों को भुगतना पड़ रहा है। विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई अब और चौड़ी हो गई है। बहुराष्ट्रीय कम्पनिओं का जाल विकासशील देशों में फैलता जा रहा है। उनके यहाँ के घरेलू उद्योग इन बहुराष्ट्रीय कम्पनिओं के आगे प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। कई उद्योग तो बहुराष्ट्रीय कम्पनिओं के सामने अपना अस्तित्व ही खो चुके हैं। ऐसे में अब पुनः इन देशों में संरक्षण के उपाय की बात की जा रही है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद मुक्त व्यापार के अवरोध जैसे प्रशुल्क, अनुदान आदि को हटाने की बात थी।

अब प्रश्न उठना लाजिमी है कि बिना संरक्षण के विकासशील देशों के छोटे उद्योग कैसे पनपेंगे। मुक्त व्यापार के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वे कुछ अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित हैं जिसके कारण इसके लाभ के जो दावे किये जाते हैं वे उपलब्ध नहीं हो पाते। मुक्त व्यापार से लाभ का जो सब्जबाग विकसित देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा दिखाया जाता है वह सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखकर होता है। इसलिए आज भी संरक्षणवादी नीतियों का महत्व है जिसका प्रयोग विकासशील देशों को अपने आवश्यकतानुसार करने में संकोच नहीं करनी चाहिए।

7.7 शब्दावली

- **मुक्त व्यापार** - यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विश्व में बिना अवरोध के व्यापार होता है। वस्तुओं और उत्पादन के साधनों का एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण निर्बाध होता है।
- **वणिकवाद** - सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से लेकर अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में प्रचलित विचारधारा जो प्रतिबंधित व्यापार का समर्थक था। इस मत का विश्वास था कि निर्यात करने से देश की

सम्पदा में वृद्धि होती है और आयात करने से कमी होती है। यह विचारधारा कट्टर राष्ट्रवाद से प्रभावित था।

- **संरक्षण** - संरक्षण का तात्पर्य ऐसी नीति से है जिसके अंतर्गत घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय किये जाते हैं। इसके लिए विदेशी वस्तुओं पर प्रशुल्क या कोटा लगाकर उनके सामने घरेलू वस्तुओं को प्रतिस्पर्धी बनाया जाता है और साथ ही अनुदान देकर उनकी लागत को कृत्रिम रूप से कम किया जाता है।
- **राशिपातन** - यह एक प्रकार का मूल्य विभेदीकरण है जिसके अंतर्गत वस्तु का मूल्य विदेशी बाजार में घरेलू बाजार की तुलना में कम रखा जाता है। घरेलू बाजार में एकाधिकारी मूल्य तथा विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धी मूल्य की स्थिति राशिपातन के अंतर्गत बनती है। कभी-कभी तो उत्पादक अपने को विदेशी बाजार में स्थापित करने के लिए अपनी वस्तु का मूल्य विदेशी बाजार में लागत से भी कम रखता है। ऐसी स्थिति को गला-काट प्रतियोगिता (Cut throat competition) कहते हैं।
- **शिशु उद्योग** - शिशु उद्योग शब्द का प्रयोग वैसे उद्योग के लिए किया जाता है जिसने अभी हाल ही में उत्पादन प्रारंभ किया है और अभी अपनी आंतरिक बचतों (Internal economies) का पूर्ण दोहन नहीं कर सका है, जिसके कारण उसकी प्रति इकाई लागत अधिक होती है और वह अन्य उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा कर सकने की स्थिति में नहीं होता।
- **राज्य व्यापार** - राज्य व्यापार से आशय सरकार के उस हस्तक्षेप से है जिसमें सरकार द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले निजी व्यापार पर पूर्ण अथवा अंशिक नियंत्रण कर लिया जाता है। राज्य व्यापार प्रायः समाजवादी देशों में देखने को मिलता है। यह मुक्त-व्यापार की अवधारणा के विपरीत है।
- **अनुदान (Subsidy)** - अनुदान लागत का वह भाग है जो सरकार वहन करती है। इससे वस्तु का मूल्य कृत्रिम रूप से कम हो जाता है। अपने देश के उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने के लिए सरकारें निर्यात-अनुदान प्रदान करती हैं। यह एक संरक्षणवादी उपाय है।

7.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

सत्य/असत्य का चुनाव

- | | | | |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 1. असत्य, | 2. सत्य | 3. असत्य | 4. सत्य |
| 5. सत्य, | 6. सत्य, | 7. असत्य, | 8. असत्य |

बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर

1. iii) कुल उत्पादन और कुल उपभोग दोनों बढ़ता है
2. iii) वस्तु और साधन दोनों का मूल्य समान होने लगता है
3. iv) उपर्युक्त तीनों,
4. ii) कोटा,

7.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- Bo Sodersten, International Economics ,Macmillan, 1999

- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006
- H. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: *International Economics: Theory and Policy*, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- एस. एन. लाल , अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र , शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहबाद, 2004
- एच. एस. अग्रवाल, तथा सी. एस. बरला, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2003.
- सुदामा सिंह एवं एम. सी. वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड एंड आई. बी. एच. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम. एल. झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010.
- डॉ. जी. सी. सिंघई एवं डॉ. जे. पी. मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा, 2010.

7.10 उपयोगी/सहायक पाठ्य सामग्री

- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006
- H. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: *International Economics: Theory and Policy*, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- एस. एन. लाल , अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र , शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहबाद, 2004
- एच. एस. अग्रवाल, तथा सी. एस. बरला, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2003.
- सुदामा सिंह एवं एम. सी. वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड एंड आई. बी. एच. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम. एल. झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010।
- ज्ञानेंद्र सिंह कुशवाहा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1979।

7.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हैं? इससे क्या लाभ है ? इसकी सीमाओं का भी उल्लेख करें।
2. संरक्षण से आप क्या समझते हैं? संरक्षण के पक्ष और विपक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करें।
3. संरक्षण की प्रमुख विधियों का विवरण प्रस्तुत करें।

इकाई 8- गैर-टैरिफ व्यापार बाधाएं (Non-Tariff Trade Barriers)

- 8.1 प्रस्तावना
- 8.2 उद्देश्य
- 8.3 गैर-टैरिफ व्यापार बाधाएं
 - 8.3.1 गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं का औचित्य
 - 8.3.2 गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं के वर्गीकरण
- 8.4 गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं के प्रकार
- 8.5 देश के आर्थिक विकास में गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं की भूमिका
- 8.6 अभ्यास हेतु प्रश्न
- 8.7 सारांश
- 8.8 शब्दावली
- 8.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 8.10 सन्दर्भ ग्रंथ सूची
- 8.11 सहायक/उपयोगी सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 8.12 निबंधात्मक प्रश्न

8.1 प्रस्तावना

जैसा कि हम जानते हैं कि जब स्वतंत्र बाजार की शक्तियां देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे में वांछित परिणाम लाने में असफल हो जाती हैं तो देश की सरकार विभिन्न प्रकार की प्रतिबंधात्मक और निर्देशात्मक उपायों को अपनाती है। इन उपायों में प्रशुल्क यानि टैरिफ की चर्चा हम पूर्व की इकाई में कर चुके हैं। प्रस्तुत इकाई में गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं की चर्चा हम करने जा रहे हैं जो घरेलू उत्पाद के पक्ष व विदेशी उत्पाद में विभेद उत्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा अपनाये जाते हैं। इस इकाई में गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं का मुख्य वर्गीकरण करने के उपरांत गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं के प्रकार से आपको परिचित कराया गया है। इसके अलावा देश के आर्थिक विकास में इन गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं की भूमिका से भी आपको अवगत कराया गया है।

8.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- ✓ गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं के औचित्य को समझ पाएंगे।
- ✓ गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं के वर्गीकरण का आधार जान पाएंगे।
- ✓ गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं के विभिन्न प्रकार से परिचित होंगे।
- ✓ गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं का देश के आर्थिक विकास में भूमिका से अवगत होंगे।

8.3 गैर-टैरिफ व्यापार बाधाएं

8.3.1 गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं का औचित्य

घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने, भुगतान संतुलन को ठीक रखने व देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में प्रशुल्क के अतिरिक्त कुछ गैर-प्रशुल्क यानि गैर-टैरिफ उपायों का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह बात विकासशील देशों पर विशेष रूप से लागू होती है। कई बार ऐसा होता है कि विदेशी कम्पनियाँ विशेषकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ प्रशुल्क लगाने के बावजूद अपनी वस्तु के मूल्य में कमी करके देश के बाजार में उसी कीमत पर बेचने में सफल हो जाती है। इससे घरेलू उद्योग को संरक्षण देने का प्रशुल्क-उपाय सफल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में गैर-प्रशुल्क उपाय कारगर साबित होते हैं और इनकी मदद से आयात को सीमित करने का प्रयास किया जाता है।

8.3.2 गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं के वर्गीकरण गैर-

प्रशुल्क बाधाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है:

1. **मात्रात्मक व्यापार प्रतिबन्ध:** इसके अंतर्गत आयात अभ्यंश, प्रशुल्क अभ्यंश, स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें, सुव्यवस्थित विपणन व्यवस्था अथवा अनुबंध, बहु-तंतु व्यवस्था आदि सम्मिलित हैं।
2. **राजकोषीय उपाय:** इसके अंतर्गत निर्यात अथवा उत्पादन सब्सिडी, निर्यात ऋण सब्सिडी, निर्यात पर कर-राहत, सरकारी वसूली, प्रति-राशिपातन शुल्क, प्रतिकार शुल्क आदि आते हैं।
3. **प्रशासनिक, प्रमाणिक तथा विनियमन उपाय:** इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, आरोग्य तथा सुरक्षा विनियम, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, सीमा मूल्यांकन तथा वर्गीकरण, मार्किंग तथा पैकेजिंग आवश्यकताएं, आयात लाइसेंसिंग कार्रवाई, सरकारी व्यापार एवं एकाधिकार, आयात की सीमाओं पर विलम्ब, सरकारी कर्मचारियों को देश में बनी वस्तुएं खरीदने के आदेश या स्वदेशी खरीद अभियान, स्थानीय अंतर्वस्तु

आवश्यकता (local content requirement) आदि आते हैं। अन्य गैर-प्रशुल्क व्यापार बाधाओं में द्विपक्षीय व्यापार समझौते, राशिपातन, अंतर्राष्ट्रीय वस्तु समझौते, अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल, आदि आते हैं।

8.4 गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं के प्रकार

गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं के वर्गीकरण के उपरान्त हम इसके मुख्य प्रकार पर विचार करते हैं। इनका विवरण प्रस्तुत किया गया है।

1. आयात कोटा (Import Quota):

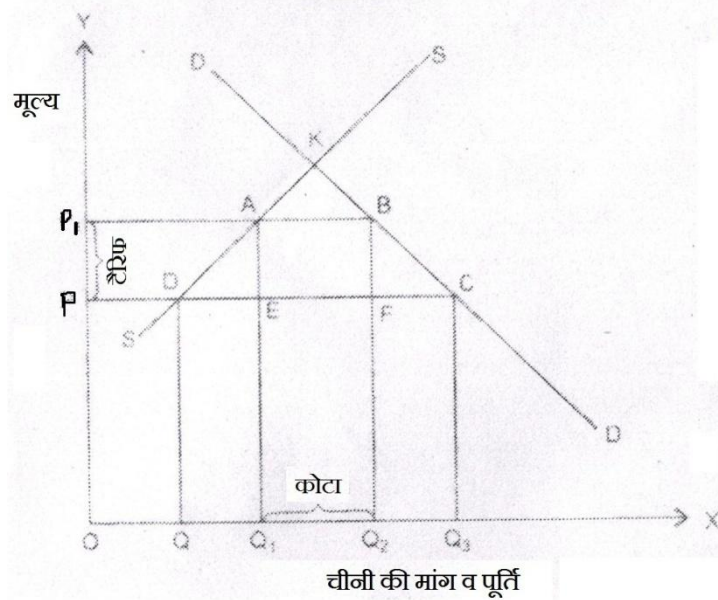
यह एक प्रभावशाली गैर-टैरिफ व्यापार बाधा है। जिसका प्रयोग बहुधा किया जाता है। इसे टैरिफ यानि प्रशुल्क के विकल्प के रूप में देखा जाता है। आयात कोटा से तात्पर्य, वस्तु की उस निश्चित मात्रा अथवा मूल्य से है। जिसका समय के एक निश्चित अवधि में देश में आयात किया जाता है। आयात को सीमित करने का यह एक प्रत्यक्ष, प्रभावी और लोचशील विधि है। देश की सरकार को विभिन्न कारणों से इसका प्रयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसके द्वारा आयात की भौतिक मात्रा अथवा आयात मूल्य की सीमा सरकार निर्धारित करती है। इस सीमा के ऊपर आयात की मनाही रहती है। जैसा कि हम जानते हैं, आयात को कम करने का आयात प्रशुल्क एक प्रचलित उपाय है किन्तु कभीकभी आयात-प्रशुल्क को निष्प्रभावी बनाने के लिए विदेशी उत्पादक अपने उत्पाद का मूल्य कम कर देते हैं, जिससे प्रशुल्क लगने के उपरान्त भी उनके उत्पाद का मूल्य अधिक नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में आयात-कोटा अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। आयात कोटा पांच प्रकार के होते हैं:

- टैरिफ कोटा:** इस कोटा प्रणाली में टैरिफ व कोटा दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। इसके अंतर्गत वस्तु की एक निर्धारित मात्रा को बिना शुल्क या सापेक्षतया कम शुल्क पर देश में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। किन्तु निर्धारित मात्रा से अधिक आयात पर सापेक्षतया उंची शुल्क दर पर आयात की अनुमति दी जाती है।
- एकपक्षीय कोटा:** एकपक्षीय कोटा प्रणाली के अन्तर्गत आयात की जानेवाली वस्तु की कुल मात्रा या मूल्य को दूसरे देश के साथ समझौता या परामर्श किये बिना ही लागू किया जाता है। इस प्रकार के कोटा में दो देशों के बीच व्यापारिक विवाद उत्पन्न होने की संभावना रहती है।
- बहुपक्षीय कोटा:** इस कोटा-प्रणाली के अन्तर्गत दूसरे देश के साथ सहमति या समझौते के आधार पर कोटा लागू किया जाता है। इस प्रकार के कोटा में दोनों देशों के बीच विवाद होने की संभावना नहीं होती।
- मिश्रित कोटा:** इस कोटा प्रणाली के अन्तर्गत निर्मित वस्तु में लगनेवाले कच्चा माल या अर्धनिर्मित वस्तु के एक निश्चित अंश को ही आयात करने की अनुमति होती है, शेष को देश में ही प्राप्त करना होता है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है, घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है व देश विदेशी निर्भरता से मुक्त होता है।

कोटे का प्रभाव: यदि किसी वस्तु की घरेलू मांग व पूर्ति वक्र बेलोचदार नहीं है तब आयात पर प्रशुल्क लगाने या कोटा निश्चित करने का प्रभाव लगभग एक समान होता है। इसे प्रस्तुत चित्र की मदद से समझा जा सकता है।

चित्र 8.1 में किसी वस्तु, उदाहरणस्वरूप चीनी, की घरेलू मांग DD वक्र से व पूर्ति SS वक्र से से दर्शाया गया है। OP मूल्य पर विदेशी चीनी की पूर्ति पूर्णतया लोचदार है। इस मूल्य पर चीनी की घरेलू मांग OQ_3 है, जबकि घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित चीनी की पूर्ति केवल OQ है। इस प्रकार इस मूल्य पर देश में चीनी की मांग इसकी घरेलू पूर्ति से कहीं अधिक है। मुक्त व्यापार की स्थिति में अतिरिक्त मांग QQ_3 ($OQ_3 - OQ$) की पूर्ति विदेश से आयात करने पर होगी। यदि सरकार चीनी की Q_1Q_2 मात्रा का आयात कोटा निश्चित कर देती है तब चीनी की इस मात्रा का आयात कोटा की अनपस्थिति में तब किया जायेगा जब सरकार चीनी के आयात पर PP_1

के बराबर टैरिफ लगा देती है। इस स्थिति में आयात कोटा व आयात टैरिफ के प्रभाव में कोई अंतर नहीं रह जायेगा और दोनों ही स्थितियों में संरक्षण प्रभाव QQ_1AD के बराबर। उपभोग प्रभाव Q_2Q_3CB के पुनर्वितरण प्रभाव $PDAP_1$ के बराबर होगा। किन्तु इनके राजस्व प्रभाव में भिन्नता होगी। टैरिफ से सरकार को $ABEF$ के बराबर राजस्व प्राप्त होता है जो कोटा लगाने से संभव नहीं था।

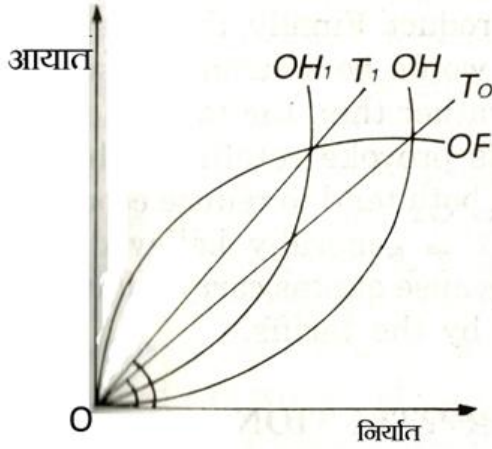


चित्र संख्या 8.1

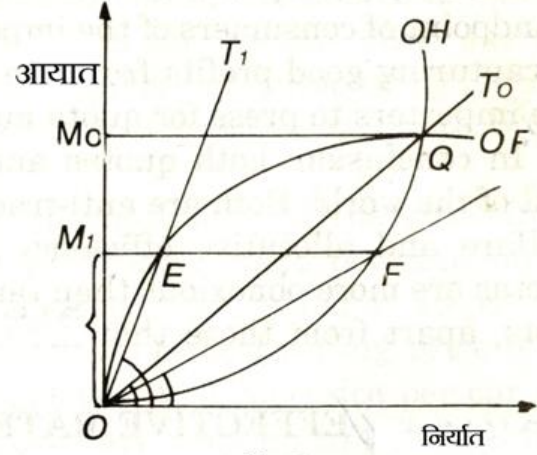
हां, यदि सरकार कोटा देने के लिए लाइसेंस शुल्क लगाती है तो प्राप्त राजस्व सरकार के खजाने में जाएगा। ऐसी स्थिति में टैरिफ व कोटा दोनों का कल्याण सम्बन्धी पुनर्वितरण प्रभाव एक हो सकता है।

किन्तु दोनों के उद्देश्य भले ही आयात को सीमित करना हो, दोनों के क्रिया-विधि भिन्न होते हैं। जहाँ टैरिफ वस्तु के मूल्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वहीं आयात मात्रा पर इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वहीं कोटा का आयात मात्रा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और मूल्य पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार टैरिफ व कोटा दोनों आयात मूल्य में वृद्धि करके आयात मात्रा में कमी लाते हैं। इसलिए उपभोग, उत्पादन, व्यापार संतुलन, राष्ट्रीय आय की मात्रा व इसके वितरण, अन्य आर्थिक क्रिया-कलाप व कल्याण पर इनके प्रभाव लगभग एक समान होते हैं।

जहाँ तक प्रभाव में भिन्नता का प्रश्न है तो टैरिफ से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है वहीं कोटा से कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं होती। इससे कल्याण सम्बन्धी मुद्दे उभर आते हैं। सरकार टैरिफ से प्राप्त राजस्व के कुछ भाग को कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर सकती है। चूंकि कोटा से कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं होती इसलिए इससे कल्याण सम्बन्धी कोई लाभ नहीं होता। हाँ, यदि सरकार कोटा को लागू करने के लिए कोई लाइसेंस शुल्क रख देती है तो उससे प्राप्त राजस्व को कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में कोटा का कल्याणकारी प्रभाव टैरिफ के कल्याणकारी प्रभाव के समान ही होगा। किन्तु कोटा लाइसेंसिंग व्यवस्था प्रशासन में भ्रष्टाचार को जन्म दे सकती है। यह बात टैरिफ में नहीं होती। कोटा कई मामलों में टैरिफ से ज्यादा प्रभावी होता है, खासकर तब जब किसी वस्तु की घरेलू मांग व पूर्ति की लोच बेलोचदार हो। रही बात व्यापार की शर्त की तब टैरिफ से तो व्यापार की शर्त पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जा सकता है किन्तु कोटा का व्यापार की शर्त पर पड़ने वाला प्रभाव अनिश्चित (indeterminate) होता है। इसे प्रस्तुत चित्र से समझा जा सकता है।



चित्र 8.2.1



चित्र 8.2.2

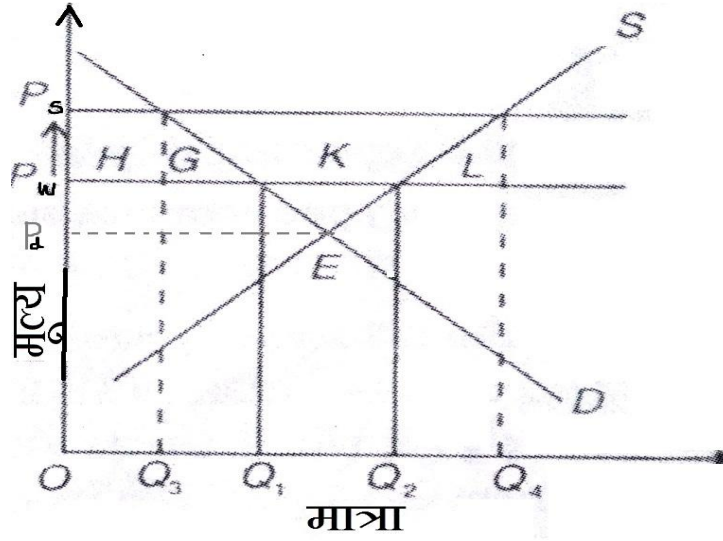
चित्र 8.2.1 और चित्र 8.2.2 में, क्रमशः टैरिफ और कोटा के व्यापार की शर्त पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाया गया है। दोनों चित्रों में OH व OF वक्र क्रमशः घरेलू देश व विदेशी देश के प्रस्ताव वक्र हैं।

चित्र 8.2.1 में टैरिफ लगने के उपरान्त टैरिफ लगाने वाले देश का प्रस्ताव वक्र OH से OH_1 हो जाता है। जिसके परिणामस्वरूप व्यापार की शर्त OT से OT_1 हो जाता है जो दर्शाता है कि टैरिफ लगने के बाद देश का व्यापार शर्त पहले से अनुकूल हो गया है। अब हम चित्र 8.2.2 में कोटा लगने पर व्यापार शर्त पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं। मुक्त व्यापार की स्थिति में संतुलन Q बिन्दु पर है। जिससे व्यापार की शर्त OTO निर्धारित होता है। ऐसी स्थिति में घरेलू देश का आयात OM_0 तथा निर्यात M_0Q होता है। यदि घरेलू देश अपने देश में कोटा लागू कर आयात को OM_1 कर देती है तब हम इसके फलस्वरूप व्यापार शर्त पर पड़नेवाले प्रभाव पर विचार करते हैं। इसके लिए M_1 एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं जो विदेशी देश के प्रस्ताव वक्र को E बिन्दु पर तथा घरेलू देश के प्रस्ताव वक्र को F बिन्दु पर कटता है। अब यदि कोटा लगने के बाद व्यापार संतुलन E बिन्दु पर होता है तब कोटा लगाने वाले देश का व्यापार शर्त अनुकूल हो जाता है क्योंकि जैसा कि चित्र से स्पष्ट है व्यापार की शर्त रेखा OT_1 की ढाल OT_0 से अधिक है। दूसरी तरफ यदि कोटा लगने के बाद व्यापार संतुलन F बिन्दु पर स्थापित होता है। तब घरेलू देश का व्यापार शर्त प्रतिकूल हो जायेगा क्योंकि तब नई व्यापार शर्त रेखा OT_2 की ढाल OT_0 से कम है। इससे स्पष्ट है कि कोटा का व्यापार शर्त पर प्रभाव का अनुमान लगाना संभव नहीं है। वहीं हमने चित्र 8.2.1 की मदद से देखा कि टैरिफ का व्यापार शर्त पर प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है।

2. निर्यात सब्सिडी(Export Subsidy):

निर्यात सब्सिडी किसी देश की सरकार द्वारा एक निर्यातक फर्म अथवा उत्पादक को दी जाने वाली आर्थिक सहायता है ताकि निर्यात वस्तुओं की कीमत में कमी की जा सके। इससे निर्यात-वस्तु को विदेशी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जाता है। सरकार निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए अपने देश के निर्यातकों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आर्थिक अनुदान देकर उत्पाद को कम मूल्य पर बेचने के लिए प्रोत्साहित करती है। किन्तु प्रत्यक्ष निर्यात सब्सिडी GATT तथा उसके बाद WTO के प्रावधानों के विरुद्ध होने के कारण सरकारें विभिन्न प्रकार की अप्रत्यक्ष निर्यात सब्सिडी ही देती हैं, जैसे रियायती दरों पर ऋण, उनके द्वारा दिए गए प्रशुल्कों में वापसी, कमी वाले कच्चे माल के आवंटन में प्राथमिकता, व्यापार मेले जैसी गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता, बाजार अनुसन्धान, विज्ञापन में वित्तीय सहायता, कर-राहत आदि।

निर्यात सब्सिडी के प्रभाव: निर्यात सब्सिडी के प्रभाव का हम आंशिक संतुलन विश्लेषण की मदद से प्रस्तुत चित्र की मदद से करते हैं।



चित्र 8.3

इस चित्र में एक छोटे से देश, जैसे नेपाल के मामले में आंशिक संतुलन के अंतर्गत निर्यात सब्सिडी के आर्थिक प्रभावों को दर्शाया गया है। यहाँ निर्यात सब्सिडी का आयातक देश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस चित्र में D और S निर्यात योग्य वस्तु के क्रमशः घरेलू मांग व पूर्ति वक्र हैं तथा बाजार संतुलन E बिन्दु पर स्थापित होता है। जिसके कारण घरेलू मूल्य OPd स्थापित होता है। विश्व बाजार मूल्य OPw है जो घरेलू मूल्य OPd से ऊपर है। ऐसी स्थिति में घरेलू मांग OQ₁ है तथा घरेलू पूर्ति OQ₂ है। मांग से पूर्ति अधिक (OQ₂ - OQ₁ = Q₁Q₂) होने के कारण देश Q₁Q₂ के बराबर निर्यात करता है। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्रत्येक निर्यातित इकाई पर PwPs देती है। इससे घरेलू कीमत, घरेलू उत्पादकों व उपभोक्ताओं दोनों के लिए बढ़कर OPs हो जाती है। निर्यात सब्सिडी के कारण निर्यात में वृद्धि होती है। जिसके फलस्वरूप घरेलू बाजार में वस्तु के पूर्ति में कमी आ परिणामस्वरूप उस वस्तु की घरेलू कीमत में वृद्धि हो जाती है।

उदाहरणस्वरूप काजू उत्पादकों को भारत में निर्यात सब्सिडी मिलने के कारण काजू के घरेलू पूर्ति में कमी आ जाती है जिसके कारण इसके घरेलू मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इससे काजू के घरेलू उपभोक्ताओं के उपभोक्ता अतिरेक (consumer's surplus) में हानि होती है। निर्यात पर सब्सिडी मिलने के कारण वस्तु का प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर होने लगता है, जिसके कारण इसकी पूर्ति घरेलू बाजार में कम हो जाती है। फलस्वरूप वस्तु की कीमत घरेलू बाजार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में बढ़ जाती है। चित्र से स्पष्ट है, घरेलू बाजार की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अधिक होने के कारण इस कीमत पर वस्तु की घरेलू मांग OQ₃ पर गिर जाती है जबकि पूर्ति OQ₄ तक बढ़ जाती है। फलस्वरूप कुल निर्यात Q₁Q₂ से Q₃Q₄ तक बढ़ जाती है।

इस निर्यात सब्सिडी के फलस्वरूप घरेलू कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप उपभोक्ता अतिरेक (consumer's surplus) में H+G क्षेत्र के बराबर कमी आती है। वहीं उत्पादक अतिरेक (producer's surplus) में H+G+K क्षेत्र के बराबर वृद्धि होती है। सरकार को निर्यात सब्सिडी पर कुल लागत G+K+L उठानी पड़ती है। इस प्रकार देश के कल्याण में शुद्ध हानि त्रिभुज G और L के बराबर है। संक्षेप में,

निर्यात सब्सिडी के फलस्वरूप

$$\text{उत्पादक अतिरेक में वृद्धि} = H+G+K$$

$$\text{उपभोक्ता अतिरेक में हानि} = -(H+G)$$

$$\text{सरकार का सब्सिडी लागत} = -(G+K+L)$$

$$\text{शुद्ध कल्याण हानि} = -(G+L)$$

इस प्रकार, देश में होनेवाली शुद्ध कल्याण हानि वस्तु पर दी जाने वाली सब्सिडी लागत और उपभोक्ता अतिरेक के हानि के योग के उत्पादक अतिरेक से अधिक होने के कारण होता है। एक बात और, निर्यात सब्सिडी के कारण देश के व्यापार शर्त में गिरावट भी आ सकती है। यदि देश अपनी वस्तु को बड़े पैमाने पर सब्सिडी दे रहा हो तब उसकी सब्सिडी देने की लागत बढ़ जाती है। जैसे-जैसे उसके निर्यात में और विस्तार होगा, उसके व्यापार शर्त में गिरावट आएगी और उसका शुद्ध कल्याण हानि और अधिक हो जायेगा।

निर्यात सब्सिडी बनाम टैरिफ: निर्यात सब्सिडी व टैरिफ के प्रभाव में कुछ भिन्नताएं हैं:

पहला, निर्यात सब्सिडी और टैरिफ दोनों में, वस्तु के घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में अंतर पैदा जो जाता है। जहाँ निर्यात सब्सिडी निर्यातयोग्य वस्तु की घरेलू कीमत बढ़ा देता है, वहीं आयात टैरिफ आयातयोग्य वस्तु के घरेलू कीमत में वृद्धि कर देता है।

दूसरा, निर्यात सब्सिडी संसाधनों को निर्यातयोग्य वस्तुओं की ओर मोड़ती है। परन्तु आयात प्रशुल्क संसाधनों को घरेलू उपभोग के लिए वस्तुओं के उत्पादन की ओर ले जाते हैं।

तीसरा, निर्यात सब्सिडी से सरकार को शुद्ध राजस्व हानि होती है, जबकि आयात-टैरिफ से सरकार को शुद्ध राजस्व लाभ प्राप्त होता है।

चौथा, घरेलू उत्पादकों को दी जानेवाली सब्सिडी आयात की जगह ले लेगी तथा देश में वास्तविक बचत बढ़ेगी। वास्तविक आय में यही लाभ वस्तु की घरेलू कीमत में वृद्धि के साथ उसी प्रतिशत में प्रशुल्क द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु वस्तु के उपभोग पर रोक के कारण उपभोक्ता अतिरेक(consumer's surplus) की हानि होगी।

पांचवां, निर्यात-सब्सिडी घरेलू कीमत ढांचे को बाहरी कीमत ढांचे के अनुसार ढालती है और इस प्रकार निर्यात को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करती है। दूसरी ओर आयात-प्रशुल्क घरेलू कीमत ढांचे को घरेलू लागत ढांचे के अनुसार ढालता है। इससे अकुशलतायें पैदा होती है तथा निर्यात के लिए विश्व बाजार में प्रतियोगिता करना कठिन हो जाता है।

अंतिम, पिछड़े देशों के दृष्टिकोण से निर्यात-सब्सिडी आयात-प्रशुल्क से श्रेष्ठ है क्योंकि यह निर्यात प्रोत्साहन के द्वारा आर्थिक विकास लाता है जबकि प्रशुल्क का उद्देश्य आयात का प्रतिस्थापन है। लेकिन विश्व मंदी के दौर में निर्यात सब्सिडी भी कभी-कभी कारगर साबित नहीं होता। परिणामस्वरूप, निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करके भुगतान संतुलन को ठीक करने का उद्देश्य पूरा नहीं होता। आयात प्रशुल्क के पक्ष में यह तर्क है कि यह आयात को सीमित करने के साथ देश को राजस्व प्रदान करता है जिससे भुगतान संतुलन की स्थिति बेहतर होती है।

3. स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें(Voluntary Export Restraints - VERs):

स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें (VER) एक ऐसा समझौता है जो निर्यातक देश के निर्यातकों अथवा सरकार द्वारा आयातक देश के साथ उसके निर्यातों को सीमित करने के लिए किया जाता है। यह आयातक देश द्वारा तब किया जाता है जब उसका घरेलू उद्योग बड़े पैमाने पर आयातों से पीड़ित होता है। कहने को तो स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें 'स्वैच्छिक' होती हैं, किन्तु यह कभी-कभार ही 'स्वैच्छिक' होती हैं। इन्हें निर्यातकों को विवशता में स्वीकार करना पड़ता है। किन्तु यदि निर्यातक उंचे मूल्य पर कम निर्यात करके अधिक लाभ कमाने की स्थिति में होता है, तो उसे इन तथाकथित स्वैच्छिक निर्यात रुकावटों को स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होती। अमेरिका तथा

यूरोपीय आर्थिक समुदाय(EEC) के देशों द्वारा इसका प्रयोग जापान तथा विकासशील देशों से स्टील, टीवी, वाहन, वस्त्र आदि के आयात पर रोक लगाने के लिए किया गया है। प्रशुल्क तथा कोटा जैसे व्यापारिक प्रतिबंधों पर GATT तत्पश्चात विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा मनाही के कारण स्वैच्छिक व्यापार प्रतिबंधों को कई देश अपनाते रहे हैं।

4. तकनीकी बाधाएं:

कई देश विशेषकर विकसित देश अपने देश में कुछ गैर-आर्थिक प्रकृति की तकनीकी बाधाओं को लगाकर आयात को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तकनीकी बाधाएं कई तरह की होती हैं जैसे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धी मानक, स्वच्छता मानक, औद्योगिक मानक, लेबलिंग और पैकेजिंग मानक आदि आते हैं। इस तरह के मानक-सम्बन्धी विनियम(regulations) लाकर देश की सरकारें अपने यहाँ आयात की मात्रा को नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं।

5. आयात लाइसेन्सिंग प्रक्रियाएं (Import Licensing Procedures):

कई देश की सरकारें अपने यहाँ आयात को प्रतिबंधित अथवा सीमित करने के लिए जटिल तथा महँगी आयात लाइसेन्सिंग प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। आयात लाइसेंस की ऊँची शुल्क तय की जाती है। इसके अलावे कई अन्य जटिल औपचारिकताओं से इच्छुक लाइसेंस-धारक को गुजरना पड़ता है। किन्तु एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि आयात लाइसेन्सिंग प्रक्रिया जटिल हो जाने से भ्रष्टाचार उत्पन्न होने का भी खतरा रहता है। कहना न होगा, भूमंडलीकरण के इस युग में आयात लाइसेन्सिंग प्रक्रियाएं अब पहले से सरल हो गई हैं।

6. सीमाशुल्क मूल्यांकन तथा वर्गीकरण(Customs Valuation and Classification):

कई बार सीमाशुल्क अधिकारी आयातित वस्तु के मूल्य का निर्धारण उस पर लिखे मूल्य के अनुसार न करके अपने देश में उत्पादित उसी वस्तु के मूल्य के आधार पर करते हैं। एक और तरीका है, आयातित वस्तु को विलम्ब से छोड़ना, जिससे आयातित वस्तु की लागत अपने आप बढ़ जाये। इसके अलावा सीमा शुल्क अधिकारी वस्तुओं का वर्गीकरण भी करते हैं और अलग-अलग वर्ग के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित करते हैं और प्रयास यही रहता है कि आयातित वस्तु को घरेलू बाजार में गैर-प्रतिस्पर्धी बनाना। इससे आयातकों में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है।

7. सरकारी वसूली(Government Procurement):

कई देशों की सरकारें अपने घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित और संरक्षण देने के लिए सरकारी खरीद नियम बनाते हैं जिसके अंतर्गत घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से ही माल खरीदने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में Buy-American Act के अंतर्गत अमेरिका के सरकारी विभागों अथवा एजेंसियों को घरेलू निविदाएँ ही स्वीकार करनी पड़ती हैं चाहे वे विदेशी निविदाओं से 12 प्रतिशत तक अधिक मूल्य की ही क्यों न हो। रक्षा सामग्री में यह 50 प्रतिशत अधिक होने पर भी मान्य होता है। जापान में तो विदेशी निविदाओं पर विचार ही नहीं किया जाता है। इस प्रकार, सरकारें विदेशी निविदाएँ स्वीकार अथवा अस्वीकार करने में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करती हैं। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करना होता है।

8.5 देश के आर्थिक विकास में गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं की भूमिका

देश के आर्थिक विकास के निर्देशन में गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेषकर, घरेलू उद्योगों को संरक्षित करने में गैर-टैरिफ बाधाएं बहुत प्रभावी होती हैं। टैरिफ जैसे उपाय कई बार कारगर साबित नहीं होते। ऐसी स्थिति में गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं की मदद लेनी पड़ती है। विकासशील देश इस तरह की कई व्यापार बाधाओं को अपनाकर अपने उद्योगों को विकसित देश के कम लागत पर बने वस्तुओं की

प्रतिस्पर्धा से बचाते हैं। ये व्यापार रुकावटें विकासशील देशों के विकास को प्रोत्साहित करने में निम्न प्रकार से मदद करती हैं:

1. ये बाधाएं घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करती हैं और इन्हें अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर प्रदान करती हैं ताकि बाद में विदेशी प्रतिस्पर्धा और बहुराष्ट्रीय कम्पनिओं से प्रतिस्पर्धा कर सकने की स्थिति में ये आ सकें।
2. ये बाधाएं विकासशील देशों को औद्योगिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति में मदद करते हैं। घरेलू उद्योगों को संरक्षण देकर तथा आयात-प्रतिस्थापन उद्योगों की स्थापना करके, इस तरह के व्यापार प्रतिबन्ध विकासशील देशों को आद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करते हैं।
3. टैरिफ व गैर-टैरिफ व्यापार बाधाएं विकासशील देशों के भुगतान संतुलन को सुधारने में मदद करती हैं। अधिकांश विकासशील देश प्राथमिक वस्तुओं के निर्यातक व आद्योगिक निर्मित वस्तुओं के आयातक होते हैं। प्रेबिश व सिंगर ने इनके प्रतिकूल भुगतान संतुलन होने के पीछे यही कारण माना है। टैरिफ व गैर-टैरिफ व्यापार प्रतिबन्ध इनके लिए न सिर्फ राजस्व जुटाने में मदद करते हैं बल्कि इनके घरेलू उद्योगों के विकास में भी सहायक होते हैं। परिणामस्वरूप, आयात कम होता है, निर्यात बढ़ता है और देश विदेशी मुद्रा अर्जित करने की स्थिति में आ जाता है जिससे भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होता है।
4. व्यापार प्रतिबंधों से उच्च बचत दर तथा घरेलू पूंजी-निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। इससे भुगतान संतुलन में सुधार होता है और विदेशी ऋण से मुक्ति मिलती है। किन्तु यह सब घरेलू उद्योगों द्वारा इन उपायों से लाभ लेने पर ही सम्भव होता है।
5. व्यापार पर टैरिफ तथा गैर-टैरिफ बाधाओं जैसे कोटा लाइसेंस से सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है। किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि इन उपायों का मुख्य उद्देश्य सरकारी राजस्व में वृद्धि करना नहीं होता।
6. इन बाधाओं से जब घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है तब घरेलू क्षेत्र में श्रमिकों के लिए रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होते हैं और बेरोजगारी की समस्या से निजात मिलता है।

8.6 अभ्यास हेतु प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. किन्हीं चार गैर-टैरिफ बाधाएं बताएं।
2. टैरिफ-अभ्यंश से क्या समझते हैं?
3. मिश्रित कोटा क्या है?
4. गैर-टैरिफ व्यापार बाधाएं किसी देश के आर्थिक विकास में किस प्रकार मदद करती हैं?
5. विकासशील देशों का व्यापार-संतुलन प्रतिकूल होने के पीछे प्रेबिश-सिंगर ने क्या तर्क दिया?

सत्य/असत्य का चुनाव करें

1. राज्य-व्यापार गैर-टैरिफ व्यापार बाधा की श्रेणी में आता है।
2. आयात-अभ्यंश आयात को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है।
3. गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं का मुक्त व्यापार पर प्रभाव नहीं पड़ता है।
4. जहाँ प्रशुल्क आयात को कम करने में विफल होता है, वहाँ आयात-अभ्यंश अधिक प्रभावशाली होता है।
5. प्रेबिश-सिंगर के अनुसार विकासशील देश प्राथमिक वस्तुओं के आयातक होते हैं।

6. गैर-टैरिफ व्यापार बाधाएं आयात-प्रतिस्थापन उद्योग को प्रोत्साहित करते हैं।
7. कोटा लाइसेंस से देश के राजस्व में वृद्धि होती है।

बहुविकल्पी प्रश्न

1. निम्नलिखित गैर-टैरिफ व्यापार बाधा है

A) आयात अभ्यंश	B) निर्यात सब्सिडी
C) राज्य व्यापार	D) सभी.
2. आयात कोटा का मूल्य पर प्रभाव होता है

A) प्रत्यक्ष	B) अप्रत्यक्ष
C) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों	D) कोई प्रभाव नहीं पड़ता
3. आयात कोटा का आयात मात्रा पर प्रभाव होता है

A) प्रत्यक्ष	B) अप्रत्यक्ष
C) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों	D) कोई प्रभाव नहीं पड़ता
4. प्रशुल्क का मूल्य पर प्रभाव होता है

A) प्रत्यक्ष	B) अप्रत्यक्ष
C) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों	D) कोई प्रभाव नहीं पड़ता
5. प्रशुल्क का आयात मात्रा पर प्रभाव होता है

A) प्रत्यक्ष	B) अप्रत्यक्ष
C) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों	D) कोई प्रभाव नहीं पड़ता

8.7 सारांश

इस प्रकार हमने देखा कि जब स्वतंत्र बाजार की शक्तियां देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे में वांछित परिणाम लाने में असफल हो जाती हैं तो सरकार विभिन्न प्रकार की प्रतिबंधात्मक और निर्देशात्मक उपायों को अपनाती है। सरकार की सबसे बड़ी चिंता आयात को कम करने तथा निर्यात बढ़ाने की होती है जिससे भुगतान संतुलन की स्थिति अनुकूल हो सके। आयात कम करने के लिए सरकार प्रशुल्क यानि टैरिफ और निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहनों जैसे उपायों को अपनाती है। किन्तु आयात कम करने में प्रशुल्क की भी अपनी सीमा है। इसलिए सरकार को कुछ गैर-प्रशुल्क उपायों का सहारा लेना पड़ता।

गैर टैरिफ बाधाओं के अंतर्गत मात्रात्मक व्यापार प्रतिबंध, राजकोषीय उपाय, प्रशासनिक, प्रमाणिक तथा विनियमन जैसे उपायों की चर्चा हमने की। इन उपायों में आयात अभ्यंश, निर्यात सब्सिडी, स्वैक्षिक निर्यात रुकावटें, जटिल आयात लाइसेंसिंग प्रक्रिया आदि बहुत प्रचलित हैं। इसके अलावा कुछ गैर-आर्थिक बाधाएं भी प्रयोग में लाई जाती हैं जैसे स्वास्थ्य व सुरक्षा सम्बन्धी मानक, पर्यावरण व पैकेजिंग सम्बन्धी मानक आदि। अन्य गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं में द्विपक्षीय व्यापार समझौते, राशिपातन, अंतर्राष्ट्रीय वस्तु समझौते, अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल, आदि आते हैं।

इस इकाई में हमने किसी देश विशेषकर विकासशील देश के आर्थिक विकास में गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। इन उपायों से घरेलू देश के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है, देश का भुगतान संतुलन सुधारने में मदद मिलती है और विदेशी मुद्रा की समस्या से देश को निजात मिलता है। घरेलू उद्योगों के प्रोत्साहन से देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। किन्तु कहना न होगा कि अत्यधिक व्यापार

प्रतिबन्ध कभी-कभी देश के लिए नुकसानदेह भी होता है। इस प्रकार के प्रतिबन्ध तभी तक लगाने चाहिए जबतक देश के उद्योग अपने पैरों पर खड़े न हो जाय और विदेशी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में न हो जाए। बाद में इन प्रतिबंधात्मक उपायों को धीरे-धीरे हटा लेनी चाहिए और देश के उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों से जूझने का अवसर देना चाहिए।

8.8 शब्दावली

- **प्रशुल्क (Tariffs)** - संरक्षण प्रदान करने की यह सबसे प्रचलित विधि है। आयात अथवा निर्यात पर लगाने वाले कर को प्रशुल्क कहते हैं। आम तौर पर आयात पर ही कर लगाने की परम्परा रही है जिसके कारण जब भी प्रशुल्क की चर्चा होती है तब इसका अर्थ आयात-कर से ही लिया जाता है। आयातित होने वाले वस्तु पर जब कर लगाया जाता है तब उसका मूल्य घरेलू बाजार में बढ़ जाता है जिसके कारण देश में निर्मित वही वस्तु अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाती है।
- **अभ्यंश(कोटा) एवं लाइसेंस(Quota and Licences)** - अभ्यंश अथवा कोटा के अंतर्गत सरकार आयातित वस्तु की अधिकतम मात्रा अथवा अधिकतम मूल्य निर्धारित करती है। इसके कारण घरेलू उद्योगों के लिए निश्चिन्ता हो जाती है कि उसे सीमित विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। लाइसेन्सिंग प्रणाली के अंतर्गत सरकार सौच-समझकर और घरेलू उद्योगों का हित देखकर आयात का लाइसेंस प्रदान करती है।
- **अनुदान (Subsidies)** - अनुदान भी घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की विधि है। अनुदान के अंतर्गत घरेलू उद्योग के उत्पाद को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार उसके उत्पादन लागत का कुछ भाग सरकार स्वयं वहन करती है। कभी-कभी निर्यात बोनस, निर्यात पुरस्कार, निर्यात करों में छूट के द्वारा भी सरकार घरेलू निर्यातकों को संरक्षण प्रदान करती है। इन सब विधियों से वस्तुओं के मूल्यों को कृत्रिम रूप से कम करके निर्यातों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके कारण विदेशी वस्तुओं को घरेलू बाजार में संघर्ष करना पड़ता है।
- **राज्य व्यापार (State Trading)** - राज्य व्यापार संरक्षण प्रदान करने की प्रत्यक्ष विधि है। विशेषकर समाजवादी देशों में राज्य व्यापार के माध्यम से घरेलू उद्योग के उत्पाद को विश्व बाजार में बेचने की जिम्मेवारी सरकार अपने ऊपर लेती है। इसके लिए सरकार ट्रेडिंग एजेंसियां निर्मित करके विदेश व्यापार करती है। इससे विदेशी वस्तु को घरेलू बाजार में अपना स्थान बनाने में बाधा उत्पन्न होती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय संघ (International Cartel)** - कई देश आपस में मिलकर संघ बना लेते हैं जिसका उद्देश्य अपने उत्पाद का विश्व बाजार में अधिक मूल्य सुनिश्चित करना होता है। ऐसे संघ को कार्टेल कहा जाता है। उदाहरणस्वरूप तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक (OPEC) एक प्रकार का कार्टेल है जिसका उद्देश्य विश्व बाजार में तेल का अधिक मूल्य प्राप्त करना है। इससे घरेलू तेल उत्पादक कम्पनियों को संरक्षण प्राप्त होता है।
- **स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें (Voluntary Export Restraints - VERs)** - स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें(VER) एक ऐसा समझौता है जो निर्यातक देश के निर्यातकों अथवा सरकार द्वारा आयातक देश के साथ उसके निर्यातों को सीमित करने के लिए किया जाता है।

8.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

सत्य/असत्य का चुनाव करें

1. सत्य 2. सत्य 3. असत्य 4. सत्य 5. असत्य.
6. सत्य 7. सत्य

बहुविकल्पी प्रश्न

1. D) सभी 2.B) अप्रत्यक्ष 3. A) प्रत्यक्ष 4. A) प्रत्यक्ष 5.B) अप्रत्यक्ष अभ्यास हेतु प्रश्न 2

8.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- Bo Sodersten, International Economics ,Macmillan, 1999
- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006
- H. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: *International Economics: Theory and Policy*, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- एस. एन. लाल , अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र , शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहबाद, 2004
- एच. एस. अग्रवाल, तथा सी. एस. बरला, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2003.
- सुदामा सिंह एवं एम. सी. वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड एंड आई. बी. एच. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम. एल. झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010.
- डॉ. जी. सी. सिंघई एवं डॉ. जे. पी. मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा, 2010.

8.11 उपयोगी/सहायक पाठ्य सामग्री

- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006
- H. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: *International Economics: Theory and Policy*, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- एस. एन. लाल , अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र , शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहबाद, 2004
- एच. एस. अग्रवाल, तथा सी. एस. बरला, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2003.
- सुदामा सिंह एवं एम. सी. वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड एंड आई. बी. एच. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007

- एम. एल. झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010।
- ज्ञानेंद्र सिंह कुशवाहा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1979।

8.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं से क्या अभिप्राय है? गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
2. किसी देश के आर्थिक विकास में गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं के महत्व तथा इसकी सीमाओं पर प्रकाश डालें।

इकाई 9 - राशिपातन और राज्य व्यापार (Dumping and State Trading)

- 9.1 प्रस्तावना
- 9.2 उद्देश्य
- 9.3 राशिपातन
 - 9.3.1 राशिपातन का अर्थ
 - 9.3.2 राशिपातन के उद्देश्य
 - 9.3.3: राशिपातन के लिए आवश्यक शर्तें
 - 9.3.4: राशिपातन नियंत्रण उपाय (Anti-dumping Measures)
- 9.4. राज्य व्यापार
 - 9.4.1 राज्य व्यापार का अर्थ एवं इसका उद्देश्य
 - 9.4.2 राज्य व्यापार के उदय के कारण
 - 9.4.3 राज्य व्यापार की विधियाँ
- 9.5: राज्य व्यापार के लाभ एवं दोष
 - 9.5.1 राज्य व्यापार के लाभ
 - 9.5.2 राज्य व्यापार के दोष
- 9.6 अभ्यास हेतु प्रश्न
- 9.7 सारांश
- 9.8 शब्दावली
- 9.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 9.10 सन्दर्भ ग्रंथ सूची
- 9.11 उपयोगी/सहायक पाठ्य सामग्री
- 9.12 निबंधात्मक प्रश्न

9.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई में राशिपातन का अर्थ इसके उद्देश्य व राशिपातन के विभिन्न तरीकों के बारे में बताया गया है। साथ ही इस इकाई में राज्य व्यापार का अर्थ, इसका उद्देश्य, इसके गुण-दोष आदि के बारे में भी चर्चा की गई है।

9.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- ✓ राशिपातन के अर्थ को समझ सकेंगे।
- ✓ राशिपातन के उद्देश्य को जान पाएंगे।
- ✓ राशिपातन की आवश्यक शर्तों से अवगत होंगे। - राज्य व्यापार के अर्थ को समझ पाएंगे।
- ✓ राज्य व्यापार के उद्देश्य को जान सकेंगे।
- ✓ राज्य व्यापार के लाभ और हानि से अवगत होंगे।

9.3 राशिपातन

9.3.1 राशिपातन का अर्थ

राशिपातन (Dumping) एक प्रकार का मूल्य विभेदीकरण है जहाँ किसी उत्पाद के लिए घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अलग-अलग मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। **जैकब वाइनर (Jacob Viner)** के शब्दों में **“राशिपातन दो बाजारों में मूल्य विभेद है (Dumping is price discrimination between two markets)। एल्सवर्थ (P.T. Ellsworth)** के अनुसार राशिपातन विदेशी बाजार में वस्तु की उत्पादन लागत से कम मूल्य पर बेचने की क्रिया मात्र नहीं है। उनके अनुसार, **“यातायात व्ययों, करों, एवं अन्य सभी हस्तान्तरण लागतों के समायोजन के पश्चात् विदेशी बाजार में वस्तु को देशी बाजार में प्राप्त होनेवाले मूल्य से कम पर बेचने को राशिपातन कहते हैं” (It means, sales in a foreign market at a price below that received in home market, after allowing transportation charges and all other costs of transfer)।**

अतः, राशिपातन के अंतर्गत विदेशी बाजार में वस्तु का मूल्य घरेलू बाजार की तुलना में कम करके रखा जाता है। राशिपातन का सहारा लेने वाले उत्पादक को घरेलू बाजार में कुछ हद तक एकाधिकारी शक्ति प्राप्त होती है जहाँ वह अपने उत्पाद का मूल्य प्रतियोगी मूल्य की अपेक्षा अधिक रखने में सफल हो जाता है। किन्तु उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है जिसके कारण उसे अपने उत्पाद का प्रतिस्पर्धी मूल्य रखना पड़ता है जो घरेलू बाजार के मूल्य की तुलना में कम होता है। राशिपातन के अंतर्गत प्रायः उत्पाद का मूल्य विदेशी बाजार में घरेलू बाजार से भी कम रखा जाता है। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि वस्तु का मूल्य विदेशी बाजार में उसकी लागत से भी कम रखा जाता है। जब घरेलू बाजार में वस्तु की मांग कम होती है तब विदेशी बाजार में राशिपातन का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा, राशिपातन का उद्देश्य विदेशी बाजार में अपनी वस्तु को स्थापित करना अथवा प्रतिस्पर्धी वस्तु को बाजार से बाहर करना भी होता है। कभी-कभी तो राशिपातन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गला-काट प्रतियोगिता (cut-throat competition) को जन्म देता है। इसलिए राशिपातन द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में तनाव भी उत्पन्न करता है।

9.3.2 राशिपातन के उद्देश्य

राशिपातन के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं:

1. राशिपातन संरक्षणवादी उपाय के अंतर्गत भी आता है। देश के किसी उद्योग-विशेष के उत्पाद को निर्यातोन्मुख बनाने के लिए सरकार निर्यात-सब्सिडी देकर उसके मूल्य को विदेशी बाज़ार में कृत्रिम रूप से कम रखने में मदद करती है। ऐसा होने से वस्तु विदेशी बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बन जाता है जिससे उस उद्योग को फायदा होता ही है, साथ में देश को विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी मदद मिलती है।
2. जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में किसी देश का प्रबल प्रतिस्पर्धी उपस्थित हो जाता है तब ऐसी स्थिति में बाज़ार में अपने उत्पाद की स्थिति मजबूत करने के लिए राशिपातन का प्रयोग किया जाता है। ऐसा भी होता है कि एक शक्तिशाली उत्पादक छोटे-मोटे उत्पादकों को बाज़ार से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए राशिपातन का प्रयोग करे। ऐसी स्थिति को गला काट (Cut-throat competition) प्रतियोगिता कहते हैं।
3. कभी-कभी कई कम्पनियाँ मिलकर कार्टेल (cartel) का निर्माण कर लेती हैं और फिर ये कम्पनियाँ अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपने उत्पाद का ऊंचा मूल्य प्राप्त करने में सफल हो जाती हैं। यह भी के प्रकार का राशिपातन ही है।
4. कभी-कभी विक्री-मौसम के अंत में घरेलू बाज़ार में वस्तु की विक्री बंद हो जाती है या कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में इसे विदेशी बाज़ार में कम मूल्य पर (at throw away prices) बेचने की योजना बनाई जाती है। यह भी राशिपातन की श्रेणी में आता है।

9.3.3 राशिपातन के लिए आवश्यक शर्तें

हैबरलर ने राशिपातन के लिए दो आवश्यक शर्तों का उल्लेख किया है।

पहला, जिस वस्तु पर राशिपातन किया गया हो उसे फिर से देश के बाज़ार में बेचने से रोका जाय। यदि नहीं रोका गया तो वही वस्तु फिर घरेलू बाज़ार में कुछ अधिक मूल्य पर आ जायेगी और घरेलू उपभोक्ता उसे खरीदना पसंद करेंगे।

दूसरी शर्त यह कि घरेलू बाज़ार में उत्पादक को एकाधिकार प्राप्त हो जहाँ वह अधिक मूल्य वसूल सके। प्रतियोगिता की स्थिति में उत्पाद का घरेलू मूल्य कम हो जाता है और फिर घरेलू और विदेशी बाजारों के मूल्य में अंतर समाप्त हो सकता है। ऐसी स्थिति में राशिपातन नहीं हो पायेगा, क्योंकि विदेशी बाजार में कम मूल्य पर उत्पाद को बेचने से जो क्षति होगी उसकी भरपाई घरेलू बाज़ार नहीं कर पायेगा।

9.3.4 राशिपातन नियंत्रण उपाय (Anti-dumping Measures)

जिस देश में राशिपातन किया जाता है, उसे आर्थिक क्षति होने की संभावना रहती है क्योंकि उसके घरेलू उद्योग के लिए समस्या खाड़ी हो जाती है। कुछ वर्ष पूर्व जापान ने अमेरिकी बाज़ार में अपने कार काफ़ी कम मूल्य पर उतारे जिसके कारण अमेरिकी कार उद्योग में हड़कंप मच गया और डेट्रॉइट की कार निर्माता कम्पनियों को अमेरिकी सरकार के समक्ष गुहार लगानी पड़ी थी। इसलिए अब हमें राशिपातन से निपटने के उपाय पर भी विचार करनी चाहिए, जो निम्नलिखित हो सकते हैं:

1. **आयात कर लगाना** - राशिपातन से बचाने का यह सामान्य तरीका है। इसके घरेलू कीमत और राशिपातन की जानेवाली वस्तुओं की कीमतों में जो अंतर बैठता है, उसके बराबर आयात शुल्क लगा दिया जाता है।

2. **अभ्यंश लगाना** - राशिपातन का सामना करने के लिए वस्तु के आयात का कोटा या विनिमय नियंत्रण के माध्यम से आयातों की मात्रा को नियंत्रित कर दिया जाता है। राशिपातन को रोकने के लिए आयात शुल्क की तुलना में मात्रात्मक प्रतिबन्ध या अभ्यंश अधिक प्रभावशाली सिद्ध होते हैं।
3. **राशिपातन वाले देश से समझौता** - यह एक बीच-बचाओ वाला उपाय है जिसमें राशिपातन करनेवाले देश और उससे प्रभावित देश आपस में मिल-बैठकर समस्या का निदान खोजते हैं और कोई बीच का रास्ता ढूँढते हैं।

9.4. राज्य व्यापार

9.4.1 राज्य व्यापार का अर्थ एवं इसका उद्देश्य

राज्य व्यापार का तात्पर्य विदेशी व्यापार में सरकार का हस्तक्षेप से है। आयात और निर्यात से सम्बंधित समस्त निर्णय सरकार खुद करती है अथवा उसमें हस्तक्षेप करती है। राज्य व्यापार उस अवस्था को कहते हैं जहाँ वस्तुओं के आयात व निर्यात सरकार द्वारा नियंत्रित या सरकारी संस्था द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सरकार के हस्तक्षेप को राज्य व्यापार कहते हैं। राज्य व्यापार का इतिहास बहुत पुराना है। वणिकवादी विचारधारा के समर्थक इसे यूरोप में सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर एडम स्मिथ के आगमन तक, यानि अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करते थे। बीसवीं शताब्दी में, रूस में साम्यवाद के उदय से राज्य व्यापार का महत्व बढ़ा। तीस के दसक के मंदी से निपटने के लिए विश्व में राज्य व्यापार को महत्व को स्वीकार किया गया और पूंजीवादी देशों ने भी इससे परहेज नहीं किया। राज्य व्यापार के कई रूप हो सकते हैं। यह सरकारी एजेंसी का रूप लेकर किसी एकाधिकारी निजी फर्म की तरह कार्य कर सकता है, अथवा सरकार का कोई मंत्रालय देश के समस्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित कर सकता है जैसा कि साम्यवादी देशों में देखने को मिलता है। आगे हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।

9.4.2 राज्य व्यापार के उदय के कारण

राज्य व्यापार के उदय के निम्नलिखित कारण हैं

1. **समाजवाद/साम्यवाद का उदय** - विश्व में समाजवाद के उदय से आर्थिक क्रिया-कलापों में राज्य की भूमिका बहुत बढ़ गई। चूँकि समाजवाद में उत्पादन और वितरण के अधिकार सरकार के हाथ में आ जाते हैं अतः स्वाभाविक है कि व्यापार में भी राज्य की भूमिका बढ़ जाती है। यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पूंजीवादी देशों ने भी पूंजीवाद के दोषों को नियंत्रित करने के लिए राज्य व्यापार को अपनाया। आजकल विकासशील देशों में भी समाजवादी लक्ष्यों को ध्यान में रखकर राज्य व्यापार को अपनाया जाता है।
2. **आर्थिक नियोजन का प्रारंभ** - विश्व के कई देशों ने सुनियोजित आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाया, जिसके कारण आर्थिक क्षेत्र में राज्य की भूमिका बढ़ी। खासकर विकासशील देशों में जहाँ आर्थिक क्रियाओं के संचालन में बाजार की शक्ति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता वहाँ राज्य व्यापार का महत्व बढ़ा और सरकारें आयात और निर्यात को निर्देशित करने लगी।
3. **विदेशी मुद्रा की समस्या** - भारत जैसे विकासशील देश प्रायः विदेशी मुद्रा के संकट से जूझते रहें हैं। ऐसी स्थिति में आयात-निर्यात को नियंत्रित करने की जिम्मेवारी सरकारों के लिए बढ़ गई। आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। सरकारें सभी वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा नहीं निर्गत करती। ये अलग बात है कि उदारीकरण और भूमंडलीकरण के इस दौर में सरकारों की भूमिका अब घटने लगी है।

4. **राजनीतिक उद्देश्य** - राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी सरकारें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी भागीदारी बढ़ाती हैं, जिसके कारण व्यापार की मात्रा, संरचना, एवं दिशा को निर्धारित करने के लिए राज्य व्यापार को प्रोत्साहन मिला।

9.4.3 राज्य व्यापार की विधियाँ

राज्य व्यापार की निम्नलिखित विधियाँ हैं:

1. विदेशों में वस्तुओं की खरीद-विक्री राज्य स्वयं करे।
2. विदेशों में वस्तुओं की खरीद-विक्री के लिए राज्य स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना करे।
3. निजी व्यापार कम्पनियों को सरकार आयात अथवा निर्यात करने के लिए लाइसेंस जारी करे और फिर इनके क्रिया-कलापों पर नज़र रखे।

राज्य व्यापार देश की आर्थिक नीति पर निर्भर करती है। कोई आवश्यक नहीं कि राज्य सभी वस्तुओं के आयात व निर्यात अपने हाथ में ले ले। प्रायः ऐसा देखा गया है कि राज्य कुछ विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं के आयात-निर्यात को अपने हाथ में लेती है। हाँ इतना जरूर है कि समाजवादी देशों में राज्य व्यापार अधिक होता है।

9.5 राज्य व्यापार के लाभ एवं दोष

9.5.1 राज्य व्यापार के लाभ

राज्य व्यापार राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। निजी व्यापार कम्पनियों का उद्देश्य लाभ कमाना होता जिसके कारण निजी उद्देश्य राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते।

1. **लागत में कमी** - राज्य एक बड़ा खरीददार या विक्रेता बनता है तो एक-मुश्त खरीद-विक्री का लाभ जो प्राप्त होता है वह राज्य को मिलता है। परिवहन लागत में कमी होती है जिसका लाभ उपभोक्ताओं को प्रदान किया जा सकता है। राज्य के लिए यह भी संभव है कि वह बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदने व बेचने के लिए अन्य देशों से द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर ले। ऐसी स्थिति में आयात के लिए वित्त जुटाने की समस्या नहीं रहती।
2. **सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि** - राज्य एक बड़ी ताकत है और जब उसे आयात या निर्यात करने की एकाधिकारी शक्ति प्राप्त होती है तब उसकी सौदेबाजी की शक्ति भी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में राज्य अपनी शर्तों पर आयात या निर्यात कर सकता है।
3. **नए बाज़ार की खोज** - नए बाज़ार की खोज के लिए निजी व्यापार कंपनियों की अपेक्षा सरकार के पास अधिक साधन एवं विशेषज्ञों की सेवाएँ विद्यमान होती हैं। इसके लिए निवेश करने का सामर्थ्य निजी कंपनियों की तुलना में सरकार के पास अधिक होती है।
4. **व्यापार के अतिरिक्त अन्य आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन** - राज्य व्यापार के माध्यम से राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा करनेवाले अन्य नीतियों का संचालन किया जा सकता है। जैसे- नेशनल बैंकिंग, परिवहन, बीमा आदि का विस्तार इसी बहाने किया जा सकता है। भारत जैसे देश में लघु उद्योगों जैसे कारपेट उद्योग, खादी उद्योग आदि को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने राज्य ट्रेडिंग कम्पनियाँ बना रखी है।
5. **भुगतान संतुलन में सुधार** - राज्य व्यापार भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार ला सकता है। जिस देश के साथ देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है, उससे आयात को रोका जा सकता है और उस देश को निर्यात बढ़ाने के उपाय किये जा सकते हैं।
6. **राज्य व्यापार से मूल्य विभेदीकरण संभव** - चूंकि राज्य की एजेंसी आयात करनेवाली एकमात्र संस्था होती है, वह आयातों के लिए ऊँचे मूल्य का भुगतान करके देश के उपभोक्ताओं को उससे कम मूल्य पर

वस्तु को उपलब्ध करा सकती है यदि इससे किसी राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति हो रही हो। यह भी संभव है कि राज्य आयातित वस्तु का देश के अलग-अलग उपभोक्ता समूहों के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारित करे।

7. **अन्य नियंत्रणों से बेहतर** - आयातों को नियंत्रित करने के लिए सरकार टैरिफ व कोटा जैसे उपाय करती है। किन्तु इनके अपने दोष हैं। राज्य व्यापार की संस्था कीमतों, उत्पाद की गुणवत्ता, व्यापार की शर्तों, आदि के आधार पर राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर खरीद कर सकती है।
8. **दुर्लभ किस्म की वस्तु के आयात व निर्यात का नियंत्रण** - दुर्लभ किस्म की वस्तुओं के आयातनिर्यात में कई तरह की कालाबाजारी होने की संभावना रहती है। राज्य एक शक्तिशाली संस्था है, इसलिए ऐसी वस्तुओं के आयात-निर्यात अपने हाथ में लेकर सरकार इस तरह की गतिविधि को नियंत्रित कर सकती है।
9. **घरेलू कीमतों में स्थायित्व** - राज्य व्यापार के माध्यम से घरेलू कीमतों में स्थायित्व लाया जा सकता है। कीमतों में उतार-चढ़ाव होने का प्रमुख कारण विदेशी व्यापार में सट्टेबाजी जैसी क्रियाएं हैं जिन्हें राज्य व्यापार के माध्यम से दूर किया जा सकता है।
10. **विदेशी व्यापार से सम्बंधित अन्य दोषों का निराकरण** - विदेशी व्यापार से सम्बंधित अन्य दोषों का निराकरण राज्य व्यापार के माध्यम से किया जाता है; जैसे निजी आयातकर्ताओं व निर्यातकर्ताओं द्वारा कर्तव्य की चोरी, विदेशी मुद्रा की कालाबाजारी आदि पर रोक इसके माध्यम से हो सकता है।

9.5.2 राज्य व्यापार के दोष

राज्य व्यापार मुक्त व्यापार के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। मुक्त व्यापार के समर्थक अर्थव्यवस्था में इस तरह के सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। इसलिए राज्य व्यापार के उपर्युक्त लाभों के बावजूद इसके विरुद्ध अनेक आपत्तियां उठाई गई हैं। ये निम्न हैं:

1. **एकाधिकार सम्बन्धी दोष** - व्यापार में प्रतियोगिता की स्थिति आदर्शतम मानी गई है। व्यापार में राज्याधिकार के कारण निजी प्रोत्साहनों को आघात लगता है। यदि व्यापार में स्वस्थ प्रतियोगिता रहे तथा उसे कुशलता से संचालित किया जाय तो विदेशी व्यापार निजी हाथों द्वारा अच्छी तरह संचालित किया जा सकता है।
2. **बहुपक्षीय व्यापार को क्षति** - राज्य व्यापार में, बहुपक्षीय व्यापार के स्थान पर, द्विपक्षीय व्यापार को समर्थन मिलाता है। एक देश प्रायः आयात करने के लिए उन्हीं देशों को प्राथमिकता देता है। जो उससे आयात करने के लिए तैयार रहते हैं। यदि स्वतंत्र प्रतियोगिता रहती है तो बहुपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलाता है।
3. **राजनीति से प्रभावित** - राज्य व्यापार शर्तें विशुद्ध आर्थिक न होकर राजनीतिक होती हैं। एक देश उस बाजार से उत्पाद नहीं खरीदता जहाँ वे सबसे सस्ती मिलाती हैं और न ही उन बाजारों में अपने उत्पाद को बेचता है जहाँ उसकी कीमत अधिकतम होती है। इन सबका निर्धारण राजनीतिक आधारों एवं पूर्वाग्रहों द्वारा होता है।
4. **व्यापार में अकुशलता** - राज्य व्यापार सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा संचालित होती है जहाँ लालफीताशाही और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है। इसके कारण व्यापार में अकुशलता उत्पन्न हो जाती है। कई अर्धविकसित देश इस समस्या के शिकार रहें हैं।

5. **व्यापार में कठिनाई** - यदि उत्पादन की प्रणाली निजी हाथों में हो तब राज्य व्यापार करना कठिन हो जाता है। क्योंकि तब समन्वय का अभाव रहता है। राज्य व्यापार घरेलू उत्पादन और वितरण पर सख्त नियंत्रण द्वारा ही संचालित हो सकता है।
6. **व्यापार के विशिष्ट ज्ञान का अभाव** - सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों में व्यापार करने के हुनर कम देखे गए हैं। उनके पास व्यापार का विशिष्ट ज्ञान नहीं होता जिसके कारण कम-से-कम प्रारम्भिक वर्षों में राज्य व्यापार करने में कई कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।
7. **निजी तथा व्यक्तिगत रूचि का अभाव** - किसी भी कार्य की सफलता के लिए यह आवश्यक है की उसमें व्यक्तिगत अभिरूचि हो, किन्तु राज्य व्यापार में ऐसा नहीं है। राज्य व्यापार के संस्थाओं के कर्मचारी इस कार्य में दिल से जुड़े नहीं होते, जिसके कारण उन्हें हानि की परवाह नहीं होती। इस कारण राज्य व्यापार की संस्थाओं का कार्य कुशलता से नहीं हो पाता।

9.6 अभ्यास हेतु प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. राशिपातन क्या है?
2. राशिपातन के क्या उद्देश्य हैं?
3. राशिपातन की कौन-कौन सी शर्तें हैं?
4. राज्य व्यापार से क्या समझते हैं?
5. राज्य व्यापार की कौन-कौन विधियाँ हैं?

सत्य/असत्य का चुनाव करें

1. राशिपातन संरक्षण का उपाय है।
2. राशिपातन एक प्रकार का मूल्य विभेदीकरण है।
3. राशिपातन के अंतर्गत घरेलू बाजार में उत्पाद का मूल्य विदेशी बाजार से अधिक होता है।
4. राशिपातन गला-काट प्रतियोगिता को जन्म दे सकता है।
5. राज्य व्यापार संरक्षण उपाय है।
6. राज्य व्यापार मुक्त व्यापार के सिद्धांत पर आधारित है।
7. एडम स्मिथ राज्य व्यापार के समर्थक थे।
8. भूमंडलीकरण के दौर में राज्य व्यापार का महत्व बढ़ा है।

बहुविकल्पी प्रश्न

1. निम्नलिखित राशिपातन नियंत्रण उपाय है
 - i) आयात कर ii) कोटा iii) दोनों iv) इनमें से कोई नहीं
2. राशिपातन संभव होता है
 - i) आयात कर से ii) निर्यात सब्सिडी से iii) आयात कोटा से iv) निर्यात कर से
3. राज्य व्यापार से बल मिलता है
 - i) बहुपक्षीय व्यापार को ii) द्विपक्षीय व्यापार को iii) एकपक्षीय व्यापार को iv) उपर्युक्त सभी को

4. राज्य व्यापार किन देशों में अधिक प्रचलित है
 - i) पूंजीवादी देशों में ii) समाजवादी देशों में iii) दोनों में
5. राज्य व्यापार के अंतर्गत होता है
 - i) राज्य स्वयं खरीद-विक्री करता है
 - ii) खरीद-विक्री के लिए राज्य स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना करता है
 - iii) निजी व्यापार कम्पनिओं को राज्य आयात-निर्यात का लाइसेंस जारी करता है
 - iv) उपर्युक्त सभी

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें

1. राशिपातन में घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु का मूल्यहोता है
(एक ही/अलग-अलग)
2. निर्यात सब्सिडी देने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश के उत्पाद का मूल्यहै।
(बढ़ता/घटता)
3. राशिपातन की स्थिति में देश के उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में का सामना करना पड़ता है।
(प्रतिस्पर्धा/एकाधिकार)
4. राज्य व्यापार मुक्त व्यापार के सिद्धांत केमें है।
(पक्ष/विपक्ष)
5. राज्य व्यापार देशों में प्रचलित है।
(पूंजीवादी/समाजवादी)
6. राज्य व्यापारकी नीति है।
(मुक्त व्यापार संरक्षणवाद)

9.7 सारांश

इस इकाई में हमने राशिपातन व राज्य व्यापार पर विचार किया। दोनों ही संरक्षण की विधियाँ हैं। दोनों ही स्थितिओं में सरकार का सहयोग घरेलू उत्पादकों को मिलता है। राशिपातन की स्थिति में वस्तु का मूल्य घरेलू बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में कम होता है जिसके पीछे सरकार का भी सहयोग रहता है। सरकार उत्पाद पर सब्सिडी देकर उसके मूल्य को विदेशी बाजार में कृत्रिम रूप से कम रखने में मदद करती है। यह अलग बात है कि कभी-कभी निर्यातक भी भविष्य की संभावना के मद्देनजर अपने उत्पाद का मूल्य विदेशी बाजार में कुछ समय के लिए कम रख सकता है। राज्य व्यापार तो सरकार समस्त विदेशी व्यापार गतिविधियों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने नियंत्रण में रखती है।

राज्य व्यापार का उदय विश्व में समाजवाद के उदय तथा आर्थिक नियोजन के प्रारम्भ के कारण हुआ। विश्व में राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी राज्य व्यापार की भूमिका बढ़ी। राज्य व्यापार के अपने फायदे और नुकसान हैं। अपने राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य व्यापार को अपनाया जाता है। सरकार व्यापारिक एजेंसियां बनाकर अथवा निजी व्यापारियों को लाइसेंस देकर विदेश व्यापार को अपने नियंत्रण में रखती है। राज्य एक बड़ी ताकत होती है इसलिए वह उन क्षेत्रों में भी व्यापारिक गतिविधियां चला सकता है। जहाँ निजी क्षेत्र साहस नहीं दिखा पाते राज्य एक मुश्त खरीददार होने के कारण उसके मोल-भाव करने की ताकत अधिक होती है और वह सस्ते मूल्य पर वस्तुओं का आयात कर सकता है किन्तु राज्य व्यापार के कुछ सीमाएं भी हैं। यह मुक्त

व्यापार के सिद्धांत के विपरीत है जिसके कारण मुक्त व्यापार के कई फायदे से देश वंचित होता है। निजी और व्यक्तिगत हित सम्मिलित नहीं होने और व्यापार सम्बन्धी विशिष्ट ज्ञान के अभाव के कारण राज्य व्यापार में अकुशलता उत्पन्न होती है। इसके अलावा व्यापार में लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार भी व्याप्त होने की संभावना रहती है।

9.8 शब्दावली

- **राशिपातन** - यह एक प्रकार का मूल्य विभेदीकरण है जिसमें विदेशी बाजार में वस्तु का मूल्य घरेलू बाजार की तुलना में कम रखा जाता है।
- **राज्य व्यापार** - जब राज्य विदेशी व्यापार में सीधा हस्तक्षेप करता है और अपने देश की आर्थिक नीतियों को ध्यान में रखकर संचालित करता है तब ऐसी स्थिति को राज्य व्यापार कहते हैं।
- **प्रशुल्क** - आयात अथवा निर्यात पर लगने वाले कर को प्रशुल्क कहते हैं। वैसे आम तौर पर प्रशुल्क का तात्पर्य आयात पर लगनेवाले कर से है।
- **सब्सिडी** - लागत का वह भाग जो सरकार वहन करती है और जिसके फलस्वरूप वस्तु का मूल्य कृत्रिम रूप से कम हो जाता है, सब्सिडी कहलाता है।
- **भुगतान संतुलन** - विदेशी व्यापार का लेखा-जोखा जिसमें देश की समस्त देनदारी व प्राप्ति का उल्लेख होता है, भुगतान संतुलन कहलाता है।
- **मूल्य विभेदीकरण** - जब एक ही उत्पाद का अलग-अलग क्रेताओं से अलग-अलग मूल्य वसूला जाता है तब ऐसी स्थिति को मूल्य विभेदीकरण कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राशिपातन (Dumping) एक प्रकार का मूल्य विभेदीकरण कहते हैं।

9.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

सत्य/असत्य का चुनाव करें।

- | | | | | |
|----------|----------|----------|---------|---------|
| 1. सत्य | 2. सत्य | 3. सत्य | 4. सत्य | 5. सत्य |
| 6. असत्य | 7. असत्य | 8. असत्य | | |

बहुविकल्पी प्रश्न

- | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| 1. iii) | 2. ii) | 3. ii) | 4. ii) | 5. v) |
|---------|--------|--------|--------|-------|

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. अलग-अलग होता है। | 2. उत्पाद का मूल्य घटता है। |
| 3. प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। | 4. विपक्ष में है। |
| 5. समाजवादी देशों में प्रचलित है। | 6. संरक्षणवाद की नीति है। |

9.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- Bo Sodersten, International Economics, Macmillan, 1999

- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006
- H. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: *International Economics: Theory and Policy*, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- एस. एन. लाल , अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र , शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहबाद, 2004
- एच. एस. अग्रवाल, तथा सी. एस. बरला, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2003.
- सुदामा सिंह एवं एम. सी. वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड एंड आई. बी. एच. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम. एल. झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010.
- डॉ. जी. सी. सिंघई एवं डॉ. जे. पी. मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा, 2010.

9.11 उपयोगी/सहायक पाठ्य सामग्री

- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006
- H. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: *International Economics: Theory and Policy*, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- एस. एन. लाल , अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र , शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहबाद, 2004
- एच. एस. अग्रवाल, तथा सी. एस. बरला, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2003.
- सुदामा सिंह एवं एम. सी. वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड एंड आई. बी. एच. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम. एल. झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010।
- ज्ञानेंद्र सिंह कुशवाहा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1979।

9.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. राशिपातन से क्या समझते हैं? इसके उद्देश्यों को रेखांकित करें व इसके आवश्यक शर्तों को बताएं।
2. राज्य व्यापार से क्या समझते हैं? राज्य व्यापार के लाभ व इसकी सीमाओं को रेखांकित करें।

इकाई 10 - सीमा संघ के सिद्धान्त (Theory of Customs Union)

- 10.1 प्रस्तावना
- 10.2 उद्देश्य
- 10.3 सीमा संघ का अर्थ
- 10.4 व्यापार सृजन और व्यापार दिशा-परिवर्तन
- 10.5 सीमा संघ का आंशिक व सामान्य संतुलन विश्लेषण
 - 10.5.1 सीमा संघ का आंशिक संतुलन विश्लेषण
 - 10.5.2 सीमा संघ का सामान्य संतुलन विश्लेषण
- 10.6 अभ्यास हेतु प्रश्न
- 10.7 सारांश
- 10.8 शब्दावली
- 10.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 10.10 सन्दर्भ ग्रंथ सूची
- 10.11 उपयोगी/सहायक पाठ्य सामग्री
- 10.12 निबंधात्मक प्रश्न

10.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई में सीमा संघ का अर्थ एवं महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही सीमा संघ के सिद्धान्त से सम्बंधित आंशिक व सामान्य संतुलन दृष्टिकोण प्रस्तुत किये गए हैं।

10.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- ✓ सीमा संघ के अर्थ को समझ सकेंगे।
- ✓ सीमा संघ से सम्बंधित जैकब वाइनर के व्यापार सृजन (Trade Creation) व व्यापार दिशा-परिवर्तन (Trade Diversion) जैसी अवधारणाओं से परिचित होंगे।
- ✓ सीमा संघ के आंशिक संतुलन विश्लेषण से आप परिचित होंगे।
- ✓ सीमा संघ से सम्बंधित लिप्से (R. G. Lipse) व वानेक (Jaroslav Vanek) के सामान्य संतुलन मॉडल से आप परिचित होंगे।

10.3 सीमा संघ का अर्थ

मुक्त व्यापार के समर्थक मुक्त व्यापार को आदर्शतम स्थिति मानते हैं। उनका तर्क है कि इससे साधनों का ईष्टतम आवंटन व वस्तुओं तथा सेवाओं का अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु मुक्त व्यापार अपने आप में वास्तविकता से बहुत दूर है। वास्तविकता तो यह है कि विभिन्न देश अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संरक्षणवादी नीति अपनाते रहें हैं और कई प्रकार के अवरोध खड़े करते रहे हैं जिनमें टैरिफ व गैर टैरिफ बाधाएं हैं जिनकी चर्चा पूर्व में की गई है। सीमा संघ का सिद्धान्त मुक्त व्यापार व संरक्षण के बीच की अवस्था है। इसे **द्वितीय श्रेष्ठ का सिद्धान्त (Theory of the Second Best)** भी कहते हैं। सीमा संघ के अंतर्गत दो या दो से अधिक देश एक संगठन बनाते हैं, जिसके सदस्य आपस में सीमा शुल्क (टैरिफ) को समाप्त कर देते हैं और संगठन के बाहर के देशों से आनेवाली वस्तुओं पर साझा शुल्क (common tariff) लगाते हैं। इस प्रकार के संगठन का उद्देश्य सदस्य देशों में कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना होता है।

अतः सीमा संघ सदस्य देशों के बीच एक प्रकार का आर्थिक एकीकरण है। इसी प्रकार के कुछ अन्य आर्थिक एकीकरण के संगठन भी हैं जो यहाँ दिए गए हैं:

प्रेफरेंसियल व्यापार संगठन (Preferential Trading Union): इसमें दो या दो से अधिक देश संगठन बना कर संघ के देशों के लिए आयात शुल्क को कम कर देते हैं। सदस्य देश संगठन के बाहर के देशों से आनेवाली वस्तुओं पर अपने-अपने आयात शुल्क निर्धारित करते हैं। राष्ट्रमंडल(Commonwealth) को इसी श्रेणी का संगठन माना जाता है।

मुक्त व्यापार संगठन (Free Trade Union/Association): इसमें संगठन के देश आपस में समस्त आयात शुल्क को समाप्त कर देते हैं और संगठन के बाहर से आनेवाले वस्तुओं पर सदस्य देश अपना-अपना शुल्क निर्धारित करते हैं।

साझा बाज़ार (Common Market): इस प्रकार के संगठन में सदस्य देश आपस में समस्त व्यापार शुल्क को समाप्त कर देते हैं और साथ ही उत्पादन के साधनों के मुक्त आवाजाही की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यूरोपीय साझा बाज़ार (European Common Market) इसका उदाहरण है।

आर्थिक संगठन (Economic Union): यह सर्वोच्च श्रेणी का आर्थिक एकीकरण है। इसमें साझा बाजार की विशेषताओं के अतिरिक्त वित्तीय, मौद्रिक, विनिमय-दर, आर्थिक नीतियों आदि में भी समानता लाई जाती है। साथ ही एक साझा मुद्रा जारी करने का प्रयास किया जाता है। यूरोपीय साझा बाजार (ECM) अब यूरोपीय आर्थिक संगठन (European Economic Union) बन चुका है। इसका एक साझा मुद्रा यूरो (Euro) भी है, जो सदस्य देशों के बीच तो स्वीकार्य है ही, दुनिया के अन्य देशों में भी इसकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है।

सीमा संघ के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का श्रेय जैकब वाइनर (Jacob Viner), जे. ई. मीड (J. E. Meade), आर. जी. लिप्से (R. G. Lipse) आदि को जाता है। वैसे तो सीमा संघ के गठन का उद्देश्य सदस्य-देशों में कल्याण के स्तर को उंचा उठाना होता है। किन्तु जैकब वाइनर ने व्यापार सृजन (Trade Creation) व व्यापार दिशा परिवर्तन (Trade Diversion) जैसी अवधारणाओं की मदद से यह सिद्ध किया कि यह कोई जरूरी नहीं है कि सीमा संघ का गठन सदस्य देशों के कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाये।

10.4 व्यापार सृजन (Trade Creation) व व्यापार दिशा परिवर्तन (Trade Diversion)

व्यापार दिशा-परिवर्तन (Trade Diversion) जैकब वाइनर ने सीमा संघ के गठन के पश्चात् व्यापार सृजन व व्यापार दिशा परिवर्तन के माध्यम से सदस्य देशों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। उनके अनुसार **व्यापार सृजन (Trade Creation) तब होता है जब सीमा संघ के गठन के बाद किसी वस्तु का घरेलू उत्पादन बंद करके उसे अधिक कुशल (more efficient) सदस्य देश से आयातित किया जाता है। जबकि, व्यापार दिशा-परिवर्तन (Trade Diversion) तब होता है जब किसी वस्तु का आयात किसी गैर सदस्य किन्तु अधिक कुशल (more efficient) देश से हटाकर कम कुशल (less efficient) सदस्य-देश से किया जाता है। (Trade creation takes place when domestic production is replaced by imports from a more efficient member-country of the Custom Union, where as, Trade Diversion takes place when import from a more efficient non-member country is switched to a less efficient member country of the Custom Union.)** यहाँ उत्पादन में कुशलता या अकुशलता का आकलन उत्पादन लागत में अंतर के आधार पर किया जाता है। सारिणी संख्या 10.1 की मदद से व्यापार सृजन को समझा जा सकता है:

सारिणी 10.1: व्यापार सृजन

देश	उत्पादन लागत रु प्रति इकाई	जर्मनी एक समान प्रति इकाई 100% आयात शुल्क लगाता	जर्मनी फ्रांस से आयातित वास्तु से सभी आयात शुल्क हटा लेता है किन्तु जापानी वस्तु पर से नहीं
जर्मनी	50	50	50
फ्रांस	40	80	40
जापान	30	60	60

सर्वप्रथम, सारिणी 10.1 की मदद से व्यापार सृजन को समझने का प्रयास करते हैं। सारिणी 10.1 में तीन देश जर्मनी, फ्रांस और जापान दर्शाये गए हैं। जर्मनी और फ्रांस सीमा संघ का गठन कर लेते हैं जबकि जापान सीमा संघ के बाहर का देश है। तीनों देशों में किसी वस्तु, जैसे टेलीविजन, का उत्पादन लागत अगले कॉलम में दिया गया है जिसके अनुसार जर्मनी में इसकी प्रति इकाई उत्पादन लागत 50 डॉलर है जबकि फ्रांस व जापान में क्रमशः 40 डॉलर और 30 डॉलर है। उत्पादन लागत के लिहाज से जापान टेलीविजन के उत्पादन में सबसे अधिक निपुण है

जबकि जर्मनी सबसे कम। मुक्त व्यापार की स्थिति में जापान से टेलीविज़न का आयात जर्मनी व फ्रांस दोनों देशों में होगा और इन दोनों देशों को इसका उत्पादन बंद करना पड़ेगा।

अब मान लीजिए जर्मनी टेलीविज़न के आयात पर 100% आयात शुल्क लगाता है। ऐसी स्थिति में फ्रांस के टेलीविज़न का मूल्य 80 डॉलर तथा जापानी टेलीविज़न का मूल्य 60 डॉलर हो जायेगा। जर्मन टेलीविज़न का मूल्य तो 50 डॉलर ही रहेगा। ऐसी स्थिति में जर्मन टेलीविज़न की विक्री घरेलू बाज़ार में होगी। 100% के आयात शुल्क के कारण फ्रांस व जापान के उत्पाद का मूल्य जर्मन बाज़ार में जर्मन टेलीविज़न से अधिक हो जायेगा जिसके कारण उनकी विक्री नहीं हो पायेगी।

अब मान लीजिए, जर्मनी व फ्रांस सीमा संघ बना लेते हैं और एक दूसरे देश से आने वाली टेलीविज़न सहित समस्त वस्तुओं पर से सीमा शुल्क हटा लेते हैं, जबकि जापान से आनेवाली वस्तुओं पर एक समान टैरिफ जो 100% है, बना रहता है। परिणामस्वरूप, जर्मन बाज़ार में जर्मन टेलीविज़न का मूल्य 50 डॉलर और फ्रांस के टेलीविज़न का मूल्य 40 डॉलर हो जाता है, जबकि जापानी टेलीविज़न का मूल्य 60 डॉलर हो जायेगा, जैसा की सारिणी 10.1 के अंतिम कॉलम में दर्शाया गया है। अब सीमा संघ के गठन के पश्चात् जर्मनी टेलीविज़न का उत्पादन बंद कर उसे फ्रांस से आयात करेगा क्योंकि वहां से उसे सस्ते मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है। यह स्थिति व्यापार सृजन (Trade Creation) का है, जो संसाधनों का बेहतर आवंटन के कारण प्राप्त होता है और जिसके कारण जर्मनी में कल्याण का स्तर ऊँचा हो जाता है। अब हम सारिणी 10.2 की मदद से अब हम व्यापार दिशा परिवर्तन (Trade Diversion) को समझने का प्रयास करेंगे।

सारिणी 10.2 व्यापार दिशा परिवर्तन (Trade Diversion)

देश	उत्पादन लागत रु प्रति इकाई	जर्मनी एक समान प्रति इकाई 50% आयात शुल्क लगाता	जर्मनी फ्रांस से आयातित वास्तु से सभी आयात शुल्क हटा लेता है किन्तु जापानी वस्तु पर से नहीं
जर्मनी	50	50	50
फ्रांस	40	60	40
जापान	30	45	45

इस सारिणी में भी टेलीविज़न की उत्पादन लागत तीनों देशों में वही है जो सारिणी संख्या 10.1 में थी। यदि जर्मनी अपने यहाँ आनेवाली वस्तु पर 50% आयात शुल्क लगाता है तब फ्रांस से आनेवाले टेलीविज़न का मूल्य 60 डॉलर तथा जापान से आनेवाले टेलीविज़न का मूल्य 45 डॉलर हो जाता है। ऐसी स्थिति में टैरिफ लगाने के बावजूद जर्मनी के लिए जापानी टेलीविज़न सबसे सस्ता होगा।

अब यदि जर्मनी और फ्रांस सीमा संघ गठन कर लेते हैं तब जर्मनी जापान से टेलीविज़न का आयात बंद कर फ्रांस से टेलीविज़न का आयात करने लगेगा क्योंकि तब उसका मूल्य सबसे कम होगा, जैसा कि सारिणी संख्या 10.2 के अंतिम कॉलम से स्पष्ट है। यह स्थिति व्यापार दिशा-परिवर्तन (Trade Diversion) की है। यहाँ जर्मनी ने टेलीविज़न का आयात सबसे कम लागत पर उत्पादित करनेवाले देश (जापान) से बंद कर उससे अधिक लागत वाले सीमा संघ के सदस्य देश (फ्रांस) से करने लगा। यह व्यापार दिशा-परिवर्तन (Trade Diversion) संसाधनों के अकुशल आवंटन के कारण उत्पन्न होता है और जिसके कारण जर्मनी में कल्याण का स्तर नीचा हो जाता है।

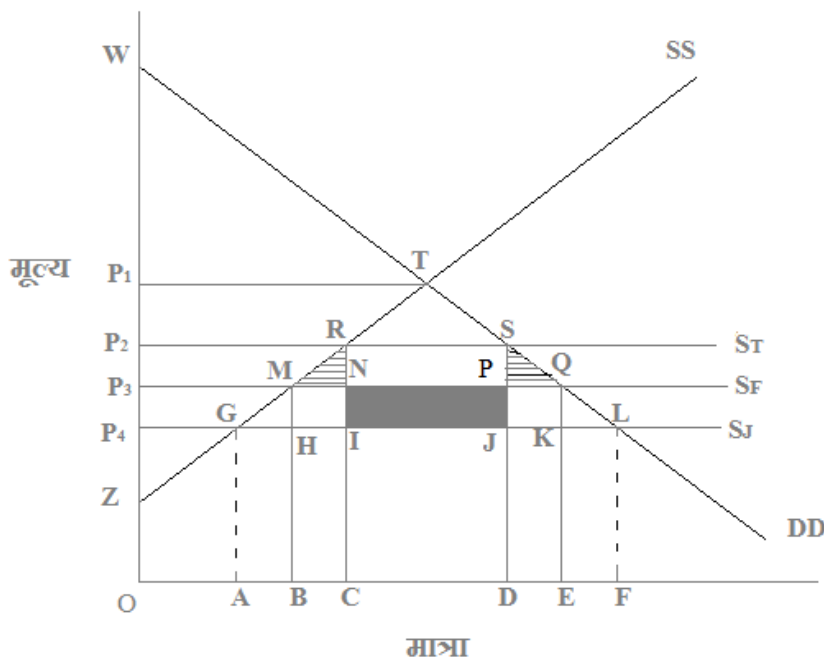
अतः हम देखते हैं कि सीमा संघ का गठन देश के कल्याण को प्रभावित करता है। शुद्ध कल्याण में वृद्धि अथवा हास इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यापार सृजन और व्यापार दिशा-परिवर्तन में कौन अधिक बलशाली है।

10.5 सीमा संघ का आंशिक व सामान्य संतुलन विश्लेषण

10.5.1 सीमा संघ का आंशिक संतुलन विश्लेषण

सीमा संघ का आंशिक संतुलन विश्लेषण प्रस्तुत करने के पूर्व बता दें कि जैकब वाइनर ने अपने विश्लेषण में सीमा संघ के गठन का उत्पादन-प्रभाव पर प्रकाश डाला जबकि **मीड** तथा **लिप्से** ने इसके उत्पादन व उपभोग दोनों प्रभावों पर प्रकाश डाला। यहाँ हम सीमा संघ के आंशिक संतुलन विश्लेषण में दोनों पक्षों के विचारों को समेकित करते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ हम एक वस्तु, टेलीविज़न का उदाहरण लेकर सीमा संघ के गठन के फलस्वरूप कल्याण पर पड़नेवाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे। हम ज्यामितीय विधि से आंशिक संतुलन विश्लेषण को प्रस्तुत कर रहे हैं।

यहाँ तीन देशों का उदाहरण लिया गया है। ये देश हैं जर्मनी, जो घरेलू देश है, दूसरा देश है फ्रांस जो जर्मनी के साथ सीमा संघ का गठन करता है। तीसरा देश है जापान जो सीमा संघ के बाहर का देश है। जर्मनी में टेलीविज़न की मांग व पूर्ति वक्र क्रमशः DD और SS हैं। इसके कारण इसका मूल्य OP_1 निर्धारित होता है। फ्रांस व जापान के टेलीविज़न का मूल्य क्रमशः OP_3 और OP_4 हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जापान टेलीविज़न के उत्पादन में सबसे निपुण देश है क्योंकि उसके उत्पाद का मूल्य सबसे कम है। फ्रांस की स्थिति जर्मनी व जापान के बीच की है। फ्रांस और जापान के पूर्ति वक्र पूर्णतः लोचदार हैं जो यह दर्शाता है कि वे अपने मूल्य पर टेलीविज़न की कोई भी मात्रा की पूर्ति करने को तैयार हैं। अब मान लीजिए जर्मनी P_2P_4 के बराबर सीमा शुल्क जर्मनी से बाहर से आनेवाले टेलीविज़न पर लगाता है। इसके कारण जापान से आनेवाले टेलीविज़न का मूल्य बढ़कर OP_2 हो जाता है। फ्रांस के उत्पाद का मूल्य अधिक हो जाने के कारण उसकी स्थिति का आकलन यहाँ नहीं किया जा रहा है। जर्मनी OP_2 मूल्य पर टेलीविज़न का उत्पादन OC मात्रा के बराबर करेगा किन्तु उसकी मांग OD के बराबर है। शेष CD मात्रा वह जापान से आयात करेगा। ऐसी स्थिति में (a) कुल उपभोक्ता की बचत(Consumer's Surplus) WSP_2 के बराबर होगा (b) कुल उत्पादक की बचत(Producer's Surplus) P_2RZ के बराबर होगा, और (c) सरकार को प्राप्त कुल राजस्व RIJS के बराबर होगा।



चित्र 10.1

अब मान लीजिए जर्मनी फ्रांस के साथ सीमा संघ बना लेता है और दोनों एक दूसरे के उत्पाद पर से समस्त आयात शुल्क हटा लेते हैं। ऐसी स्थिति में जर्मनी फ्रांस से बिना आयात शुल्क के टेलीविज़न का आयात करेगा जिसका मूल्य OP_3 के बराबर होगा जो जापान के टेलीविज़न के मूल्य OP_2 (आयात शुल्क सहित) से कम है। ऐसी स्थिति में अधिक मूल्य होने के कारण जापानी टेलीविज़न की विक्री जर्मन बाज़ार में नहीं होगी। अब हम ऐसी स्थिति में हम सीमा संघ के गठन का जर्मनी पर पड़ने वाले कुल प्रभाव का आकलन करते हैं, जो निम्न प्रकार हैं:

- (a) **मूल्य प्रभाव (Price Effect):** जर्मनी की खरीददारी मूल्य OP_2 से घटकर OP_3 हो जाता है।
- (b) **उत्पादन प्रभाव (Production Effect):** जर्मनी में टेलीविज़न का उत्पादन OC (OP_2 मूल्य पर) से घटाकर OB (OP_3 मूल्य पर) हो जाता है। जिसके कारण जर्मनी के आयात में BC के बराबर वृद्धि होती है जो सीमा संघ के गठन के बाद टेलीविज़न के घरेलू उत्पादन में कमी के कारण संभव हुआ और यह मात्रा अधिक कुशल (more efficient) सदस्य देश से आयातित होता है। जैकब वाइनर के अनुसार यह व्यापार सृजन है।
- (c) **उपभोग प्रभाव (Consumption Effect):** मूल्य में कमी (OP_2 से OP_3) हो जाने से जर्मनी के टेलीविज़न उपभोग में DE के बराबर वृद्धि होती है। उपभोग में यह वृद्धि फ्रांस से शुल्क-रहित टेलीविज़न के आयात से पूरा किया जाता है। यह भी व्यापार सृजन है जिसे जैकब वाइनर ने नहीं पहचाना। इसे प्रस्तुत करने का श्रेय मीड, लिप्से, जॉनसन जैसे अर्थशास्त्रियों को जाता है। इन लोगों ने सीमा संघ के गठन का उत्पादन तथा उपभोग प्रभाव दोनों को महत्व दिया।
- (d) **कल्याण सृजन प्रभाव (Welfare Creation Effect):** जैसा कि हमने देखा, सीमा संघ के गठन के पश्चात् उत्पादन में वृद्धि (BC) व उपभोग में वृद्धि (DE) के बराबर होता है। इनके कारण सीमा संघ का व्यापार सृजन प्रभाव क्रमशः RMN और SPQ के बराबर होता है। इन दोनों का योग जर्मनी के कल्याण में कुल वृद्धि को मापता है।
- (e) **कल्याण हास प्रभाव (Welfare Reducing Effect):** सीमा संघ के गठन के कारण व्यापार सृजन के साथ ही व्यापार दिशा-परिवर्तन (Trade Diversion) भी होता है। इसका कारण यह है कि जर्मनी सीमा संघ के गठन के पश्चात् एक अधिक निपुण (more efficient) देश जापान के बदले एक कम निपुण (less efficient) देश फ्रांस से टेलीविज़न का आयात करने लगा। जापानी टेलीविज़न की उत्पादन लागत सबसे कम 30 डॉलर प्रति इकाई थी। यह व्यापार दिशा-परिवर्तन, व्यापार सृजन के विपरीत जर्मनी के कल्याण में कमी लाता है।

यहाँ ध्यान देने योग्य है कि सीमा संघ के गठन के बाद, जर्मनी का टेलीविज़न आयात CD (जापान से) की जगह BE (फ्रांस से) हो रहा है। इनमें BC और DE के बराबर आयात में वृद्धि व्यापार सृजन करता है, जिसके कारण कल्याण में वृद्धि होती है। CD मात्रा के आयात का दिशा-परिवर्तन (जापान से फ्रांस) होता है जिसका हमें कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना है।

सीमा संघ के गठन के पूर्व जर्मनी के लिए CD मात्रा के आयात (जापान से) पर ग्राहकों द्वारा कुल भुगतान $CRSD$ था। जिसमें RJS के बराबर जर्मन सरकार को राजस्व के रूप में प्राप्त होता था। यह एक प्रकार का आंतरिक हस्तान्तरण था जिसे सम्पूर्ण देश के सन्दर्भ में लागत नहीं माना जायेगा।

अतः CD मात्रा के आयात का वास्तविक लागत $CIJD$ माना जायेगा। अब देखते हैं, सीमा संघ के गठन का बाद क्या स्थिति बनती है। सीमा संघ के गठन के बाद CD मात्रा के आयात के लिए जर्मनी

फ्रांस को CDPN भुगतान करता है, जो सीमा संघ के गठन के पूर्व जापान को किये गए भुगतान (CDJI) से IJPN अधिक है। सीमा संघ के गठन के बाद यही व्यापार दिशा परिवर्तन की लागत है जिसे हम **कल्याण ह्रास प्रभाव (Welfare reducing effect)** कहेंगे।

(f) शुद्ध कल्याण प्रभाव (Net Welfare Effect): इस प्रकार हमने देखा कि सीमा संघ का गठन व्यापार सृजन व व्यापार दिशा परिवर्तन को जन्म देता है। व्यापार सृजन कल्याण में वृद्धि करता है जबकि व्यापार दिशा-परिवर्तन कल्याण में कमी लाता है। इस प्रकार शुद्ध कल्याण-प्रभाव इन दोनों का अंतर होगा। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है।

कल्याण में वृद्धि = (RMN + SPQ) और कल्याण में कमी = IJPN

यदि,

$$(RMN + SPQ) = IJPN,$$

तब सीमा संघ के गठन से जर्मनी के कल्याण के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं।

यदि,

$$(RMN + SPQ) > IJPN,$$

तब सीमा संघ के गठन से जर्मनी के कल्याण के स्तर में वृद्धि होगी।

यदि,

$$(RMN + SPQ) < IJPN$$

तब सीमा संघ के गठन से जर्मनी के कल्याण के स्तर में कमी होगी।

अब यहाँ प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कौन-कौन से कारक सीमा संघ के गठन से शुद्ध कल्याण को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ बता दें कि निम्नलिखित दो कारक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं:

1. घरेलू देश (जर्मनी) की मांग व पूर्ति की लोच, और
2. सीमा संघ के गठन पूर्व मुक्त-व्यापार मूल्य OP4, सीमा संघ के गठन पूर्व शुल्क सहित मूल्य OP2, तथा सीमा संघ के गठन के बाद का मूल्य OP3, इन तीनों के बीच का अंतर।

सीमा संघ के गठन से कल्याण पर प्रभाव कुछ अन्य बातों पर भी निर्भर करते हैं, जो इस प्रकार हैं:

- a) यदि सीमा संघ के दोनों सदस्य देश किसी वस्तु का उत्पादन ही नहीं करते तो इसके गठन का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि तब दोनों ही देशों को वह वस्तु सीमा संघ के बाहर के देश से आयात करना पड़ेगा।
- b) यदि किसी देश का प्रारंभिक सीमा शुल्क दर बहुत कम हो तो सीमा संघ के गठन से कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि तब व्यापार सृजन व्यापार दिशापरिवर्तन से कम होगा। इसके विपरीत, यदि सीमा शुल्क दर बहुत अधिक हो तो सीमा संघ के गठन से कल्याण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।
- c) यदि सीमा संघ के सदस्य-देश आपस में पूरक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तब सीमा संघ के गठन से कल्याण सम्बन्धी लाभ कम होगा, और यदि वे स्थानापन्न व प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तब सीमा संघ के गठन से कल्याण सम्बन्धी लाभ अधिक होगा।

10.5.2 सीमा संघ का सामान्य संतुलन विश्लेषण

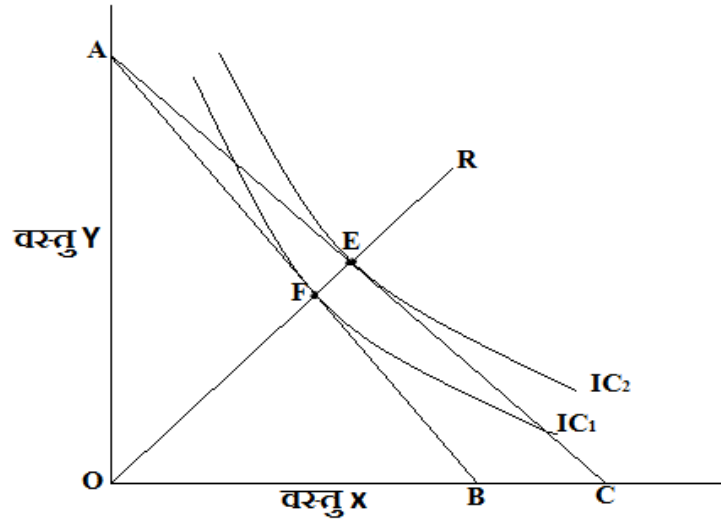
सीमा संघ के आंशिक संतुलन विश्लेषण में हमने कई बातों की अनदेखी की जो सीमा संघ के गठन से उत्पन्न होती है। सीमा संघ व्यापार-सृजन व व्यापार दिशा-परिवर्तन के अतिरिक्त कई अन्य प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं, जैसे भुगतान संतुलन प्रभाव, व्यापार की शर्त पर प्रभाव आदि। अतः सीमा संघ का सामान्य संतुलन विश्लेषण

का अध्ययन अपरिहार्य हो जाता है। यहाँ हम सीमा संघ के सामान्य संतुलन से सम्बंधित दो मॉडल की चर्चा करेंगे, एक लिप्से (R.G. Lipse) का मॉडल तथा दूसरा वानेक (Jaroslav Vanek) का मॉडल।

a) लिप्से का मॉडल

जैकब वाइजर ने कहा था कि सीमा संघ के गठन का व्यापार दिशा-परिवर्तन (Trade Diversion) प्रभाव कल्याण के स्तर में कमी लाता है। लिप्से ने जैकब वाइजर के इस मत पर इसी शर्त पर सहमती जताई कि सीमा संघ के गठन के बाद भी देश में वस्तु का उपभोग पूर्व के ही अनुपात में हो, भले ही वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्य में परिवर्तन हो गया हो। वाइजर की ही तरह लिप्से भी अपने विश्लेषण को इस मान्यता के आधार पर आगे बढ़ाते हैं कि देश में उत्पादन स्थिर लागत के नियम के अनुसार हो रहा है।

यहाँ भी हम तीन देश - जर्मनी, फ्रांस और जापान का उदाहरण लेते हैं, जिसमें जर्मनी घरेलू देश है, फ्रांस उसके सीमा संघ का जोड़ीदार देश है। जबकि जापान सीमा संघ के बाहर का देश है। चित्र 10.2 में, जर्मनी वस्तु Y के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त कर चुका है। सीमा संघ के गठन के पूर्व AC व्यापार की शर्त पर वह जापान से वस्तु Y के निर्यात के बदले वस्तु X का आयात करता है। वह उत्पादन A बिंदु पर करता है और उपभोग E बिंदु पर करता है और उसके कल्याण का स्तर अनाधिमान वक्र IC_1 से दर्शाया गया है।



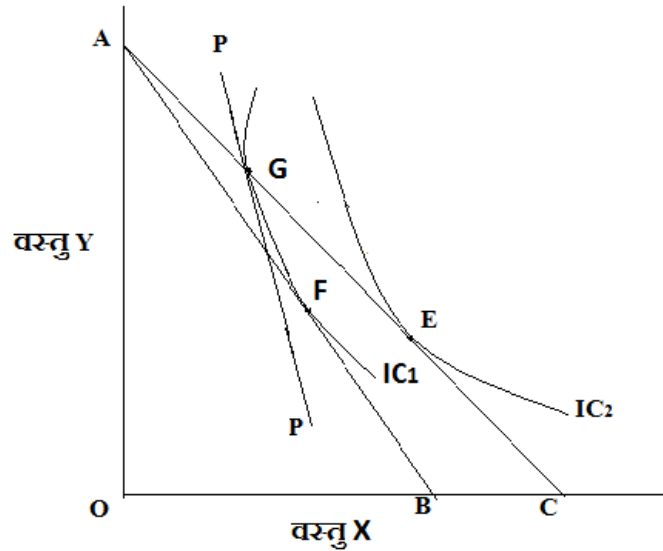
चित्र 10.2

अब मान लीजिए कि जर्मनी फ्रांस के साथ सीमा संघ बना लेता है। जिसके कारण अब व्यापार दिशा-परिवर्तन होता है जहाँ जर्मनी का आयात कम लागत पर उत्पादन करने वाले देश जापान से परिवर्तित होकर फ्रांस से होने लगता है। फ्रांस से व्यापार की शर्त AB है, जो यह दर्शाता है कि वस्तु X अब सापेक्षिक रूप से महँगी हो गई है। अब जर्मनी का उपभोग F बिंदु पर हो रहा है जो पूर्व की भांति स्थिर उपभोग-अनुपात है जिसे OR रेखा से दर्शाया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि F बिंदु पर कल्याण का स्तर जिसे IC_1 से दर्शाया गया है, वह E बिंदु के कल्याण IC_2 से नीचे है।

इस प्रकार सीमा संघ के गठन से व्यापार दिशा परिवर्तन के कारण जर्मनी के कल्याण का स्तर पहले से कम हो गया। किन्तु यह तभी होगा जब जैकब वाइजर के स्थिर उपभोग की मान्यता को स्वीकार किया जाय। यह मान्यता अत्यंत कठोर और वास्तविकता से दूर है। वास्तविकता तो यह है कि सीमा संघ के गठन के पश्चात् वस्तुओं के सापेक्ष मूल्य में बदलाव आता है।

अब हम दूसरे चित्र 10.3 में स्थिर उपभोग अनुपात की मान्यता को त्याग कर देखते हैं। यहाँ भी जर्मनी वस्तु Y के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त कर A बिंदु पर उत्पादन करता है। मुक्त व्यापार के अवस्था में वह

AC व्यापार की शर्त पर जापान से वस्तु X का आयात वस्तु Y के बदले करता है और उसका उपभोग अनाधिमान वक्र IC₂ के E बिंदु पर होता है। अब यदि जर्मनी जापान के वस्तु Y पर सीमा शुल्क लगा देता है तब दोनों वस्तुओं का सापेक्षिक मूल्य बदल जाता है जिसे मूल्य-रेखा PP से दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में जर्मनी का उपभोग, मूल्य रेखा PP के G बिंदु पर होगा जहाँ एक नीचा अनाधिमान वक्र IC₁ मूल्य रेखा PP स्पर्श करता है। यह स्थिति अनुकूलतम दशा को नहीं दर्शाता क्योंकि IC₁ व्यापार की शर्त रेखा AC को G बिंदु पर स्पर्श नहीं करता बल्कि काटता है। यह अनुकूलतम से नीचे (Sub-optimal) अवस्था है।



चित्र 10.3

वस्तु X अब जर्मनी और फ्रांस सीमा संघ बना लेते हैं और सभी प्रकार के टैरिफ समाप्त कर देते हैं। दोनों के बीच का व्यापार की शर्त AB है जो दर्शाता है कि वस्तु X का सापेक्षिक मूल्य फ्रांस में जापान की तुलना में अधिक है। किन्तु फ्रांस के वस्तु X पर सीमा शुल्क नहीं लगाने के कारण वह शुल्क-युक्त जापानी वस्तु से सस्ती है। ऐसी स्थिति में जर्मनी में वस्तु X का प्रतिस्थापन वस्तु Y के बदले होगा फलस्वरूप वस्तु X का उपभोग बढ़ेगा और नया संतुलन अनाधिमान वक्र IC₁ के F बिन्दु पर स्थापित होगा जहाँ वह व्यापार की शर्त रेखा AB को स्पर्श करता है। अब ध्यान देने योग्य बात है कि बिंदु F और बिंदु G एक ही अनाधिमान वक्र IC₁ पर स्थित हैं, जिससे यह पता चलता है कि फ्रांस के साथ सीमा संघ के गठन के बाद, व्यापार दिशा-परिवर्तन (Trade Diversion) के बावजूद जर्मनी में कल्याण के स्तर में कोई बदलाव नहीं आया।

जैकब वाइनर के अनुसार तो प्रत्येक व्यापार दिशा-परिवर्तन (Trade Diversion) कल्याण में कमी लाता है। यहाँ एक बात निकलकर आती है। यदि सीमा संघ के गठन के पश्चात् जर्मनी व फ्रांस के व्यापार की शर्त का स्थान AC व AB के बीच स्थित होता है तब तो सीमा संघ के गठन के बाद व्यापार दिशा-परिवर्तन होने के बावजूद जर्मनी के कल्याण के स्तर में वृद्धि ही होती और उपभोग का स्तर अनाधिमान वक्र IC₁ और IC₂ के बीच स्थित होता।

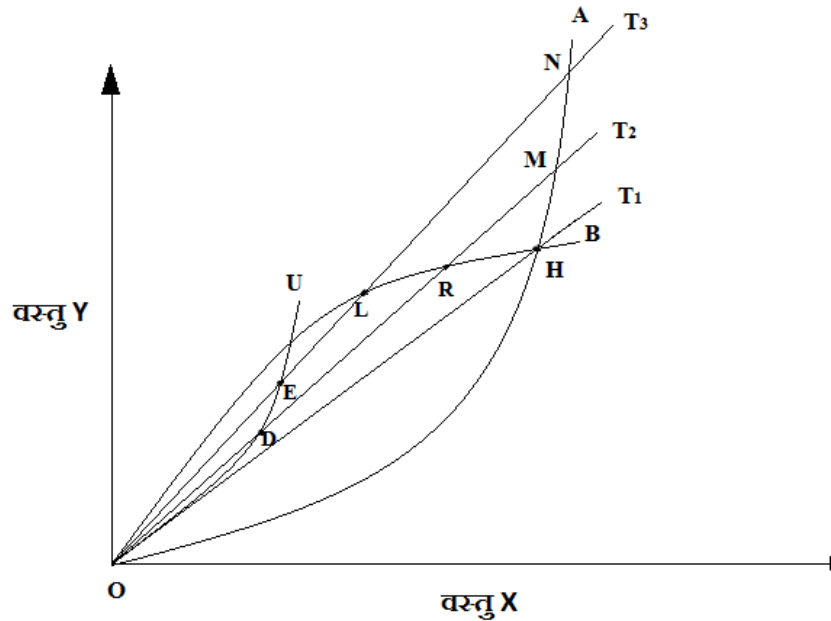
अतः व्यापार दिशापरिवर्तन के फलस्वरूप देश के कल्याण के स्तर में परिवर्तन सीमा संघ के गठन के पूर्व व बाद लागत तथा सापेक्षिक मूल्य की दशा पर निर्भर करता है।

b) वानेक का मॉडल जारोस्लाव वानेक (Jaroslav Vanek)

वानेक का मॉडल जारोस्लाव वानेक (Jaroslav Vanek) ने प्रस्ताव वक्र तकनीक (offer curve technique) की मदद से सीमा संघ का सामान्य संतुलन विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उनके विश्लेषण को समझने के लिए मान लीजिए कि जर्मनी और फ्रांस सीमा संघ का गठन करते हैं। जबकि जापान सीमा संघ के बाहर का देश है। चित्र 10.4 में जर्मनी और फ्रांस क्रमशः वस्तु X और वस्तु Y का निर्यात करते हैं जबकि जापान केवल वस्तु Y का निर्यात कर सकता है। OA और OB सीमा संघ गठन के पूर्व क्रमशः जर्मनी व फ्रांस के प्रस्ताव वक्र हैं। सीमा संघ के गठन के बाद संघ का प्रस्ताव वक्र OU है। जिसे अतिरिक्त प्रस्ताव वक्र (excess offer curve) कहा गया है।

अतिरिक्त प्रस्ताव वक्र वस्तु X की वह मात्रा प्रदर्शित करता है। जो सीमा संघ के देश जापान से वस्तु Y की एक निश्चित मात्रा के बदले लेन-देन करने का प्रस्ताव करते हैं। अब जर्मनी व फ्रांस के प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को H बिंदु पर काटते हैं। जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार की शर्त OT_1 निर्धारित होता है। ऐसी स्थिति में संघ का प्रस्ताव वक्र यह दर्शाता है कि अभी संघ के बाहर के देश जापान से लेन-देन की स्थिति उनके लिए नहीं बनी है।

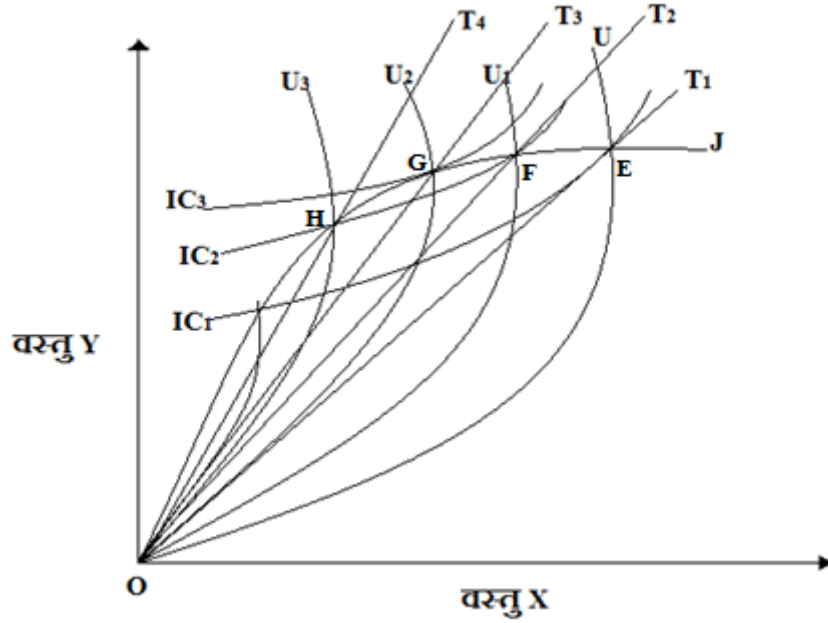
व्यापार की शर्त यदि OT_2 हो जाता है तब स्पष्ट है कि जर्मनी अपने प्रस्ताव वक्र के M बिंदु पर व्यापार करना चाहेगा जबकि फ्रांस अपने प्रस्ताव वक्र के R बिंदु पर व्यापार करना चाहेगा। यानि जर्मनी वस्तु X के कम निर्यात के बदले वस्तु Y का अधिक आयात चाहता है। चित्र में RM इस अतिरिक्त मात्रा को प्रदर्शित करता है। यदि हम मूल बिंदु से OT_2 रेखा पर RM के बराबर दूरी लें जो OD के बराबर है, तब हमें अतिरिक्त प्रस्ताव की मात्रा प्राप्त होगी। इसी प्रकार व्यापार की शर्त OT_3 पर OE के बराबर अतिरिक्त प्रस्ताव की मात्रा प्राप्त होगी।



चित्र 10.4

इन विभिन्न बिन्दुओं D, E, आदि को मिलाने से हमें संघ का प्रस्ताव वक्र OU प्राप्त होगा। इसकी मदद से सीमा संघ के देश संघ के बाहर के देश जापान से उसके प्रस्ताव वक्र को रखकर व्यापार की संभावना देखेंगे। जिसे अगले चित्र की मदद से दर्शाया गया है।

चित्र 10.5 में हम सीमा संघ के अतिरिक्त प्रस्ताव वक्र (excess offer curve) OU को संघ के बाहर के देश जापान के प्रस्ताव वक्र OJ पर रखते हैं। तब E बिंदु व्यापार संतुलन का बिंदु होगा और व्यापार की शर्त OT_1 निर्धारित होगा।



चित्र 10.5

सीमा संघ के गठन के बाद संघ के बाहर से आने वाली वस्तुओं पर एक समान सीमा शुल्क लगेगा। टैरिफ लगाने पर संघ का अतिरिक्त प्रस्ताव वक्र OU से खिसककर क्रमशः OU_1, OU_2, OU_3 होता जायेगा और संघ के लिए व्यापार की शर्त अनुकूल होता जायेगा जो क्रमशः OT_2, OT_3, OT_4 आदि से प्रगट होता है। ऐसी स्थिति में संघ के कल्याण में भी वृद्धि होती जाएगी। संघ का कल्याण, व्यापार अनाधिमान वक्र (Trade Indifference Curve) IC_3 के G बिंदु पर अधिकतम होगा जहाँ वह जापान के प्रस्ताव वक्र को स्पर्श करता है और व्यापार की शर्त OT_3 स्पर्श बिंदु G से होकर गुजरता है। इस सीमा शुल्क (टैरिफ) को अनुकूलतम टैरिफ कहते हैं।

10.6 अभ्यास हेतु प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. सीमा संघ से क्या समझते हैं?
2. व्यापार सृजन व व्यापार दिशा-परिवर्तन किसे कहते हैं?
3. सीमा संघ का सामान्य संतुलन विश्लेषण क्या है ?
4. सीमा संघ में सदस्य-देशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है?
5. अतिरिक्त प्रस्ताव वक्र क्या है?
6. व्यापार अनाधिमान वक्र क्या है?

अति लघु उत्तरीय प्रश्न:

1. व्यापार सृजन व व्यापार दिशा-परिवर्तन की अवधारण किसने विकसित की?
2. द्वितीय सर्वोत्तम का सिद्धांत किसे कहते हैं?

बहुविकल्पीय प्रश्न:

1. निम्नलिखित में किसमें आर्थिक एकीकरण सबसे अधिक होता है –

- a) सीमा संघ में b) साझा बाज़ार में c) आर्थिक संगठन में.
2. द्वितीय सर्वोत्तम का सिद्धांत किसने विकसित की –
a) मार्शल ने b) लिप्से तथा लेंकास्टर ने c) जैकब वाइनर ने
3. सीमा संघ के सदस्य, संघ के बाहर के देशों पर लगाते हैं -
a) एक समान शुल्क लगाते हैं
b) अलग-अलग शुल्क लगाते हैं
c) शुल्क लगाते ही नहीं.
4. जैकब वाइनर ने सीमा संघ का प्रभाव निम्न पर डाला –
a) उत्पादन पर b) उपभोग पर c) उत्पादन तथा उपभोग दोनों पर
5. शुद्ध कल्याण में वृद्धि निर्भर करता है–
a) व्यापार सृजन की मात्रा पर
b) व्यापार दिशा-परिवर्तन की मात्रा पर
c) व्यापार सृजन तथा व्यापार दिशा-परिवर्तन दोनों की मात्रा पर

सत्य-असत्य का चुनाव करें:

1. व्यापार सृजन से कल्याण घटता है।
2. व्यापार दिशा-परिवर्तन से कल्याण बढ़ता है।
3. लिप्से के अनुसार व्यापार दिशा-परिवर्तन से कल्याण अनिवार्यतः नहीं घटता।

10.7 सारांश

इस प्रकार इस इकाई में आप सीमा संघ के अर्थ, इसके सिद्धांत आदि से परिचित हुए। सीमा संघ मुक्त व्यापार व संरक्षण के बीच की स्थिति है। इसे द्वितीय श्रेष्ठ का सिद्धांत भी कहते हैं। सीमा संघ एक प्रकार का आर्थिक एकीकरण है। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक देश एक संगठन बनाते हैं, जिसके सदस्य देश आपस में सीमा शुल्क (टैरिफ) को समाप्त कर देते हैं और संगठन के बाहर के देशों से आनेवाली वस्तुओं पर साझा शुल्क लगाते हैं। इस प्रकार के संगठन का उद्देश्य सदस्य देशों में कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना होता है। सीमा संघ के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का श्रेय जैकब वाइनर (Jacob Viner), जे. ई. मीड (J. E. Meade), आर जी. लिप्से (R. G. Lipse) आदि को जाता है।

जैकब वाइनर ने व्यापार सृजन (Trade Creation) व व्यापार दिशा परिवर्तन (Trade Diversion) जैसी अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार व्यापार सृजन तब होता है जब सीमा संघ के गठन के बाद किसी वस्तु का घरेलू उत्पादन करने की जगह उसे अधिक कुशल सदस्य देश से आयातित किया जाता है। जबकि, व्यापार दिशा-परिवर्तन तब होता है। जब किसी वस्तु का आयात किसी गैर सदस्य किन्तु अधिक कुशल देश से हटाकर कम कुशल सदस्य-देश से किया जाता है।

जैकब वाइनर ने अपना विश्लेषण स्थिर उपभोग अनुपात की मान्यता पर विकसित की, जिसे आगे चलाकर लिप्से ने चुनौती दी। सीमा संघ के आंशिक संतुलन विश्लेषण के अंतर्गत हमने एक वस्तु का उदहारण लेकर सीमा संघ के गठन का देश के कल्याण पर पड़नेवाले प्रभाव का अध्ययन किया। किन्तु सीमा संघ के आंशिक संतुलन विश्लेषण में कई बातों की अनदेखी हो जाती है। जो सीमा संघ के गठन से उत्पन्न होती है।

सीमा संघ व्यापार सृजन व व्यापार दिशा-परिवर्तन के अतिरिक्त कई अन्य प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं, जैसे भुगतान संतुलन प्रभाव, व्यापार की शर्त पर प्रभाव आदि। सीमा संघ के सामान्य संतुलन विश्लेषण के अंतर्गत हम

इन बातों को भी सम्मिलित करते हैं। सीमा संघ के सामान्य संतुलन से सम्बंधित हमने दो मॉडलों की चर्चा की, एक लिप्से (R. G. Lipse) का मॉडल तथा दूसरा वानेक (Jaroslav Vanek) का मॉडल। लिप्से ने जहाँ वस्तु के सापेक्षिक मूल्य रेखा की मदद से अपने तर्क को प्रस्तुत किया वहीं वानेक ने प्रस्ताव वक्र की मदद ली। वानेक ने अतिरिक्त प्रस्ताव वक्र (excess offer curve) और व्यापार अनाधिमान वक्र (Trade Indifference Curve) जैसे तकनीक का भी प्रयोग किया।

10.8 शब्दावली

- **सीमा संघ** - सीमा संघ दो या दो से अधिक राष्ट्रों का व्यापारिक संगठन है, जिसके सदस्य आपस में सीमा शुल्क (टैरिफ) को समाप्त कर देते हैं और संगठन के बाहर के देशों से आनेवाली वस्तुओं पर साझा शुल्क लगाते हैं।
- **व्यापार सृजन (Trade Creation)** - व्यापार सृजन तब होता है जब सीमा संघ के गठन के बाद किसी वस्तु का घरेलू उत्पादन करने की जगह उसे कम लागत पर उत्पादित करने वाले सीमा संघ अन्य सदस्य देश से आयातित किया जाता है।
- **व्यापार दिशा-परिवर्तन (Trade Diversion)** - व्यापार दिशा-परिवर्तन तब होता है जब किसी वस्तु का आयात कम लागत पर उत्पादित करने वाले सीमा संघ के बाहर के देश की जगह अधिक लागत पर उत्पादित करने वाले सीमा संघ के ही किसी सदस्य देश से किया जाता है।
- **आंशिक संतुलन** - सीमा संघ के आंशिक संतुलन विश्लेषण के अंतर्गत हम किसी एक वस्तु का उदाहरण लेकर सीमा संघ के गठन के फलस्वरूप मूल्य, उत्पादन, उपभोग, कल्याण आदि पर पड़नेवाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं।
- **सामान्य संतुलन** - सीमा संघ के सामान्य संतुलन विश्लेषण के अंतर्गत हम एक से अधिक वस्तु का उदाहरण लेकर वस्तु के मूल्य, उत्पादन, उपभोग, कल्याण आदि के अतिरिक्त भुगतान संतुलन, व्यापार की शर्त आदि पर पड़नेवाले प्रभाव का भी अध्ययन करते हैं।
- **अतिरिक्त प्रस्ताव वक्र** - अतिरिक्त प्रस्ताव वक्र किसी वस्तु (जैसे X) की वह मात्रा प्रदर्शित करता है जो सीमा संघ के देश किसी गैर-सदस्य देश के अन्य वस्तु (जैसे Y) की एक निश्चित मात्रा के बदले विनिमय का प्रस्ताव करते हैं।
- **व्यापार अनाधिमान वक्र** - किसी देश का व्यापार अनाधिमान वक्र उस देश के किसी वस्तु का दूसरे देश के किसी अन्य वस्तु से विनिमय के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिससे उस देश का कल्याण का स्तर अपरिवर्तित रहे।

10.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अति लघु उत्तरीय प्रश्न:

1. जैकब वाइनर ने
2. लिप्से व लेंकास्टर ने

बहुविकल्पीय प्रश्न:

1. c)
2. c)
3. c)
4. c)
5. d)

सत्य-असत्य का चुनाव करें:

1. असत्य 2. असत्य 3. सत्य

10.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- Bo Sodersten, International Economics ,Macmillan, 1999
- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006
- H. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: *International Economics: Theory and Policy*, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- एस. एन. लाल , अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र , शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहबाद, 2004
- एच. एस. अग्रवाल, तथा सी. एस. बरला, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2003.
- सुदामा सिंह एवं एम. सी. वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड एंड आई. बी. एच. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम. एल. झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010.
- डॉ. जी. सी. सिंघई एवं डॉ. जे. पी. मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा, 2010.

10.11 उपयोगी/सहायक पाठ्य सामग्री

- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006
- H. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: *International Economics: Theory and Policy*, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- एस. एन. लाल , अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र , शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहबाद, 2004
- एच. एस. अग्रवाल, तथा सी. एस. बरला, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2003.
- सुदामा सिंह एवं एम. सी. वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड एंड आई. बी. एच. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम. एल. झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010।
- ज्ञानेंद्र सिंह कुशवाहा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1979।

10.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. व्यापार सृजन व व्यापार दिशा-परिवर्तन की व्याख्या करें।
2. सीमा संघ के आंशिक संतुलन विश्लेषण की सचित्र व्याख्या करें।
3. सीमा संघ के सामान्य संतुलन के लिप्से व वानेक मॉडल की सचित्र व्याख्या करें।

इकाई 11 - भुगतान संतुलन: परिभाषा एवं अवधारणा (Balance of Payments: Definition and Concepts)

- 11.1 प्रस्तावना
- 11.2 उद्देश्य
- 11.3 भुगतान संतुलन की परिभाषा
- 11.4 भुगतान संतुलन के घटक
- 11.5 भुगतान संतुलन का मापन तथा विभिन्न अवधारणाएं
- 11.6 भुगतान संतुलन का स्वायत्त तथा समायोजक लेनदेन
- 11.7 भुगतान संतुलन में असंतुलन
 - 11.7.1 भुगतान संतुलन में निपटान तथा समायोजन
- 11.8 भुगतान संतुलन में असंतुलन के प्रकार
 - 11.8.1 अस्थायी या अल्पकालीन असंतुलन
 - 11.8.2 दीर्घकालीन या आधारभूत असंतुलन
 - 11.8.3 चक्रीय असंतुलन
 - 11.8.4 संरचनात्मक असंतुलन
- 11.9 भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण
- 11.10 भुगतान संतुलन में समायोजन
- 11.11 अभ्यास हेतु प्रश्न
- 11.12 सारांश
- 11.13 शब्दावली
- 11.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 11.15 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 11.16 उपयोगी/ सहायक पाठ्य सामग्री
- 11.17 निबंधात्मक प्रश्न

11.1 प्रस्तावना

इससे पहले की इकाईयों के अध्ययन के पश्चात् आप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्तों, व्यापार शर्तों, स्वतन्त्र व्यापार और संरक्षण तथा संरक्षण के विभिन्न उपायों के बारे में बता सकते हैं। आप जान गए होंगे की व्यापार की शर्तों के प्रतिकूल होने के कारण एक देश को भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का भी सामना करना पड़ सकता है।

भुगतान संतुलन के घाटे से निपटने के लिए प्रायः देश विभिन्न प्रकार के व्यापारिक प्रतिबंधों का सहारा लेते हंत जैसे प्रशुल्क, कोटा, विनिमय नियंत्रण इत्यादि प्रस्तुत इकाई में हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बंधित एक महत्वपूर्ण संकल्पना भुगतान संतुलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप भुगतान संतुलन से सम्बंधित विभिन्न संकल्पनाओं के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

11.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप –

- ✓ भुगतान संतुलन के अर्थ एवं प्रकृति को समझ सकेंगे।
- ✓ भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन में अंतर समझ सकेंगे।
- ✓ चालू खाता तथा पूंजी खाता में अंतर जान पाएंगे।
- ✓ भुगतान संतुलन के मापन की विधि जान पाएंगे।
- ✓ भुगतान संतुलन की विभिन्न अवधारणाएं समझ सकेंगे।
- ✓ भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण को जान पाएंगे।
- ✓ भुगतान संतुलन में समायोजन के तरीकों को समझ सकेंगे।

11.3 भुगतान संतुलन की परिभाषा

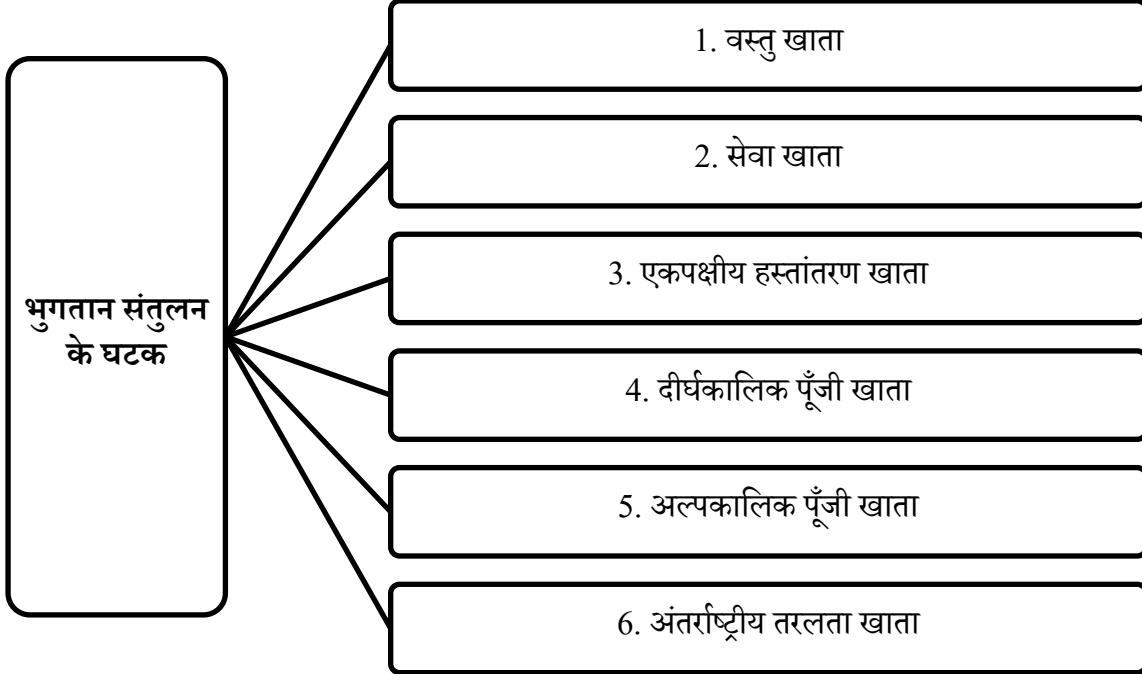
प्रत्येक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार होता है। आप जानते हैं कि कोई देश यदि वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे देशों को बेचता है तो उसे 'निर्यात' कहते हैं तथा यदि दूसरे देशों से खरीदता है तो उसको 'आयात' कहते हैं। एक देश का विश्व के अन्य सभी देशों के साथ होने वाले समस्त प्रकार के लेन-देन, चाहे वह वस्तुओं के रूप में हो, सेवाओं के रूप में हो या फिर पूंजी के रूप में, का एक सुव्यवस्थित लेखा भुगतान-संतुलन है। भुगतान संतुलन एक दी हुई समयावधि में किसी देश द्वारा किए गए समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है।

भुगतान-संतुलन का लेन-देन एक दिए हुए वर्ष में सभी विदेशी प्राप्तियों तथा भुगतानों को सम्मिलित करता है। भुगतान शेष लेखा की दोहरी-प्रविष्टि (Double entry) बहीखाता सिद्धान्त पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक सौदा, बैलेंस शीट में क्रेडिट (लेनदारियाँ या प्राप्तियाँ) तथा डेबिट (देनदारियाँ या भुगतान) पक्ष में दर्ज किया जाता है। प्राप्तियों में विदेशी विनिमय के सभी प्रकार के अर्जन (earnings) तथा उधार (borrowings) सम्मिलित होते हैं। जोकि क्रेडिट मद के रूप में रिकार्ड किया जाता है। भुगतानों में विदेशी विनिमय के सभी प्रकार के व्यय तथा दिए गए उधार सम्मिलित किए जाते हैं और इसे डेबिट मद के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

इस प्रकार सभी प्रकार की विदेशी प्राप्तियाँ एक वर्ष में हुए समस्त वित्तीय अंतर्प्रवाह को तथा समस्त भुगतान वित्तीय बहिर्प्रवाह को बताता है।

11.4 भुगतान संतुलन के घटक

भुगतान संतुलन के अंतर्गत मुख्यतः 6 प्रमुख खाते होते हैं



1 वस्तु खाता (Goods Account)

इसके अंतर्गत 'दृश्य' वस्तुओं का लेन-देन आता है। व्यापारिक वस्तु के निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा को प्राप्ति तथा उनके आयात पर व्यय विदेशी मुद्रा को भुगतानों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यदि वस्तु के निर्यातों का मूल्य, वस्तुओं के आयातों के मूल्य से अधिक होगा तो वस्तु-खाता धनात्मक होगा जो कि उस देश के 'पक्ष' में या अनुकूल कहा जाएगा, जबकि आयातों के मूल्य को निर्यातों के मूल्य से अधिक होने पर ऋणात्मक वस्तु-खाता उस देश के 'विपक्ष' में होगा।

2 सेवा खाता (Service Account)

वस्तुओं की तरह ही सेवाओं का भी व्यापार – निर्यात-आयात - होता है। सेवा खाते में एक देश द्वारा एक वर्ष के लिए गए सभी सेवाओं के निर्यातों तथा आयातों का ब्यौरा होता है। चूंकि सेवाएँ वस्तुओं की तरह 'दृश्य' नहीं होती हैं इसलिए सेवाओं के लेन-देन को भुगतान संतुलन की अदृश्य मदें कहा जाता है। व्यापारिक वस्तुओं की तरह बंदरगाहों पर इनकी आवाजाही रिकार्ड नहीं की जाती है। सेवा खातों में मुख्यतः निम्नलिखित सेवाएँ सम्मिलित हैं -

- (क) परिवहन, बैंकिंग तथा बीमा
- (ख) पर्यटन, यात्रा सेवाएँ, पर्यटनों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद
- (ग) शिक्षा सेवाएँ
- (घ) सरकारों द्वारा दूतावासों और उनके स्टाफ पर होने वाला व्यय
- (ङ) डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि विशेषज्ञों की सेवाएँ
- (च) ब्याज, लाभ, लाभांश तथा रॉयल्टी - इन मदों को 'निवेश आय' कहा जाता है।

निम्नलिखित सारणी से आप भुगतान- संतुलन के विभिन्न खातों तथा अवधारणाओं को समझ सकते हैं

सारणी 11.1 : भुगतान-संतुलन के विभिन्न खातें

खातों के प्रकार	क्रेडिट (लेनदारियाँ) प्राप्ति	डेबिट (देनदारियाँ) भुगतान
वस्तु-खाता	दृश्य वस्तुओं का निर्यात	दृश्य वस्तुओं का आयात
सेवा-खाता	अदृश्य मदों या सेवाओं का निर्यात (क) परिवहन, बैंकिंग तथा बीमा सेवाओं से प्राप्ति (ख) विदेशियों द्वारा देश में पर्यटन, यात्रा सेवाएँ, वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद से हुई प्राप्ति (ग) देश में पढ़ रहे विदेशियों द्वारा हुई प्राप्ति (घ) डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक इत्यादि विशेषज्ञों की सेवाओं से विदेश में हुई प्राप्ति (ङ) विदेशी सरकार द्वारा दूतावासों और उनके स्टाफ पर व्यय (च) भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में किए गए दीर्घकालिक निवेशों से प्राप्त ब्याज, लाभ, लाभांश तथा रायल्टी	अदृश्य मदों या सेवाओं का आयात (क) परिवहन, बैंकिंग तथा बीमा सेवाओं के लिए विदेशी देश का भुगतान (ख) पर्यटन, यात्रा सेवा, वस्तुओं एवं सेवाओं की भारतीय पर्यटकों द्वारा विदेशों में खरीद पर व्यय (ग) विदेशों में पढ़ रहे छात्रों द्वारा किया गया व्यय (घ) विदेशी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिकों द्वारा सेवाओं पर हुए भुगतान (ङ) घरेलू सरकार द्वारा दूतावास व स्टाफ पर व्यय (च) विदेशी कंपनियों द्वारा देश में किए गए दीर्घकालिक निवेशों से प्राप्त ब्याज, लाभ, लाभांश तथा रायल्टी का भुगतान
एकपक्षीय हस्तांतरण खाता	विदेशी सरकारों या निजी व्यक्तियों से प्राप्त उपहार, दान, अनुदान, सहायता इत्यादि।	घरेलू देश की सरकार या निजी व्यक्तियों द्वारा विदेशी सरकारों या व्यक्तियों को दिए गए उपहार, दान, सहायता इत्यादि।
दीर्घकालिक पूँजी खाता	(क) विदेश के नागरिकों तथा कम्पनियों द्वारा किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (ख) विदेशी नागरिकों तथा फर्मों द्वारा घरेलू प्रतिभूतियाँ, बांडों, शेयरों इत्यादि में किया गया पोर्टफोलियो निवेश (ग) घरेलू सरकार द्वारा विदेशी सरकारों या संस्थाओं से किया गया उधार	(क) घरेलू नागरिकों तथा कम्पनियों द्वारा विदेशों में किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (ख) घरेलू नागरिकों तथा फर्मों द्वारा विदेशों में प्रतिभूतियाँ, बांडों, शेयरों इत्यादि में किया गया निवेश (ग) विदेशी सरकारों द्वारा देश से लिया गया उधार

भूल-चूक, जिसमें अल्पकालिक पूँजी खाता सम्मिलित हो	(क) एक वर्ष से कम की अवधि के लिए विदेशों से प्राप्त बैंक जमाएँ इत्यादि। (ख) अप्रमाणित व्यवसायों से प्राप्तियाँ	(क) एक वर्ष से कम की अवधि के लिए विदेशी देश को किए गए अल्पकालिक बैंक हस्तांतरण (ख) अप्रमाणित व्यवसायों में किया गया भुगतान
(6) अंतर्राष्ट्रीय तरलता अनुपात	(क) सोने का निर्यात (ख) विदेशी मुद्रा भण्डार में कमी (ग) मित्र देशों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से उधार	(क) सोने का अयात (ख) विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि (ग) विदेशी देशों को उधार

एक देश द्वारा परिवहन, बैंकिंग तथा बीमा सेवाओं से प्राप्त आय; पर्यटन, यात्रा सेवाएँ, विदेशी पर्यटकों द्वारा किए गए व्यय, विदेशी छात्रों द्वारा देश में किए गए व्यय; विदेशी सरकारों द्वारा उनके दूतावासों इत्यादि पर हुए व्यय; देश के डॉक्टरों, इंजीनियरों आदि विशेषज्ञों की प्राप्ति; विदेशी देश से ब्याज, लाभ, लाभांश तथा रायल्टी के रूप में प्राप्त 'निवेश आय' सभी मिलाकर सेवा खाते पर या अदृश्य मदों से प्राप्त आय है। जबकि इन सभी अदृश्य मदों पर होने वाले व्यय एक देश के सेवाओं पर हुए भुगतानों को दर्शाता है। यदि सेवाओं के निर्यात (प्राप्तियों) तथा आयात (भुगतानों) का अंतर धनात्मक है तो यह उस देश के पक्ष में होगा और यदि भुगतान प्राप्तियों से अधिक है तो उस देश के सेवा-खाते पर घाटा होगा।

3 एक पक्षीय हस्तांतरण खाता (Unilateral Transfer Account)

इस खाते में सभी प्रकार के उपहार, अनुदान, सहायता इत्यादि सम्मिलित है। यह दो प्रकार का हो सकता है; एक सरकारी और दूसरा निजी। विदेश आर्थिक सहायता और अनुदान, या विदेश सैनिक सहायता और अनुदान एक देश की प्राप्तियों में सम्मिलित होगा, जबकि इस देश द्वारा दूसरे देशों को दी गयी आर्थिक तथा सैनिक सहायता व अनुदान उसके भुगतानों में सम्मिलित होंगे। चूँकि इनके बदले किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता है और यह सिर्फ एकपक्षीय प्रवाह को दर्शाता है, इसलिए इसे एकपक्षीय हस्तांतरण प्राप्तियाँ या भुगतान कहा जाता है।

4 दीर्घकालिक पूँजी खाता (Long term Capital Account)

इसके अंतर्गत उन विनियोगों को सम्मिलित किया जाता है जो एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किए जाते हैं। इस खाते को तीन भागों में बाँटा जा सकता है

- (क) निजी प्रत्यक्ष निवेश
- (ख) निजी पोर्टफोलियो निवेश
- (ग) सरकारी उधार या ऋण

यदि देश के नागरिकों तथा कम्पनियों द्वारा विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश किया जा रहा है तो यह डेबिट पक्ष (देनदारियों) में सम्मिलित होगा तथा यदि विदेशी नागरिक तथा कम्पनियाँ घरेलू देश में प्रत्यक्ष निवेश कर रही हैं तो यह भुगतान-संतुलन के क्रेडिट-पक्ष (लेनदारियों) में सम्मिलित होगा।

इसी प्रकार, देश के नागरिकों तथा कम्पनियों द्वारा विदेशी प्रतिभूतियों या स्टॉक या बॉन्ड या शेयर में किया गया निवेश डेबिट तथा विदेशियों द्वारा घरेलू प्रतिभूतियों, स्टॉक, बांड, शेयर इत्यादि में किया गया निवेश क्रेडिट पक्ष में सम्मिलित होगा।

प्रत्यक्ष निजी निवेश में पूँजी प्रवाह घरेलू देश और विश्व के अन्य देशों में लाभ दर के अंतर पर निर्भर करती है। यदि घरेलू पदेश में लाभ की दर (Profit rate) शेष विश्व से अधिक है तो देश के अंदर प्रत्यक्ष विदेश निवेश के रूप में पूँजी का अंतर्प्रवाह बढ़ेगा। इसी प्रकार, पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत पूँजी का अंत या बाह्य प्रवाह घरेलू देश और

शेष-विश्व में ब्याज दर, लाभांश या पूँजी पर प्रतिफल की दर के बीच अंतर पर निर्भर करेगा। यदि घरेलू देश द्वारा विदेशी सरकार या देश को ऋण दिया जाता है तो वह भुगतान-संतुलन के डेबिट तथा यदि विदेशी देश द्वारा घरेलू देश को ऋण दिया जाता है तो क्रेडिट पक्ष में सम्मिलित होगा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दीर्घकालिक पूँजी खाता देश के अंदर या बाहर नए पूँजी प्रवाह को सम्मिलित करता है। पूर्व के कल दीर्घकालिक पूँजी निवेश का प्रभाव सेवा खाते के पूँजी सेवाओं से प्राप्त आय (निवेश आय) पर पड़ता है। यदि एक देश ऋण देने वाला और विदेशों में अत्यधिक पूँजी निवेश करने वाला देश है उसका दीर्घकालिक पूँजी खाते में घाटा हो सकता है परन्तु इससे सेवा खते में उसकी निवेश आय का प्राप्तियाँ बढ़ती है और यदि एक देश उधार लेने वाला और अत्यधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला देश है तो इससे उसके पूँजी खाते में अतिरेक होगा, परन्तु इससे निवेश आय के रूप में उस देश के भुगतान में वृद्धि होगी और सेवा खाते में वह घाटे का सामना कर सकता है।

5 अल्पकालिक पूँजी खाता (Short term Capital Account)

इस खाते के अंतर्गत वे अल्पकालिक पूँजी मदें आती हैं। जोकि एक वर्ष से कम की अवधि के लिए होती है। इसके अंतर्गत बैंक जमाएं, सरकारों के अल्पकालीन बांड और अन्य अल्पकालिक भुगतान तथा प्राप्तियाँ आती हैं। अल्पकालिक पूँजी लेन-देन में ज्यादातर हिस्सा व्यापार तथा वाणिज्य के वित्तियन के लिए बैंक हस्तांतरण होते हैं।

कुछ देशों में, अल्पकालिक पूँजी खाते को 'भूल-चूक' (Error and Omissions) खाता भी कहा जाता है। कुल देशों में इसे 'गैर विवरणी लेन-देन खाता' (Unrecorded transactions) कहते हैं।

इन खातों में अल्पकालिक पूँजी लेन-देन के अतिरिक्त निम्नलिखित मदें सम्मिलित होती हैं

(क) सांख्यिकीय और विवरणीय भूल (Statistical & Recording Errors)

(ख) स्मगलिंग

(ग) गैर-कानूनी तथा गोपनीय पूँजी प्रवाह

(घ) अपूर्ण अनुमान प्रक्रिया (Imperfect Estimation Procedures)

वास्तव में 'भूल-चूक' एक तरह से अप्रमाणित व्यवसायों से संबंधित लेन-देन को दर्शाते हैं।

6 अन्तर्राष्ट्रीय तरलता खाता (International Liquidity Account)

यह खाता भुगतान संतुलन के घाटे या अतिरेक के समायोजन से संबंधित है जो कि सीधे तौर पर विदेशी रिजर्वों में परिवर्तन को दर्शाता है। इसलिए यह एक तरह से आधिकारिक व्यवस्थापन खाता (Official Settlement Account) है। यह खाता अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के व्यवस्थापन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य सभी साधनों को सम्मिलित करता है।

यदि एक देश के ऊपर से सभी पांच खातों की प्राप्तिओं का योग उसके कुल भुगतानों से कम है तो इसका अर्थ यह है कि डेबिट भुगतान के क्रेडिट प्राप्तिओं से अधिक देने के कारण इसे भुगतान-संतुलन में घाटे का सामना करना पड़ रहा है। इस घाटे को पूरा करने के लिए यह देश निम्नलिखित में से किसी एक उपाय या तीनों उपायों का सहारा ले सकता है

(क) घाटे के बराबर सोने का निर्यात या बिक्री

(ख) घाटे के बराबर पहले से संचित विदेशी मुद्रा भण्डार में से निकासी

(ग) घाटे के बराबर, मित्र देशों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अल्पकालिक या दीर्घकालिक उधार।

इस प्रकार, ऊपर के पांच खातों पर हुए घाटे का वित्तीयन किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाते में क्रेडिट पक्ष में प्राप्तियों को दर्शाना उसी मात्रा में उस वर्ष में भुगतान-शेष के घाटे को बताता है।

ठीक इसी प्रकार यदि एक देश में भुगतान-संतुलन के पांच खातों की प्राप्तियों का योग उसके भुगतानों से अधिक है तो यह उसके भुगतान-शेष के अतिरेक को दर्शाता है और उतनी मात्रा के बराबर अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाते के डेबिट पक्ष में भुगतान को दर्शाया जाएगा। यह डेबिट या भुगतान निम्नलिखित रूप में हो सकता है

(क) अतिरेक के बराबर सोने की खरीद या आयात

(ख) विदेशी मुद्रा भण्डार में अतिरेक के बराबर वृद्धि

(ग) दूसरे देशों को, अतिरेक के बराबर के ऋण।

11.5 भुगतान संतुलन का मापन तथा विभिन्न अवधारणाएं

1 व्यापार संतुलन (Balance of Trade)

जेम्स ई0 मीड तथा कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार व्यापार संतुलन निर्यातित तथा आयातित वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतर होता है। यदि एक देश के वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात उसके वस्तुओं और सेवाओं के कुल आयात से अधिक है तो व्यापार-संतुलन अतिरेक में या उस देश के पक्ष में होगा, परन्तु यदि कम है तो व्यापार-संतुलन में घाटा होगा, और यह स्थिति उस देश के प्रतिकूल होगी। सारणी 11.2 में, व्यापार शेष का घाटा 250 करोड़ के बराबर है। कुछ अर्थशास्त्री सिर्फ व्यापारिक या दृश्य वस्तुओं के निर्यात तथा आयात के अन्तर को अर्थात् सिर्फ 'वस्तु-खाता' के अन्तर को ही व्यापार-संतुलन के रूप में परिभाषित करते हैं।

सारणी 11.2 : भुगतान संतुलन की सारणी (करोड़ रुपये में)

	मुख्य खाते	क्रेडिट (प्राप्तियाँ)	डेबिट (भुगतान)	शुद्ध अतिरेक या घाटा
1.	वस्तु खाता	500	800	-300
2.	सेवा खाता	350	300	+50
I	व्यापार शेष(1+2)	850	1100	-250
3.	एक पक्षीय हस्तांतरण खाता	150	100	+50
II	चालू खाते पर भुगतान संतुलन(1+2+3)	1000	1200	-200
4.	दीर्घकालिक पूँजी खाता	300	175	+125
III	आधारभूत संतुलन (1+2+3+4)	1300	1375	-75
5.	अल्पकालिक पूँजी खाता	75	50	+25
IV	पूँजी खाते पर भुगतान संतुलन(4+5)	375	225	+150

V.(II+IV)	कुल भुगतान संतुलन(1+2+3+4+5)	1375	1425	-50
6.	अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाता (विदेशी मुद्रा भण्डार में शुद्ध परिवर्तन)	50	-	-
VI	भुगतान संतुलन (लेखांकन संतुलन)	1425	1425	00

भारत में भी व्यापार-संतुलन का अर्थ वस्तु-खाते का अन्तर है अर्थात् सिर्फ वस्तुओं के निर्यातों और आयातों का अन्तर। सारणी 11.2 में वस्तु खाता में 300 करोड़ का घाटा है जो कि व्यापार-संतुलन के घाटे को दिखा रहा है। यदि वस्तुओं का निर्यात वस्तुओं के आयात से अधिक होगा तो व्यापार-संतुलन में अतिरेक होगा और यह स्थिति देश के लिए अनुकूल होगी। परन्तु मीड के अनुसार व्यापार शेष की इस परिभाषा का महत्व कम है और राष्ट्रीय आय की गणना की दृष्टि से यह व्यापार शेष को मापने का गलत तरीका है। राष्ट्रीय आय की गणना में शुद्ध निर्यात या वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातों और आयातों का अंतर (X-M) सम्मिलित होता है, गणितीय रूप में

$$Y=C+I+G+(X-M)$$

(X-M) या व्यापार-संतुलन राष्ट्रीय में हुई शुद्ध वृद्धि को बताता है।

2 चालू खाते पर भुगतान संतुलन

वस्तु खाता, सेवा खाता तथा एकपक्षीय हस्तांतरण खाता को सम्मिलित रूप से चालू खाते पर भुगतान संतुलन कहा जाता है। चालू खाते पर भुगतान-संतुलन शुद्ध विदेशी प्राप्तियों को दर्शाता है क्योंकि यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशी व्यापार के योगदान को बताता है। चालू खाता किसी भी देश के व्यापार से प्राप्त अर्जन (earning) तथा कुल व्ययों (spendings) को दर्शाता है। इस प्रकार चालू खाते का अतिरेक या घाटा किसी भी देश के भुगतान-संतुलन की स्थिति जानने का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। सारणी 11.2 में चालू खाते पर 200 करोड़ का घाटा है जोकि देश के लिए प्रतिकूल स्थिति को बताता है।

3 पूँजी खाते पर भुगतान-संतुलन

दीर्घकालिक पूँजी खाता और अल्पकालिक पूँजी खाता का योग पूँजी खाते पर भुगतान-संतुलन होता है। इस प्रकार एक देश के पूँजी तथा निवेश से संबंधित सभी प्रकार के लेन-देन (चाहे वे निजी हों या सरकारी, दीर्घकालिक हो या अल्पकालिक, प्रत्यक्ष या पोर्टफोलियो, व्यक्तिगत या संस्थागत) भुगतान-संतुलन के पूँजी खाते के अंतर्गत आएं। सारणी 11.2 में पूँजी खाते पर 150 करोड़ का अतिरेक है जो यह बताता है कि यह देश विश्व के शेष देशों में पूँजी निवेश या उधार लेने वाला देश है। जिससे भविष्य में इसके सेवा खाते में निवेश आय बढ़ेगी।

4 आधारभूत संतुलन

चालू खाते पर भुगतान-संतुलन तथा दीर्घकालिक पूँजी खाते का योग भुगतान-संतुलन का आधारभूत संतुलन कहा जाता है। इसमें अल्पकालिक पूँजी खाता सम्मिलित नहीं किया जाता है। सारणी 11.2 में आधारभूत संतुलन में 75 करोड़ का अतिरेक है।

5 कुल भुगतान संतुलन

चालू खाते तथा पूँजी खाते पर भुगतान-संतुलन का योग कुल भुगतान संतुलन को बताता है। यह एक देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक लेन-देन को सम्मिलित करता है। यदि भुगतान-संतुलन की कुल प्राप्तियाँ उसके भुगतानों से अधिक है तो भुगतान-संतुलन घाटे में होगा। सारणी 11.2 में कुल भुगतान संतुलन में 50 करोड़ का घाटा है, जोकि चालू खाते के घाटे के कारण है, जोकि इस देश के लिए प्रतिकूल स्थिति को बताता है। परन्तु कुल भुगतान-संतुलन का घाटा या अतिरेक उस देश के लिए बेहतर है या प्रतिकूल स्थिति को दर्शाता है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि चालू खाते और पूँजी-खाते पर भुगतान-संतुलन की स्थिति क्या है? यदि भुगतान-संतुलन का अतिरेक चालू खाते के अतिरेक के कारण है, परन्तु पूँजी-खाते के अतिरेक के कारण नहीं है तो यह स्थिति उस देश के लिए अनुकूल हो सकती है। इसी प्रकार, यदि भुगतान-संतुलन का कुल घाटा चालू खाते के घाटे के कारण है न कि पूँजी खाते के कारण तो यह उस देश के लिए प्रतिकूल स्थिति हो सकती है।

6 लेखांकन भुगतान संतुलन

जब कुल भुगतान-संतुलन के असंतुलन (अतिरेक या घाटा) को दूर करने के लिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाता जोड़ दिया जाता है तो लेखांकन की दृष्टि से भुगतान-संतुलन की समस्त प्राप्तियाँ (क्रेडिट-लेनदारियाँ) तथा भुगतानों (डेबिट-देनदारियाँ) के बराबर जो जाती है और भुगतान संतुलन, संतुलन में हो जाता है। उल्लेखनीय है कि लेखांकन या बही खाता (Book-Keeping) की दृष्टि से भुगतान-संतुलन सदैव संतुलित होना चाहिए अर्थात् क्रेडिट और डेबिट पक्ष सदैव संतुलन में होते हैं। सारणी 11.2 में भुगतान-संतुलन के पाँच खातों में हुए समस्त लेन-देन में भुगतान (डेबिट), प्राप्तिओं से 50 करोड़ अधिक है अर्थात् भुगतान-शेष में 50 करोड़ का घाटा है। 50 करोड़ के बराबर की राशि अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाते के क्रेडिट पक्ष में सम्मिलित होगी जिससे कि भुगतान-संतुलन लेखांकन की दृष्टि से संतुलन में हो जाए। इसके लिए यह देश निम्नलिखित में से कोई भी उपाय कर सकता है, या तीनों के संयोग का सहारा ले सकता है -

- (क) वह '50 करोड़ के बराबर सोने का निर्यात करे, या
- (ख) देश के विदेशी मुद्रा भण्डार से '50 करोड़ का निकाले या
- (ग) मित्र देशों या संस्थानों से '50 करोड़ के बराबर उधार ले।

यदि उस देश के भुगतान-संतुलन के पाँच खातों को मिलाकर 50 करोड़ का अतिरेक होता तो भुगतान-संतुलन को लेखांकन की दृष्टि से संतुलित करने के लिए वह 50 करोड़ के बराबर अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाते के डेबिट पक्ष में सम्मिलित करेगा। वह देश इस अतिरेक को निम्नलिखित तरीके से खत्म कर सकता है।

- (क) 50 करोड़ के बराबर सोने की खरीद या आयात, या
- (ख) देश के विदेशी मुद्रा भण्डार में 50 करोड़ के बराबर वृद्धि, या
- (ग) जरूरतमंद देशों को 50 करोड़ के बराबर उधार देकर या विदेशी आय अर्जन या अल्पाकालिक परिसम्पत्तियाँ खरीद सकती है।

इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाता भुगतान संतुलन को लेखांकन की दृष्टि से समायोजन करता है।

7 भुगतान-संतुलन तथा व्यापार-संतुलन में अन्तर

जैसा कि आपने देखा कि किसी देश का भुगतान शेष उसके किसी एक वर्ष में किए गए वस्तुओं सेवाओं तथा पूँजी के समस्त प्रकार के लेन-देन की प्राप्तियाँ और भुगतानों का व्यवस्थित रिकार्ड होता है। इस प्रकार भुगतान-संतुलन के अंतर्गत लेनदारियाँ तथा देनदारियों की समस्त मदें सम्मिलित होती हैं, जिनके कारण एक देश को भुगतान प्राप्त होते हैं या शेष विश्व को भुगतान करने पड़ते हैं।

जबकि एक देश का व्यापार-संतुलन का सम्बन्ध सिर्फ दृश्य वस्तुओं के निर्यातित तथा आयातित मूल्यों का अंतर होता है। इस अर्थ में व्यापार शेष का कोई विश्लेषणात्मक महत्व नहीं है। यदि व्यापार शेष को मीड के

अर्थों में लिया जाय तो इसमें दृश्य और अदृश्य सेवाएँ वस्तुओं दोनों सम्मिलित होंगी। अर्थात् तब व्यापार शेष निर्यातित तथा आयातित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का अंतर होगा। और इस अर्थ में, व्यापार शेष का राष्ट्रीय आय के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

स्पष्ट है कि व्यापार शेष, अपने दोनों ही अर्थों में भुगतान-संतुलन का एक हिस्सा हैं। भुगतान संतुलन एक बड़ी संकल्पना है जबकि व्यापार शेष उससे छोटी संकल्पना है। वास्तव में व्यापार-संतुलन किसी देश के भुगतान-संतुलन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अनुकूल भुगतान-शेष की स्थिति में भी व्यापार शेष प्रतिकूल हो सकता है। और यह स्थिति उस देश के विरुद्ध हो सकती है। जबकि प्रतिकूल भुगतान-शेष की स्थिति में भी व्यापार-संतुलन अनुकूल हो सकता है और यह स्थिति उस देश के लिए अनुकूल हो सकती है।

11.6 भुगतान संतुलन का स्वायत्त तथा समायोजक लेनदेन (Autonomous and Accommodating transactions)

यदि कोई लेन-देन, भुगतान-संतुलन के अन्य मदों के आकार को ध्यान में रखे बिना होता है तो उसे स्वायत्त लेन-देन कहते हैं अर्थात् भुगतान-संतुलन के किसी भी खाते में जो लेन-देन स्वायत्त ढंग से होता है। इसे 'रेखा के ऊपर का लेन-देन' भी कहते हैं। भुगतान-शेष के प्रारम्भिक पांच खातों - वस्तु खाता, सेवा खाता, एकपक्षीय हस्तांतरण खाता, दीर्घकालिक ओर अल्पकालिक पूँजी खाता- में हुए लेन-देन 'स्वायत्त' या 'रेखा के ऊपर' का लेन-देन कहे जाते हैं। ये लेन-देन स्वायत्त आर्थिक गतिविधियों के फलस्वरूप होते हैं और ये भुगतान संतुलन की स्थिति से स्वतंत्र होते हैं अर्थात् भुगतान-संतुलन के अतिरेक या घाटे को ध्यान में रखते हुए ये लेन-देन नहीं होते हैं बल्कि उससे पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं।

छठा खाता, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाता है, समायोजक लेन-देन खाता है। जो कि भुगतान-शेष की स्थिति पर निर्भर करता है। यह भुगतान-संतुलन की स्थिति का परिणाम है। जबकि 'स्वायत्त' लेन-देन भुगतान-संतुलन की स्थिति का कारण होता है। 'स्वायत्त' लेन-देन के कारण ही भुगतान संतुलन में असंतुलन (अतिरेक या घाटा) पैदा होता है और इसी असंतुलन को दूर करने के लिए समायोजक लेन-देन खाते का सहारा लिया जाता है। इस लेन-देन की मात्रा स्वायत्त लेन-देन के कारण भुगतान-संतुलन में हुए अतिरेक या घाटे की मात्रा पर निर्भर करती है। समायोजक लेन-देन को 'रेखा के नीचे' का लेन-देन भी कहते हैं।

यदि कोई सोना निर्यातक देश दूसरे देश को सोने का निर्यात करता है तो यह उसके वस्तु-खाते के अंतर्गत उसकी प्राप्ति में जुड़ेगा। यहाँ सोने का निर्यात एक स्वायत्त गतिविधि के रूप में या चालू खाता लेन-देन के रूप में है। परन्तु यदि एक देश अपने देश के भुगतान-शेष के असंतुलन (घाटे) को दूर करने के लिए सोने का निर्यात करता है तो यह उसके अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाते के क्रेडिट पक्ष में अंकित होगा और यह समायोजक लेन-देन होगा। इसी प्रकार यदि एक देश अपने मित्र देश से या विश्व बैंक से अपने आधारीक संरचना (सड़क, सीवर, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि) के विकास के लिए उधार लेता है तो यह एक स्वायत्त लेन-देन है जो कि दीर्घकालिक पूँजी खाते के अंतर्गत क्रेडिट के रूप में सम्मिलित होगा। परन्तु यदि यह देश अपने स्वायत्त लेन-देन के फलस्वरूप उत्पन्न भुगतान-संतुलन के घाटे को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष, विश्व बैंक या किसी अन्य से उधार लेता है तो यह 'समायोजक' लेन-देन के अंतर्गत आएगा और उस देश के अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाता में क्रेडिट के रूप में सम्मिलित होगा।

परन्तु 'स्वायत्त' तथा 'समायोजक' लेन-देन के मध्य स्पष्ट अन्तर करना आसान नहीं है। कोई भी देश अपने भुगतान-संतुलन की स्थिति को देखते हुए चालू खाते या पूँजी खाते पर इस प्रकार से लेन-देन कर सकता है कि भुगतान संतुलन में असंतुलन उत्पन्न न हो। फिर भी, लेखांकन के उद्देश्य से चालू तथा पूँजी खाते पर होने वाले

समस्त लेन-देनों को स्वायत्त तथा अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाते के लेन-देन को 'समायोजक लेन-देन' कहना तर्कसंगत होगा। स्वायत्त लेन-देन के किसी भी असंतुलन के वित्तीयन के लिए जान बूझकर किए जाने वाले लेन-देन समायोजक लेन-देन होता है।

भुगतान-संतुलन में अतिरेक या घाटा स्वायत्त लेन-देनों का परिणाम है। यदि एक देश के स्वायत्त भुगतानों का मूल्य स्वायत्त प्राप्तियों के मूल्य से अधिक है, अर्थात् भुगतान-संतुलन में घाटा है तो सामान्यतया इसे उस देश के लिए प्रतिकूल या ऋणात्मक स्थिति माना जाता है और यदि स्वायत्त प्राप्तियाँ, स्वायत्त भुगतानों से अधिक है, अर्थात् भुगतान शेष में अतिरेक होता है तो उसे उस देश के लिए धनात्मक या अनुकूलतम स्थिति माना जाता है। परन्तु वास्तव में भुगतान संतुलन का अतिरेक या घाटा उस देश के लिए अच्छा या बुरा यह उसकी 'स्थिति' (location) तथा 'अवधि' (duration) पर निर्भर करेगा।

यदि भुगतान-संतुलन के चालू खाते में अतिरेक है तो सामान्यतया यह अनुकूल स्थिति को दर्शाता है क्योंकि चालू खाते का अतिरेक एक देश को निर्यातों से कुल विदेशी मुद्रा की अर्जन-क्षमता (earning capacity) को दिखाता है। परन्तु यदि पूँजी खाते पर अतिरेक है तो यह उस देश के लिए अनुकूल स्थिति नहीं भी हो सकती है क्योंकि पूँजी खाते का अतिरेक उसके उधार लेने की क्षमता को बताती है। जोकि उसके भविष्य की देनदारियों को बढ़ाती है। परन्तु यदि एक देश उधार या विदेशी निवेश से अपनी उत्पादक क्षमता में वृद्धि करने में सफल रहता है और ऋणात्मक ब्याज अदायगी की उसकी क्षमता बढ़ जाती है तो पूँजी खाते का घाटा भी उसके लिए अच्छा हो सकता है।

इसी प्रकार, चालू खातों का घाटा एक देश की प्रतिकूल स्थिति को दर्शाता है क्योंकि विदेशी मुद्रा की प्राप्तियों की अपेक्षा उसका भुगतान अधिक है जबकि प्रतिकूल चालू खाता घाटा उस देश के लिए अनुकूल भी हो सकता है क्योंकि पूँजी खाते का घाटे का तात्पर्य है कि देश ऋण-प्रदाता देश है या पूँजी-निवेशक है। जोकि बाद में ब्याज, लाभ, लाभांश, रॉयल्टी आदि के रूप में पूँजी के अंतप्रवाह में वृद्धि करके चालू खाते पर प्राप्तियाँ में वृद्धि करेगा, जिसका कि भुगतान-संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव होगा।

यदि भुगतान शेष का घाटा अस्थायी प्रकृति का है। तो इससे इसका कोई गम्भीर नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। परन्तु यदि भुगतान संतुलन का घाटा स्थायी प्रकृति का या मूलभूत प्रकृति का है। तो यह अर्थव्यवस्था के लिए काफी खराब है। विशेष रूप से यदि यह चालू खाते के असंतुलन से उत्पन्न हुआ है। चालू खाते के अल्पकालिक असंतुलन को अल्पकालिक या दीर्घकालिक विदेशी उधारों के द्वारा दूर किया जा सकता है। परन्तु यदि चालू खाते का घाटा कई वर्षों तक लगातार बना रहता है तो इसे सिर्फ अल्पकालिक और दीर्घकालिक विदेशी उधारों से दूर नहीं किया जा सकता है और न ही करना चाहिए। भुगतान-शेष के इस प्रकार के आधारभूत घाटे को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था में 'संरचनात्मक समायोजन' की आवश्यकता होती है। जिससे की घाटा उत्पन्न करने वाले मूल कारकों को नियंत्रित या दूर किया जा सके।

यदि चालू खाते पर अतिरेक है तो सामान्यतया इसे अच्छा माना जाता है। यदि अतिरेक अस्थायी हो और इस अतिरेक का उपयोग पूँजी खाते के घाटे को समाप्त करने या निवेश आय के बहिर्गमन के प्रभाव को कम करने या पुराने ऋणों को चुकाने में होता है। तो इसका प्रभाव अच्छा होगा। परन्तु यदि चालू खाते का अतिरेक लगातार कई वर्षों से बना हुआ है और यह पूँजी-खाते के घाटे से अधिक है तो इससे अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा रिजर्व भण्डार में वृद्धि होने से मुद्रा-आपूर्ति बढ़ सकती है और इससे अर्थव्यवस्था में स्फितिकारी दबाव उत्पन्न हो सकते हैं। साथ ही इससे घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के मुकाबले बढ़ने से (विनिमय दर में मूल्य वृद्धि से) देश के निर्यातों की कीमत विश्व बाजार में बढ़ जाएगी और आयात सस्ते होंगे। जिससे निर्यात कम होगा और आयात बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था पर चालू खाते के अतिरेक का ठीक-ठीक प्रभाव विनिमय दर नीति, मौद्रिक और राजकोषीय

नीति तथा विनिमय नियंत्रण नीति पर निर्भर करेगा। इस प्रकार भुगतान शेष का लगातार और स्थायी अतिरेक अर्थव्यवस्था पर हमेशा अच्छे प्रभाव होगा यह आवश्यक नहीं है।

11.7 भुगतान-संतुलन का असंतुलन

लेखा के अर्थ में किसी देश का भुगतान-संतुलन एक दिए हुए समय में आर्थिक लेन-देन जो कि वह शेष विश्व से करता है, का क्रमबद्ध विवरण है। और लेखा के अर्थ में यह सदैव ही संतुलित रहता है। जब विदेशी विनिमय की स्वायत्त पूर्ति (प्राप्तियाँ) एवं स्वायत्त माँग (भुगतान) बराबर हो तो भुगतान संतुलन में संतुलन होता है। परन्तु यदि भुगतान-संतुलन में अतिरेक या घाटा है तो दोनों ही दशाएँ असंतुलन की स्थिति को व्यक्त करती हैं। जब विदेशी विनिमय की स्वायत्त पूर्ति, स्वायत्त माँग से अधिक है तो अतिरेक तथा जब विदेशी विनिमय की स्वायत्त पूर्ति, स्वायत्त माँग से कम है तो भुगतान संतुलन में घाटा होगा।

भुगतान-संतुलन में असंतुलन किसी भी देश की आन्तरिक अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के दृष्टिकोण से भी चिंताजनक माना जाता है। परन्तु अतिरेक की अपेक्षा घाटा अधिक चिंताजनक होता है क्योंकि भुगतान-संतुलन में असंतुलन का बोझ अतिरेक वाले देश की तुलना में घाटे वाले देश पर अधिक पड़ता है।

भुगतान-संतुलन का निपटान (Settlement) तथा समायोजन (Adjustment)

जब भुगतान-संतुलन के असंतुलन को अंतर्राष्ट्रीय तरलता खातों या समायोजित लेन-देन के द्वारा दूर किया जाता है तो यह भुगतान-संतुलन का निपटान (settlement) कहा जाता है। यह भुगतान-संतुलन को लेखांकन की दृष्टि से संतुलन में लाने का एक अस्थायी उपाय है। वास्तव में इससे असंतुलन की मूलभूत समस्या का समाधान नहीं होता है।

यदि भुगतान-संतुलन के अतिरेक या घाटे को दूर करने के लिए या नियंत्रित के लिए उन कारकों को नियंत्रित किया जाता है जो कि इस अतिरेक या घाटे के लिए जिम्मेदार है तो इसे भुगतान-संतुलन का समायोजन (adjustment) कहते हैं। अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाते के बिना भुगतान-संतुलन के स्वायत्त लेन-देन में संतुलन ले आना भुगतान-संतुलन समायोजन कहा जाएगा। स्पष्ट है कि भुगतान-संतुलन का समायोजन, निपटान की अपेक्षा अधिक वांछनीय है। यह असंतुलन की समस्या का स्थायी और ठोस समाधान प्रस्तुत करता है परन्तु समायोजन का रास्ता अधिक कठिन और दीर्घकालिक उपाय है।

11.8 भुगतान-संतुलन में असंतुलन के प्रकार

भुगतान-संतुलन में अतिरेक या घाटे के लिए अनेक कारक जिम्मेदार होते हैं, और इसी आधार पर असंतुलन की प्रकृति भी निर्भर करती है।

भुगतान-संतुलन में असंतुलन के निम्नलिखित प्रकार हैं।

1. **अस्थायी या अल्पकालीन असंतुलन-** जब निर्यात मौसमी उतार-चढ़ाव, व्यापार में आकस्मिक परिवर्तन, प्रतिकूल मौसम आदि से प्रभावित होता है तो भुगतान-संतुलन में अल्पकालीन असंतुलन पैदा हो जाता है। प्राथमिक उत्पादनशील और निर्यात करने वाले देशों को ऐसे असंतुलन का सामना करना पड़ता है।
2. **दीर्घकालीन या आधारभूत असंतुलन-** जब किसी देश के भुगतान-संतुलन में असंतुलन लंबे समय तक बना रहता है और उसकी प्रवृत्ति संचयी हो जाती है। उसे आधारभूत असंतुलन कहते हैं। इस असंतुलन का कारण मुद्रापूर्ति में तकनीकी परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि इत्यादि हैं। विकास की प्रारम्भिक अवस्था में

निवेश के लिए या फिर प्रदर्शन-प्रभाव से प्रेरित होकर विकासशील देश उद्योगों के स्थापना के लिए और आयातों के लिए विदेशों से भारी मात्रा में ऋण लेना पड़ता है। जो आगे ब्याज अदायगी और आयात वृद्धि के रूप में भुगतान-संतुलन पर और अधिक नकारात्मक प्रभाव डालता है।

3. चक्रीय असंतुलन (Cyclical Disequilibrium) - व्यापार चक्र की अवस्थाओं के कारण, विभिन्न देशों में जब मंदी और तेजी की स्थिति में भिन्नता हो तो भुगतान संतुलन में चक्रीय असंतुलन उत्पन्न होता है। यदि विभिन्न देशों में व्यापार चक्रों की प्रकृति भिन्न हो या आयातों की माँग की लोचें भिन्न हों तो चक्रीय असंतुलन उत्पन्न होता है।

4. संरचनात्मक असंतुलन (Structural Disequilibrium) - निर्यातों तथा आयातों की माँग तथा पूर्ति के ढाँचे में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न असंतुलन, भुगतान संतुलन का संरचनात्मक असंतुलन कहा जाता है। माँग तथा पूर्ति की संरचना में परिवर्तन के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे-उपभाक्ताओं की रुचि या प्राथमिकता में परिवर्तन, विदेशी पूँजी के प्रवाह में कमी, संसाधनों की कमी इत्यादि।

11.9 भुगतान-संतुलन में असंतुलन के कारण

जैसा की आपने देखा कि असंतुलन की अलग-अलग प्रकृति होती है जो कि उसके कारणों पर निर्भर करती है। विभिन्न देशों में भुगतान-संतुलन में असंतुलन के विभिन्न कारण हो सकते हैं तथा एक ही देश में अलग-अलग समय में असंतुलन के अलग-अलग कारण हो सकते हैं। सामान्यतया निम्नलिखित कारणों से भुगतान-संतुलन में असंतुलन पैदा होता है:

- (1) विकासात्मक व्यय में वृद्धि भुगतान-संतुलन में असंतुलन पैदा होता है। अपनी विकास की प्रारम्भिक अवस्था में सभी देश भारी मात्रा में निवेश करते हैं। परन्तु पर्याप्त मात्रा में पूँजी तथा तकनीकी के अभाव के कारण ये देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों से उधार लेते हैं और मशीनों तथा तकनीकी आदि का आयात करते हैं परन्तु प्राथमिक उत्पादनशील होने के कारण निर्यात में तेज वृद्धि नहीं होती है जिससे भुगतान-संतुलन का घाटा बढ़ता है जिसकी प्रकृति प्रायः संरचनात्मक या आधारभूत प्रकृति की स्थायी होती है।
- (2) चक्रीय उच्चावचन से भुगतान-संतुलन में असंतुलन पैदा होता है। व्यापार चक्र के उच्चावचन के कारण भी विभिन्न देश के भुगतान-संतुलन में असंतुलन पैदा हो जाता है।
- (3) विकासशील देशों में आय में वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग व्यय में हुई वृद्धि प्रायः प्रदर्शन प्रभाव के कारण आयातों में वृद्धि कर देती है।
- (4) अर्थव्यवस्था के भीतर स्फीतिकारी दबाव रहने पर जब कीमतें बढ़ती हैं तो निर्यातों की विश्व बाजार में प्रतियोगी क्षमता कम हो जाती है जबकि आयात आकर्षक हो जाते हैं। दूसरे देशों द्वारा आयातों पर प्रतिबन्ध के कारण निर्यात में वृद्धि नहीं हो पाने से भी असंतुलन पैदा होता है।
- (5) राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर आयातों के बढ़ने की प्रवृत्ति पायी जाती है जिससे भुगतान-संतुलन का घाटा बढ़ता है।
- (6) मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि के कारण जब घरेलू कीमत स्तर बढ़ता है तो आयातित वस्तुओं की माँग में वृद्धि होती है तथा निर्यात मंहगे हो जाते हैं जिससे भुगतान-संतुलन में घाटा होता है।
- (7) तकनीकी परिवर्तन के कारण वस्तुओं की लागतों, कीमतों तथा गुणवत्ता में परिवर्तन होता है जिससे भुगतान-संतुलन प्रभावित होता है।

- (8) विनिमय दर में परिवर्तन से भी भुगतान-संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। घरेलू मुद्रा के विदेशी मुद्रा के मुकाबले अवमूल्यन से निर्यात सस्ते तथा आयात महंगे होंगे जिससे भुगतान-संतुलन में घाटा कम या अतिरेक हो सकता है।
- (9) यदि एक देश बड़े पैमाने पर दूसरे देश को उधार देता है या निवेश करता है उसके पूँजी खाते में घाटा होगा। परन्तु यदि एक देश दूसरे देशों से अधिक उधार लेता है और अधिक विदेशी मुद्रा के निवेश को प्रोत्साहित करता है तो दीर्घकाल में उसके चालू खाते में घाटा काफी बढ़ सकता है क्योंकि ब्याज, लाभ, लाभांश आदि के रूप में पूँजी का बाह्य प्रवाह बढ़ेगा।
- (10) तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण विकासशील देशों में घरेलू उपभोग में वृद्धि होती है। इससे इन देशों में निर्यात की क्षमता कम हो जाती है और आयात बढ़ते हैं।
- (11) राजनीतिक अस्थिरता या घरेलू अर्थव्यवस्था में विश्वास की कमी से विदेशी पूँजी का अंतर्प्रवाह कम हो सकता है/रुक सकता है और बाह्य प्रवाह बढ़ सकता है जो कि गम्भीर भुगतान-संतुलन के असंतुलन को जन्म देता है।

11.10 भुगतान-संतुलन में समायोजन

यदि भुगतान-संतुलन में असंतुलन की स्थिति दीर्घकाल तक बनी रहती है तो यह न सिर्फ उस देश के लिए वरन पूरे विश्व के लिए ठीक नहीं है। अतः एक सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए भुगतान-संतुलन में संतुलन आवश्यक है। असंतुलन को समायोजित करने के लिए एक देश किस प्रकार की आर्थिक नीतियाँ/उपायों को लागू करे, यह उसके भुगतान-संतुलन की स्थिति पर निर्भर करेगा। चूंकि भुगतान-संतुलन का अतिरेक समान्यतया कोई बड़ी समस्या पैदा नहीं करता है और प्रतिकूल या घाटे में भुगतान-संतुलन की अपेक्षा कम हानिकारक है इसलिए भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर विचार करना अधिक आवश्यक है।

भुगतान-संतुलन के घाटे के पूरा करने के लिए आवश्यक है कि स्वायत्त लेन-देन में भुगतानों की अपेक्षा प्राप्तियों में अधिक वृद्धि हो। स्पष्ट है कि असंतुलन को दूर करने के लिए उन मदों या कारकों में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है जो कि भुगतान-संतुलन की प्राप्तियों तथा भुगतानों को प्रभावित करते हैं।

यदि घाटा दीर्घकालिक और स्थायी प्रकृति का है तो इसके लिए भुगतान-संतुलन को प्रभावित करने वाले कारकों को प्रभावित करने के लिए स्थायी सुधारों की आवश्यकता होगी। स्थायी सुधारों की दृष्टिकोण से जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें दो वर्गों में रखा जा सकता है- व्यय घटाने वाली (expenditure reducing) तथा व्यय बदलाव वाली (expenditure switchingswitching)। विस्फिति जैसे उपायों के द्वारा कुल व्यय में कटौती की जाती है जबकि व्यय की दिशा में परिवर्तन के लिए अवमूल्यन प्रशुल्क, कोटा, निर्यात सब्सिडी, विनिमय नियंत्रण जैसे उपायों का सहारा लिया जाता है।

यदि एक देश पहले से कठोर राजकोषीय और मौद्रिक नीति और प्रशुल्क तथा आयात नियंत्रणों का सहारा ले रहा है और फिर भी भुगतान-संतुलन में घाटा है तो ऐसे में उस देश के लिए घाटे से निजात पाना काफी मुश्किल है, ऐसे में यह घाटा संभाव्य घाटा को दिखाता है। इन कठोर नीतियों या उपायों की अनुपस्थिति में घाटा और भी अधिक होगा। ऐसे ही यदि देश में बेरोजगारी का ऊँचा स्तर है तो भी उस देश के लिए सम्भव नहीं होगा कि वह संकुचनकारी मौद्रिक, राजकोषीय तथा अन्य नीतियों के द्वारा घाटे को दूर करने की कोशिश करें। इन स्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय पूँजी का अंतर्प्रवाह ही घाटे को दूर करने का एक बेहतर तरीका है परन्तु यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पूँजी की प्रकृति काफी महत्वपूर्ण है। यदि एक देश दीर्घकालिक पूँजी खाते के अंतर्गत नियोजित ढंग से पूँजी का

आयात करता है तो बिना घरेलू नीतियों में परिवर्तन के लंबे समय तक (15 से 20 वर्ष) भुगतान-शेष के घाटे से निश्चित होकर अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार कर सकता है।

भुगतान-संतुलन के घाटे को दूर करने के लिए कुछ उपायों का हम संक्षेप में वर्णन करेंगे

1. **विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन-** यदि विनिमय दरें परिवर्तनशील है तो विदेशी विनिमय की माँग और पूर्ति की शक्तियाँ स्वयं भुगतान-शेष के असंतुलन को दूर कर देती हैं। घाटे की स्थिति में यदि घरेलू मुद्रा के मूल्य में अन्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले कमी आती है या मूल्यहास होता है तो निर्यात सस्ते तथा आयात महंगे होंगे और यदि आयातों तथा निर्यातों की माँग लोचशील हैं तो इससे भुगतान-संतुलन के घाटे को कम करने में सहायता मिलेगी।
2. **अवमूल्यन -** प्रतिकूल भुगतान-संतुलन को ठीक करने के लिए यदि सरकार अपनी मुद्रा का मूल्य जानबूझकर विश्व की अन्य मुद्राओं के मुकाबले कम कर देती है तो इसे अवमूल्यन कहते हैं और इसका भी प्रभाव मुद्रा के मूल्यहास की ही तरह होगा। मूल्यहास और अवमूल्यन दोनों की ही सफलता आयातों और निर्यातों की माँग की लोच पर निर्भर करेगी।
3. **आय में परिवर्तन-** भुगतान-संतुलन के स्वायत्त लेन-देन चूंकि देश की घरेलू आय से सम्बन्धित होता है इसलिए घरेलू आय में परिवर्तन के द्वारा भी भुगतान-शेष के असंतुलन को दूर किया जा सकता है। घाटे को घरेलू आय में हास या विदेशियों की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके दूर किया जा सकता है क्योंकि घरेलू आय में वृद्धि से आयातों में वृद्धि होती है। घरेलू आय में कमी से आयात में कितनी कमी होगी यह सीमांत आय प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, जो कि विदेशी व्यापार गुणक के मान को निर्धारित करती है।
4. **प्रत्यक्ष नियंत्रण-** भुगतान-संतुलन के घाटे को प्रत्यक्ष नियंत्रण के द्वारा आयातों को नियंत्रित करके भी कम किया जा सकता है। प्रशुल्क,कोटा इत्यादि के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण करके घाटे को कम किया जा सकता है। परन्तु प्रत्यक्ष नियंत्रण बाजार की स्वतन्त्र कार्यप्रणाली में अवरोध उत्पन्न करते हैं।
5. **विनिमय नियंत्रण -** विदेशी विनिमय के समस्त लेन-देन को नियंत्रित करके भी सरकार भुगतान संतुलन के घाटे को ठीक कर सकती है। विनिमय नियंत्रण के तहत सरकार समस्त विदेशी विनिमय को अपने पास जमाकर, फिर उसे राष्ट्रीय प्रायधिकताओं के अनुरूप आवंटित करती है।
6. **आयात-प्रतिस्थापन-** जिन वस्तुओं का एक देश आयात करता है उसे अपने देश में ही उत्पादित करने से आयात कम होते हैं और घाटा कम करने में मदद मिलती है।
7. **निर्यात को प्रोत्साहन-** निर्यातकों को अनेक प्रकार की रियायत देकर निर्यात को बढ़ाया जा सकता है। इससे घाटे में कमी होगी।
8. **विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन-** विदेशी पर्यटकों की संख्या देश में बढ़ाने के लिए पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देकर सेवा खाते पर प्राप्ति में वृद्धि की जा सकती है। जिससे भुगतान संतुलन का घाटा कम होगा।

11.11 अभ्यास हेतु प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न:

1. भुगतान सन्तुलन का अर्थ बताइए?
2. भुगतान संतुलन के अंतर्गत कौन से प्रमुख खाते होते हैं?
3. अन्तर्राष्ट्रीय तरलता खाता से आप क्या समझते हैं?
4. भुगतान-संतुलन तथा व्यापार-संतुलन में अन्तर स्पष्ट कीजिये।

5. 'स्वायत्त' तथा 'समायोजक' लेन-देन के मध्य अन्तर स्पष्ट कीजिये।
6. कुल भुगतान संतुलन के असंतुलन से आप क्या समझाते हैं?
7. लेखांकन की दृष्टि से भुगतान-संतुलन सदैव संतुलित होता है। विवेचना कीजिये।
8. भुगतान-संतुलन का निपटान तथा समायोजन अन्तर स्पष्ट कीजिये।
9. भुगतान-संतुलन में असंतुलन के कारण स्पष्ट कीजिये।
10. भुगतान-संतुलन में असंतुलन के प्रकार बताइए।
11. भुगतान-संतुलन में समायोजन के उपायों पर प्रकाश डालिए।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

1. एक देश का भुगतान सन्तुलन विवरण है।
 - (क) एक वर्ष में आयात-निर्यात का लेखा-जोखा
 - (ख) सेवाओं तथा वस्तुओं के आयात-निर्यात
 - (ग) एक वर्ष पूँजी खाते में सभी प्राप्तियों तथा भुगतानों का
 - (घ) एक वर्ष विशेष में संसार के अन्य देशों के कुल आर्थिक सौदों का लेखा-जोखा
2. भुगतान सन्तुलन में
 - (क) सरकारी एवं गैर-सरकारी दृश्य एवं अदृश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मदें सम्मिलित होती है।
 - (ख) सरकारी एवं गैर-सरकारी दृश्य व्यापार की मदें सम्मिलित होती हैं।
 - (ग) केवल सरकारी दृश्य एवं अदृश्य व्यापार की मदें सम्मिलित होती हैं।
 - (घ) केवल निजी दृश्य व्यापार एवं अदृश्य व्यापार की मदें सम्मिलित होती हैं।
3. निम्न में से कौन सी मद भुगतान सन्तुलन की डेबिट मद नहीं है?
 - (क) वस्तुओं का आयात
 - (ख) सेवाओं का आयात
 - (ग) विदेशों से प्राप्त उपहार
 - (घ) विदेशियों द्वारा खरीदी परिसम्पत्तियाँ
4. भुगतान संतुलन के अंतर्गत मुख्यतः खाते होते हैं।
 - (क) 3
 - (ख) 4
 - (ग) 5
 - (घ) 6
5. अल्पकालिक पूँजी खाता में अल्पकालिक पूँजी लेन-देन के अतिरिक्त निम्नलिखित मद/ मदें सम्मिलित होती हैं
 - (क) सांख्यिकीय और विवरणीय भूल
 - (ख) स्मगलिंग
 - (ग) गैर-कानूनी तथा गोपनीय पूँजी प्रवाह
 - (घ) उपरोक्त सभी
6. आधिकारिक व्यवस्थापन खाता (Official Settlement Account) है।
 - (क) वस्तु-खाता
 - (ख) अन्तर्राष्ट्रीय तरलता खाता
 - (ग) सेवा-खाता
 - (घ) अल्पकालिक पूँजी खाता
7. वस्तु खाता, सेवा खाता तथा एकपक्षीय हस्तांतरण खाता को सम्मिलित रूप से कहा जाता है
 - (क) चालू खाते पर भुगतान संतुलन
 - (ख) पूँजी खाते पर भुगतान संतुलन
 - (ग) भुगतान संतुलन का आधारभूत संतुलन
 - (घ) व्यापार -संतुलन
8. इसमें अल्पकालिक पूँजी खाता सम्मिलित नहीं किया जाता है।
 - (क) पूँजी खाते पर भुगतान संतुलन
 - (ख) भुगतान-संतुलन का आधारभूत संतुलन
 - (ग) कुल भुगतान संतुलन
 - (घ) लेखांकन भुगतान-संतुलन

9. यदि भुगतान-संतुलन का कुल घाटा चालू खाते के घाटे के कारण है न कि पूँजी खाते के कारण तो यह स्थिति उस देश के लिए हो सकती है।
 (क) प्रतिकूल (ख) अनुकूल (ग) कोई बदलाव नहीं होगा।
10. 'रेखा के ऊपर का लेन-देन' नहीं है।
 (क) वस्तु खाता (ख) सेवा खाता
 (ग) अन्तर्राष्ट्रीय तरलता खाता (घ) एकपक्षीय हस्तांतरण खाता
11. चालू खाते पर भुगतान संतुलन में सम्मिलित नहीं किया जाता है।
 (क) वस्तु खाता (ख) सेवा खाता
 (ग) एकपक्षीय हस्तांतरण खाता (घ) अल्पकालिक पूँजी खाता
12. आधिकारिक व्यवस्थापन खाता (Official Settlement Account) है।
 (क) वस्तु-खाता (ख) अन्तर्राष्ट्रीय तरलता खाता
 (ग) सेवा-खाता (घ) अल्पकालिक पूँजी खाता
13. यदि किसी देश के भुगतान-शेष में 100 करोड़ का अतिरेक है तो वह
 (क) मित्र देशों या संस्थानों से 100 करोड़ के बराबर उधार लेगा
 (ख) देश के विदेशी मद्रा भण्डार से 100 करोड़ निकालेगा
 (ग) वह 100 करोड़ के बराबर सोने का निर्यात करेगा
 (घ) वह 100 करोड़ के बराबर सोने का आयात करेगा
14. भुगतान-संतुलन में अल्पकालीन असंतुलन पैदा हो जाता है।
 (क) व्यापार में आकस्मिक परिवर्तन, प्रतिकूल मौसम आदि से
 (ख) जब किसी देश के भुगतान संतुलन में असंतुलन लंबे समय तक बना रहता है
 (ग) व्यापार चक्र की अवस्थाओं के कारण
 (घ) निर्यातों तथा आयातों की मांग तथा पूर्ति के ढांचे में परिवर्तन के फलस्वरूप
15. निम्नलिखित उपाय के द्वारा भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने के लिए कुल व्यय में कटौती की जाती है।
 (क) विस्फिती (ख) अवमूल्यन
 (ग) प्रशुल्क (घ) विनिमय नियंत्रण
16. निम्नलिखित उपाय के द्वारा भुगतान-संतुलन के घाटे को दूर करने के लिए कुल व्यय की दिशा में परिवर्तन किया जाता है।
 (क) निर्यात सब्सिडी (ख) अवमूल्यन
 (ग) कोटा (घ) उपरोक्त सभी
17. भुगतान-संतुलन के घाटे को दूर करने का उपाय नहीं है।
 (क) अवमूल्यन (ख) विदेशी विनिमय की मूल्य वृद्धि
 (ग) घरेलू आय में कमी (घ) विदेशी विनिमय की मूल्यहास
18. भुगतान-संतुलन के घाटे का कारण नहीं है।
 (क) आय में वृद्धि (ख) मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि
 (ग) विकासात्मक व्यय में कमी (घ) चक्रीय उच्चावचन

सत्य व असत्य :

1. यदि घरेलू देश द्वारा विदेशी सरकार या देश को ऋण दिया जाता है तो वह भुगतान-संतुलन के क्रेडिट पक्ष में सम्मिलित होगा।
2. यदि विदेशी देश द्वारा घरेलू देश को ऋण दिया जाता है तो डेबिट पक्ष में सम्मिलित होगा।
3. यदि घरेलू देश में लाभ की दर शेष विश्व से अधिक है तो देश के अंदर प्रत्यक्ष विदेश निवेश के रूप में पूँजी का अंतर्प्रवाह बढ़ेगा।
4. पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत पूँजी का अंत या बाह्य प्रवाह घरेलू देश और शेष-विश्व में ब्याज दर, लाभांश या पूँजी पर प्रतिफल की दर के बीच अंतर पर निर्भर करेगा।
5. भुगतान संतुलन के प्राप्ति में विदेशी विनिमय के सभी प्रकार के अर्जन तथा उधार सम्मिलित होते हैं। जोकि डेबिट मद के रूप में रिकार्ड किया जाता है।
6. ब्याज, लाभ, लाभांश तथा रॉयल्टी को 'निवेश आय' कहा जाता है।
7. जेम्स ई. मीड के अनुसार व्यापार संतुलन निर्यातित तथा आयातित वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतर होता है।
8. यदि भुगतान संतुलन का अतिरेक चालू खाते के अतिरेक के कारण है, परन्तु पूँजी-खाते के अतिरेक के कारण नहीं है तो यह स्थिति उस देश के लिए अनुकूल हो सकता है।
9. लेखांकन या बही खाता (Book-Keeping) की दृष्टि से भुगतान संतुलन सदैव संतुलित होना चाहिए।
10. चालू खाता किसी भी देश के व्यापार से प्राप्त अर्जन (earning) तथा कुल व्ययों (spendings) को दर्शाता है।
11. चालू खाते पर भुगतान-संतुलन तथा दीर्घकालिक पूँजी खाते का योग भुगतान-संतुलन का आधारभूत संतुलन कहा जाता है।
12. यदि चालू खाते का अतिरेक लगातार कई वर्षों से बना हुआ है तो इससे मुद्रा-आपूर्ति बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्था में स्फितिकारी दबाव उत्पन्न हो सकते हैं।
13. भुगतान-शेष के आधारभूत घाटे को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था में 'संरचनात्मक समायोजन' की आवश्यकता नहीं होती है।
14. भुगतान-संतुलन में अतिरेक या घाटा स्वायत्त लेन-देनों का परिणाम नहीं है।
15. अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाता समायोजक लेन-देन खाता है।
16. अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाता भुगतान-संतुलन की स्थिति का परिणाम है।
17. भुगतान-संतुलन, व्यापार-संतुलन का एक हिस्सा है।
18. जब विदेशी विनिमय की स्वायत्त पूर्ति, स्वायत्त माँग से कम है तो भुगतान संतुलन में अतिरेक होगा।
19. जब भुगतान-संतुलन के असंतुलन को अंतर्राष्ट्रीय तरलता खातों या समायोजित लेन-देन के द्वारा दूर किया जाता है तो यह भुगतान-संतुलन का समायोजन (adjustment) कहा जाता है।
20. भुगतान-संतुलन का निपटान भुगतान-संतुलन को लेखांकन की दृष्टि से संतुलन में लाने का एक अस्थायी उपाय है।
21. भुगतान-संतुलन का निपटान से असंतुलन की मूलभूत समस्या का समाधान नहीं होता है।
22. यदि भुगतान-संतुलन के अतिरेक या घाटे को दूर करने के लिए या नियंत्रित के लिए उन कारकों को नियंत्रित किया जाता है जो कि इस अतिरेक या घाटे के लिए जिम्मेदार है तो इसे भुगतान संतुलन का निपटान (settlement) कहते हैं।

23. अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाते के बिना भुगतान संतुलन के स्वायत्त लेन-देन में संतुलन ले आना भुगतान-संतुलन समायोजन कहा जाएगा।
24. भुगतान संतुलन का समायोजन, निपटान की अपेक्षा अधिक वांछनीय है।
25. मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि के कारण भुगतान संतुलन में घाटा होता है।

11.12 सारांश

एक देश का विश्व के अन्य सभी देशों के साथ होने वाले समस्त प्रकार के लेन-देन, चाहे वह वस्तुओं के रूप में हो, सेवाओं के रूप में हो या फिर पूँजी के रूप में, का एक सुव्यवस्थित लेखा भुगतान-संतुलन है। भुगतान संतुलन एक दी हुई समयावधि में किसी देश द्वारा किए गए समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। भुगतान शेष लेखा की दोहरी-प्रविष्टि बहीखाता सिद्धान्त पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक सौदा, बैलेंस शीट में क्रेडिट (लेनदारियाँ या प्राप्तियाँ) तथा डेबिट (देनदारियाँ या भुगतान) पक्ष में दर्ज किया जाता है।

भुगतान शेष लेखा की दोहरी-प्रविष्टि बहीखाता सिद्धान्त पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक सौदा, बैलेंस शीट में क्रेडिट (लेनदारियाँ या प्राप्तियाँ) तथा डेबिट (देनदारियाँ या भुगतान) पक्ष में दर्ज किया जाता है। भुगतान-शेष के प्रारम्भिक पांच खातों- वस्तु खाता, सेवा खाता, एकपक्षीय हस्तांतरण खाता, दीर्घकालिक ओर अल्पकालिक पूँजी खाता- में हुए लेन-देन 'स्वायत्त' या 'रेखा के ऊपर' का लेन-देन कहे जाते हैं। ये लेन-देन स्वायत्त आर्थिक गतिविधियों के फलस्वरूप होते हैं ओर ये भुगतान संतुलन की स्थिति से स्वतंत्र होते हैं अर्थात् भुगतान-संतुलन के अतिरेक या घाटे को ध्यान में रखते हुए ये लेन-देन नहीं होते हैं बल्कि उससे पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं।

वस्तु खाता के अंतर्गत 'दृश्य' वस्तुओं का लेन-देन आता है। सेवा खाते में एक देश द्वारा एक वर्ष के लिए गए सभी सेवाओं के निर्यातों तथा आयातों का ब्यौरा होता है। चूंकि सेवाएँ वस्तुओं की तरह 'दृश्य' नहीं होती हैं इसलिए सेवाओं के लेन-देन को भुगतान संतुलन की अदृश्य मदें कहा जाता है।

एकपक्षीय हस्तांतरण खाते में सभी प्रकार के उपहार, अनुदान, सहायता इत्यादि सम्मिलित है। दीर्घकालिक पूँजी खाता के अंतर्गत उन विनियोगों को सम्मिलित किया जाता है जो एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किए जाते हैं। इस खाते को तीन भागों में बाँटा जा सकता है- निजी प्रत्यक्ष निवेश, निजी पोर्टफोलियो निवेश सरकारी उधार या ऋण।

अल्पकालिक पूँजी खाते के अंतर्गत वे अल्पकालिक पूँजी मदें आती हैं। जोकि एक वर्ष से कम की अवधि के लिए होती हैं। यह खाता भुगतान संतुलन के घाटे या अतिरेक के समायोजन से संबंधित है जो कि सीधे तौर पर विदेशी रिजर्वों में परिवर्तन को दर्शाता है। इसलिए यह एक तरह से सरकारी व्यवस्थापन लेखा है। यह खाता अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के व्यवस्थापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य सभी साधनों को सम्मिलित करता है।

जेम्स ई. मीड तथा कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार व्यापार संतुलन निर्यातित तथा आयातित वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतर होता है। कुछ अर्थशास्त्री सिर्फ व्यापारिक या दृश्य वस्तुओं के निर्यात तथा आयात के अन्तर को अर्थात् सिर्फ 'वस्तु-खाता' के अंतर को ही व्यापार-संतुलन के रूप में परिभाषित करते हैं। भारत में भी व्यापार-संतुलन का अर्थ वस्तु-खाते का अन्तर है अर्थात् सिर्फ वस्तुओं के निर्यातों और आयातों का अन्तर। व्यापार शेष, अपने दोनों ही अर्थों में भुगतान संतुलन का एक हिस्सा है। वस्तु खाता, सेवा खाता तथा एकपक्षीय हस्तांतरण खाता को सम्मिलित रूप से चालू खाते पर भुगतान संतुलन कहा जाता है। चालू खाते तथा पूँजी खाते पर भुगतान संतुलन का योग कुल भुगतान-संतुलन को बताता है।

कुल भुगतान-संतुलन का घाटा या अतिरेक उस देश के लिए बेहतर है या प्रतिकूल स्थिति को दर्शाता है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि चालू खाते और पूँजी-खाते पर भुगतान-संतुलन की स्थिति क्या है? यदि भुगतान-

संतुलन का अतिरेक चालू खाते के अतिरेक के कारण है, परन्तु पूँजी-खाते के अतिरेक के कारण नहीं है तो यह स्थिति उस देश के लिए अनुकूल हो सकता है। जब कुल भुगतान-संतुलन के असंतुलन (अतिरेक या घाटा) को दूर करने के लिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाता जोड़ दिया जाता है तो लेखांकन की दृष्टि से भुगतान-संतुलन की समस्त प्राप्तियाँ (क्रेडिट-लेनदारियाँ) तथा भुगतानों (डेबिट-देनदारियाँ) के बराबर जो जाती है और भुगतान संतुलन, संतुलन में हो जाता है। जब भुगतान-संतुलन के असंतुलन को अंतर्राष्ट्रीय तरलता खातों या समायोजित लेन-देन के द्वारा दूर किया जाता है तो यह भुगतान-संतुलन का निपटान (settlement) कहा जाता है।

यदि भुगतान-संतुलन के अतिरेक या घाटे को दूर करने के लिए या नियंत्रित के लिए उन कारकों को नियंत्रित किया जाता है जो कि इस अतिरेक या घाटे के लिए जिम्मेदार है तो इसे भुगतान-संतुलन का समायोजन (adjustment) कहते हैं। अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाते के बिना भुगतान-संतुलन के स्वायत्त लेन-देन में संतुलन ले आना भुगतान-संतुलन समायोजन कहा जाएगा। असंतुलन की अलग-अलग प्रकृति होती है जोकि उसके कारणों पर निर्भर करती है। विभिन्न देशों में भुगतान-संतुलन में असंतुलन के विभिन्न कारण हो सकते हैं तथा एक ही देश में अलग-अलग समय में असंतुलन के अलग-अलग कारण हो सकते हैं।

असंतुलन को समायोजित करने के लिए एक देश किस प्रकार की आर्थिक नीतियाँ/ उपायों को लागू करे, यह उसके भुगतान संतुलन की स्थिति पर निर्भर करेगा। भुगतान-संतुलन के घाटे के पूरा करने के लिए आवश्यक है कि स्वायत्त लेन-देन में भुगतानों की अपेक्षा प्राप्तियों में अधिक वृद्धि हो। स्पष्ट है कि असंतुलन को दूर करने के लिए उन मदों या कारकों में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है जो कि भुगतान-संतुलन की प्राप्तियों तथा भुगतानों को प्रभावित करते हैं।

11.13 शब्दावली

- **भुगतान-शेष-** किसी देश का भुगतान-शेष किसी दी हुई अवधि (जैसे एक वर्ष) में उस देश के नागरिकों द्वारा विश्व के अन्य देशों के नागरिकों के बीच हुए समस्त आर्थिक लेन-देन का व्यस्थित विवरण है।
- **व्यापार शेष -** वस्तु खाते पर हुई प्राप्तियों तथा भुगतानों का अन्तर व्यापार-शेष कहलाता है। अर्थात् सिर्फ दृश्य व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात तथा आयात मूल्यों का अंतर व्यापार-शेष है। परन्तु व्यापक अर्थों में व्यापार-शेष वस्तुओं या सेवाओं के निर्यात तथा आयात मूल्यों का अंतर है।
- **भुगतान संतुलन निपटान (Settlement) -** जब भुगतान-संतुलन में लेखांकन संतुलन समायोजक लेन-देन या अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाता की सहायता से ले आया जाता है तो उसे भुगतान-संतुलन का निपटान कहते हैं।
- **भुगतान-संतुलन समायोजन (Adjustment) -** जब भुगतान-संतुलन में लेखांकन संतुलन, समायोजक लेन-देन की सहायता के बिना होता है तो इसे भुगतान-संतुलन समायोजन कहा जाता है।
- **भुगतान-संतुलन का 'पूर्ण रोजगार' संतुलन -** यदि भुगतान-संतुलन में बिना वाणिज्यिक नीति का सहारा लिए तथा देश के सकल राष्ट्रीय आय में स्फीतिकारी या अवस्फीतिकारी अंतराल उत्पन्न किए, संतुलन ले आया जाता है तो यह सही मायने में संतुलन या 'पूर्ण रोजगार' संतुलन कहा जाता है। परन्तु यदि यह संतुलन व्यापार पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्धों और इसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति या बेरोजगार उत्पन्न हुई है, तो यह 'पूर्ण रोजगार' संतुलन नहीं होगा।

11.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न:

1. घ 2. क 3. ग 4. घ 5. घ 6. ख 7. घ 8. ख 9. क
10. ग 11. घ 12. ख 13. ग 14. क 15. क 16. घ 17. ख 18. ग

सत्य व असत्य :

- | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. असत्य | 2. असत्य | 3. सत्य | 4. सत्य | 5. सत्य |
| 6. सत्य | 7. सत्य | 8. असत्य | 9. सत्य | 10. सत्य |
| 11. सत्य | 12. सत्य | 13. असत्य | 14. असत्य | 15. असत्य |
| 16. सत्य | 17. असत्य | 18. असत्य | 19. असत्य | 20. सत्य |
| 21. सत्य | 22. असत्य | 23. सत्य | 24. सत्य | 25. सत्य |

11.15 संदर्भ ग्रंथ सूची

- HH. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: International Economics: Theory and Policy, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- Charles P Kindleberger, International Economics, Richard D. Irwin Inc., Illinois, 1968
- Dominik Salvatore, International Economics, John Willy & Sons, Inc., 2008
- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006 •
- सुदामा सिंह एवं एम0सी0 वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफ़ोर्ड एंड आई0बी0एच0 पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम0एल0 झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010।
- ज्ञानेंद्र सिंह कुशवाहा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1979।

11.16 उपयोगी/सहायक पाठ्य सामग्री

- HH. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt.Ltd. 2001
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: International Economics: Theory and Policy, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- Charles P Kindleberger, International Economics, Richard D. Irwin Inc.,Illinois, 1968
- Dominik Salvatore, International Economics, John Willy & Sons, Inc.,2008

- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006
- एस. एन. लाल, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद, 2004
- एच. एस. अग्रवाल, तथा सी. एस. बरला, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2003.
- सुदामा सिंह एवं एम. सी. वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड एंड आई. बी. एच. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम0 एल0 झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010.
- डॉ. जी. सी. सिंघई एवं डॉ. जे. पी. मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा, 2010

11.17 निबंधात्मक प्रश्न

1. “भुगतान संतुलन सदैव सन्तुलित रहता है।” यदि ऐसा है तो फिर हम किसी देश के भुगतान-संतुलन में अतिरेक या घाटे की चर्चा क्यों करते हैं?
2. किसी देश के प्रतिकूल भुगतान-संतुलन से आप क्या समझते हैं? भुगतान शेष के असन्तुलन को दूर करने के लिए अपनाये जाने वाले उपायों का उल्लेख कीजिए।
3. भुगतान-संतुलन के असंतुलन का क्या अर्थ है? भुगतान-संतुलन के घाटे को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों की चर्चा कीजिए।
4. भुगतान-संतुलन के ‘अतिरेक’ तथा ‘घाटे’ से आप क्या समझते हैं? भुगतान-संतुलन का किस प्रकार का ‘घाटा’ अधिक खतरनाक है। क्या भुगतान-संतुलन का ‘अतिरेक’ किसी देश के लिए हमेशा अनुकूल होता है?

इकाई 12 - विदेशी व्यापार गुणक (Foreign Trade Multiplier)

- 12.1 प्रस्तावना
- 12.2 उद्देश्य
- 12.3 विदेशी व्यापार गुणक - भूमिका
 - 12.3.1 घरेलू अर्थव्यवस्था तथा विदेशी व्यापार में सम्बन्ध
 - 12.3.2 निवेश गुणक
- 12.4 विदेशी प्रतिक्रियाओं या प्रतिप्रभाव की अनुपस्थिति में विदेशी व्यापार गुणक या शुद्ध विदेशी व्यापार गुणक
 - 12.4.1 विदेशी व्यापार गुणक की व्युत्पत्ति
 - 12.4.2 विदेशी प्रतिक्रियाओं या प्रतिप्रभाव की अनुपस्थिति में विदेशी व्यापार गुणक का प्रभाव
- 12.5 विदेशी प्रतिक्रियाओं या प्रतिप्रभाव की उपस्थिति में विदेशी व्यापार गुणक
 - 12.5.1. निर्यातों का फिडबैक विदेशी व्यापार गुणक
 - 12.5.2. निवेश का फिडबैक विदेशी व्यापार गुणक
- 12.6 विदेशी व्यापार गुणक का चित्र द्वारा निरूपण
 - 12.6.1 विदेशी प्रतिक्रियाओं या प्रतिप्रभाव की अनुपस्थिति में विदेशी व्यापार गुणक या शुद्ध विदेशी व्यापार गुणक
 - 12.6.2 विदेशी प्रतिक्रियाओं या प्रतिप्रभाव की उपस्थिति में विदेशी व्यापार गुणक
- 12.7 विदेशी व्यापार गुणक का महत्त्व
- 12.8 विदेशी व्यापार गुणक की आलोचनाएं
- 12.9. अभ्यास हेतु प्रश्न
- 12.10 सारांश
- 12.11 शब्दावली
- 12.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 12.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 12.14 उपयोगी/ सहायक पाठ्य सामग्री
- 12.15 निबंधात्मक प्रश्न

12.1 प्रस्तावना

इससे पहले इससे पहले की इकाई में आपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बंधित एक महत्वपूर्ण संकल्पना भुगतान संतुलन के बारे में अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात् आप भुगतान संतुलन का अर्थ एवं प्रकृति को समझ समझ गए होंगे। आप जान गए होंगे कि भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन में क्या अंतर होता है। साथ ही भुगतान संतुलन की विभिन्न अवधारणाएं, भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण, भुगतान संतुलन में समायोजन के तरीकों को समझ गए होंगे।

किसी भी देश की राष्ट्रीय आय और भुगतान-संतुलन में काफी गहन सम्बन्ध होता है। किसी भी एक चर में परिवर्तन से दूसरे चर में परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि आपने विछले अध्याय में देखा कि भुगतान-शेष के घाटे को दूर करने के लिए राष्ट्रीय आय में कमी करके घाटे को कम किया जा सकता है। आय में कमी से आयातों में कमी होगी। यह सीमांत आयात प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा कि आयात में कितनी कमी होगी। वास्तव में, यह विदेशी व्यापार गुणक पर निर्भर करेगा कि आय में परिवर्तन से प्रेरित आयातों या निर्यातों में कितना परिवर्तन होगा या फिर निर्यातों में वृद्धि या कमी से विदेशी व्यापार गुणक के कार्यकरण से राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि या कमी होगी। विदेशी व्यापार गुणक निर्यात में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न आय-परिवर्तन को व्यक्त करता है। विदेशी व्यापार गुणक का मान आयात की सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है।

आर्थिक नीति निर्धारण में गुणक का विशेष महत्व है। जिसके अनुसार, स्वायत्त विनियोग में थोड़ी सी वृद्धि के फलस्वरूप आय में काफी अधिक वृद्धि हो जाती है। राष्ट्रीय आय में समायोजन के माध्यम से भुगतान-संतुलन के असंतुलन को दूर किया जा सकता है। प्रस्तुत इकाई में हम विदेशी व्यापार गुणक की विस्तार से चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय आय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परस्पर संबंध को भी देखेंगे। भुगतान-संतुलन के असंतुलन को कम करने या बढ़ाने में विदेशी व्यापार गुणक की भूमिका पर भी हम चर्चा करेंगे।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप विदेशी व्यापार गुणक, विदेशी प्रतिक्रियाओं या प्रतिप्रभाव की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति में विदेशी व्यापार गुणक के कार्यकरण तथा प्रभावों सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

12.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप

- ✓ राष्ट्रीय आय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परस्पर संबंध जान सकेंगे।
- ✓ विदेशी व्यापार गुणक को समझ सकेंगे।
- ✓ विदेशी प्रतिक्रियाओं या प्रतिप्रभाव की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति में विदेशी व्यापार गुणक के कार्यकरण तथा प्रभावों को समझ सकेंगे।
- ✓ विदेशी व्यापार गुणक के महत्त्व को जान सकेंगे।

12.3 विदेशी व्यापार गुणक - भूमिका

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय तथा विदेशी व्यापार में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का समीकरण होता है

$$Y = C + I + G + (X - M) \dots \dots (1)$$

जहाँ,

Y= राष्ट्रीय आय

G= सरकारी व्यय

C= उपभोग

X= निर्यात

I= निवेश

M= आयात

(X-M) व्यापार-संतुलन है जोकि शुद्ध निर्यात आय को दर्शाता है। (X-M) का मूल्य ही राष्ट्रीय आय में विदेशी व्यापार के योगदान को बताता है।

जब किसी देश के निर्यात में वृद्धि होती है तो निर्यात उद्योगों से संबंधित सभी व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है। इस बढ़ी हुई आय से अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मांग उत्पन्न होती है, उन उद्योगों का विस्तार होता है, रोजगार में वृद्धि होती है और आगे आय में और वृद्धि होती है। इस प्रकार, अंतिम रूप में आय में हुई वृद्धि निर्यात-वृद्धि की अपेक्षा काफी अधिक होती है, जो कि गुणक प्रभाव का परिणाम है। निर्यात में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई यह विदेशी व्यापार गुणक या निर्यात गुणक पर निर्भर करता है। इसे हम सूत्र के रूप में निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं

$$\Delta y = k\Delta x$$

जहाँ,

 Δy =-आय में परिवर्तन Δx = निर्यात में परिवर्तन k = निर्यात गुणक या विदेशी व्यापार गुणक

वास्तव में, निर्यात गुणक का मूल्य सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या बचत प्रवृत्ति तथा सीमांत आयात प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम आयातों को भी लेते हुए विस्तृत रूप में, विदेशी व्यापार गुणक पर विचार करेंगे।

12.3.1 घरेलू अर्थव्यवस्था तथा विदेशी व्यापार में संबंध

एक खुली अर्थव्यवस्था में घरेलू उपभोक्ताओं, निवेशकों और सरकार का व्यय तथा साथ ही देश के निर्यातों पर विदेशियों द्वारा व्यय देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के सृजन को व्यक्त करता है। यह अर्थव्यवस्था में सृजित कुल आय को बताता है। संकेत रूप में

$$C + I + G + X = \text{सृजित आय} \dots \dots \dots (2)$$

जहाँ,

C= उपभोग

G= सरकारी व्यय

I= निवेश

X= निर्यात

उल्लेखनीय है कि अर्थव्यवस्था में उत्पन्न यह कुल आय, राष्ट्रीय आय नहीं है। यह सृजित आय वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, बचत, करों के भुगतान तथा विदेशी वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात में व्यय हो जाती है। संकेत रूप में

$$C + S + T + M = \text{व्यय की गयी आय} \dots \dots \dots (3)$$

जहाँ,

C= उपभोग

T= कर अदायगी

S= बचत

M= आयात व्यय

चूंकि कुल सृजित आय, कुल व्यय के बराबर होगी, अर्थात्

$$C + I + G + X = C + S + T + M \dots \dots \dots (4)$$

अथवा

$$I + G + X = S + T + M \text{ (दोनों पक्षों में से } C \text{ घटाने पर)} \dots\dots (5)$$

यदि मान लें कि सरकारी व्यय (G) सरकार के कुल कर (T) के बराबर है, अर्थात् सरकार का बजट संतुलित है तो समीकरण (5) को निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है।

$$I + X = S + M \dots\dots\dots (6)$$

जैसा कि आप जानते हैं कि निवेश और निर्यात राष्ट्रीय आय के प्रवाह में वृद्धि करते हैं जबकि बचत तथा आयात राष्ट्रीय आय के प्रवाह में रिसाव है, आय को कम करते हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त यह है कि बचत और निवेश हमेशा बराबर हों। अर्थात् संतुलन की स्थिति में निर्यात और आयात भी बराबर होंगे और घरेलू तथा विदेशी क्षेत्र दोनों एक साथ संतुलन में होंगे। समीकरण (6) से

$$I - S = M - X \dots\dots\dots (7)$$

स्पष्ट है कि यदि घरेलू क्षेत्र में बचत-निवेश का अंतर शून्य है तो व्यापार-संतुलन में संतुलन शून्य होगा। यदि निवेश बचत से अधिक है तो व्यापार-संतुलन में घाटा और यदि निवेश बचत से कम है तो अतिरेक होगा।

इस प्रकार, स्पष्ट है कि घरेलू तथा विदेशी क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध है। स्वायत्त विनियोग (I) में यदि वृद्धि होती है तो यह प्रारम्भिक संतुलन की स्थिति (I = S) को विगाड़ती है और साथ ही आयात तथा निर्यात की समानता को समाप्त कर व्यापार-संतुलन में अतिरेक या घाटे की स्थिति पैदा कराती है। व्यापार-संतुलन में उत्पन्न असंतुलन उपभोग बचत और आयातों की सीमान्त-प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। इसी प्रकार, निर्यातों या आयातों में स्वायत्त परिवर्तन से घरेलू बचत निवेश का संतुलन बिगड़ता है जो कि पूरी अर्थव्यवस्था का प्रभावित करता है।

12.3.2 निवेश गुणक

आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि निवेश गुणक क्या है। आप जानते होंगे कि गुणक की धारणा कीन्सीय रोजगार सिद्धान्त की एक अति-महत्वपूर्ण संकल्पना है। स्वायत्त निवेश में वृद्धि (या कमी) से राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि (या कमी) होगी यह गुणक के मान पर निर्भर करता है। गुणक यह बताता है कि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में वृद्धि निवेश में प्रारम्भिक वृद्धि और गुणक के गुणनफल के बराबर होगी। अर्थात्

$$\Delta y = k \Delta I$$

जहाँ

Δy = आय में परिवर्तन,

K = गुणक

ΔI = निवेश में परिवर्तन।

k, जो कि निवेश गुणक है, सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (b या MPC) सीमान्त बचत प्रवृत्ति (s या MPS) पर निर्भर करता है। ($k = \frac{1}{1-MPC}$), MPC जितनी ही अधिक होगी, निवेश गुणक उतना ही अधिक होगा।

एक बन्द अर्थव्यवस्था में, सरकारी व्यय तथा करों की अनुपस्थिति में, आप साधारण कीन्सीय निवेश गुणक व्युत्पन्न कर सकते हैं।

आप जानते हैं कि –

$$Y = C + I$$

जहाँ,

Y = आय

C = उपभोग

I = निवेश

$$\Delta y = \Delta C + \Delta I$$

(जहाँ Δ वृद्धि का सूचक है ; जैसे Δy = आय में वृद्धि, ΔC = उपभोग वृद्धि तथा ΔI = निवेश में वृद्धि)

अथवा

$$\frac{\Delta Y}{\Delta Y} = \frac{\Delta C}{\Delta Y} + \frac{\Delta I}{\Delta Y}$$

दोनों पक्षों में ΔY से भाग देने पर

अथवा

$$1 = b + \frac{\Delta I}{\Delta Y}$$

($\frac{\Delta C}{\Delta Y} = \text{MPC} = b$ सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति है)

अथवा

$$\frac{\Delta I}{\Delta Y} = 1 - b$$

अथवा

$$\frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{1 - b}$$

यदि

$$\frac{1}{1 - b} = K$$

तो

$$\frac{\Delta Y}{\Delta I} = k$$

या

$$\Delta Y = k\Delta I$$

अर्थात् आय में परिवर्तन प्रारम्भिक स्वायत्त निवेश में परिवर्तन से अधिक होगा। k गुणक है जो कि s या $(1-b)$ का व्युत्क्रमानुपाती है।

अर्थात्

$$k = \frac{1}{1 - b}$$

या

$$k = \frac{1}{s} (s = 1 - b)$$

जहाँ s = सीमान्त बचत प्रवृत्ति है।

वास्तव में सा कि आप जानते हैं निवेश दो प्रकार का होता है, स्वायत्त तथा प्रेरित। प्रेरित विनियोग आय के बढ़ने पर बढ़ता है। ऐसी स्थिति में यदि सीमान्त निवेश प्रवृत्ति g हो तो गुणक का मान होगा

$$k = \frac{1}{1 - b - g} \text{ या } k = \frac{1}{s - g}$$

उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि गुणक तथा सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति और सीमान्त निवेश प्रवृत्ति का सीधा संबंध है जबकि गुणक का सीमान्त बचत प्रवृत्ति से उल्टा या व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। यदि स्वायत्त निवेश में वृद्धि होती है तो आय में वृद्धि गुणक के मान पर निर्भर करेगी।

12.4 विदेशी प्रतिक्रियाओं या प्रतिप्रभाव (Foreign Repercussions) की अनुपस्थिति में विदेशी व्यापार गुणक या शुद्ध विदेशी व्यापार गुणक

एक बन्द अर्थव्यवस्था में निवेश गुणक की व्युत्पत्ति कैसे की जाती है, आपने ऊपर देखा। एक बंद अर्थव्यवस्था में गुणक का मान होगा

$$k = \frac{1}{1 - b - g}$$

एक खुली अर्थव्यवस्था में, राष्ट्रीय आय की गणना में उपभोग और बचत के अतिरिक्त निर्यात (X) और आयात (M) को भी सम्मिलित किया जाता है। अर्थात् समस्त उत्पादित वस्तुओं (Y) और आयातित वस्तुओं (M) का योग, समस्त खरीदी गयी वस्तुओं (C+I+G) और निर्यातित वस्तुओं (X) के योग के बराबर होगा। गणितीय रूप में

$$Y + M = C + I + G + X$$

यदि हम मान लें कि सरकारी व्यय और कर शून्य है और बचत और निवेश भी नहीं हो रहा है, उपभोग के अतिरिक्त सिर्फ आयात और निर्यात हो रहा है तो संतुलन में

$$Y + M = C + X$$

$$Y = C + X - M$$

ऐसी स्थिति में, विदेशी व्यापार गुणक (k_f) का मान होगा

$$k_f = \frac{1}{m}$$

जहाँ, m सीमान्त आयात प्रवृत्ति है।

स्पष्ट है कि विदेशी व्यापार गुणक का मान सीमान्त आयात प्रवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ k शुद्ध विदेशी व्यापार गुणक है। जहाँ केवल विदेशी क्षेत्र की उपस्थिति है जबकि घरेलू क्षेत्र इस अर्थ में अनुपस्थित है कि घरेलू बचत व निवेश शून्य है। चूंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में घरेलू और विदेशी क्षेत्र दोनों मौजूद रहता है इसलिये यदि घरेलू क्षेत्र के साथ विदेशी क्षेत्र को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो विदेशी व्यापार गुणक को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है

$$k_f = \frac{1}{1 - b - g + m} \text{ या } \frac{1}{s - g + m}$$

k_f = विदेशी व्यापार गुणक है।

निर्यातों (X) को सामान्यतया बहिर्जात रूप से निर्धारित माना जाता है क्योंकि निर्यातों की मांग, विदेशों में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करती है, जो कि घरेलू अर्थव्यवस्था से बाहर के कारक है। दूसरी तरफ, आयातों (M) की मांग घरेलू अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में परिवर्तनों पर निर्भर करती है। इस प्रकार आयात एक सीमा तक अंतर्जात चर है। आयात का एक हिस्सा तो स्वायत्त होता है जो कि राष्ट्रीय आय से प्रभावित नहीं होता है जबकि एक हिस्सा आय प्रेरित होता है। आयात फलन को निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है

$$M = M_0 + mY$$

जहाँ

M =आयात, M_0 =स्वायत्त आयात m =सीमान्त आयात प्रवृत्ति ($\Delta M/\Delta Y$)

विदेशी व्यापार गुणक (k_f) का मान केन्सीय निवेश गुणक से कम होगा क्योंकि इसके अंश में सीमान्त आयात प्रवृत्ति जुड़ गयी है। इस प्रकार सीमान्त आयात प्रवृत्ति (m) घरेलू तथा विदेशी क्षेत्र को जोड़ती है।

12.4.1 विदेशी व्यापार गुणक की व्युत्पत्ति

अब हम विदेशी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा घरेलू क्षेत्र की उपस्थिति में स्वायत्त निर्यात में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय तथा अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों की स्पष्ट व्याख्या करेंगे। निर्यात में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई यह विदेशी व्यापार गुणक या निर्यात गुणक पर निर्भर करता है। आप जानते हैं एक खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का समीकरण निम्नलिखित होगा

$$Y = C + I = G + (X - M)$$

जैसा कि आप जानते हैं

$$C = C_0 + bY_d$$

(जहाँ C_0 - स्वायत्त उपभोग,

Y_d =व्यय योग्य आय)

$$Y_d = Y - T$$

(जहाँ T = कर)

$$I = I_0 + gY$$

(जहाँ I_0 =स्वायत्त निवेश)

$$M = M_0 + mY$$

जहाँ M = आयात, M_0 = स्वायत्त आयात m = सीमान्त आयात प्रवृत्ति)

Therefore $Y = (C_0 + bY_d) + (I_0 + gY) + G + [X - (M_0 + mY)]$

$$Y = C_0 + b(Y - T) + I_0 + gY + G + X - M_0 - mY$$

$$Y = C_0 + bY - bT + I_0 + gY + G + X - M_0 - mY$$

$$Y - bY - gy + mY = C_0 + I_0 + G + X - M_0 - bT$$

$$Y(1 - b - g + m) = C_0 + I_0 + GX - M_0 - bT$$

$$Y = \frac{1}{1 - b - g + m} (C_0 + I_0 + G + X - M_0 - bT)$$

$$\text{जहाँ } \frac{1}{1 - b - g + m} = k_f$$

k_f विदेशी व्यापार गुणक है।

यदि निर्यातों में वृद्धि होती है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होगी यह विदेशी व्यापार गुणक के मान पर निर्भर करेगा।

12.4.2 विदेशी प्रतिक्रियाओं या प्रतिप्रभाव की अनुपस्थिति में विदेशी व्यापार गुणक का प्रभाव

मान लीजिए $b = 0.75$, $g = 0.2$ तथा $m = 0.2$ तथा निर्यात में वृद्धि $(\Delta X) = 200$ करोड़ है। तो

$$k_f = \frac{1}{1 - b - g + m} = \frac{1}{1 - 0.75 - 0.2 + 0.2}$$

$$= \frac{1}{1.2 - 0.95} = \frac{1}{0.25} = 4$$

अर्थात् विदेशी व्यापार गुणक का मान 4 है।

इसलिए आय में वृद्धि $\Delta Y = k\Delta X$

अथवा $\Delta Y = 4 * 200 = 800$ Cr

निर्यात में वृद्धि से निर्यातकों के आय अर्जन में वृद्धि होती है। बढ़ी हुई आय को घरेलू तथा आयातित वस्तुओं के उपभोग पर व्यय किया जाता है। यह व्यय की मात्रा क्रमशः सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (b) तथा सीमान्त आयात प्रवृत्ति (m) निर्भर करती है। घरेलू वस्तु के उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति जितनी ही अधिक होगी और सीमान्त आयात प्रवृत्ति जितनी ही कम होगी, विदेशी व्यापार गुणक का मान उतना ही अधिक होगा और राष्ट्रीय आय में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। स्पष्ट है कि बढ़ी हुई आय को आयात पर व्यय करना एक प्रकार से आय में रिसाव है।

निर्यात में वृद्धि से व्यापार घाटा ($X-M$) कम होगा-यदि आयात की सीमान्त प्रवृत्ति कम है तो निर्यातों में वृद्धि की अपेक्षा आयातों की वृद्धि कम होगी। साथ ही, निवेश बचत अन्तराल में भी कमी होगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि घरेलू क्षेत्र तथा विदेशी क्षेत्र का घनिष्ठ संबंध है। निर्यातों में परिवर्तन से राष्ट्रीय आय प्रभावित होगी और राष्ट्रीय आय आगे आयातों को प्रभावित करेगी। यहाँ व्यापार शेष के घाटे को दूर करने में विदेशी व्यापार गुणक का महत्व स्पष्ट है।

12.5 विदेशी प्रति-प्रभाव (Foreign Repercussions effect) और विदेशी व्यापार गुणक

अब तक के विदेशी व्यापार गुणक की चर्चा से आप जान गए होंगे कि यह सीमान्त बचत प्रवृत्ति (s) और सीमान्त आयात प्रवृत्ति (m) के योग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस प्रकार उपभोग, निवेश या सरकारी व्यय में वृद्धि का राष्ट्रीय आय पर प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार निर्यात वृद्धि का भी (या आयात में कमी का) राष्ट्रीय आय पर प्रभाव पड़ता है। स्वायत्त निर्यातों में वृद्धि (या आयातों में कमी से) विदेशी व्यापार मुक्त गुणक द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और इससे शुद्ध विदेशी निवेश अर्थात् $(X-M)$ में वृद्धि होती है।

स्पष्ट है कि निर्यात वृद्धि के कारण हुई आय वृद्धि का आयात बिल के भुगतान के रूप में रिसाव होता है जिसके कारण विदेशी व्यापार गुणक का मान निवेश गुणक की तुलना में कम हो जाता है। परन्तु अब तक हमने मान लिया था कि आयात तो राष्ट्रीय आय का फलन है परन्तु निर्यातों का निर्धारण स्वतः ही होता है क्योंकि वह बाह्य कारकों से प्रभावित होता है।

वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो तरफा यातायात की तरह है। एक देश का निर्यात, दूसरे देश का आयात है तथा दूसरे देश का निर्यात घरेलू देश का आयात है। इस प्रकार घरेलू देश का निर्यात विदेशी देश में होने वाले राष्ट्रीय आय के परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं या विदेशी देश की सीमान्त आयात प्रवृत्ति पर निर्भर होते हैं। इसी प्रकार घरेलू देश में आयात देश की आय में परिवर्तनों या सीमान्त आय प्रवृत्ति पर निर्भर करते हैं। जोकि इस तरह विदेशी देश के निर्यातों को निर्धारित करते हैं। इसे 'विदेशी प्रतिप्रभाव' या 'फीड बैक प्रभाव' कहते हैं।

विदेशी प्रति प्रभाव की अनुपस्थिति में विदेशी व्यापार गुणक केवल घरेलू सीमान्त बचत (या उपभोग) तथा आयात प्रवृत्तियों (विश्लेषण की सरलता के लिए सीमान्त निवेश प्रवृत्ति को छोड़ा जा सकता है) पर निर्भर करता है।

अर्थात्

$$k_f = \frac{1}{s + m} = \frac{1}{1 - b + m}$$

विदेशी प्रति प्रभाव की उपस्थिति में विदेशी व्यापार गुणक न सिर्फ घरेलू सीमान्त बचत तथा आयात प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है बल्कि यह विदेशी सीमान्त बचत तथा आयात प्रवृत्तियों पर भी निर्भर करता है। जिस प्रकार घरेलू विनियोग का राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन पर विस्तारकारी प्रभाव होता है उसी प्रकार अतिरिक्त निर्यात और विदेशी विनियोग का भी देश के उत्पादन, रोजगार और आय पर विस्तारकारी प्रभाव होता है। एक देश दूसरे देश की अपेक्षा जितना छोटा होगा, विदेशी प्रति-प्रभाव उतना ही कम होगा।

विदेशी प्रति-प्रभाव की अनुपस्थिति में, निवेश में वृद्धि या निर्यात में वृद्धि दोनों का ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि पर एक तरह का प्रभाव पड़ेगा।

उदाहरण के तौर पर, यदि

$$k=4, \text{ तथा निर्यात वृद्धि } \Delta X = 200Cr$$

$$\text{तो } \Delta y = 4 * 200 = 800$$

यदि निवेश में 200 Cr की वृद्धि होती है तो भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि 800 Cr की होगी, क्योंकि तब भी सूत्र वही होगा

$$\Delta y = k \Delta I = 4 * 200 = 800 Cr$$

परन्तु विदेशी प्रति-प्रभाव की उपस्थिति में निर्यात में वृद्धि और उसी मात्रा में निवेश में वृद्धि का राष्ट्रीय आय पर प्रभाव अलग-अलग होगा।

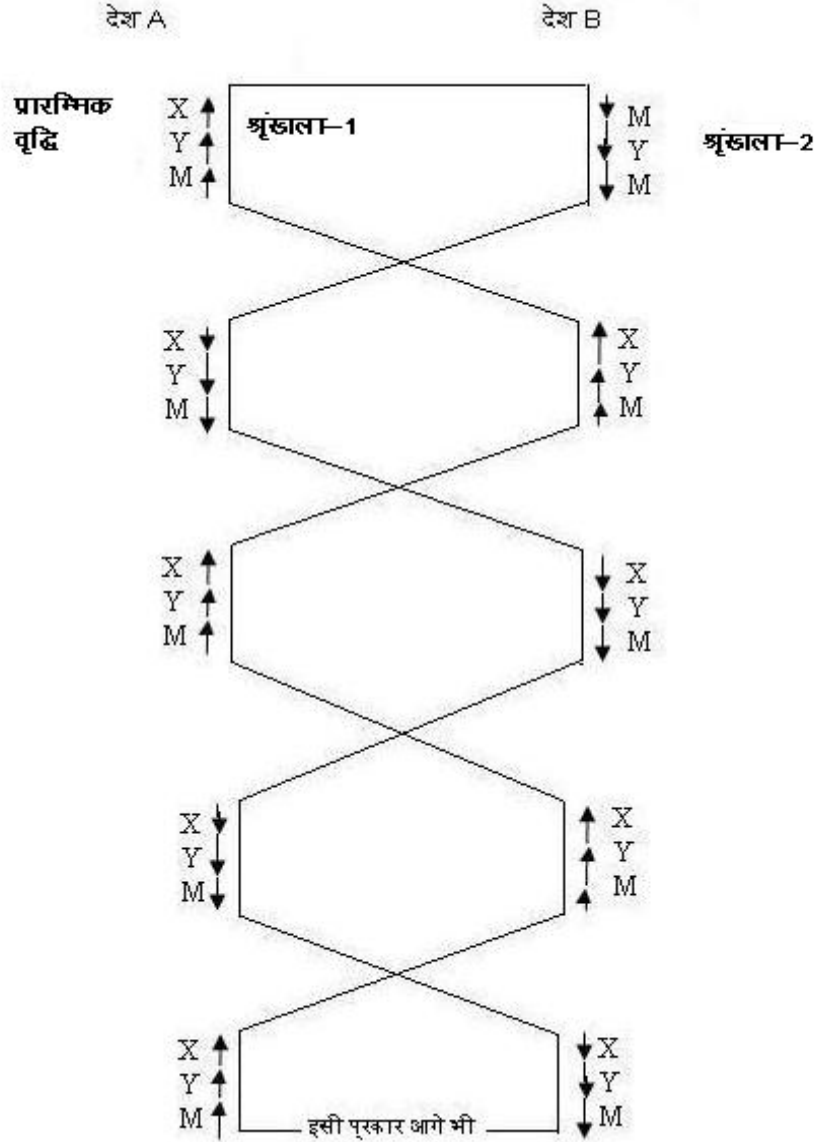
12.5.1 निर्यातों का फीडबैक विदेशी व्यापार गुणक (Feedback Foreign Trade Multiplier Model of Exports)

यदि एक देश के निर्यात में स्वायत्त रूप से वृद्धि हो रही है तो विदेशी प्रति-प्रभाव की उपस्थिति में हम विदेशी व्यापार गुणक (K) के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। यह निर्यात में वृद्धि विदेशी देश में अधिक सीमान्त आय प्रवृत्ति या निवेश वृद्धि के कारण हुए आर्थिक विस्तार के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा प्रेरित हो सकती है।

मान लिया दो देश हैं, घरेलू देश A तथा विदेशी देश B घरेलू देश A में निर्यात वृद्धि का विदेशी प्रतिक्रियाओं या प्रतिप्रभाव या फीडबैक प्रभाव की उपस्थिति में उसकी राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप यह निम्नलिखित चित्र के माध्यम से देख सकते

घरेलू देश A में निर्यात में प्रारम्भिक वृद्धि से आय में वृद्धि होती है जो कि इस देश के आयातों में भी वृद्धि लाती है। देश A के आयातों में वृद्धि से देश B के निर्यातों में वृद्धि होगी। देश B में निर्यातों की वृद्धि उसकी राष्ट्रीय आय और आयातों में वृद्धि आती है। देश B में आयातों में वृद्धि से देश A में निर्यातों में 'प्रेरित' वृद्धि होती है।

जिससे देश A में राष्ट्रीय आय तथा आयातों में वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया दोनों देशों के बीच चलती रहती है और दोनों देशों में व्यापार तथा आय में लगातार विस्तारकारी प्रभाव होता है। इसे चित्र 12.1 में श्रृंखला-1 के माध्यम से दर्शाया गया है।



चित्र 12.1

परन्तु देश A में निर्यात वृद्धि का एक दूसरा प्रभाव भी होगा जो कि अर्थव्यवस्था पर संकुचनकारी प्रभाव डालेगा। इसे चित्र 12.1 में श्रृंखला-2 के माध्यम से दर्शाया गया है। देश A के निर्यात में प्रारम्भिक वृद्धि से सीधे विदेशी देश B में आयात में वृद्धि होगी जिससे देश B में राष्ट्रीय आय और आयातों में कमी होती है। जब देश B के आयातों में कमी होती है तो इससे सीधे देश A में निर्यातों में कमी होगी, जो देश A के राष्ट्रीय आय तथा आयातों को कम करती है। परिणामस्वरूप, फिर से सीधे देश B में निर्यातों में कमी होगी जोकि देश B में आय और आयातों में कमी लाएगी और यह प्रक्रिया चलती रहेगी।

जब निर्यात में वृद्धि के उपरोक्त दोनों धनात्मक तथा ऋणात्मक प्रभाव पूरी तरह से एक साथ काम करते हैं तो घरेलू देश A में राष्ट्रीय आय में वृद्धि दो बातों पर निर्भर करती है- (i) देश A में निर्यातों की प्रारम्भिक वृद्धि कितनी है, और (ii) देश A में फीडबैक विदेशी व्यापार गुणक (k_f^*) का मान कितना है।

फीडबैक विदेशी व्यापार गुणक का सूत्र होगा

$$k_f = \frac{1}{S_1 + M_1 + M_2 \left(\frac{S_1}{S_2} \right)}$$

जहाँ,

S_1 = घरेलू देश A में सीमान्त बचत प्रवृत्ति

M_1 = घरेलू देश A में सीमान्त आयात प्रवृत्ति

M_2 = विदेशी देश B में सीमान्त आयात प्रवृत्ति

S_2 = विदेशी देश B में सीमान्त बचत प्रवृत्ति

विदेशी प्रति-प्रभाव की उपस्थिति में विदेशी व्यापार गुणक (k_f) का मान साधारण विदेशी व्यापार गुणक (K_f) की अपेक्षा कम होगा। क्योंकि श्रृंखला-2 का प्रभाव आय को घटाने वाला होगा।

यदि $S_1=0.3$, $M_1=0.2$

तो साधारण विदेशी व्यापार गुणक

$$k_f = \frac{1}{S_1 + M_1}$$

यदि $S_2 = 0.30$, $M_2 = 0.30$

$$k_f^* = \frac{1}{S_1 + M_1 + M_2 \left(\frac{S_1}{S_2} \right)}$$

$$= \frac{1}{0.30 + 0.20 + 0.30 \left(\frac{0.30}{0.30} \right)} = \frac{1}{0.50 + 0.30} = \frac{1}{0.80} = 1.25$$

स्पष्ट है कि K_f^* का मान (1.25), K_f के मान (2) से कम है। क्योंकि देश B के आयातों में वृद्धि से उसकी आय क्रमशः कम होगी, जिसका देश A की राष्ट्रीय आय पर भी ऋणात्मक प्रभाव होगा। यदि निर्यात में 200 की वृद्धि होती है तो आय में वृद्धि होगी।

$$\Delta Y = K_f^* \Delta X$$

$$= 1.25 \times 200$$

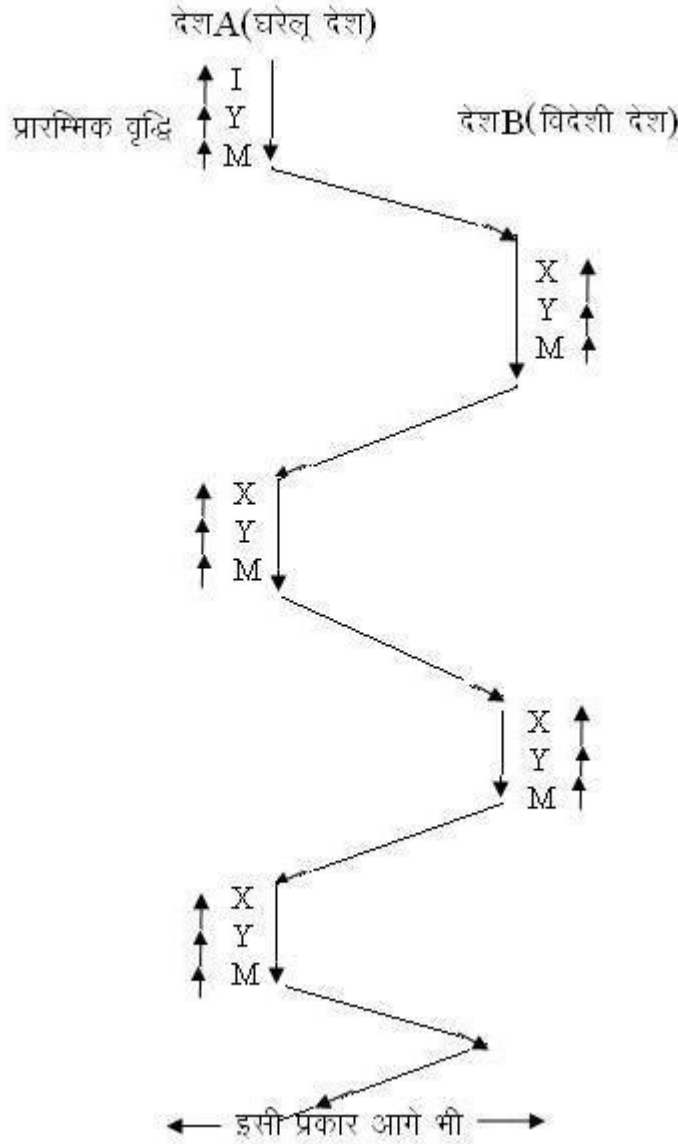
$$= 250Cr$$

12.5.2 निवेश का फीडबैक विदेशी व्यापार गुणक मॉडल:

निर्यात वृद्धि की जगह यदि देश A में निवेश में वृद्धि होती है तो देश A में राष्ट्रीय आय में वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक होगी।

देश A में निवेश में प्रारम्भिक वृद्धि का विदेशी प्रति-प्रभाव की उपस्थिति में राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह निम्नलिखित चित्र 12.2 में व्यक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसमें सिर्फ एक ही श्रृंखला बनेगी जो कि प्रति-प्रभाव को दर्शाती है।

निवेश में (I) प्रारम्भिक वृद्धि से देश A में आय तथा आयात में वृद्धि होगी; देश A में आयात वृद्धि से देश B के निर्यातों में वृद्धि होगी जिससे आय तथा आयातों में भी वृद्धि होगी।



चित्र 12.2

देश B के आयातों में वृद्धि की प्रतिक्रिया आगे देश A पर होगी और देश A के निर्यातों में वृद्धि होगी, जिससे उसके आय तथा आयात भी बढ़ेंगे। इसके परिणामस्वरूप देश B में भी निर्यात-आय तथा आयातों में वृद्धि होगी। यह प्रक्रिया संचयी रूप से चलती रहेगी और देश A तथा B दोनों ही देशों में आय, आयातों तथा निर्यातों को बढ़ाएगी। निवेश में वृद्धि पर देश A में वृद्धि निवेश वृद्धि की प्रारम्भिक मात्रा तथा फीडबैक विदेशी व्यापार गुणक के मान पर निर्भर करेगी। इस स्थिति में फीडबैक विदेश व्यापार गुणक का सूत्र होगा -

$$Kf^* = \frac{1 + (M_2/S_2)}{S_1 + M_1 + M_2(S_1/S_2)}$$

यदि, हम ऊपर दिए गए मानों को सूत्र में रखें तो,

$$K_f * = \frac{1 + (0.30/0.30)}{0.30 + 0.20 + 0.30(0.30/0.30)}$$

$$\frac{1 + 1}{0.50 + 0.30} = \frac{2}{0.80} = 2.50$$

स्पष्ट है कि यहाँ फीडबैक विदेशी व्यापार गुणक का मान (2.50) साधारण विदेशी व्यापार गुणक के मान (2) से अधिक है। इसलिए यदि देश A में प्रारम्भिक निवेश में 200 की वृद्धि होती है तो आय में वृद्धि होगी।

$$\Delta Y = K_f * \Delta I$$

$$2.50 * 200 = 500Cr$$

साधारण विदेशी व्यापार गुणक (K) की स्थितियाँ

$$\Delta Y = K_f * \Delta I = 2.50 * 200 = 500$$

उल्लेखनीय है कि विदेशी प्रति-प्रभाव की उपस्थिति में निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि (500Cr), निर्यात में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि (250Cr) की अपेक्षा अधिक है। साथ ही यह साधारण विदेशी व्यापार गुणक की स्थिति में राष्ट्रीय आय में वृद्धि (400Cr) से भी अधिक है।

विदेशी प्रति-प्रभाव या अति निर्यात प्रभाव का नीतिगत निहितार्थ यह है कि यदि एक देश द्वारा निर्यात प्रोत्साहन की नीति अपनायी जाती है तो इससे उस देश तथा उससे व्यापारिक संबंध रखने वाले देशों की राष्ट्रीय आय में वृद्धि धीमी गति से होगी। परन्तु यदि निवेश में वृद्धि की नीति अपनायी जाती है तो इससे इस देश सहित सभी देशों की राष्ट्रीय आय में तीव्र गति से वृद्धि होगी। निवेश विस्तार कार्यक्रमों से वस्तुओं और सेवाओं के विश्व व्यापार के आकार में बढोत्तरी होगी, विश्व आय तथा रहन-सहन के स्तर में सुधार तो होगा ही।

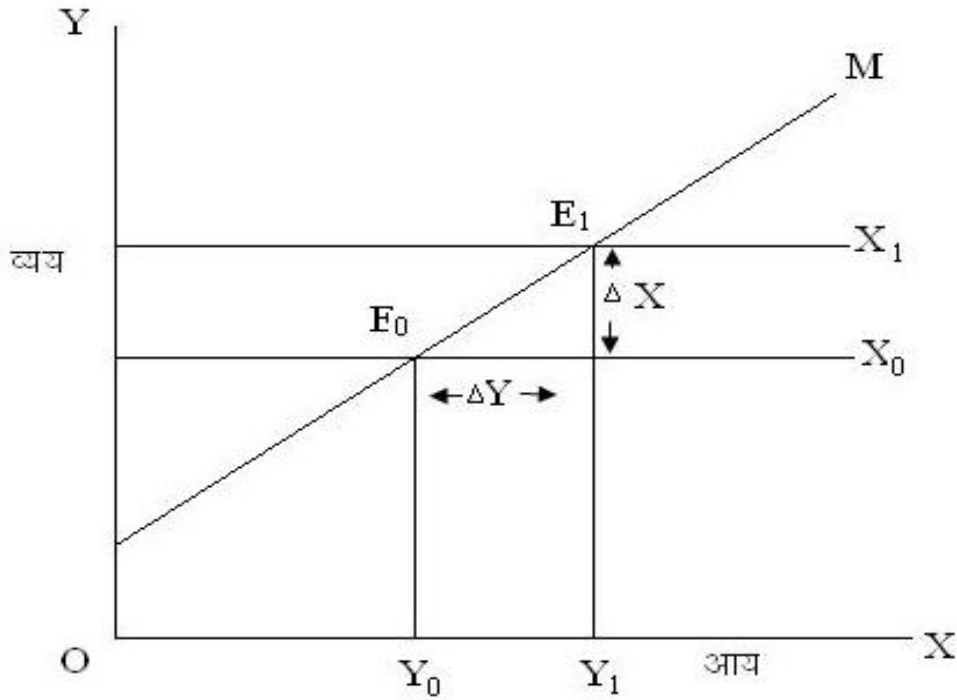
विकसित देशों में अपने निर्यात वृद्धि के साथ-साथ विकासशील तथा अर्द्धविकसित देशों की राष्ट्रीय तथा प्रतिव्यक्ति आय पर पड़ने वाले प्रभावों को भी ध्यान में रखना चाहिए अन्यथा इन देशों की राष्ट्रीय आय पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव विकसित देशों की राष्ट्रीय आय से भी प्रभावित करेंगे।

वास्तव में निर्यात प्रोत्साहन नीतियाँ घरेलू निवेश की तुलना में व्यापार कर रहे सभी देश में राष्ट्रीय आय को कम दर से बढ़ाती हैं। घरेलू निवेश में वृद्धि की नीतियाँ या कार्यक्रम प्रति-प्रभावों द्वारा विदेशी व्यापार गुणक के मान को बढ़ाकर राष्ट्रीय आय को कई गुणा बढ़ा देती हैं जिससे व्यापार-संतुलन का घाटा कम हो जाता है।

विकसित या बड़े देशों का प्रति-प्रभाव या अति-निर्यात प्रभाव (Backwash effect) अधिक होगा जैसे यदि निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप अमेरिका की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो इससे उसके आयातों में वृद्धि से अन्य कई देशों के निर्यात में और फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। जिससे इन देशों की आयातों में वृद्धि होगी जो आगे अमेरिका के निर्यात और आय को बढ़ाएगी।

12.6 विदेशी व्यापार गुणक का चित्र द्वारा निरूपण

घरेलू क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र की अनुपस्थिति में विदेशी व्यापार गुणक $\frac{1}{MPM}$ के बराबर होगा और राष्ट्रीय आय में वृद्धि निर्यात वृद्धि की अपेक्षा अधिक होगी। चित्र 12.3 में X अक्ष पर आय तथा Y अक्ष पर व्यय है। वक्र-X निर्यात तथा वक्र-M आयातों को प्रदर्शित कर रहा है। आय स्तर Y पर आयात M तथा निर्यात X आपस में बराबर हैं।

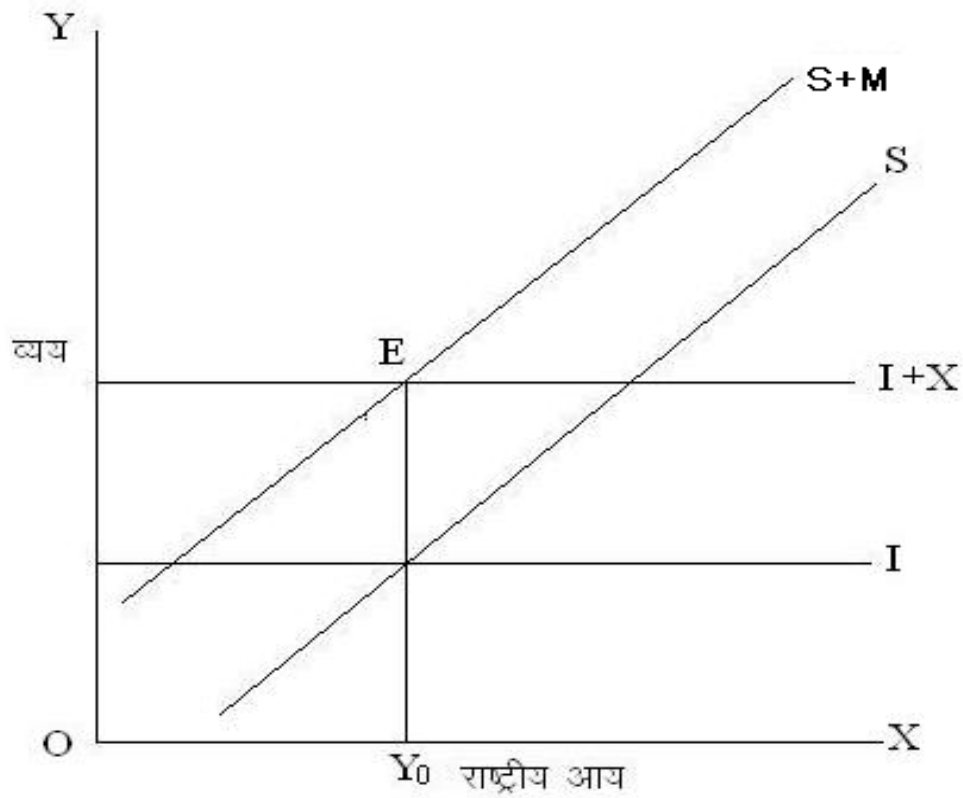


चित्र संख्या 12.3

जब निर्यात X से बढ़कर X_1 हो जाता है तो संतुलन राष्ट्रीय आय Y से बढ़कर Y_1 हो जाती है। बिन्दु E_1 पर, Y_1 आय स्तर पर भी निर्यात और आयात बराबर है। निर्यात में परिवर्तन (OX) के फलस्वरूप आय में परिवर्तन (OY) निर्यात वृद्धि से अधिक है। आय में वृद्धि विदेशी व्यापार गुणक (K_f) के मान पर निर्भर करता है और विदेशी व्यापार गुणक (K_f) का मान सीमान्त आय प्रवृत्ति (MPM) पर निर्भर करता है।

आयात वक्र M की ढाल सीमान्त आय प्रवृत्ति को बताती है। यह ढाल जितना ही कम होगा अर्थात आय प्रवृत्ति को बताती है। यह ढाल जितना ही कम होगा अर्थात सीमान्त आय प्रवृत्ति (MPM) का मान जितना ही कम होगा गुणक का मान उतना ही अधिक होगा और निर्यात वृद्धि से आय में वृद्धि उतनी ही अधिक होगी। यदि आयात फलन के साथ निवेश और बचत फलन को भी सम्मिलित कर लिया जाय तो अर्थव्यवस्था के संतुलन को चित्र 12.4 में दिखाया गया है।

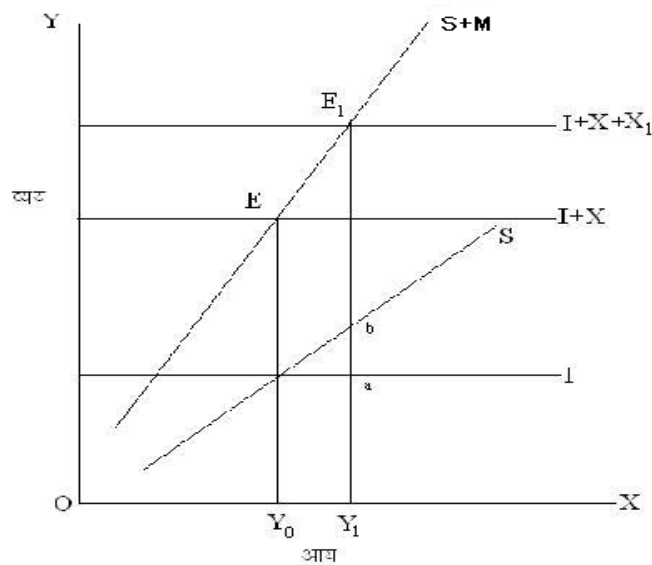
चित्र 12.4 में Y_0 आय स्तर पर बचत और निवेश तथा आयात और निर्यात आपस में बराबर है। S वक्र बचत और (S+M) वक्र बचत तथा आयात के योग को दर्शाता है। I घरेलू निवेश को व्यक्त करता है तथा (I+X) वक्र घरेलू निवेश तथा निर्यात के योग को व्यक्त करता है। बिन्दु E पर बचत तथा आयातों का योग, निवेश तथा निर्यातों के योग के बराबर है ($I+M=I+X$)।



चित्र 12.4

12.6.1 विदेशी प्रतिक्रियाओं या प्रतिप्रभाव की अनुपस्थिति में विदेशी व्यापार गुणक

यदि निर्यात में वृद्धि के कारण $(I+X)$ वक्र ऊपर की ओर सरक कर $(I+X+X_1)$ हो जाता है तो नया संतुलन E_1 बिन्दु पर होता है। जहाँ $(I+X+X_1)$ तथा $(S+M)$ आपस में बराबर हैं और राष्ट्रीय आय OY_0 से बढ़कर OY_1 हो जाती है जैसा कि चित्र 12.5 में दिखाया गया है।



चित्र 12.5

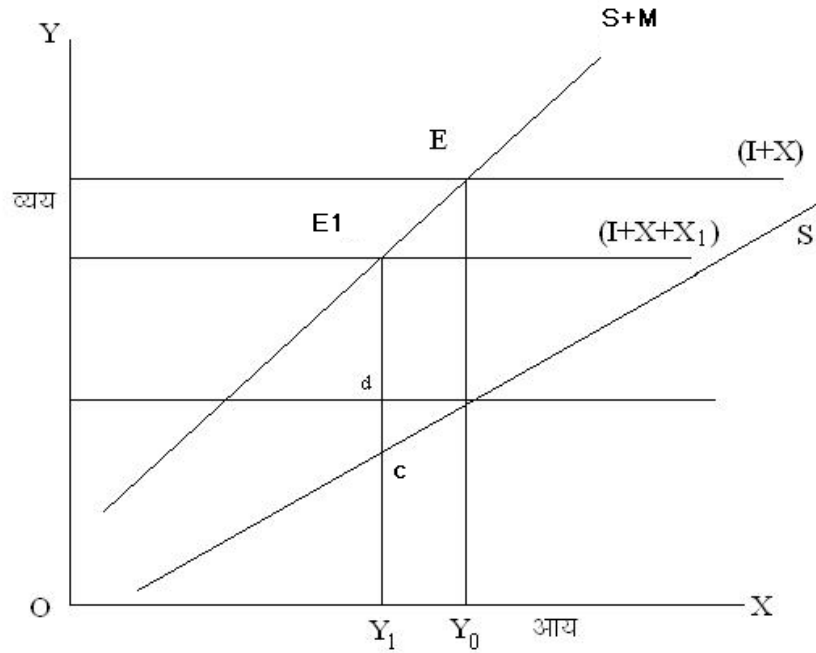
आय में वृद्धि गुणक प्रभाव के कारण होती है। आय में वृद्धि कितनी होगी यह विदेशी व्यापार गुणक (K_f) पर निर्भर करेगी क्योंकि

$$\Delta Y = k_f \Delta X$$

यहाँ,

$$k_f = \frac{1}{MPS + MPM} = \frac{1}{S + M}$$

अर्थात् विदेशी व्यापार गुणक K_f का मूल्य सीमान्त बचत तथा आयात प्रवृत्ति या $(S+M)$ वक्र के ढाल पर निर्भर करेगा। Y_1 आय स्तर पर बचत निवेश से ab अधिक है। अतः Y आय स्तर पर निर्यात भी आयात से ab मात्रा में अधिक है। अतः Y आय स्तर पर भुगतान संतुलन का चालू खाता संतुलन में नहीं है और देश पूँजी का निर्यात करता है जिससे A बिन्दु पर निर्यात और निवेश का योग बचत तथा आयात के योग के बराबर है।



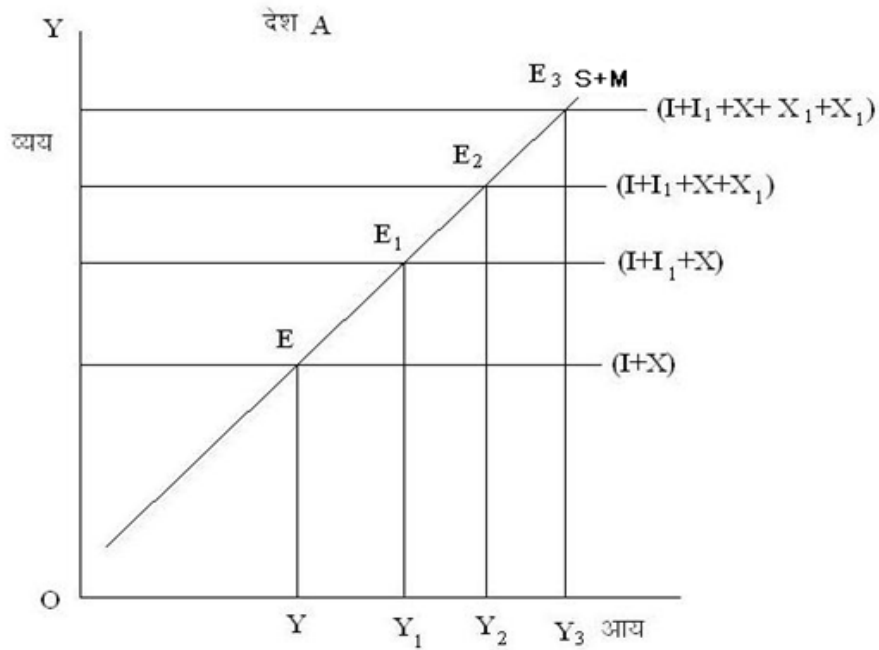
चित्र 12.6

चित्र 12.6 में इसके विपरीत यदि निर्यात में कमी हो जाती है तो $(I+X)$ वक्र नीचे की ओर विवर्तित होकर $(I+X+X_1)$ हो जाता है और संतुलन Y_0 से घटकर Y_1 आय स्तर पर आ जाता है। यहाँ विदेशी व्यापार गुणक विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। Y_1 आय स्तर घरेलू विनियोग (I), घरेलू बचत (S) से cd अधिक है। अर्थात् आयात भी निर्यात से cd मात्रा में अधिक है और चालू खाता में घाटा है और देश को निवेश की पूर्ति के लिए पूँजी का आयात करना पड़ेगा।

12.6.2 विदेशी प्रतिक्रियाओं या प्रतिप्रभाव की उपस्थिति में विदेशी व्यापार गुणक

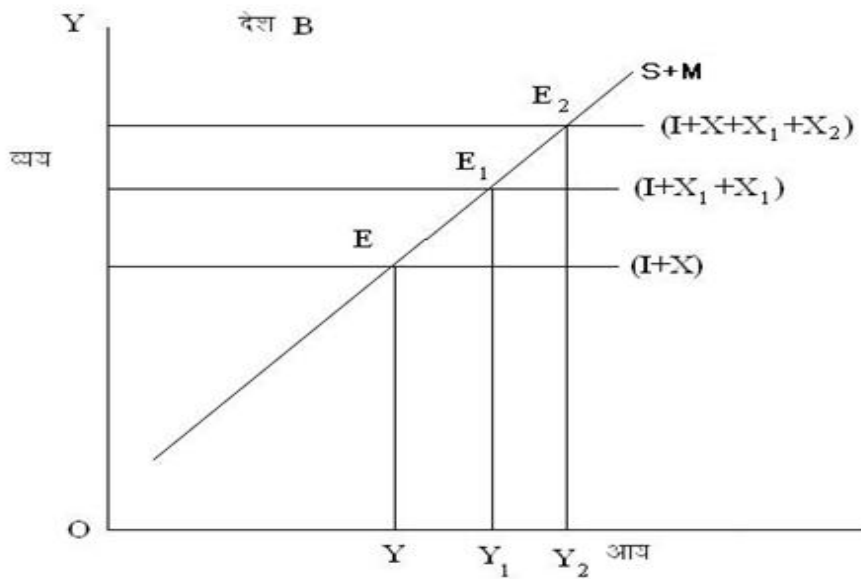
निवेश के फीडबैक विदेशी व्यापार गुणक के प्रभाव को चित्र 12.7 में दर्शाया गया है। चित्र 12.7(A) में घरेलू देश A के निवेश में II मात्रा में वृद्धि होती है जिससे $(I+X)$ वक्र ऊपर की ओर सरक कर $(I+II+X)$ हो

जाता है। परिणामस्वरूप बचत और आयात तथा निवेश और निर्यात के योग का नया संतुलन E_1 बिन्दु पर होता है जहाँ राष्ट्रीय आय OY से बढ़कर OY_1 हो जाती है।



चित्र 12.7 A

जब देश A में राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो उसके आयातों में वृद्धि होने से देश के निर्यातों में वृद्धि होती है जिससे देश B का $I+X$ वक्र ऊपर की ओर विवर्तित होकर $I+X+X_1$ हो जाता है और देश B की राष्ट्रीय आय OY से बढ़कर OY_1 हो जाती है। जैसा चित्र 12.7 (B) में दिखाया गया है। जब देश B की आय में वृद्धि हाती है तो इसके आयात बढ़ते हैं। जोकि देश के निर्यातों को सीधे बढ़ा देते हैं। जो कि अति निर्यात-प्रभाव या फीडबैक प्रभाव है।



चित्र 12.7 B

चित्र 12.7(A) में, देश A के निर्यात में वृद्धि होने पर $(I+I_1+X)$ वक्र ऊपर की ओर विवर्तित होकर $(I+I_1+X+X_1)$ हो जाता है और नए संतुलन बिन्दु E_2 पर राष्ट्रीय आय बढ़कर OY_2 हो जाती है। और यह पुनः आगे देश B के निर्यातों और राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाती है और यह क्रम दोनों ही देशों में संचयी रूप से चलता रहता है।

12.7 विदेशी व्यापार गुणक का महत्व

विदेशी व्यापार गुणक से हमें यह ज्ञात होता है कि विदेशी क्षेत्र में हुए परिवर्तनों का या घरेलू क्षेत्र में हुए परिवर्तनों का राष्ट्रीय आय या अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, बचत और निवेश अन्तराल का विदेशी आयात तथा निर्यात अन्तराल से घनिष्ठ संबंध है। इसलिए विभिन्न नीतियों के निर्माण में विदेशी व्यापार गुणक का विशेष महत्व है विशेषकर एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जहाँ विदेशी व्यापार का राष्ट्रीय आय में योगदान अधिक है।

विदेशी व्यापार गुणक यह बताता है कि आयात प्रवृत्तियों को कम करके गुणक के मान को बढ़ाया जा सकता है और तब निर्यात संवर्धन-कार्यक्रमों को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है, इससे व्यापार संतुलन के घाटे में कमी लायी जा सकती है।

घरेलू निवेश बढ़ाकर घरेलू उद्योगों को विकसित कर राष्ट्रीय आय तथा निर्यातों में तेजी से वृद्धि की जा सकती है क्योंकि तब गुणक का मान अधिक होगा।

12.8 विदेशी व्यापार गुणक की आलोचनाएँ

1. विदेशी व्यापार गुणक के विश्लेषण में यह मान लिया गया है कि निर्यात और निवेश स्वायत्त है अर्थात् राष्ट्रीय आय में परिवर्तनों से स्वतंत्र है तथा आयात आय का फलन है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। निर्यात में वृद्धि से आय में हमेशा वृद्धि नहीं होती है, और फिर आयात भी सिर्फ आय से ही प्रभावित नहीं होता है। प्रो. मीड ने आयात को व्यय का फलन माना है। कुछ आयात, जैसे पूँजीगत वस्तुओं इत्यादि का आयात राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाते हैं।
2. यहाँ आयात क्षमता और आय में धनात्मक संबंध माना गया है। अर्थात् आय बढ़ने पर आयात बढ़ेगा और भुगतान-संतुलन प्रतिकूल हो जाएगा, परन्तु यह जरूरी नहीं है। क्योंकि राष्ट्रीय आय बढ़ने पर आन्तरिक तथा बाह्य मितव्ययिताओं में वृद्धि आती है जिससे निर्यात बढ़ते हैं।
3. विश्लेषण में उपभोग प्रवृत्ति, बचत प्रवृत्ति तथा आयात प्रवृत्ति को स्थिर मान लिया गया है, जो कि अवास्तविक मान्यता है।
4. यदि कोई देश छोटा हो तो विदेशी व्यापार गुणक का प्रभाव नगण्य होता है।
5. विश्लेषण में राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियों के प्रभाव की उपेक्षा की गयी है; जबकि सरकारें सदैव अपनी इन नीतियों के द्वारा आयातों तथा निर्यातों को प्रभावित करने में लगी रहती है।
6. यह इस मान्यता पर आधारित है कि स्वतंत्र व्यापार हो रहा है और व्यापार प्रतिबंध तथा विनिमय नियंत्रण नहीं है। वस्तुतः राज्य विभिन्न प्रतिबंधात्मक उपायों द्वारा व्यापार में अवरोध उत्पन्न करते हैं और विदेशी व्यापार गुणक के कार्यकरण को रोकते हैं।

12.9 अभ्यास हेतु प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न:

1. विदेशी व्यापार गुणक की व्याख्या कीजिए।

2. विदेशी व्यापार गुणक की व्युत्पत्ति कैसे की जाती है?
3. निवेश गुणक से आप क्या समझते हैं?
4. विदेशी व्यापार गुणक की कमियों पर प्रकाश डालिए।
5. निवेश के फीडबैक विदेशी व्यापार गुणक मॉडल की विवेचना कीजिये।
6. विदेशी व्यापार गुणक का महत्व बताइए।
7. निर्यात के फीडबैक विदेशी व्यापार गुणक मॉडल की विवेचना कीजिये।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न:

1. निवेश गुणक का सूत्र लिखिये।
2. साधारण विदेशी व्यापार गुणक का सूत्र लिखिये।
3. निवेश फीडबैक विदेशी व्यापार गुणक का सूत्र लिखिये।
4. फीडबैक विदेशी व्यापार गुणक का सूत्र लिखिये।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

1. विदेशी व्यापार गुणक का सूत्र है

$$(क) \Delta Y = k \Delta X \quad (ख) \frac{1}{1-b-g+m} = k_f$$

$$(ग) \frac{1}{s-g+m} = k_f \quad (घ) \text{ उपरोक्त सभी}$$

2. यदि निर्यात में वृद्धि 100 करोड़ रूपया तथा आय में वृद्धि 150 करोड़ रुपये हो तो गुणक का मान होगा...

$$(क) 0.67 \quad (ख) 1.5 \quad (ग) 1 \quad (घ) 0.59$$

3. यदि स्वायत्त निवेश में वृद्धि होती है तो आय में वृद्धि निर्भर करेगी

$$(क) \text{ गुणक के मान पर} \quad (ख) \text{ MPC पर}$$

$$(ग) \text{ MPS पर} \quad (घ) \text{ उपरोक्त सभी}$$

4. खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का समीकरण होता है

$$(क) Y = C+I+G \quad (ख) Y = C+I+G+(X+M)$$

$$(ग) Y = C+I+G+(X-M) \quad (घ) Y = C+I+G+X$$

5. यदि b का मान 0.8, g का मान 0.2 तथा m का मान 0.4 हो तो k_f का मान होगा

$$(क) 0.8 \quad (ख) 2.5 \quad (ग) 1 \quad (घ) 0.612$$

6. निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण अर्थव्यवस्था के संतुलन को व्यक्त नहीं करता है?

$$(क) C+I+G-X = C+S+T-M \quad (ख) I+G+X = S+T+M$$

$$(ग) C+I+G+X=C+S+T+M \quad (घ) I+X = S+M$$

7. विदेशी व्यापार गुणक का मान निवेश गुणक की तुलना में कम हो जाता है

$$(क) \text{ आयात बिल के भुगतान के रूप राष्ट्रीय आय में रिसाव होता है}$$

$$(ख) \text{ निर्यात वृद्धि के कारण हुई आय वृद्धि से निवेश बढ़ता है}$$

$$(ग) \text{ निर्यात वृद्धि के कारण आयातों में कमी होती है।}$$

$$(घ) \text{ निर्यात वृद्धि के कारण हुई आय वृद्धि से निवेश घटता है}$$

8. विदेशी प्रति प्रभाव की उपस्थिति में विदेशी व्यापार गुणक निर्भर करता है।

- (क) घरेलू सीमान्त बचत (ख) घरेलू सीमान्त आयात प्रवृत्ति
 (ग) विदेशी सीमान्त आयात प्रवृत्ति (घ) उपरोक्त सभी
9. विदेशी प्रति-प्रभाव की अनुपस्थिति में, निवेश में वृद्धि या निर्यात में वृद्धि दोनों का ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा
 (क) दोनों का एक तरह का प्रभाव होगा
 (ख) निवेश में वृद्धि का प्रभाव निर्यात में वृद्धि के प्रभाव से कम होगा
 (ग) निवेश में वृद्धि का प्रभाव निर्यात में वृद्धि के प्रभाव से अधिक होगा
 (घ) दोनों का प्रभाव अनिश्चित होगा
10. विदेशी प्रति-प्रभाव की उपस्थिति में, निवेश में वृद्धि तथा निर्यात में वृद्धि दोनों का ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा
 (क) दोनों का एक तरह का प्रभाव होगा
 (ख) निवेश में वृद्धि का प्रभाव निर्यात में वृद्धि के प्रभाव से कम होगा
 (ग) निवेश में वृद्धि का प्रभाव निर्यात में वृद्धि के प्रभाव से अधिक होगा
 (घ) दोनों का प्रभाव अनिश्चित होगा
11. निर्यात में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में वृद्धि निर्भर करती है
 (क) देश A में निर्यातों की प्रारम्भिक वृद्धि कितनी है,
 (ख) देश A में फीडबैक विदेशी व्यापार गुणक (K) का मान कितना है
 (ग) उपरोक्त दोनों पर
 (घ) उपरोक्त में से किसी पर नहीं
12. फीडबैक विदेशी व्यापार गुणक का सूत्र होगा
 (क) $K_f^* = \frac{1}{S_2 + M_1 + M_2(S_1/S_2)}$ (ख) $K_f^* = \frac{1}{S_2 + M_1 - M_2(S_1/S_2)}$
 (ग) $K_f^* = \frac{1}{S_2 - M_1 + M_2(S_1/S_2)}$ (घ) $K_f^* = \frac{1}{S_2 - M_1 - M_2(S_1/S_2)}$
13. निवेश फीडबैक विदेश व्यापार गुणक का सूत्र होगा -
 (क) $\frac{1 + (M_2/S_2)}{S_2 + M_1 + M_2(S_1/S_2)}$ (ख) $\frac{1}{S_2 + M_1 + M_2(S_1/S_2)}$
 (ग) $\frac{1 + (M_2/M_1)}{S_2 + M_1 + M_2(S_1/S_2)}$ (घ) $\frac{1 + (S_1/S_2)}{S_2 + M_1 + M_2(S_1/S_2)}$
14. यदि कोई देश छोटा हो तो विदेशी व्यापार गुणक का प्रभाव होगा -
 (क) शून्य होगा (ख) अधिक होगा
 (ग) नगण्य (घ) अनिश्चित होगा

सत्य व असत्य :

1. निर्यात में वृद्धि से व्यापार घाटा (X-M) कम होगा।
2. विदेशी व्यापार गुणक (k) का मान केन्सीय निवेश गुणक से अधिक होगा।

3. आयात एक सीमा तक अंतर्जात चर है। निर्यातों (X) को सामान्यतया बर्हिजात रूप से निर्धारित माना जाता है।
4. गुणक तथा सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति और सीमान्त निवेश प्रवृत्ति का सीधा संबंध है जबकि गुणक का सीमान्त बचत प्रवृत्ति से उल्टा या व्युत्क्रमानुपाती संबंध है।
5. यदि निवेश बचत से अधिक है तो व्यापार-संतुलन में अतिरेक और यदि निवेश बचत से कम है तो घाटा होगा।
6. निवेश और निर्यात राष्ट्रीय आय के प्रवाह में वृद्धि करते हैं जबकि बचत तथा आयात राष्ट्रीय आय के प्रवाह में रिसाव है।
7. घरेलू देश का निर्यात विदेशी देश की सीमान्त आयात प्रवृत्ति पर निर्भर होता है।
8. अतिरिक्त निर्यात और विदेशी विनियोग का देश के उत्पादन, रोजगार और आय पर विस्तारकारी प्रभाव होता है।
9. निर्यात वृद्धि की जगह यदि देश A में निवेश में वृद्धि होती है तो देश A में राष्ट्रीय आय में वृद्धि अपेक्षाकृत कम होगी।
10. एक देश दूसरे देश की अपेक्षा जितना छोटा होगा, विदेशी प्रति-प्रभाव उतना ही अधिक होगा।
11. यदि एक देश द्वारा निर्यात प्रोत्साहन की नीति अपनायी जाती है तो इससे उस देश तथा उससे व्यापारिक संबंध रखने वाले देशों की राष्ट्रीय आय में वृद्धि धीमी गति से होगी।
12. यदि निवेश में वृद्धि की नीति अपनायी जाती है तो इससे इस देश सहित सभी देशों की राष्ट्रीय आय में तीव्र गति से वृद्धि होगी।
13. घरेलू निवेश में वृद्धि की नीतियाँ या कार्यक्रम प्रति-प्रभावों द्वारा विदेशी व्यापार गुणक के मान को बढ़ाकर राष्ट्रीय आय को कई गुणा बढ़ा देती है जिससे व्यापार-संतुलन का घाटा कम हो जाता है।
14. बड़े देशों का अति-निर्यात प्रभाव कम होगा।
15. आयात प्रवृत्तियों को कम करके गुणक के मान को बढ़ाया जा सकता है और तब निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों को ज्यादा प्रभावी बनाकर व्यापार संतुलन के घाटे में कमी लायी जा सकती है।
16. प्रतिबंधात्मक उपाय विदेशी व्यापार गुणक के कार्यकरण को रोकते हैं।

12.10 सारांश

भुगतान-शेष के घाटे को दूर करने के लिए राष्ट्रीय आय में कमी करके घाटे को कम किया जा सकता है। जब किसी देश के निर्यात में वृद्धि होती है तो निर्यात उद्योगों से संबंधित सभी व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है। इस बढ़ी हुई आय से अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मांग उत्पन्न होती है, उन उद्योगों का विस्तार होता है। रोजगार में वृद्धि होती है और आगे आय में और वृद्धि होती है। इस प्रकार, अंतिम रूप में आय में हुई वृद्धि निर्यात-वृद्धि की अपेक्षा काफी अधिक होती है, जो कि गुणक प्रभाव का परिणाम है। निर्यात में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई यह विदेशी व्यापार गुणक या निर्यात गुणक पर निर्भर करता है। निर्यात गुणक का मूल्य सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या बचत प्रवृत्ति तथा सीमांत आयात प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। विदेशी व्यापार गुणक

k_f को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है- $k_f = \frac{1}{1-b-g+m}$

विदेशी प्रति प्रभाव की उपस्थिति में विदेशी व्यापार गुणक न सिर्फ घरेलू सीमान्त बचत तथा आयात प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है बल्कि यह विदेशी सीमान्त बचत तथा आयात प्रवृत्तियों पर भी निर्भर करता है। विदेशी प्रति-प्रभाव की अनुपस्थिति में निवेश में वृद्धि या निर्यात में वृद्धि दोनों का ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि पर एक तरह

का प्रभाव पड़ेगा। परन्तु विदेशी प्रति-प्रभाव की उपस्थिति में निर्यात में वृद्धि और उसी मात्रा में निवेश में वृद्धि का राष्ट्रीय आय पर प्रभाव अलग-अलग होगा।

विदेशी प्रति-प्रभाव की उपस्थिति में विदेशी व्यापार गुणक का मान साधारण विदेशी व्यापार गुणक की अपेक्षा कम होगा। परन्तु विदेशी प्रति-प्रभाव की उपस्थिति में निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि निर्यात में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि की अपेक्षा अधिक होगी। साथ ही यह साधारण विदेशी व्यापार गुणक की स्थिति में राष्ट्रीय आय में वृद्धि से भी अधिक होगी।

विदेशी क्षेत्र में हुए परिवर्तनों का या घरेलू क्षेत्र में हुए परिवर्तनों का राष्ट्रीय आय या अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है यह हमें विदेशी व्यापार गुणक से ज्ञात होता है। विशेषकर एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जहाँ विदेशी व्यापार का राष्ट्रीय आय में योगदान अधिक है विभिन्न नीतियों के निर्माण में विदेशी व्यापार गुणक का विशेष महत्व है। यह बताता है कि आयात प्रवृत्तियों को कम करके गुणक के मान को बढ़ाया जा सकता है और तब निर्यात संवर्धन-कार्यक्रमों को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है, इससे व्यापार संतुलन के घाटे में कमी लायी जा सकती है। घरेलू निवेश बढ़ाकर घरेलू उद्योगों को विकसित कर राष्ट्रीय आय तथा निर्यातों में तेजी से वृद्धि की जा सकती है।

12.11 शब्दावली

- **सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC or b)** - आय में वृद्धि के फलस्वरूप हुई उपभोग वृद्धि का आय वृद्धि से अनुपात है सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति। गणितीय रूप में MPC या $b = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$
- **सीमान्त बचत प्रवृत्ति (MPS or s)** - आय में वृद्धि के फलस्वरूप हुई बचत वृद्धि तथा आय वृद्धि का अनुपात सीमान्त बचत प्रवृत्ति (s) कहलाता है। गणितीय रूप में MPS या $s = \frac{\Delta S}{\Delta Y}$ सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमान्त बचत प्रवृत्ति का योग इकाई के बराबर होता है।
अर्थात् $MPC + MPS = 1$ ($b + s = 1$)
 $MPC = 1 - MPS$ या $MPS = 1 - MPC$
- **सीमान्त निवेश प्रवृत्ति (g)** - यदि आय में वृद्धि के फलस्वरूप प्रेरित निवेश बढ़ता है तो निवेश वृद्धि का आय वृद्धि से अनुपात सीमान्त निवेश प्रवृत्ति कहलाता है।
 MPI या $g = \frac{\Delta I}{\Delta Y}$
- **विदेशी प्रति-प्रभाव या अतिनिर्यात प्रभाव** - एक देश के निर्यात और आयात में परिवर्तन न सिर्फ उस देश की राष्ट्रीय आय को प्रभावित करते हैं और उससे प्रभावित होते हैं बल्कि इसका प्रभाव उन देशों की राष्ट्रीय आय पर भी पड़ता है जिनसे उसका व्यापारिक संबंध है। बदले में दूसरे देशों की राष्ट्रीय आय में परिवर्तनों के भी उस देश के आयातों और राष्ट्रीय आय पर प्रभाव पड़ता है, इसे विदेश प्रति-प्रभाव या अतिनिर्यात प्रभाव कहते हैं।

12.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न:

1. घ	2.ख	3.घ	4.ग	5.ख	6.क
7. क	8.घ	9. क	10. ग	11.ग	12. ख
13.क	14.ग				

सत्य व असत्य :

1. सत्य	2. असत्य	3. सत्य	4. सत्य	5. असत्य	6.सत्य
7. सत्य	8.सत्य	9. असत्य	10.असत्य	11.सत्य	12.सत्य
13.सत्य	14.असत्य	15.सत्य	16.सत्य		

12.13 संदर्भ ग्रंथ सूची

- HH. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: International Economics: Theory and Policy, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- Charles P Kindleberger, International Economics, Richard D. Irwin Inc., Illinois, 1968
- Dominik Salvatore, International Economics, John Willy & Sons, Inc., 2008
- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006 •
- सुदामा सिंह एवं एम0सी0 वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफ़ोर्ड एंड आई0बी0एच0 पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम0एल0 झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010।
- ज्ञानेंद्र सिंह कुशवाहा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1979।

12.14 उपयोगी/सहायक पाठ्य सामग्री

- HH. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt.Ltd. 2001
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: International Economics: Theory and Policy, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- Charles P Kindleberger, International Economics, Richard D. Irwin Inc.,Illinois, 1968
- Dominik Salvatore, International Economics, John Willy & Sons, Inc.,2008
- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006

- एस. एन. लाल, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहबाद, 2004
- एच. एस. अग्रवाल, तथा सी. एस. बरला, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2003.
- सुदामा सिंह एवं एम. सी. वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड एंड आई. बी. एच. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम0 एल0 झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010.
- डॉ. जी. सी. सिंघई एवं डॉ. जे. पी. मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा, 2010

12.15 निबंधात्मक प्रश्न

1. विदेशी व्यापार गुणक की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। यह किस प्रकार निवेश गुणक से भिन्न है। विदेशी व्यापार गुणक का महत्व भी बताइए।
2. विदेशी प्रति-प्रभाव के बिना तथा विदेशी प्रति-प्रभाव की उपस्थिति में विदेशी व्यापार गुणक की संकल्पना की व्याख्या कीजिए।
3. विदेशी व्यापार गुणक किस प्रकार से राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है, विस्तृत विवेचना कीजिए।
4. यह बताइए कि विदेश व्यापार गुणक क माध्यम से किस प्रकार भुगतान-संतुलन सिद्धान्त को गत्यात्मकता प्रदान की जा सकती है?
5. विदेशी प्रति-प्रभाव की उपस्थिति में विदेशी व्यापार गुणक की संकल्पना की विस्तृत व्याख्या कीजिए। निर्यात के फीडबैक विदेशी व्यापार गुणक मॉडल तथा निवेश के फीडबैक विदेशी व्यापार गुणक मॉडल में अंतर स्पष्ट कीजिये।

इकाई 13 - भुगतान संतुलन में समायोजन के परंपरागत अवशोषण (Conventional Absorption adjustment in Balance of Payments)

- 13.1 प्रस्तावना
- 13.2 उद्देश्य
- 13.3 भुगतान संतुलन में समायोजन
 - 13.3.1 व्यय-परिवर्तनकारी नीतियाँ
 - 13.3.2 व्यय-बदलावकारी नीतियाँ
- 13.4 अवमूल्यन
 - 13.4.1 भुगतान संतुलन के असंतुलन को दूर करने में अवमूल्यन का प्रभाव
- 13.5 अवमूल्यन का लोच दृष्टिकोण
 - 13.5.1 मार्शल लर्नर शर्ते या दशाएं
 - 13.5.2 लोच दृष्टिकोण का मूल्याङ्कन
- 13.6 अवमूल्यन का अवशोषण दृष्टिकोण
 - 13.6.1 अवशोषण दृष्टिकोण का मूल्याङ्कन
- 13.7 अभ्यास हेतु प्रश्न
- 13.8 सारांश
- 13.9 शब्दावली
- 13.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 13.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 13.12 उपयोगी/ सहायक पाठ्य सामग्री
- 13.13 निबंधात्मक प्रश्न

13.1 प्रस्तावना

इससे पहले की इकाई में आपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बंधित एक महत्वपूर्ण संकल्पना भुगतान संतुलन असंतुलन को कम करने या बढ़ाने में विदेशी व्यापार गुणक की भूमिका के बारे में अध्ययन किया . अध्ययन के पश्चात् आप विदेशी व्यापार गुणक की भूमिका तथा महत्व को समझ गए होंगे. आप जान गए होंगे कि राष्ट्रीय आय में समायोजन के माध्यम से भुगतान-संतुलन के असंतुलन को दूर किया जा सकता है।

पिछले अध्याय में आपने देखा कि निर्यात या घरेलू निवेश में परिवर्तन के द्वारा विदेशी व्यापार गुणक किस प्रकार से कार्य करता है और आय परिवर्तनों के द्वारा भुगतान -संतुलन के असंतुलन को दूर करने में सहायक हो सकता है। इस अध्याय में हम उन नीतियों की चर्चा करेंगे जो घरेलू व्यय में अर्थात् अवशोषण में कमी लाती है और इस संदर्भ में हम विशेष रूप से अवमूल्यन की चर्चा करेंगे।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप भुगतान संतुलन के असंतुलन को दूर करने में परम्परागत उपायों के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. विशेष रूप से अवमूल्यन के भुगतान संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों के सन्दर्भ में आप विस्तार से जान सकेंगे.

13.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप

- ✓ अवमूल्यन के बारे में जान पाएंगे. –
- ✓ अवमूल्यन के भुगतान संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों को विस्तार से समझ सकेंगे. –
- ✓ अवमूल्यन के लोच दृष्टिकोण के बारे में जान पाएंगे. –
- ✓ अवमूल्यन के अवशोषण दृष्टिकोण को जान पाएंगे. –
- ✓ आप समझ सकेंगे की अवमूल्यन भुगतान संतुलन के असंतुलन को दूर करने में किन स्थितियों में सहायक हो सकता है।

13.3 भुगतान संतुलन में समायोजन

पिछले अध्यायों के अध्ययन से आप समझ गए होंगे कि भुगतान संतुलन का असंतुलन एक देश के लिए हानिकारक है, इसका अर्थव्यवस्था पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से भुगतान संतुलन का घाटा अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसलिए भुगतान-संतुलन के घाटे के समायोजन के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं।

एक देश के भुगतान संतुलन के घाटे को खत्म या अवशोषित करने की क्षमता उसके अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय रिजर्वों की मात्रा द्वारा सीमित होती है। अल्पकालिक पूँजी उधारों द्वारा भुगतान-संतुलन घाटे को कुछ समय तक समायोजित किया जा सकता है। परन्तु इस पर लगातार वर्षों तक निर्भर नहीं रहा जा सकता है। यदि कीमतों, व्याज दरों, आय स्तरों और विनिमय दरों में परिवर्तनीयता हो तो भुगतान-संतुलन में समायोजन स्वतः ही हो जाएगा और यदि ऐसा नहीं है तो फिर समायोजन के लिए सरकार को विभिन्न नीतियों/ उपायों का सहारा लेना पड़ता है जैसे संकुचनकारी मौद्रिक और राजकोषीय नीति, अवमूल्यन, विनिमय नियंत्रण इत्यादि।

वास्तव में घाटे को दूर करने के लिए, यह आवश्यक है कि समायोजन के द्वारा या तो स्वायत्त प्राप्ति में वृद्धि हो या फिर स्वायत्त भुगतानों में कमी हो। यदि सरकार का कोई हस्तक्षेप न हो तो भुगतान-संतुलन का स्वतः समायोजन बाजार की शक्तियों द्वारा हो जाता है। परन्तु स्वतंत्र बाजारों की अनुपास्थिति में भुगतान-संतुलन के

समायोजन से संबंधित सरकारी नीति या उपाय अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वास्तविक जगत में आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप तथा नियंत्रण एक वास्तविकता है। सरकारें आज कीमतों, ब्याज दरों, आय स्तरों और विनिमय दरों सभी को नियंत्रित करती है। इसलिए भुगतान संतुलन का समायोजन मुख्यतः नीतिगत मुद्दा है।

एक देश द्वारा भुगतान-असंतुलन के घाटे को दूर करने के लिए जिन नीतिगत यंत्रों या विधियों का प्रयोग किया जाता है उसे मुख्यतः तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है

- (i) राजकोषीय तथा मौद्रिक नीति
- (ii) अवमूल्यन
- (iii) विनिमय नियंत्रण

मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ व्यय परिवर्तनकारी नीति (Expenditure Changing Policy) है जबकि अवमूल्यन व्यय बदलावकारी नीति (Expenditure Switching Policy) है। विनिमय नियंत्रणों का अध्ययन आप अगली इकाई में विस्तार से करेंगे।

13.3.1 व्यय परिवर्तनशील नीतियाँ (Expenditure Changing Policies)

राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियों के माध्यम से घरेलू व्यय (उपभोग+निवेश+सरकारी व्यय या C+I+G) में परिवर्तन किया जाता है। राजकोषीय नीति सरकारी व्यय (G) तथा करों के माध्यम से और मौद्रिक नीति मुद्रा पूर्ति (Ms) तथा ब्याज दर (i) के माध्यम से अर्थव्यवस्था के कुल व्यय को परिवर्तित करके भुगतान-संतुलन के असंतुलन को दूर करती है।

अनेक अर्थशास्त्रियों (जैसे जानसन) के अनुसार अवस्फिति (deflation) के द्वारा अर्थव्यवस्था में व्यय में कटौती और तदनु रूप आयातों पर व्यय में कटौती के द्वारा असंतुलन को दूर किया जा सकता है। आयातों पर व्यय में कटौती के लिए एक देश को संकुचनकारी राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ लागू करना होगा। राजकोषीय नीति के तहत सरकार, सरकारी व्ययों में कमी तथा करों में वृद्धि करेगी; जबकि मौद्रिक नीति के तहत मुद्रा-पूर्ति में कमी तथा ब्याज दरों में वृद्धि करेगी। इस प्रकार की संकुचनकारी नीति से राष्ट्रीय आय में कमी आएगी। जिससे आयात भी कम होंगे। यदि सीमान्त आयात प्रवृत्ति (MPM - m) अधिक होगी तो राष्ट्रीय आय की अपेक्षा आयात व्यय में कमी और भी अधिक होगी। और यदि यह मान लिया जाए कि निर्यात पर इस नीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो आयात-व्यय में कमी से भुगतान संतुलन घाटा कम होगा।

आगे हम, अवमूल्यन के अवशोषण दृष्टिकोण में भी देखेंगे कि यदि घरेलू व्यय या अवशोषण (C+I+G) में कमी होती है तो भुगतान संतुलन का घाटा कम होता है। जैसा कि आप जानते हैं

$$Y = (C + I + G) + (X - M)$$

जहाँ,

Y = राष्ट्रीय आय

G = सरकारी व्यय

C = उपभोग

X = निर्यात तथा

I = निवेश

M = आयात

यदि

$$C + I + G - a \text{ तथा } X - M = b$$

$$Y = a + b$$

$$b = Y - a$$

इस प्रकार व्यापार-संतुलन (b), राष्ट्रीय आय तथा घरेलू व्यय या अवशोषण (a) का अंतर है और अवशोषण या घरेलू व्यय के कम होने पर कम होगा। इस प्रकार, सरकार राजकोषीय और मौद्रिक नीति के द्वारा

अवशोषण और व्यय में कमी करके घाटे को कम कर सकती है।

13.3.2 व्यय बदलावकारी नीतियाँ

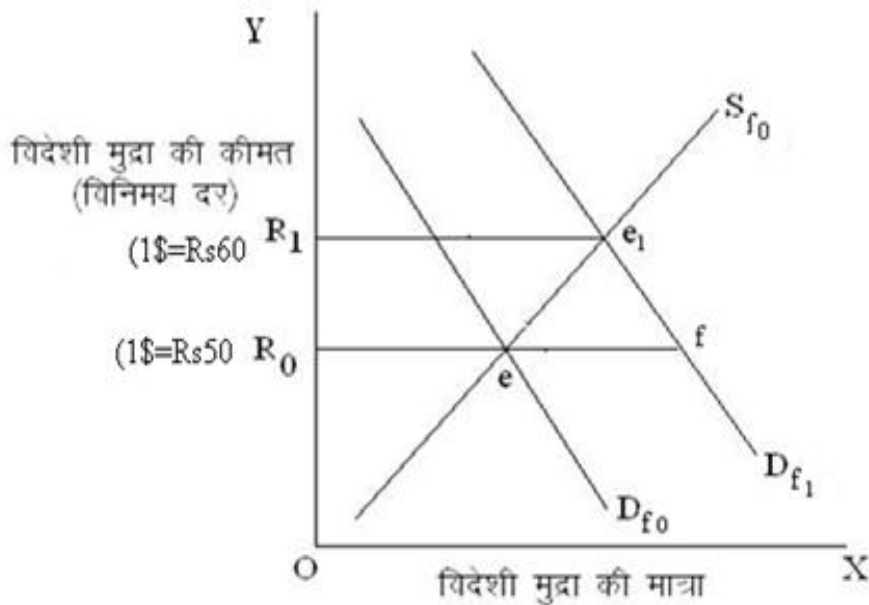
व्यय बदलावकारी नीतियों में वे उपाय आते हैं जो व्यय की दिशा को परिवर्तित कर देते हैं, जिससे घरेलू व्यय आयात-वस्तुओं से हटकर आयात-प्रतिस्थापित वस्तुओं की ओर चला जाए। आयात प्रतिस्थापन को उच्च प्रशुल्क देरे, कोटा, प्रत्यय नियंत्रण इत्यादि के द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है। दूसरी ओर यह नीति निर्यातों को आर्थिक सहायता देकर या निर्यात कीमतों में कमी करके निर्यात प्रोत्साहन भी करती है। अवमूल्यन व्यय की दिशा बदलने का एक यंत्र है।

13.4 अवमूल्यन

अवमूल्यन भुगतान-संतुलन के घाटे को समायोजित करने का एक यंत्र है जो घरेलू तथा विदेशी व्यय की दिशा को परिवर्तित कर देता है। अवमूल्यन घरेलू तथा विदेशी व्यय को विदेशी वस्तुओं तथा सेवाओं से हटाकर घरेलू वस्तुओं तथा सेवाओं की ओर मोड़ देता है। इसीलिए इसे व्यय बदलावकारी नीति (Expenditure Switching Policy) कहते हैं।

अवमूल्यन का अर्थ है सरकार द्वारा जानबूझकर घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य को अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राओं, सोना तथा SDRs के मुकाबले कम करना। इस प्रकार घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम करना अवमूल्यन है। स्पष्ट है कि अवमूल्यन के बाद अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राओं का मूल्य घरेलू मुद्रा की अपेक्षा बढ़ जाता है।

अवमूल्यन मुद्रा के मूल्य हास से भिन्न है। घरेलू मुद्रा के मूल्य में, विदेशी विनिमय बाजार में लगातार गिरावट मूल्यहास (Depreciation) है, जो कि बाजार की शक्तियों के कार्यकरण का परिणाम है। जब विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग विदेशी मुद्रा की पूर्ति से अधिक हो जाती है तो घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरता है यह मूल्यहास है। जैसा चित्र 13.1 में दिखाया गया है। चित्र में D_f तथा S_f विदेशी मुद्रा की मांग तथा पूर्ति वक्र हैं। विदेशी विनिमय बाजार में प्रारम्भिक संतुलन e बिन्दु पर जहाँ विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर है।



चित्र 13.1

जब मांग बढ़ती है और मांग वक्र D_f हो जाता है तो Rविनिमय दर पर (मान लिया $1\$=50$), विदेशी विनिमयकी मांग उसकी पूर्ति से e_f अधिक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप विदेशी विनिमय के मूल्य में वृद्धि या घरेलू मुद्रा के मूल्य में हास होता है और नए संतुलन e_1 पर विनिमय दर $R1(1\$='60)$ हो जाती है। इस प्रकार, मूल्य हास विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति के बीच असंतुलन का प्राकृतिक परिणाम है और यह भुगतान शेष के घाटे को दूर करने का एक तरीका है जबकि विदेशी विनिमय दर पूर्णतया परिवर्तनशील हो।

इसके विपरीत अवमूल्यन जानबूझकर और कानूनी ढंग से लिया गया अधिकृत सरकारी निर्णय है जिसके तहत घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी की जाती है। वस्तुतः अवमूल्यन का प्रभाव, मूल्यहास के समान ही होता है।

13.4.1 भुगतान-संतुलन के घाटे को दूर में अवमूल्यन का प्रभाव

अवमूल्यन का तात्कालिक प्रभाव यह होता है कि घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी से निर्यात सस्ते तथा आयात महंगे हो जाते हैं। निर्यातों की सापेक्षिक कीमतों के कम होने तथा आयातों की सापेक्षिक कीमतों के बढ़ने से निर्यात अर्जन में हुई वृद्धि या आयात व्यय में हुई कमी वस्तु और सेवाओं की मांग तथा पूर्ति लोचों पर निर्भर करेगी और इसी पर भुगतान-संतुलन के घाटे में कमी की सफलता निर्भर करेगी। यह अवमूल्यन के प्रभाव का 'लोच दृष्टिकोण' है।

परन्तु अवमूल्यन न सिर्फ निर्यातों तथा आयातों की सापेक्षिक कीमतों को प्रभावित करता है बल्कि यह अर्थव्यवस्था में आय परिवर्तनों को भी जन्म देता है। भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने में अवमूल्यन की सफलता आय में परिवर्तनों के कारण घरेलू व्यय या अवशोषण ($C+I+G$) में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करती है। इस दृष्टिकोण को 'अवशोषण दृष्टिकोण' कहते हैं।

इस प्रकार भुगतान-संतुलन के घाटे को दूर करने के लिए व्यय बदलावकारी नीति के रूप में अवमूल्यन के प्रभाव को लोच दृष्टिकोण और अवशोषण दृष्टिकोण दोनों ही विधियों से देखेंगे। पहले हम लोच दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे।

13.5 लोच दृष्टिकोण (Elasticity Approach)

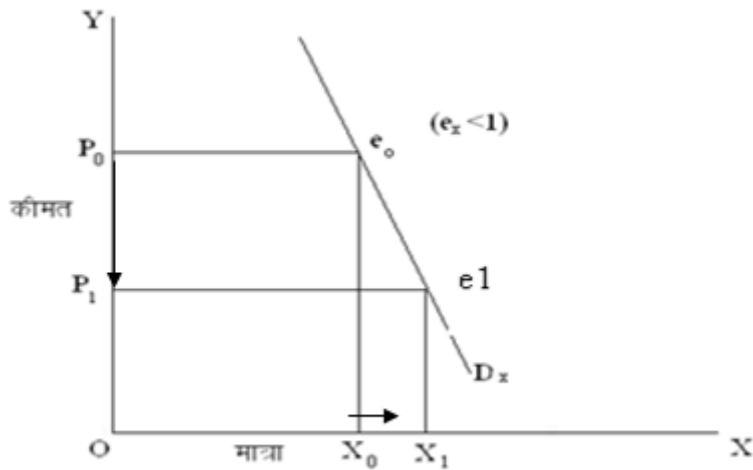
आप अब जान गए होंगे कि कोई देश जब अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले घरेलू मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और इस प्रकार उसके निर्यात विदेशों में सस्ते हो जाते हैं, जबकि घरेलू कीमतें स्थिर रहती हैं तथा आयात महंगे हो जाते हैं। स्पष्ट है कि यदि निर्यातों तथा आयातों का मांग-वक्र सामान्य हो तो; (i) निर्यात मांग बढ़ेगी और परिणामस्वरूप निर्यात आय भी, तथा (ii) आयातों की मांग कम होगी और परिणामस्वरूप आयात व्यय भी कम होगा।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए प्रारम्भ में $1\$=50$ था तथा अवमूल्यन (20%) के पश्चात $1\$=60$ हो जाता है। अब अवमूल्यन के पश्चात $1\$$ की आयातित वस्तु के लिए घरेलू उत्पादकों को 60 देने पड़ेंगे जबकि पहले वे मात्र 50 देते थे। इस प्रकार, विदेशों में पहले 50 की वस्तु के लिए $1\$$ खर्च करने पड़ते थे परन्तु अवमूल्यन के बाद अब $1\$$ में विदेशों में 60 की वस्तु मिल जाएगी। इस प्रकार घरेलू देश में लागत कीमत संरचना अवमूल्यन के बाद भी अपरिवर्तित है परन्तु अवमूल्यन के कारण विदेशों में उसकी वस्तु सस्ती हो जाती है। इसी प्रकार विदेशी देश में भी लागत-कीमत संरचना अपरिवर्तित है परन्तु घरेलू देश में अवमूल्यन के कारण आयातित वस्तु की कीमत बढ़ जाती है।

परन्तु अवमूल्यन के कारण निर्यात-आय में वृद्धि और आयात-व्यय में कमी निर्यात तथा आयात मांग-वक्रों की लोचों पर निर्भर करेगा। इस प्रकार, भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने में अवमूल्यन की सफलता

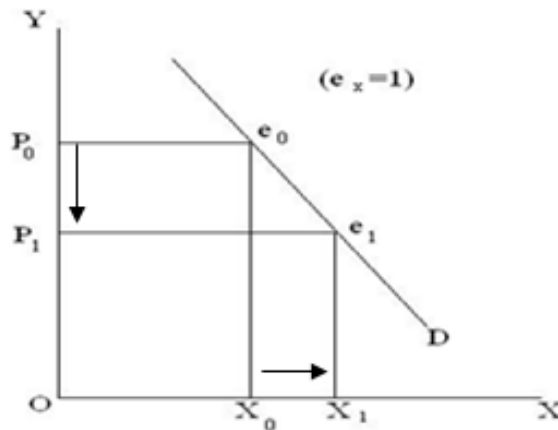
आयात तथा निर्यात की मांग लोचों पर निर्भर करेगी। आयात तथा निर्यात मांगे जितनी ही अधिक लोचशील होगी भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने में (या अधिक्य सृजन में) अवमूल्यन उतना ही अधिक सफल होगा। और यदि आयात तथा निर्यात की मांग कम लोचदार या बेलोचदार हैं तो अवमूल्यन देश के घाटे को कम करने में असफल रहेगा, वास्तव में तब यह भुगतान संतुलन के घाटे के आकार को और बढ़ा देगा। इसे हम चित्र की सहायता से समझ सकते हैं।

सबसे पहले निर्यात कीमतों को लेते हैं। जैसा कि आपने देखा अवमूल्यन से निर्यातित वस्तुओं की कीमत कम हो जाएगी और इससे निर्यातों की मांग बढ़ेगी। परन्तु इसका निर्यात आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह निर्यातों की विदेशी देश में मांग की लोच पर निर्भर करेगा। चित्र 13.2 में निर्यातों की मांग लोच की तीन विभिन्न स्थितियों में निर्यात अर्जन पर पड़ने वाले प्रभावों का दिखाया गया है। चित्र 13.2 में X-अक्ष पर निर्यातों की मात्रा तथा Y-अक्ष पर निर्यातों की कीमतें हैं। निर्यात वक्र D_x ऋणात्मक ढाल वाला है जो यह बताता है कि मांग और निर्यात कीमत में विपरीत संबंध है।



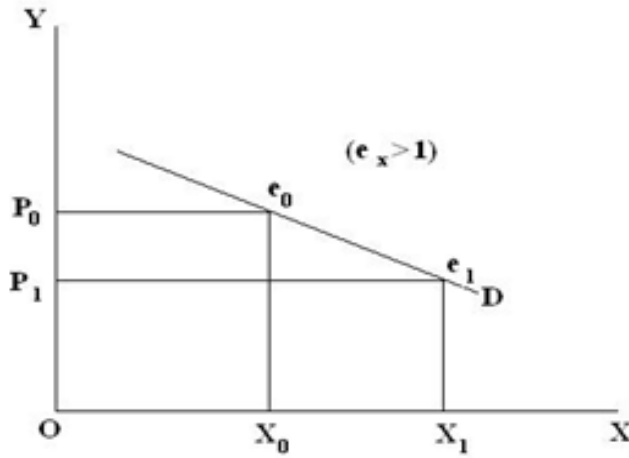
चित्र 13.2A

चित्र 13.2 (A) में निर्यात मांग वक्र D_x बेलोचदार है। अवमूल्यन के कारण निर्यात कीमत जब OP_0 से OP_1 हो जाती है तो निर्यातों की मांग OX_0 से OX_1 हो जाती है। निर्यात अर्जन जो कि पहले $P_0OX_0e_0$ था, अवमूल्यन के पश्चात $P_1OX_1e_1$ हो जाता है। यहाँ स्पष्ट है कि आयात $P_1OX_1e_1$ का क्षेत्रफल $P_0OX_0e_0$ से कम है अर्थात अवमूल्यन के पश्चात निर्यात आय में कमी हो जाती है।



चित्र 13.2 (B)

चित्र 13.2 (B) में निर्यात मांग वक्र की लोच इकाई है ($e_x=1$) तो निर्यात कीमत में कमी के फलस्वरूप निर्यात अर्जन $P_1OX_1e_1$ हो जा रहा है। जो अवमूल्यन से पहले के निर्यात अर्जन $P_0OX_0e_0$ से के ही बराबर है।

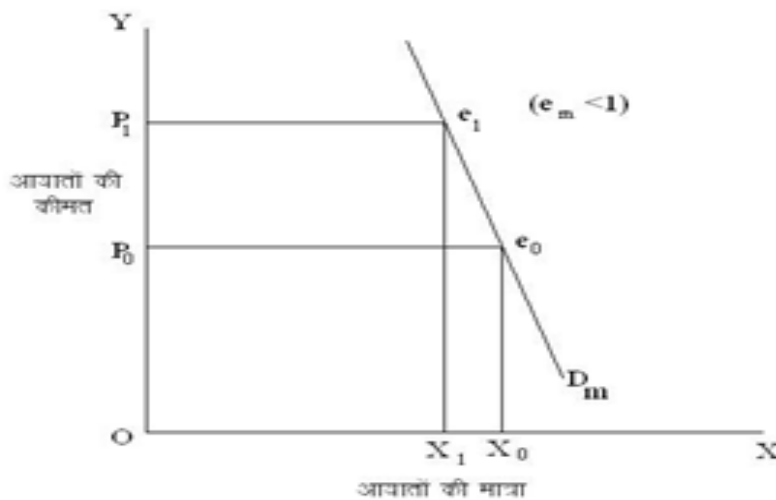


चित्र 13.2(C)

चित्र 13.2 (C) में निर्यात मांग वक्र लोचदार है ($e_x > 1$) अर्थात् इसकी लोच इकाई से अधिक है। अवमूल्यन के पश्चात् जब निर्यात कीमत घटकर OP हो जाती है तो निर्यात मांग बढ़कर OX_1 हो जाती है और परिणामस्वरूप निर्यात अर्जन $P_0OX_0e_0$ से बढ़कर $P_1OX_1e_1$ हो जाता है। स्पष्ट है कि आयात $P_1OX_1e_1$ का क्षेत्रफल आयात $P_0OX_0e_0$ के क्षेत्रफल से अधिक है।

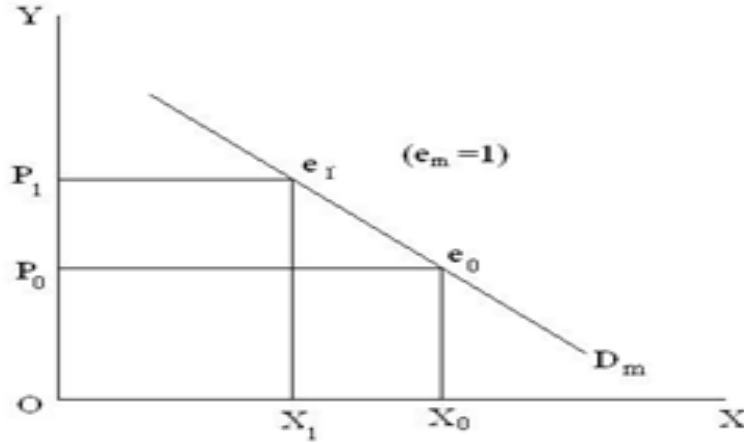
इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि निर्यातों की मांग-लोच इकाई से अधिक है अर्थात् लोचदार है तो अवमूल्यन निर्यात अर्जन में वृद्धि के द्वारा भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने में सफल होगा। यदि इकाई से कम है या बेलोचदार है तो घाटे को बढ़ाएगा और यदि इकाई के बराबर है तो न तो घाटा बढ़ेगा और न ही उसमें कोई सुधार होगा।

इसी प्रकार, आयात-कीमतों में परिवर्तन आयातों की मांग-लोच पर निर्भर करेगा कि आयात-व्यय में कितनी कमी होगी और उसका व्यापार-संतुलन के घाटे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चित्र 13.3 में आयातों की मांग लोच – लोचदार, इकाई लोच तथा बेलोचदार - का आयात व्यय पर पड़ने वाले प्रभावों को दिखाया गया है। चित्र 13.3 में X-अक्ष पर आयातों की मात्रा तथा Y-अक्ष पर आयातों की कीमतें हैं।



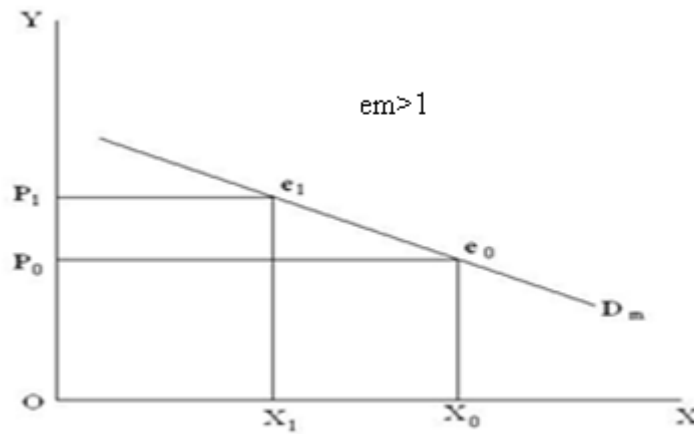
चित्र 13.3(A)

चित्र 13.3 (A) में आयात मांग वक्र बेलोचदार ($e_m < 1$) है। अवमूल्यन के कारण जब आयातित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत OP से बढ़कर OP_1 हो जाती है तो आयात OX से कम होकर OX_1 हो जाता है। स्पष्ट है कि कीमतों में वृद्धि की अपेक्षा व्यय में हुई कमी काफी कम है क्योंकि अवमूल्यन के बाद आयातों पर व्यय $P_1OX_1e_1$, अवमूल्यन के पहले आयातों पर होने वाले व्यय $P_0OX_0e_0$ से काफी अधिक है।



चित्र 13.3 (B)

चित्र 13.3 (B) में आयात मांग-वक्र की लोच इकाई के बराबर है ($e_m=1$)। आयात कीमतों में, अवमूल्यन के कारण, वृद्धि के फलस्वरूप आयात में कमी कीमत में वृद्धि के बराबर है और अवमूल्यन से पहले तथा बाद दोनों ही आयात व्यय बराबर है अर्थात् $P_1OX_1e_1 = P_0OX_0e_0$



चित्र 13.3(C)

चित्र 13.3 (C) में आयात मांग-वक्र लोचदार है अर्थात् इसकी लोच इकाई से अधिक है ($e_m > 1$)। अवमूल्यन के कारण जब आयात कीमत बढ़कर OP_0 से OP_1 हो जाती है तो मांग से OX , घटकर OX_1 हो जाती है और आयात व्यय $P_0OX_0e_0$ से $P_1OX_1e_1$ हो जाता है। परन्तु $P_1OX_1e_1 < P_0OX_0e_0$ । अवमूल्यन के बाद आयातों पर व्यय अवमूल्यन के पहले आयातों पर होने वाले व्यय से काफी कम है।

यदि आयातों की मांग-लोच इकाई से अधिक है या लोचदार है तो अवमूल्यन आयात कीमतों में वृद्धि के द्वारा आयात-व्यय में कमी लाएगा और भुगतान संतुलन के घाटे को कम करेगा; यदि आयातों की मांग-लोच इकाई है तो आयात-व्यय अवमूल्यन के बाद भी अपरिवर्तित रहेगा और यदि मांग लोच इकाई से कम या बेलोचदार है तो अवमूल्यन के बाद आयात व्यय में वृद्धि हो जाएगी और अवमूल्यन भुगतान-शेष के घाटे को बढ़ा

देगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अवमूल्यन की भुगतान-संतुलन के घाटे को कम करने की सफलता आयातों तथा निर्यातों की मांग-लोच पर निर्भर करेगी।

इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि आयात और निर्यात मांगे जितनी ही अधिक लोचदार होंगी, भुगतान-संतुलन के घाटे को कम करने में अवमूल्यन उतना ही अधिक सफल होगा और यदि आयात और निर्यात मांग लोचें इकाई से कम है या बेलोचदार है तो अवमूल्यन घाटे को कम करने में सफल नहीं होगा बल्कि यह घाटे को और बढ़ा देगा।

13.5.1 मार्शल और लर्नर शर्तें या दशाएं

उपरोक्त व्याख्या एक अति सामान्यीकृत व्याख्या है जो कि अवमूल्यन के प्रभावों का भुगतान-शेष पर प्रभावों का संकेत मात्र करती है। मार्शल-लर्नर दशाएं या शर्तें (Conditions) अवमूल्यन के भुगतान-संतुलन पर प्रभावों की अधिक विशिष्ट व्याख्या प्रस्तुत करता है। मार्शल-लर्नर शर्तों के अनुसार व्यापार-संतुलन को सुधारने (अर्थात् घाटा कम करने) में अवमूल्यन की सफलता आयात तथा निर्यात मांग लोचों के योग पर निर्भर करती है। यदि आयात तथा निर्यात की पूर्ति लोचे अनन्त दी हुई हो तो **मार्शल-लर्नर** के अनुसार, यदि निर्यातों तथा आयातों की मांग लोचों का योग ($e_x + e_m$)

- (i) इकाई से अधिक हो अर्थात् ($e_x + e_m$) > 1 तो अवमूल्यन व्यापार संतुलन के घाटे को कम करेगा और उसमें सुधार होगा,
- (ii) इकाई के बराबर है अर्थात् ($e_x + e_m$) $= 1$ तो अवमूल्यन से व्यापार-संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (iii) यदि इकाई से कम हो अर्थात् ($e_x + e_m$) < 1 तो अवमूल्यन व्यापार-संतुलन की स्थिति को और खराब कर देगा अर्थात् यह घाटे को और बढ़ा देगा।

13.5.2 लोच दृष्टिकोण का मूल्यांकन

1. मार्शल-लर्नर दशाएं पूँजीगतियों पर अवमूल्यन के प्रभावों की अवहेलना करती है। मार्शल-लर्नर दशाएं सिर्फ वस्तु व्यापार या चालू खाता भुगतान-संतुलन पर ही लागू होती है। सामान्यतया अवमूल्यन से पूँजी के अंतर्प्रवाह में वृद्धि होती है क्योंकि अवमूल्यन के पश्चात् विदेशी मुद्रा की एक इकाई से अधिक घरेलू मुद्रा खरीदी जा सकती है। अतः अवमूल्यन से अवमूल्यन करने वाले देश में दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक पूँजी के अंतर्प्रवाह में वृद्धि हो सकती है। साथ ही अवमूल्यन व्यक्तियों व फर्मों को देश के बाहर पूँजी ले जाने के लिए हतोत्साहित करता है। इस प्रकार भुगतान-संतुलन में सुधार लाने के लिए अवमूल्यन के पड़ने वाले प्रभाव को पूरी तरह से तभी जाना जा सकता है जबकि पूँजी खाते पर भी इसके प्रभाव को जान लिया जाय। इस प्रकार अवमूल्यन से एक देश के भुगतान-संतुलन के घाटे में सामान्यतया कमी आएगी क्योंकि अवमूल्यन वस्तु एवं सेवाओं के निर्यातों को बढ़ाएगा तथा आयातों को कम करेगा और इस प्रकार चालू खाता संतुलन में सुधार लाएगा। साथ ही पूँजी के अंतर्प्रवाह में वृद्धि तथा बहिर्प्रवाह में कमी के द्वारा पूँजी खाता में सुधार लाएगा। अवमूल्यन से एक पक्षीय हस्तांतरण भुगतानों के अंतर्प्रवाह में भी वृद्धि होती है। यदि अवमूल्यन देश में पर्याप्त मात्रा में पूँजी के अंतर्प्रवाह को बढ़ाने में सफल रहा तो निर्यात और आयात मांग लोचों के इकाई से कम होने पर भी भुगतान-संतुलन के घाटे को सुधारने में सफल होगा और यदि यह पर्याप्त मात्रा में पूँजी के अंतर्प्रवाह को बढ़ाने में सफल नहीं रहा तो निर्यात और आयात मांग लोचों के इकाई से कम होने पर भी घाटे को सुधारने में सफल नहीं होगा।

2. वास्तव में मार्शल-लर्नर दशाएँ सिर्फ वस्तु और सेवा घाटे पर लागू होती है। अवमूल्यन से निर्यात कीमतों में कमी और आयात कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप व्यापार-शर्ते (वस्तु व्यापार-शर्ते) उस देश के विरुद्ध हो जाती है। परन्तु यहाँ उल्लेखनीय है कि आय व्यापार शर्तों में सुधार के लिए एक देश जानबूझकर वस्तु व्यापार शर्तों में बिगड़ाव लाता है।
3. अवमूल्यन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि घरेलू देश में राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियों की प्रकृति कैसी है और वह घरेलू लागातों और कीमतों को नियंत्रित करने में कितना सफल रहता है। यदि अवमूल्यन के बाद घरेलू तथा विदेशी देश में कीमतों में परिवर्तन होता है तो अवमूल्यन के प्रभाव कम या समाप्त हो सकते हैं।
4. यदि एक देश पर अत्यधिक मात्रा में विदेशी ऋण हो तो अवमूल्यन के बाद विदेशी ऋण का भार और बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसे देश के लिए अवमूल्यन उसके वित्तीय संकट को और बढ़ा सकता है।
5. एक ऐसे देश को, जहाँ के आयात बेलोचदार हों, जहाँ आवश्यक मध्यवर्ती तथा पूँजीगत वस्तुओं और सेवाओं का आयात में हिस्सा अधिक हो, अवमूल्यन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे देश में अवमूल्यन के कारण आयात-व्यय और बढ़ जाएगा और भुगतान-संतुलन का घाटा भी।
6. मार्शल-लर्नर दशाएँ यह मान लेती है कि पूर्ति लोच अनन्त है। परन्तु सामान्यतया ऐसी स्थिति व्यवहार में नहीं पायी जाती है। विशेषकर अल्प विकसित देशों में निर्यातों के लिए उत्पादन बढ़ाने में पूर्ति पक्ष की ओर से अनेक प्रकार के अवरोध और कठोरताएँ पायी जाती है, जिससे वे अवमूल्यन से निर्यात कीमतों से कमी के कारण निर्यात मांग में वृद्धि के बावजूद उत्पादन पूरी तरह बढ़ाने में सक्षम नहीं होने के कारण अवमूल्यन के फायदों को पूरी तरह प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार पूर्ति लोचे अवमूल्यन की सफलता को काफी सीमित कर देती
7. अवमूल्यन एक अकेले देश के भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने में जो सहायक हो सकता है परन्तु यदि विश्व के अधिकतर देश भुगतान-संतुलन के घाटे से ग्रस्त हो और सभी अवमूल्यन का सहारा ले तो अवमूल्यन की इस प्रकार की होड़ से यह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकता। चूंकि अवमूल्यन अन्य देशों के व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव डालता है इसलिए अवमूल्यन की होड़ से विश्व व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
8. लोच दृष्टिकोण सिर्फ अवमूल्यन का सापेक्ष कीमतों और आयात-निर्यात की मात्राओं के आधार पर भुगतान-संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों को देखता है। इन परिवर्तनों का घरेलू अर्थव्यवस्था की आय पर प्रभाव पड़ेगा, और इस आय-वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा इसका अध्ययन यह दृष्टिकोण नहीं करता है।
9. अवमूल्यन का देश के अंदर संसाधनों के पुनर्वितरण की भी यह दृष्टिकोण उपेक्षा करता है।
10. यह दृष्टिकोण पूर्ण-प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है जो कि वास्तविक नहीं है।

वास्तव में, अवमूल्यन का प्रभाव स्थायी नहीं होता है। इसका लाभ सिर्फ सीमित समय तक ही रहता है जब तक कि नई विनिमय दर समता के अनुरूप लागत-कीमता संरचना, घरेलू तथा विदेशी देश में समायोजित नहीं हो जाती है। सामान्यतया अवमूल्यन का प्रभाव 2-3 वर्षों में समाप्त हो जाता है। अवमूल्यन इस दौरान अवमूल्यन करने वाले देश को समय प्रदान करता है कि वह अपने लागत-कीमता संरचना में उपयुक्त सुधार कर ले।

इस प्रकार, अवमूल्यन भुगतान-संतुलन में केवल अस्थायी समायोजन ही कर सकता है। स्थायी प्रकृति का दीर्घकालिक समायोजन तभी हो सकता है जबकि असंतुलन लाने वाले मूल कारकों को नियंत्रित किया जाए। अवमूल्यन अधिक मूलभूत प्रकृति के उपायों का पूरक ही हो सकता है उनका स्थानापन्न नहीं हो सकता है।

13.6 अवशोषण दृष्टिकोण

भुगतान-संतुलन पर अवमूल्यन के प्रभावों का लोच दृष्टिकोण आंशिक संतुलन विश्लेषण है। यह सिर्फ आयातों और निर्यातों की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन का भुगतान-संतुलन के घाटे पर पड़ने वाले प्रभावों की ही चर्चा करता है। इस परिवर्तन का अर्थव्यवस्था में समष्टि चरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी व्याख्या यह दृष्टिकोण नहीं करता है। इसलिए कई अर्थशास्त्रियों ने यह माना कि लोच दृष्टिकोण अवास्तविक और अपर्याप्त है।

वस्तुतः अवमूल्यन सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में आय-परिवर्तनों को भी जन्म देता है। कीन्सीयन अर्थशास्त्र से प्रभावित होकर बाद में, अवमूल्यन के प्रभावों के विश्लेषण में आय-प्रभावों को भी सम्मिलित किया गया। सिडनी एलेक्जेंडर ने केन्सीय विचारधारा के आधार पर अवमूल्यन के आय-प्रभावों का विश्लेषण किया और एक समष्टिभावी दृष्टिकोण से अवमूल्यन की प्रभाविता के संदर्भ में विचार किया। इस दृष्टिकोण को 'अवशोषण दृष्टिकोण' कहा जाता है जो कि सामान्य संतुलन प्रकृति का है।

केन्स के राष्ट्रीय आय संबंधों पर आधारित होने के बावजूद यह केन्सीय मॉडल से भिन्न है। केन्स का मॉडल अवमूल्यन से निर्यातों के बढ़ने तथा आयातों के कम होने से आय में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करता है जबकि अवशोषण सिद्धान्त घरेलू व्यय (यानि अवशोषण) में परिवर्तन के द्वारा अवमूल्यन के प्रभावों का विश्लेषण करता है।

आप समझ गए होंगे कि लोच दृष्टिकोण के अनुसार अवमूल्यन 'कीमत-प्रभाव' के माध्यम से भुगतान-संतुलन की स्थिति में सुधार लाता है। जबकि घरेलू अर्थव्यवस्था में लागत-कीमत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संकेतात्मक रूप में, इस परम्परागत समष्टिभावी दृष्टिकोण को इस प्रकार लिखा जा सकता है

$$B = X - M$$

जहाँ,

B-व्यापार-संतुलन, X-निर्यातों का मूल्य, M-आयातों का मूल्य है।
लोच दृष्टिकोण में अवमूल्यन सीधे इन बाह्य चरों को प्रभावित कर भुगतान संतुलन में सुधार लाता है। यह व्यष्टिभावी दृष्टिकोण है।

अवशोषण दृष्टिकोण अवमूल्यन के प्रभाव का समष्टिभावी दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार अवमूल्यन का प्रभाव सिर्फ 'कीमत प्रभाव' तक ही सीमित नहीं है बल्कि अवमूल्यन घरेलू अर्थव्यवस्था में अन्य आर्थिक चरों जैसे उपभोग, निवेश तथा राष्ट्रीय आय पर भी प्रभाव डालता है। अतः भुगतान-संतुलन पर अवमूल्यन के प्रभाव को जानने के लिए इन सभी प्रभावों को भी ध्यान में रखना होगा।

सिडनी अलेक्जेंडर ने अवशोषण दृष्टिकोण में कीन्स द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय आय समीकरण का प्रयोग किया, जिसके अनुसार, एक खुली अर्थव्यवस्था में, राष्ट्रीय आय होगी

$$Y = C + I + G + (X - M) \dots \dots \dots (I)$$

जहाँ,

Y=राष्ट्रीय आय, G=सरकारी व्यय,
C=उपभोग, X=निर्यात,
I-घरेलू निवेश, M=आयात

उपरोक्त समीकरण (I) में (C+I+G) कुल घरेलू व्यय को बताता है तथा (X-M) शुद्ध निर्यातों को। इस प्रकार राष्ट्रीय आय कुल घरेलू व्यय तथा शुद्ध निर्यातों का योग है।

समीकरण (I) से (

$$X - M) = Y - (C + I + G) \dots \dots \dots (II)$$

$$(X - M) = B \dots \dots \dots III)$$

जहाँ, B व्यापार संतुलन है।

$$(C + I + G) = A \dots \dots \dots (IV)$$

A 'अवशोषण' या घरेलू व्यय है जो कि यह बताता है कि राष्ट्रीय का कितना हिस्सा उपभोग, निवेश तथा सरकारी व्यय के रूप में अर्थव्यवस्था में अवशोषित हुआ। कुल अवशोषण में अर्थव्यवस्था में सभी उद्देश्यों के लिए की गयी माँगें – उपभोग तथा निवेश उद्देश्यों – सम्मिलित है।

समीकरण (II) को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं

$$B = Y - A \dots \dots \dots (V)$$

इससे स्पष्ट है कि व्यापार संतुलन राष्ट्रीय आय तथा अवशोषण का अन्तर है। अवमूल्यन से यदि राष्ट्रीय आय में अवशोषण की अपेक्षा तेज वृद्धि होती है तो यह व्यापार-संतुलन के घाटे को कम कर सकता है।

अवमूल्यन निर्यातों को सस्ता करके निर्यात अर्जन बढ़ा देते हैं। निर्यात में वृद्धि घरेलू आर्थिक चरों पर आय प्रभाव तथा अन्य प्रभाव उत्पन्न करेगी। यही अवशोषण दृष्टिकोण का निचोड़ है। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप उसका समष्टि प्रभाव निम्नलिखित हो सकता है।

- (i) निर्यातों (X) में वृद्धि
- (ii) निर्यातों में वृद्धि से आय (Y) में वृद्धि
- (iii) आय में वृद्धि से उपभोग (C) में वृद्धि – उपभोग में वृद्धि सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (b) पर निर्भर करती है।
- (iv) आय में वृद्धि से निवेश (I) में वृद्धि- निवेश में वृद्धि निवेश की सीमान्त प्रवृत्ति (g) पर निर्भर करती है।
- (v) आय में वृद्धि से आयात (M) में वृद्धि –आयात की सीमान्त प्रवृत्ति (M) पर निर्भर करती है।

निर्यात में वृद्धि (OX) से राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि (OY) होगी यह गुणक के मान पर निर्भर करता है। गुणक का मान जितना ही अधिक होता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि उतनी ही अधिक होती है। और भुगतान-संतुलन पर उसका प्रभाव भी उतना ही अनुकूल होता है। क्योंकि

$$X - M = Y - (C + I + G)$$

समीकरण में Y का मान बढ़ने पर व्यापार घाटा (X-M) कम होगा। इस प्रकार अवमूल्यन के परिणामस्वरूप यदि निर्यात या राष्ट्रीय में वृद्धि होती है तो यह भुगतान-संतुलन के घाटे को कम करने में अनुकूल होता है। परन्तु अवमूल्यन का यह प्रभाव यही समाप्त नहीं होता है बल्कि गुणक प्रभाव के द्वारा आय में वृद्धि आगे अर्थव्यवस्था में उपभोग, निवेश तथा आयातों को बढ़ाती है जो कि भुगतान-संतुलन के घाटे को कम करने में अनुकूल नहीं है। आय में वृद्धि आयातों में कितनी वृद्धि लाएगी यह आयातों की सीमान्त आयात प्रवृत्ति (m) पर निर्भर करती है। m का मान जितना ही अधिक होगा, घाटा कम करने में अवमूल्यन का प्रभाव उतना ही कम होगा। इसी प्रकार, आय में वृद्धि से उपभोग तथा निवेश में कितनी वृद्धि होगी यह b तथा g पर निर्भर करती है। b तथा g का मान जितना ही अधिक होगा घाटा कम करने में अवमूल्यन उतना ही कम सफल होगा।

वस्तुतः अवशोषण जितना अधिक होगा भुगतान-संतुलन के घाटे को कम करने में अवमूल्यन उतना ही कम सफल होगा। जैसा कि आय समीकरण (VI) से समझ गए होंगे

$$B = Y - A \dots \dots \dots (VI)$$

उपभोग, निवेश तथा सरकारी व्यय मिलकर अवशोषण (B) को निर्धारित करते हैं। समीकरण से स्पष्ट है कि B का मान बढ़ने पर व्यापार-संतुलन का घाटा बढ़ेगा - b और g के अधिक होने पर अवशोषण (B) में वृद्धि होगी।

सिडनी अलेक्जेंडर सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (b) तथा सीमान्त निवेश प्रवृत्ति (g) के योग को अवशोषण

की सीमान्त प्रवृत्ति (e) कहते हैं। अर्थात् $e = b+g$, e का मान जितना ही अधिक होगा व्यापार-संतुलन के घाटे को कम करने में अवमूल्यन उतना ही कम सफल होगा। यदि m का मान दिया हुआ हो तो यदि

- (i) e का मान इकाई से कम है ($e < 1$) तो अवमूल्यन व्यापार-संतुलन की स्थिति सुधार लाएगा।
- (ii) e का मान इकाई के बराबर हो ($e = 1$) तो अवमूल्यन के कारण व्यापार-संतुलन में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- (iii) e का मान इकाई से अधिक है ($e > 1$) तो अवमूल्यन के कारण व्यापार-संतुलन की स्थिति और खराब हो जाएगी।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि यदि अवमूल्यन के कारण आय में वृद्धि होती है तो आय प्रेरित अवशोषण या घरेलू व्यय में भी वृद्धि होगी और आयातों में भी। अवमूल्यन घाटा कम करने में सफल तभी होगा जब आय में हुई वृद्धि अवशोषण में हुई वृद्धि से अधिक हो। अवशोषण की सीमान्त प्रवृत्ति (e) के अतिरिक्त अन्य कारक भी अवमूल्यन की सफलता को प्रभावित करते हैं।

एलेक्जेंडर के अनुसार अवमूल्यन के बाद व्यय या अवशोषण पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ेगा-प्रत्यक्ष प्रभाव तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव। आय-प्रभाव के कारण अवशोषण में परिवर्तन अवमूल्यन का अप्रत्यक्ष प्रभाव जबकि अवमूल्यन से प्रेरित अवशोषण या व्यय में परिवर्तन प्रत्यक्ष प्रभाव है। अवमूल्यन के फलस्वरूप जब मुद्रा आय और मुद्रा कीमतें बढ़ती है तो कोई प्रभाव जो कि वास्तविक आय को कम कर देता है, वह अवशोषण पर प्रत्यक्ष प्रभाव है। इस प्रकार का अध्ययन नकदी शेष प्रभाव, आय पुर्नवितरण प्रभाव, मुद्रा-विभ्रम इत्यादि के अंतर्गत किया जा सकता है।

1. अवमूल्यन के कारण व्यापार-शर्तें देश के प्रतिकूल हो जाती हैं। जिससे देश की वास्तविक आय कम हो जाती है, निवासियों की क्रय शक्ति में कमी से अवशोषण भी कम होगा। यदि अवशोषण की सीमान्त प्रवृत्ति इकाई से अधिक है ($e > 1$) तो अवशोषण वास्तविक आय की अपेक्षा अधिक तेजी से कम होता है और देश के व्यापार-संतुलन में सुधार होता है।
2. अवमूल्यन गैर-आय प्रभावों के माध्यम से भी कार्य करता है जैसे नकदी-शेष प्रभाव। जब एक देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसकी घरेलू कीमतों में वृद्धि होती है- आयात कीमतों में वृद्धि तथा निर्यातों में वृद्धि के कारण। यदि मुद्रा-पूर्ति (M) स्थिर हो तो कीमतों के बढ़ने से मुद्रा-पूर्ति का वास्तविक मूल्य (M_0) कम हो जाएगा और इससे वास्तविक ब्याज दरें (i_0) बढ़ जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अपने वास्तविक नकदी शेष की मात्रा अपरिवर्तित रखना चाहता है, तो कीमत वृद्धि की स्थिति में, उसे अपने बचत में वृद्धि या व्यय में कटौती करनी होगी। इस प्रकार अवशोषण में कमी होगी और व्यापार-संतुलन में सुधार होगा। बचत बढ़ने तथा व्यय में कमी होने से वास्तविक आय में कमी होगी और यदि e का मान 1 से अधिक है तो अवशोषण आय से अधिक तेज गिरेगा और व्यापार-संतुलन में सुधार होगा।
3. यदि अवमूल्यन विकसशील देशों में आय के वितरण को प्रभावित करता है तो यह अवशोषण के माध्यम से व्यापार-संतुलन को प्रभावित करेगा। यदि अवमूल्यन से आय-वितरण ऊँची सीमान्त अवशोषण प्रवृत्ति से नीची सीमान्त अवशोषण प्रवृत्ति की ओर होता है अर्थात् यदि अवमूल्यन आय का पुर्नवितरण ऊँची बचत प्रवृत्ति वाले लोगों के पक्ष में कर देता है तो उस सीमा तक अवशोषण में कमी होगी और व्यापार-संतुलन में सुधार होगा। आय पुर्नवितरण प्रभाव भी अवमूल्यन का गैर-आय प्रभाव है।
4. मुद्रा-विभ्रम भी एक प्रकार का गैर-आय प्रभाव है। प्रायः लोग अपनी मौद्रिक आय या मौद्रिक मूल्यों से अधिक प्रभावित होती है। यदि अवमूल्यन से कीमतों में वृद्धि हो जाती है और लोगों के व्यय में कमी हो जाती है तो अवशोषण में कमी आएगी और व्यापार-संतुलन में सुधार होगा। यदि मौद्रिक आय में वृद्धि

होती है और कीमतों में वृद्धि उससे अधिक तेजी से होती है जिससे उनकी वास्तविक आय कम हो जाती है, तब भी लोग मुद्रा-विभ्रम के कारण अपने को ज्यादा धनी महसूस करते हैं और अपने व्यय को बढ़ा देते हैं। जिससे अवशेष में वृद्धि हो जाती है और व्यापार-संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

13.6.1 अवशेषण दृष्टिकोण का मूल्यांकन

1. व्यापार-संतुलन को प्रभावित करने वाले अनेक तत्वों- आय तथा गैर आय तत्वों के होने से अवमूल्यन के प्रभावों की भविष्यवाणी काफी कठिन हो जाती है। इसमें से अनेक तत्वों का मात्रात्मक रूप से मापन संभव नहीं है। जैसे, आय वितरण प्रभाव, मुद्रा-विभ्रम इत्यादि। और भुगतान-संतुलन पर अवमूल्यन के प्रभावों को जानने के लिए पूँजी प्रवाहों में परिवर्तन पर अवमूल्यन के पड़ने वाले प्रभावों को सम्मिलित करना आवश्यक है।
2. मैक्लप के अनुसार, अवशेषण दृष्टिकोण में कैन्सीय सर्वसमिकाओं का ही पुनर्प्रस्तुतीकरण है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। यह दृष्टिकोण $B = Y - A$ समीकरण पर आधारित है जिसके अनुसार यदि समग्र पूर्ति Y समग्र मांग A से अधिक तेजी से बढ़ती है या फिर समग्र मांग A में गिरावट समग्र पूर्ति Y की अपेक्षा अधिक तेज होती है तो व्यापार संतुलन B में सुधार होगा।
3. मैक्लप ने एलेक्जेण्डर की सापेक्षिक कीमत प्रभावों की उपेक्षा के लिए भी आलोचना की। मैक्लप के अनुसार अवमूल्यन के प्रभाव जानने में व्यय प्रवृत्तियाँ कम विश्वसनीय है जबकि मौद्रिक और राजस्व नीतियों का अवमूल्यन पर प्रभाव अधिक व्यापक होता है जिनकी अवशेषण विधि उपेक्षा करती है।
4. जोनसन के अनुसार अवशेषण विधि वास्तविक आय और वास्तविक व्यय द्वारा भुगतान संतुलन पर प्रभावों का अध्ययन करती है और कीमत स्तर में परिवर्तन की उपेक्षा करती है।
5. यह धारणा अवमूल्यन के कीमत प्रभाव की उपेक्षा करती है जो अति महत्वपूर्ण है। अवशेषण विधि सापेक्षिक कीमतों की उपेक्षा घरेलू उपभोग के स्तर पर अधिक बल देती है। अवशेषण कम करने के लिए केवल घरेलू उपभोग के स्तर को कम करने का यह तात्पर्य नहीं है कि अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग भुगतान-संतुलन को सुधारने में लगाए जाएंगे।
6. यह विधि अन्य देशों के अवशेषण पर अवमूल्यन के प्रभावों का अध्ययन नहीं करती है। अवमूल्यन के बाद यदि अवमूल्यन करने वाले देश में निर्यात वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो अवमूल्यन का लाभ समाप्त हो जाएगा। इसलिए उचित नीतियों और सरकारी नियंत्रणों द्वारा घरेलू कीमतों को स्थिर रखना आवश्यक है।
7. अवशेषण की धारणा, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत भुगतान शेष घाटे को ठीक करने के उपाय के रूप में बिल्कुल असफल है। जब अवमूल्यन के साथ कीमतें बढ़ती हैं तो लोग अपने उपभोग व्यय को घटाते हैं। मुद्रा पूर्ति स्थिर रहने पर ब्याज दर बढ़ती है जिससे अवशेषण के साथ-साथ उत्पादन में कमी होती है। इस प्रकार, अवमूल्यन का भुगतान शेष घाटे से बहुत कम प्रभाव पड़ेगा।
8. अवमूल्यन की सफलता के लिए दूसरे देशों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होना आवश्यक है। यदि अवमूल्यन के बाद दूसरे देश भी अवमूल्यन करते हैं या अपने आयातों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लागते हैं तो अवमूल्यन करने वाले देश को लाभ नहीं होगा। साथ ही दूसरे देशों द्वारा निर्यात-सब्सिडी देने पर भी अवमूल्यन का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार मुद्रा अवमूल्यन की होड़ देशों में न लगे, इसके लिए अवमूल्यन करने के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सलाह और समझौता जरूरी है।

अवशेषण दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि व्यापार-संतुलन की स्थिति में परिवर्तनों को सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखा जाना चाहिए। यह सिद्धान्त संदेश देता है कि यदि भुगतान संतुलन के घाटे को कम करना है तो

एक देश को उपभोग और निवेश के रूप में अत्यधिक अवशोषण करने या व्यय करने की अपेक्षा वस्तुओं व सेवाओं का अधिक उत्पादन करना चाहिए।

13.7 अभ्यास हेतु प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न:

1. भुगतान सन्तुलन के असन्तुलन को दूर करने के लिए अपनाये जाने वाले उपायों का उल्लेख कीजिए।
2. मार्शल-लर्नर शर्तें क्या हैं?
3. व्यय बदलावकारी नीति क्या है?
4. व्यय परिवर्तनकारी नीति क्या है?
5. अवमूल्यन तथा घरेलू मुद्रा के मूल्य हास में क्या अंतर है?
6. अवशोषण दृष्टिकोण क्या है?
7. अवमूल्यन गैर-आय प्रभावों के माध्यम से किस प्रकार कार्य करता है ?
8. अवशोषण दृष्टिकोण की कमियों का उल्लेख कीजिये।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न:

1. व्यय बदलावकारी नीतियों का उल्लेख कीजिए।
2. व्यय परिवर्तनकारी नीतियों का उल्लेख कीजिए।
3. मुद्रा के मूल्य हास का क्या अर्थ है?
4. अवशोषण की सीमान्त प्रवृत्ति (e) से आप क्या समझते हैं?
5. मुद्रा-विभ्रम का क्या अर्थ है?
6. 'अवशोषण दृष्टिकोण' किस अर्थशास्त्री ने दिया?
7. 'अवशोषण दृष्टिकोण' किस विचारधारा पर आधारित है?

बहुविकल्पीय प्रश्न:

1. निम्न में से कौन-सा उपाय भुगतान सन्तुलन के असन्तुलन को दूर कर सकता
(क) विनिमय नियन्त्रण (ख) मुद्रा का अवमूल्यन
(ग) मुद्रा-संकुचन (घ) उपर्युक्त सभी
2. अवमूल्यन को व्यय की दिशा बदलने का एक यंत्र कहा जाता है क्योंकि अवमूल्यन
(क) घरेलू तथा विदेशी व्यय को विदेशी वस्तुओं तथा सेवाओं से हटाकर घरेलू वस्तुओं तथा सेवाओं की ओर मोड़ देता है।
(ख) विदेशी व्यय को विदेशी वस्तुओं तथा सेवाओं से हटाकर घरेलू वस्तुओं की ओर मोड़ देता है।
(ग) विदेशी व्यय को घरेलू वस्तुओं तथा सेवाओं से हटाकर विदेशी वस्तुओं की ओर मोड़ देता है।
(घ) घरेलू व्यय को घरेलू वस्तुओं तथा सेवाओं से हटाकर विदेशी वस्तुओं की ओर मोड़ देता है।
3. अवमूल्यन का अर्थ है
(क) घरेलू मुद्रा के मूल्य में, विदेशी विनिमय बाजार में लगातार गिरावट
(ख) घरेलू मुद्रा के मूल्य में, विदेशी विनिमय बाजार में लगातार वृद्धि
(ग) घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य को सरकार द्वारा जानबूझकर कम करना

- (घ) घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य को सरकार द्वारा जानबूझकर वडाना
4. अवमूल्यन का तात्कालिक प्रभाव यह होता है कि
- (क) निर्यात मंहगे तथा आयात सस्ते हो जाते हैं
(ख) निर्यात सस्ते तथा आयात मंहगे हो जाते हैं
(ग) आयात तथा निर्यात सस्ते हो जाते हैं
(घ) आयात तथा निर्यात मंहगे हो जाते हैं
5. भुगतान-संतुलन के घाटे को कम करने में अवमूल्यन अधिक सफल होगा यदि
- (क) आयात मांग लोच इकाई से कम है
(ख) निर्यात मांग लोच इकाई से कम है
(ग) निर्यात मांग लोच इकाई से अधिक है
(घ) आयात मांग लोच इकाई के बराबर है
6. मार्शल-लर्नर के अनुसार, यदि निर्यातों तथा आयातों की मांग लोचों का योग
- (क) इकाई से कम है तो अवमूल्यन व्यापार-संतुलन घाटे को और बढ़ा देगा।
(ख) इकाई से कम है तो अवमूल्यन व्यापार-संतुलन घाटे को और कम कर देगा।
(ग) इकाई से अधिक है तो अवमूल्यन व्यापार-संतुलन घाटे को और बढ़ा देगा।
(घ) इकाई के बराबर है तो अवमूल्यन व्यापार-संतुलन घाटे को और बढ़ा देगा।
7. अवमूल्यन कुल अवशोषण को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है
- (क) आय से अनुप्रेरित परिवर्तन (ख) प्रत्यक्ष परिवर्तन
(ग) नकदी-शेष प्रभाव (घ) उपर्युक्त सभी
8. अवमूल्यन के परिणामस्वरूप उसका समष्टि प्रभाव होगा
- (क) आय (Y) में कमी होगी
(ख) उपभोग (C) में कमी होगी
(ग) निवेश (I) में कमी होगी
(घ) आय में वृद्धि से आयात (M) में वृद्धि होगी
9. अवशोषण दृष्टिकोण' किस अर्थशास्त्री के विचारधारा के आधार पर अवमूल्यन के आय-प्रभावों का विश्लेषण करता है
- (क) सिडनी एलेक्जेंडर (ख) केन्स
(ग) जोनसन (घ) मार्शल-लर्नर
10. 'अवशोषण दृष्टिकोण' किस अर्थशास्त्री ने दिया
- (क) सिडनी एलेक्जेंडर (ख) केन्स
(ग) जोनसन (घ) मार्शल-लर्नर
11. अवमूल्यन से यदि राष्ट्रीय आय में अवशोषण की अपेक्षा तेज वृद्धि होती है तो यह व्यापार-संतुलन के घाट को
- (क) बड़ा कर देगा
(ख) कम कर देगा
(ग) अपरिवर्तित रहेगा
(घ) कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता

12. अवशोषण है

(क) $C+I+G+ (X-M)$ (ख) $X-M$ (ग) $C+I+G$ (घ) $Y-A$

13. गैर-आय प्रभाव नहीं है

(क) नकदी-शेष प्रभाव

(ख) आय पुर्नवितरण प्रभाव

(ग) मुद्रा-विभ्रम

(घ) व्यापार-शती पर प्रभाव

सत्य व असत्य :

1. भुगतान-संतुलन पर अवमूल्यन के प्रभावों का लोच दृष्टिकोण सामान्य संतुलन विश्लेषण है।
2. अवमूल्यन का प्रभाव स्थायी नहीं होता है।
3. अवमूल्यन का प्रभाव, मूल्यहास के समान ही होता है।
4. अवमूल्यन व्यय परिवर्तनकारी नीति है।
5. आयात तथा निर्यात मांगे जितनी ही अधिक लोचशील होगी भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने में अवमूल्यन उतना ही कम सफल होगा।
6. मार्शल-लर्नर शर्तों के अनुसार व्यापार-संतुलन को सुधारने में अवमूल्यन की सफलता आयात तथा निर्यात पूर्ति लोचों के योग पर निर्भर करती है।
7. मार्शल-लर्नर दशाएं सिर्फ वस्तु व्यापार या चालू खाता भुगतान-संतुलन पर ही लागू होती है।
8. मार्शल-लर्नर दशाएं पूँजीगतियों पर अवमूल्यन के प्रभावों की अवहेलना करती
9. मार्शल-लर्नर दशाएँ यह मान लेती है कि पूर्ति लोच अनन्त है।
10. अवमूल्यन सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में आय-परिवर्तनों को भी जन्म देता है।
11. अवमूल्यन घाटा कम करने में सफल तभी होगा जब आय में हुई वृद्धि अवशोषण में हुई वृद्धि से कम हो।
12. व्यापार संतुलन राष्ट्रीय आय तथा अवशोषण का अन्तर है।
13. कुल अवशोषण में अर्थव्यवस्था में सभी उद्देश्यों के लिए की गयी माँगें सम्मिलित होती है।
14. आय में वृद्धिउपभोग, निवेश तथा आयातों को बढ़ाती है जो कि भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने में अनुकूल है।
15. b तथा g का मान जितना ही अधिक होगा घाटा कम करने में अवमूल्यन उतना ही कम सफल होगा।
16. अवमूल्यन के कारण व्यापार-शर्तें देश के प्रतिकूल हो तो देश के व्यापार-संतुलन में सुधार होता है।
17. यदि अवमूल्यन आय का पुर्नवितरण ऊँची बचत प्रवृत्ति वाले लोगों के पक्ष में कर देता है तो व्यापार-संतुलन में घाटा होगा।
18. यदि अवमूल्यन से कीमतों में वृद्धि हो जाती है और लोगों के व्यय में कमी हो जाती है तो व्यापार-संतुलन में सुधार होगा।

13.8 सारांश

व्यापार-संतुलन राष्ट्रीय आय तथा घरेलू व्यय या अवशोषण का अंतर होता है। इस प्रकार, व्यापार-संतुलन अवशोषण या घरेलू व्यय के कम होने पर कम होगा। सरकार राजकोषीय और मौद्रिक नीति के द्वारा अवशोषण और व्यय में कमी करके व्यापार-संतुलन घाटे को कम कर सकती है। अवमूल्यन घरेलू तथा विदेशी

व्यय को विदेशी वस्तुओं तथा सेवाओं से हटाकर घरेलू वस्तुओं तथा सेवाओं की ओर मोड़ देता है। इसीलिए इसे व्यय बदलावकारी नीति (Expenditure Switching Policy) कहते हैं। अवमूल्यन का तात्कालिक प्रभाव यह होता है कि घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी से निर्यात सस्ते तथा आयात मंहगे हो जाते हैं।

अवमूल्यन की भुगतान-संतुलन के घाटे को कम करने की सफलता आयातों तथा निर्यातों की मांग-लोच पर निर्भर करेगी। आयात और निर्यात मांगे जितन लोचदार होंगी, भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने में अवमूल्यन उतन सफल होगा और यदि आयात और निर्यात मांग लोचें इकाई से कम है या बेलोचदार है तो अवमूल्यन घाटे को कम करने में सफल नहीं होगा बल्कि यह घाटे को और बढ़ा देगा। मार्श-लर्नर शर्तों के अनुसार व्यापार-संतुलन को सुधारने में अवमूल्यन की सफलता आयात तथा निर्यात मांग लोचों के योग पर निर्भर करती है। यदि निर्यातों तथा आयातों की मांग लोचों का योग इकाई से अधिक हो तो अवमूल्यन व्यापार संतुलन के घाटे को कम करेगा।

परन्तु अवमूल्यन न सिर्फ निर्यातों तथा आयातों की सापेक्षिक कीमतों को प्रभावित करता है बल्कि यह अर्थव्यवस्था में आय परिवर्तनों को भी जन्म देता है। भुगतान-संतुलन के घाटे को कम करने में अवमूल्यन की सफलता आय में परिवर्तनों के कारण घरेलू व्यय या अवशोषण (C+I+G) में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करती है। अवमूल्यन निर्यातों को सस्ता करके निर्यात अर्जन बढ़ा देते हैं। निर्यात में वृद्धि घरेलू आर्थिक चरों पर आय प्रभाव तथा अन्य प्रभाव उत्पन्न करेगी। यदि अवमूल्यन के कारण आय में वृद्धि होती है तो आय प्रेरित अवशोषण या घरेलू व्यय में भी वृद्धि होगी और आयातों में भी। अवमूल्यन घाटा कम करने में सफल तभी होगा जब आय में हुई वृद्धि अवशोषण में हुई वृद्धि से अधिक हो। अवशोषण जितना अधिक होगा भुगतान-संतुलन के घाटे को कम करने में अवमूल्यन उतना ही कम सफल होगा। अवमूल्यन गैर-आय प्रभावों के माध्यम से भी कार्य करता है।

अवमूल्यन भुगतान-संतुलन में केवल अस्थायी समायोजन ही कर सकता है। स्थायी प्रकृति का दीर्घकालिक समायोजन तभी हो सकता है जबकि असंतुलन लाने वाले मूल कारकों को नियंत्रित किया जाए।

13.9 शब्दावली

- **अवशोषण (Observation)** - राष्ट्रीय आय के कुल अवशोषण का अर्थ है कुल घरेलू व्यय। संकेतात्मक रूप में, अवशोषण $A=C+I+G$ स्पष्ट है कि कुल अवशोषण में अर्थव्यवस्था में उपभोग तथा कुल निवेश उद्देश्यों के लिए की गयी मांग सम्मिलित होती है। अवशोषण का अर्थ यह है कि राष्ट्रीय आय का जिस भाग उपयोग उपभोग तथा कुल निवेश के रूप में अवशोषण नहीं हुआ, उसका संचय (Hoarding) होगा। अवशोषण में जितनी ही कमी होगी संचय में उतनी ही वृद्धि होगी।
- **मुद्रा-विभ्रम (Money Illusion)** - यदि लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि हो परन्तु कीमतों में उससे तेज वृद्धि के कारण वास्तविक आय में कमी हो जाए, परन्तु मौद्रिक आय के बढ़ने के कारण लोग अपने को पहले से अधिक धनी समझकर अपने व्यय को बढ़ा दें या पहले ही इतना बरकरार रखें तो इसे 'मुद्रा-विभ्रम' की संज्ञा दी जाती है। मुद्रा-विभ्रम के संदर्भ में मुख्य बात यह है कि लोग अपनी वास्तविक आय की अपेक्षा मौद्रिक आय से प्रभावित होकर अपने आर्थिक निर्णय लेते हैं और कीमत के आय पर पड़ने वाले प्रभावों को नहीं समझ पाते हैं।
- **निर्यातों तथा आयातों की मांग लोच** - निर्यात की कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्यात की मांग में हुआ परिवर्तन निर्यातों की मांग लोच है।

$$\text{निर्यातों की मांग लोच} = \frac{\text{मांग में प्रतिशत परिवर्तन}}{\text{निर्यात कीमत में प्रतिशत परिवर्तन}}$$

इसी प्रकार,

$$\text{आयातों की मांग} - \text{लोच} = \frac{\text{आयात मांग में प्रतिशत परिवर्तन}}{\text{आयात कीमत में प्रतिशत परिवर्तन}}$$

- **विनिमय दर** - किसी देश की घरेलू मुद्रा का अन्य देशों की मुद्रा से जिस दर पर विनिमय किया जाता है उसे विदेशी विनिमय दर पर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, विदेशी मुद्रा की घरेलू मुद्रा के रूप में कीमत विनिमय दर है। जैसे यदि 1\$ में 50 मिलते हैं तो, भारत में डालर के रूप में विदेशी विनिमय दर होगी- 1\$=50।
- **अवमूल्यन** - प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले घरेलू-मुद्रा के मूल्य में जानबूझकर कानूनी ढंग से की गयी कमी अवमूल्यन है। मुद्रा मूल्य हास - विदेशी विनिमय बाजार में, विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति में परिवर्तन के कारण घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी, मुद्रा-मूल्य हास कहा जाता है। अवमूल्यन तथा मूल्य-हास दोनों का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर एक समान होता है।
- **व्यय बदलाव की नीतियाँ** - वे उपाय जो व्यय की दिशा को परिवर्तित करके विदेशी वस्तु और सेवाओं से घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की ओर कर देते हैं।

13.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न:

- | | | | | |
|-------|------|------|------|------|
| 1. घ, | 2.क, | 3.ग, | 4.ख, | 5.ग, |
| 6.क | 7. घ | 8.घ | 9.ख | 10.क |
| 11.ख | 12.ग | 13.घ | | |

सत्य व असत्य :

- | | | | | |
|----------|----------|---------|----------|----------|
| 1. असत्य | 2.सत्य | 3.सत्य | 4.असत्य | 5.असत्य |
| 6.असत्य | 7.सत्य | 8.सत्य | 9.सत्य | 10. सत्य |
| 11.असत्य | 12.सत्य | 13.सत्य | 14.असत्य | 15.सत्य |
| 16.सत्य | 17.असत्य | 18.सत्य | | |

13.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

- HH. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: International Economics: Theory and Policy, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- Charles P Kindleberger, International Economics, Richard D. Irwin Inc., Illinois, 1968
- Dominik Salvatore, International Economics, John Willy & Sons, Inc., 2008
- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006 •

- सुदामा सिंह एवं एम0सी0 वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफ़ोर्ड एंड आई0बी0एच0 पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम0एल0 झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010।
- ज्ञानेंद्र सिंह कुशवाहा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1979।

13.12 उपयोगी/सहायक पाठ्य सामग्री

- HH. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt.Ltd. 2001
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: International Economics: Theory and Policy, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- Charles P Kindleberger, International Economics, Richard D. Irwin Inc.,Illinois, 1968
- Dominik Salvatore, International Economics, John Willy & Sons, Inc.,2008
- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006
- एस. एन. लाल, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहबाद, 2004
- एच. एस. अग्रवाल, तथा सी. एस. बरला, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2003.
- सुदामा सिंह एवं एम. सी. वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफ़ोर्ड एंड आई. बी. एच. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम0 एल0 झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010.
- डॉ. जी. सी. सिंघई एवं डॉ. जे. पी. मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा, 2010

13.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. भुगतान सन्तुलन के असन्तुलन को ठीक करने हेतु अवशोषण विधि पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए।
2. मार्शल-लर्नर शर्त की व्याख्या कीजिए। इसकी क्या-क्या आलोचनाएँ हैं? आप इसे किस सीमा तक व्यावहारिक मानते हैं?
3. भुगतान सन्तुलन के असन्तुलन को ठीक करने हेतु अवमूल्यन के लोच दृष्टिकोण का मूल्याङ्कन कीजिये।

इकाई 14 - मौद्रिक उपागम तथा भुगतान संतुलन में समायोजन (Monetary Approach and Adjustment Mechanism of Balance of Payments)

- 14.1 प्रस्तावना
- 14.2 उद्देश्य
- 14.3 परिवर्तनशील तथा स्थिर विनिमय दरें तथा भुगतान संतुलन
 - 14.3.1. परिवर्तनशील विनिमय दरें तथा भुगतान संतुलन
 - 14.3.2. स्थिर विनिमय दरें तथा भुगतान संतुलन
- 14.4. मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ तथा भुगतान संतुलन
 - 14.4.1. राजकोषीय नीति तथा भुगतान संतुलन
 - 14.4.2. मौद्रिक नीति तथा भुगतान संतुलन
- 14.5. भुगतान संतुलन के सन्दर्भ में मौद्रिकवादियों का दृष्टिकोण- सामान्य विवेचना
- 14.6. भुगतान संतुलन समायोजन और मौद्रिक उपागम
 - 14.6.1. मान्यताएं
 - 14.6.2. स्थिर विनिमय दरें तथा भुगतान संतुलन समायोजन
 - 14.6.3. परिवर्तनशील विनिमय दरें तथा भुगतान संतुलन समायोजन
 - 14.6.4. आलोचना
- 14.7. अभ्यास हेतु प्रश्न
- 14.8. सारांश
- 14.9. शब्दावली
- 14.10. अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 14.11. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 14.12. उपयोगी/ सहायक पाठ्य सामग्री
- 14.13. निबंधात्मक प्रश्न

14.1 प्रस्तावना

इससे पहले की इकाई में आपने भुगतान संतुलन के असंतुलन को दूर करने में परम्परागत उपायों की भूमिका विशेष रूप से अवमूल्यन के भुगतान संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों के सन्दर्भ में के बारे में अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात् भुगतान संतुलन के असंतुलन को दूर करने में अवमूल्यन की भूमिका तथा महत्व को समझ गए होंगे। आप जान गए होंगे कि अवमूल्यन किस प्रकार से और किन स्थितियों भुगतान-संतुलन के असंतुलन को दूर कर सकता है।

आपने देखा कि लोच दृष्टिकोण के अनुसार निर्यातों और आयातों की मांग और पूर्ति लोचों की सापेक्षिक प्रभाविता का अवमूल्यन या विनिमय दर के मूल्यहास द्वारा भुगतान-संतुलन के असंतुलन को दूर करने में के लिए विशेष महत्व है। दूसरी ओर मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार विनिमय दर देश के वास्तविक उत्पादन की सापेक्षिक कीमत न होकर देश की करेन्सी की सापेक्षिक कीमत है। इसलिए मौद्रिकवादी वनिस्पत परिसम्पत्तियों के स्टॉक के बाजार के कोषों के प्रवाह के बाजारों के महत्व पर अधिक जोर देते हैं।

भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने के लिए मौद्रिक उपायों की चर्चा ने 1970 के दशक में विशेष रूप से जोर पकड़ा। परम्परागत दृष्टिकोण से भुगतान-संतुलन के घाटे को दूर करने के लिए समष्टिगत स्तर पर अल्पकालिक विश्लेषण किया गया है, जबकि मौद्रिकवादियों ने भुगतान-संतुलन के समष्टि आर्थिक विश्लेषण में दीर्घकालिक समस्या पर अधिक ध्यान दिया। मुद्रावादियों के अनुसार भुगतान-संतुलन की संकल्पना में मुद्रा के अंतर्प्रवाह तथा बहिर्प्रवाह का विशेष महत्व है।

हाल के वर्षों में, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भुगतान संतुलन के असंतुलन को दूर करने में मौद्रिक उपायों पर अधिक जोर दिया है। भुगतान-संतुलन के समायोजन में मुद्रा और अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने स्थिर तथा परिवर्तनशील दरों की स्थिति में भुगतान संतुलन के समायोजन में मौद्रिक नीति की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था में मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि से आन्तरिक कीमत बढ़ता है जिससे आयातों में वृद्धि तथा निर्यातों में कमी आती है इससे सोने का बहिर्प्रवाह बढ़ता है। इससे मौद्रिक आधार कमजोर होता है और मुद्रा-पूर्ति में कमी आती है, जिससे कीमतें गिरती हैं और आयात हतोत्साहित तथा निर्यात प्रोत्साहित होते हैं और इस प्रकार भुगतान-संतुलन का घाटा स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

आधुनिक अर्थशास्त्री, प्रतिष्ठित दृष्टिकोण को ही पुनर्स्थापित करने का प्रयास करते हैं। मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार भुगतान-संतुलन स्वतः एक मौद्रिक परिघटना है। क्योंकि भुगतान-संतुलन का घाटा और अतिरेक मूलतः अर्थव्यवस्था में मुद्रा के वास्तविक ऐच्छिक स्टॉक (Actual Desired Stocks) के समायोजन की प्रक्रिया है। मुद्रावादियों के अनुसार भुगतान-संतुलन का घाटा मुद्रा-पूर्ति के आधिक्य के बराबर होगा। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप भुगतान संतुलन के असंतुलन को दूर करने में मौद्रिक उपायों के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

14.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप

- ✓ स्थिर तथा परिवर्तनशील दरों की स्थिति में भुगतान शेष में समायोजन कैसे होता है, जान पाएंगे।
- ✓ भुगतान शेष के असंतुलन को दूर करने में मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों की प्रभावित को जन सकेंगे।
- ✓ भुगतान शेष के सम्बन्ध में मुद्रावादियों के दृष्टिकोण को समझ सकेंगे।

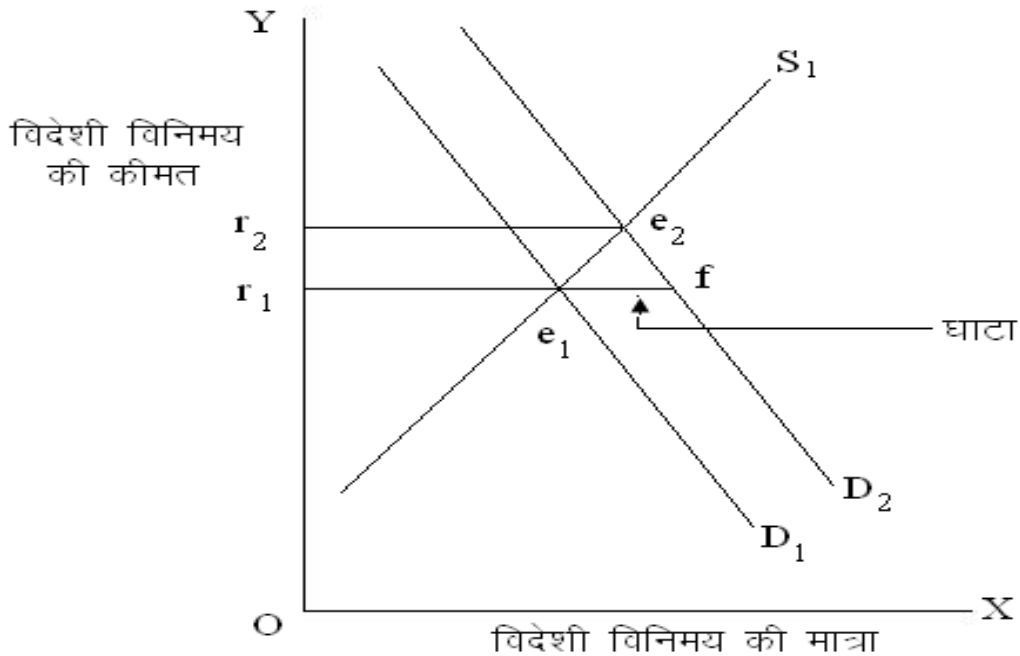
- ✓ भुगतान शेष में समायोजन के मौद्रिक उपागम के बारे में जान सकेंगे।

14.3 परिवर्तनशील तथा स्थिर विनिमय दरें तथा भुगतान संतुलन

मौद्रिकवादियों का यह मानना है कि भुगतान संतुलन का असंतुलन एक अस्थायी परिघटना है। जोकि मुद्रा बाजार में असंतुलन के कारण बनी रहती है। दीर्घकाल में यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। एक देश के भुगतान संतुलन में अतिरेक मुद्रा मांग में आधिक्य और भुगतान संतुलन का घाटा मुद्रा-स्टॉक की पूर्ति में आधिक्य का परिणाम हैं। स्थिर विनिमय दरों के अंतर्गत भुगतान-संतुलन का असंतुलन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रवाह का परिणाम है जबकि परिवर्तनशील विनिमय दरों के अंतर्गत भुगतान-संतुलन का असंतुलन बिना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रवाह के उत्पन्न होता है और समाप्त होता है। भुगतान-संतुलन के असंतुलन के समायोजन के मौद्रिक उपागम के अध्ययन से पहले आप यह जानेंगे की स्थिर तथा परिवर्तनशील विनिमय दरों की प्रणाली के अंतर्गत भुगतान-संतुलन के असंतुलन का समायोजन किस प्रकार से होता है।

14.3.1 परिवर्तनशील विनिमय दरें तथा भुगतान संतुलन

परिवर्तनशील विनिमय दरें विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति के शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है तथा इसमें मौद्रिक प्राधिकरण का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। परिवर्तनशील विनिमय दरों के अंतर्गत समायोजन प्रक्रिया किसी व्यक्तिगत देश के किसी आन्तरिक समायोजन पर निभर नहीं करती है। बल्कि यह विनिमय दर में परिवर्तनों पर आधारित है। विनिमय दरों में परिवर्तन देश की भुगतान-संतुलन की बदलती हुई स्थिति के अनुरूप विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन के फलस्वरूप स्वतः ही उत्पन्न होता है। यहाँ सरकारी या राज्य हस्तक्षेप के लिए कोई स्थान नहीं है और न ही संतुलन उत्पन्न करने के लिए समायोजक पूँजी लेन-देन (अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाता) की आवश्यकता है।



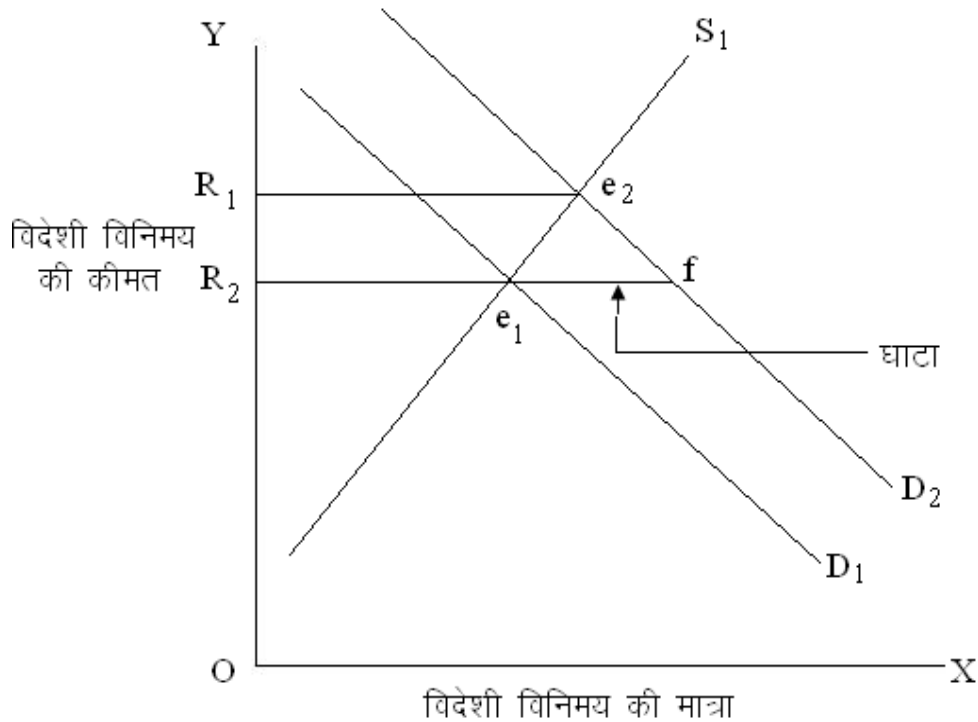
चित्र 14.1

चित्र 14.1 में भुगतान संतुलन का प्रारम्भिक संतुलन e बिन्दु पर है। जहाँ विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति आपस में बराबर है। बिन्दु e_1 पर विदेशी विनिमय की मांग वक्र D_1 पूर्ति वक्र S_1 को काटता है। यदि किन्हीं कारणों से (आयात प्रवृत्ति बढ़ जाने, आयात बढ़ने इत्यादि) मांग वक्र ऊपर की ओर विवर्तित हो जाता है या फिर निर्यातों के कम होने से निर्यात-अर्जन में कमी आने से विदेशी विनिमय पूर्ति वक्र ऊपर की ओर खिसक जाता है तो भुगतान-संतुलन में घाटा उत्पन्न हो जाता है।

चित्र 14.1 में मांग वक्र के ऊपर विवर्तित हो जाने से संतुलन बिन्दु e_1 से e_2 पर आ जा रहा है। विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाने से विदेशी विनिमय बाजार में e_1 के बराबर घाटा हो जाता है। परन्तु परिवर्तनशील विनिमय दरों के कारण नया संतुलन e_2 पर हो जा रहा है तथा विनिमय दर R_1 से R_2 हो जा रही है। अर्थात् विदेशी विनिमय दर के मूल्य में वृद्धि या घरेलू मुद्रा के मूल्य में मूल्य हास के द्वारा भुगतान संतुलन का घाटा स्वतः ही दूर हो जाता है। इसी प्रकार भुगतान संतुलन का अतिरेक विदेशी विनिमय दर में मूल्य हास या घरेलू मुद्रा के अधिमूल्यन के द्वारा स्वतः ही दूर हो जाएगा।

14.3.2 स्थिर विनिमय दरें तथा भुगतान संतुलन

इस व्यवस्था के अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में सरकार या राज्य का पूरा हस्तक्षेप रहता है। बाजार विनिमय दर एक दी हुई संतुलन स्तर पर स्थिर रहती है यदि मांग और पूर्ति की शक्तियाँ इस संतुलन को बिगाडती हैं या सट्टेबाजी की गतिविधियाँ इस संतुलन को बिगाडती है तो सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है और इस संतुलित विनिमय दर को बनाए रखती है। सरकार विदेशी विनिमय के क्रय या विक्रय के माध्यम से ऐसा करती है।



चित्र 14.2

चित्र 14.2 में R_0 , विनिमय दर संतुलित विदेशी विनिमय बाजार को बताती है। जहाँ विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति बराबर है। यदि आयातों में वृद्धि के कारण मांग वक्र ऊपर की ओर विवर्तित हो जाता है या निर्यातों में कमी के कारण पूर्ति-वक्र ऊपर की ओर विवर्तित हो जाता है तो विदेशी विनिमय बाजार में घाटा होगा।

चित्र में 14.2 मांग वक्र ऊपर की ओर विवर्तित होकर D_1 से D_2 हो जाता है। परिवर्तनशील विनिमय दरों

की स्थिति में यह घाटा घरेलू मुद्रा में मूल्यहास के द्वारा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और नयी विनिमय दर R_0 से R_1 हो जाएगी। परन्तु यदि सरकार विनिमय दर को R_0 पर स्थिर रखना चाहती है तो उतनी ही मात्रा में विदेशी विनिमय (e_f के बराबर) विदेशी मुद्रा बाजार में बेचेगी। इस घाटे को समाप्त करने के लिए सरकार भुगतान-संतुलन के समायोजन खाते का सहारा लेती है। सरकार निम्नलिखित तीन संभव उपायों द्वारा इस घाटे या अन्तराल को पूरा करेगी

- (i) अपने पहले के विदेशी मुद्रा भण्डार में कमी करेगी,
- (ii) दूसरे देशों या संस्थानों से उधार लेगी,
- (iii) सोने का निर्यात करेगी।

इन उपायों में से किसी एक या तीनों के संयोग के द्वारा सरकार घाटे को समाप्त कर विनिमय दर R_0 पर बनाए रख सकती है। यह वास्तव में भुगतान संतुलन के घाटे को व्यवस्थित (settlement) करना है।

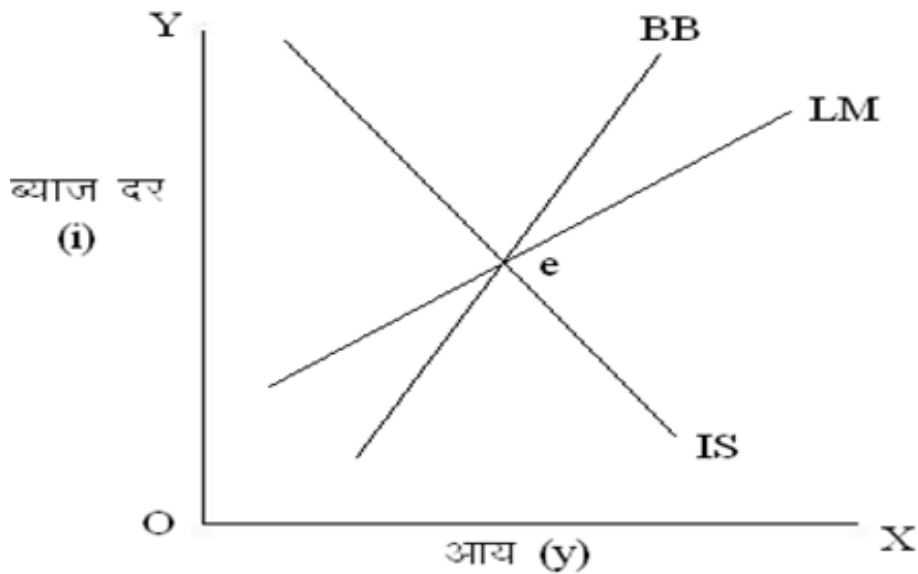
इसी प्रकार भुगतान संतुलन में अतिरेक होने पर विदेशी विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने के लिए सरकार विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा को खरीदेगी और इसके लिए वह समायोजन लेन-देन के अंतर्गत सोने का आयात, अपने विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि या बाह्य उधार देने जैसे उपायों का सहारा ले सकती है।

14.4 मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ तथा भुगतान संतुलन

भुगतान शेष के असंतुलन विशेष रूप से घाटे का समायोजन किसी भी देश के विदेशी मुद्रा रिजर्वों के उसके भंडार पर निर्भर करती है। और फिर बाह्य संतुलन के साथ साथ आंतरिक संतुलन के लिए भी देश हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इसलिए सरकार नीतिगत यंत्रों के माध्यम से भुगतान शेष के असंतुलन समायोजन का प्रयास करते हैं। बाह्य आंतरिक संतुलन प्राप्त करने के लिए मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों की भूमिका काफी प्रभावी होती है। ये व्ययकारी नीतियाँ होती हैं। जोकि अर्थव्यवस्था में कुल में परिवर्तन लाकर भुगतान शेष को प्रभावित करती हैं। यहाँ यह महत्वपूर्ण है की भुगतान शेष के असंतुलन को दूर करने में मौद्रिक नीति अधिक प्रभावी और निश्चित परिणाम वाली होती है। राजकोषीय नीति के ठीक विपरीत मौद्रिक नीति के भुगतान संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव बिल्कुल सीधे-सीधे और स्पष्ट है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एक विस्तारक मौद्रिक नीति या मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि भुगतान-संतुलन में घाटा लाएगी तथा संकुचनकारी मौद्रिक नीति या मुद्रा-पूर्ति में कमी भुगतान-संतुलन में अतिरेक लाएगी। इसलिए मौद्रिक उपागम से पहले आपको मौद्रिक नीति के भुगतान संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों तथा उसकी सापेक्षिक प्रभावित को जानना जरूरी है।

मौद्रिक नीति, मुद्रा-पूर्ति (M) तथा ब्याज दर (i) में परिवर्तन के द्वारा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है। जबकि राजकोषीय नीति सरकारी व्यय (G) तथा करों (T) के द्वारा अर्थव्यवस्था में प्रभावित करती है। इन नीतियों के माध्यम से व्यय में परिवर्तन के द्वारा भुगतान-शेष के घाटे को दूर किया जा सकता है। हम मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों के भुगतान-शेष पर प्रभाव जानने के लिए IS (निवेश-बचत) वक्र, LM (मुद्रा की मांग तथा पूर्ति) वक्र तथा BB (भुगतान-शेष) वक्र का प्रयोग करेंगे। IS वक्र राष्ट्रीय आय (Y) तथा ब्याज दर (i) के उन संयोगों को बताता है जो कि निवेश (I) तथा बचत (S) की समानता को प्रस्तुत करते हैं।

LM वक्र मुद्रा की मांग तथा पूर्ति की समानता को दर्शाने वाले राष्ट्रीय आय तथा ब्याज दर के विभिन्न संयोग को बताते हैं; जबकि BB वक्र राष्ट्रीय आय तथा ब्याज दर के उन संयोगों को बताता है जो कि भुगतान शेष में संतुलन को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि से आयात में वृद्धि होती है जिससे भुगतान-संतुलन का घाटा बढ़ता है। जबकि ब्याज में वृद्धि से विदेशी निवेश आकर्षित होता है और देश में पूँजी के अंतर्प्रवाह बढ़ने से भुगतान-शेष का घाटा कम होता है।

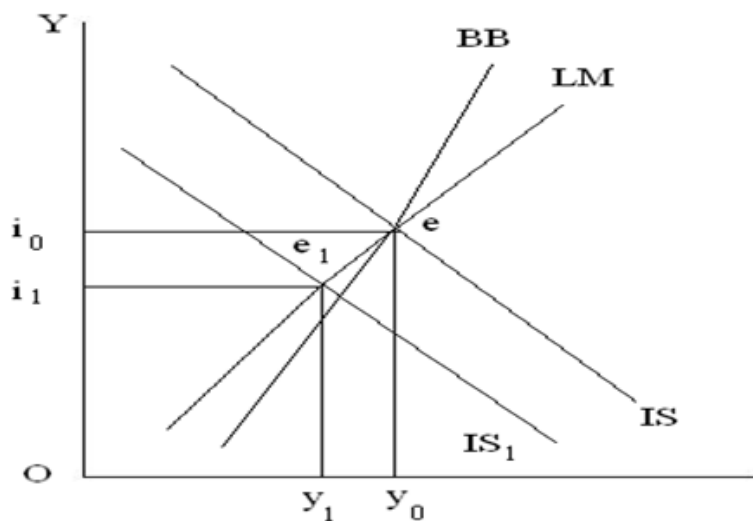


चित्र 14.3

चित्र 14.3 में BB वक्र के बायीं ओर कोई भी बिन्दु भुगतान-संतुलन में अतिरेक को दर्शाता है जबकि BB वक्र के दायीं ओर नीचे की तरफ कोई बिन्दु भुगतान-संतुलन में घाटा को प्रदर्शित करता है। सरकारी ब्याज (G) में वृद्धि होने या कर (T) में कमी होने से IS वक्र दायीं ओर ऊपर सरक जाता है जबकि सरकारी व्यय में कमी या करों में वृद्धि से IS वक्र नीचे की ओर विवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि होने पर LM वक्र नीचे की ओर विवर्तित हो जाता है जबकि मुद्रा-पूर्ति में कमी होने पर LM वक्र ऊपर की ओर विवर्तित हो जाता है। अब हम भुगतान-संतुलन के असंतुलन को दूर करने में राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों की प्रभाविता की विवेचना करेंगे।

14.4.1 राजकोषीय नीति तथा भुगतान-संतुलन

मान लिया अर्थव्यवस्था में प्रारम्भिक संतुलन की स्थिति है। चित्र 14.4 में बिन्दु e पर IS-LM-BB वक्र एक दूसरे को काटते हैं। अर्थात् बिन्दु पर अर्थव्यवस्था में आन्तरिक तथा बाह्य दोनों संतुलन विद्यमान है।

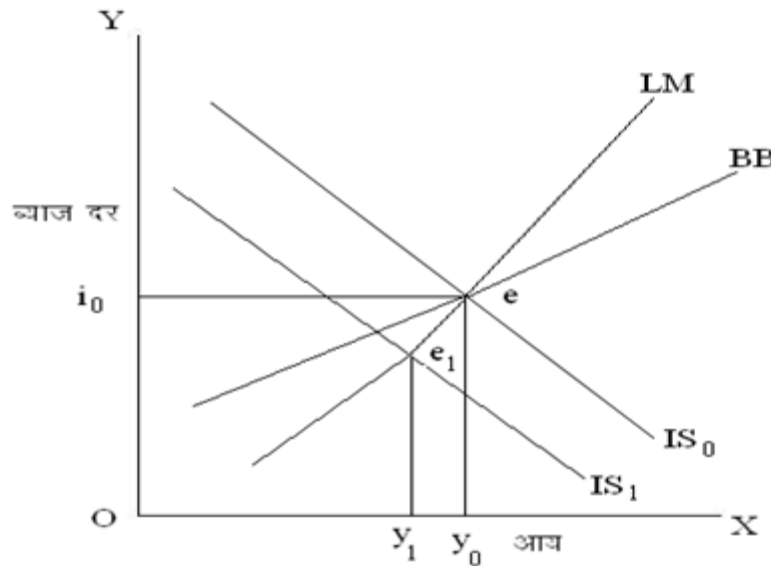


चित्र 14.4 A

माना कि सरकार संकुचनकारी राजकोषीय नीति अपनाती है और सरकारी व्यय में कमी करती है। सरकारी व्यय (G) में कमी से IS वक्र नीचे की ओर सरक कर IS_1 हो जाता (चित्र 14.4) है और LM वक्र को e_1 बिन्दु पर काटता है। नए संतुलन बिन्दु पर आय कम होकर y_1 तथा ब्याज दर कम होकर i_1 हो जाती है। सरकारी व्यय में कमी से राष्ट्रीय आय (y) में कमी होगी तथा आय में कितनी कमी होगी यह गुणक के मान पर निर्भर करता है।

व्यय में वृद्धि होने पर ब्याज दर (i) में भी वृद्धि होगी क्योंकि सरकारी व्यय में वृद्धि से निजी निवेश के लिए फण्ड (कोष) की उपलब्धता कम हो जाएगी, जिससे फण्ड या पूंजी की कीमत अर्थात् ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी।

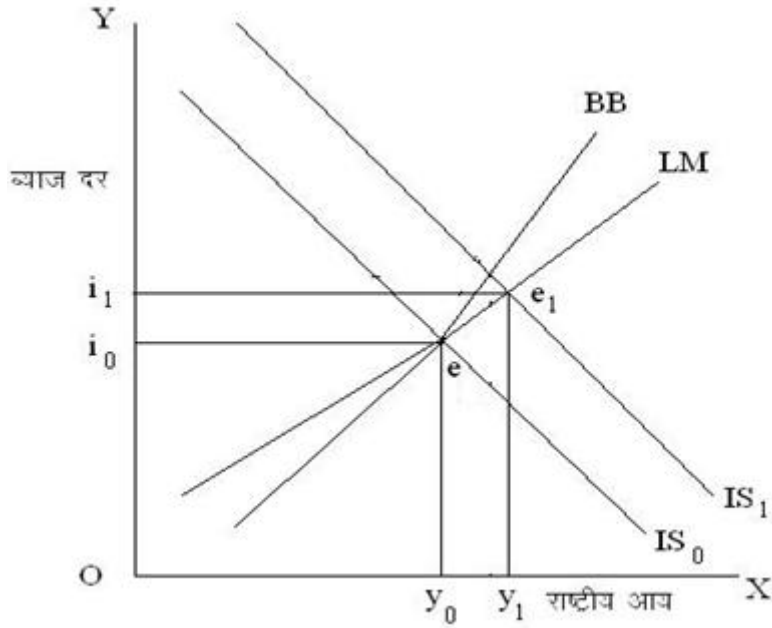
सरकारी व्यय में परिवर्तन का भुगतान संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह भुगतान-संतुलन वक्र (BB) की लोच पर निर्भर करेगा। यदि BB वक्र LM वक्र की अपेक्षा अधिक बेलोचदार या तिरछा है तो सरकारी व्यय में कमी होने पर भुगतान शेष में अतिरेक उत्पन्न होगा (चित्र 14.4A) जबकि यदि LM वक्र BB वक्र की अपेक्षा अधिक तिरछा है अर्थात् BB वक्र, LM वक्र की अपेक्षा अधिक लोचदार है (चित्र 14.4B) तो सरकारी व्यय में कमी से भुगतान संतुलन का घाटा होगा। इस प्रकार व्यय परिवर्तन का भुगतान-संतुलन पर प्रभाव LM वक्र के सापेक्ष BB वक्र के ढाल पर निर्भर करेगा।



चित्र 14.4 B

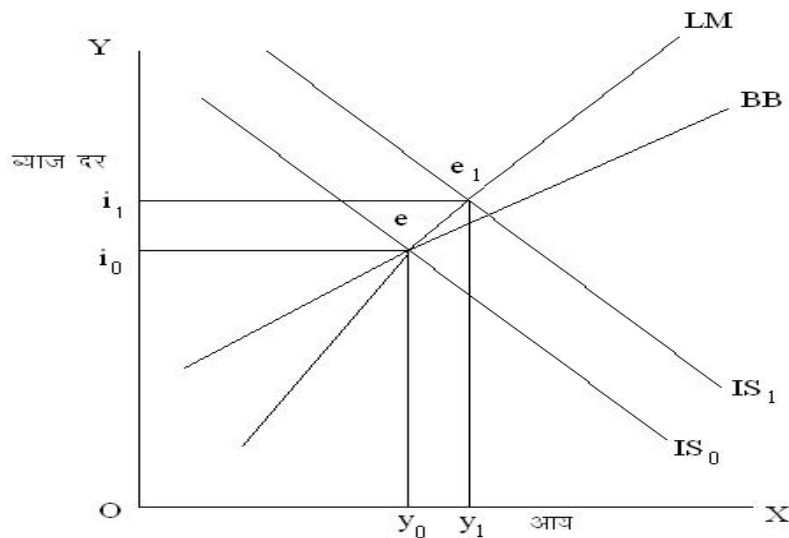
सरकारी व्यय में कमी से आय में कमी आएगी और फलस्वरूप आयातों में भी कमी आएगी। आयातों में कितनी कमी होगी यह सीमान्त आयात प्रवृत्ति पर निर्भर करेगी। स्पष्ट है कि आयातों में कमी से भुगतान-संतुलन की स्थिति में सुधार होगा अर्थात् चालू खाते में घाटे में कमी आएगी। परन्तु सरकारी व्यय में कमी का दूसरा प्रभाव यह होगा कि ब्याज-दर (i) में भी कमी आएगी जिससे देश में शृद्ध पूँजी प्रवाह में कमी आएगी, यह कमी कितनी होगी यह पूँजी प्रवाह के ब्याज-लोच पर निर्भर करेगा। किसी भी स्थिति में ब्याज-दर में कमी से पूँजी के अंतर्प्रवाह में हुई कमी, भुगतान-संतुलन के पूँजी खाते पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। इस प्रकार व्यय में कमी से भुगतान संतुलन पर अंतिम प्रभाव क्या होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आय में कमी से आयात में कमी का प्रभाव अधिक सशक्त है या ब्याज-दर में कमी से पूँजी के अंतर्प्रवाह में कमी का प्रभाव अधिक सशक्त है। यदि आयात में कमी से चालू खाते का अतिरेक पूँजी खाते के घाटे से अधिक सशक्त है तो भुगतान-संतुलन में अतिरेक होगा (चित्र

14.5A) और यदि पूँजी खाते का घाटा, चालू खाते के अतिरेक से अधिक है तो भुगतान-संतुलन में घाटा होगा (चित्र 14.5)। यह बात इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि चित्र 14.5A में, बिन्दु e_1 वक्र BB में बायीं तरफ है जबकि चित्र 14.5 B में बिन्दु e_1 वक्र के दायीं तरफ है।



चित्र 14.5A

इसी प्रकार, सरकारी व्यय में वृद्धि से IS वक्र ऊपर दायीं ओर विवर्तित हो जाएगा जिससे नया संतुलन e से e_1 पर हो जाएगा और आय तथा ब्याज दर दोनों बढ़ जाएगी (चित्र 14.6)। आय के बढ़ने पर आयातों में वृद्धि होगी जिससे चालू खाते का घाटा बढ़ेगा जबकि ब्याज दर (i) बढ़ने से पूँजी का अंतर्प्रवाह बढ़ेगा जिससे पूँजी खाता में अतिरेक उत्पन्न होने की प्रवृत्ति होगी। यदि धनात्मक चालू खाते का घाटा, पूँजी खाते के अतिरेक से अधिक है तो भुगतान-संतुलन में घाटा (चित्र 14.6A) होगा और यदि पूँजी खाते का अतिरेक चालू खाते के घाटा से अधिक हो जाता है तो भुगतान-संतुलन में अतिरेक होगा (चित्र 14.6B)।



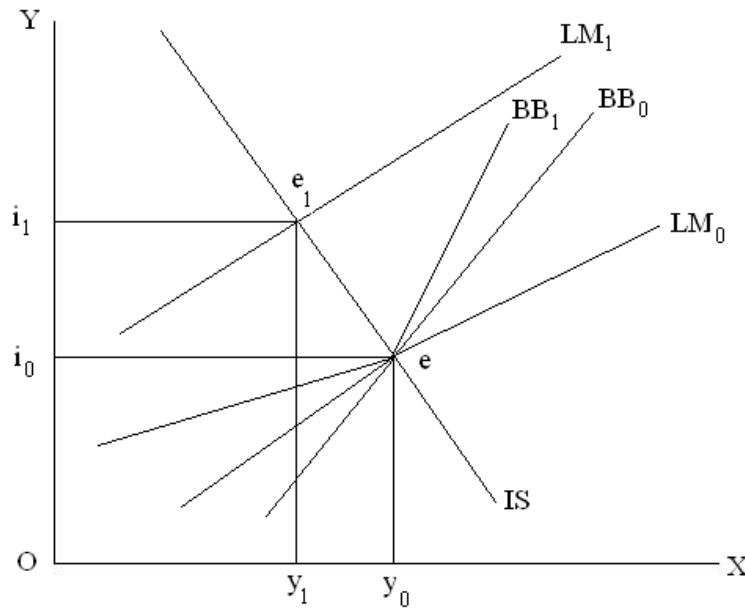
चित्र 14.5 B

इस प्रकार, आपने देखा कि यह स्पष्ट है कि राजकोषीय उपायों का भुगतान संतुलन पर क्या प्रभाव होगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि LM वक्र के सापेक्ष भुगतान-संतुलन का ढाल क्या होगा। दूसरे शब्दों में, यदि आय गुणक, आयात की सीमान्त प्रवृत्ति और पूँजी प्रवाहों की ब्याज-लोच ज्ञात हो तो सरकार ब्यय में परिवर्तन के भुगतान संतुलन पर प्रभावों को जाना जा सकता है।

14.4.2 मौद्रिक नीति तथा भुगतान-संतुलन

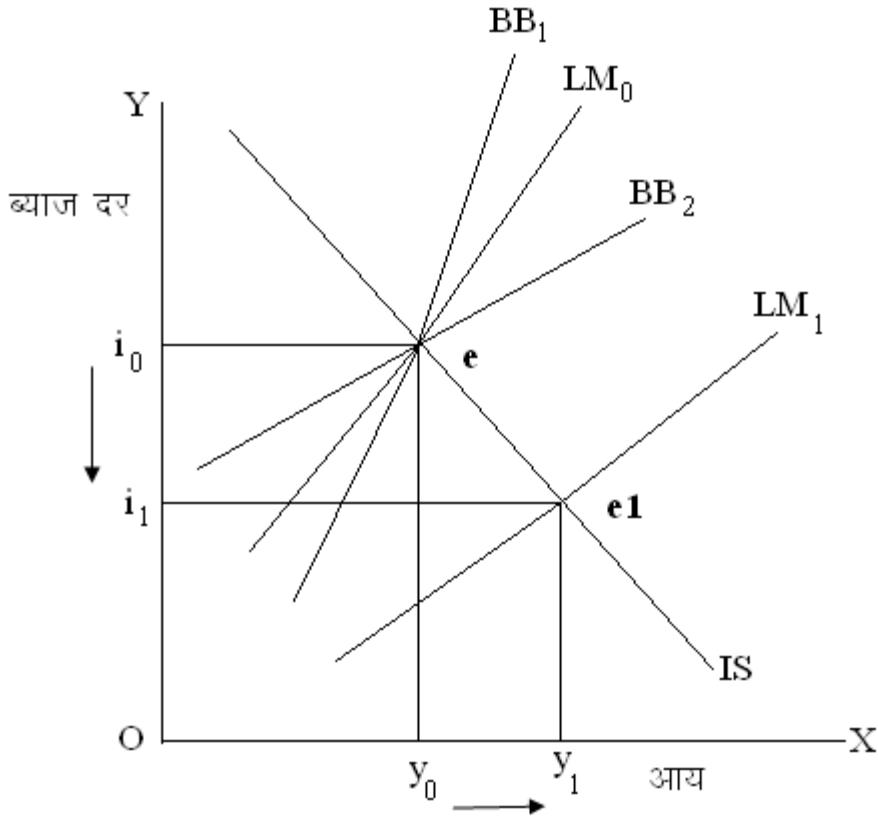
राजकोषीय नीति के ठीक विपरीत मौद्रिक नीति के भुगतान-संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव बिल्कुल सीधे-सीधे और स्पष्ट है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एक विस्तारक मौद्रिक नीति या मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि भुगतान-संतुलन में घाटा लाएगी तथा संकुचनकारी मौद्रिक नीति या मुद्रा-पूर्ति में कमी भुगतान-संतुलन में अतिरेक लाएगी, चाहे LM वक्र तथा BB वक्र का ढाल कुछ भी हो।

चित्र 14.6 में IS और LM वक्र के कटान बिन्दु e_0 पर संतुलन है। जबकि ब्याज दर i_0 तथा राष्ट्रीय आय y_0 है। मुद्रा पूर्ति में कमी से LM वक्र ऊपर बायीं ओर विवर्तित हो जाएगा जिससे नया संतुलन e_2 पर हो जाता है। जहाँ ब्याज दर बढ़कर i_1 तथा राष्ट्रीय आय घटकर y_1 हो जाती है। e_1 बिन्दु BB वक्र के बायीं ओर स्थित है इसलिए भुगतान-संतुलन में अतिरेक है। स्पष्ट है कि BB वक्र तिरछा है या चपटा, LM वक्र के मुकाबले, e_2 बिन्दु BB वक्र में बायीं ओर ही होगा। अर्थात् मुद्रा-पूर्ति में कमी से स्पष्ट भुगतान-संतुलन में अतिरेक होगा।



चित्र 14.6 A

मुद्रा-पूर्ति में कमी से आय में कमी होगी जिससे आयात में कमी होगी और चालू खाते के घाटे में आधिक्य या अतिरेक आएगा। दूसरी तरफ मुद्रा-पूर्ति में कमी से ब्याज-दर में वृद्धि हागी जिससे पूँजी का अंतर्प्रवाह बढ़ेगा और पूँजी खाते का अतिरेक बढ़ेगा। इस प्रकार, मुद्रा-पूर्ति में कमी से राष्ट्रीय आय में कमी और ब्याज-दर में वृद्धि दोनों का ही प्रभाव भुगतान-संतुलन का अतिरेक उत्पन्न करने वाला होगा। परन्तु भुगतान-संतुलन अतिरेक से अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है और संतुलन e_1 बिन्दु पर नहीं बना रहता है। मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि से LM_1 वक्र दायीं ओर खिसक कर पुनः LM_0 की स्थिति में आ जाएगा और इस स्थिति में भुगतान-संतुलन का अतिरेक समाप्त हो जाएगा।



चित्र 14.6 B

चित्र 14.6 B मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि से LM₀ वक्र दायीं तरफ नीचे की ओर खिसक आता है जिससे संतुलन e से e₁ पर आ जाता है। जिससे आय बढ़कर y₁ तथा ब्याज दर घटकर i₁ हो जाती है। e₁ बिन्दु BB वक्र के दायीं ओर स्थित है अर्थात् भुगतान शेष में घाटा होगा। वास्तव में, मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि के कारण आय में हुई वृद्धि से आयातों में वृद्धि होगी जिससे चालू खाते का घाटा बढ़ेगा जबकि ब्याज दर में कमी से पूँजी का बर्हिप्रवाह होगा जिसके कारण पूँजी खाते में घाटा होगा। इस प्रकार, कुल भुगतान-संतुलन में घाटा उत्पन्न होने की प्रवृत्ति होगी।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भुगतान-संतुलन के घाटे को दूर करने में राजकोषीय उपायों की प्रभाविता अनिश्चित है जबकि मौद्रिक उपायों की प्रभाविता बिल्कुल स्पष्ट है। एक संकुचनकारी मौद्रिक नीति या मुद्रा-पूर्ति में कमी निश्चित ही भुगतान-संतुलन के घाटे को दूर करने में प्रभावी होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भुगतान-संतुलन के घाटे को दूर करने में मौद्रिक नीति का प्रयोग करना उचित होगा। ऐसी स्थिति में राजकोषीय नीति का प्रयोग आन्तरिक संतुलन लाने अर्थात् पूर्ण रोजगार तथा कीमतों में स्थिरता लाने के लिए किया जा सकता है। जिससे कि भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने में मौद्रिक नीति अधिक प्रभावी हो सके।

14.5 भुगतान संतुलन के सन्दर्भ में मुद्रावादियों का दृष्टिकोण- सामान्य विवेचना

मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार, भुगतान संतुलन के असंतुलन को दूर करने के लिए वित्तीय बाजार पर ध्यान देना आवश्यक है। वित्तीय बाजार में मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति में असंतुलन के परिणामस्वरूप भुगतान-संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका परीक्षण आवश्यक है। मुद्रावादी भुगतान-संतुलन तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति की कड़ी का परीक्षण करके भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने का सुझाव देते हैं।

एक सरलीकृत मौद्रिक व्यवस्था में मुद्रा-पूर्ति का समीकरण निम्नलिखित होता है

$$M = C + D + F$$

जहाँ,

M= मुद्रा पूर्ति

C= अर्थव्यवस्था में प्रचलन में वह मुद्रा जो कि लोगों के पॉकेट में हो

D= बैंकों की मांग जमाएं या साख मुद्रा

F= विदेशी मुद्रा भण्डार

यदि भुगतान-संतुलन में लगातार घाटा होता है तो विदेशी मुद्रा भण्डार (F) में कमी आएगी, और इससे मुद्रा पूर्ति M में भी कमी आएगी। परन्तु साख-मुद्रा (D) में विस्तार के द्वारा M में कमी को रोक दिया जाता है। इससे यह स्पष्ट है होता है कि भुगतान-संतुलन में लगातार घाटा तभी बना रह सकता है जबकि घरेलू साख मुद्रा (D) में विस्तार के द्वारा मुद्रा-पूर्ति को बढ़ने दिया जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का मानना है कि कोई भी देश लगातार बहुत लम्बे समय तक अपने विदेशी मुद्रा भण्डार (F) में कमी के द्वारा अपने भुगतान-संतुलन के घाटे का वित्तियन नहीं कर सकता है। इसलिए उसे एक सीमा के बाद साख का विस्तार आवश्यक रूप से रोकना पड़ेगा।

इस प्रकार मौद्रिकवादियों का यह मानना है कि भुगतान संतुलन का असंतुलन एक अस्थायी परिघटना है। जोकि मुद्रा बाजार में असंतुलन के कारण बनी रहती है। दीर्घकाल में यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

भुगतान-संतुलन सिद्धान्त के परम्परागत दृष्टिकोण के अनुसार जब बैंक साख में विस्तार होता है तो ब्याज दरों में गिरावट आती है जो कि निवेश में विदेशी मुद्रा भण्डार (F) में कमी आएगी, और इससे मुद्रा पूर्ति M में भी कमी आणी लाती है। इसके विपरीत मुद्रावादियों का यह मानना है कि जब मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि होती है तो लोग इसे अपने पास नकदी के रूप में रखने की अपेक्षा खर्च करना पसंद करते हैं। इससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है और उत्पादन स्थिर रहने की स्थिति में कीमतों में वृद्धि होती है। मुद्रा-पूर्ति बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ी घरेलू मांग निर्यातों की आपूर्ति को प्रभावित करती है। घरेलू उपभोग में वृद्धि के कारण, संभाव्य निर्धारित वस्तुओं व सेवाओं की खपत घरेलू अर्थव्यवस्था में ही हो जाती है और फलस्वरूप निर्यात में कमी आती है इससे भुगतान-संतुलन में घाटा उत्पन्न होता है या फिर बढ़ जाता है।

इस प्रकार मुद्रावादियों के अनुसार अल्पविकसित देशों में अवमूल्यन उसी मात्रा में मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि बैंक साख में नियंत्रण/संकुचन के द्वारा मुद्रा-पूर्ति को नियंत्रित किया जाए। यदि अवमूल्यन के साथ क साख का अत्यधिक विस्तार होता है तो भुगतान-संतुलन का घाटा कम होने के बजाए और बढ़ भी सकता है।

14.6 भुगतान संतुलन समायोजन और मौद्रिक उपागम

भुगतान-संतुलन के मौद्रिक दृष्टिकोण की शुरुआत 1960 के दशक में राबर्ट मण्डल और हैरी जानसन द्वारा की गयी थी और 1970 के दशक में यह पूरी तरह विकसित हुआ। भुगतान-संतुलन को पूर्णतया एक मौद्रिक परिघटना मानते हुए यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि दीर्घकाल में भुगतान-संतुलन में असंतुलन पैदा करने और उसके समायोजन दोनों में मुद्रा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। यह मुद्रा की मांग और पूर्ति के रूप में भुगतान शेष के परिवर्तनों का विवेचन करता है। भुगतान-संतुलन में अतिरेक का कारण मुद्रा-पूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की मांग का अधिक होना है। जबकि घाटे का कारण मुद्रा-पूर्ति का मुद्रा की मांग से अधिक होना है।

14.6.1 मान्यताएँ

1. यह माना लिया गया है कि परिवहन लागतों को जोड़ने पर, विभिन्न देशों में बेची गई एक समान वस्तुओं की कीमत एक समान रहती है। इसलिए स्थिर विनिमय दरों के अन्तर्गत करेंसी प्रवाहों को रोकना संभव नहीं है।
2. यह मान लिया गया है कि दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है या पूर्ण रोजगार की प्रवृत्ति है और राष्ट्रीय आय या उत्पादन पूर्ण रोजगार की स्थिति में उत्पादन को दर्शाता है।
3. सभी देशों में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, इसलिए एक देश में बढ़ी हुई मांग को घरेलू उत्पाद में वृद्धि से पूरा नहीं किया जा सकता।
4. एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग आय, धन और ब्याज दर का स्थिर फलन है। जब आय बढ़ती है तो मुद्रा की मांग (नकद शेष) बढ़ती है और ब्याज दरें बढ़ती हैं तो मुद्रा की मांग गिरती है।
5. वस्तु और पूंजी दोनों बाजारों में उपभोग में पूर्ण स्थानापन्नता होती है जो प्रत्येक वस्तु के लिए एक कीमत और संपूर्ण देश के लिए एक ब्याज दर सुनिश्चित करती
6. सभी देशों में मजदूरी-कीमत लोचशीलता पूर्ण रोजगार स्तर पर उत्पादन को निश्चित करती है।

14.6.2 मौद्रिक उपागम

मौद्रिक दृष्टिकोण में मुद्रा-रूप मुद्रा-शेषों को मुद्रा-रूप (nominal) राष्ट्रीय आय का फलन माना गया है। मुद्रा-शेषों का राष्ट्रीय आय से धनात्मक संबंध है जो कि दीर्घकाल में स्थिर रहता है। इस प्रकार, मुद्रा की मांग के समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता

$$M_d = kPy \dots \dots \dots (1)$$

जहाँ,

M_d = मुद्रा-रूप मुद्रा शेषों की मांगी गयी मात्रा है।

k = मुद्रा-रूप मुद्रा-शेषों का मुद्रा-रूप राष्ट्रीय आय से अनुपात या राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा जिसे लोग नकदी-शेष के रूप में रखना चाहते हैं।

P = घरेलू कीमत स्तर

y = वास्तविक उत्पादन

समीकरण (1) में Py = मौद्रिक राष्ट्रीय आय या उत्पादन (Y)

k राष्ट्रीय आय के उस अनुपात को बताता है जिसे लोग नकदी-शेष के रूप में रखते हैं और यह मुद्रा के चलन-वेग (v) का व्युत्क्रमानुपाती ($k=1/v$) है। चूंकि v अनेक संस्थागत कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए k भी k मनोवैज्ञानिक कारकों तथा अन्य आर्थिक चरों पर भी निर्भर करता है जिसे कि स्थिर मान लिया गया है। ऐसी स्थिति में, मुद्रा-रूप मुद्रा-शेषों की मांग (M_d) घरेलू कीमत स्तर और वास्तविक राष्ट्रीय आय का स्थिर और धनात्मक फलन है।

मौद्रिक उपागम के अनुसार, मुद्रा की मांग ब्याज दर (i) का भी फलन है।

$$M_d = f(Y.P.i) \dots \dots \dots (2)$$

परन्तु इनमें ऋणात्मक संबंध है। इस प्रकार, M_d का Py से सीधा तथा i से व्युत्क्रम संबंध होता है।

विश्लेषण की सरलता के लिए हम M_d को सिर्फ Py या मुद्रा-रूप राष्ट्रीय आय या उत्पादन का ही फलन मानेंगे। दूसरी ओर, मुद्रा की पूर्ति दी हुई है

$$M_s = m(D + F) \dots \dots \dots (3)$$

जहाँ,

M_s = राष्ट्र की कुल मुद्रा-पूर्ति

m = मुद्रा-गुणक

D = राष्ट्र के मौद्रिक आधार का घरेलू घटक

F = राष्ट्र के मौद्रिक आधार का अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी घटक

देश के मौद्रिक आधार का घरेलू घटक (D) देश के मौद्रिक प्राधिकरणों द्वारा सृजित घरेलू साख या घरेलू परिसम्पत्तियाँ हैं जो कि राष्ट्र की मुद्रा-पूर्ति का हिस्सा हैं। मुद्रा-पूर्ति का विदेशी घटक (F), राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्वों (मुद्रा भंडार) को बताता है जो कि भुगतान-संतुलन के अतिरेक में होने पर बढ़ जाता है जबकि घाटे में होने पर कम हो जाता है।

$(D + F)$ देश का मौद्रिक आधार या उच्च शक्ति मुद्रा (High Powered Money) कहा जाता है। इस प्रकार, देश में मुद्रा-पूर्ति उच्च शक्ति मुद्रा और मुद्रा गुणक के मान पर निर्भर करती है। मुद्रा गुणक का मान स्थिर है। संतुलन की स्थिति में, मुद्रा की मांग (M_d) मुद्रा की पूर्ति (M_s) के बराबर होगी।

$$M_d = M_s \dots \dots \dots (4)$$

या

$$M_d = m (D + F) \dots \dots \dots (5)$$

सरलता के लिए m , जो एक स्थिरांक है, की उपेक्षा करने पर

$$M_d = (D + F) \dots \dots \dots (6)$$

$$F = M_d - D \dots \dots \dots (7)$$

या

$$\Delta F = \Delta M_d - \Delta D \dots \dots \dots (8)$$

अर्थात् विदेशी मुद्रा रिजर्वों (मुद्रा भंडार) में परिवर्तन मुद्रा की मांग में परिवर्तन और मौद्रिक आधार के घरेलू घटक का अंतर है।

भुगतान शेष घाटा या अतिरेक देश के विदेशी मुद्रा रिजर्व में परिवर्तनों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार,

$$\Delta F = B \dots \dots \dots (9)$$

या

$$B = \Delta M_d - \Delta D \dots \dots \dots (10)$$

जहाँ B भुगतान शेष को व्यक्त करता है जो मुद्रा की मांग में परिवर्तन (ΔM_d) और घरेलू साख में परिवर्तन (ΔD) के बीच अंतर के बराबर होता है। समीकरण 8 से स्पष्ट है कि यदि भुगतान शेष में घाटा है तो B ऋणात्मक होगा जो विदेशी मुद्रा रिजर्व (मुद्रा भंडार) F एवं इसलिए मुद्रा पूर्ति (M_s) को कम करता है। दूसरी ओर, यदि भुगतान शेष में अतिरेक है तो B धनात्मक होगा जो विदेशी मुद्रा रिजर्व (मुद्रा भंडार) R और इसलिए मुद्रा पूर्ति (M_s) को बढ़ाता है। जब $B = 0$ हो तो इसका अर्थ है, भुगतान शेष संतुलन में है या भुगतान शेष में असंतुलन नहीं है।

मौद्रिक धारणाओं में स्वतः समायोजन तंत्र की विवेचना स्थिर और लोचशील दोनों विनिमय दर प्रणालियों के अन्तर्गत की जाती है।

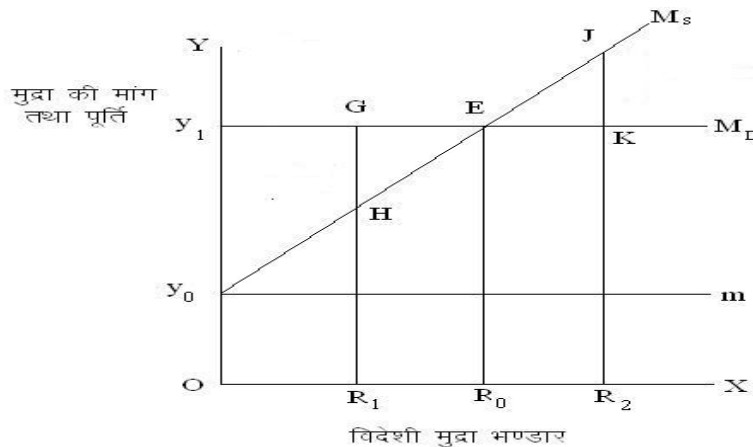
14.6.3 स्थिर विनिमय दरों के के अंतर्गत मौद्रिक दृष्टिकोण:

स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत मान लें कि मुद्रा की मांग (M_D) मुद्रा की पूर्ति (M_S) के बराबर ($M_D=M_S$) है जिससे भुगतान शेष (या B) शून्य होता है। मान लें कि यदि GDP में वृद्धि के कारण मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है तो संतुलन बनाने के लिए या तो देश के घरेलू मौद्रिक आधार में वृद्धि होगी या अंतर्राष्ट्रीय रिजर्वों का अंतर्प्रवाह बढ़ेगा या फिर भुगतान संतुलन में अतिरेक होगा। यदि देश के मौद्रिक प्राधिकरण मुद्रा-पूर्ति (D) में वृद्धि नहीं करते हैं तो मुद्रा की अतिरिक्त मांग, विदेशी मुद्रा पूर्ति (f) या भुगतान-संतुलन के अतिरेक द्वारा संतुष्ट की जाएगी या होगी। अर्थात् यदि दी हुई विनिमय दर पर $M_S < M_D$ हो तो भुगतान शेष अतिरेक होगा।

परिणामस्वरूप, लोग विदेशियों को वस्तुएँ और प्रतिभूतियाँ बेचकर घरेलू मुद्रा प्राप्त करते हैं। वे अपनी आय की तुलना में व्यय को सीमित कर अतिरिक्त मुद्रा शेषों (money balances) को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में मौद्रिक अधिकारी घरेलू करेंसी के बदले अतिरिक्त विदेशी मुद्रा खरीदेंगे। इससे विदेशी मुद्रा रिजर्व (मुद्रा भंडार) का अन्तःप्रवाह (inflow) होगा और घरेलू मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगी। इस प्रकार, विदेशी मुद्रा रिजर्व के अन्तःप्रवाह का अर्थ है मुद्रा-पूर्ति के विदेशी घटक (F) और इसलिए घरेलू मुद्रा पूर्ति (M_S) में वृद्धि।

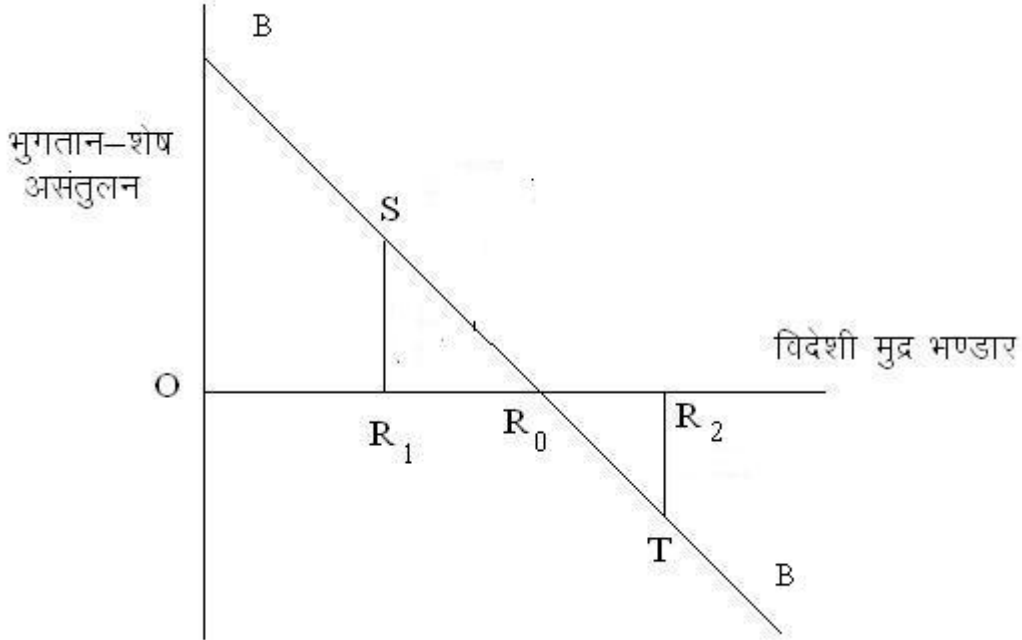
यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक मुद्रा की मांग (M_D) मुद्रा की पूर्ति (M_S) के बराबर ($M_D=M_S$) नहीं हो जाता तथा भुगतान शेष ($B = 0$) में पुनः संतुलन स्थापित नहीं हो जाता। दूसरी ओर, यदि मुद्रा की मांग अपरिवर्तित हो तो देश के मौद्रिक आधार के घरेलू घटक (D) में वृद्धि होने पर और इस कारण मुद्रा-पूर्ति (M_S) में वृद्धि होने पर अंतर्राष्ट्रीय पूँजी का बहिर्गमन होगा या भुगतान-संतुलन में घाटा होगा। अर्थात् यदि $M_S > M_D$ तो वे लोग जिनके पास अत्यधिक नकदी शेष हैं वे अधिक विदेशी वस्तुओं और प्रतिभूतियों की अपनी खरीदारियाँ बढ़ाते हैं। इसलिए उनकी कीमतें बढ़ती हैं और वस्तुओं एवं विदेशी परिसंपत्तियों के आयात में वृद्धि होती है। इससे भुगतान शेष में चालू और पूँजी दोनों खतों में व्यय में वृद्धि होती है जिससे भुगतान शेष में घाटा उत्पन्न होता है।

स्थिर विनिमय दर कायम रखने के लिए मौद्रिक अधिकारी विदेशी विनिमय रिजर्व (मुद्रा भंडार) को बेचेगा एवं घरेलू मुद्रा को खरीदेगा। इस प्रकार, विदेशी मुद्रा रिजर्व के बाह्य प्रवाह का अर्थ है मुद्रा-पूर्ति के विदेशी घटक (F) और इसलिए घरेलू मुद्रा पूर्ति (M_S) में कमी। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक मुद्रा की मांग (M_D) मुद्रा की पूर्ति (M_S) के बराबर ($M_D=M_S$) नहीं हो जाता तथा भुगतान शेष ($B = 0$) में पुनः संतुलन स्थापित नहीं हो जाता। इस प्रकार, भुगतान शेष घाटा या अतिरेक एक अस्थायी धारणा है जो दीर्घकाल में स्वतः ठीक हो जाता है।



चित्र 14.7A

चित्र 14.7A में, M_D स्थिर मुद्रा मांग वक्र है और M_S मुद्रा पूर्ति वक्र है। क्षैतिज रेखा m मौद्रिक आधार को व्यक्त करती है जो घरेलू साख D का गुणज है एवं स्थिरांक है। यह मुद्रा पूर्ति का घरेलू अवयव है। यही कारण है कि M_S वक्र y_0 बिन्दु से प्रारम्भ होता है।



चित्र 14.7 B

M_S और M_D वक्र E बिन्दु पर एक दूसरे को काटते हैं जहाँ देश का भुगतान शेष संतुलन में होता है और उसका विदेशी मुद्रा रिजर्व OR_0 होता है। चित्र 14.7 B में वक्र BB भुगतान असंतुलन वक्र है जो भाग 14.7A के M_S और M_D वक्र के बीच अनुलंब अंतर के रूप में खींचा गया है। चित्र 14.7B में R_0 , 14.7A में E बिन्दु से संगत है, जहाँ भुगतान शेष में कोई असंतुलन नहीं है।

यदि $M_S < M_D$ हो तो GH भुगतान शेष अतिरेक होता है। चित्र 14.7A में संतुलन बिन्दु E के बायीं ओर मुद्रा की मांग (M_D) मुद्रा की पूर्ति (M_S) से अधिक है। जब मुद्रा की मांग (M_D) मुद्रा की पूर्ति (M_S) से GH के बराबर अधिक है इससे विदेशी मुद्रा रिजर्वों का अंतर्वाह (inflow) होता है। जिससे विदेशी विनिमय रिजर्व (मुद्रा भंडार) बढ़कर OR_1 से OR हो जाता है इससे मुद्रा पूर्ति बढ़ती है और अंततः E बिन्दु पर भुगतान शेष संतुलन में होता है।

दूसरी ओर, यदि $M_S > M_D$ हो तो $JKJK$ के बराबर भुगतान शेष में घाटा होता है। जिससे विदेशी मुद्रा रिजर्व का बाह्य प्रवाह होता है और वह कम होकर OR_2 से OR हो जाती है इससे मुद्रा पूर्ति में कमी होती है और E बिन्दु पर भुगतान शेष पुनः संतुलन में आ जाता है। 14.7 A में परिवर्तन के अनुरूप चित्र 14.7 B में इसी प्रक्रिया की विवेचना की गई है जहाँ भुगतान शेष असंतुलन स्वतः ठीक हो जाता है। चित्र 14.7 B में भुगतान शेष अतिरेक $R_1S_1 = GH$ तथा घाटा $R_2T = JK$ बराबर होते हैं।

इस प्रकार, एक देश के भुगतान संतुलन में अतिरेक का कारण है-देश के अंदर मुद्रा की मांग की अपेक्षा राष्ट्र के मौद्रिक आधार के घरेलू घटक (D) में धीमी वृद्धि है। जबकि भुगतान-संतुलन में घाटा का कारण है मुद्रा की मांग की अपेक्षा मुद्रा-पूर्ति के घरेलू घटक की पूर्ति में तेज वृद्धि या अधिक होना जिससे मौद्रिक रिजर्व का देश से बहिर्प्रवाह होने लगता है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत, इस प्रकार, दीर्घकाल में एक देश को अपनी

मुद्रा-पूर्ति पर नियंत्रण नहीं होता है। दीर्घकाल में, देश के मुद्रा-पूर्ति का आकार भुगतान-संतुलन के संतुलन के साथ संगत होगा।

इस प्रकार, एक देश के भुगतान-संतुलन में अतिरिक्त मुद्रा मांग में आधिक्य का परिणाम है क्योंकि मुद्रा मांग के आधिक्य को घरेलू मौद्रिक प्राधिकरण मुद्रा-पूर्ति द्वारा संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। जबकि भुगतान संतुलन का घाटा मुद्रा-स्टॉक की पूर्ति में आधिक्य का परिणाम है क्योंकि मुद्रा-पूर्ति के इस आधिक्य को घरेलू मौद्रिक प्राधिकरण खत्म या सुधार नहीं करते हैं। दीर्घकाल में भुगतान-संतुलन के अतिरिक्त या घाटे के स्वतः ही ठीक हो जाने की प्रवृत्ति होती है। यह विदेशी मुद्रा के अंतर्प्रवाह या बहिर्प्रवाह के द्वारा स्वतः ही अतिरिक्त या घाटे को ठीक कर देगा। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत दीर्घकाल में एक देश का अपनी मुद्रा-पूर्ति पर नियंत्रण नहीं होता है।

14.6.4 परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत मौद्रिक उपागम

परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत भुगतान-शेष का असंतुलन तुरंत ही बिना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा या रिजर्वों के प्रवाह के विनिमय दरों में स्वतः परिवर्तनों के द्वारा ठीक हो जाता है। इस प्रकार परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत एक राष्ट्र का अपनी मुद्रा-पूर्ति तथा मौद्रिक नीति पर पूरा नियंत्रण होता है। घरेलू कीमतों में परिवर्तन होने पर विनिमय दरों में भी परिवर्तन होता है और परिणाम स्वरूप भुगतान-संतुलन के असंतुलन में स्वतः समायोजन की प्रक्रिया शुरू होती है।

मान लें कि मौद्रिक अधिकारी मुद्रा पूर्ति बढ़ाता है और मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मांग ($M_s > M_D$) से अधिक है और भुगतान शेष में घाटा होता है। वे लोग जिनके पास अतिरिक्त नकद शेष है, अधिक वस्तुएँ खरीदते हैं जिससे घरेलू और आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है। इससे घरेलू करेंसी में मूल्यहास (Depreciation) और विनिमय दर में वृद्धि होती है। फलस्वरूप मुद्रा की मांग बढ़ती है जब तक की मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मांग के बराबर न हो जाय और भुगतान शेष संतुलन में न हो जाय। इसके विपरीत स्थिति तब उत्पन्न होगी जब $M_s < M_D$ हो तो कीमतों में कमी और घरेलू करेंसी में मूल्यवृद्धि (Appreciation) होता है। जो स्वतः मुद्रा की आधिक्य मांग को समाप्त कर देता है। विनिमय दर तब तक गिरती है जब तक $M_s = M_D$ एवं विदेशी मुद्रा रिजर्वों में किसी अन्तर्प्रवाह के बिना भुगतान शेष संतुलन में न हो जाए।

इस प्रकार, यदि अतिरिक्त मुद्रा-पूर्ति के कारण भुगतान-संतुलन में घाटा होता है तो यह स्वतः देश की मुद्रा में मूल्य हास लाएगा। जिसके कारण कीमतों और इसलिए मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है जिससे कि अतिरिक्त मुद्रा-पूर्ति खप जाती है और भुगतान-संतुलन का घाटा समाप्त हो जाता है। दूसरी ओर यदि मुद्रा की अतिरिक्त मांग के कारण भुगतान-संतुलन में अतिरिक्त हो तो यह ही देश की करेंसी में अधिमूल्यन लाएगा। इससे घरेलू कीमतों में कमी आएगी और भुगतान संतुलन का अतिरिक्त भी समाप्त हो जाएगा।

स्पष्ट है कि स्थिर विनिमय दरों के अंतर्गत भुगतान संतुलन का असंतुलन मुद्रा या रिजर्वों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह का परिणाम है जबकि परिवर्तनशील विनिमय दरों के अंतर्गत भुगतान-संतुलन का असंतुलन बिना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रवाह के उत्पन्न होता है और समाप्त होता है। यह विनिमय दरों में स्वतः परिवर्तन के द्वारा तुरंत स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसलिए राष्ट्र का अपनी मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण रहता है जबकि स्थिर विनिमय दरों की स्थिति में देश का अपनी मुद्रा-पूर्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता है।

14.6.5 आलोचना

1. जॉन्सन के अनुसार "बेची गई समान वस्तुओं के लिए एक कीमत नियम" मान्य नहीं है। क्योंकि जब उत्पादन के साधनों को गैर-व्यापाररत वस्तुओं को उत्पादित करने वाले क्षेत्रों में लगाया जाता है तो गैर-व्यापाररत वस्तुओं की अधिक मांग, व्यापाररत वस्तुओं की घटी हुई पूर्ति में समायोजित हो जाएगी।

इससे आयात बढ़ेंगे और सभी व्यापार वस्तुओं के लिए एक कीमत के नियम में बाधा पड़ेगी। बाजार अपूर्णताओं के कारण भी अनेक बाजारों में एक कीमत के नियम को सही ढंग से कार्य करने में विघ्न पड़ता है। फिर व्यापारियों द्वारा विदेशी कीमतों और व्यापार नियमों के बारे में सूचनाओं के अभाव के कारण कीमत पिभेदक हो सकते हैं।

2. मुद्रा की मांग दीर्घकाल में स्थिर हो सकती है परन्तु अल्पकाल में नहीं। इसलिए आलोचक मुद्रा की स्थिर मांग की मान्यता से सहमत नहीं हैं।
3. आलोचकों के अनुसार स्थिर विनिमय दरों के अंतर्गत मुद्रा प्रवाहों को निष्फल करना संभव नहीं है। वे तर्क देते हैं कि करेंसी प्रवाहों का निष्फल करना पूरी तरह से संभव है यदि मुद्रा शेषों और बांडो के सापेक्ष महत्व के बारे में निजी क्षेत्र अपने सम्पत्ति पोर्टफोलियों की संरचना को समायोजित करने के लिए इच्छुक है, अथवा यदि सार्वजनिक क्षेत्र ऊँचा बजट घाटा करने को तैयार है, जब भी उसे भुगतान शेष घाटे का सामना करना पड़ता है।
4. मौद्रिक धारणा किसी देश के भुगतान शेष और उसकी मुद्रा पूर्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित है। कई अर्थशास्त्रियों को इसमें संदेह है। इन दोनों के बीच संबंध भुगतान शेष में घाटा या अरितेक होने पर मौद्रिक अधिकारी द्वारा विदेशी मुद्रा रिजर्वों के अन्तर्ग्रवाहो एवं वाह्यप्रवाहों को निष्प्रभाव करने की क्षमता पर निर्भर करता है। इसके लिए बाहरी प्रवाहों के निष्फलन की कुछ आवश्यकता होती है। परन्तु यह वित्तीय बाजारों के वैश्वीकरण (globalisation) के कारण संभव नहीं होता है।
5. यह धारणा भुगतान शेष संतुलन लाने में घरेलू साख की भूमिका पर जोर देती है और आर्थिक नीति उपायों की उपेक्षा करती है। प्रो. क्यूरी (Currie) के अनुसार, भुगतान शेष संतुलन व्यय बदलावकारी (expediture-switch) से कार्य करती है।
6. मौद्रिक धारणा भुगतान शेष में स्वतः ठीक होने वाले दीर्घकालीन संतुलन से संबंधित होती है। यह धारणा अवास्तविक है क्योंकि यह अल्पकाल की व्याख्या करने में असफल है जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था नए संतुलन पर पहुंचने के लिए गुजरती है।
7. पूर्ण रोजगार की मान्यता वास्तविक नहीं है।

14.7 अभ्यास हेतु प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न:

1. स्थिर विनिमय दरों के अंतर्गत भुगतान संतुलन के समयोजन की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।
2. मौद्रिक नीति के भुगतान-संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।
3. भुगतान संतुलन के सन्दर्भ में मुद्रावादियों के दृष्टिकोण का वर्णन कीजिये।
4. भुगतान संतुलन के समयोजन के सन्दर्भ में मौद्रिक उपागम का संक्षिप्त वर्णन कीजिये।
5. परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत मौद्रिक उपागम की समीक्षा कीजिये।
6. स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत मौद्रिक उपागम की समीक्षा कीजिये।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

1. परिवर्तनशील विनिमय दरें विदेशी विनिमय बाजार में भुगतान-संतुलन का घाटा स्वतः ही दूर हो जाता है
(क) विदेशी विनिमय दर के मूल्य में वृद्धि तथा घरेलू मुद्रा के मूल्य में मूल्य हास के द्वारा
(ख) विदेशी विनिमय दर के मूल्य में मूल्य हास तथा घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि के द्वारा

- (ग) विदेशी विनिमय दर तथा घरेलू मुद्रा के मूल्य में मूल्य हास के द्वारा
 (घ) विदेशी विनिमय दर तथा घरेलू मुद्रा के मूल्य में मूल्य में वृद्धि के द्वारा
2. विदेशी विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने के लिए सरकार भुगतान संतुलन का घाटा को समाप्त करने के लिए
 (क) अपने पहले के विदेशी मुद्रा भण्डार में कमी करेगी,
 (ख) दूसरे देशों या संस्थानों से उधार लेगी,
 (ग) सोने का निर्यात करेगी।
 (घ) उपरोक्त सभी
3. भुगतान-संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव बिल्कुल सीधे-सीधे और स्पष्ट के
 (क) राजकोषीय नीति के
 (ख) मौद्रिक नीति के
 (ग) उपरोक्त दोनों के
 (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
4. भुगतान-संतुलन में लगातार घाटा होता है तो
 क) विदेशी मुद्रा भण्डार (F) में कमी आएगी, और इससे मुद्रा पूर्ति M में भी कमी आएगी
 (ख) विदेशी मुद्रा भण्डार (F) में कमी आएगी, और इससे मुद्रा पूर्ति M में वृद्धि आएगी
 (ग) विदेशी मुद्रा भण्डार (F) में वृद्धि आएगी, और इससे मुद्रा पूर्ति M में भी कमी आएगी
 (घ) विदेशी मुद्रा भण्डार (F) में कमी आएगी, और इससे मुद्रा पूर्ति M में भी कमी आएगी
5. मुद्रा-रूप मुद्रा-शेषो को फलन माना गया है
 (क) बचत का
 (ख) वास्तविक राष्ट्रीय आय का
 (ग) मुद्रा-रूप राष्ट्रीय आय का
 (घ) निवेश का
6. यदि मुद्रा की मांग (M_d) मुद्रा की पूर्ति (M_s) से अधिक है तो
 (क) भुगतान शेष अतिरेक होगा।
 (ख) विदेशी मुद्रा रिजर्व(मुद्रा भंडार) का अन्तःप्रवाह (inflow) होगा
 (ग) घरेलू मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगा
 (घ) उपरोक्त सभी

सत्य व असत्य :

1. मौद्रिक नीति के भुगतान-संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव बिल्कुल सीधे-सीधे और स्पष्ट नहीं है।
2. परिवर्तनशील विनिमय दरों के अंतर्गत मौद्रिक प्राधिकरण का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।
3. भुगतान-संतुलन के घाटे को दूर करने में राजकोषीय उपायों की प्रभाविता निश्चित है।
4. भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने में मौद्रिक नीति का प्रयोग करना उचित होगा।
5. मुद्रावादियों के अनुसार भुगतान शेष घाटा या अतिरेक एक अस्थायी धारणा है जो दीर्घकाल में स्वतः ठीक हो जाता है।
6. एक देश के भुगतान संतुलन में अतिरेक का कारण है-देश के अंदर मुद्रा की मांग की अपेक्षा राष्ट्र के

- मौद्रिक आधार के घरेलू घटक (D) में तेज वृद्धि है।
7. स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत, दीर्घकाल में एक देश को अपनी मुद्रा-पूर्ति पर नियंत्रण होता है।
 8. भुगतान संतुलन में घाटा के कारण है मौद्रिक रिजर्व का देश से बहिर्प्रवाह होने लगता है।
 9. स्थिर विनिमय दरों के अंतर्गत भुगतान-संतुलन का असंतुलन मुद्रा या रिजर्वों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह का परिणाम है।
 10. यदि अतिरिक्त मुद्रा-पूर्ति के कारण भुगतान-संतुलन में घाटा होता है तो यह स्वतः देश की मुद्रा में मूल्य वृद्धि लाएगा।

14.8 सारांश

आधुनिक मुद्रावादी दृष्टिकोण परम्परागत प्रतिष्ठित सिद्धान्त का ही विस्तार है। मुद्रावादी आधुनिक अर्थशास्त्री स्टॉक-प्रवाह समायोजन की एक आधुनिक संकल्पना के माध्यम से मौद्रिक संतुलन की प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं। इनके अनुसार, मुद्रा-पूर्ति की अधिक मांग का अर्थव्यवस्था के समग्र मांग और व्यय पर सीधा प्रभाव पड़ता है और फलस्वरूप भुगतान-संतुलन प्रभावित होता है।

भुगतान शेष का मौद्रिक सिद्धान्त समग्र भुगतान शेष की व्याख्या है। इस सिद्धान्त के अनुसार, भुगतान शेष घाटा सदैव और सभी स्थानों पर एक मौद्रिक तत्व है। इसलिए यह केवल मौद्रिक उपायों से ही ठीक किया जा सकता है। भुगतान संतुलन का घाटा और अतिरिक्त मूलतः अर्थव्यवस्था में मुद्रा के वास्तविक ऐच्छिक स्टॉक (actual desired stocks) के समायोजन की प्रक्रिया है।

स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत, जब अतिरिक्त मुद्रा-पूर्ति, भुगतान-संतुलन में घाटे का मुख्य कारण हो तब यह आवश्यक हो कि उचित मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा-पूर्ति को नियंत्रित किया जाए या फिर आय या ब्याज दर में परिवर्तन की नीति से मुद्रा की मांग को बढ़ाया जाए जिससे कि मुद्रा की अतिरिक्त पूर्ति को खपाया जा सके और भुगतान-संतुलन के घाटे को खत्म किया जा सके। एक परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा के वास्तविक स्टॉक में कमी जो कि विनिमय दर के हास के कारण होती है, से भुगतान-संतुलन का असंतुलन (घाटा) के स्वतः ही दूर होने की प्रवृत्ति होगी।

इस प्रकार मौद्रिकवादियों का यह मानना है कि भुगतान-संतुलन का असंतुलन एक अस्थायी परिघटना है। जोकि मुद्रा बाजार में असंतुलन के कारण बनी रहती है। एक देश के भुगतान-संतुलन में अतिरिक्त मुद्रा मांग में आधिक्य का परिणाम है क्योंकि मुद्रा मांग के आधिक्य को घरेलू मौद्रिक प्राधिकरण मुद्रा-पूर्ति से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। जबकि भुगतान संतुलन का घाटा मुद्रा-स्टॉक की पूर्ति में आधिक्य का परिणाम है क्योंकि मुद्रा-पूर्ति के इस आधिक्य को घरेलू मौद्रिक प्राधिकरण खत्म या सुधार नहीं करते हैं।

दीर्घकाल में भुगतान-संतुलन के अतिरिक्त या घाटे के स्वतः ही ठीक हो जाने की प्रवृत्ति होती है। यह विदेशी मुद्रा के अंतर्प्रवाह या बहिर्प्रवाह के द्वारा स्वतः ही अतिरिक्त या घाटे को ठीक कर देगा। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत दीर्घकाल में एक देश का अपनी मुद्रा-पूर्ति पर नियंत्रण नहीं होता है। परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत भुगतान-शेष का असंतुलन तुरंत ही बिना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा या रिजर्वों के प्रवाह के विनिमय दरों में स्वतः परिवर्तनों के द्वारा ठीक हो जाता है।

इस प्रकार परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत एक राष्ट्र का अपनी मुद्रा-पूर्ति तथा मौद्रिक नीति पर पूरा नियंत्रण होता है। घरेलू कीमतों में परिवर्तन होने पर विनिमय दरों में भी परिवर्तन होता है और परिणाम स्वरूप भुगतान-संतुलन के असंतुलन में स्वतः समायोजन की प्रक्रिया शुरू होती है।

14.9 शब्दावली

- **विनिमय दर** - विनिमय दर का तात्पर्य है, वह विदेशी मुद्रा जो कि विश्व के सभी व्यापार करने वाले देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य हो। विदेशी विनिमय की कीमत या विदेशी विनिमय दर घरेलू मुद्रा की वह मात्रा है जो कि विदेशी विनिमय की प्रति इकाई के बदले दी जाती है। विदेशी विनिमय दर, विदेशी मुद्रा की घरेलू मुद्रा के रूप में कीमत है। किसी भी वस्तु की कीमत की तरह विदेशी मुद्रा की कीमत या विनिमय दर, विदेशी विनिमय की मांग तथा विदेशी विनिमय की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है।
- **परिवर्तनशील विनिमय दर** - परिवर्तनशील विनिमय दर विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति के शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है तथा इसमें मौद्रिक प्राधिकरण का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।
- **स्थिर विनिमय दर** - जब विदेशी विनिमय बाजार में सरकार या राज्य का पूरा हस्तक्षेप रहता है बाजार विनिमय दर एक दी हुई संतुलन स्तर पर स्थिर रहती है। यदि मांग और पूर्ति की शक्तियाँ इस संतुलन को बिगाडती हैं या सट्टेबाजी की गतिविधियाँ इस संतुलन को बिगाडती है तो सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है और इस संतुलित विनिमय दर को बनाए रखती है। सरकार विदेशी विनिमय के क्रय या विक्रय के माध्यम से ऐसा करती है। इसे स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहते हैं।
- **मौद्रिक नीति** - मौद्रिक नीति, मुद्रा-पूर्ति (Ms) तथा ब्याज दर (i) में परिवर्तन के द्वारा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है।
- **राजकोषीय नीति** - राजकोषीय नीति सरकारी व्यय (G) तथा करों (T) के द्वारा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है।
- **ब्याज दर** - ब्याज-धारीत प्रतिभूतियों की जगह निष्क्रिय मुद्रा-शेषों के रूप में नकदी रखने की लागत है।

14.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न:

1. क 2. घ 3. ख 4. क 5. ग 6. घ

सत्य व असत्य :

1. असत्य 2. सत्य 3. असत्य 4. सत्य 5. असत्य
6. असत्य 7. असत्य 8. सत्य 9. सत्य 10. असत्य

14.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

- HH. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: International Economics: Theory and Policy, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- Charles P Kindleberger, International Economics, Richard D. Irwin Inc., Illinois, 1968
- Dominik Salvatore, International Economics, John Willy & Sons, Inc., 2008
- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006 •

- सुदामा सिंह एवं एम0सी0 वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड एंड आई0बी0एच0 पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम0एल0 झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010।
- ज्ञानेंद्र सिंह कुशवाहा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1979।

12.14 उपयोगी/सहायक पाठ्य सामग्री

- HH. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt.Ltd. 2001
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: International Economics: Theory and Policy, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- Charles P Kindleberger, International Economics, Richard D. Irwin Inc.,Illinois, 1968
- Dominik Salvatore, International Economics, John Willy & Sons, Inc.,2008
- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006
- एस. एन. लाल, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहबाद, 2004
- एच. एस. अग्रवाल, तथा सी. एस. बरला, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2003.
- सुदामा सिंह एवं एम. सी. वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड एंड आई. बी. एच. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम0 एल0 झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010.
- डॉ. जी. सी. सिंघई एवं डॉ. जे. पी. मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा, 2010

14.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. भुगतान-शेष के असंतुलन को दूर करने में राजकोषीय उपायों की अपेक्षा मौद्रिक उपाय अधिक प्रभावी और निश्चित है, विवेचना कीजिए।
2. भुगतान संतुलन की समस्या को हल करने हेतु मौद्रिक सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
3. भुगतान-शेष के घाटे को समाप्त या कम करने में व्यय परिवर्तनकारी उपायों की विवेचना कीजिए।
4. भुगतान-संतुलन के सन्दर्भ में मुद्रवादियों के दृष्टिकोण की समीक्षा कीजिये.

इकाई 15 - इष्टतम मुद्रा क्षेत्र सिद्धान्त (Theory of Optimum Currency Area)

- 15.1 प्रस्तावना
- 15.2 उद्देश्य
- 15.3 इष्टतम मुद्रा क्षेत्र
- 15.4 विभिन्न सिद्धान्त
 - 15.4.1 मण्डल का साधन गतिशीलता सिद्धान्त
 - 15.4.2 मैककिनन का खुली अर्थव्यवस्था सिद्धान्त
 - 15.4.3 केनन का वस्तु विविधीकरण सिद्धान्त
 - 15.4.4 मैगनीफिको का स्फीति की प्रवृत्ति सिद्धान्त
 - 15.4.5 वुड का लागत-लाभ सिद्धान्त
- 15.5 इष्टतम मुद्रा क्षेत्र का सामान्य सिद्धान्त
- 15.6 इष्टतम मुद्रा क्षेत्र के लाभ
- 15.7 अभ्यास हेतु प्रश्न
- 15.8 सारांश
- 15.9 शब्दावली
- 15.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 15.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 15.12 उपयोगी/ सहायक पाठ्य सामग्री
- 15.13 निबंधात्मक प्रश्न

15.1 प्रस्तावना

इससे पहले की इकाईयों में आपने भुगतान संतुलन के असंतुलन को दूर करने में परम्परागत उपायों की भूमिका विशेष रूप से अवमूल्यन के भुगतान संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों और मौद्रिक उपायों के बारे में अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात् भुगतान संतुलन के असंतुलन को दूर करने में व्यय परिवर्तनकारी तथा व्यय बदलावकारी नीति के महत्व और उनके कार्यकरण को समझ गए होंगे। आप जान गए होंगे कि भुगतान संतुलन के असंतुलन को दूर करने में मौद्रिक उपागम की क्या भूमिका है।

पहले की इकाई में आपने देखा कि स्थिर विनिमय दरों के अंतर्गत भुगतान-संतुलन का असंतुलन मुद्रा या रिजों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह का परिणाम है इसलिए स्थिर विनिमय दरों की स्थिति में देश का अपनी मुद्रा-पूर्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। जबकि परिवर्तनशील विनिमय दरों के अंतर्गत भुगतान-संतुलन का असंतुलन बिना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रवाह के उत्पन्न होता है और समाप्त होता है। यह विनिमय दरों में स्वतः परिवर्तन के द्वारा तुरंत स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसलिए राष्ट्र का अपनी मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण रहता है। इस इकाई में भुगतान-संतुलन के असंतुलन को दूर करने के लिए इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र के सिद्धान्त का अध्ययन करेंगे। इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र का सिद्धान्त ‘परिवर्तनशील तथा स्थिर विनिमय दर’ बहस का ही एक विस्तार है।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र, इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र के विभिन्न सिद्धान्त और उसके महत्व के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

15.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप

- ✓ इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र के संबंध में जान पाएंगे।
- ✓ इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र के सिद्धान्तों को समझ सकेंगे।
- ✓ इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र के अंतरिक और बाह्य असंतुलन को दूर करने में उसके महत्त्व तथा कार्यकरण को समझ सकेंगे।

15.3 इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र (Optimum Currency Area)

भुगतान-संतुलन के असंतुलन को दूर करने के लिए इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र का सिद्धान्त कई अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया। मीड के अनुसार इष्टतम मुद्रा क्षेत्र विश्व के देशों के भुगतान-संतुलन के संतुलन की समस्या के लिए सबसे बेहतर दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत करता है। सबसे पहले मण्डल ने इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र का सिद्धान्त दिया। बाद में मेकिनन, पीटर केनेन, मैगनीफिको और वुड ने भी अपने सिद्धान्त दिए।

इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र का सिद्धान्त ‘परिवर्तनशील तथा स्थिर विनिमय दर’ बहस का ही एक विस्तार है। इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र का अर्थ है एक सांझा मुद्रा क्षेत्र या एक क्षेत्र जिसमें स्थिर विनिमय दरें क्रियाशील हों। दूसरे शब्दों में देशों का एक समूह एक सांझा मुद्रा-क्षेत्र (Common Currency Area) बना सकते हैं।

- (i) या तो सांझा मुद्रा के चलन के द्वारा, जो कि सभी सदस्य देशों के राष्ट्रीय मुद्राओं का स्थान लेगी या फिर
- (ii) सदस्य देशों के बीच स्थिर विनिमय दर प्रणाली लागू करके तथा विश्व के शेष देशों, जो कि उस सांझा मुद्रा क्षेत्र से बाहर हों, में परिवर्तनशील विनिमय दर लागू करके।

‘इष्टतम’ का अर्थ यहाँ अस्पष्ट है। मण्डल के अनुसार ‘इष्टतम’ का अर्थ है पूरे सांझा मुद्रा-क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार और कीमत को स्थिर करने की क्षमता। इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बरोजगारी तथा भुगतान

संतुलन का असंतुलन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और यह सब बिना सरकारी नीतियों के हस्तक्षेप के स्वतः होता है।

केनन और मैकिनन भी मुद्रा क्षेत्र के इष्टतम होने की यही परिभाषा देते हैं। ये अर्थशास्त्री एक क्षेत्र के अंतर्गत सांझा (कॉमन) मुद्रा लाने के लाभ या निहितार्थों पर विचार नहीं करते हैं, बल्कि वे सिर्फ उन स्थितियों या दशाओं की चर्चा करते हैं जिसके अंतर्गत एक मुद्रा क्षेत्र इष्टतम दशाओं को प्राप्त कर सके अर्थात् स्वतः ही बेरोजगारी तथा भुगतान संतुलन के घाटे को दूर कर सके। इस अर्थ में सांझा क्षेत्र, सांझा मुद्रा क्षेत्र की बजाए एक विनिमय दर संघ बन जाता है। बाद में मैगनीफिको, वुड और फ्लेमिंग आदि अर्थशास्त्रियों ने इष्टतम मुद्रा क्षेत्र का दूसरे अर्थ में प्रयोग किया। इन अर्थशास्त्रियों के सांझा मुद्रा क्षेत्र के सिद्धान्त मुद्रा क्षेत्र में आन्तरिक और बाह्य संतुलन लाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप पर निर्भर करते हैं। ये सिद्धान्त एक ऐसे वातावरण उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं जिसमें राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ विनिमय दर में परिवर्तन न होने की दशा में आन्तरिक तथा बाह्य संतुलन ला सके।

इस प्रकार इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र ऐसे देशों का समूह है जिन्होंने अपनी मुद्राओं को एक स्थिर विनिमय प्रणाली से स्थायी रूप से जोड़ दिया है। परन्तु सदस्य देशों के अतिरिक्त शेष विश्व से, इन देशों की मुद्राओं की दर परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली से जुड़ी होती है। एक सांझा मुद्रा क्षेत्र एक सांझा मुद्रा द्वारा जुड़ा हुआ होता है। जैसे यूरोपीय देशों का समूह (EC) 'यूरो' (EURO) से जुड़ा है।

15.4 विभिन्न सिद्धान्त

15.4.1 मण्डल का साधन गतिशीलता सिद्धान्त

सबसे पहले मण्डल ने साँझा मुद्रा क्षेत्र के सम्बन्ध में चर्चा शुरू की और इष्टतम साँझा मुद्रा क्षेत्र के लिए नियमों का निर्धारण किया। 1961 में मण्डल ने साधन गतिशीलता सिद्धान्त देते हुए साधन गतिशीलता के रूप में मुद्रा क्षेत्र की अनुकूलता (optimality) को परिभाषित करते हैं।

माना दो देश हैं, A और B दोनों ही देशों में प्रारम्भ में संतुलन है: आन्तरिक और बाहरी संतुलन दोनों। यानि दोनों ही देशों में पूर्ण रोजगार है और भुगतान-संतुलन भी साम्य में है।

यदि देश A के निर्यातों के लिए देश B में कमी हो जाती है और देश B आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाता है तो देश A में निर्यात उद्योगों में मंदी से बेरोजगारी उत्पन्न होगी और भुगतान संतुलन का घाटा होगा जबकि देश B में अधिशेष होगा और श्रम की कमी होगी, अति-पूर्णरोजगार की स्थिति होगी। इस प्रकार दोनों ही देशों में आन्तरिक और बाह्य असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा।

इस असंतुलन को दूर करने का दो तरीका हो सकता है –

- एक तरीका परिवर्तनशील विनिमय दरों का है। परिवर्तनशील दरों की स्थिति में देश A में मुद्रा का मूल्यहास होगा तथा देश B में मुद्रा का अधिमूल्यन होगा। जब तक कि देश A का भुगतान शेष का घाटा तथा देश B का अतिरेक समाप्त नहीं हो जाता है और साथ ही आन्तरिक संतुलन नहीं स्थापित हो जाता है। परन्तु इष्टतम मुद्रा क्षेत्र के अंतर्गत विनिमय दर में परिवर्तनों के माध्यम से संतुलन ले आने के तरीके को मण्डल नकार देते हैं।
- इस असंतुलन को दूर करने का दूसरा तरीका है उचित राजकोषीय और मौद्रिक नीति का प्रयोग। परन्तु इस तरीके में भुगतान-संतुलन के समायोजन का भार घरेलू कारकों पर होता है। देश A, भुगतान-संतुलन के घाटे को कम करने के लिए संकुचनकारी मौद्रिक और राजकोषीय नीति का

सहारा लेगा जिससे घरेलू बरोजगारी बढ़ेगी। जबकि देश B अपने अतिरिक्त को खत्म करने के लिए विस्तारकारी राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियों का सहारा लेगा जिससे घरेलू स्फीति बढ़ेगी। इस प्रकार अन्तरिक असंतुलन दोनों ही देशों में बढ़ता है। इसलिए यह रास्ता भी स्वीकार्य नहीं है। इसलिए मण्डल इन नीतियों के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप को अपने माडल में बिल्कुल स्थान नहीं देते है।

मण्डल के मुद्रा-क्षेत्र सिद्धान्त में न तो विनिमय दर की स्थिरता और न ही सरकारी हस्तक्षेप के लिए कोई जगह है। मण्डल के अनुसार दोनों देशों को एक मुद्रा-क्षेत्र बनाना चाहिए। और इस प्रकार दोनों ही देशों के उत्पादन के संसाधनों की स्वतन्त्र गतिशीलता सुनिश्चित कर देनी चाहिए, अर्थात् श्रम और पूँजी की स्वतंत्र गतिशीलता दोनों देशों के मध्य होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में दोनों ही देशों में आन्तरिक और बाह्य संतुलन स्वतः स्थापित हो जाता है।

पूर्ण संसाधन गतिशीलता की स्थिति में देश A में निर्यातों की कमी के कारण निर्यात-उद्योग से बेरोजगार हुए संसाधन रोजगार की तलाश में देश B में जायेंगे जहाँ आयात प्रतिस्थापन उद्योग में उन्हें काम मिलेगा और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि देश A की बेरोजगारी और देश B की श्रम की कमी समाप्त नहीं हो जाती है। इस प्रकार, दोनों ही देशों में सिर्फ स्वतंत्र साधन गतिशीलता के कारण आन्तरिक संतुलन स्वतः ही स्थापित हो जाता है।

इसी प्रकार, दोनों देशों में बाह्य संतुलन भी स्वतः ही स्थापित हो जाएगा। जब देश B में देश A के संसाधनों की मात्रा बढ़ेगी तो देश B में देश A के उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी। अर्थात् देश A के निर्यात तथा देश B के आयात बढ़ेंगे, जिससे देश A का भुगतान-संतुलन का घाटा तथा देश B का आधिक्य घटेगा और अंततः भुगतान-संतुलन साम्य में होगा।

इस प्रकार मण्डल के अनुसार इष्टतम मुद्रा क्षेत्र पूर्ण रोजगार और भुगतान संतुलन में संतुलन के साथ स्वतः ही आन्तरिक और बाह्य संतुलन स्थापित कर देता है, इसके लिए न तो मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत होती है और न ही परिवर्तनशील विनिमय दरों के नीति की। यह संतुलन सिर्फ सदस्य देशों के बीच संसाधनों की पूर्ण गतिशीलता के कारण स्वतः ही आता है।

मण्डल ने अपने सिद्धान्त का निर्माण इस मान्यता पर किया है कि प्रारम्भिक भुगतान संतुलन का असंतुलन विभिन्न देशों के बीच इकाई साधन लागतों की भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। यदि अधिक लागत वाले देशों से कम लागत वाले देशों की ओर सिर्फ साधनों की ही गतिशीलता हो तो लागत का यह अंतर और संतुलन समाप्त हो जाएगा। मण्डल इष्टतम मुद्रा क्षेत्र के अन्तर्गत साधन गतिशीलता को विनिमय दर समायोजन के स्थानापन्न के रूप में देखते हैं। साथ ही यह मुद्रा-क्षेत्र के सभी देशों में आन्तरिक तथा बाह्य संतुलन की गारण्टी देता है।

आलोचना:

परन्तु यदि बाह्य असंतुलन का कारण साधन कीमतों का अंतर न हो, तो मण्डल का सिद्धान्त बेकार साबित होता है। और यदि मान भी लिया जाय कि एक देश के निर्यातों की आधिक लागत और कीमत के कारण भुगतान-संतुलन में असंतुलन उत्पन्न होता है तो भी समस्या बनी रह सकती है क्योंकि श्रम और पूँजी देशों के बीच पूरी तरह से गतिशील नहीं होते हैं।

मण्डल के मॉडल में भुगतान-संतुलन समायोजन की प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा मजदूरी और कीमतों की नीचे की तरफ बेलोचशीलता है। विशेष रूप से श्रम-संघों के दबाव के कारण मजदूरी में कमी ले आ पाना संभव नहीं होता। इसलिए कीमतों में भी कमी संभव नहीं होता। इसलिए देश A से देश B में में श्रमिकों के पलायन के बावजूद देश A में मजदूरी में कमी नहीं हो सकती है और इसलिए दोनों देशों के बीच लागत अन्तर बराबर रह

सकता है। वास्तव में मण्डल ने मजदूरी तथा कीमतों के निर्धारण में स्वतंत्र बाजार के कार्यकरण की मान्यता ली है जो कि व्यवहार में पूरी तरह लागू नहीं हो पाता है।

मण्डल के सिद्धान्त के पूरी तरह से प्रभावशील होने के लिए यह भी आवश्यक है कि संसाधन गतिशीलता के साथ-साथ सभी उद्योगों में पूँजी-श्रम अनुपात भी समान हो जो कि व्यवहार में पाया जाना सम्भव नहीं है। देश B में आयात-प्रतिस्थापन उद्योगों में श्रमिकों की मांग देश A में बेरोजगार श्रमिकों की संख्या से कम हो सकती है, क्योंकि दोनों देशों में दोनों उद्योगों में उत्पादन-फलन भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। और फिर सभी श्रम इकाईयाँ योग्यता और क्षमता में समान नहीं होती है। इसलिए संसाधन गतिशीलता से भी लागत अन्तर समान नहीं हो सकता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि पूँजी का दो देशों के मध्य चलन मुख्यतः पूँजी के प्रतिफल के ऊपर निर्भर करता है न कि सिर्फ पूँजी का मांग पर। साथ ही निवेश के पूरे वातावरण तथा दूसरे देश में निवेश करने के जोखिम पर भी निर्भर करता है। इसलिए पूँजी का दो देशों के बीच चलन बहुत सुगम और अवरोध रहित नहीं है।

मण्डल का सिद्धान्त स्थैतिक सिद्धान्त है और समय-तत्त्व को अपने विश्लेषण में सम्मिलित नहीं करता है। वास्तव में एक देश से दूसरे देश में संसाधनों के चलन में काफी समय लगता है।

मण्डल मॉडल इस मान्यता पर आधारित है कि प्रारम्भ में दोनों ही देशों में पूर्ण रोजगार है और भुगतान-संतुलन में भी संतुलन है। परन्तु यदि दोनों ही देशों में श्रम और/या पूँजी बेरोजगार हो तो मण्डल का सिद्धान्त लागू नहीं हो पाता है।

अन्त में, यह भी कहा जा सकता है कि संसाधनों की गतिशीलता क्षेत्रीय आयोजन तथा नीति निर्माण का आधार होती है। इसलिए इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वस्तुतः संसाधनों की गत्यात्मक गतिशीलता में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए मण्डल का भी मानना था कि करेन्सी क्षेत्र अपने सदस्य देशों के मध्य बेरोजगार और स्फीति दोनों को नहीं रोक सकता है।

इस प्रकार, संसाधन गतिशीलता मुद्रा-क्षेत्र में आन्तरिक तथा बाह्य असंतुलनों के सभी-प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं है। मण्डल के सिद्धान्त के आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जिन देशों के मध्य संसाधन गतिशीलता आसान और सम्भव हो वे देश मुद्रा-क्षेत्र के निर्माण में सबसे उचित स्थिति में होंगे। इस प्रकार मण्डल एक मुद्रा क्षेत्र की अनुकूलता के लिए संसाधन गतिशीलता को एक मापदण्ड के रूप में स्थापित करते हैं। बाद के लेखकों ने मुद्रा-क्षेत्र की अनुकूलता के लिए अलग मापदण्ड निर्धारित किए।

15.4.2 मैककिनन का खुली अर्थव्यवस्था सिद्धान्त

मैककिनन इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र के निर्माण में अत्यधिक खुली अर्थव्यवस्थाओं और आंतरिक कीमत स्थिरता को अधिक महत्व देते हैं। मैककिनन की मुद्रा क्षेत्र की अनुकूलता की दशाएँ मण्डल के समान ही हैं, जो कि इस क्षेत्र के आन्तरिक और बाह्य संतुलन प्राप्त कर लेने की इसकी क्षमता पर निर्भर करती है। मण्डल के विपरीत, मैककिनन मुद्रा क्षेत्र के उद्देश्य के रूप में भुगतान संतुलन के साम्य के स्थान पर आन्तरिक कीमत स्थिरता पर अधिक बल देते हैं। मैककिनन के अनुसार बंद अर्थव्यवस्थाओं की जगह खुली अर्थव्यवस्थाएँ मुद्रा-क्षेत्र के निर्माण के लिए अधिक उपयुक्त हैं। मैककिनन के सिद्धान्त में व्यापाररत वस्तुओं का गैर-व्यापाररत वस्तुओं से अनुपात जितना ही अधिक होगा अथवा विदेशी व्यापार से सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अनुपात जितना ही अधिक होगा, मुद्रा-क्षेत्र का निर्माण उतना ही अधिक लाभकारी होगा।

मैककिनन के सिद्धान्त के मुख्य तर्क निम्नलिखित हैं

1. विदेशी व्यापार से सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अनुपात जितना ही अधिक होगा, घरेलू कीमत स्तर पर

विनिमय दर परिवर्तन का प्रभाव उतना ही अधिक होगा।

2. घरेलू कीमत स्थिरता ले आना मुख्य उद्देश्य है क्योंकि कीमत उच्चावचन से राष्ट्रीय आय, व्यापार तथा विशिष्टीकरण पर गम्भीर नकरात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं।
3. एक खुली अर्थव्यवस्था को आन्तरिक तथा बाह्य संतुलन हासिल करने के लिए, मौद्रिक और राजकोषीय नीति परिवर्तनों पर निर्भर रहना चाहिए, न कि विनिमय दरों में परिवर्तनों पर। जबकि एक बंद अर्थव्यवस्था में आन्तरिक तथा बाह्य संतुलन के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों की अपेक्षा विनिमय दर परिवर्तनों पर निर्भर करना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि मुद्रा-क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसके सदस्य देशों के मध्य विनिमय दर की स्थिरता है। इसलिए एक खुली अर्थव्यवस्था जो कि बाह्य संतुलन को हासिल करने के लिए विनिमय दर समायोजन पर निर्भर नहीं करती है। वह मुद्रा-क्षेत्र के निर्माण में सर्वाधिक अर्थ और तार्किक सदस्य होती है। एक बंद अर्थव्यवस्था में बाह्य संतुलन प्राप्त करने के लिए विनिमय दरों में परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। इसलिए वह मुद्रा-क्षेत्र के निर्माण में उचित उम्मीदवार नहीं होती है। वास्तव में मैककिनन का इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र का सिद्धान्त इस विश्वास पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था जितनी ही खुली होगी, बाह्य असंतुलनों को दूर करने में मौद्रिक और राजकोषीय नीति की प्रभाविता उतनी ही अधिक होगी और बाह्य संतुलन बनाए रखने के लिए विनिमय दरों में परिवर्तन, कम वांछनीय या उपयोगी होगा।

आलोचना

यदि गैर सदस्य देशों में स्फीति है तो ऐसी स्थिति में उँची आयात कीमतों के कारण मुद्रा-क्षेत्र में आन्तरिक कीमत स्थिरता को बनाए रखना काफी मुश्किल भरा होगा। आयातित मुद्रा-स्फीति से इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र में कीमत स्थिरता भंग हो सकती है। परन्तु ऐसी स्थिति में मुद्रा-क्षेत्र के सदस्य देश परिवर्तनशील विनिमय दरों की नीति अपना सकते हैं और इस प्रकार विश्व कीमतों में परिवर्तनों से अपनी आन्तरिक स्थिरता की रक्षा कर सकने में सफल हो सकते हैं।

15.4.3 केनन का वस्तु विविधीकरण सिद्धान्तः

केनन के अनुसार, इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उम्मीदवार वे अर्थव्यवस्थाएँ हैं। जोकि कम खुली हैं और सामान्यतया अधिक विविधीकृत अर्थव्यवस्थाएँ हैं। इस प्रकार केनन का इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र के लिए मापदण्ड मैककिनन के ठीक विपरीत है, जो कि यह मानता है कि जो अर्थव्यवस्थाएँ अधिक खुली और कम विविधीकृत हैं। वे मुद्रा क्षेत्र के निर्माण में अधिक उपयुक्त हैं।

केनन कहते हैं कि बंद या कम खुली अर्थव्यवस्था सामान्यतया अत्यधिक विविधीकृत अर्थव्यवस्था होती है और बाह्य उथल-पुथल से भी अधिक स्वतंत्र होती है। बाहरी परिवर्तनो या उथल-पुथल का इसके घरेलू कीमत और आय स्तर पर कम प्रभाव पड़ता है। इस तर्क का आधार यह है कि यदि अर्थव्यवस्था विविधीकृत है तो एक उत्पाद की निर्यात मांग में कमी किसी दूसरे उत्पाद के निर्यात मांग की वृद्धि से समायोजित हो सकती है और इस प्रकार निर्यात आय में या घरेलू रोजगार में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं आएगी। ऐसा देश बेरोजगारी और भुगतान-संतुलन के घाटे की गम्भीर समस्याओं से प्रभावित नहीं होगा और इस प्रकार यह देश स्थिर विनिमय दरों की नीति लागू कर सकने की स्थिति में होगा, जो कि मुद्रा-क्षेत्र निर्माण के लिए आवश्यक है।

यदि अर्थव्यवस्थाएँ अधिक खुली हैं तो वे सामान्यतया कम विविधीकृत होंगी और उपेक्षाकृत कम वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में अधिक दक्ष होंगी। ऐसी अर्थव्यवस्थाएँ बाह्य उथल-पुथल के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होंगी। इसके निर्यात उत्पाद की मांग में कमी से घरेलू रोजगार तथा आय में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है और भुगतान-संतुलन का घाटा भी बढ़ सकता है। अधिकांश अल्पविकसित देशो की यही स्थिति है। इस प्रकार

कम विविधीकृत अर्थव्यवस्थाओं में और अधिक खुलेपन की प्रवृत्ति पायी जाती है और वे विश्व बाजार में अपने उत्पादों की मांग और कीमतों में परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। उनके पास स्वतः समायोजन वाला तंत्र विकसित नहीं हो पाता है जैसा कि अधिक विविधीकृत और कम खुली अर्थव्यवस्थाओं के पास होता है। इसलिए कम विविधीकृत और अधिक खुली अर्थव्यवस्थाओं को विनिमय दर परिवर्तनशीलता की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार केनन के अनुसार, चूँकि कम खुली और अधिक विविधीकृत अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी उथल-पुथल का सामना करने के लिए एक स्वतः समायोजन वाला तंत्र विकसित हो जाता है। इसलिए ये अर्थव्यवस्थाएँ एक सांझा मुद्रा क्षेत्र की स्थापना के लिए अनुकूलता के मापदण्ड को पूरा करती हैं।

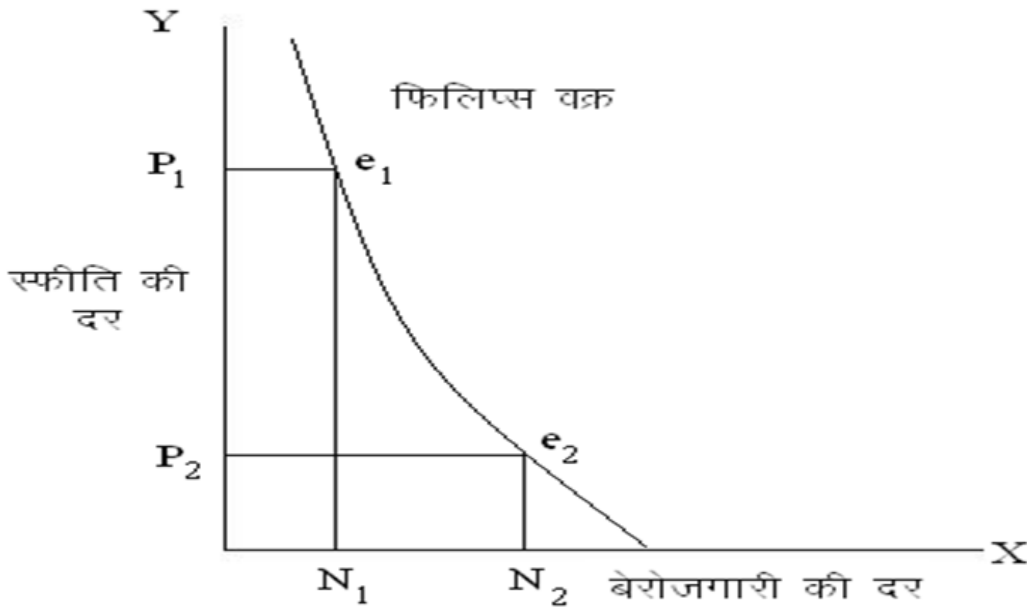
आलोचना

आलोचकों का कहना है कि विदेशी उथल-पुथल हमेशा स्वतः ही समायोजित नहीं हो जाते हैं। प्रायः निर्यात माँग में परिवर्तन एक ही दिशा में होते हैं। इसलिए यदि विदेशी उथल-पुथल हो तो एक विविधीकृत अर्थव्यवस्था भी बेरोजगारी तथा भुगतान-संतुलन के घाटे से नहीं बच सकती है,

15.4.4 मैगनीफिकों का स्फीति की प्रवृत्ति सिद्धान्त

मैगनीफिकों का कहना है कि मुद्रा-क्षेत्र का निर्माण उन देशों को करना चाहिए जहाँ स्फीति की प्रवृत्तियाँ समान हों। मैगनीफिकों का सिद्धान्त फिलिप्स वक्र पर आधारित है। जोकि स्फीति और बेरोजगारी के बीच विनिमय (trade-off) को प्रदर्शित करता है। विभिन्न देशों में रोजगार के एक निश्चित स्तर पर स्फीति की दरें भी भिन्न होंगी। क्योंकि **फिलिप्स वक्र** पर विनिमय बिन्दु अलग-अलग देशों में अलग-अलग होगा।

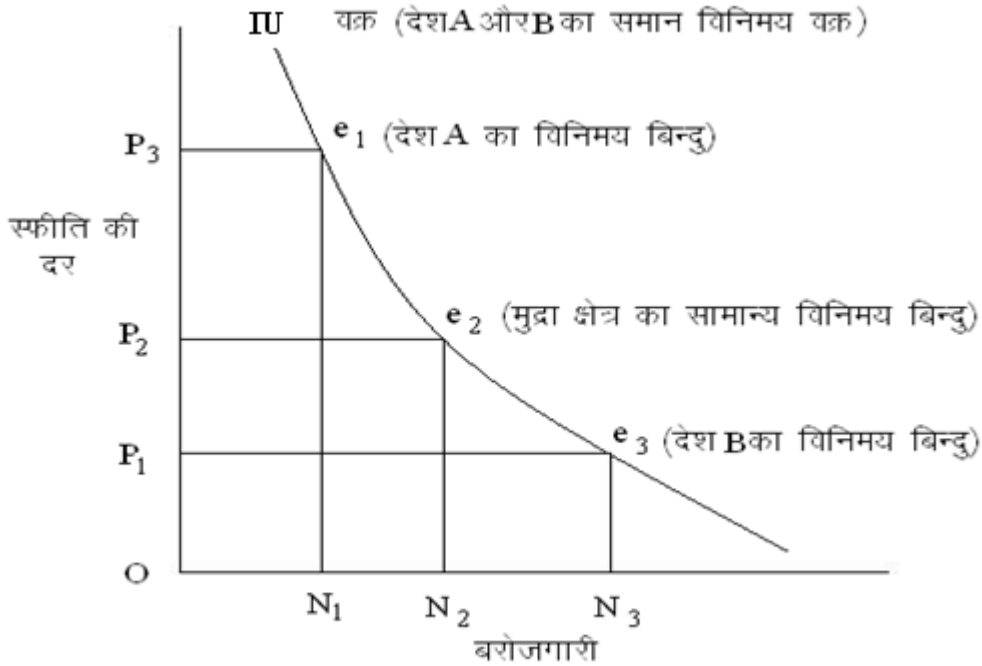
फिलिप्स वक्र यह इंगित करता है कि पूर्ण-रोजगार और कीमत स्थिरता एक साथ संभव नहीं है। इस प्रकार यह आन्तरिक स्थिरता की अवधारणा की वैधता को ही चुनौती देता है। चित्र 15.1 में X-अक्ष पर बेरोजगारी की दर तथा Y-अक्ष पर स्फीति की दर है। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की दर तथा स्फीति की दर के बीच विनिमय को दर्शाता है। जब स्फीति दर OP_1 है तो बेरोजगारी ON_1 है और यदि स्फीति OP_2 है तो बेरोजगारी दर ON_2 हो जा रही है। स्फीति और बेरोजगारी में विनिमय प्रत्येक देश के लिए अपनी नीति निर्धारित करने का मौका देता है।



चित्र 15.1

इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र का निर्माण इसके सदस्य द्वारा स्फीति और बेरोजगारी के बीच समान दरों पर समझौते पर निर्भर करता है। मैगनीफिको का कहना है कि यदि विभिन्न देशों के मध्य स्फीति की राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ (अथवा वांछित विनिमय बिन्दु) भिन्न होने पर, ऐसे देशों के बीच मुद्रा क्षेत्र का निर्माण व्यावहारिक नहीं होगा। स्फीति दरों की भिन्नता की स्थिति में भुगतान-संतुलन की समस्याएँ उत्पन्न होंगी जिसके लिए विनिमय दरों में समायोजन की आवश्यकता होगी जो की मुद्रा क्षेत्र के सिधांत के विपरीत है क्योंकि मुद्रा-क्षेत्र के अन्तर्गत विनिमय दरें स्थिर होनी चाहिए।

माना दो देश A और B हैं, जिनके स्फीति बेरोजगारी विनिमय दर वक्र एक समान हैं। चित्र 15.2 में इसे IU वक्र से दर्शाया गया है। बिन्दु e_1 देश A तथा बिन्दु e_3 देश B की स्फीति और बेरोजगारी के बीच विनिमय की स्थिति को दर्शाता है। यदि देश A और देश B मुद्रा क्षेत्र का निर्माण करते हैं तो देश A में भुगतान-संतुलन का घाटा होगा। देश A को इस घाटे को समाप्त करने के लिए विनिमय दर के समायोजन की आवश्यकता पड़ेगी।



चित्र 15.2

1. देश A के लिए एक विकल्प यह है कि वह मुद्रा-क्षेत्र के गठन के बाद देश B के विनिमय बिन्दु e_3 को स्वीकार कर ले। इसके लिए देश A को देश के अन्दर संकुचनकारी मौद्रिक और राजकोषीय नीति लागू करनी होगी जिससे स्फीति दर OP_3 से कम होकर OP_1 स्तर पर आ सके और बेरोजगारी बढ़कर ON_1 से ON_3 स्तर पर पहुंच जाए।
2. एक दूसरा विकल्प यह भी है कि देश B, देश A के विनिमय बिन्दु e_1 को स्वीकार कर लें और स्फीतिकारी मौद्रिक और राजकोषीय कीमतों के माध्यम से स्फीति दर को बढ़ाकर OP_1 से OP_3 तथा बेरोजगारी दर को कम करके ON_3 से ON_1 कर दे।
3. एक अन्य विकल्प यह है कि दोनों देश आपस में समझौता करके एक स्वीकार्य स्फीति दर को मान लें। चित्र 15.2 में यदि दोनों देश मुद्रा क्षेत्र के गठन के पश्चात् OP_2 स्फीति दर और ON_2 बेरोजगारी स्तर को मुद्रा-क्षेत्र के लिए स्वीकार कर लेते हैं। इस स्थिति में देश A के रोजगार में N_1N_2 की कमी आती है। जबकि देश B में बेरोजगारी N_2N_3 मात्रा में कम हो जाती है। परन्तु मुद्रा-क्षेत्र में सम्पूर्ण रोजगार समान बना रहता है,

क्योंकि

$$ON_1 + ON_3 = 2ON_2$$

जबकि परन्तु मुद्रा क्षेत्र में स्फीति की औसत दर पहले की अपेक्षा कम हो गयी। क्योंकि

$$(OP_1 + OP_3) > 2OP_2$$

इस प्रकार, चित्र से स्पष्ट है कि मुद्रा-क्षेत्र के निर्माण के पश्चात् विनिमय में सुधार हुआ है। यह अभी भी सम्भव है कि देश A स्फीति में कमी करे जिससे कि रोजगार में आयी कमी की क्षतिपूर्ति कर सके या देश B रोजगार में वृद्धि करें जिससे कि वह कीमत वृद्धि के कारण हुए कल्याण में कमी की क्षतिपूर्ति कर सके। परन्तु मुद्रा-क्षेत्र के निर्माण के लिए जो सबसे आवश्यक बात है वह यह कि देशों की बीच विनिमय की समानता के साथ-साथ दिए हुए विनिमय वक्र पर एक समान अधिमान बिन्दु भी हो।

अतः जिन देशों में स्फीति की राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ एक समान हों वे देश मुद्रा-क्षेत्र के गठन के लिए उपयुक्त होंगे क्योंकि वे आसानी से एक सांझी स्फीति की दर और रोजगार स्तर के लिए आपस में समझौता कर सकते हैं। इसीलिए मैगनीफिको मुद्रा-क्षेत्र में अनुकूलता के लिए समान स्फीति प्रवृत्ति पर बल देते हैं।

परन्तु आलाचकों का कहना है कि इस प्रकार का विचार अति-सरलीकृत है और ठीक नहीं है और यह इस बात को सुनिश्चित नहीं करता है कि भुगतान-संतुलन की समस्याएं हल हो जाएगी। वास्तव में सांझा क्षेत्र के भी देशों के बीच स्फीति तथा बेरोजगारी की एक समान (सांझा) दरों का समझौता संभव नहीं हो पाता है। मण्डल का भी मानना है कि एक मुद्रा-क्षेत्र अपने सदस्यों के बीच स्फीति तथा बेरोजगारी दोनों की रक्षा नहीं कर सकता है। और फिर मैगनीफिको का सिद्धान्त फिलिप्स वक्र पर आधारित है जो कि स्वयं ही आजकल बहुत स्वीकार्य नहीं है। वर्तमान में अधिकांश देशों में अपस्फीति की स्थिति है अर्थात् स्फीति और बेरोजगारी दोनों एक साथ है और बढ़ रहे हैं और फिलिप्स वक्र द्वारा सुझाए गए स्फीति और बेरोजगारी में उस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता है।

15.4.5 वुड का लागत-लाभ सिद्धान्तः

इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र के उपरोक्त सिद्धान्तों की एक कमी यह है कि वे मुद्रा-क्षेत्र के लाभों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं। वुड का सिद्धान्त इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र की व्यवहारिकता या उपादेयता का विचार उसके लाभों के आधार पर करता है और इस अर्थ में इसे अन्य सिद्धान्तों पर एक सुधार माना जा सकता है।

वुड मुद्रा-क्षेत्र के उपादेयता के प्रश्न को एक अनुकूलता समस्या के रूप में नहीं देखते हैं बल्कि लागत-लाभ के आधार पर उस पर विचार करते हैं। उनके अनुसार एक मुद्रा-क्षेत्र का गठन तभी किया जाना चाहिए यदि उसके लाभ उसकी लागतों की अपेक्षा अधिक हों। मुद्रा-क्षेत्र के अनेक संभावित लाभ हैं। जैसे- बैंकिंग तथा विदेशी विनिमय लेन-देन या फिर अन्य लेन-देनों में संसाधनों की बचत से होने वाला लाभ; मुद्रा-क्षेत्र में सांझे संसाधनों के पुर्नआवंटन से होने वाला लाभ; व्यापार में वृद्धि तथा अनिश्चितता में कमी के कारण होने वाला लाभ और मौद्रिक प्रणाली के बेहतर कार्यकरण के कारण होने वाला लाभ। जबकि मुद्रा-क्षेत्र की संभाव्य लागत है- भुगतान संतुलनों के असंतुलन को ठीक करने के लिए विनिमय दरों में परिवर्तन की अयोग्यता।

वुड मुद्रा-क्षेत्र का कोई ठोस सिद्धान्त नहीं देते हैं बल्कि मुद्रा-क्षेत्र के निर्माण से पहले लागतों और लाभों के अध्ययन का सुझाव देते हैं

15.4.6 इष्टतम मुद्रा क्षेत्र का सामान्य सिद्धान्त

इष्टतम मुद्रा क्षेत्र का सामान्य सिद्धान्त मुण्डेल के साधन गतिशीलता सिद्धान्त तथा वुड के लागत-लाभ सिद्धान्त पर आधारित है। इस सिद्धान्त के अनुसार इष्टतम मुद्रा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है। जिसमें सदस्य देशों की मुद्राएँ एक दुसरे के साथ स्थिर दर जुड़ी रहती हैं तथा संसाधन मुद्रा क्षेत्र के भीतर पूरी तरह से गतिशील होते हैं। सदस्य

देशों की मुद्राएं शेष विश्व के साथ लचीली विनिमय दर प्रणाली द्वारा जुड़ी रह सकती है। इष्टतम मुद्रा क्षेत्र की सदस्यता लागत-लाभ के आधार पर हो सकती है। इष्टतम मुद्रा क्षेत्र में सम्मिलित होने वाला देश गैर सदस्यीय देशों के साथ लचीली विनिमय दर और सदस्य देशों के साथ स्थिर विनिमय दर के अन्तर्गत अधिक मौद्रिक कुशलता का लाभ प्राप्त करता है। श्रम तथा पूंजी जैसे साधनों की सदस्य देशों की बीच मुक्त गति से मौद्रिक कुशलता का लाभ स्वतः ही अधिक हो जाता है।

इष्टतम मुद्रा क्षेत्र के भीतर श्रम तथा पूंजी की स्वतंत्र गतिशीलता के कारण कम घरेलू स्फीति तथा आर्थिक कीमत स्थिरता की संभावनाएं अधिक होती है। परन्तु इष्टतम मुद्रा क्षेत्र में सम्मिलित होने वाले देश को इसकी सदस्यता की लागतें भी वहन करनी पड़ती है। लागतों के उत्पन्न होने का कारण यह है कि देश उत्पादन तथा रोजगार स्थिरता के लिए अपनी मौद्रिक नीति तथा विनिमय दर में परिवर्तन की क्षमता को खो देता है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत देश का अपनी मुद्रा-पूर्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता है; घरेलू तथा विदेशी वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन करना सम्भव नहीं होता। ऐसे में यदि निर्यात योग्य वस्तुओं की मांग में गिरावट आएगी तो यह उत्पादन तथा रोजगार के सन्दर्भ में आर्थिक अस्थिरता को जन्म देगी। यह देश की आर्थिक स्थिरता में हानि है जो वस्तु की कीमत तथा मजदूरी में कमी के साथ मन्दी की ओर ले जाती है। यदि देश की आर्थिक संघ के साथ इष्टतम मुद्रा क्षेत्र मजबूत है तो मन्दी का काल छोटा होगा तथा अर्थव्यवस्थाओं में समायोजन की कीमत कम चुकानी पड़ेगी, आर्थिक स्थिरता में हानि होगी।

इसका कारण यह है कि

- यदि देश मुद्रा क्षेत्र के साथ मजबूती से जुड़ा है तो इसकी निर्यात योग्य वस्तुओं की कीमतों में मामूली गिरावट से आर्थिक संघ में उसके वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। इससे देश में उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि होगी,
- यदि संघ क्षेत्र के बीच श्रम तथा पूंजी मुक्त गतिशील रहते हैं तो बेरोजगार श्रमिक काम की तलाश में दूसरे देशों में जा सकते हैं तथा पूंजी अन्य देशों में आर्थिक लाभदायक योजनाओं में लगाई जा सकती है।

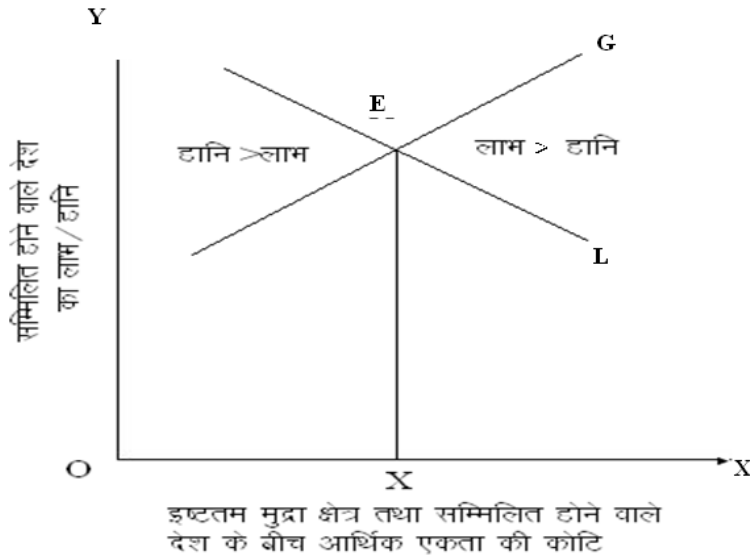
अतः इष्टतम मुद्रा क्षेत्र में सम्मिलित देशों के बीच मजबूत आर्थिक एकता विनिमय दर के कारण आर्थिक स्थिरता की हानि कम कर देती है, जो कि मांग, उत्पादन तथा रोजगार में गिरावट के कारण उत्पन्न होती है।

चित्र 15.3 में X- अक्ष मुद्रा क्षेत्र में सम्मिलित होने वाले देश तथा इष्टतम मुद्रा क्षेत्र के बीच आर्थिक संघ या एकता की कोटि (degree of economic union between the joining country and optimum currency area) को मापता है। Y- अक्ष मुद्रा क्षेत्र में सम्मिलित होने वाले देश के मौद्रिक कुशलता के लाभ तथा आर्थिक स्थिरता की हानि को मापता है। मान लिया की एक देश स्थिर विनिमय दर के साथ इष्टतम मुद्रा क्षेत्र में सम्मिलित होता है। इस देश के मौद्रिक कुशलता लाभ तथा आर्थिक संघ की कोटि के बीच संबंध की स्थिति को वक्र G द्वारा दिखाया गया है।

वक्र की धनात्मक ढलान यह प्रदर्शित करती है कि जैसे-जैसे आर्थिक संघ की कोटि बढ़ती जाती है अर्थात् देश का क्षेत्र के साथ आर्थिक एकीकरण मजबूत होता है देश का मौद्रिक कुशलता लाभ बढ़ता है। वक्र L इष्टतम मुद्रा क्षेत्र में सम्मिलित देश के आर्थिक स्थिरता की हानि को प्रदर्शित करता है। वक्र की नीचे की ओर ढलान यह प्रदर्शित करती है कि जैसे-जैसे आर्थिक संघ की कोटि बढ़ती जाती है, देश की आर्थिक स्थिरता की हानि बढ़ती है।

चित्र में वक्र G तथा L एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं। बिन्दु E के अनुरूप आर्थिक संघ की कोटि X है अर्थात् इस स्थिति में मुद्रा क्षेत्र में सम्मिलित देश का मौद्रिक कुशलता लाभ आर्थिक स्थिरता की हानि के

बराबर है। यदि आर्थिक संघ की कोटि का स्तर X के बाईं ओर है तो देश संघ में शामिल होने के बाद कीमत, उत्पादन तथा रोजगार अस्थिरता से पीड़ित होगा।



चित्र 15.3

अन्य शब्दों में, आर्थिक स्थिरता हानि मौद्रिक कुशलता लाभ से अधिक होगी। इसके विपरीत, X के दाईं ओर आर्थिक संघ में शामिल होना लाभकारी होगा, अर्थात् मौद्रिक कुशलता लाभ आर्थिक स्थिरता हानि से अधिक है। अन्य शब्दों में, यदि देश व्यापार तथा साधन गतिशीलता द्वारा संघ से मजबूती से जुड़ा है तो कीमत स्थिरता तथा उत्पादन व रोजगार के उच्च स्तर के साथ आर्थिक संघ में सम्मिलित होने का मौद्रिक लाभ इसकी लागत से अधिक होगा।

15.5 इष्टतम मुद्रा क्षेत्र के लाभ

साझा मुद्रा क्षेत्र एक विस्तृत बाजार का निर्माण करता है जिससे सदस्य देशों में आर्थिक गतिविधियों जैसे निवेश, रोजगार आदि में वृद्धि होती है। यह पैमाने की बचतों से लाभ को सुनिश्चित करता है। इष्टतम मुद्रा क्षेत्र लचीली विनिमय दरों के कारण उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता को समाप्त करता है।

इष्टतम मुद्रा क्षेत्र से वस्तु विशिष्टीकरण होता है। व्यापार से लाभ में वृद्धि तथा निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। मुद्रा क्षेत्र के निर्माण से सदस्य देशों के बीच कीमत स्थिरता उत्पन्न होती है। इसमें कुशल मौद्रिक प्रबन्धन प्राप्त होता है जिससे सदस्य देशों के बीच स्फीति एवं मन्दी की दशा समाप्त होने में मदद मिलती है। परन्तु इष्टतम मुद्रा क्षेत्र में यदि संघ द्वारा अपने सदस्यों के आर्थिक हितों का समान रूप से ध्यान नहीं रखा जाता है तो मुद्रा क्षेत्र के असफल रहने अथवा इसके टूटने की पूरी सम्भावना रहती है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) इष्टतम मुद्रा क्षेत्र का एक सफल उदाहरण है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की एक साझी मुद्रा 1 जनवरी, 1990 को अस्तित्व में आई। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों द्वारा स्थापित साझा बाजार व्यवस्था को यूरोपीय साझा बाजार (ECM) कहा जाता है। वर्तमान में ECM के कुल सदस्यों की संख्या 15 है। यद्यपि खाते की मुद्रा में यूरो का प्रयोग 1 जनवरी, 1990 से आरम्भ हो चुका था, परन्तु सौदों में नकद यूरो का प्रयोग 1 जनवरी, 2002 से किया जा रहा है।

15.6 अभ्यास हेतु प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. मण्डल के इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र सिद्धान्त का उल्लेख कीजिए।
2. मैककिनन का खुली अर्थव्यवस्था सिद्धान्त क्या है?
3. केनेन का वस्तु विविधीकरण सिद्धान्त क्या है?
4. मुद्रा क्षेत्र के इष्टतम होने की दशाओं का वर्णन कीजिये।
5. मैगनीफिको के इष्टतम मुद्रा क्षेत्र के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
6. वुड का लागत-लाभ सिद्धान्त क्या है?
7. इष्टतम मुद्रा क्षेत्र के लाभ बताइए।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. सबसे पहले किसने इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र का सिद्धान्त दिया ?
(क) मण्डल (ख) मैकिनन, (ग) वुड (घ) पीटर केनेन
2. किस अर्थशास्त्री का नाम इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र सिद्धान्त से नहीं जुड़ा है ?
(क) मैगनीफिको (ख) मैकिनन, (ग) मीड (घ) केन्स
3. देशों का एक समूह एक सांझा मुद्रा -क्षेत्र (Common Currency Area) बना सकते हैं
(क) सांझा मुद्रा के चलन के द्वारा
(ख) सदस्य देशों के बीच स्थिर विनिमय दर प्रणाली लागू करके
(ग) उपरोक्त दोनों
(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
4. मण्डल के अनुसार 'इष्टतम' का अर्थ है
(क) जिसमें बरोजगारी तथा भुगतान-संतुलन का असंतुलन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है।
(ख) सांझा मुद्रा-क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार और कीमत को स्थिर करने की क्षमता।
(ग) एक क्षेत्र जिसमें स्थिर विनिमय दरें क्रियाशील हों।
(घ) उपरोक्त सभी
5. किन अर्थशास्त्रियों के सांझा मुद्रा क्षेत्र के सिद्धान्त मुद्रा क्षेत्र में आन्तरिक और बाह्य संतुलन लाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप पर निर्भर करते हैं
(क) मैगनीफिको – मैकिनन (ख) मैगनीफिको- वुड
(ग) मण्डल- वुड (घ) मण्डल- केनेन
6. किस अर्थशास्त्री का सिद्धान्त ऐसा वातावरण उत्पन्न करने की कोशिश करता है जिसमें राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ विनिमय दर में परिवर्तन न होने की दशा में आन्तरिक तथा बाह्य संतुलन ला सके
(क) मैकिनन (ख) मैगनीफिको
(ग) मण्डल (घ) केनेन
7. किस अर्थशास्त्री ने साधन गतिशीलता के रूप में मुद्रा क्षेत्र की अनुकूलता को परिभाषित किया।
(क) मैकिनन (ख) मैगनीफिको
(ग) मण्डल (घ) केनेन

8. प्रारम्भिक भुगतान-संतुलन का असंतुलन विभिन्न देशों के बीच इकाई साधन लागतों की भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। किस अर्थशास्त्री ने अपने सिद्धान्त का निर्माण इस मान्यता पर किया के
- (क) मण्डल (ख) मैगनीफिको
(ग) मैककिनन (घ) केनेन
9. किस अर्थशास्त्री के अनुसार बंद अर्थव्यवस्थाओं की जगह खुली अर्थव्यवस्थाएँ मुद्रा-क्षेत्र के निर्माण के लिए अधिक उपयुक्त है।
- (क) मण्डल (ख) मैगनीफिको
(ग) मैककिनन (घ) केनेन
10. किस अर्थशास्त्री के अनुसार वे अर्थव्यवस्थाएँ हैं जो कि कम खुली हैं और सामान्यतया अधिक विविधीकृत अर्थव्यवस्थाएँ है मुद्रा-क्षेत्र के निर्माण के लिए अधिक उपयुक्त है।
- (क) मण्डल (ख) मैगनीफिको
(ग) मैककिनन (घ) केनेन
11. किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा-क्षेत्र के निर्माण से पहले लागतों और लाभों के अध्ययन का सुझाव दिया
- (क) मण्डल (ख) मैककिनन
(ग) वुड (घ) पीटर केनेन
12. किस अर्थशास्त्री का सिद्धान्त का सिद्धान्त फिलिप्स वक्र पर आधारित है।
- (क) मैककिनन (ख) मैगनीफिको
(ग) मण्डल (घ) केनेन
13. मैगनीफिको के अनुसार मूद्रा-क्षेत्र के निर्माण के लिए जो सबसे आवश्यक बात है वह यह कि
- (क) स्फीति और बेरोजगारी के बीच विनिमय विनिमय की समानता
(ख) विनिमय वक्र पर एक समान अधिमान बिन्दु
(ग) उपरोक्त दोनों
(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
14. किस अर्थशास्त्री के अनुसार जिन देशों में स्फीति की राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ एक समान हों वे देश मुद्रा-क्षेत्र के गठन के लिए उपयुक्त होंगे
- (क) मैगनीफिको (ख) मण्डल
(ग) मैककिनन (घ) केनेन
15. इष्टतम मुद्रा क्षेत्र मजबूत है तो
- (क) आर्थिक कीमत स्थिरता की संभावनाएं अधिक होती है।
(ख) मन्दी का काल छोटा होगा
(ग) मौद्रिक कुशलता लाभ आर्थिक स्थिरता हानि से अधिक होगा
(घ) उपरोक्त सभी

सत्य व असत्य

1. इष्टतम मुद्रा क्षेत्र का सिद्धान्त 'परिवर्तनशील तथा स्थिर विनिमय दर' बहस का ही एक विस्तार है।
2. इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र का अर्थ है एक सांझा क्षेत्र जिसमें 'परिवर्तनशील विनिमय दरें' क्रियाशील हों।

3. इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बरोजगारी तथा भुगतान-संतुलन का असंतुलन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है।
4. केनेन और मैकिनन उन स्थितियों या दशाओं की चर्चा करते हैं जिसके अंतर्गत एक मुद्रा क्षेत्र इष्टतम दशाओं को प्राप्त कर सके।
5. साझा मुद्रा क्षेत्र के सदस्य देशों की मुद्राएं शेष विश्व की मुद्राओं से स्थिर विनिमय प्रणाली से जुड़ी होती है।
6. मण्डल साधन गतिशीलता के रूप में मुद्रा क्षेत्र की अनुकूलता को परिभाषित करते हैं।
7. मण्डल सरकारी हस्तक्षेप को अपने माडल में महत्वपूर्ण स्थान देते है।
8. मैकिनन इष्टतम मुद्रा क्षेत्र के निर्माण में अत्यधिक बंद अर्थव्यवस्थाओं और आंतरिक कीमत स्थिरता को अधिक महत्व देते हैं।
9. एक बंद अर्थव्यवस्था में बाह्य संतुलन प्राप्त करने के लिए विनिमय दरों में परिवर्तनों की आवश्यकता होती है।
10. यदि अर्थव्यवस्थाएं अधिक खुली हैं तो वे सामान्यतया कम विविधीकृत होंगी।
11. साझा मुद्रा क्षेत्र पैमाने की बचतों से लाभ को सुनिश्चित करता है।
12. इष्टतम मुद्रा क्षेत्र लचीली विनिमय दरों के कारण उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता को बढ़ा देता है।
13. मैगनीफिको का सिद्धान्त फिलिप्स वक्र पर आधारित है।
14. फिलिप्स वक्र स्फीति और बेरोजगारी के बीच विनिमय को प्रदर्शित करता है।
15. मैगनीफिको मुद्रा-क्षेत्र में अनुकूलता के लिए असमान स्फीति प्रवृत्ति पर बल देते
16. इष्टतम मुद्रा क्षेत्र में सम्मिलित देशों के बीच मजबूत आर्थिक एकता विनिमय दर के कारण आर्थिक स्थिरता की हानि कम कर देती है।
17. यदि देश की आर्थिक संघ के साथ इष्टतम मुद्रा क्षेत्र मजबूत है तो मन्दी का काल छोटा होगा।
18. स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत घरेलू तथा विदेशी वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन करना सम्भव होता।
19. इष्टतम मुद्रा क्षेत्र में सम्मिलित देश मौद्रिक नीति तथा विनिमय दर में परिवर्तन की क्षमता को खो देता है।

15.7 सारांश

इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र का सिद्धान्त “परिवर्तनशील तथा स्थिर विनिमय दर बहस का ही एक विस्तार है। इष्टतम मुद्रा क्षेत्र का अर्थ है एक साझा मुद्रा क्षेत्र या एक क्षेत्र जिसमें स्थिर विनिमय दरें क्रियाशील हों। भुगतान-संतुलन के असंतुलन को दूर करने के लिए इष्टतम मुद्रा क्षेत्र का सिद्धान्त कई अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया। सबसे पहले मण्डल ने इष्टतम मुद्रा क्षेत्र का सिद्धान्त दिया। बाद में मैकिनन, केनेन, मैक्कीफिको और वुड ने भी अपने सिद्धान्त दिए।

इष्टतम मुद्रा क्षेत्र के सिद्धान्तों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहले समूह के अर्थशास्त्रियों ने बिना सरकारी हस्तक्षेप के स्वतः समायोजन के सिद्धान्त दिए जबकि दुसरे समूह के अर्थशास्त्रियों ने सरकारी हस्तक्षेप को समायोजन के लिए महत्वपूर्ण माना। स्वतः समायोजन के सिद्धान्त साँझा मुद्रा क्षेत्र की उन विशेषताओं को निर्धारित करते हैं जी की स्वतः ही आंतरिक तथा बाह्य संतुलन लाती हैं। सरकारी हस्तक्षेप को समायोजन के लिए महत्वपूर्ण मानने वाले सिद्धान्त नीति - उन्मुख हैं और उन दशाओं को स्थापित करने की कोशिश करते हैं जिनमें मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ आंतरिक तथा बाह्य संतुलन ला सकें। सबसे पहले मण्डल ने साँझा मुद्रा क्षेत्र के सम्बन्ध में

चर्चा शुरू की और इष्टतम साँझा मुद्रा क्षेत्र के लिए नियमों का निर्धारण किया। मण्डल ने साधन गतिशीलता सिद्धान्त देते हुए साधन गतिशीलता के रूप में मुद्रा क्षेत्र की अनुकूलता (optimality) को परिभाषित करते हैं। मैककिनन इष्टतम मुद्रा क्षेत्र के निर्माण में अत्यधिक खुली अर्थव्यवस्थाओं और आंतरिक कीमत स्थिरता को अधिक महत्व देते हैं। केनन के अनुसार, इष्टतम मुद्रा क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उम्मीदवार वे अर्थव्यवस्थाएँ हैं जो कि कम खुली हैं और सामान्यतया अधिक विविधीकृत अर्थव्यवस्थाएँ हैं। मैगनीफिको का कहना है कि मुद्रा क्षेत्र का निर्माण उन देशों को करना चाहिए जहाँ स्फीति की प्रवृत्तियाँ समान हों। वुड का सिद्धान्त इष्टतम मुद्रा क्षेत्र की व्यवहारिकता या उपादेयता का विचार उसके लाभों के आधार पर करता है।

इष्टतम मुद्रा क्षेत्र के सिद्धान्तों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इष्टतम मुद्रा क्षेत्र की स्थापना और व्यवहारिकता के सन्दर्भ में निम्न लिखित तथ्य महत्वपूर्ण हैं: सदस्य देशों के बीच संसाधनों की व्यक्त गतिशीलता होनी चाहिए; मुद्रा क्षेत्र की लागतों की अपेक्षा इसके लाभ अधिक होने चाहिए, सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएँ आपसी आर्थिक संबंधों के लिए खुली होनी चाहिए, गैर-सदस्य देशों के साथ व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सदस्य देशों के बीच वस्तु विविधीकरण होना चाहिए; आन्तरिक एवं बाह्य संतुलन बनाए रखने के लिए सदस्य देशों में मौद्रिक राजकोषीय तथा अन्य नीतियों से सम्बन्धित नीति होनी चाहिए और एक इष्टतम मुद्रा क्षेत्र की स्थापना के लिए सदस्य देशों की बीच आर्थिक विचारों में समानता के साथ – साथ सामाजिक एवं राजनीतिक सौहार्द भी होना आवश्यक है।

15.8 शब्दावली

- **इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र** - इष्टतम मुद्रा-क्षेत्र ऐसे देशों का समूह है जिन्होंने अपनी मुद्राओं को एक स्थिर विनिमय प्रणाली से स्थायी रूप से जोड़ दिया है। परन्तु सदस्य देशों के अतिरिक्त शेष विश्व से, इन देशों की मुद्राओं की दर परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली से जुड़ी होती है। एक साँझा मुद्रा क्षेत्र एक साँझा मुद्रा द्वारा जुड़ा हुआ होता है।
- **परिवर्तनशील विनिमय दरें**- परिवर्तनशील विनिमय दरें विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति के शक्ति के द्वारा निर्धारित होती है तथा इसमें मौद्रिक प्राधिकरण को कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। विनिमय दरों में परिवर्तन देश की भुगतान-संतुलन की बदलती हुई स्थिति के अनुरूप विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन के फलस्वरूप स्वतः ही उत्पन्न होता है।
- **स्थिर विनिमय दरें**- इस व्यवस्था के अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में सरकार या राज्य का पूरा हस्तक्षेप रहता है। बाजार विनिमय दर एक दी हुई संतुलन स्तर पर स्थिर रहती है। यदि मांग और पूर्ति की शक्तियाँ इस संतुलन को बिगाड़ती हैं या सट्टेबाजी की गतिविधियाँ इस संतुलन को बिगाड़ती हैं तो सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है और इस संतुलित विनिमय दर को बचाए रखती है। सरकार विदेशी विनिमय के क्रय या विक्रय के माध्यम से ऐसा करती है।
- **आन्तरिक और बाह्य संतुलन** - देश के अन्दर कीमत स्थिरता तथा संसाधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति आन्तरिक संतुलन है ; इस स्थिति से विचलन अर्थव्यवस्था में असंतुलन करता है। जोकि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए घातक होता है। बाह्य असंतुलन का अर्थ है भुगतान संतुलन में असंतुलन, अर्थात् अतिरेक या घाटा।

15.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न:

- 1.क 2.घ 3.ग 4.घ 5.ख 6.ख 7.ग 8.क
9.ग 10.घ 11.ग 12.ख 13.ग 14.क 15.घ

सत्य व असत्य

1. सत्य 2.असत्य 3.सत्य 4.सत्य 5.असत्य
6.सत्य 7.असत्य 8.असत्य 9.सत्य 10.सत्य
11. सत्य 12.असत्य 13.सत्य 14.सत्य 15.असत्य
16.सत्य 17.सत्य 18.असत्य 19.सत्य

15.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- Bo Sodersten, International Economics ,Macmillan, 1999
- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006
- H. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: *International Economics: Theory and Policy*, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- एस. एन. लाल , अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र , शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहबाद, 2004
- एच. एस. अग्रवाल, तथा सी. एस. बरला, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2003.
- सुदामा सिंह एवं एम. सी. वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड एंड आई. बी. एच. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम. एल. झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010.
- डॉ. जी. सी. सिंघई एवं डॉ. जे. पी. मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा, 2010.

15.11 उपयोगी/सहायक पाठ्य सामग्री

- D. M. Mithani, International Economics, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2006
- H. G. Mannur, International Economics ,Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 2001
- Paul Krugman and Maurice Obstfeld: *International Economics: Theory and Policy*, Dorling Kindersley India Pvt Ltd, 2009.
- एस. एन. लाल , अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र , शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहबाद, 2004

- एच. एस. अग्रवाल, तथा सी. एस. बरला, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2003.
- सुदामा सिंह एवं एम. सी. वैश्य, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफ़ोर्ड एंड आई. बी. एच. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
- एम. एल. झिंगन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृंदा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010।
- ज्ञानेंद्र सिंह कुशवाहा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1979।

15.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. इष्टतम मुद्रा क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। इष्टतम मुद्रा क्षेत्र के सामान्य सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
2. इष्टतम मुद्रा क्षेत्र के प्रमुख सिद्धान्तों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।
3. विभिन्न सिद्धान्तों के सन्दर्भ में इष्टतम मौद्रिक क्षेत्र की व्याख्या कीजिए।
4. मुद्रा क्षेत्र के इष्टतम होने की दशाओं का वर्णन कीजिये। मण्डल का इष्टतम मुद्रा क्षेत्र का साधन गतिशीलता सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
5. मैककिनन तथा केनन के इष्टतम मुद्रा क्षेत्र के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
6. मैगनीफिको का स्फीति की प्रवृत्ति सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए तथा इष्टतम मुद्रा क्षेत्र के लाभ बताइए।